

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

सूक्ष्म एवं व्यापक-अर्थशास्त्र

(Micro and Macro-Economics)

जीवाजी विश्वविद्यालय के बी. ए. तृतीय वर्ष हेतु
नवीन पाठ्यक्रम अनुसार

लेखक

एस. के. जैन

सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष
(अर्थशास्त्र विभाग)

जैन स्नातक महाविद्यालय, भिण्ड (म. प्र.)

प्रकाशक

नीरज प्रकाशन

विक्टोरिया मार्केट, ग्वालियर-१

प्रकाशक :

नीरज प्रकाशन

ग्वालियर-१

★

वितरक :

नरेश स्टोर्स

ग्वालियर-१

★

मूल्य २०.०० रुपये

★

मुद्रक :

ओमेश्वर प्रेस,

कसेराओली, ग्वालियर-१

अनुक्रमणिका

(CONTENTS)

प्रथम खण्ड

सूक्ष्म-अर्थशास्त्र

[Micro-Economics]

व्याप	१	सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थ-शास्त्र Micro and Macro-Economics	१
अध्याय	२	उपयोगिता-विश्लेषण Utility-Analysis	३५
अध्याय	३	तटस्थता-वक्र विश्लेषण Indifference-Curve Analysis	२४
अध्याय	४	उपभोक्ता का सन्तुलन Consumers Equilibrium	४२
अध्याय	५	उत्पादन-फलन Production-Function	५१
अध्याय	६	पैमाने के प्रतिफल Returns to Scale	५७
अध्याय	७	समोत्पाद-वक्र Iso-Product Curves	६४
अध्याय	८	मूल्य-निर्धारण का सामान्य सिद्धान्त General Theory of Value	६६
अध्याय	९	आगम एवं लागत के विचार The Concept of Revenue and Costs	८०
अध्याय	१०	पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण Price-Determination Under Perfect Competition	९३
अध्याय	११	एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण Price-Determination Under Monopoly	१०८
अध्याय	१२	एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण Price-Determination under Monopolistic Competition	१३२
अध्याय	१३	प्रतिनिधि फर्म Representative Firm	१४२
अध्याय	१४	लागत Rent	१५०
अध्याय	१५	मजदूरी Wages	१७०
अध्याय	१६	व्याज Interest	१६२
अध्याय	१७	लाभ Profit	२२२

व्यापक-अर्थशास्त्र

[Macro-Economics]

अध्याय १	स्थिर एवं गतिशील अर्थशास्त्र ✓ Static and Dynamic Economic	२४
अध्याय २	राष्ट्रीय आय ✓ National Income	२५
अध्याय ३	आर्थिक प्रणाली के कार्य Functions of the Economic System	२६
अध्याय ४	पूँजीवाद ✓ Capitalism	२७
अध्याय ५	समाजवाद Socialism	२८
अध्याय ६	मिश्रित अर्थ-व्यवस्था Mixed Economy	३०
अध्याय ७	आर्थिक विकास की परिभाषा व महत्व ✓ Definition and Importance of Economic Growth	३१
अध्याय ८	आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व ✓ Determinants of Economic Growth	३२
अध्याय ९	अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था ✓ Under Developed Economy	३३
अध्याय १०	विकसित अर्थ व्यवस्था Developed Economy	३४
अध्याय ११	आर्थिक नियोजन की परिभाषा एवं विशेषताएँ Definition and Characteristics of Economic Planning	३५
अध्याय १२	आर्थिक नियोजन के उद्देश्य ✓ Objectives of Economic Planning	३६
अध्याय १३	आर्थिक नियोजन के प्रकार एवं तकनीक Types and Techniques of Economic Planning	३७
अध्याय १४	प्रथम पंचवर्षीय योजना First Five Year Plan	३८
अध्याय १५	द्वितीय पंचवर्षीय योजना Second Five Year Plan	३९
अध्याय १६	तृतीय पंचवर्षीय योजना Third Five Year Plan	४०
अध्याय १७	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ✓ Fourth Five Year Plan	४१
अध्याय १८	पाचवी पंचवर्षीय योजना Fifth Five Year Plan	४२

भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक जीवाजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है। यद्यपि आर्थिक विश्लेषण पर हिन्दी भाषा में पुस्तक पर्याप्त है परन्तु विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार पुस्तक का नितान्त अभाव है। प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पाठ्यक्रमानुसार सामग्री उपलब्ध कराना है।

पुस्तक की भाषा सरल एवं व्यावहारिक है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिये स्थान-स्थान पर विद्वानों के उद्धरणों को हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी दिया गया है। इसके साथ ही पुस्तक में नवीन व आधुनिक प्रवृत्तियों का पूर्ण समावेश है।

पुस्तक को तैयार करते समय विभिन्न पुस्तकें, सदस्य ग्रन्थ, पत्र-पत्रिकाओं तथा लेखों से सहायता एवं सामग्री प्राप्त की है। उन समस्त प्रकाशकों व लेखकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

विश्वास है यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने हेतु रचनात्मक सुझावों का स्वागत करेंगा।

जीवाजी विश्वविद्यालय

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

अर्थशास्त्र ECONOMICS

बी ए तृतीय वर्ष

Paper I—Micro Economic Theory

Nature and Significance of Micro Economic, Utility analysis and indifference curve, Consumer's equilibrium.

Production :

Production, Function and Returns to scale—Isoquant curves, Theory of value—Price determination under—Perfect, Imperfect, Monopolistic competitions and Monopoly, Price discrimination under monopoly

Factor Price Determination :

Recent Theories of Rent, Wages, Interest and Profit

Paper II—Macro-Economic Theory

Nature and Significance of Macro-Economic, Static & Dynamic Economics, National Income—Various concepts of national income

Functioning of various economic systems

Economic Growth & Planning :

Meaning of Economic Growth Characteristics of under-developed and developed economics, Determination of Economic Growth, Planning—Definition of Planning, objective and types of planning, Study of India's Five Year Plans with special reference to employment Resources mobilisation and agriculture, Industry under Fourth Five Year Plan

Study of India's Five Year Plans with special reference to Employment, Resource Mobilisation, Agriculture and Industry

प्रथम खण्ड

सूक्ष्म-अर्थशास्त्र
(MICRO-ECONOMICS)

सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र

[Micro and Macro-Economics]

★ ★ ★

आधुनिक आर्थिक विश्लेषण अब दो भागों में विभक्त किया जाने लगा है,

a) सूक्ष्म विश्लेषण (Micro analysis); (b) व्यापक विश्लेषण (Macro analysis)। विश्लेषण के इन दो दृष्टिकोणों के आधार पर अर्थशास्त्र का अध्ययन निम्न दो भागों में किया जाता है

अ) सूक्ष्म अर्थशास्त्र (Micro-Economics), तथा

ब) व्यापक अर्थशास्त्र (Macro-Economics)।

आज ये दोनों शब्द आर्थिक शब्दावली (Economic Terminology) के अविभाज्य भाग बन गये हैं। इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम ऑस्वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रेग्नर फ्रिश (Regner Frisch) ने किया। इससे पश्चात् अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसे अपनाया।

सूक्ष्म^१ (Micro) और व्यापक^२ (Macro) दोनों ही शब्द मूलतः यूनानी भाषा के हैं। 'माइक्रो' (Micro) का अर्थ है 'छोटा' तथा 'मैक्रो' (Macro) का अर्थ है बड़ा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र विभिन्न इकाइयों या वैयक्तिक इकाइयों (individual units) का अध्ययन करता है, जैसे—किसी एक फर्म का उत्पादन, किसी एक वस्तु की माग आदि। व्यापक अर्थशास्त्र

* Micro-Economics—सूक्ष्म अर्थशास्त्र को आर्थिक व्यक्तिवाद, व्यक्ति विश्लेषण, विभिन्न अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं।

Macro-Economics—व्यापक अर्थशास्त्र को आर्थिक समष्टिवाद, समष्टि विश्लेषण, सामूहिक शक्ति अर्थशास्त्र भी कहते हैं।

वैयर्थिक इकाइयों की ओर ध्यान न देकर 'समूह' (aggregate) का अध्ययन करता है अर्थात् अर्थ-व्यवस्था का उसमें समग्र रूप से अध्ययन करना है, जैसे—कुल आय, कुल वचन, कुल विनियोग, सामान्य मूल्य स्तर आदि।

सूक्ष्म अर्थशास्त्र (Micro-Economics)

सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों अथवा वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे—किसी फर्म का उत्पादन, किसी एक वस्तु की माग इत्यादि।

सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (The Historical Background of Micro Economics) —

आर्थिक विश्लेषण के दोनों दृष्टिकोणों से प्राचीन अर्थशास्त्री परिचित थे, फिर भी प्रारम्भ में सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ओर अधिक ध्यान दिया गया। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विकास का धर्म एडम स्मिथ (Adam Smith) को है, जिन्होंने आर्थिक विचारों को व्यवस्था प्रदान कर उसे एक सामाजिक शास्त्र का स्वरूप प्रदान किया। प्रतिष्ठित आर्थिक विश्लेषण (classified economic analysis) में सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिकोणों का मिश्रण पाया जाता है। उनका मत था कि व्यक्ति निजी हित से प्रभावित होकर आर्थिक संगठन को सुचारु रूप से चलाने रहते हैं। इस 'निजी हित' (self interest) के आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह समझने का प्रयत्न किया कि अर्थ व्यवस्था में उत्पादन किस प्रकार होता है, किस प्रकार वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है और किस प्रकार कुल आय का वितरण होता है।

मार्शल (Marshall) ने सूक्ष्म और आर्थिक विश्लेषण को अधिक महत्व प्रदान किया। मार्शल तथा उसके अन्य साथियों ने सामान्य आर्थिक विश्लेषण तथा माल्थस और कार्ल मार्क्स (Malthus and Karl Marx) जैसे प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के लेखों की अवहेलना कर सूक्ष्म अर्थशास्त्र को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। यद्यपि इस समय बृहत् अन्य अर्थशास्त्रियों ने छुटपुट रूप में व्यापक विश्लेषण का प्रयोग किया, लेकिन उनकी अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई।

१९२९-३२ की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। इस स्थिति के कारण अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। की-स (Keynes) ने सूक्ष्म विश्लेषण की मान्यताओं की आधारभूत कमियों की ओर अर्थशास्त्रियों का ध्यान दिलाया और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर अधिक जोर दिया। वालरस (Walras), विकसेल (Wicksell) तथा इरविंग फिशर (Irving Fisher)

आदि प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने भी व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन के फलस्वरूप ही आज सूक्ष्म अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि में चला गया है और व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है।

सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ (Meaning of Micro Economics)

‘सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विस्तारण की यह शाखा है जिसमें वैयक्तिक इकाई के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।’³

यह वैयक्तिक इकाई एक पद, एक वस्तु का उत्पादन, एक व्यक्ति की आय, एक दम्पति का मूल्य, बहुत भी हो सकती है।

‘इसमें समूह का अध्ययन न किया जाकर विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है।’⁴

सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा मत व्यक्त किये जाये हैं।⁵ इसकी प्रमुख परिभाषायें निम्नलिखित हैं —

✓ **के ई बौलडिंग (K. E. Boulding)** ने कहा है—‘सूक्ष्म अर्थशास्त्र विभिन्नता पदों, विभिन्नता परिवारों, वैयक्तिक सीमितों, मजदूरियों, आयों, वैयक्तिक उद्योगों और विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन करता है।’⁶

हैंडरसन क्वान्ट (Henderson Quandt) ने अनुवाद—‘सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तियों और व्यक्तियों के सुपरिभाजित समूहों व आर्थिक कार्यों का अध्ययन है।’⁷

विलियम फैलनर (William Fellner) ने कहा है—‘सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सम्बन्ध वैयक्तिक निर्णय करने वाले इकाइयों से है।’⁸

3 “Micro Economics is the study of the economic behaviour of an individual unit”

4 “It is not aggregative but selective”

5 “Micro Economics is the study of particular firms, particular households individual prices, wages incomes, individual industries, particular commodities —K. E. Boulding

6 “Micro Economics is the study of economic actions of individuals and well defined groups of individuals”

—Henderson Quandt

7 “Micro Economics relates to individual of decision making units” —William Fellner

इस प्रकार स्पष्ट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत उपभोक्ता तथा उत्पादक के व्यवहार, आर्थिक उद्देश्य, व्यक्तिगत फर्मों एवं उद्योगों के संगठन तथा संचालन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।

सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धान्त (price theory), भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अध्ययन का मुख्य विषय किसी वस्तु अथवा सेवा की कीमत निर्धारित करना है।^८

सूक्ष्म अर्थशास्त्र की दो बात महत्वपूर्ण हैं—

(अ) सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण सीमान्त विश्लेषण (marginal analysis) है। इसी विश्लेषण के आधार पर अर्थशास्त्र में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जैसे—उपयोगिता, ह्रास नियम, समीचीनता उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की वक्तव्य आदि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नियम सीमान्त विश्लेषण पर आधारित हैं।

(ब) सूक्ष्म अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इस मान्यता के आधार पर ही यह पता लगाया जाता है किस प्रकार उत्पादक या उपभोक्ता साम्य अवस्था को प्राप्त करता है।

सूक्ष्म अर्थशास्त्र की उपयोगिता (Utility of Micro Economics) :

सूक्ष्म-विश्लेषण आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है—

(अ) आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक—सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वैयक्तिक तौर पर विशिष्ट आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, जिसके माध्यम से सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की समस्याओं को सही रूप में समझा जा सकता है।

(ब) अर्थ-व्यवस्था के विश्लेषण में सहायक—यह विश्लेषण वैयक्तिक व्यय, वक्तव्य, आय, विनियोग, उपभोग इत्यादि पर प्रकाश डालता है और उनका सूक्ष्म रूप में विश्लेषण करता है जिससे सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का विश्लेषण करने में सहयोग प्राप्त होता है।

(स) वैयक्तिक इकाइयों के स्वभाव का अध्ययन—यह विश्लेषण वैयक्तिक इकाइयों, जैसे—फर्म या एक उद्योग के कार्यों तथा उसके स्वभाव का अध्ययन करता है और उसकी समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है।

प्रो. शूल्ज (Schultz) ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य क्षेत्र कीमत सिद्धान्त बताया है। लेफ्टविच (Leftwich) ने कीमत सिद्धान्त को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा है।

- (द) आर्थिक निर्णय लेने में सहायक—सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन से व्यक्तियाँ, परिवारों, फर्मों इत्यादि को आर्थिक निर्णय लेने में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है।
- (घ) कीमत-निर्धारण विधि का धरेण—यह विश्लेषण वस्तुओं और सेवाओं की कीमत-निर्धारण विधि का वर्णन करता है।

सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएँ (Limitation of Micro Economics) :

साहें कोम्स ने सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण को अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी और आवश्यक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इस विश्लेषण की कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। इस विश्लेषण की सीमाएँ (दोष) निम्नलिखित हैं —

- (अ) सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से कभी कभी गलत होते हैं—कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो निष्कर्ष वैयक्तिक इकाई के बारे में सत्य हैं वह समूह (aggregate) के बारे में भी सत्य हों। उदाहरणार्थ बचन एक व्यक्ति की दृष्टि से उचित एवं लाभदायक होती है, परन्तु यदि सम्पूर्ण समाज ही बचन करना पारम्भ कर दे तो वह अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि जब सभी व्यक्ति बचन करेंगे तो प्रभावपूर्ण माग (effective demand) कम होगी जिसके परिणामस्वरूप रोजगार की मात्रा कम हो जायगी, जो कि राष्ट्रीय आय में कमी कर देगी।
- (ब) सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा आर्थिक समूहों की कार्यप्रणाली का पूर्ण और सही चित्र प्राप्त नहीं होता—सूक्ष्म विश्लेषण में अध्ययनकर्ता अलग-अलग इकाइयों का विश्लेषण करने में ही लगा रहता है जिसके कारण सामान्य धारें छूट जाती हैं। इसी के परिणामस्वरूप सामूहिक आधार पर अपनायी जाने वाली सामान्य नीति का परिणाम वैयक्तिक इकाइयों के योग से कभी कभी भिन्न होता है।
- (स) सूक्ष्म विश्लेषण की मान्यताएँ अवास्तविक हैं—यह विश्लेषण निम्न दो अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है
 - (अ) अन्य बातें समान रहती हैं, तथा
 - (ब) समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति पायी जाती है।

ये दोनों ही मान्यताएँ अवास्तविक हैं, क्योंकि न तो समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति पायी जाती है और न ही अन्य बातें समान रहती हैं।
- (द) सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है—इस विश्लेषण द्वारा अनेक आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाना

सम्भव नहीं है, जैसे—राष्ट्रीय आय का वितरण, राजस्व की समस्याएँ, मूल्य निर्धारण, मौद्रिक व प्रत्यक्ष नीति आदि।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि सूक्ष्म विश्लेषण को कुछ परिमाणों में है लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह विश्लेषण आर्थिक विश्लेषण में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। वास्तविकता यह है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र पर काफी प्रकाश डालता है, जैसे—राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, नालो व्यक्तियों और हजारों फर्मों के निर्णय का परिणाम होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वैयक्तिक फर्मों, निजी व्यक्तियों तथा वैयक्तिक उद्योगों की प्रवृत्ति का तथा वैयक्तिक इकाइयों को प्रभावित करने वाले सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाय। अतः हम यह कह सकते हैं कि बिना सूक्ष्म विश्लेषण का अध्ययन किसे सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

व्यापक अर्थशास्त्र (Macro-Economics)

व्यापक अर्थशास्त्र वैयक्तिक इकाइयों की ओर ध्यान न देकर 'समूह' का अध्ययन करता है, अर्थात् अर्थ व्यवस्था का उसके समग्र रूप में अध्ययन करता है, जैसे—कुल आय, कुल खर्च, कुल निनिमोग आदि।

व्यापक अर्थशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background of Macro-Economics)

आर्थिक विश्लेषण के दोनो रूप—सूक्ष्म और व्यापक से प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने ध्यान रखा है। सर्वप्रथम व्यापारवादी (mercantilists) लेखकों तथा प्रजातिवादी (physiocrats) लेखकों ने व्यापक अर्थशास्त्र को पृष्ठभूमि प्रदान की। परन्तु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दोनों विश्लेषणों का मिश्रित प्रयोग किया। माल्थस (Malthus) पहला अर्थशास्त्री है जिसने समाज की कुल मांग और कुल उत्पादन में सम्बन्ध स्थापित किया तथा जनसंख्या की समस्या पर प्रकाश डाला। इस प्रकार यदि माल्थस को व्यापक अर्थशास्त्र का जन-मदाता बड़े तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिस्मोंडी (Sismondi) तथा मार्क्स (Marx) जैसे विद्वान अर्थशास्त्रियों ने भी अपने लेखों में व्यापक अर्थशास्त्र को महत्व प्रदान किया।

१९२९-३२ की विश्वव्यापी मन्दी के परिणामस्वरूप अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और उनका ध्यान सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ। व्यापक विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय कीन्स को है, जिन्होंने अपनी पुस्तक 'जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लायमेन्ट, इन्टरेस्ट एण्ड मनी' (General

Theory of Employment, Interest and Money) में इस विश्लेषण को प्रमुख स्थान दिया। फीशर ने पूर्ण समुच्चय (Schumpeter), बाह्य बावक (Bohm Bowark) तथा फिशर (Fisher) ने भी व्यापक आर्थिक विश्लेषण के विकास में अपना योग दिया। वर्तमान में अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यापक विश्लेषण का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में किया जाता है।

प्रो एलन (Allen) के शब्दों में—“विगत कुछ वर्षों में व्यापक अर्थशास्त्र का विकास इतनी तीव्र गति से हुआ है जिससे कि अर्थशास्त्र के ढाँचे में उलट-पुलट हो गई है।

व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ (Meaning of Macro Economics)

व्यापक अर्थशास्त्र ‘समूह’ का अध्ययन करता है इसलिये इसे ‘सामूहिक अर्थशास्त्र’ (Aggregative Economics) भी कहते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र को कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं —

प्रो के ई बोर्डिंग के शब्दों में—‘व्यापक अर्थशास्त्र का सम्बन्ध वैयक्तिक मामलों से न होकर इन मात्राओं के समूह से होता है, इसका सम्बन्ध वैयक्तिक आय से न होकर राष्ट्रीय आय से होता है, वैयक्तिक मूल्यों से न होकर सामान्य मूल्य स्तर से होता है, वैयक्तिक उत्पादन से न होकर राष्ट्रीय उत्पादन से होता है।’

गार्डनर एक्ले (Gardner Ackley) के अनुसार—‘व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक मामलों का बड़े रूप में अध्ययन करता है। वह आर्थिक जीवन की सभी दिशाओं से सम्बन्धित है यह उन वृत्तों से पृथक् होकर जंगल के वृक्षों की प्रकृति का विश्लेषण करता है जो कि इनके निर्माता हैं।’

इन प्रकार हम यह देखते हैं कि व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफी विस्तृत है, क्योंकि यह सापेक्ष प्रणाली के औसतों (averages) और समूहों (aggregates) का

9 “Macro Economics deals not with individual quantities as such, but with aggregate of these quantities, not with individual income, but with the national income, not with individual prices but with price levels, not with the individual output but with the national output”
—Prof K E Boulding

10 “Macro-Economics deals with economic affairs in the large It concerns the over-all dimensions of economic life It studies the character of the forest independently of the trees which compose it.”
—Gardner Ackley

अध्ययन है । व्यापक अर्थशास्त्र के अध्ययन के केन्द्र-बिन्दु राष्ट्रीय आय और रोजगार हैं, इसलिये कभी कभी इसे राष्ट्रीय आय विश्लेषण (national income analysis) भी कहते हैं । इसके अतिरिक्त इसमें कुल उत्पादन, सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रा तथा बैंकिंग की समस्याएँ, विदेशी व्यापार तथा राजस्व का अध्ययन किया जाता है ।

व्यापक, अर्थशास्त्र के अध्ययन में वृद्धि करने वाले कारक

जैसा कि पूर्व में संकेत दिया गया है कि व्यापक विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय कीन्स को है, यद्यपि कीन्स से पहले भी अर्थशास्त्रियों ने व्यापक विश्लेषण का प्रयोग किया लेकिन कीन्स की पुस्तक 'जनरल थ्योरी' ने इस विश्लेषण को नींव की अधिक भज्युत कर दिया । व्यापक विश्लेषण की अधिक लोकप्रियता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

- (अ) **आर्थिक मन्दी (Economic depression)**—व्यापक आर्थिक विश्लेषण के प्रयोग में तात्कालिक वृद्धि का कारण १९२९-३२ की महान् आर्थिक मन्दी थी, जिसके परिणामस्वरूप समाज में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उत्पन्न हो गई । इस समस्या के हल करने के लिये अर्थशास्त्रियों ने व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया ।
- (ब) **राष्ट्रीय लाभांश (National dividend)**—डॉ. मार्शल द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय लाभांश का विचार भी व्यापक, अर्थशास्त्र के विकास का महत्वपूर्ण कारण बना । मार्शल ने एक व्यक्ति की आय के स्थान पर सम्पूर्ण आय का अध्ययन किया । इसके पश्चात् पीगू और फिशर ने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाया ।
- (स) **भुगतानों का चक्रीय प्रवाह (Circular flow of payment)**—प्रवृत्तिशायी अर्थशास्त्रियों (physiocrats) की इस धारणा की, कि समाज की कुल आय समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों में चक्र के रूप में घूमती है, व्यापक विश्लेषण का पर्याप्त प्रोत्साहन मिला ।
- (द) **मुद्रा का सिद्धान्त (Theory of money)**—मुद्रा के सिद्धान्त में किसी व्यक्ति के स्थान पर सम्पूर्ण समाज पर मुद्रा के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है । मुद्रा के मूल्य-निर्धारण में कुल प्रभावपूर्ण माग, कुल पूर्ति, कुल विनियोग, कुल वचत तथा उपभोग आदि का अध्ययन होता है, जिससे व्यापक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण के विकास को सहयोग प्राप्त हुआ ।
- (य) **व्यापार चक्र (Trade cycles)**—व्यापार चक्र का अध्ययन सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर किया जाता है । इस प्रकार व्यापार चक्र भी इस विश्लेषण के विकास में सहायक सिद्ध हुआ है ।

- (१) योजनाबद्ध आर्थिक विकास (Planned economic development)—वर्तमान समय में आर्थिक विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। आर्थिक विकास ॥ दिन-प्रतिदिन की जटिलताओं और समस्याओं को समझने के लिए सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अतः स्वभाविक रूप से व्यापक विश्लेषण को प्रोत्साहन मिलता है।

व्यापक अर्थशास्त्र की उपयोगिता (Utility of Macro Economics) —

सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाओं तथा अन्य कारणों ने व्यापक अर्थशास्त्र का अधिक उपयोगी बना दिया है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है —

- (अ) आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक—आज सभी देशों की सरकारें (चाहे उनमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो) अपने नागरिकों के कल्याण के लिये और सुरक्षा के लिए नीतियाँ निर्धारित करती हैं। इन नीतियों की सफलता के लिए व्यक्तिगत हित के स्थान पर समूह के हित को महत्व प्रदान किया जाता है। प्रो. बौलडिंग (Boulding) के शब्दों में—‘आर्थिक नीति के दृष्टिकोण से व्यापक अर्थशास्त्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह इसलिए कि सरकार की आर्थिक नीतियों का सम्बन्ध व्यक्ति से न होकर बड़े समूहों और व्यक्तियों के योगों (aggregates of individuals) से होता है। वास्तविकता यह है कि आर्थिक दृष्टि से राज्य स्वयं व्यक्तियों का समूह है, इसलिए इसका अध्ययन व्यापक आर्थिक दृष्टि से होना चाहिए।’^{११}
- (ब) जटिल आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक—व्यापक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण से वर्तमान जटिल अर्थ-व्यवस्था का ज्ञान सरलता से किया जा सकता है। व्यापक अर्थशास्त्र अर्थ-व्यवस्था के आर्थिक समूहों और संचालन का सही ज्ञान प्रदान करता है, जो कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा सम्भव नहीं है।
- (स) आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक—यह विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सहयोग प्रदान करता है। अर्थशास्त्र की अनेक समस्याओं, जैसे—

11 “From the point of view of economic policy, Macro-Economics is extremely important. This is because the economic policies of government concern themselves not with individuals, but with large groups and aggregates of individuals. Indeed, from an economic point of view the national state itself is an aggregate of individuals and must, therefore, be treated in Macro Economic terms.”
—Prof Boulding

(ब) व्यापक अर्थशास्त्र में कभी कभी सजातीय समूहों (homogeneous groups) के स्थान पर विजातीय समूहों (heterogeneous groups) का अध्ययन किया जाता है—कभी-कभी व्यापक विश्लेषण में निष्कर्ष निकालते समय ऐसे समूहों को सम्मिलित कर लिया जाता है जो कि समरूप या सजातीय नहीं होते।

प्रो० बोल्डिंग के शब्दों में—“समूहों को बनाने वाली मद परस्पर सम्बन्ध राने वाली, महत्वपूर्ण और रोचक होनी चाहिये।”

जैसे •

(a) ६ सेव + ७ सेव = १३ सेव—यह समूह महत्व रखता है।

(b) ६ सेव + ७ नारंगी = १३ फन—यह समूह कुछ महत्व रखता है।

(c) ६ सेव + ७ मकान = यह समूह निरर्थक है क्योंकि सेव और मकान विजातीय हैं। अतः इस प्रकार के विजातीय निरर्थक समूहों के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष व्यापक विश्लेषण के महत्व को कम कर देने हैं।

(स) समूह की अपेक्षा समूह की रचना अधिक महत्वपूर्ण होती है—जब अर्थशास्त्रियों द्वारा बिना समूह की प्रतिया की समझे ही समूह के आधार पर अभिव्यक्तियों की जाती है या कोई सुझाव दिया जाता है तो वह प्रायः गलत होता है। अतः यह आवश्यक है कि पहले समूह की भिन्न भिन्न इकाइयों का अलग अलग अध्ययन किया जाय।

प्रो० बोल्डिंग के शब्दों में—“हमें समूह की भिन्न भिन्न मदों के स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। सभी मदों की एक ही स्वभाव की समझ लेना भयंकर भूल होगी।”

उदाहरण के लिए, १९७० का सामान्य मूल्य स्तर कुछ समान है अर्थात् इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यह सम्भव है कि इस वर्ष में कृषि वस्तुओं के मूल्यों में कमी आ गई हो और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हों। इस स्थिति में कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन एक-दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे तथा मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः समूह के आधार पर बिना समूह की रचना समझे हुए अभिव्यक्तियों करना उचित नहीं है।

(द) समूह (aggregate) अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित नहीं करता—सदैव यह आवश्यक नहीं है कि सामूहिक प्रवृत्ति अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित करे, जैसे सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती। मूल्य स्तर में

वृद्धि से निश्चित आय प्राप्त करने वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि उत्प्रेरक वर्ग को लाभ प्राप्त होता है।

- (घ) समूह की भाषना कठिन है—इस विश्लेषण में यह कठिनाई आती है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव वाली वस्तुओं को एक वस्तु के रूप में व्यक्त किया जाय।

सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता (Interdependence of Micro and Macro Economics)

सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र का अलग अलग अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि विश्लेषण की दोनों विधियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। ये दोनों विश्लेषण अपने क्षेत्र, विषय वस्तु और दृष्टिकोण की दृष्टि से अर्थशास्त्र में अपना अलग-अलग स्थान रखते हैं, परन्तु यह भिन्नता दोनों को असम्बद्ध नहीं करती। अपनी विचारधारा के अनुसार एवं अर्थशास्त्री किसी एक दृष्टिकोण पर जोर देना है तो दूसरा अर्थशास्त्री दूसरे दृष्टिकोण पर। परन्तु दृष्टिकोणों की यह भिन्नता सूक्ष्म और व्यापक विश्लेषण की पारस्परिक निर्भरता को कम नहीं करनी। इस स्थिति को हम निम्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं—

- (अ) सूक्ष्म अर्थशास्त्र की व्यापक अर्थशास्त्र पर निर्भरता—मान लीजिए कि एक फर्म अपने फर्म में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी के सम्बन्ध में निर्णय लेती है, यह समस्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की है, क्योंकि यह फर्म विशेष से ही सम्बन्धित है। यह फर्म मजदूरी निर्धारित करते समय दूसरी फर्मों में श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को देखेगी तथा राष्ट्रीय मजदूर नीति को भी ध्यान में रखेगी। इसका कारण यह है कि एक फर्म में दी जाने वाली मजदूरी उसी फर्म की मांग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सम्पूर्ण आर्थिक सङ्गठन की स्थिति से प्रभावित होती है।
- (ब) यदि एक फर्म अपनी उत्पादित वस्तु का मूल्य निर्धारित करती है तो वह मूल्य निर्धारित करने से पहले दूसरी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों की ओर भी ध्यान देती है।
- (स) यदि एक फर्म अपनी वस्तु के उत्पादन की मात्रा निर्धारित करना चाहती है तो वह मात्रा निर्धारित करते समय समाज की कुल मांग और रोजगार की स्थिति को ध्यान में रखती है।

अतः हम यह कह सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को विभिन्न वैयक्तिक इकाइयों की समस्याओं का अध्ययन करने और उनकी सुलझान के लिए व्यापक अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है।

व्यापक अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर निर्भरता

जिस प्रकार सूक्ष्म अर्थशास्त्र की समस्याओं के अध्ययन के लिए व्यापक अर्थशास्त्र का सहयोग आवश्यक है, उसी प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र की समस्याओं के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सहयोग की आवश्यकता होती है :—

- (अ) यदि एक अर्थशास्त्री सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करना चाहता है तब उसे इस अध्ययन के लिए स्थितियों, फर्मों, परिवारों और उद्योगों का अध्ययन करना आवश्यक होगा, क्योंकि वैयक्तिक इकाइयों के स्वरूप को बिना समझे अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो सकेगी।
- (ब) यदि सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के लिए किसी योजना का निर्माण करना है तो इसके लिए वैयक्तिक फर्मों, उद्योगों आदि की योजनाओं की ओर ध्यान देना होता है। इस सम्बन्ध में प्रो डी एन गुट्टे का कथन उल्लेखनीय है—“असिक्त समस्याओं पर सूक्ष्म रूप से विचार किये बिना सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की समस्याओं को जानना और सुलझाना उसी प्रकार अकल्पनीय है जिस प्रकार कोई बिना सीढ़ियों को पार किये हुए कमरे की छत पर पहुँचना चाहे।”

इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सहयोग भी आवश्यक है।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं। इन दोनों में कोई विभेद अपने में पूर्ण नहीं है। किसी भी आर्थिक समस्या के लिए दोनों दृष्टिकोणों का सहयोग लेना पड़ता है। इस सम्बन्ध में प्रो सम्युलसन (Samuelson) का कथन सही प्रतीत होता है। उन्हीं के शब्दों में—

“वास्तव में सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है। दोनों अत्यावश्यक हैं। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्ध-सिद्धि हैं।”¹²

12 “There is really no opposition between Micro and Macro-Economics. Both are absolutely vital And you are only half educated if you understand the one while being ignorant of the other ”
— Prof Samuelson

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र पर एक लेख लिजिए ।
- २ सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अन्तर बताइए तथा दोनों प्रकार के विश्लेषण की सीमाओं भी समझाइए ।
- ३ सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं । आर्थिक विश्लेषण में सूक्ष्म अर्थशास्त्र के महत्व को समझाइये और इसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिये ।
- ४ व्यापक अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है ? आर्थिक विश्लेषण में व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व समझाइये और इसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए ।
- ५ “वास्तव में सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है । दोनों अत्यावश्यक हैं । यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्द्धशिक्षित हैं —सैम्प्यूनसन” । इस कथन की व्याख्या कीजिए ।
- ६ “अर्थशास्त्री को सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र, दोनों का अध्ययन करना पड़ता है । दोनों विधियाँ एक-दूसरे की पूरक (complementary) हैं, वैकल्पिक (alternate) नहीं ।” इसकी व्याख्या कीजिए ।
- ७ सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र की उपयोगिता बताइए और इसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए ।

अध्याय २

★

उपयोगिता-विश्लेषण

[Utility-Analysis]

★ ★ ★

उपयोगिता का अर्थ (Meaning of Utility) •

सामान्य भाषा में उपयोगिता (utility) और लाभदायकता (usefulness) को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकता को सन्तुष्ट करने की शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु या सेवा की वह शक्ति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आवश्यकता को सन्तुष्ट करती है, उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए पैन, में उपयोगिता है क्योंकि यह हमारी लिखने की आवश्यकता को सन्तुष्ट करता है।

उपयोगिता की परिभाषा को समझने के लिये निम्नांकित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :—

- (१) उपयोगिता व्यक्तिगत (Subjective) तथा सापेक्षिक (Relative) होती है—
उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। यह व्यक्ति की आन्तरिक भावनाओं से सम्बन्धित है। उपयोगिता व्यक्तिगत और सापेक्षिक होने के कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न-भिन्न हो सकती है। यह भी सभव है कि उपयोगिता एक ही व्यक्ति के लिये भिन्न-भिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न हो। उदाहरण के लिये, मेज A व्यक्ति के लिये उपयोगी है, आवश्यक नहीं है कि वह B व्यक्ति के लिये भी उपयोगी हो।
- (२) उपयोगिता तथा लाभदायकता में निश्चित सम्बन्ध नहीं होता—उपयोगिता तथा लाभदायकता दोनों अलग-अलग हैं, एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं। यह सभव

है कि कोई वस्तु एक व्यक्ति के लिये लाभदायक नहीं हो, फिर भी वह वस्तु उस व्यक्ति के लिये उपयोगिता रखती हो। उदाहरण के लिये, शराब स्वास्थ्य के लिये लाभदायक नहीं है फिर भी शराबी के लिये यह अत्यधिक उपयोगिता रखती है।

(३) उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है—जिस वस्तु की प्राप्ति करने के लिये हमारी इच्छा जितनी अधिक तीव्र होगी, उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता या सतुष्टि प्राप्त होगी। इस प्रकार उपयोगिता का वस्तु से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता।

(४) उपयोगिता तथा नैतिकता (Morality) का सम्बन्ध नहीं होता—उपयोगिता का सम्बन्ध नैतिकता से विलुप्त भी नहीं है। उदाहरण के लिये, बिना लाइसेंस के पिस्तौल रखना अपराध है तथा गैर कानूनी है लेकिन उस व्यक्ति के लिये उपयोगी है जो कि स्मगलिंग का कार्य करता है।

(५) उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है—जैसे-जैसे किसी एक वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे उसकी अगली इकाई की वृद्धि से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। एक सीमा के बाद उस वस्तु की उपयोगिता शून्य रह जाती है। इस प्रकार एडवर्ड नेविन (Edward Navin) के शब्दों में—“अर्थशास्त्र में उपयोगिता से अर्थ उस सतुष्टि से है जो किसी व्यक्ति को धन या सम्पत्ति के उपयोग से प्राप्त होती है।”^१

फ्रेजर ने इस धारणा को अधिक विस्तृत कर दिया है। फ्रेजर (Fraser) के शब्दों में—“यह केवल इच्छा करना है।”^२

उपयोगिता की माप (Measurement of Utility)

किसी वस्तु अथवा सेवा का वह गुण जिसमें मानवीय आवश्यकता को सतुष्ट करने की क्षमता है, उपयोगिता कहलाता है। उपयोगिता वस्तुगत न होकर उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक स्थिति एवं दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। अतः एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? उपयोगिता की माप के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में दो दृष्टिकोण हैं—

१ एडवर्ड नेविन ने बताया है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ यह है कि कुछ व्यक्ति इसे चाहते हैं, किन्तु व्यक्ति इसे क्यों चाहते हैं इससे अर्थशास्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं।

२ “It is simply desirousness”

—Fraser

(१) गणनावाचक दृष्टिकोण (Cardinal approach), तथा

(२) क्रमवाचक दृष्टिकोण (Ordinal approach) ।

गणनावाचक दृष्टिकोण (Cardinal Approach)

माशेल तथा पोसू आदि अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि उपयोगिता की माप सम्भव है । उपयोगिता की माप करने के लिये वे धुन्ना रूपी पैमाने का प्रयोग करते हैं । उनका विचार है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिये कीमत उसकी उपयोगिता से अधिक नहीं देगा । अतः किसी वस्तु के लिये दी जाने वाली कीमत मीठे रूप में उस वस्तु की उपयोगिता की माप है । उदाहरण के लिये, एक व्यक्ति पुस्तक के लिये ₹२ रुपये देने को तैयार है तो उस व्यक्ति के लिये पुस्तक की उपयोगिता ₹२ रुपये के बराबर है ।

उपयोगिता की माप सम्भव है । इस दृष्टिकोण को गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं, तथा इस दृष्टिकोण के मानने वाले अर्थशास्त्रियों को गणनावाचक अर्थशास्त्री (cardinalist) कहते हैं । इनके अनुसार उपयोगिता को सीधे सरायाओं में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे—४, ६, ८, १० इत्यादि । अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता की मापना और तुलना करना सम्भव है । जैसे A व्यक्ति को समुद्रे से ३० उपयोगिता प्राप्त होती है तथा सेब से १५ इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है । इससे स्पष्ट है कि समुद्रे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता A व्यक्ति के लिये सेब की उपयोगिता से दुगुनी है ।

इस दृष्टिकोण को गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण (cardinal utility approach) या गणनावाचक उपयोगिता (cardinal utility) भी कहते हैं ।

क्रमवाचक दृष्टिकोण (Ordinal Approach)

माशेल के गणनावाचक दृष्टिकोण से कुछ अर्थशास्त्री सहमत नहीं हैं । परेडो (Pareto), ऐलन (Allen) तथा हिक्स (Hicks) आदि ने बताया कि उपयोगिता की माप करना सम्भव नहीं है और न ही उपयोगिता को सराया में व्यक्त किया जा सकता है । इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार वस्तुओं को विभिन्न समूहों के आधार पर क्रमबद्ध रूप से रखा जा सकता है । दूसरे शब्दों में, उपयोगिता की बेवज 'क्रमवाचक सराया' ही प्रदान की जा सकती है । जैसे यदि हम पैन और स्वाही की उपयोगिता की मापना चाहें तो उसे निम्नलिखित सराया में प्रदर्शित करके केवल यह कहेंगे कि पैन की उपयोगिता स्वाही से अधिक है । यह प्रकट केवल प्राथमिकता (preference), निर्धारण करते हैं ।

इस दृष्टिकोण को क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं तथा इस दृष्टिकोण के मानने वाले अर्थशास्त्रियों को क्रमवाचक अर्थशास्त्री (ordinalists) कहते हैं । हिक्स के अनुसार

उपयोगिता की माप करना संभव नहीं है, अतः उन्होंने उपयोगिता विश्लेषण (utility analysis) के स्थान पर 'तटस्थता वक्र विश्लेषण' (indifference curve analysis) का रीति प्रतिपादित की।³ पेरेटो तथा हिक्स ने उपयोगिता के मापन का विरोध निम्नादिन कारणों से किया —

- (१) उपयोगिता मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत विचार है, अतः इसे मापने का प्रयास करना गलत है।
- (२) उपयोगिता में परिवर्तन व्यक्ति एवं परिस्थिति में परिवर्तन होने के साथ ही हो जाते हैं, अतः परिवर्तनशील तत्त्व को मापना कठिन है।
- (३) उपयोगिता को मापने के लिये कोई निश्चित तथा स्थिर पैमाना नहीं है।

इस प्रकार हिक्स आदि अर्थशास्त्री न तो उपयोगिता को मापना संभव मानते हैं और न आवश्यक। आधुनिक अर्थशास्त्री गणनावाचक दृष्टिकोण के स्थान पर क्रमवाचक दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान करते हैं।

उपयोगिता के रूप (Forms of Utility) -

उपयोगिता को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है —

- (१) सीमान्त उपयोगिता (Marginal utility), तथा
- (२) कुल उपयोगिता (Total utility)।

सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility)

जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वह वस्तु की पहली, दूसरी, तीसरी इकाई का उपभोग करता जाता है। उपभोग की जाने वाली अन्तिम इकाई को सीमान्त इकाई (marginal unit) कहते हैं, तथा इस इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमान्त उपयोगिता कहते हैं। परन्तु इस प्रकार की परिभाषा अधिक उपयुक्त नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार—

“उपभोग की जाने वाली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि होने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, उसे सीमान्त उपयोगिता कहते हैं।

यह उपयोगिता हमेशा वस्तु की अन्तिम इकाई से प्राप्त होती है। प्रो. बोल्डिंग के शब्दों में—“वस्तु की किसी मात्रा की सीमान्त उपयोगिता कुल उपयोगिता में वृद्धि है जो कि उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के परिणामस्वरूप होती है।”⁴

3 विस्तृत अध्ययन के लिये 'तटस्थता वक्र विश्लेषण' (Indifference Curve Analysis) अध्याय देखिये।

4 'The marginal utility of any quantity of a commodity is the increase in total utility which results from a unit increase in consumption'

सीमान्त उपयोगिता को निम्न उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है

सन्तरो की संख्या	सीमान्त उपयोगिता	कुल उपयोगिता
१	१०	१०
२	८	१८
३	६	२४
४	४	२८
५	२	३०
६	०	३०—पूर्ण तृप्ति का बिन्दु
७	-२	२८

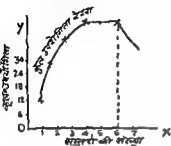
उपर्युक्त उदाहरण में सीमान्त उपयोगिता के तीन रूप बताये गये हैं—(अ) धनात्मक (positive), (ब) शून्य zero) और (स) ऋणात्मक (negative)। जब उपभोक्ता सन्तरे की ५ इकाइयों तक उपभोग करता है तो उसे कुछ सन्तुष्टि प्राप्त होती है, यह धनात्मक उपयोगिता है। जब ६वीं इकाई का उपभोग करता है तो उसे कोई सन्तुष्टि प्राप्त नहीं होती अर्थात् सीमान्त उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसके बाद भी ७वीं इकाई का उपभोग करता है तब अनुपयोगिता प्राप्त होती है, अर्थात् ऋणात्मक उपयोगिता मिलने लगती है। शून्य उपयोगिता की अवस्था को अवशान्त में पूर्ण तृप्ति की अवस्था (Point of Satety) कहते हैं। इस स्थिति को चित्र में स्पष्ट किया गया है।



कुल उपयोगिता (Total Utility) :

किसी व्यक्ति को वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता है। जैसे-जैसे किसी वस्तु की इकाइयों के उपभोग में वृद्धि करते जाते हैं, वैसे वैसे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। जब सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि रुक जाती है।

मेयर्स (Meyers) के अनुसार—“किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणामस्वरूप प्राप्त सीमान्त उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता है।”



बढ़ने के स्थान पर घट जाती है।

कुल उपयोगिता की इस अवस्था को रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया गया है।

सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में सम्बन्ध

(Relationship between Marginal Utility and Total Utility)

किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता गणितीय रूप से सम्बन्धित है। सन्तरो के उदाहरण में यह सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। इनकी प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं :—

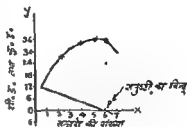
- (१) वस्तु के उपभोग की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है, तथा कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। कुल उपयोगिता में यह वृद्धि घटती हुई अनुपात में होती है।
- (२) जब सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता की वृद्धि रुक जाती है। उस समय कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इसी बिन्दु को अधिकतम सन्तुष्टि का बिन्दु कहते हैं।
- (३) शून्य उपयोगिता के बाद भी यदि उपभोग का क्रम जारी रखा जाता है तो सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कुल उपयोगिता घटन लगती है।

5 "Total utility = the sum of the marginal utilities, associated with the consumption of the successive units"

—A. L. Meyers

रेखाचित्र के माध्यम से भी सीमान्त उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के सम्बन्ध को स्पष्ट किया जा सकता है।

उपयुक्त चित्र में पहली इकाई से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता समान है। इसके बाद ५वीं इकाई तक सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है, तथा कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। ६वीं इकाई पर सीमान्त उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ७वीं इकाई के उपभोग के सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता गिर जाती है।



सीमान्त के विचार का महत्व

(Importance of the Concept of Margin)

सीमान्त के विचार या सीमान्त विश्लेषण (marginal analysis) का आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। सीमान्त विश्लेषण के इसी महत्व के कारण प्रो० मेहता ने कहा है—

“यह कहा जा सकता है कि लगभग सम्पूर्ण आर्थिक ठाढ़ा सीमान्त उपयोगिता विचार पर आधारित है।”^६

इस विचार का महत्व निम्नांकित विवरण से स्पष्ट हो जाता है —

- (१) उपभोग—उपभोग के क्षेत्र में यह विश्लेषण सभी प्रमुख सिद्धान्तों का आधार है। समसीमान्त उपयोगिता नियम, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम आदि सीमान्त विश्लेषण पर ही आधारित है।
- (२) उत्पादन—उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह उत्पादन के विभिन्न साधनों—भूमि, श्रम, पूँजी, व्यवस्था को इस प्रकार प्रयोग में लाना है जिससे कि समस्त साधनों से प्राप्त सीमान्त उत्पादन एकत्रित हो जाय। इसी स्थिति में उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। अतः सीमान्त विश्लेषण का महत्व उत्पादन के क्षेत्र में भी है।

6 “It can be said that almost the entire economic structure is based on the conception of marginal utility”

(३) विनिमय (Exchange)—विनिमय अर्थात् मूल्य-निर्धारण के क्षेत्र में सीमान्त विदलेपन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जब वस्तु को ख़य करता है तो वह उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता को ध्यान में रखता है। वह वस्तु का मूल्य सीमान्त उपयोगिता से अधिक देने को नैयार नहीं होता। अतः सीमान्त उपयोगिता ख़य की सीमा निर्धारित कर देती है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का यह दृष्टिकोण है कि वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है, न कि सीमान्त उपयोगिता द्वारा। इस सम्बन्ध में जे. के. मेहता का ख़य उल्लेखनीय है, उन्हीं के शब्दों में—

“उत्पादन व्यय स्वयं उत्पत्ति के साधनों की सीमान्त उपयोगिताओं द्वारा निर्धारित होता है।”^७

मूल्य निर्धारण की सन्तुलन (equilibrium) की अवस्था में सीमान्त उपयोगिता तथा उत्पादन व्यय (सीमान्त लागत) बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में, सीमान्त उपयोगिता तथा सीमान्त लागत दोनों मूल्य निर्धारित करती हैं।

(४) वितरण—प्रत्येक उत्पत्ति के साधन को हिस्सा या पुरस्कार उस साधन की सीमान्त उत्पादकता (marginal productivity) के बराबर दिया जाता है। अतः साधनों का पुरस्कार निर्धारित करने में भी सीमान्त विदलेपन महत्वपूर्ण है।

(५) राजस्व (Public finance)—सरकार का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सीमान्त उपयोगिता का सहारा लेती है। आय प्राप्त करने तथा व्यय करने, दोनों ही स्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों के सीमान्त ख़ाग तथा सीमान्त उपयोगिता को ध्यान में रखती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सीमान्त विदलेपन का प्रयोग अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में होता है तथा यह अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

सीमांत विश्लेषण की मान्यताएँ (Assumptions of Marginal Analysis)

अर्थशास्त्र के अन्य नियमों के समान यह विश्लेषण भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है। ये मान्यताएँ निम्न प्रकार हैं—

7 “ the cost of production itself is determined by marginal utilities of the factors of production ”
—J K Mehta

- (१) वस्तु की सभी इकाइया एकसु (homogeneous) होती है ।
- (२) मूल्य में परिवर्तन होने से वस्तु की माग तथा पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाते हैं ।
- (३) उपभोक्ता सदैव विवेकपूर्ण (rational) तरीके से कार्य करता है ।
- (४) मनुष्य के पास व्यय करने के लिये निश्चित आय होती है ।
- (५) बाजार में बहुत से क्रोता और विक्रेता होते हैं, लेकिन विपाराधीन व्यक्ति विशेष ही होता है ।

सीमान्त विश्लेषण की उपर्युक्त मान्यताओं में से अधिकांश मान्यतायें वास्तविक तथा तथ्यहीन हैं, अतः वास्तविकता से इनका सम्बन्ध नहीं होता ।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. उपयोगिता से क्या अभिप्राय है ? इसकी माप किस प्रकार की जाती है ।
२. क्या उपयोगिता मापनीय विचार है ? अतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाये गये माप के तरीकों के विरुद्ध आपत्ति क्यों उठायी जाती है ?
३. सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता के विचार की व्याख्या कीजिए । इन दोनों के बीच के सम्बन्ध की व्याख्या कीजिए ।
४. यह सिद्ध कीजिए कि जब एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है तो उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है ।
५. मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण सम्बन्धी विचार की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।

अध्याय ३

★

तटस्थता-वक्र विश्लेषण

[Indifference-Curve Analysis]

★ ★ ★

माशल एवं उससे पूर्व के सभी अर्थशास्त्रियों की यह धारणा थी कि उपयोगिता को माप इस या सभी मापदण्ड के द्वारा करना समभव है। सर्वप्रथम अर्थशास्त्री पेरैटो (Pareto) ने १९०६ में यह बताया कि उपयोगिता की ठीक-ठीक माप करना समभव नहीं है। पेरैटो ने बताया कि उपयोगिता तुलनात्मक तथा सापेक्षिक होती है, न कि निरपेक्ष। किसी वस्तु के उपभोग से वास्तविक उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई है इसका ज्ञान केवल उपभोक्ता को ही होता है। अतः उन्होंने माशल के उपयोगिता विश्लेषण (utility analysis) को अस्वीकार कर प्राथमिकता क्रम (scale of preference) के विचार का प्रयोग प्रारम्भ किया।

उपयोगिता विश्लेषण का विचार संख्यात्मक (cardinal) है जबकि 'प्राथमिकता चक्र' (preference approach or scale of preference) का विचार क्रमवाचक (ordinal) है। इसमें उपयोगिता को मापन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं को कम करते समय अपने 'प्राथमिकता क्रम' को ध्यान में रखता है अर्थात् महत्व के अनुसार वस्तुओं को क्रय करता है। प्रत्येक क्रम को क्रमवाचक मन्थार्य प्रदान की जाती है और प्रत्येक क्रम सन्तुष्टि के स्तर को स्पष्ट करता है।

तटस्थता वक्रों की पृष्ठभूमि (The Background of Indifference Curve)

सर्वप्रथम एजवर्थ (Edgeworth) ने १८८१ में तटस्थता वक्र रेखाओं का प्रयोग किया। तत्पश्चात् इटलियन अर्थशास्त्री पेरैटो (Pareto) ने १९०६ में यह स्पष्ट किया कि उपयोगिता को मापना समभव नहीं है अतः उन्होंने उपयोगिता के विचार के स्थान पर प्राथमिकता क्रम (scale of preference) को महत्व दिया।

पेरैटो के इस विचार में १९१३ में जॉनसन (Johnson) ने तथा १९१५ में स्लुट्स्की (Slutsky) ने कुछ सुधार किये। तत्पश्चात् ऐलन (Allen) तथा हिक्स (Hicks)

ने इस विचार की विस्तृत तथा स्पष्ट व्याख्या की । विकस्टीड (Wickstead), वीजर (Wieser) तथा चैम्बरलीन (Chamberlin) ने भी भाग विश्लेषण के लिये तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया है । इस प्रकार मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता वक्र रेखाओं का प्रयोग सगातार बढ़ता जा रहा है ।

तटस्थता वक्र की परिभाषा (Definition of Indifference Curve)

तटस्थता वक्र वह रेखा है जिस पर स्थित प्रत्येक बिन्दु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है, जिससे किसी उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि प्राप्त होती है । अर्थात् तटस्थता वक्र पर अनित्य प्रत्येक बिन्दु उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि प्रदान करने वाले संयोगों को प्रदर्शित करता है । सभी संयोगों से समान सन्तुष्टि प्राप्त होने के कारण ही उपभोक्ता संयोगों के क्रमांक में रुचि नहीं दिखाता, अर्थात् तटस्थ रहता है । संयोगों के क्रमांक में तटस्थता के कारण ही इसे तटस्थता वक्र कहते हैं । तटस्थता वक्र की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषायें निम्न प्रकार हैं —

जे ■ ईस्टहम (J K Eastham) के शब्दों में—“यह मानाओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिन्दुओं का मार्ग होता है जिनमें व्यक्ति तटस्थ होता है इसी कारण इसे तटस्थता वक्र कहते हैं ।”^१

स्टिग्लर (Stigler) के अनुसार—“यदि वस्तुयें विभाजित की जा सकती हैं तो हम X और Y वस्तुओं के ऐसे संयोग बना सकते हैं जो सन्तुष्टि की दृष्टि से समान हों । यदि ऐसे समान संयोगों को ग्राफ पर प्रदर्शित कर एक-दूसरे से मिला दें तो एक वक्र रेखा I₀ बन जाती है । I₀ वक्र रेखा को तटस्थता वक्र रेखा कहते हैं । क्योंकि इस रेखा पर प्रदर्शित X और Y वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से वह चुनाव करने में तटस्थ रहता है ।”^२

1 It is the laws of points representing pairs of quantities between which individual is indifferent, so it is termed as indifference curve”
—J. K. Eastham

2 “If the commodities are divisible, we can construct an infinite number of combinations of X and Y which are equivalent. If we plot on co ordinate paper all the combinations which are equivalent, we construct a continuous curve I₀, the curve I₀ is called indifference curve because the consumer is indifferent as to which of the combinations of X and Y an I₀ he possesses”
—Stigler

के ई बोलिडिय के मतानुसार—“समान प्राथमिकतायें (preference) प्रदर्शित करने वाली रेषायें तटस्थता वक्र रेषायें कहलाती हैं, क्योंकि वे ऐसी मात्राओं के संयोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि एक-दूसरे से न अच्छे हैं और न बुरे, बल्कि तटस्थ हैं।”³

तटस्थता वक्र सामान्यतः X और Y अक्षाओं के मध्य में खींचे जाते हैं, इनमें एक अक्ष पर एक वस्तु और दूसरे अक्ष पर दूसरी वस्तु को मापा जाता है। जिन वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं वे भौतिक वस्तुयें, सेवाएँ अथवा मुद्रा हो सकती हैं, जिनके बीच विनिमय संभव होता है।

तटस्थता वक्र सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण बातें (Some important points related to Indifference Curve) —

तटस्थता वक्रों का निर्माण करते समय कुछ बातें आवश्यक हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

- (१) तटस्थता तालिका (Indifference Schedule) — तटस्थता वक्र के निर्माण से पूर्व तटस्थता तालिका तैयार की जानी चाहिए। तटस्थता तालिका दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करती है, जिनमें प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि प्राप्त होती है। इन विभिन्न संयोगों में उपभोक्ता अपने को प्राथमिकता (preference) प्रदान करने में असमर्थ होता है। प्रो मेयर्स (Meyers) का शब्दों में—“तटस्थता तालिका वह तालिका है जो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बताती है जिनसे कि किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त होता है।”⁴

तटस्थता तालिका को उदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

तटस्थता तालिका

मसाला संख्या	काफी की संख्या	सिगरेट की संख्या	प्राप्त उपयोगिता
१	२ कप	१५	} समान उपयोगिता
२	३ "	१०	
३	४ "	६	
४	५ "	३	
५	६ "	१	

- 3 “lines of equal preference are called indifference curves because they represent combinations of quantities which are neither better nor worse than each other but are indifferent”

—K E Boulding

- 4 “An indifference schedule may be defined as a schedule of various combinations of goods that will be equally satisfactory to the individual concerned”

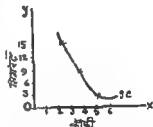
—A L Meyers

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता को २ कप कॉफी और १५ सिगरेट (पहला संयोग) से जितनी उपयोगिता प्राप्त होती है उतनी ही उपयोगिता ६ कप कॉफी और १ सिगरेट (पाचवा संयोग) से प्राप्त होती है, अर्थात् प्रत्येक संयोग समान उपयोगिता प्रदान करता है। इसीलिए उपभोक्ता विभिन्न संयोगों के चुनाव के विषय में मिल्कुल तटस्थ रहता है।

(२) तटस्थता वक्र (Indifference Curve) — उपभोक्ता को इस तटस्थता को एक तटस्थता वक्र के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। सिगरेट और कॉफी के विभिन्न संयोगों के बिन्दुओं को यदि मिला दिया जाय तो यह वक्र (curve) बन जाता है। यह वक्र तटस्थता वक्र कहलाता है। मेयर्स के शब्दों में—“यदि इसे (तटस्थता तालिका) एक रेखा के रूप में दिखाया जाय तब हमें तटस्थता वक्र प्राप्त होता है।”^५

तटस्थता वक्र पर अंकित प्रत्येक बिन्दु समान सन्तुष्टि प्रदान करता है। अतः उपभोक्ता इन विभिन्न संयोगों के मध्य तटस्थ रहता है, इसीलिये तटस्थता वक्रों को ‘समान उपयोगिता वक्र (Iso-utility curve) भी कहते हैं।

उपयुक्त चित्र में I_c तटस्थता वक्र है। यह वक्र कॉफी और सिगरेट के विभिन्न संयोगों के बिन्दुओं को मिलाकर बना है। इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिन्दु कॉफी और सिगरेट के संयोग को प्रदर्शित करता है।

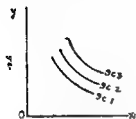


तटस्थता मानचित्र (Indifference Map)

उपयुक्त तटस्थता तालिका तथा तटस्थता वक्र में कॉफी और सिगरेट के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित किया गया है जिनके चुनाव करने में उपभोक्ता तटस्थ रहता है। परन्तु कॉफी और सिगरेट के ऐसे संयोग भी बनाये जा सकते हैं, जिससे उपभोक्ता को भिन्न-भिन्न उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। भिन्न-भिन्न उपयोगिता प्रदान करने वाले भिन्न-भिन्न संयोगों को एक ही रेखा के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, बल्कि इन संयोगों को अलग-अलग

5 “If we depict this (indifference schedule) in the form of a curve, we get an indifference curve” —A. L. Meyers

रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न संयोगों के लिए अलग-अलग रेखाओं का निर्माण करना होगा। इस प्रकार एक ही रेखा चित्र द्वारा, अनेक तटस्थता वक्रों का, जो कि उपभोक्ता के लिये विभिन्न सतुष्टि के स्तर को बताते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, तटस्थता मानचित्र कहलाता है।



प्रो० मेयर्स (Meyers) शब्दों में तटस्थता

वक्रों के परिवार को तटस्थता मानचित्र कहते हैं।

उपयुक्त रेखा चित्र में Ic_1 , Ic_2 , Ic_3 रेखाएँ उपभोक्ता के लिए विभिन्न सतुष्टि के स्तरों को प्रदर्शित करती हैं। प्रत्येक रेखा दो वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करती है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि मूल बिन्दु (point of origin) से जितनी तटस्थता रेखा दूर होगी, उतनी ही अधिक सतुष्टि (उपभोक्ता के लिये) वह प्रदर्शित करेगी। जैसा-जैसे रेखा मूल बिन्दु (बायीं ओर) की ओर खिसकती जायेगी, वैसे-वैसे कम सतुष्टि को बना दगी।

तटस्थता मानचित्र की तुलना परिधि रेखाओं (contour lines) से करते हुए स्टोनियर और हैग (Stonier and Hague) ने लिखा है—

तटस्थता रेखाएँ मानचित्र की परिधि रेखाओं के समान हैं जो कि समुद्रतल से समान ऊँचाई के स्थानों को प्रदर्शित करती हैं। स्थानों की ऊँचाई का निरूपण करने के स्थान पर तटस्थता रेखा सतुष्टि के एक स्तर को ही प्रदर्शित करती हैं। सतुष्टि की मात्रा की माप उस विधि से करना सम्भव नहीं जिससे समुद्रतल की ऊँचाई मापी जाती है।”

तटस्थता वक्रों की मान्यताएँ (Assumptions of Indifference Curves)—

तटस्थता वक्रों की प्रमुख मान्यताएँ निम्नलिखित हैं

- (१) उपभोक्ता एक वस्तु की कम मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा को पसन्द करता है।
- (२) उपभोक्ता का व्यवहार 'विवेकपूर्ण' होता है।
- (३) उपयोगिता यह जानकारी रख सकती है कि एक संयोग से प्राप्त उपयोगिता दूसरे संयोग में प्राप्त उपयोगिता से कम है या अधिक है।

6 “We may have a family of such curves or as we may call it an indifference map”

—A L Meyers

(४) वस्तुयें एक रूप (homogeneous) तथा विभाज्यनीय (divisible) होती ह ।
तटस्थता वक्रों की विशेषतायें (Characteristics of Indifference Curves)

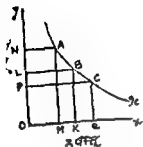
तटस्थता वक्र की विशेषताओं को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न रूपों में अभि-
प्रकृत किया है लेफ्टविच (Leftwich) ने तटस्थता वक्रों की तीन मूलभूत विशेषतायें
प्रस्तुत की हैं—

- I. ये वक्र नीचे, दांयी तरफ झुकते हैं,
- II. तटस्थता वक्र मूल बिन्दु के उन्नतोदर (convex) होने हैं,
- III. तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं ।

रिचार्ड बिलस (Richard Bilas) तथा बोनमल (Banmal) आदि अर्थशास्त्रियों ने
भी तटस्थता वक्रों की विशेषताओं का उल्लेख किया है । इनकी प्रमुख विशेषतायें—
निम्नलिखित हैं—

1925

- (1) तटस्थता वक्र पर सभी बिन्दु समान उपयोगिता (संतुष्टि) प्रदान करने वाले वस्तुओं
के संयोगों को प्रदर्शित करते हैं—तटस्थता वक्र के सभी बिन्दु उपभोक्ता को समान
करते हैं उपभोक्ता उन सभी संयोगों के प्रति तटस्थ रहता है ।
- (2) तटस्थता वक्र धायें से धायें नीचे की ओर झुकते हैं—इसका कारण यह है कि जब
एक उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग को इवाईया बढ़ा देता है तब यह दूसरी
वस्तु के उपभोग की इवाईयों में कमी कर देता है । इस प्रकार एक वस्तु के स्थान
पर दूसरी वस्तु प्रतिस्थापित होती है । इस कारण रेखा बाय से धायें नीचे की ओर
झुकती है अर्थात् रेखा का ढाल ऋणात्मक (negative) होता है ।
- (3) तटस्थता वक्र मूल बिन्दु की ओर उन्नतोदर होते हैं—एक तटस्थता वक्र जैसे-जैसे
नीचे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उपभोग की गई एक वस्तु की मात्रा में कमी होती
है और दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है । इसे चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते
हैं । चित्र में X वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है अर्थात् X वस्तु की सीमान्त
उपयोगिता घटती जाती है और Y वस्तु की मात्रा घटती जाती है अर्थात् Y वस्तु
की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है । Y वस्तु की मात्रा में जो कमी आती है
उसकी पूर्ति X वस्तु की मात्रा में वृद्धि से की जाती है । इस प्रकार रेखा का
उन्नतोदर आकार प्राप्त होता है जो कि घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर
(diminishing marginal rate of substitution) का बताता है । तटस्थता
वक्र की इस विशेषता के सम्बन्ध में स्टॉनियर और हेग (Stonier and Hague) ने
लिखा है—



“ज्यों-ज्यों हम तटस्थता वक्र पर चलते जाते हैं तो अपनी भ्रान्तता के अनुसार वह मूल बिन्दु के ऊपरतोर तथा ऊपर की ओर ढाल (steep) तथा दाहिनी ओर षोडा होता है। यह इस तथ्य को बताता है कि खो-खो किसी वस्तु का अधिक उपभोग किया जाता है इस वस्तु की दूसरी वस्तु की अपेक्षा सीमान्त उप-योगिता घटती जाती है।”

- (४) तटस्थता रेखाएँ एक दूसरे की काटती नहीं हैं—विभिन्न तटस्थता रेखाओं द्वारा



दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए दो तटस्थता रेखाएँ न तो कभी एक दूसरे की स्पर्श करेंगी और न ही एक-दूसरे की काटेंगी। यदि एक रेखा दूसरी रेखा को किसी बिन्दु पर काटती है तो उस बिन्दु पर दोनों तटस्थता रेखाएँ समान सन्तुष्टि को प्रदर्शित

करेंगी। परन्तु यह समभव नहीं है, क्योंकि दो रेखाएँ सन्तुष्टि के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करती हैं।

- (५) तटस्थता रेखाओं का एक दूसरे के समानान्तर होना आवश्यक नहीं है—दो तटस्थता रेखाओं का एक दूसरे के समानान्तर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि (अ) सभी तटस्थता तालिकाओं (indifference curve schedules), में दो वस्तुओं के बीच समान प्रतिस्थापन दर (equal rate of substitution) का होना आवश्यक नहीं है। (ब) तटस्थता वक्र गणनात्मक संख्या (cardinal number) पर आधारित नहीं होते।

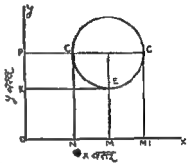
- (६) प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक से अधिक तटस्थता वक्र हो सकते हैं—प्रत्येक उपभोक्ता के लिये कोई एक तटस्थता रेखा नहीं होती, अपितु वस्तुओं के विभिन्न

7 "As One moves along an indifference curve, the assumption that it is convex to the origin, that it gets flatter to the right and steeper upwards, implies that the marginal significance of the one good in terms of the other will always diminish progressively as one acquires more of the former good" —Stoner and Hague

संयोगों के लिये इन रेखाओं को एक शृंखला होनी है उपभोक्ता किसी एक रेखा पर संतुलन की स्थिति में रहता है।

(७) तटस्थता रेखाएँ गोलाकार (circular shape) भी हो सकती हैं—तटस्थता रेखा

का गोलाकार रूप उसी स्थिति में संभव है जबकि किसी वस्तु के अधिक मात्रा में प्रयोग से ऋणात्मक उपयोगिता (negative utility) प्राप्त होने लगती है। सामान्यतः पूर्ण संतुष्टि के बिन्दु के पश्चात् यदि उपभोक्ता वस्तु का उपयोग करता है तो ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को दूसरी वस्तु के उपयोग की मात्रा को घटाने के स्थान पर बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि पहली वस्तु से प्राप्त अनुपयोगिता की पूर्ति दूसरी वस्तु की उपयोगिता से करली जाय। इस प्रकार तटस्थता वक्र का रूप गोलाकार हो जाता है। हम चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।



उपर्युक्त चित्र में X वस्तु की OM मात्रा तथा Y OP मात्रा का बिना किसी ऋणात्मक उपयोगिता के उपयोग किया जा सकता है। यदि X वस्तु की OM मात्रा में वृद्धि की जाय तो ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती, जिसकी क्षतिपूर्ति करने के लिये Y वस्तु की मात्रा OK में वृद्धि करनी होगी। यदि उपभोक्ता Y वस्तु की OP मात्रा से अधिक उपयोग करता है तो उसे X वस्तु की OM मात्रा में वृद्धि करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में तटस्थता वक्र का रूप गोलाकार हो जाता है।

(८) तटस्थता रेखा की ऊँची रेखा नीची रेखा से अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करती है—तटस्थता रेखा जो मूल बिन्दु से अधिक दूर होती है वह मूल बिन्दु के पास वाली रेखा की अपेक्षा अधिक संतुष्टि को बताती है।

सीमान्त प्रतिस्थापन दर अथवा प्रतिस्थापन की सीमांत दर (Marginal Rate of Substitution)

प्रो० हिक्स तथा एलन ने मुख्य सिद्धान्त में मार्शल की सीमान्त उपयोगिता के स्थान पर 'सीमान्त प्रतिस्थापन दर' शब्दों का प्रयोग किया। हिक्स के अनुसार सीमान्त प्रतिस्थापन दर एक निर्दिष्ट अर्थ रखती है।

सीमान्त प्रतिस्थापन दर एक विनिमय अनुपात है जो यह बताता है कि एक वस्तु को निश्चित मात्रा के बदले दूसरी वस्तु कितनी मात्रा में दी जायेगी। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता को सतुष्टि के उसी स्तर पर बनाये रखने के लिये एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को कितनी मात्रा दी जा सकती है।

प्रो० हिक्स के अनुसार—“Y के लिये X की प्रतिस्थापन दर Y की वह मात्रा है जो कि उपभोक्ता को X की सीमान्त इकाई की हानि की पूर्ति करती है।”^८

प्रो० बोल्डिंग ने प्रतिस्थापन दर के सम्बन्ध में लिखा है, “सीमान्त प्रतिस्थापन दर द्रव्य की वह मात्रा है जिससे कि उतनी ही सतुष्टि प्राप्त होती है जितनी कि उस वस्तु की एक इकाई से प्राप्त होती है।”^९

इस प्रकार यदि दो वस्तुओं के संयोग में यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ायी जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटायी जायेगी ताकि उपभोक्ता की सतुष्टि में न तो कमी हो और न ही वृद्धि, अर्थात् सतुष्टि का स्तर समान बना रहे।

सीमान्त प्रतिस्थापन दर की उदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—

संयोग	X वस्तु	Y वस्तु	Y के लिये X की प्रतिस्थापन दर
प्रथम	२	२०	
द्वितीय	३	१५	१५
तृतीय	४	११	१४
चतुर्थ	५	८	१३

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम संयोग में उपभोक्ता के पास X वस्तु की २ इकाइया तथा Y वस्तु का २० इकाइया हैं। द्वितीय संयोग में वह X वस्तु की एक इकाई के लिये Y वस्तु की ५ इकाइया छोड़ने को तैयार है। तृतीय संयोग में X वस्तु की एक इकाई के लिये Y वस्तु की ४ इकाइया तथा चतुर्थ संयोग में Y वस्तु की ३ इकाइया छोड़ने को तैयार है। इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे X वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है Y वस्तु की मात्रा घटती जाती है। X वस्तु की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि से Y वस्तु की प्रतिस्थापन दर घटती जाती है। इन सभी संयोगों से प्राप्त उपयोगिता समान है।

8 “We may define the Marginal Rate of Substitution of X for Y as the quantity of Y which would just compensate the Consumer for the loss of marginal unit of X” —Hicks

9 “The Marginal Rate of Substitution is that sum of many which will afford the same satisfaction as one unit of the commodity in question” —Prof Boulding

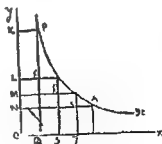
प्रो० मेयर्स (Meyers) के शब्दों में—'X की Y के लिए सीमान्त प्रतिस्थापन दर Y की वे इकाईयाँ हैं जिनके लिये X की एक इकाई स्थापना होती है ।'

अतः प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर उभोता दो वस्तुओं के संयोगो ॥ प्राप्त उपयोगिता को समान रखत हुए किसी वस्तु की एक छोटी मात्रा को किसी दूसरी वस्तु की छोटी मात्रा से प्रतिस्थापित करता है ।

घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत या सीमान्त प्रतिस्थापन दर ह्रास नियम (The Principle of Diminishing Marginal Rate of Substitution)

साधारणतया किसी दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन दर का क्रमशः ह्रास होत लगता है । किन्तु दो वस्तुओं के संयोग में यदि किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो संतुष्टि के स्तर को समान बनाय रखने के लिये दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी होती है । इसके साथ ही दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी का अनुपात घटता जाता है यदि पहली वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है । सीमांत प्रतिस्थापन दर की घालिका से यह स्पष्ट होता है । जैसे-जैसे X वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है Y वस्तु की मात्रा घटती जाती है तथा X वस्तु की इकाई का सीमान्त महत्व Y वस्तु के रूप में घटता जाता है, इसी को घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर का सिद्धान्त कहत हैं ।

प्रो० हिक्स के शब्दों में—'मान लिया कि हम वस्तुओं को एक दी हुई मात्रा से प्रारम्भ करते हैं और X की मात्रा ॥ वृद्धि और Y की मात्रा में कमी इस प्रकार में करते जाते हैं कि उपभोक्ता की स्थिति में तो पहले से अच्छी हो होती है और न बुरी हो । तब Y की मात्रा जो कि X की दूसरी इकाई को प्राप्त करने के लिये घटायी जाती है Y की उस मात्रा से कम होगी जो कि X की पहली इकाई को प्राप्त करने के लिये घटायी जाती है । दूसरे शब्दों में जितना अधिक X को Y



- 10 "The Marginal Rate of Substitution of X for Y will be the number of Y for which one unit of X is substituted"

—A. L. Meyers

के लिये प्रतिस्थापित किया जाता है उतनी ही X को Y के लिये सीमान्त प्रतिस्थापन दर घटती जाती है ।¹¹

प्रतिस्थापन दर के सिद्धान्त की व्याख्या उपरोक्त चित्र के माध्यम से भी की जा सकती है ।

उपर्युक्त चित्र में उपभोक्ता I C रेखा पर P बिन्दु से A बिन्दु पर आता है, तब वह X वस्तु की मात्रा बढ़ाता है और Y वस्तु की मात्रा घटाता है, अर्थात् वह Y के स्थान पर X वस्तु की प्रतिस्थापित करता है, जिससे कि उनके कुल सन्तुष्टि में कमी नही आये । जब उपभोक्ता X वस्तु की इकाई में वृद्धि करके O Q R का प्रयोग करता है तब उसे Y वस्तु की K L इकाई घटानी पड़ती है । यदि X वस्तु की एक और इकाई R S में वृद्धि करती है तो Y वस्तु की L M इकाइयों द्वारा प्रतिस्थापन करता है । इसी प्रकार X वस्तु की S T मात्रा में वृद्धि को Y वस्तु की M N मात्रा से प्रतिस्थापित करता है । इस प्रकार X की प्रत्येक वृद्धि को Y की घटती हुई मात्रा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है । इसका कारण यह है कि X वस्तु के उपयोग में वृद्धि करने पर सीमान्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है तथा X वस्तु की मात्रा में कमी करने पर उसकी सीमान्त उपयोगिता क्रमशः बढ़ती जाती है । इसका ही घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर कहते हैं ।

अपवाद (Exaption)

साधारणतया सीमान्त प्रतिस्थापन दर दो वस्तुओं के मध्य घटती जाती है, परन्तु इसमें कुछ अपवाद हैं—

- (१) यदि दो वस्तुयें एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हों तो उनमें प्रतिस्थापन दर स्थिर (constant) या समान होगी ।
- (२) यदि दो वस्तुयें एक-दूसरे की पूर्ण पूरक (perfectly complementary) हैं तो उनके बीच प्रतिस्थापन दर घटती हुई नही होगी । इस स्थिति में प्रतिस्थापन की दर को अनन्त (infinite) कहा जाता है ।

11 "Suppose we start with a given quantity of goods and then go on increasing the amount of X and diminishing that of Y in such away that the consumer is left neither better off nor worse off on balance, then the amount of Y which has to be subtracted in order to set off a second unit of X will be less than that which has to be subtracted in order to set off the first unit. In other words the more X is substituted for Y, the less will be the marginal rate of substitution of X for Y."

घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर तथा उपयोगिता ह्रास नियम (Principle of Diminishing Marginal Rate of Substitution and the Law of Diminishing Utility)

राबर्टसन तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार सीमान्त प्रतिस्थापन की घटती हुई दर का सिद्धान्त उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है तथा उसका परिवर्तित रूप है। इसके दो कारण हैं :—

- (१) एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापन सीमान्त उपयोगिता के आधार पर होना है।
- (२) सीमान्त उपयोगिता में समान ही प्रतिस्थापन दर भी क्रमशः घटती जाती है।

प्रो. हिक्स उपर्युक्त दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। उन्होंने इन दोनों में भ्रंतर बताया है —

- (१) सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम उपयोगिता के परिमाणात्मक मापन पर आधारित है, जबकि प्रतिस्थापन दर के नियम में उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं होती।
- (२) उपयोगिता ह्रास नियम द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता को स्थिर करता है जबकि प्रतिस्थापन नियम ऐसा नहीं मानता।
- (३) सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम में केवल एक ही वस्तु का अध्ययन किया जाता है तथा सम्बन्धित वस्तुओं (related goods) के प्रभाव पर ध्यान नहीं देता जबकि सीमान्त प्रतिस्थापन दर का सिद्धान्त दो सम्बद्ध वस्तुओं का अध्ययन करता है।

इस प्रकार हिक्स की घटती हुई प्रतिस्थापन दर का सिद्धान्त मरशल के सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम से श्रेष्ठ है।

सीमान्त प्रतिस्थापन दर का महत्व (Significance of the Marginal Rate of Substitution)

प्रतिस्थापन दर का सिद्धान्त अर्थशास्त्र के लगभग सभी क्षेत्रों में क्रियाशील होता है। गॉसिन (Gossen) का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है और वह प्रतिस्थापन के नियम का प्रयोग करके कम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तुओं के स्थान पर अधिकतम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करता है।

प्रतिस्थापन के नियम का प्रयोग व्यक्ति जाने या अनजाने में करता रहता है । प्रो रॉबिन्स (Prof Robbins) ने इसे 'अर्थशास्त्र का व्यापार' बताया है ।

प्रो मार्शल के शब्दों में—“आर्थिक सौज के लगभग सभी स्रोतों में प्रतिस्थापन का नियम क्रियाशील होता है ।”^{१२}

तटस्थता वक्रों के प्रयोग (Uses of Indifference Curves)

मार्शल को मांग सम्बन्धी व्याख्या की श्रुतियों को दूर करने के लिए हिक्स (Hicks) तथा ऐलन (Allen) ने तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया । आजकल इन सिद्धांतों का प्रयोग अधिक व्यापक रूप से किया जाता है । स्टिग्लर (Stigler) ने तटस्थता रेखाओं के प्रयोग के तीन श्रेणें बताये हैं—(अ) दो व्यक्तियों के मध्य विनिमय, (ब) करारोपण, (स) सूचक वक्रों की समस्या । इन रेखाओं के महत्वपूर्ण प्रयोगों की व्याख्या नीचे की जा रही है —

- (१) दो व्यक्तियों के मध्य विनिमय की सीमा के निर्धारण में—एजवर्थ (Edgeworth) पहला अर्थशास्त्री था जिसने तटस्थता वक्रों का प्रयोग दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली विनिमय की सीमा को प्रदर्शित करने के लिए किया । एजवर्थ का विचार था कि विनिमय की जाने वाली वस्तुओं के मध्य विनिमय दर का निर्धारण करना सम्भव नहीं है । केवल ऐसी सीमाएँ ही बतायी जा सकती हैं जिनके मध्य विनिमय किया जावेगा ।
- (२) करारोपण के क्षेत्र में—तटस्थता वक्रों की सहायता से यह ज्ञान किया जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के करों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है । सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्येक कर व्यक्ति की आय अथवा वस्तु के मूल्य को प्रभावित करता है, इन वक्रों से यह जाना जा सकता है कि करारोपण के प्रभाव हितकर हैं या अहितकर । इन करारोपण के क्षेत्र में इन रेखाओं का प्रयोग करारोपण की हानियों को मापने, कर की श्रेष्ठता को बताने तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करने के लिए किया जाता है ।
- (३) सूचक वक्रों की समस्या के सम्बन्ध में—तटस्थता वक्रों की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि समय अवधि में परिवर्तन होने से उपभोक्ता का जीवन स्तर ऊँचा उठा है, अथवा नीचा गिरा है । उपभोक्ता की आय या वस्तुओं की कीमत में

12 'The application of the Principle of Substitution extends over almost everyfield of economic enquiry' — Marshall

परिवर्तन होने से उपभोक्ता के जीवन स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ना है या प्रतिकूल । इन सब प्रभावों का अध्ययन तटस्थता रेखाओं द्वारा किया जाता है ।

(४) राशनिंग के क्षेत्र में—युद्ध काल में या आर्थिक संकट के समय में राशनिंग की व्यवस्था की जाती है । राशनिंग की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे कि न्यायोचित वितरण हो तथा उपभोक्ताओं का अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त हो सके । तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ताओं के रुचि-क्षेत्र से राशनिंग की समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं ।

(५) दो वस्तुओं में बीच प्राथमिकता क्रम (Scale of preference) का निर्धारण — बेनहम (Benham) के अनुसार तटस्थता वक्रों के द्वारा यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि एक उपभोक्ता प्राय और आराम, वर्तमान तथा भविष्य के उपयोग तरल सम्पत्ति (liquid assets) तथा आय देने वाली सम्पत्ति (income yielding assets) में से किसकी पसन्द करेगा । इन रेखाओं के द्वारा यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि मजदूरी में वृद्धि हो जाने से धनिक के कार्य और भवकाश की गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

(६) उपभोक्ता की वृत्त की माप—तटस्थता वक्रों द्वारा उपभोक्ता सम्बन्धी बातों का वर्णन अधिक स्पष्ट और उत्तम रीति से किया जा सकता है । इन रेखाओं द्वारा उपभोक्ता की वृत्त की माप आसानी से की जा सकती है ।

(७) उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग —जिस प्रकार उपभोग के क्षेत्र में समान उपयोगिता वाले वक्रों की सहायता से यह पता लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए उपभोग की वस्तुओं का प्राथमिकता का क्रम क्या है उसी प्रकार से उत्पादन के क्षेत्र में समान उत्पादन क्षमता वाले उत्पादन में साधनों के संयोगों का भी पता लगा सकते हैं । उत्पादन के क्षेत्र में तटस्थता वक्रों की सम-उत्पादक-वक्र (iso-product curves) कहते हैं ।

तटस्थता वक्र विश्लेषण का आलोचनात्मक अध्ययन

[A Critical Study of the Indifference Curve Analysis]

हिस तथा ऐसन ने तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के दोषों को दूर करने के लिये किया तथा अपने विचारों को अधिक वैज्ञानिक एवं निश्चित रूप प्रदान किया । प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि तटस्थता विश्लेषण

मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण से श्रेष्ठ है या नहीं। इनके लिये हमें इसके गुण व दोषों की विवेचना करनी होगी।

तटस्थता वक्र विश्लेषण की श्रेष्ठता तथा गुण (Superiority and Merits of the Indifference Curve Technique)

हिक्स तथा अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह विश्लेषण मार्शल के 'उपयोगिता विश्लेषण' से निम्नांकित आधार पर श्रेष्ठ है—

- (१) मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण मापन (quantitative measurement) पर आधारित है जो कि अस्पष्ट व अवास्तविक है। यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता अमापनीय है जो कि उचित है। इसके अनुसार हम दो सतों को माप नहीं सकते उनकी तुलना कर सकते हैं।
स्टोनियर एव हेग (Stonier and Hague) ने लिखा है—“सन्तुष्टि की मात्रा को मापना इतना कठिन होता है, जितना कि समुद्र धरातल के ऊपर ऊँचाई मापना।”
- (२) मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता स्थिर (constant) रहती है, जबकि तटस्थता विश्लेषण ऐसी मान्यता पर आधारित नहीं है।
- (३) तटस्थता विश्लेषण मापन पर पाते जाने प्रभाव—मूल्य प्रभाव (price effect), आय प्रभाव (income effect) और प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect) का अध्ययन करता है, जिससे उपयोगिता के अध्ययन में अधिक सुविधा प्राप्त हो जाती है। मार्शल ने इन 'प्रभावों' का अध्ययन नहीं किया है। इस प्रकार यह विश्लेषण मार्शल के विश्लेषण से श्रेष्ठ है।
- (४) तटस्थता विश्लेषण प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुओं (competitive goods) तथा पूरक वस्तुओं (complementary goods) का भी अध्ययन करता है, जबकि मार्शल केवल एक वस्तु को लेकर व्याख्या करता है।
- (५) प्रो हिक्स ने सीमान्त उपयोगिताओं के अनुपात को एक नया नाम 'प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (marginal rates of substitution)' दिया। यह विचार उपयोगिता के परिमाणात्मक मापन से स्वतन्त्र है।
- (६) तटस्थता विश्लेषण का प्रयोग उत्पादन के क्षेत्र में भी किया जाता है। इस प्रकार

प्रो हिवस ने तटस्थता विश्लेषण के रूप में सभी क्षेत्रों के लिये एक 'एकीकृत सिद्धांत' (unified theory) प्रस्तुत किया है।

उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की तुलना में तटस्थता विश्लेषण थोड़ा और अधिक स्पष्ट है।

तटस्थता वक्र विश्लेषण के दोष (Defects of Indifference Curve Technique)

यद्यपि तटस्थता विश्लेषण की स्पष्टता असद्विषय है फिर भी कुछ अदृशान्वितों द्वारा इसकी आलोचनाएँ की गई हैं। इनमें से कुछ आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) प्रो नाईट (Prof Knight) के अनुसार उपभोक्ता की यह इच्छा होती है कि वह वस्तु के उपयोग से प्राप्त सतोष की गणना विहित परिणाम में कर सके। वह दो वस्तुओं के स्थानापन्न के प्रभाव पर विशेष ध्यान नहीं देता। इसलिये मार्गक सिद्धान्त में इन बातों का ध्यान न रखकर गलती की गई है।

(२) तटस्थता विश्लेषण अनेक दृष्टान्तविक मान्यताओं पर आधारित है—

(अ) उपभोक्ता पूर्ण विवेकशील होता है।

(ब) उपभोक्ता को वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त उपयोगिता की जानकारी होती है।

(ग) वस्तु प्रमाणित (standardized) होती है।

(द) पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है।

उपर्युक्त सभी मान्यताएँ अथवावहारिक व असम्भव हैं क्योंकि न तो उपभोक्ता हमेशा ध्यय करते समय विवेक का प्रयोग करता है और न ही उसे विभिन्न संयोगों से प्राप्त उपयोगिता की पूर्ण जानकारी ही होती है। पूर्ण प्रतियोगिता व्यवहार में पायी नहीं जाना। वस्तु का पूर्ण प्रमाणित होना भी सम्भव नहीं है।

(३) तटस्थता विश्लेषण का प्रयोग केवल दो या तीन वस्तुओं के लिये ही किया जा सकता है। यदि वस्तुओं की संख्या अधिक हो जाती है तो इसका प्रयोग कठिन हो जाता है जबकि व्यवहार में उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं के बीच ही चयन नहीं करता।

(४) यह विश्लेषण गणितीय विधि पर आधारित है तथा चित्रों का सहारा काफी बड़ा मात्रा में लेना पड़ता है। अतः यह विश्लेषण काफी कठिन हो गया है।

(५) शम्पीटर (Schumpeter) के अनुसार इस विश्लेषण का प्रयोग अनुभव पर आधारित

अध्ययन और शोध पर नहीं कर सकते तथा वास्तविक तटस्थता रेखाओं का खींचना भी बहुत कठिन है ।

(६) प्रो हॉले (Prof Hawley) के अनुसार—उपभोक्ता का तटस्थता मानचित्र (indifference map) एक अल्पकालीन घटना है, जिसमें लगानार परिवर्तन होते रहते हैं ।

(७) प्रो राबर्टसन (Prof Robertson) के अनुसार—तटस्थता वक्र विश्लेषण एक नयी द्रोतन में पुरानी शराब मान है । इस विश्लेषण में परिमाणात्मक प्रणाली के स्थान पर गुणात्मक प्रणाली, 'सीमान्त उपयोगिता' के स्थान पर 'प्रतिस्थापन की सीमान्त दर', 'उपयोगिता' के स्थान पर 'पसन्दगी क्रम' (preference scale) तथा 'जमागत उपयोगिता ह्याम नियम' के स्थान पर 'घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर' का प्रयोग किया गया है । प्रो हिक्स इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है ।

निष्कर्ष (Conclusion)

उपरोक्त अध्ययन तथा राबर्टसन के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो जाना है कि यह विश्लेषण पूर्ण रूप से नया नहीं है तथा इसमें अनेक दोष भी हैं । फिर भी यह विश्लेषण मार्शल के उपयोगिता विप्लेव में अधिक श्रेष्ठ है तथा इसका आधार अधिक वैज्ञानिक है । तटस्थता विश्लेषण का प्रयोग अर्थशास्त्र में अधिकाधिक माना जा सकता है । एडवर्ड नेविन (Edward Navin) का कथन इसके महत्त्व को स्पष्ट करता है । उनके अनुसार—

“इसमें माननीय तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही उपभोक्ता द्वारा प्रदर्शित पसन्दगी का अध्ययन किया जाता है ।”^{१३}

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ तटस्थता वक्र से आप क्या समझते हैं ? तटस्थता वक्र की मान्यताओं तथा विरोधताओं को बताइये ।
- २ तटस्थता वक्र की परिभाषा दीजिए । आर्थिक विश्लेषण में तटस्थता वक्रों के महत्त्व को समझाइये ।

13 'Indifference analysis does not require to attach a quantitative magnitude to the satisfaction derived by consumer from commodities but simply accepts the preferences expressed in the market place'

३. तटस्पता रेखाये क्या है ? चित्र की सहायता से उनकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए ।
४. 'घटते हुए सीमान्त प्रतिस्थापन दर' (principle of Diminishing Marginal Rate of Substitution) के नियम की व्याख्या कीजिये ।
५. 'सीमान्त प्रतिस्थापन दर' से आप क्या समझते हैं ? क्या घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर उपयोगिता नियम का केवल रूपान्तरण है ।
६. घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर के नियम की व्याख्या कीजिए । क्या यह नियम सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम से श्रेष्ठ है ।

— — —

अध्याय ४

★

उपभोक्ता का सन्तुलन

[Consumer's Equilibrium]

★ ★ ★

सन्तुलन से अभिप्राय उस अवस्था से होता है जिसमें कि परिवर्तन का अभाव पाया जाता है अर्थात् अपरिवर्तनशील अथवा विधाम की अवस्था (position of rest) ही सन्तुलन की अवस्था है।

उपभोक्ता की आय निश्चित है और उसकी आवश्यकतायें असीमित हैं। उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी आय को इन विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार व्यय करने का होना है कि उस अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके। अर्थात् उस अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त होती है वही उपभोक्ता के सन्तुलन की अवस्था होती है। प्रारम्भ में मार्शल (Marshall) ने उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता के सन्तुलन की अवस्था का वर्णन किया। मार्शल के विक्षेपण के अनुसार उपभोक्ता 'सम सीमांत उपयोगिता नियम (Law of Equi marginal utility)' के आधार पर अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। परन्तु मार्शल के इस विक्षेपण को हिक्स (Hicks), ऐलन (Allen) आदि अर्थशास्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता मापनीय नहीं है। इन अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता के सन्तुलन, अर्थात् अधिकतम सन्तुष्टि की अवस्था का विक्षेपण तटस्थ वक्रों के माध्यम से किया है। इस विक्षेपण के अनुसार—

‘उपभोक्ता उस समय सन्तुलन की स्थिति में होता है जबकि उसकी कीमत रेखा (Price Line) उसकी तटस्थता रेखा को स्पर्श करती है।’

कीमत रेखा (Price Line)

कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती

१. नामत रेखा को बजट रेखा (Budget line), व्यय रेखा (outlay line) तथा उपभोग सम्भाव्यता रेखा (consumption possibility line) भी कहते हैं।

है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की वर्तमान कीमत के आधार पर क्रय कर सकता है।

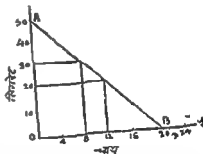
मान लिया कि किसी उपभोक्ता के पास ५) रुपये ह, वह इन ५) रुपये को चाय और सिगरेट पर व्यय करना चाहता है। यदि चाय की कीमत २५ पैसे प्रति ५प है और सिगरेट की कीमत १० पैसे प्रति सिगरेट। वह इन दोनों वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो। यदि वह समस्त राशि को एक ही वस्तु पर व्यय करता है तो उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि एक ही वस्तु का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता क्रमशः घटती जायेगी। अतः उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का उपभोग करना चाहेगा। यदि वह अपनी राशि ५) रुपये की दोनों वस्तुओं पर व्यय करना चाहना है तो उसे दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोग प्राप्त होंगे—

पहला संयोग— ४ ५प + ४० सिगरेट

दूसरा संयोग— ८ ५प + ३० सिगरेट

तीसरा संयोग— १२ ५प + २० सिगरेट

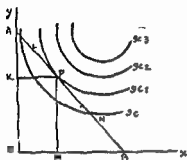
इससे अतिरिक्त भी अनेक संयोग हो सकते हैं जिन्हें उपभोक्ता ५) रुपये में क्रय कर सकता है। निम्नांकित चित्र में A B रेखा चाय और सिगरेट के विभिन्न संयोगों का प्रदर्शन करती है। A B रेखा की सीमान्त रेखा (price line) कहा जा सकता है। उपभोक्ता चाय और सिगरेट के केवल उन्हीं संयोगों को चुनेगा जो कि इस रेखा से व्यक्त होते हैं।



उपभोक्ता सन्तुलन की अवस्था को

कैसे प्राप्त करता है, अबवा उसे अधिकतम सन्तुष्टि कैसे प्राप्त होती है, इसके लिए हम तटस्थता मानचित्र (indifference map) और कीमत रेखा (price line) का प्रयोग करते हैं। उपभोक्ता के सामने विभिन्न संयोगों से बनी अनेक तटस्थ रेखाएँ हो सकती हैं जो कि सन्तुष्टि के विभिन्न स्तरों का व्यक्त करती हैं। उपभोक्ता इन विभिन्न तटस्थ रेखाओं में से किस रेखा का चयन करे, इसके निये कीमत रेखा की सहायता ली जाती है। उपभोक्ता उसी तटस्थता रेखा का चयन करता है, जो कि कीमत रेखा को स्पर्श करती है, क्योंकि सन्तुलन की अवस्था उसी स्थिति में प्राप्त होगी जबकि तटस्थता रेखा कीमत रेखा को स्पर्श करे। यदि उपभोक्ता अन्य किसी तटस्थता रेखा को चुनता है

तो उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त नहीं होगी। इस स्थिति को रेखाचित्र से स्पष्ट किया गया है।



इस चित्र में उपभोक्ता की दी हुई आय तथा दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों के आधार पर कीमत रेखा खींची है, तथा उपभोक्ता के लिए विभिन्न तटस्थता वक्रों को दर्शाया है। A B कीमत रेखा है जिस पर स्थित वस्तुओं के किसी भी संयोग को उपभोक्ता खर्च कर

इस बिन्दु में उपभोक्ता के लिए IC,

तथा IC₃ तटस्थता वक्र महत्व नहीं रखने क्योंकि उपभोक्ता के पास इतनी आय नहीं है कि वह उन वक्रों पर स्थित वस्तुओं के संयोगों को खर्च कर सके। इन दोनों रेखाओं में विभिन्न संयोग कीमत रेखा से बाहर है। IC तटस्थता रेखा कीमत रेखा को L और N बिन्दु पर स्पर्श करती है, परन्तु यहाँ भी उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हम रेखा पर विभिन्न संयोगों से प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि की मात्रा IC₁ पर स्थित P बिन्दु पर प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि की मात्रा से कम होगी। P बिन्दु पर स्थित चाय और सिगरेट का संयोग L और N बिन्दु की अपेक्षा उच्च स्तर पर स्थित है, अतः अधिक सन्तुष्टि प्रदान करेगा। P बिन्दु पर उपभोक्ता O M मात्रा चाय की तथा O K मात्रा सिगरेट को खर्च करता है। P बिन्दु पर उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि इसलिए प्राप्त होगी, क्योंकि वह IC₂ वक्र के उच्चतम स्तर पर स्थित है जहाँ पर वह अपनी निश्चित व्यय की राशि के द्वारा पहुँच सकता है। इस बिन्दु पर ही कीमत रेखा तथा तटस्थता रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती है।

उपभोक्ता को P बिन्दु पर ही अधिकतम सन्तुष्टि इसलिये प्राप्त होगी है क्योंकि P बिन्दु पर ही कीमत रेखा का ढाल तटस्थता रेखा IC₂ के ढाल के बराबर है। दूसरे शब्दों में, P बिन्दु पर दोनों वस्तुओं के बीच की प्रतिस्थापना दर (जो तटस्थता रेखा IC₂ के ढाल द्वारा व्यक्त होती है) तथा दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात (जो कीमत रेखा AB से व्यक्त होता है) समान है। अतः इसी बिन्दु पर उपभोक्ता सन्तुलन की अवस्था में होता है।

उपभोक्ता के स्थायी सन्तुलन के लिये यह भी आवश्यक है कि तटस्थता रेखा सन्तुलन बिन्दु पर मूल बिन्दु के उत्तरोत्तर (convex) हो, अर्थात् सन्तुलन बिन्दु पर एक

वस्तु (अर्थात् चाय) की दूसरी वस्तु (अर्थात् सिगरेट) के लिए प्रतिस्थापन दर घटती हुई हो। प्रो हिक्स (Hicks) के अनुसार सन्तुलन बिन्दु पर प्रतिस्थापन दर न तो बढ़ती हुई हो सकती है और न ही स्थित, चल्कि घटती हुई प्रतिस्थापन दर होती है।

उपयुक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उपभोक्ता सन्तुलन की अवस्था में निम्नलिखित स्थितियों में रह सकता है —

- (१) जिस बिन्दु पर कीमत रेखा तटस्थता रेखा को स्पर्श करती है।
- (२) जिस बिन्दु पर कीमत रेखा और तटस्थता रेखा का ढाल समान है।
- (३) जिस बिन्दु पर सीमान्त प्रतिस्थापन दर घटती हुई है।

उपभोक्ता सन्तुलन की मान्यतायें :

उपभोक्ता सन्तुलन का अध्ययन कुछ मान्यताओं पर आधारित है। ये मान्यतायें निम्नलिखित हैं—

- (१) उपभोक्ता के पास व्यय करने के लिये मुद्रा की मात्रा निश्चिन तथा सीमित होती है।
- (२) उपभोक्ता विवेक से कार्य करता है, अर्थात् वह अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए विकल्पों में से व्यय करता है।
- (३) उपभोक्ता को बाजार के मूल्यों का ज्ञान होता है।
- (४) सभी वस्तुएँ एकरूप (homogeneous) तथा विभाज्यनीय होती हैं।
- (५) उपभोक्ता को तटस्थता मानचित्र की आवश्यकता होती है।

उपभोक्ता सन्तुलन के परिवर्तनकारी तत्व (Various Factors effecting the Consumer's Equilibrium) :

अभी तक की उपभोक्ता के सन्तुलन की स्थिति में हम यह मानकर चले हैं कि उपभोक्ता की आय में तथा उसके द्वारा प्रयोज्य की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। परन्तु वास्तविकता यह है कि उपभोक्ता की आय और वस्तु के मूल्य दोनों ही बदलते रहते हैं। हम यहां पर यह अध्ययन करेंगे कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने या वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होने या दोनों में एक साथ परिवर्तन होने पर उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, हम उपभोक्ता के सन्तुलन को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता के सन्तुलन को प्रभावित करने वाले तीन तत्व प्रमुख हैं—

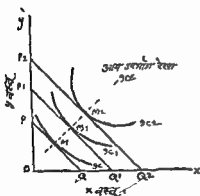
- (१) आय प्रभाव (Income effect),

(२) कीमत प्रभाव (Price effect) ।

(३) प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution effect) ।

यह एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आय प्रभाव, कीमत प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत रेखा पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, तटस्थता रेखाओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि तटस्थता रेखाओं का निर्माण करते समय उपभोक्ता की आय और वस्तुओं के मूल्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।

(१) आय प्रभाव (Income effect) — वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को आय प्रभाव कहते हैं। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य यदि स्थिर रहते हैं तो उसकी प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि की मात्रा उसकी आय पर निर्भर करती है। आय में कमी या वृद्धि होने से वह वस्तुओं की मांग कम या अधिक करेगा जिससे उसकी प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि की मात्रा पहले से कम या अधिक हो सकती है। साधारणतया उपभोक्ता की आय में होने वाली प्रत्येक वृद्धि उपभोक्ता का ऊँचे तटस्थता वक्र पर ले जाती है तथा आय में होने वाली प्रत्येक कमी नीचे तटस्थता वक्र की



और। दूसरे शब्दों में, (आय में वृद्धि से उसकी प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि की मात्रा बढ़ जाती है और आय की कमी में सन्तुष्टि की मात्रा घट जाती है)

इस प्रकार उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से कीमत रेखा बायी ओर विवर्तित (shift) हो जाती है तथा आय में कमी होने से कीमत रेखा बायी ओर विवर्तित होती है। वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहती हैं, इसलिए नयी कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समानान्तर रहती है।

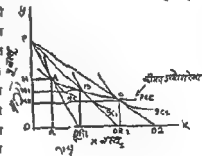
रेखा चित्र के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है ।

उपयुक्त चित्र में PQ कीमत रेखा है, जो तटस्थता रेखा को M बिन्दु पर स्पर्श करती है, इस प्रकार M सन्तुलन बिन्दु हुआ, अर्थात् उपभोक्ता इस बिन्दु पर सन्तुलन की अवस्था है। अब यदि उसकी आय में वृद्धि होती है जबकि X Y वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो नयी कीमत रेखा P_1Q_1 हो जाती है और उपभोक्ता नये सन्तुलन बिन्दु M_1 ,

पर पहुँच जाता है, उपभोक्ता के नये तटस्थता वक्र पर चले जाने के कारण उसकी सन्तुष्टि में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यह वक्र पूर्व के वक्र से दायाँ और उच्च बिन्दु पर स्थित है। महा पर उपभोक्ता पहले से अधिक मात्रा में X और Y वस्तु की मात्राये ग्रहण करेगा। यदि उसकी आय और अधिक बढ़ जाती है तो नयी कीमत रेखा $P_2 Q_2$ हो जाती है और उपभोक्ता नये सन्तुलन बिन्दु M_2 पर पहुँच जाता है। इस प्रकार वह पहले से अधिक मात्रा में X और Y वस्तु की मात्राये ग्रहण करेगा, जिससे उसको प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि की मात्रा पहले से अधिक होगी।

जैसे-जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे तटस्थता वक्र बायीं ओर ऊपर की ओर उठता चला जाता है, अर्थात् उसको प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि की मात्रा बढ़ती जाती है। वस्तु की कीमत स्थिर रहने की दशा में, उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले विभिन्न सन्तुलन बिन्दुओं (equilibrium points) को यदि जोड़ दिया जाय तो एक नयी रेखा प्राप्त होती है, जिसे आय उपभोग रेखा (income consumption curve) कहते हैं। आय उपभोग रेखा यह व्यक्त करती है कि यदि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे तो आय में परिवर्तन होने से उपभोग की मात्रा में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं।

(२) कीमत प्रभाव (price effect)—वस्तु की कीमत का उपभोक्ता की भाग पर पड़ने वाले प्रभाव को कीमत प्रभाव कहते हैं। “जब उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और उपभोक्ता द्वारा ग्रहण की जाने वाली दो वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है तथा दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे कीमत प्रभाव कहते हैं।” आय स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को पहले से अधिक या कम सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है। इस स्थिति को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।



उपरोक्त चित्र में प्रारम्भ में उपभोक्ता A बिन्दु पर सन्तुलन की अवस्था में है। इस बिन्दु पर कीमत रेखा $P_1 Q_1$ तटस्थता रेखा को A बिन्दु पर स्पर्श करती है। इस स्थिति में वह X वस्तु की $O R$ मात्रा और Y वस्तु की $O N$ मात्रा ग्रहण करता है। यदि मान लिया जाय कि X वस्तु की कीमत घट जाती है और Y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना (जबकि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है) तो उपभोक्ता X वस्तु को पहले से

अधिक मात्रा में ख़य कर सकता है। X वस्तु की कीमत घटने से पूर्व यदि उपभोक्ता अपनी समस्त आय को X वस्तु पर व्यय करता तो वह उसकी OQ^1 मात्रा ख़य कर सकता था, परन्तु कीमत में कमी आ जाने के कारण अब वह अपनी आय से OQ मात्रा ख़य कर सकता है। Y वस्तु की कीमत अप्रभावित रहने के कारण वह उस वस्तु की पूर्व की मात्रा OP का ख़य करता रहेगा। X वस्तु की कीमत में कमी आने का प्रभाव यह होगा कि कीमत रेखा PQ से PQ^1 हो जायेगी, अर्थात् कीमत-रेखा दायी ओर विवर्तित होगी। कीमत रेखा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नया सन्तुलन बिन्दु B स्थापित हुआ। इस बिन्दु पर उपभोक्ता X वस्तु की OR^1 मात्रा और Y वस्तु की ON^1 मात्रा का ख़य करता है। X वस्तु के मूल्य में और कमी आने के परिणामस्वरूप C सन्तुलन बिन्दु स्थापित होगा, जिस पर उपभोक्ता OR_2 मात्रा X वस्तु की और ON_2 मात्रा Y वस्तु का ख़य करता है। यदि इन सन्तुलन बिन्दुओं A, B, C को मिलाया जाय तो हमें कीमत-उपभोग रेखा (price consumption curve) प्राप्त होगी। यह रेखा वस्तुओं को उन विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करती है जिनको उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर ख़य करता है।

(३) प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect) वस्तु की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन का कारण वस्तु के उपयोग में परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। यदि दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि दोनों वस्तुओं के उपयोग मात्रा में परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता की स्थिति न तो पहले से अच्छी होती है और न ख़राब, तो उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। कीमतों में परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरूप उपभोक्ता उस वस्तु की मात्रा-अधिक उपभोग में लाता है जो कि सस्ती हो जाती है तथा उस वस्तु को कम जो कि महंगी हो जाती है। इस प्रकार वह अपेक्षाकृत महंगी वस्तु के स्थान पर अपेक्षाकृत सस्ती वस्तु का उपभोग अधिक करता है। इस प्रतिस्थापन से उसको प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात् समान सन्तुष्टि प्राप्त होती है उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि उसी अवस्था में प्राप्त होगी जबकि उपभोक्ता का तटस्थता वक्र अपरिवर्तित रहता है, यद्यपि वस्तु की मांग में परिवर्तन होने से सन्तुलन बिन्दु बदल जाता है।

स्टोनिगर तथा हेन ने प्रतिस्थापन प्रभाव के सम्बन्ध में लिखा है—“प्रतिस्थापन प्रभाव तब होता है जबकि वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन इस प्रकार का हो कि उपभोक्ता की दशा न पहले से अच्छी हो और न बुरी, लेकिन वस्तुओं के श्रेणियों

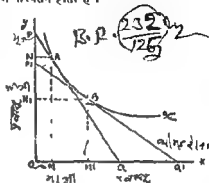
को सापेक्ष परिवर्तनों के वस्तु रूप पुनः प्रवर्णित re arrange करना पड़े ।²

प्रतिस्थापन प्रभाव को निम्नलिखित मान्यताएँ हैं—

(१) दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होता है ।

(२) एक वस्तु सापेक्षिक रूप से सस्ती तथा दूसरी सापेक्षिक रूप से महंगी हो जाती है, जिससे एक वस्तु के महंगे होने के प्रभाव दूसरी वस्तु के सस्ते होने के कारण समाप्त हो जाता है ।

(३) उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है ।



उपभोक्ता की कुल सन्तुष्टि में पूर्ण परिवर्तन नहीं होता प्रतिस्थापन प्रभाव को बिना द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है ।

उपर्युक्त चित्र में PQ कीमत रेखा है । यह रेखा तटस्थता रेखा को A बिन्दु पर स्पर्श करती है, अतः A सन्तुलन बिन्दु है । इस स्थिति में उपभोक्ता X वस्तु की OM मात्रा तथा Y वस्तु की ON मात्रा खरीद करता है । यदि यहाँ यह मान लें कि X वस्तु की कीमत गिर जाती है और Y वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दोनों वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि Y वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के प्रभाव को X वस्तु की कीमत में होने वाली कमी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है । दूसरे शब्दों में, X वस्तु के रूप में होने वाली उपभोक्ता की आय में वृद्धि इस प्रकार होती है कि Y वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उपभोक्ता को होने वाली क्षति को पूरा कर देती है । इस प्रकार उपभोक्ता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात् तटस्थता वक्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होता । लेकिन कीमतों में परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरूप उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं

2 "A Substitution effect occurs when the relative prices of goods change in such a way that the consumer is neither better or worse off than he was before, but has to rearrange his purchases in accordance with the new relative prices"

की मात्राओं में परिवर्तन हो जाता है। उपर्युक्त चित्र में कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता का नया सन्तुलन बिन्दु B हो जाता है। कीमत में परिवर्तन के कारण नयी कीमत रेखा भी बनती है जो कि P_1, Q_1 है। इस स्थिति में उपभोक्ता X वस्तु को OM^1 मात्रा और Y वस्तु को ON^1 मात्रा क्रय करता है, अर्थात् X वस्तु को पहले से अधिक और Y वस्तु को पहले से कम मात्रा में क्रय करता है। यद्यपि उपभोग की जान वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है, परन्तु इस परिवर्तन से उपभोक्ता की स्थिति न तो पहले से अच्छी होती है और न ही खराब, क्योंकि उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र पर रहता है। इस प्रकार उपभोक्ता का सन्तुलन बिन्दु A से हटकर B हो जाता है, यह परिवर्तन ही प्रतिस्थापन प्रभाव है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

1. उपभोक्ता के सन्तुलन से क्या अभिप्राय है ? उपभोक्ता के सन्तुलन की शर्तों को बताइए।
2. तटस्थता वक्र रेखा की विशेषताएँ समझाइए। तटस्थता वक्र रेखाओं की सहायता से उपभोक्ता के सन्तुलन की व्याख्या कीजिए।
3. "एक उपभोक्ता सन्तुलन की स्थिति में तब होगा जबकि वस्तुओं के बीच की प्रतिस्थापन दर उनकी कीमत के अनुपात के बराबर होनी है।" व्याख्या कीजिए।

("The Consumer is only in full equilibrium if the marginal rate of substitution between any two goods equals their price ratio" Explain)

4. 'आय प्रभाव' तथा 'प्रतिस्थापन प्रभाव' का अन्तर स्पष्ट कीजिए। ये उपभोक्ता के सन्तुलन में परिवर्तन को किस प्रकार व्यक्त करते हैं।
5. तटस्थता वक्र विक्षेपण की सहायता से उपभोक्ता के व्यवहार पर आय में परिवर्तन होने के प्रभाव तथा कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को बताइए।

अध्याय ५

★

उत्पादन-फलन

[Production Function]

★ ★ ★

उत्पादन फलन (production function) या उत्पादन प्रकाश का अर्थ समझने से पूर्व फलन या प्रकारों शब्द को समझ लेना आवश्यक है। फलन गणित का शब्द है। जब हम कहते हैं कि P फलन X और Y का है, तो इसका अभिप्राय यह है कि P निर्भर करता है X और Y पर। गणित में इस फलनीय सम्बन्ध (functional relationship) को सूत्र रूप में इस प्रकार लिखा जाता है—

$$P = F(X, Y)$$

इस सूत्र को हम इस प्रकार पढ़ेंगे—P फलन है X और Y का, अर्थात् P निर्भर करता है X और Y पर।

उत्पादन फलन का अर्थ (Meaning of Production Function)

किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सहयोग आवश्यक है। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे हम उत्पादन (output) कहते हैं। तथा जिन साधनों के सहयोग से उत्पादन किया जाता है उसे आपत (input) कहते हैं।¹ उत्पादन किसी फर्म के भौतिक उत्पादों तथा भौतिक बायतों के बीच के सम्बन्ध को व्यक्त करता है।

-
- 1 output को उत्पादन, उत्पाद या प्रदा, तथा input को आगत, पड़त या आगदा कहते हैं।

दूसरे शब्दों में—“किसी फर्म के भौतिक उत्पादनों और भौतिक आगतों के सम्बन्ध को उत्पादन फलन कहते हैं।”²

आगतों एवं उत्पादन साधनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। ये दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं, किन्तु आगत शब्द अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें उन सभी वस्तुओं का सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रयोग एक फर्म द्वारा उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है। उत्पादन या उत्पाद (out put) शब्द से अभिप्राय उन सब वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं से है जिनका उत्पादन एक फर्म द्वारा विभिन्न आगतों के सहयोग से किया जाता है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सेम्युएलसन (Samuelson) ने उत्पादन फलन की परिभाषा निम्न-लिखित शब्दों में दी है—

“उत्पादन फलन वह प्राविधिक सम्बन्ध है जो यह बताता है कि आगतों के विद्यमान समूह का उत्पादन क साधनों द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। यह किसी दी हुई प्राविधिक ज्ञान की स्थिति के लिए पारिभाषित किया जाता है।”³

जब कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है तो वह उत्पादन करने में पूरे साधनों के विभिन्न विवरणों पर विचार करता है और यह देखता है कि किन साधनों से उसे कितना उत्पादन प्राप्त होगा। जिन साधनों के संयोग से उसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त होने की सम्भावना दिखाई देती है उसे ही वह अपना लेता है। अतः उत्पादन फलन उत्पादन सम्भावनाओं की सूची है।

अर्थशास्त्र में उत्पादन फलनों (production functions) की सत्ता काफी अधिक है। प्रो. लाइटविच ने लिखा है—

“किसी भी फर्म का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है, यदि गणितीय रूप में रखा जाय तो इसे उत्पादन फलन कहते हैं।”

प्रो. लैफ्टविच (Prof. Leftwich) के अनुसार—“उत्पादन फलन शब्द उस भौतिक सम्बन्ध के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो कि एक फर्म के साधनों की इकाइयों

- 2 The relationship between the physical input and physical output of a firm is generally referred to as production function
- 3 “The Production Function is the technical relationship telling the amount of output capable of being produced by each and every set of specified input or factors of production. It is defined for a given store of technical knowledge” —Samuelson

(inputs) और प्रति इकाई समयानुसार प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं (outputs) के बीच पाया जाता है।”

प्रो लेपटविच ने अपने उन कथन को गणितीय रूप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है—

$$X = F(a, b, c)$$

इस सूत्र में X वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा है तथा a, b, c प्रति समय इकाई में विभिन्न उत्पादन के साधन (inputs) हैं। किसी भी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा (output) उस फर्म द्वारा प्रयुक्त किये गये साधनों (inputs) की मात्रा और रूप पर निर्भर करती है। यदि इन साधनों की मात्राओं में परिवर्तन हुआ जाता है तो उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। उत्पादन के लिए प्रयुक्त तकनीकों का भी उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। यदि प्रयुक्त तकनीकों में कार्य कुशलता कम है तो उत्पादन की मात्रा कम प्राप्त होती है, तथा अधिक कार्यकुशल तकनीकों के प्रयोग से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

उत्पादन फलन की विशेषताएँ Characteristics of Production Functions)

उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) उत्पादन फलन की परिभाषा से स्पष्ट है कि उत्पादन फलन साधनों की भौतिक मात्रा (physical quantities of inputs) तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा (physical quantities of outputs) के सम्बन्ध को व्यक्त करता है। भूत उत्पादन फलन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आता अपितु उत्पादन इंजीनियरिंग (production engineering) के क्षेत्र में आता है। इन प्रकार उत्पादन फलन आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग समस्या है।

उत्पादन फलन की कोई भौतिक विशेषताएँ नहीं होती हैं, अर्थात् उत्पादन फलन उत्पादित वस्तु की कीमत एवं साधनों की कीमत से पूर्णतया स्वतन्त्र रहता है, लेकिन ये नीति ही एक फर्म के उत्पादन के इस निर्णय को प्रभावित करती है कि किस वस्तु का और किसकी मात्रा में उत्पादन दिया जाय। दूसरे शब्दों में—

“एक इंजीनियर साधनों के भौतिक संयोगों में रुचि रखता है जबकि एक व्यापारी ऐसे संयोगों में भौतिक पक्षों में रुचि लेता है।”⁴

4 “The engineer is interested in physical combinations, the businessman is interested in the monetary elements of such combinations”

- (२) एक उत्पादन फलन दो हुई तकनीकी ज्ञान (technical knowledge) की स्थिति के सदृश में परिभाषित किया जाता है।^१ प्रत्येक घम का उत्पादन फलन तकनीकी ज्ञान और प्रवृत्त योग्यता की स्थिति के द्वारा निर्धारित होता है। तकनीकी ज्ञान की स्थिति में सुधार होना से नया उत्पादन फलन प्राप्त होगा। इसका अभिप्राय यह है कि यदि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता अर्थात् उत्पादन समान रहता है, तो पहले से कम ही साधन प्रयुक्त होंगे और यदि पहले के समान ही साधन प्रयुक्त किये गये तो उत्पादन पहले से अधिक बढ़ जायेगा।
- (३) एक उत्पादन फलन को हमेशा एक दिये हुये समय (for a given period of time) में प्रति इकाई समय (per unit of time) के रूप में ही व्यक्त किया जाता है।
- (४) एक उत्पादन फलन की प्रकृति को जानने के लिये पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि उत्पादन में परिवर्तन करने के लिये साधनों (inputs) की मात्राओं में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी साधन की मात्रा को उसके कार्य करने के समय की लम्बाई के रूप में मापा जाता है, जैसे—घण्टों या महीनों, घण्टों में इत्यादि।

विगत कुछ वर्षों में अर्थशास्त्रियों से भौतिक आगतों और भौतिक उत्पादन के बीच परिवर्तनों से सम्बन्ध को सांख्यिकी विश्लेषण करके अनेक उत्पादन फलनों का प्रतिपादन किया है। सांख्यिकी उत्पादन फलन का एक श्रेष्ठ उदाहरण कॉब-डॉगलस उत्पादन फलन (Cobb Douglas Production Function) है। इस उत्पादन फलन का प्रतिपादन अमरीकी अर्थशास्त्री पी एच डॉगलस (P H Douglas) तथा सी डब्लू कॉब (C W Cobb) द्वारा किया गया।

अर्थशास्त्र इन दो प्रकार के उत्पादन फलनों से सम्बन्धित है जिनका प्रतिपादन साधनों की स्थिरता तथा परिवर्तनशीलता के आधार पर किया गया है—

- (१) वह उत्पादन फलन जिसमें साधनों की कुछ मात्राएँ स्थिर रहती हैं तथा कुछ परिवर्तनशील।
- (२) वह उत्पादन फलन जिसमें सभी साधनों की मात्राएँ परिवर्तनशील होती हैं।
- अर्थशास्त्रियों ने प्रथम प्रकार के उत्पादन फलन को अल्पकालीन व दूसरे प्रकार के उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा है।

5 "A production function is defined for a given state of technical knowledge"

यदि बिसो एक साधन को स्थिर रखकर अन्य में परिवर्तन किया जाय या अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में परिवर्तन किया जाय तो उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। सुविधा के लिए हम यह मान लेते हैं कि फर्म एक साधन में परिवर्तन करती है तथा अन्य को स्थिर रखती है। अर्थात् एक परिवर्तनशील साधन वाले उत्पादन फलन (production function with one variable input) को दिखाना करते हैं। इस प्रकार का उत्पादन फलन अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस प्रकार यदि एक फर्म अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि करती है तो स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों के बीच अनुपात में परिवर्तन हो जाता है।

‘उत्पत्ति ह्रास नियम’ (Law of Diminishing Returns) या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम (Law of Variable Proportions) उत्पादन फलन की अवस्था है।

जब अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में परिवर्तन किया जाता है तब उत्पादन फलन (साधन उत्पादन सम्बन्ध) को तीन भागों में बांटा जाता है—

(१) जब उत्पादन के साधन में वृद्धि करने से कुल उत्पादन घटते हुए अनुपात में बढ़ता है, अर्थात् सीमान्त उत्पादन और औसत उत्पादन घटने लगता है। इसे उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) या ‘लागत वृद्धि नियम’ (The Law of Increasing Costs) कहते हैं।

(२) जब उत्पादन के साधन में वृद्धि करने से कुल उत्पादन बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है अर्थात् सीमान्त उत्पादन और औसत उत्पादन बढ़ने लगता है। इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) या लागत ह्रास नियम (Law of Diminishing Cost) कहते हैं।

(३) जब उत्पादन के साधन में वृद्धि करने से कुल उत्पादन समान अनुपात में बढ़ता है तो इसे उत्पत्ति समता नियम (Law of Constant Returns) या लागत समता नियम (Law of Constant Cost) कहते हैं।

अब हम द्वितीय अवस्था को लेते हैं जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होने हैं, अर्थात् कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता। ऐसे उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे सभी परिवर्तनशील साधनों के साथ उत्पादन फलन (Production function with all the variable inputs) कहते हैं।

जब सभी साधनों की मात्राओं में एक साथ परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि फर्म के 'प्लांट का पैमाना' (scale of plant) बदल गया है। ऐसी स्थिति में (अर्थात् साधनों की मात्राओं में परिवर्तन होने से) उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे 'पैमाने का प्रतिफल' (return to scale) कहते हैं।

जब सभी साधनों को समान मात्रा में परिवर्तित किया जाता है तब प्राप्त होने वाले उत्पादन की मात्रा की तीन स्थितियाँ देखने की मिलती हैं —

- (१) पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था (stage of increasing returns to scale)
- (२) पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल की अवस्था (stage of constant returns to scale)
- (३) पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की अवस्था (scale of decreasing returns to scale)

नोट—(हम उपयुक्त तीनों स्थितियों का अध्ययन 'पैमाने के प्रतिफल' (Return to Scale) अध्याय के अन्तर्गत करेंगे।)

किसी देश के उत्पादन फलन के स्वरूप की उस देश की तकनीकी ज्ञान की अवस्था प्रभावित करती है यदि तकनीकी ज्ञान में सुधार हो जाता है तो पुराना उत्पादन फलन बकार हो जाता है और नया उत्पादन फलन प्राप्त हो जाता है। इस नये उत्पादन फलन में पुराने साधनों (inputs) द्वारा ही अधिक उत्पादन प्राप्त होता है या पहले के बराबर उत्पादन कम साधनों या आगनों को प्रयुक्त करके प्राप्त किया जा सकता है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। अल्पवासीन और दीर्घवासीन उत्पादन फलन में क्या अन्तर है?
२. उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

अध्याय ६

★

पैमाने के प्रतिफल

[Returns to Scale]

★ ★ ★

अल्पकाल में समय इतना अधिक नहीं होता कि सभी साधनों की मात्राओं में परिवर्तन किया जा सके, अतः फर्म का 'पैमाना' अपरिवर्तित रहता है। परन्तु दीर्घकाल में सभी साधनों (भागों) की मात्राओं में परिवर्तन करके फर्म के पैमाने को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल (Returns to Scale) कहते हैं। पैमाने का प्रतिफल केवल दीर्घकाल से ही सम्बन्धित है, क्योंकि सभी साधनों में परिवर्तन, दीर्घकाल में ही सम्भव है।

सभी साधनों की मात्राओं में एक साथ परिवर्तन करने से उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, पैमाने के प्रतिफल में इस विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है कि यदि सभी साधनों में समान अनुपात से परिवर्तन किया जाय तो उत्पादन की मात्रा में किस प्रकार से परिवर्तन होगा।

जब सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि की जाती है तो प्राप्त होने वाले उत्पादन की मात्रा में तीन स्थितियाँ देखने को मिलती हैं—

- (१) पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति
(Stage of increasing returns to scale),
- (२) पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल की स्थिति
(Stage of constant returns to scale),
- (३) पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की स्थिति
(Stage of decreasing returns to scale)।

पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल (Increasing Returns to Scale)

उत्पादन के साधनों की मात्रा में बिस अनुपात में वृद्धि करते हैं उत्पादन उससे अधिक अनुपात में प्राप्त होता है उसे पैमाने में बढ़ते हुए प्रतिफल कहते हैं, जैसे—यदि साधनों में वृद्धि का अनुपात १५ प्रतिशत है इस वृद्धि में उत्पादन २० प्रतिशत बढ़ जाता है तो यह बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति होती है।

पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के निम्नलिखित कारण हैं —

(१) **वितीय बचतें (Dimensional economics)**—जब उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पूंजीगत वस्तु के आकार में वृद्धि की जाती है और इस बड़े आकार की पूंजीगत वस्तु से प्राप्त उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक होता है तो इसे वितीय बचतें कहते हैं, जैसे—यदि एक सेल पाइप के आकार को दुगुना कर दिया जाय तो उस पाइप से पहने की तुलना में दुगुने में अधिक तेल निकाला जा सकता है। अतः एक सीमा तक उत्पादन क्षमता पूंजीगत वस्तुओं में किये गये विनियोग की वृद्धि के अनुपात से अधिक बढ़ती है, जिसके कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत घट जाती है।

(२) **अविभाज्यता (Indivisibility)**—संपन की अविभाज्यता पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का एक महत्वपूर्ण कारण है। अविभाज्यता से अभिप्राय है कि पूंजीगत वस्तुएँ कुछ निश्चित आकारों में ही उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे—एक बल्ब बनावट की मशीन है, जो कि एक दिन में ५००० बल्ब बना सकती है, लेकिन यदि इस मशीन का केवल १००० बल्ब बनाने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है तो प्रति बल्ब की उत्पादन लागत अधिक होगी, क्योंकि कुल स्थिर लागत को १००० बल्बों पर ही विभाजित किया जायेगा। यदि यही मशीन ५००० बल्बों का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो प्रति इकाई लागत कम होगी, क्योंकि कुल स्थिर लागत को ५००० बल्बों पर विभाजित किया जायेगा।

अविभाज्यतायें केवल मशीनों या यंत्रों से ही सम्बंधित नहीं होतीं—धर्म, प्रबंध, वित्त तथा अनुसंधान और विज्ञान में भी अविभाज्यतायें उपलब्ध होती हैं।

(२) **उत्पादन बचतें (Production economics)**—बड़े पैमाने में उत्पादन की बचतें दो प्रकार की होती हैं—

(a) आन्तरिक बचतें (Internal economics),

(b) बाह्य बचतें (External economics)।

- (a) **आन्तरिक बचतें**—आन्तरिक बचतें वे बचतें हैं जो किसी फर्म का उसकी आन्तरिक कुशलता और थोड़ा व्यवस्था के कारण प्राप्त हानो हैं। मार्शल के अनुसार ये बचतें निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं—

(१) **तकनीकी बचतें (Technical economics)**—तकनीकी बचतें बड़े पैमाने के उत्पादन में श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण उत्पादन की थोड़ी तकनीक और बड़ी मशीनों के प्रयोग के कारण प्राप्त होती हैं, इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम हो जाती है।

(२) **प्रबन्ध सम्बन्धी बचतें (Manageable economics)**—बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रबन्ध व्यवस्था का कार्य कई विधेयताओं द्वारा किया जाता है। उसमें व्यक्तियों की योग्यता के आधार पर कार्य दिया जाता है जिससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और उत्पादन लागत घट जाती है।

(३) **वित्तीय बचतें (Financial economics)**—बड़े पैमाने के उत्पादन में वित्त की व्यवस्था करने में अधिक कठिनाई नहीं आती, क्योंकि इन फर्मों की साख अच्छी होती है जिससे कम म्याज की दर पर पूँजी और साख सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं।

(४) **विक्रय बचतें (Marketing economics)**—बड़े पैमाने के उत्पादन करने से फर्मों को बच्चा माल समूह मूल्यों पर उपलब्ध हो जाता है। ये फर्म अपने उत्पादित माल को बाजार में आसानी से बेच देती हैं, क्योंकि इनके पास छोटी फर्मों की तुलना में साधन अधिक होते हैं जिससे विज्ञापन और प्रचार कार्य के द्वारा आसानी से क्रेताओं को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसके साथ ही ये फर्म अपने माल को सस्ते मूल्य पर बेचती हैं क्योंकि इन फर्मों की प्रति इकाई लागत कम होती है।

- (b) **बाह्य बचतें (External economics)**—जब किसी उद्योग का विकास होता है तब उसमें सम्मिलित सभी फर्मों को बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं।

भाशेल के अनुसार—“वाह्य वचते उद्योग के समान विकास पर निर्भर होती हैं। जैसे जैसे किसी उद्योग विशप का विकास हो जाता है वैसे वैसे ये वचते भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं।”

एक स्थान पर उद्योग केन्द्रित होने के कारण थमिक स्वत ही इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे थमिका पर कम खर्चा करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनेक सहायक उद्योगों की स्थापना हो जाती है। ये उद्योग अनरु सहयोगी वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे केन्द्रों पर ढाक तार, आवागमन आदि की सुविधायें उपलब्ध हो जाती हैं तथा तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थायें स्थापित हो जाती हैं। इसमें सभी फर्म लाभ प्राप्त करती हैं और प्रति इकाई लागत घट जाती है।

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि पूँजीगत वस्तुओं के आकार में वृद्धि, साधनों की अविभाज्यतायें तथा उत्पादन की आंतरिक वाह्य वचतों के प्राप्त होने के कारण जब किसी फर्म के सभी साधनों में वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पादन में वृद्धि साधनों में वृद्धि के अनुपात से अधिक होती है।

बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल की स्थिति उद्योग के स्वल्प पर निर्भर करती है। साधारणतया फर्म के विस्तार की अवस्था में यह क्रियाशील रहती है। लेकिन यदि फर्म में पूँजीगत वस्तुओं (capital assets) का प्रयोग कम होता है या अविभाज्यता तथा विशिष्टता का क्षेत्र सीमित है, तो बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो जाती है और इसके स्थान पर पैमाने के प्रतिफल से सम्पन्न स्थिर अथवा ह्रास की स्थिति कायशील होन लगती है। यही कारण है कि कृषि में बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल की स्थाति का क्षेत्र सीमित है।

२ पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल (Constant Returns to Scale) :

जब उत्पादन के साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे पैमाने का स्थिर या समान प्रतिफल कहते हैं, जैसे—यदि साधनों की इस वृद्धि का अनुपात १५ प्रतिशत है, साधनों की इस वृद्धि से उत्पादन में भी १५ प्रतिशत वृद्धि होती है, तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति बड़े है।

साधनों में अविभाज्यता, विनिष्टीकरण तथा उत्पादन में आंतरिक और बाह्य वचन प्राप्त होने की एक सीमा होती है। इस सीमा के बाद यदि फर्म का विस्तार किया जाता है तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति शिथिल हो जाती है, क्योंकि फर्म को प्राप्त होने वाली सभी वस्तुएँ एक सीमा के बाद निश्चित हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, एक सीमा के बाद आंतरिक व बाह्य अवयवों (internal and external dis economics) प्रभावहीन (neutral) बना देती हैं।

गणितीय भाषा में पैमाने के स्थिर प्रतिफल का रेखीय एवं समातम (linear or homogeneous) अवस्था 'प्रथम मात्रा का समत्प (homogeneous of first order) उत्पादन फलन' कहते हैं।

३ पैमाने के घटते हुए प्रतिफल (Decreasing Returns to Scale)

जब उत्पादन के साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है, तो उसे पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की स्थिति कहते हैं जैसे—उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि का अनुपात १५ प्रतिशत है, तो उत्पादन की वृद्धि से उत्पादन में केवल १० प्रतिशत वृद्धि होती है या इस पैमाने के घटते हुए प्रतिफल का ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति बहेगी।

जब किसी फर्म का विस्तार स्थिर प्रतिफल की स्थिति के बाद भी किया जाता है तो वहाँ घटते हुए प्रतिफल की स्थिति शिथिल हो जाती है। इसका कारण यह है कि एक सीमा के बाद आन्तरिक व बाह्य वचनों के स्थान पर फर्म को उत्पादन की अवयवों या अमितत्व्यताओं का सामना अधिक करना पड़ता है, जिससे प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, विशाल स्तरीय प्रबंधन की कठिनाईयाँ एवं जटिलताएँ घटते हुए प्रतिफल की अवस्था के कामशील होने की प्रमुख कारण हैं।

उदाहरण एवं रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण

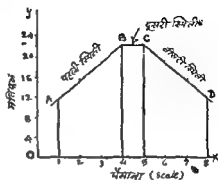
पैमाने के प्रतिफल से सम्बन्धित तीन स्थितियों को अब पृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है।

क्रम संख्या	पैमाना (Scale)	कुल उत्पादन या प्रतिफल (Total Returns)	सीमान्त उत्पादन या प्रतिफल (Marginal Returns)	टिप्पणियाँ (Remark)
१	१ श्रमिक + २ एकड़ भूमि	१० क्विंटल	१० क्विंटल	बढ़ता हुआ प्रतिफल
२	२ श्रमिक + ४ एकड़ भूमि	२४ "	१४ "	
३	३ श्रमिक + ६ एकड़ भूमि	४२ "	१८ "	
४	४ श्रमिक + ८ एकड़ भूमि	६४ "	२२ "	स्थिर प्रतिफल
५	५ श्रमिक + १० एकड़ भूमि	८६ "	२२ "	
६	६ श्रमिक + १२ एकड़ भूमि	१०५ "	१९ "	घटता हुआ प्रतिफल
७	७ श्रमिक + १४ एकड़ भूमि	१२० "	१५ "	
८	८ श्रमिक + १६ एकड़ भूमि	१३० "	१० "	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में जब एक श्रमिक और दो एकड़ भूमि है तब कुल उत्पादन १० क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है। जब साधनों को दुगुना कर दिया जाता है, अर्थात् दो श्रमिक और चार एकड़ भूमि है तब उत्पादन दुगुने से अधिक बढ़ जाता है, अर्थात् कुल उत्पादन २४ क्विंटल प्राप्त होता है। साधनों के पैमाने में पुनः समान अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन दबकर ४२ क्विंटल हो जाता है। इस प्रकार पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता है। यदि इस सीमा के बाद साधनों के अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि उसी अनुपात में होती है, अर्थात् पैमाने का स्थिर प्रतिफल होता है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल की सीमा ५ श्रमिक और १० एकड़ भूमि तक रहती है। इस सीमा के बाद भी यदि साधनों को मानाप्रो में वृद्धि की जाती है तो सीमान्त प्रतिफल घटता जाता है, अर्थात् घटते हुए प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होती है।

उपयुक्त स्थिति को रेखाचित्र के माध्यम से भी स्पष्ट किया जा सकता है—

समान रेखाचित्र में पहली स्थिति में पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल दूसरी स्थिति में स्थिर प्रतिफल तथा तीसरी स्थिति में पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होती है।



अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

1. 'पैमाने के प्रतिफल' से आप क्या समझते हैं? पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल (Increasing Returns to Scale), पैमाने के स्थिर प्रतिफल (Constant Returns to Scale) तथा पैमाने के घटते हुए प्रतिफल (Decreasing Returns to Scale) की व्याख्या कीजिए।
2. 'पैमाने के प्रतिफल' से सम्बन्धित बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था के कारणों की सविस्तार व्याख्या कीजिए।
3. पैमाने के घटते हुए प्रतिफल (Decreasing Returns to Scale) को समझाइए। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल तथा घटते हुए प्रतिफल (Decreasing Returns) के अन्तर को समझाइए।

अध्याय ७

★

समोत्पाद-वक्र

[Iso-Product Curves]

★ ★ ★

किसी वस्तु के उत्पादन में कई साधनों, जैसे—भूमि, श्रम, पूँजी का समुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। दी हुई तकनीकी दशाओं के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों में विभिन्न संयोग समान उत्पत्ति प्रदान कर सकते हैं। साधनों के विभिन्न संयोगों को एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ऐसी रेखाओं को जो उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के संयोगों (सुविधा की दृष्टि से केवल दो ही उत्पत्ति के साधनों का लिया जाता है) का व्यक्त करती हैं, समोत्पाद वक्र या समोत्पाद रेखाएँ कहते हैं।

हम यह कह सकते हैं कि समोत्पाद वक्र और तटस्थता-वक्र में काफी समानता पायी जाती है, क्योंकि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जो कि उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार समोत्पाद-वक्र भी दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जिनसे कि समान उत्पादन प्राप्त होता है। इस समानता के कारण ही इनको 'उत्पादन तटस्थता-वक्र (production indifference curves) भी कहा जाता है।¹ कीरस्टेड (Keirstead) ने समोत्पाद वक्र की परिभाषा इस प्रकार की है—

“समोत्पाद रेखा दो साधनों के उन सब संभावित संयोगों को बताती है जो कि एक समान कुल उत्पादन प्रदान करते हैं।”²

- 1 समोत्पाद वक्रों को सम-उत्पाद रेखाएँ (Equal Product curves) या सम-उत्पादन रेखाएँ (Iso-quant curves, भी कहते हैं।
- 2 “Iso product curve represents all possible combinations of the two factors that will give the same total product” —Keirstead

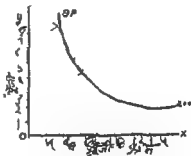
समोत्पाद वक्र को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लिया कि अम और पूँजी दो उत्पादों के साधन हैं और इन साधनों के विभिन्न संयोग २०० इकाइयों के बराबर उत्पादन देते हैं।

पूँजी की इकाइया	अम की इकाइया	कुल उत्पादन
८	४	२००
५	८	२००
३	१४	२००

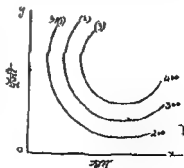
इसे चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र में IP समोत्पाद-वक्र है जो कि अम तथा पूँजी के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिनसे कि उत्पादक को एक समान उत्पादन (अर्थात् २०० इकाइया) प्राप्त होता है।

समोत्पाद मानचित्र (Iso Product Map)



एक उत्पादक के लिए अनेक समोत्पाद-वक्र हो सकते हैं। प्रत्येक समोत्पाद वक्र उत्पादन की विभिन्न मात्रा को व्यक्त करता है। जब अनेक समोत्पाद-वक्रों को, जो कि उत्पादक के लिए उत्पादन की विभिन्न समान मात्राओं को व्यक्त करते हैं, एक ही चित्र में प्रदर्शित किया जाता है, उसे समोत्पाद मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में अंकित प्रत्येक रेखा वस्तु की विशेष मात्रा उत्पन्न करने वाले विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है। मूल बिन्दु से दायीं ओर स्थित समोत्पाद-वक्र अधिक उत्पादन को व्यक्त करती हैं। समोत्पाद मानचित्र को सलग्न दर्शाया गया है।



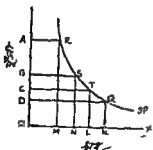
समोत्पाद-वक्रों की विशेषतायें (Characteristics of Iso Product Curves)

समोत्पाद-वक्रों की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

- (१) समोत्पाद वक्र बायें से दायें नीचे की ओर झुकते हैं—इससे अभिप्राय यह है कि जब एक साधन (input) की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो दूसरे साधन की मात्रा में (जो कि पहले साधन के साथ प्रयोग में लाया जाता है) कमी करनी होती है, जिससे कि प्राप्त उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे, अर्थात् वक्र पर अंकित प्रत्येक बिन्दु समान उत्पादन को प्रदर्शित करे।

यदि एक साधन की मात्रा स्थिर रखकर दूसरे में परिवर्तन किया जाय तो उत्पादन को या तो बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त होगा या घटता हुआ प्रतिफल। इसी प्रकार यदि दोनों साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाय तो उत्पादन की समान मात्रा प्राप्त नहीं होगी, जबकि समोत्पाद वक्र समान मात्रा प्रदर्शित करते हैं। अतः समोत्पाद वक्र हमेशा बायें से दायें नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, अर्थात् उनका ढाल ऋणात्मक होता है।

- (२) समोत्पाद वक्र मूल बिन्दु के उन्नतोंदर होते हैं (Iso product curves are convex to the origin)—इसका कारण यह है कि एक साधन का दूसरे साधन के रूप में महत्व घटता जाता है, अर्थात् सीमान्त प्रतिस्थापन दर (marginal rate of substitution) घटती जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि हम धम की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो पूँजी की मात्रा में कमी करनी होती है। प्रारम्भ में प्रतिस्थापन की दर कम होती है तथा बाद में यह बढ़ जाती है। इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।



सलग्न चित्र में समोत्पाद वक्र बायें से दायें नीचे की ओर झुकता है। धम की एक इकाई MN पूँजी की AB इकाइयों को प्रतिस्थापित करती है। यदि धम की एक इकाई और बढ़ायी जाती है तो वह पूँजी की BC इकाइयों को प्रतिस्थापित करती है। इस प्रकार यदि धम की एक और इकाई LN बढ़ायी जाती है तो वह पूँजी की CD इकाइयों का प्रतिस्थापन

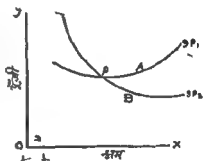
करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धम की प्रत्येक इकाई को पूँजी की घटती हुई मात्रा से प्रतिस्थापित किया जाना है। यही कारण है कि समोत्पाद वक्र मूल बिन्दु के उन्नतोंदर होता है।

- (३) विभिन्न समोत्पाद वक्र उत्पादन के विभिन्न स्तरों को बताते हैं—समोत्पाद वक्र

उत्पादन के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। बायीं ओर स्थित प्रत्येक समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में, समोत्पाद वक्र मूल बिन्दु से जितना दूर होया उत्पादन का स्तर उतना ही अधिक होगा।

- (४) समोत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं—जैसा कि पूर्व में लिखा गया है विभिन्न समोत्पाद वक्र विभिन्न उत्पादन के स्तरों को व्यक्त करते हैं तथा मूल बिन्दु के पास वाला समोत्पाद वक्र दूर वाले समोत्पाद वक्र की तुलना में कम उत्पादन की मात्रा को बताता है। यदि दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उस बिन्दु पर जहाँ कि दोनों समोत्पाद वक्र मिलते हैं, या काटते हैं, समान उत्पादन की मात्रा को प्रदर्शित करेंगे, जो कि सम्भव नहीं है। इसे बिना द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

समान बिन्दु में IP_1 तथा IP_2 वक्र एक दूसरे को P बिन्दु पर काटते हैं। इसका अर्थ यह है कि P बिन्दु पर उत्पादक को समान उत्पादन मिलता है, परन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि IP_1 वक्र पर स्थित A बिन्दु IP_2 पर स्थित B बिन्दु की अपेक्षा अधिक उत्पादन को व्यक्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि समोत्पाद वक्र एक-दूसरे को नहीं काटते।



समोत्पाद वक्र एवं तटस्थता वक्र में अन्तर (Difference between Iso-product Curves and Indifference Curves)

समोत्पाद वक्र एवं तटस्थता वक्र में काफी समानता है। समोत्पाद वक्र साधनों के उन संयोगों को व्यक्त करता है, जो कि वस्तु की समान मात्रा उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करता है जो उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि प्रदान करते हैं। इस समानता के साथ ही दोनों में महत्वपूर्ण अन्तर है, जो कि निम्नलिखित है—

- (१) समोत्पाद वक्रों की उत्पादन की इकाइयों को भौतिक इकाइयों (physical units) के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि तटस्थता वक्रों को इस प्रकार व्यक्त नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, समोत्पाद वक्रों की उत्पादन की इकाइयों को राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जबकि तटस्थता वक्रों को केवल एक क्रम (order) में ही रखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि सन्तुष्टि को मापने की कोई भौतिक इकाई उपलब्ध

नहीं है, जबकि उत्पादन को मीटर, लिटर, किलोग्राम और मेट्रिक टन जैसी भौतिक इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

- (२) यदि हम समोत्पाद मानचित्र (Iso product map) का निर्माण करें तो हम सरलता से यह बता सकते हैं कि एक समोत्पाद वक्र दूसरे समोत्पाद वक्र की तुलना में कितनी कम या कितनी अधिक मात्रा को व्यक्त करता है, जबकि तटस्थता मानचित्र में ऐसा बताना सम्भव नहीं है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ समोत्पाद वक्र से क्या अभिप्राय है ? समोत्पाद वक्रों की विशेषताओं को बताइए।
- २ समोत्पाद वक्र की परिभाषा दीजिए। ये वक्र तटस्थता वक्र से किस प्रकार भिन्न हैं।

अध्याय ८

★

मूल्य-निर्धारण का सामान्य सिद्धान्त

[General Theory of Value]

★ ★ ★

अर्थशास्त्र में मूल्य निर्धारण की समस्या का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारम्भ में ही इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन प्रारम्भ में मूल्य निर्धारण सम्बन्धी विचारों में काफी गिरफ्तारी रही है। प्रारम्भिक विचारों का हम दो भागों में बाँट सकते हैं—

- (१) उत्पादन लागत सम्बन्धी सिद्धान्त (Cost of production theory),
- (२) उपयोगिता सम्बन्धी सिद्धान्त (Utility theory)।

एडम स्मिथ (Adam Smith), रिचार्डो (Ricardo) आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि वस्तु का मूल्य उस वस्तु की उत्पादन लागत के द्वारा निर्धारित होता है। यद्यपि वस्तु के मूल्य निर्धारण पर अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पादन लागत का ही होता है। अतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन लागत सिद्धान्त प्रतिपादित किया। इनके मतानुसार यदि किसी वस्तु की उत्पादन लागत दस रुपये आती है तो उस वस्तु का मूल्य भी दस रुपये होगा। इस प्रकार यह सिद्धान्त केवल पूर्ति पक्ष पर ही ध्यान केन्द्रित करता है।

इसके विपरीत जेवन्स (Jevons), वालरस (Walras) आदि आस्ट्रियन विचारधारा के अर्थशास्त्रियों ने बताया कि वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। इस सिद्धान्त को 'सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त' (marginal utility theory) कहते हैं। जेवन्स ने लिखा है —

“निरन्तर अध्ययन एवं छानबीन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वस्तु का मूल्य पूर्णतः उपयोगिता पर निर्भर करता है।”¹

जेवन्स ने बताया कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के लिये मूल्य उसकी सीमान्त उपयोगिता (marginal utility) से अधिक नहीं देगा, जैसे—यदि एक पुस्तक से १५) रुपये के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है तो उपभोक्ता उसने लिये १५) रुपये से अधिक मूल्य देने के लिये तैयार नहीं होगा। इस प्रकार यह सिद्धान्त मूल्य-निर्धारण की मांग व पूँति की ओर की व्याख्या करता है।

उपर्युक्त दोनों सिद्धान्त अपूर्ण एवं एकपक्षीय हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य न तो केवल उत्पादन लागत के द्वारा ही निर्धारित होता है और न ही केवल उपयोगिता द्वारा।

मार्शल के विचार (Marshall's Views)

मार्शल ने उपर्युक्त दोनों विरोधी विचारधाराओं को मूल्य-निर्धारण का एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया। उसने बताया कि वस्तु का मूल्य न तो केवल उत्पादन लागत द्वारा (जो कि पूँति से सम्बन्धित है) निर्धारित होता है और न ही उपयोगिता (जो कि मांग से सम्बन्धित है) द्वारा निर्धारित होता है, बल्कि वस्तु की मांग व पूँति दोनों मिलकर मूल्य निर्धारित करती हैं। उन्होंने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग और पूँति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निश्चित होता है। इसकी स्पष्ट करते हुए मार्शल ने लिखा है—

“जिस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि बैबी के ऊपर का ब्लेड या नीचे का ब्लेड कपड़े को काटता है, इसी प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि मूल्य-निर्धारण केवल मांग द्वारा (जो कि उपयोगिता पर निर्भर है) या केवल पूँति द्वारा (जो कि उत्पादन लागत पर निर्भर है) होता है। जिस प्रकार काटने का कार्य उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि दोनों ब्लेड नहीं मिलते, ठीक उसी प्रकार मूल्य तब तक निर्धारित नहीं होगा जब तक मांग और पूँति आपस में नहीं मिलते। जिस बिन्दु पर ये दोनों

1 “Repeated reflections and enquiry have led me to the somewhat novel opinion that value depends entirely upon utility.”

आपस में मिलते हैं उसे सन्तुलन बिन्दु कहते हैं और उन बिन्दु पर ही मूल्य निश्चित होता है ।^२

मार्शंस के इस दृष्टिकोण को अर्थशास्त्री सिल्वरमन (Silverman) ने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है—

“माग पक्ष की ओर से किसी वस्तु के मूल्य की प्रवृत्ति उसकी सीमान्त उपयोगिता अथवा सीमान्त फल के अनुमान (estimate of marginal purchase) के बराबर होने की रहती है, जबकि पूर्ति पक्ष की ओर से इसकी प्रवृत्ति सीमान्त उत्पादन लागत या सीमान्त फर्म की लागत के बराबर होने की होती है । सीमान्त उपयोगिता एवं सीमान्त लागत के सम्मिलन का बिन्दु ही, जिसे मुद्रा द्वारा मापा जाता है, मूल्य को व्यक्त करता है ।”^३

अतः हम यह कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य माग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है ।

माग शक्ति (Demand Force)

केताओं और उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की माग की जाती है । माग इसलिए की जाती है क्योंकि वस्तु में उपयोगिता होती है । कोई भी उपभोक्ता या केता किसी वस्तु के लिए मूल्य उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता से अधिक नहीं देता है । इस प्रकार उपभोक्ता

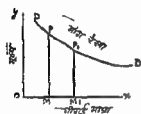
2 “Just as we cannot say whether it is the upper or lower blade of a pair of scissors that cuts a piece of cloth when the two blades operate together, so we cannot say whether demand (depending on utility) alone or supply (depending cost of production) alone determines value, and just as then can be no cutting until the two blades meet, so there can be no value until supply meets demand—the point at which they meet in order to cut, i. e., equilibrium point, is the point at which market value is fixed”
—Marshall

3 “From the side of demand, the price of an article tends to equal the marginal utility or the estimate of marginal purchase, while from the side of supply it tends to equal the marginal cost of production or the cost incurred by the marginal firm. The point of coincidence between the marginal cost and marginal utility both as measured in terms of money, indicate the price”

—Silverman

के लिए (माग पक्ष की ओर से) मूल्य की अधिकतम सीमा उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता होती है।

किसी वस्तु की माग, माग के नियम द्वारा नियन्त्रित होती है, अर्थात् अधिक मूल्य होने पर उपभोक्ता की माग कम होती है और कम मूल्य पर उपभोक्ता ^{अधिक} वस्तु की माग करता है। प्रत्येक श्रेता की एक माग सारणी होती है, जो यह व्यक्त करती है कि श्रेता



भिन्न-भिन्न मूल्यों पर वस्तु की कितनी मात्राएँ खरीद करेगा। इन व्यक्तिगत माग सारणियों को यदि मिला दिया जाय तो बाजार की माग सारणी प्राप्त हो जाती है। यदि इसे रेखा द्वारा व्यक्त किया जाय तो हमें बाजार की माग रेखा प्राप्त होती है। यह रेखा बायें से दायें नीचे की ओर झुकती हुई होती है। इस रेखा को

चित्र में प्रदर्शित किया गया है —

उपर्युक्त चित्र में DD माग रेखा है। जब वस्तु का मूल्य PM है तब वस्तु की मागी गई मात्रा OM है। जब मूल्य घट कर $P'M'$ हो जाता है तब वस्तु की माग बढ़ कर OM' हो जाती है।

पूर्ति शक्ति (Supply Force)

उत्पादक या विक्रेता वस्तु की पूर्ति करते हैं। उत्पादक या विक्रेता वस्तु का मूल्य इसलिए लेते हैं, क्योंकि उस वस्तु का उत्पादन करने में कुछ-न-कुछ लागत अवश्य आती है। कोई भी उत्पादक या विक्रेता अपनी वस्तु के लिए कम-से-कम मूल्य उस वस्तु की उत्पादन लागत के बराबर प्राप्त करेगा, अर्थात् उत्पादन लागत से कम मूल्य पर वह वस्तु को नहीं बेचेगा। यदि वह लागत से कम मूल्य पर वस्तु को बेचेगा तो उसे हानि होगी। इस प्रकार उत्पादन लागत वस्तु के मूल्य की न्यूनतम सीमा है।

किसी वस्तु की पूर्ति 'पूर्ति नियम' के द्वारा नियन्त्रित होती है। सामान्यतः अधिक मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा और कम मूल्य पर वस्तु की कम मात्रा बेची जाती है जिस प्रकार प्रत्येक श्रेता की माग सारणी होती है उसी प्रकार प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति सारणी होती है, जो कि यह व्यक्त करती है कि एक विक्रेता विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की कितनी मात्राएँ बेचेगा। पूर्ति सारणी को यदि रेखा द्वारा व्यक्त करें तो हमें पूर्ति

रेखा प्राप्त हो जाती है। पूर्ति रेखा बायें से दायें ऊपर की ओर उठती हुई होती है। इस रेखा को चित्र द्वारा स्पष्ट किया है।

समतल चित्र में SS पूर्ति रेखा है। जब वस्तु का मूल्य PM है तब वस्तु की पूर्ति OM है। जब मूल्य बढ़कर P'M' हो जाता है तो पूर्ति बढ़कर OM' हो जाती है।



माग और पूर्ति का संतुलन Equilibrium of Demand and Supply)

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रेता वस्तु का कम-से-कम मूल्य देना चाहता है, जबकि विक्रेता प्रेता वस्तु के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, दूसरे शब्दों में प्रेता सीमा तक उपभोगिता से अधिक मूल्य देने को तैयार नहीं होगा और विक्रेता उत्पादन लागत से कम मूल्य लेने को तैयार नहीं होगा। वस्तु का मूल्य इन दो सीमाओं—अधिकतम और न्यूनतम—के बीच घूमता रहता है। जिस बिन्दु पर ये दोनों मिलते हैं, अर्थात् माग और पूर्ति की शक्तियाँ बराबर हो जाती हैं, वही पर मूल्य निर्धारित हो जाता है। मूल्य-निर्धारण के इस बिन्दु को साम्य बिन्दु (equilibrium point) कहते हैं।

साम्य बिन्दु वह बिन्दु है जिस पर माग और पूर्ति की शक्तियाँ समान हैं। प्रो. बौलिंग (Prof. Boulding) के शब्दों में—

“किसी वस्तु के विक्रेता किसी मूल्य पर वस्तु की जितनी मात्रा बेचना चाहते हैं यदि उस मूल्य पर प्रेता उस वस्तु की उतनी ही मात्रा त्रय करना चाहते हैं तो उसे उस वस्तु का साम्य मूल्य कहते हैं।”⁴

1. साम्य में ‘साम्य बिन्दु वह बिन्दु है जहाँ पर बाजार साफ होता है।’
उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण.

निम्नांकित उदाहरण द्वारा मूल्य-निर्धारण की स्थिति को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—

- 4 “The equilibrium price is the price at which the quantity of a good which the sellers are willing to offer is equal to the amount which the buyers want to purchase.”
—Boulding

X वस्तु का मूल्य	X वस्तु की मांग	X वस्तु की पूर्ति
१० पैसे प्रति इकाई	१०० इकाई	५०० इकाई
८ पैसे " "	२०० " "	४०० "
६ पैसे " "	३०० " "	३०० "
सन्तुलन मूल्य क्योंकि मांग और पूर्ति बराबर है		
४ पैसे " "	४०० " "	२०० ,
२ पैसे " "	५०० " "	१०० "

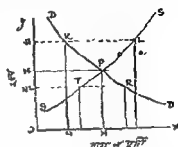
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यदि वस्तु का मूल्य १० पैसे प्रति इकाई है तो पूर्ति ५०० इकाई की है, जबकि मांग केवल १०० इकाई है। इस स्थिति में प्रत्येक विक्रेता के लिए अपनी वस्तु को बेचना सम्भव नहीं है, यदि सभी विक्रेता अपनी वस्तु को बेचना चाहते हैं तो वस्तु का मूल्य नीचा करना होगा। यदि वस्तु का मूल्य ८ पैसे प्रति इकाई है तो वस्तु की मांग २०० इकाई और पूर्ति ४०० इकाई है, अर्थात् अतिरिक्त पूर्ति २०० इकाई है। इस स्थिति में भी विक्रेताओं की पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक है, इसलिए पुनः मूल्य में कमी करनी होगी। जब वस्तु का मूल्य ६ पैसे प्रति इकाई है, उस स्थिति में मांग और पूर्ति बराबर हैं, अर्थात् इस स्थिति में न तो अतिरिक्त मांग है और न ही अतिरिक्त पूर्ति, अतः यह बिन्दु सन्तुलन बिन्दु है, क्योंकि मांग और पूर्ति की शान्ति समान है। यदि मूल्य घटकर ४ पैसे प्रति इकाई हो जाता है तो वस्तु की मांग ४०० इकाई की है, जबकि पूर्ति २०० इकाई है, इस प्रकार इस स्थिति में अतिरिक्त मांग २०० इकाई है। मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होने के कारण वस्तु का मूल्य बढ़ेगा क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु को प्राप्त करना चाहेगा, इसलिए वह अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हो जायेगा।

निष्कर्ष रूप में, हम यह कह सकते हैं कि जब वस्तु का मूल्य ६ पैसे प्रति इकाई है तब मांग व पूर्ति दोनों ३०० इकाई हैं, अर्थात् इस मूल्य पर सन्तुलन स्थापित हो जाता है। बाजार में वस्तु की कीमत न इससे अधिक होगी और न इससे कम। रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण।

मूल्य-निर्धारण को रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है—

इस बिन्दु में DD माग रेखा है तथा SS पूर्ति रेखा। II साम्य बिन्दु है, क्योंकि इस बिन्दु पर माग और पूर्ति रेखाएँ दोनों एक-दूसरे को काटती हैं। इस प्रकार PM या ON मूल्य हुआ। इस मूल्य की माग व पूर्ति OM है, अर्थात् माग व पूर्ति बराबर है।

यदि बाजार में मूल्य ON के स्थान पर ON^1 हो जाता है तो इस स्थिति में माग N^1K है तथा पूर्ति N^1L अर्थात् माग की अपेक्षा पूर्ति ($N^1L - N^1K = KL$) अधिक है। पूर्ति अधिक होने के कारण मूल्य में कमी आयेगी और मूल्य घटकर P बिन्दु पर आ जायेगा।



यदि बाजार में मूल्य ON^2 हो जाता है तो वस्तु की माग N^2R है तथा पूर्ति N^2T , अर्थात् पूर्ति की अपेक्षा माग ($N^2R - N^2T = TR$) अधिक है, माग अधिक होने के कारण मूल्य में वृद्धि होगी और मूल्य बढ़कर P बिन्दु पर पहुँच जायेगा।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि माग, पूर्ति और मूल्य में क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है। न तो केवल माग (अपवोगेण्डा) और न केवल पूर्ति (उत्पादन सापेक्ष) ही मूल्य को निर्धारित करती है, अपितु मूल्य भी वस्तु की माग और पूर्ति को प्रभावित करता है। इस प्रकार माग, पूर्ति व मूल्य तीनों परस्पर सम्बन्धित हैं। मार्शल ने इन तीनों के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए इनकी तुलना एक तन्तु की छेदों से की है। जिस प्रकार एक तन्तु के छेदों के टुकड़े का स्थान दूसरे दो टुकड़ों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार माग, पूर्ति व मूल्य परस्पर सम्बन्धित हैं।

मार्शल ने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में माग व पूर्ति की शक्तियों का यह प्रभाव रहता है कि वे सन्तुलन बिन्दु को प्राप्त कर सकें। मार्शल के अनुसार—

“मूल्य एक महाराज के बीच में पत्थर के समान होता है जो कि दोनों ओर के प्रभाव पूर्ण दबाव, अर्थात् एक ओर माग और दूसरी ओर पूर्ति की शक्तियों द्वारा साम्य बनाता है।”

- 5 “The price rests like the keystone of an arch, balanced in equilibrium between the contending pressures of its two opposing sides; demand on the one side and supply on the other.”

—Prof. Marshall

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ रिकार्डों के अनुसार 'वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से निर्दिष्ट होता है' जबकि जेवन्स के मत में यह उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है ।' इन दोनों में कौन सा मत सही है ?
- २ मार्शल के मूल्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए ।
- ३ 'जिस प्रकार हम यह नहीं कह सकते हैं कि कपड़े के टुकड़े को रूई का केवल ऊपर वाला ब्लेड या केवल नीचे वाला ब्लेड काटता है, उसी प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि मूल्य केवल उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है या अकेले उपयोगिता द्वारा ।' व्याख्या कीजिए ।
- ४ 'माग में वृद्धि से मूल्य बढ़ते हैं तथा माग में कमी से मूल्य घटते हैं ।' इस कथन की व्याख्या कीजिए ।
- ५ संतुलन मूल्य से आप क्या समझते हैं ? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मार्शल के अनुसार मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ?



अध्याय ६

★

आगम एवं लागत के विचार

[The Concepts of Revenue and Costs]

★ ★ ★

कीमत सिद्धान्त का अध्ययन करने से पहले उन सैद्धान्तिक उपकरणों (theoretical tools) की व्याख्या करना आवश्यक है जिनकी सहायता से कीमत (मूल्य) की समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। इस अध्याय में इन्हीं सैद्धान्तिक उपकरणों की व्याख्या की जा रही है।

जिस प्रकार उद्योगों का अधिकतम सतुष्टि प्राप्त कर सतुलन की अवस्था प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार एक फर्म भी उसी समय सतुलन की अवस्था में होती है जबकि वह अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त करती है। फर्म की इस सतुलनावस्था का पता दो तथ्यों की ध्यान में रखकर लगाया जाता है—(१) फर्म उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को रखकर कितनी आम (revenue) प्राप्त कर रही है, (२) उत्पादन की इन विभिन्न मात्राओं को उत्पादित करने में कितनी लागत आती है। संक्षेप में, कुल आय (total revenue) एवं कुल लागत (total cost) का पता लगाना चाहिए। कुल आय एवं कुल लागत का अन्तर ही फर्म का लाभ है। कुल लाभ जब अधिकतम होगा तब ही फर्म सतुलन की अवस्था में होगी।

कुल लागत एवं कुल आय के आधार पर सतुलन की अवस्था प्राप्त करने में कुछ त्रुटियाँ हैं, इन त्रुटियों के कारण आधुनिक अर्थशास्त्री इन रखाओं का प्रयोग नहीं करते। आधुनिक अर्थशास्त्री इन रखाओं से थोड़े रखाओं का अध्ययन करते हैं जो कि स्थिति की थोड़ी व्याख्या करती है और अधिक जानकारी प्रदान करती है। एक ओर ये औसत आय (average revenue) और सीमान्त आय (marginal revenue) का प्रयोग

करते हैं, दूसरी ओर औसत लागत (average cost) और सीमान्त लागत (marginal cost) का। ये चार चक्र मूल्य निर्धारण की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक उपकरण हैं। जिस बिन्दु पर सीमान्त आगम तथा सीमान्त लागत बराबर होते हैं उसी बिन्दु पर फर्म का सतुलन स्थापित होता है, अर्थात् फर्म सतुलनावस्था में होती है। इस बिन्दु पर ही फर्म अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त करती है।

आगम या आय का विचार (The Concept of Revenue)

आगम से अभिप्राय विप्रेता अथवा उत्पादन की आय से होता है, अर्थात् वस्तु की बिक्री द्वारा जो कुछ विप्रेता को प्राप्त होता है वह उसकी आय या आगम कहलाती है। अर्थशास्त्री आगम शब्द को तीन अर्थों में प्रयुक्त करते हैं—(१) कुल आगम, (२) औसत आगम तथा (३) सीमान्त आगम।

४ कुल आगम (Total Revenue)

विप्रेता को अपनी वस्तु की कुल मात्रा बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहते हैं, अर्थात् एक फर्म की बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल राशि कुल आगम होती है, जैसे—एक उत्पादक को वस्तु की १००० इकाइयाँ बेचने से ५००० रुपये प्राप्त होते हैं, तो कुल आगम ५००० रुपये हुआ।

कुल आगम को दूसरे प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है। वस्तु की बेची जाने वाली इकाइयों की उसकी प्रति इकाई के मूल्य से गुणा कर दिया जाये तो कुल आगम निकल आती है। इस प्रकार—

$$\text{कुल आगम} = \text{वस्तु की मात्रा} \times \text{मूल्य}$$

$$(T R) \quad (Quantity) \quad (Price)$$

२ औसत आगम (Average Revenue)

औसत आगम से अभिप्राय वस्तु की प्रति इकाई आय से है। कुल आगम में वस्तु की बेची गई इकाइयों का भाग देने से औसत आगम प्राप्त होता है, अर्थात्

$$\text{औसत आगम} = \frac{\text{कुल आगम}}{\text{कुल बिक्री की मात्रा}}$$

$$(A R)$$

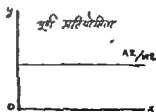
$$\text{उपरोक्त उदाहरण से औसत आगम} = \frac{5000}{1000} = 5 \text{ रुपये}$$

औसत आगम के सम्बन्ध में निम्न बातें मूल्यपूर्ण हैं—

1. औसत आगम (A.R.) तथा कीमत (Price) में कोई अन्तर नहीं होता, अर्थात् दोनों एक हैं। औसत आगम उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर वस्तु का मूल्य बताता है।
2. औसत आगम रेखा की माग रेखा (demand curve) भी कहते हैं। एक जेता किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देता है वह फर्म की दृष्टि से औसत आगम है। औसत आगम रेखा यह बताती है कि फर्म को वस्तु की विभिन्न मात्राओं के बेचने से कितना मूल्य प्राप्त होगा, अर्थात् कितनी माग प्राप्त होगी। अतः औसत आगम रेखा माग रेखा भी होती है। कुछ अर्थशास्त्री औसत आगम रेखा को विक्रय रेखा (sales curve) भी कहते हैं।
3. अपूर्ण प्रतियोगिता (imperfect competition) में औसत आगम रेखा नीचे की ओर गिरती हुई होती है। जैसा कि चित्र १ में दर्शाया गया है। गिरती हुई औसत आगम रेखा यह बताती है कि यदि कोई फर्म अपनी वस्तु को अधिक मात्रा में बेचना चाहती है तो उसे अपनी वस्तु का मूल्य नीचा निश्चित करना होगा। यदि वस्तु का मूल्य पहले से कम नहीं किया जाता है तो अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अपनी वस्तु अधिक मात्रा में नहीं बेच सकती।
4. पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम (A.R.) रेखा पड़ी हुई रेखा होती है जैसा कि चित्र २ में दर्शाया गया है। पड़ी हुई रेखा यह बताती है कि एक रुपये हुए मूल्य पर फर्म अपनी वस्तु की कितनी ही मात्रा बेच सकती है। अधिक मात्रा में वस्तु बेचने के लिए मूल्य कम कर देने की आवश्यकता नहीं होती।



चित्र-१



चित्र-२

३ सीमान्त आगम (Marginal Revenue),

किसी वस्तु की कुल माग में एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमान्त आगम कहते हैं, जैसे—वस्तु की १००० इकाइयाँ बेचने से कुल आय ५०००) रु प्राप्त होती है, तथा १००१ इकाइयाँ बेचने से कुल आय ५००४) रु प्राप्त होती है इस प्रकार सीमान्त आगम ४) रु है। दूसरे शब्दों में,

सीमान्त आगम = अतिरिक्त इकाई बेचने के पश्चात् कुल आगम —
(M R) इससे बेचने के पहले की कुल आगम

सैमुएलसन (Samuelson) आदि अर्थशास्त्रियों ने इसे निम्न सूत्र ० द्वारा व्यक्त किया है—'मान लिया कि n किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या को व्यक्त करता है, अतः nवीं इकाई की सीमान्त आय = (n-1) इकाई से n तक जाने में कुल आगम में अन्तर।' किंतु व्यवहार में कोई भी फर्म अपने उत्पादन को एक समय में केवल एक अतिरिक्त इकाई से ही नहीं बढ़ाती अथवा घटाती, अतः सीमान्त आगम को निम्न प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है—

$$\text{सीमान्त आगम} = \frac{\text{अतिरिक्त आगम}}{\text{अतिरिक्त उत्पादन}} \\ (M R)$$

अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमान्त आगम (M R) गिरती हुई रेखा होती है तथा सीमान्त आगम (M R) औसत आगम से कम होता है। इसका कारण यह है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बेचने के लिए मूल्य में कमी करनी पड़ती है, अतः सीमान्त आगम औसत आगम से कम होता है। दूसरे शब्दों में, कोई एक फर्म जब बिक्री बढ़ाने के लिए मूल्य कम करती है तो मूल्य की यह कमी केवल अतिरिक्त इकाई पर ही नहीं की जाती, बल्कि पिछली सभी इकाइयों पर की जाती है।

पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सीमान्त आगम और औसत आगम दोनों एक ही रेखा द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं। चूंकि औसत आगम रेखा पड़ी हुई रेखा होती है अतः सीमान्त आगम रेखा भी पड़ी हुई रेखा होती है, जैसा कि चित्र २ से स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि कोई एक विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता, वह उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य पर कितनी ही वस्तु बेच सकता है। अतः विक्रेता को अतिरिक्त इकाई के बेचने से जो आय प्राप्त होगी वह मूल्य (A R_n) के बराबर होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में MR=AR (अर्थात् मूल्य) होगा।

औसत आगम तथा सीमान्त आगम का दायसी सम्बन्ध

औसत एवं सीमान्त आगम के सम्बन्ध को निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट दिया गया है

विक्री की गई इकाइया	कुल आगम (T R)	औसत आगम (A R)	सीमान्त आगम (M R)
१	२०	२०	२०
२	२६	१८	१६
३	४८	१६	१२
४	६६	१४	८
५	६०	१२	४

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जैसे जैसे विक्रय की गई वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होती है वैसे-वैसे सीमान्त आगम और औसत आगम घटती जाती है परन्तु सीमान्त आगम में वृद्धि औसत आगम की अपेक्षा अधिक तेजी से आती है।

पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में सीमान्त आगम तथा औसत आगम एक ही रेखा द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं, क्योंकि वस्तु का मूल्य बाजार में समान रहता है, अर्थात् विक्रेता को अपनी वस्तु के लिये एक मूल्य मिलता है अर्थात् किन्नर २ से स्पष्ट है।

लागत का निचार

(The Concept of Cost)

किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की माग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। वस्तु की पूर्ति के पीछे उत्पादन लागत छिपी रहती है। एक दिये हुए मूल्य पर उत्पादन करतु विशेष का बितना उत्पादन करेगा यह उत्पादन लागत पर निर्भर करेगा। उत्पादन लागत को प्रायः तीन अर्थों में प्रयुक्त करते हैं—

- (१) मौद्रिक लागत या द्वाव्यिक लागत (Money cost),
- (२) वास्तविक लागत (Real cost),
- (३) अवसर लागत (Opportunity cost)।

१ मौद्रिक लागत (Money Cost)

लागत का सबसे महत्वपूर्ण रूप उत्पादन की मौद्रिक लागत होता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रो मौद्रिक लागत में तीन प्रकार की मदें शामिल करते हैं—

(अ) स्पष्ट लागतें^१ (Explicit costs)—स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जो कि एक उत्पादन स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को क्रय करने में व्यय करता है। इसमें तीन मदें सम्मिलित रहती हैं—

(१) उत्पादन लागतें—जैसे कच्चे माल की कीमत, थमिन्को की मजदूरी, प्रवचको का वेतन, उधार ली गई पूंजी का व्याज, भूमि तथा भवनों का किराया इत्यादि।

(२) विज्ञापन लागतें—विज्ञापन पर व्यय तथा बिक्री सम्बन्धी व्यय इत्यादि।

(३) अन्य लागतें—जैसे सरकार को दिया जाने वाला कर, वीमा व्यय इत्यादि।

(ब) अस्पष्ट लागतें^२ (Implicit costs)—इसके अन्तर्गत उन साधनों तथा सेवाओं का मूल्य शामिल रहता है, जिन पर उत्पादक या साहसी प्रत्यक्ष रूप से व्यय नहीं करता। दूसरे शब्दों में, साहसी को स्वयं के साधनों पर प्राप्त पुरस्कार अस्पष्ट लागतें हैं, जैसे—निजी पूंजी पर व्याज, निजी वेतन इत्यादि। व्यावहारिक जीवन में उत्पादक अस्पष्ट लागतों को प्रायः उत्पादन लागत में शामिल नहीं करते।

(स) सामान्य लाभ (Normal profit)—सामान्य लाभ, लाभ का वह स्तर है जो कि किसी उत्पादक या साहसी को उद्योग में बनाये रखने के लिये केवल पर्याप्त (just sufficient) है। यदि साहसी को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त नहीं होता तो वह दूसरे उद्योग में चला जायेगा। इस प्रकार

1 स्पष्ट लागतों को 'व्यय लागतें' (Expenditure costs) या 'भुगतान की गई लागतें' (Paid out costs) भी कहते हैं।

2 अस्पष्ट लागतों को निहित लागतें तथा अव्यय लागतें (Non expenditure costs) भी कहते हैं।

सामान्य लाभ साहसी को उद्योग विशेष में बनाये रखने की न्यूनतम लागत है।

इस प्रकार अर्थशास्त्र में मौद्रिक लागतों में स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें तथा सामान्य लाभ शामिल रहते हैं, जबकि व्यवहार में उत्पादक या एंजाइन्टेड कैबल स्पष्ट लागतों की ही मौद्रिक लागतों में जोड़ते हैं।

वास्तविक लागत (Real Cost)

वास्तविक लागत के अर्थ उन प्रयासों, श्रमों तथा त्याग से हैं, जो उत्पादन करने में उठाने पड़ते हैं। मार्शल ने वास्तविक लागत का विचार प्रस्तुत किया, उनके शब्दों में—

“किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों द्वारा बिये जाने वाले प्रयत्न तथा पूँजी व बचत के लिये आवश्यक त्याग और प्रतीक्षा, ये सब प्रयत्न तथा त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहे जाते हैं।”³

इस प्रकार वास्तविक लागत में दो बात पायी जाती हैं

- (१) श्रमिकों के शारीरिक तथा मानसिक प्रयत्न जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कार्य में लगे होते हैं
- (२) पूँजी संचय करने से समाज की उत्पन्न होने वाला कष्ट और त्याग।

इस प्रकार मार्शल की वास्तविक लागत की परिभाषा सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मार्शल ने इसे सामाजिक लागत (social cost) की संज्ञा दी है।

वास्तविक लागत के विचार की आलोचना (Criticism of the Concept of Real Cost)

वास्तविक लागत का विचार आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अमहत्वपूर्ण है। हैन्डरसन (Handerson) के शब्दों में—

“वास्तविक लागत का सिद्धान्त हमें सदेहात्मक विचार तथा अवास्तविक के दलदल में फँसा देता है।”⁴

- 3 The exertions of all the different kinds of labour that are directly or indirectly involved in making it, together with the abstinances or rather the waitings required for saving the capital used in making it, all these efforts and sacrifices together will be called the real cost of production of the commodity”

—Marshall

- 4 “The doctrine of real cost would lead into a quagmire of unreality and dubious hypothesis.”

—Handerson

इस विचार की आलोचनायें निम्नलिखित हैं—

- (१) वास्तविक लागत की माप त्याग तथा कष्ट है, परन्तु त्याग तथा कष्ट व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक विचार है, जिसकी माप करना कठिन है।
- (२) यह विचार व्यावहारिक है। व्यवहार में हम यह देखते हैं कि एक कुली या मजदूर का कष्ट या त्याग एक शिक्षक या मैनजर को अपक्षा बहुत अधिक होता है, फिर भी कुली या मजदूर को अपेक्षाकृत बहुत कम मजदूरी प्राप्त होती है।

अवसर लागत (Opportunity Cost)

आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में 'वास्तविक लागत' (real cost) अवसर लागत के रूप में व्यक्त की जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार त्याग या कष्ट को मापना सम्भव नहीं है। साधन सीमित होते हैं तथा उनके अनेक प्रयोग सम्भव हैं। साधनों की सीमितता के कारण सभी प्रयोगों में पूर्ण रूप से साधनों को प्रयुक्त करना सम्भव नहीं है। समाज की दृष्टि से साधन की किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिये लगाने का अर्थ है उसका अन्य प्रयोगों से वंचित करना। इस प्रकार किसी वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत अन्य वस्तुओं की वह भापें हैं जिनका त्याग करना पड़ता है। किसी वस्तु A की वास्तविक उत्पादन लागत (अवसर लागत) B वस्तु की त्यागी गई माना क बराबर है। इस प्रकार अवसर लागत का अर्थ दूसरे सर्वोत्तम विकल्प (next best alternative) से होता है। उदाहरणार्थ, यदि एक कृषक ५० क्विंटल चावल का उत्पादन कर रहा है, इन्हीं साधनों से वह ६० क्विंटल गेहूँ का उत्पादन कर सकता है, तो ५० क्विंटल चावल की अवसर लागत ६० क्विंटल गेहूँ है।

अवसर लागत को हस्तांतरण आय या हस्तांतरण लागत भी कहते हैं क्योंकि उत्पत्ति के साधन को उद्योग विशेष में बनाये रखने के लिये कम से कम उतना मूल्य अवश्य देना पड़ेगा जितना कि उस साधन को वैकल्पिक उद्योगों में प्राप्त होगा, अन्यथा वह साधन दूसरे उद्योग में हस्तांतरित हो जायेगा। प्रो० बेनहम (Benham) ने अवसर लागत की व्याख्या इस प्रकार की है—

- 5 अवसर लागत को वैकल्पिक लागत (alternation cost), विस्थापित लागत (displaced cost), हस्तांतरण आय (transfer earning) तथा हस्तांतरण लागत (transfer cost) भी कहते हैं।

“द्रव्य को वह माना जो कोई एक इकाई अपने सर्वोत्तम वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है उसे कभी-कभी हस्तांतरण आय भी कहते हैं।”^६

श्रीमती जोन रॉबिन्सन (Mrs. Joan Robinson) ने हस्तांतरण आय के विचार को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है—

‘वह मूल्य जो कि साधन की एक दी हुई इकाई को किसी विशेष उद्योग में बनाये रखने के लिये आवश्यक है, हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य कहा जाता है।’^७

उदाहरण के लिये, एक सीमेंट उत्पादक को अपनी फर्म चलाने के लिये श्रमिकों की आवश्यकता है, तो उसे श्रमिकों को अपनी फर्म में आकर्षित करने के लिये कम-से-कम इतनी मजदूरी देनी चाहिए जितनी कि श्रमिकों को दूसरे व्यवसायों से प्राप्त होती है। अतः सीमेंट उत्पादक के लिये श्रमिकों की अवसर लागत वह मजदूरी है जो कि श्रमिकों को अन्य व्यवसायों से प्राप्त होती है। इस प्रकार अवसर लागत से अभिप्राय उन भुगतानों से है जो कि एक व्यवसायी या उत्पादक द्वारा अपने व्यवसाय में उत्पादन के साधनों को आकर्षित करने के लिये दिये जाते हैं।

अवसर लागत का विचार सर्वप्रथम डी० एल० ग्रोन ने प्रस्तुत किया, तथापि जेवन्पोर्ट, हेडरसर तथा रॉबिन्स आदि अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रयोग किया।

अवसर लागत की विशेषतायें

अवसर लागत की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

- (१) साधन जितना अधिक विशिष्ट होगा उसकी अवसर लागत उतनी ही कम होगी।
- (२) अवसर लागत का सिद्धान्त सभी उत्पत्ति के साधनों में तथा सभी व्यवसायों में लागू होता है।

६ “The amount of money which any particular unit could earn in its best paid alternative use is sometimes called its transfer earnings”
—Benham

७ “The price which is necessary to retain a given unit of a factor in a certain industry may be called its transfer earnings or transfer price.”
—Mrs. Joan Robinson

- (३) अवसर लागत में अस्पष्ट लागतें (implicit cost) तथा स्पष्ट लागत (explicit cost) दोनों होती हैं।

अवसर लागत का महत्व (Significance of Opportunity Cost)

यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों में से एक है। इसका महत्व निम्न-लिखित बातों से स्पष्ट होता है—

- (१) उत्पत्ति के साधनों के वितरण में सहायक—अवसर लागत के सिद्धान्त के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का विभिन्न उपयोगों में वितरण होता है क्योंकि यह सिद्धांत व्याख्या करता है कि साधन को एक प्रयोग में कम-से-कम इतना अवयव मिलना चाहिए जितना कि उसे वैकल्पिक उपयोगों में प्राप्त होता है।
- (२) लागत में परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालता है—प्रो० वेनहम के अनुसार यह सिद्धान्त इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी उद्योग में उत्पादन की लागत किस सीमा तक उसके उत्पादन के साथ साथ बदल सकती है।
- (३) लगान मापन में सहायक—आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार लगान अवसर लागत पर आश्रित (surplus) है, अर्थात् किसी साधन का लगान उसकी वास्तविक आय और अवसर लागत का अन्तर है। उदाहरणार्थ, यदि एक श्रमिक को एक व्यवसाय में २०० रुपये प्राप्त होते हैं, और उसकी अवसर लागत १७५ रुपये है तो उसका लगान २५ रुपये ($200 - 175 = 25$) होगा। इस प्रकार यह सिद्धांत लगान ज्ञात करने में सहायता प्रदान करता है।

अवसर लागत की सीमाएँ व आलोचनाएँ (Limitations and Criticism of Opportunity Cost)

अवसर लागत की सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) यह विचार विशिष्ट साधनों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता, विशिष्ट साधन वह साधन है जिसका केवल एक ही प्रयोग सम्भन है, अतः विशिष्ट साधनों की अवसर लागत शून्य होती है। ऐसे साधनों के प्रयोग के लिए जो मूल्य प्राप्त होता है वह लगान होता है। व्यवहार में अविशेष साधन आंशिक रूप से विशिष्ट तथा आंशिक

रूप से अवशिष्ट होते हैं। अतः इनमें पुरस्कार लगान एवं अवसर लागत दोनों होते हैं।

- (२) यह विचार पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जबकि व्यवहार में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पायी जाती।
- (३) पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता अल्प-हारिक है।
- (४) यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन किसी कार्य के लिए कोई विशेष रुचि या गन्तव्य (preference) नहीं रखते, किन्तु यह मान्यता गलत है।

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद अर्थशास्त्र में अवसर लागत का सिद्धान्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

कुल, औसत और सीमान्त लागत (Total, Average and Marginal Cost)

- (१) कुल लागत (Total cost)—कुल लागत से अभिप्राय कुल भौतिक लागत से है जो किसी के उत्पादन में आती है। दूसरे शब्दों में, किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन में जो कुछ भौतिक व्यय करता पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं।
- (२) औसत लागत (Average cost)—कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है उसे औसत लागत कहते हैं। औसत लागत किसी वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत है। दूसरे शब्दों में—

$$\text{औसत लागत} = \frac{\text{कुल लागत}}{\text{उत्पादन की मात्रा}}$$

(उदाहरणार्थ, यदि १० इकाइयों की कुल उत्पादन लागत ५०) रु है तो औसत लागत (प्रति इकाई लागत) = $\frac{50}{10} = 5$ रु होगी।

- (३) सीमान्त लागत (Marginal cost)—सीमान्त लागत अन्तिम इकाई अर्थात् सीमांत इकाई के उत्पादन की लागत है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु के कुल उत्पादन में एक इकाई की कमी या वृद्धि करने में कुल लागत में जो कमी या वृद्धि होती है उसे सीमान्त लागत कहते हैं, जैसे—१० इकाइयों पर लागत ५०) रु आती है, यदि एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत बढ़कर ५५) रु हो जाती है तो सीमान्त लागत ५) रु ($55 - 50 = 5$) होगी।

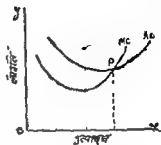
कुल, औसत एवं सीमान्त लागतों को निम्न तालिका से भी स्पष्ट किया जा सकता है—

उत्पादन की इकाइयों की संख्या	कुल लागत (TC)	औसत लागत (AC)	सीमान्त लागत (MC)
१	१०	१०	१०
२	१८	९	८
३	२४	८	६
४	२८	७	४
५	३४	६.८	६
६	४२	७	८
७	५२	७.४	१०

यदि उपर्युक्त तालिका को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो हम कुल लागत, औसत लागत एवं सीमान्त लागत वक्र प्राप्त हो जायेंगे।

मूल्य विश्लेषण में कुल लागत की धारणा महत्वपूर्ण नहीं है। सीमान्त लागत और औसत लागत का विचार सीमान्त आगम तथा औसत आगम के समान महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जब औसत लागत घटती है तो सीमान्त लागत भी घटती है और जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमान्त लागत भी बढ़ती है। परन्तु सीमान्त लागत में कमी या वृद्धि औसत लागत में कमी या वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है। सीमान्त लागत एवं औसत लागत के सम्बन्ध को रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है।

समस्त चित्र से स्पष्ट है कि जब औसत लागत वक्र (AC) नीचे की ओर खिसकता है तब सीमान्त लागत वक्र (MC) इसके नीचे ही रहता है, जब औसत लागत वक्र ऊपर की ओर उठता है तब सीमान्त लागत वक्र इससे भी अधिक ऊपर उठ जाता है। स्पष्ट है कि सीमान्त लागत वक्र उसी से नीचे की ओर गिरता है और उठने से ऊपर की ओर उठ जाता है। सामान्यतः सीमान्त लागत वक्र (MC) औसत लागत वक्र (AC) को उसके निम्नतम बिन्दु पर काटता है।



सामान्यतः सीमान्त लागत एवं औसत लागत वक्रों की आकृति मारेजी के अक्षर U के समान होती है। लागत वक्रों की प्रवृत्ति उत्पादन के विभिन्न स्तर पर नीचे की ओर हो जाने की गहरी होती अर्थात् ऊपर उठने की भी होती है, फलस्वरूप दोनों लागत वक्रों की आकृति U आकार की हो जाती है।

स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत (Fixed and Variable Cost)

कूल लागत को मारशल ने दो भागों में विभक्त किया है—

- (१) स्थिर लागत या पूरक लागत (Fixed cost or Supplementary cost),
- (२) परिवर्तनशील लागत या प्रमुख लागत (Variable cost or Prime cost)।

- (१) **स्थिर लागत या पूरक लागत**—स्थिर लागत वह लागत है जो कि उत्पादन के स्थिर साधनों पर व्यय की जाती है। स्थिर साधन से अभिप्राय उन साधनों से है जिनकी मात्रा उत्पादन में परिवर्तन होने से बहुत शीघ्रता से परिवर्तित नहीं होती। दूसरे शब्दों में, वह लागत जो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर घटती या बढ़ती नहीं है, स्थिर लागत है। प्रो बेन के अनुसार—

“स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कूल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्णतया अपरिवर्तित रहती है।”

- ४ स्थिर लागतों को सामान्य लागत (general costs), पूरक लागत (supplementary costs), अप्रत्यक्ष लागत (indirect costs) तथा उपरिब्यय लागत (over-head costs) भी कहते हैं।

सक्षेप में, यदि उत्पादन की मात्रा दाय है तो भी स्थिर लागत घनात्मक होती है, अर्थात् यदि अल्पकाल में उत्पादन वृद्धि भी हो जाता है फिर भी स्थिर लागत में सामान्यतः निम्नांकित व्यय सम्मिलित रहते हैं—

- (a) प्रारम्भिक व्यय,
- (b) स्थिर पूँजी के व्यय,
- (c) व्यवस्थापकों का वेतन,
- (d) श्रावण पत्रों पर व्याज,
- (e) घिसावट व्यय,
- (f) बीमा किस्त आदि पर व्यय ।

- (२) परिवर्तनशील लागत या प्रमुख लागत—परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो कि उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर व्यय की जाती है, अर्थात् वह लागत है जो कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ-साथ घटती बढ़ती रहती है। दूसरे शब्दों में, जब उत्पादन बढ़ता है प्रमुख लागत बढ़ जाती है तथा जब उत्पादन घटता है प्रमुख लागत घट जाती है ।

प्रो बेन के शब्दों में—“परिवर्तनशील लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ-साथ परिवर्तित होती हैं।”⁹

सक्षेप में, जब उत्पादन शून्य होता है तो लागत भी शून्य होती है । परिवर्तनशील लागत में निम्न व्यय सम्मिलित रहते हैं—

- (a) श्रमिकों की मजदूरी,
- (b) कच्चे माल का मूल्य,
- (c) यन्त्रों की घिसावट का व्यय,
- (d) ईंधन पर व्यय आदि ।

इस प्रकार परिवर्तनशील लागत विभाज्य साधनों (divisible factors) का व्यय है तथा स्थिर लागत अविभाज्य साधनों (indivisible factors) का व्यय । यदि स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों को जोड़ दिया जाय तो कुल लागत प्राप्त हो जाती है ।

9 परिवर्तनशील लागतों की प्रमुख लागत (prime cost) प्रत्यक्ष लागत (direct cost) अस्थिर लागत तथा विशेष लागत (special cost) भी कहते हैं ।

10 “Variable costs are the costs that vary with the amount of output”
— Prof Ben

स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें

- (१) उत्पादन स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों के योग का परिणाम है ।
- (२) परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन उत्पादन में परिवर्तन होने पर होते रहते हैं जबकि स्थिर लागत का उत्पादन से सम्बन्ध नहीं होता ।
- (३) परिवर्तनशील तथा स्थिर लागतों के बीच अन्तर केवल अल्पकाल में ही लागू होता है । दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं ।
- (४) प्रो. मार्शल के अनुसार स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अन्तर किस्म का नहीं है अपितु केवल धरा (degree) का अन्तर है ।
- (५) स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों के बीच अन्तर की कोई निश्चित तथा स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती । कुछ लागतें स्थिर तथा परिवर्तनशील दोनों प्रकार की होती हैं ।

मूल्य-निर्धारण में स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत का महत्व (Significance of Prime and Supplementary Cost in the Theory of Value)

मूल्य निर्धारण में दोनों लागतों का बहुत महत्व है । अल्पकाल में जबकि मूल्य पर माग का प्रभाव अधिक होता है, यह सम्भव है कि उत्पादक को अपनी वस्तु का मूल्य कुल लागत के बराबर प्राप्त न हो रहा हो । यदि अल्पकाल में उसे वस्तु का मूल्य परिवर्तनशील लागत के बराबर प्राप्त हो जाता है तो वह अपना उत्पादन कार्य जारी रखेगा क्योंकि उसे आशा रहती है कि भविष्य में उसकी स्थिर लागत भी निकल आयेगी । अर्थात् अल्पकाल में वह स्थिर लागत की अधिक चिन्ता नहीं करता । परन्तु यदि वस्तु का मूल्य इतना गिर जाय कि उत्पादक परिवर्तनशील लागत के बराबर मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे तो उसे अपने उत्पादन को प्रन्द कर देना पड़ेगा । अतः अल्पकाल में उत्पादक अधिक से अधिक हानि स्थिर लागत के बराबर सहन कर सकता है । दूसरे शब्दों में, अल्पकाल में वस्तु का मूल्य परिवर्तनशील लागत से कम नहीं होगा ।

दीर्घकाल में उत्पादक अपनी वस्तु का मूल्य कम से कम इतना अवश्य प्राप्त करेगा कि उसकी कुल लागत (स्थिर लागत + परिवर्तनशील लागत) निकल आये । यदि दीर्घकाल में कुल लागत के बराबर मूल्य प्राप्त नहीं होगा तो वह उत्पादन बन्द कर देगा । अतः दीर्घकाल में स्थिर व परिवर्तनशील लागत में भेद करने का कोई महत्व नहीं है ।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ औसत आगम तथा सीमान्त आगम में सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए ।
- २ कल लागत, सीमान्त लागत तथा औसत लागत का वर्णन कीजिए तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध को समझाइए ।
- ३ वास्तविक लागत तथा अवसर लागत में अंतर समझाइए तथा अवसर लागत के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।
- ४ स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत के अंतर को बताइए तथा समझाइए कि मूल्य निर्धारण में इनका क्या महत्व है ।
- ५ मौद्रिक लागत एवं वास्तविक लागत की व्याख्या कीजिए ।

अध्याय १०

★

पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण [Price Determination Under Perfect Competition]

★ ★ ★

अर्थशास्त्र में मूल्य निर्धारण का अर्थ उस मूल्य का पता लगाने से होता है जो कि साम्य की दशा में बाजार में प्रचलित होता है। इस प्रकार ज्ञात किया जाने वाला मूल्य साम्य मूल्य (equilibrium price) होगा। प्रो० मेहता के अनुसार—

“मूल्य-निर्धारण का उद्देश्य साम्य मूल्य का पता लगाना होता है, अर्थात् इस बात का पता लगाना कि वह कौनसा मूल्य है जो एक बार बाजार में प्रचलित होने के बाद अपने आपको बनाये रखता है।”^१

परिभाषा (Definition)

साधारणतया पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय श्रेताओं और विनंताओं के बीच पूर्ण प्रतिस्पर्धा से होता है जिसके फलस्वरूप वस्तु के मूल्य में एकरूपता आती है। थोमसी जोन रॉबिन्सन (Mrs Joan Robinson) के अनुसार—

“पूर्ण प्रतियोगिता उस स्थिति में होती है जहाँ प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की माग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका आशय है कि प्रथम विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे किसी एक उत्पादक की उपज कुल उपज का एक बहुत

1 “The object of price determination, therefore, is to find out the equilibrium price, that is, to find out which particular price would maintain itself once it rules in the market”

ही थोड़ा भाग होती है, तथा द्वितीय क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है।”^२

संक्षेप में, पूर्ण प्रतियोगिता के लिये निम्न दशाया का पूरा होना आवश्यक है —

- (१) **बेताओं और बिचताओं की अधिक संख्या**—पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई एक क्रेता या विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ रहे। इसका अर्थ है कि एक विक्रेता कुल उत्पादन का छोटा सा भाग बेचता है तथा एक क्रेता कुल माग का छोटा-सा अंश कर सकता है।
- (२) **समरूप (Homogeneous) वस्तु का होना** तथा वस्तु विभेद की पूर्ण अनुपस्थिति—पूर्ण प्रतियोगिता में बिचने की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ एक ही होनी चाहिए। वस्तु के आकार, रंग, रूप, गुण आदि में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए, जिससे क्रेता किसी भी बिचता से वस्तु को खरीद सकें। बिचताओं द्वारा प्रमाणीकृत (standardised) वस्तुएँ बेची जाती हैं, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में गैर-मूल्य प्रतियोगिता (non price competition) नहीं पायी जाती। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में बिचने लागत (selling cost) का अभाव रहता है।
- (३) **फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बाहिर्गमन**—पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को उद्योग में प्रवेश या बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इसके कारण कोई भी फर्म एकाधिकार की स्थिति में नहीं आ पाती। साथ ही सभी फर्मों को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यदि किसी उद्योग विशेष में अधिक लाभ प्राप्त होता है तो नयी नयी फर्में उस उद्योग में प्रवेश करने लगती हैं, जिसके कारण पूँति बढ़ जाती है और मूल्य घटकर लागत के बराबर हो जाता है।
- (४) **बेताओं एवं बिचनेताओं की पूर्ण जानकारी**—पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थितियों की पूर्ण जानकारी होती है। इस कारण कोई भी विक्रेता प्रचलित मूल्य से कम मूल्य पर अपनी वस्तु नहीं बेचता तथा कोई क्रेता

2 “Perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. This entails, first, that the number of sellers is large, so that the output of any one seller is a negligibly small proportion of the total output of the commodity, and second, that the buyers are all alike in respect of their choice between rival sellers so that the market is perfect.”

किसी वस्तु के लिये अधिक मूल्य नहीं देता। अतः बाजार में वस्तु विशेष का एक ही मूल्य प्रचलन में होता है।

(६) उत्पत्ति ■ साधनों की पूर्ण गतिशीलता—पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में स्वतन्त्रतापूर्वक आ-जा सकते हैं। उद्योग पूर्ण गतिशीलता के कारण ही साधनों का हिस्सा (प्रतिफल) उनकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होगा।

(७) परिवहन लागतों का अभाव—पूर्ण प्रतियोगिता में यह मान लिया जाता है कि भिन्न-भिन्न जगहों पर एक-दूसरे के बहुत निकट स्थित होती हैं, अतः परिवहन लागत नहीं होती। इस प्रकार बाजार में वस्तु का मूल्य एक ही होगा। मार्शल के अनुसार यदि वस्तु की लागत में अन्तर परिवहन लागत के अन्तर के बराबर है, फिर भी बाजार पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहा जायेगा।

पूर्ण प्रतियोगिता की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का पता लगता है जो निम्न प्रकार हैं —

(१) पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का बाजार में एक मूल्य होता है। इसका अर्थ है दीर्घकाल में सभी विक्रेता एक ही मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं तथा जैसा एक ही मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं।

(२) पूर्ण प्रतियोगिता में एक विक्रेता (अथवा कर्म, के लिये) माग पूर्णतया लोच-सार होती है। दीर्घकाल में वस्तु का एक मूल्य होने के कारण माग रेखा OX रेखा के समानान्तर होता है, अर्थात् मूल्य का थोड़ा-सा परिवर्तन माग में अनपेक्षित परिवर्तन उत्पन्न कर देता है।

(३) पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय (AR) तथा सीमान्त आय (MR) बराबर होती है क्योंकि विक्रेता वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचता है अतः किसी की माग में कमी या वृद्धि होने पर मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता।

(४) पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन तथा मूल्य के विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वस्तु विभेद (product differentiation) नहीं होता तथा ज्ञेताओं और विक्रेताओं का बाजार की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रतियोगिता में किसी व्यय नहीं होता।

(५) साधनों में पूर्ण गतिशीलता रहती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पत्ति के साधनों की सीमान्त उत्पादकता समान रहती है।

- (६) पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म स्वयं अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारण करने की स्थिति में नहीं होती, बल्कि उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य को ग्रहण कर लेती है।

विशुद्ध प्रतियोगिता एवं पूर्ण प्रतियोगिता (Pure Competition and Perfect Competition)

प्रो चेम्बरलिन (Chamberlin) ने विशुद्ध प्रतियोगिता एवं पूर्ण प्रतियोगिता में अन्तर किया है। उनके अनुसार विशुद्ध प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार के एकाधिकारी तत्व का अभाव पाया जाता है। विशुद्ध प्रतियोगिता के लिये तीन बातें होनी चाहिए —

- (१) क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या।
- (२) वस्तु की समरूपता।
- (३) फर्मों की प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतन्त्रता।

विशुद्ध प्रतियोगिता में उपर्युक्त तीन शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में इन तीन शर्तों के अतिरिक्त निम्न तीन बातें और सम्मिलित होनी चाहिए —

- (१) क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए,
- (२) उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए तथा
- (३) परिवहन लागतें नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार 'पूर्ण प्रतियोगिता' शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में तथा 'विशुद्ध प्रतियोगिता' शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है।

अमेरिकी अर्थशास्त्री 'विशुद्ध प्रतियोगिता' में कम मान्यतायें देने के कारण इसी शब्द को प्राथमिकता देते हैं, जबकि ब्रिटिश अर्थशास्त्री 'पूर्ण प्रतियोगिता' शब्द को महत्व देते हैं। मूल्य निर्धारण में प्रायः 'पूर्ण प्रतियोगिता' को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग विस्तृत अर्थ में होता है।

फर्म का साम्य (Equilibrium of the Firm)

आधुनिक अर्थशास्त्री किसी वस्तु के मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण को 'फर्म के साम्य' के शब्दों में व्यक्त करते हैं।³

- 3 मार्शल तथा अन्य प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने उद्योग में निर्धारित मूल्य तथा उत्पादन पर ही अधिक जोर दिया है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री व्यक्तिगत फर्म की मूल्य तथा उत्पादन नीति को ही महत्व प्रदान करते हैं तथा इसे वे 'फर्म के साम्य' के रूप में व्यक्त करते हैं।

फर्म साम्य की अवस्था में उस समय होती है जबकि उसको लाभ अधिकतम प्राप्त हो रहा हो। जिस मात्रा का उत्पादन करने में लाभ अधिकतम होता है उसे साम्य उत्पादन कहते हैं। साधारणतया 'साम्य' का अर्थ 'परिवर्तन की अनुपस्थिति' से होता है। किसी फर्म में 'परिवर्तन की अनुपस्थिति' उस अवस्था में होगी, जबकि उत्पादन में परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन में परिवर्तन उस अवस्था में नहीं होगा जबकि फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो। इस प्रकार साम्य-अवस्था में फर्म उस मात्रा का उत्पादन करती है जिसमें कुल लाभ अधिकतम हो।

प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। अधिकतम लाभ या अधिकतम शुद्ध आय (maximum net revenue) अथवा एक फर्म की साम्य की स्थिति को व्यक्त करने की दो रीतियाँ हैं—

१ कुल लागत तथा कुल आयम रेखाओं की रीति (total revenue and total cost curves approach)।

२ सीमान्त तथा औसत रेखाओं की रीति (marginal and average curves approach)।

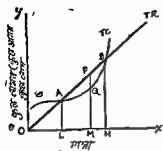
फर्म III साम्य की मान्यताएँ (Assumptions) :

दोनों ही रीतियों द्वारा व्याख्या करते समय अर्थशास्त्री कुछ मान्यताएँ लेकर चलते हैं, उसमें से प्रमुख मान्यताएँ इस प्रकार हैं—

- (१) प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है।
- (२) प्रत्येक उत्पादक वा प्रयत्न अपनी लागत को न्यूनतम करने का होता है।
- (३) एक फर्म केवल एक ही वस्तु (identical commodity) वा उत्पादन करती है।
- (४) प्रत्येक उत्पादक के साधन की इकाईयाँ समान होती हैं।

कुल लागत तथा कुल आयम रेखाओं की रीति (Total Revenue and Total Cost Curves Approach) :

इस रीति द्वारा एक फर्म साम्य की अवस्था में उस समय होती है जबकि कुल लागत तथा कुल आयम का अन्तर अधिकतम होता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादन की जिस मात्रा पर कुल आयम और कुल लागत का अन्तर अधिकतम होगा वही पर फर्म को लाभ



अधिकतम प्राप्त होगा, तथा वही अवस्था फर्म के लिये साम्य की अवस्था होगी। इस रीति द्वारा फर्म के साम्य की अवस्था को ज्ञात करने के लिए कुल आगम रेखा (T.R. Curve) तथा कुल लागत रेखा (T.C. Curve) का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है।

समान चित्र में TR रेखा कुल आगम रेखा तथा TC कुल लागत रेखा है। जब फर्म OM मात्रा का उत्पादन करती है तब TR तथा TC के बीच की दूरी PQ सबसे अधिक है, अर्थात् इस बिन्दु पर उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इस अवस्था में फर्म साम्य की स्थिति में होगी। यदि फर्म OL मात्रा का उत्पादन करती है तो कुल लाभ शून्य होगा, क्योंकि इस बिन्दु पर TC तथा TR बराबर हैं, इसी प्रकार ON मात्रा का उत्पादन करने पर भी शून्य लाभ ही प्राप्त होगा, अर्थात् दोनों ही स्थितियों में सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी है। इन दोनों बिन्दुओं (A तथा B) को 'Break Even Points' कहते हैं। L तथा N के बीच उत्पादन के किसी भी स्तर पर फर्म को लाभ प्राप्त होगा। यदि OL से कम या ON से अधिक उत्पादन किया जाता है तो फर्म को हानि प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में कुल लागत (TC) कुल आगम (TR) से अधिक है।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस रीति की आलोचना की है और इसे भद्दी रीति (cumbersome approach) बताया है। इनके अनुसार

- (१) कुल आगम तथा कुल लागत के बीच की दूरी को एक दृष्टि डालकर सरलतापूर्वक पता नहीं लगाया जा सकता।
- (२) एक ही दृष्टि में प्रति इकाई मूल्य ज्ञात करना भी कठिन है।

सीमान्त तथा औसत रेखाओं की रीति (Marginal and Average Curves Approach)

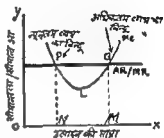
आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कुल लागत तथा कुल आगम रीति में कुछ कमियां होने के कारण उसकी आलोचना की तथा सीमान्त तथा औसत रेखाओं द्वारा फर्म के साम्य की अवस्था ज्ञात करने पर जोर दिया।

- (१) फर्म का साम्य—आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक फर्म साम्य की अवस्था में उभर समय होती है जबकि उसमें न तो विस्तार की प्रवृत्ति होती है और न ही

संबुध्ति की। यह उसी अवस्था में सम्भव है जबकि फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो। अधिकतम लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जबकि फर्म में सीमान्त लागत (marginal cost) तथा सीमान्त आगम (marginal revenue) बराबर हो। अतः फर्म के साम्य की दशा यह है जहाँ पर $MR = MC$ के हो।

इसे चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं।

समान चित्र में Q बिन्दु पर MR और MC बराबर है इस बिन्दु पर OM मात्रा का उत्पादन होता है। फर्म इस बिन्दु से न तो अधिक उत्पादन करेगी और न कम, क्योंकि यदि MR अधिक है MC से। तो फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि करके अपने कुल लाभ में वृद्धि कर सकेगी। यदि MR कम है MC से तब फर्म उत्पादन की मात्रा में कमी कर देती है, क्योंकि इस स्थिति में अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत इस इकाई से प्राप्त होने वाली माय की अपेक्षा अधिक होती है।



(२) सीमान्त लागत रेखा (MC) सीमान्त आगम रेखा (MR) को नीचे से काटती है—साम्य की अवस्था में MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटती है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि यदि फर्म अपने उत्पादन को P बिन्दु में, अर्थात् ON मात्रा में घटाती है तो सीमान्त लागत (MC) घटती जाती है तथा L बिन्दु के बाद पुनः बढ़ने लगती है। MC रेखा उत्पादन की मात्रा N से M तक से MR रेखा के नीचे रहती है, अर्थात् N से M तक के क्षेत्र में फर्म उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करके अपने लाभ को अधिकतम कर सकती है। इस प्रकार Q बिन्दु पर उसे अधिकतम लाभ होगा, इसी बिन्दु पर MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटती है।

आ साम्य की अवस्था के लिए आवश्यक है कि फर्म में MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटे।

(३) पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की मांग रेखा पड़ी हुई रेखा होती है—पूर्ण प्रतियोगिता में मांग रेखा, अर्थात् AR एक पड़ी हुई रेखा होती है तथा सीमान्त आगम (MR) और औसत आगम (AR) बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म स्वयं अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने की स्थिति में नहीं होती वह मूल्य ग्रहण करती है, अर्थात् उद्योग में वस्तु की कुल पूर्ति तथा कुल माय द्वारा जो मूल्य निर्धारित होता है उसे प्रत्येक फर्म दिया हुआ मान लेती है, इसीलिए AR रेखा प्रत्येक फर्म में पड़ी हुई रेखा होती है।

पट्टी हुई AR रेखा से यह भी अर्थ है कि एक दिए हुये मूल्य पर एक फर्म अपनी वस्तु को कितनी ही मात्रा में बेच सकती है।

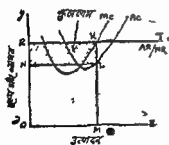
अल्पकाल में फर्म का साम्य या अल्पकाल में मूल्य निर्धारण (Equilibrium of a firm in the Short Period or Price Determination Under Short Period)

स्टिग्लर (Stigler) का अनुसार—“अर्थशास्त्री अल्पकाल का अर्थ साधारणतया उस समयावधि से लगाते हैं जिसमें वर्तमान प्लांटों से पूर्ण दर घटाई-वढाई जा सकती है परन्तु प्लांटों की संख्या व उनके आकार यथास्थित रहते हैं।”⁴

अतः अल्पकाल में इतना समय नहीं मिलता कि वस्तु की पूर्ति को घटा-वढाकर माग के अनुरूप किया जा सके।

पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म मूल्य निर्धारक न होकर मूल्य ग्रहण करने वाली होती है, फर्म की अपनी कोई मूल्य नीति नहीं होती इसीलिए फर्म को उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही अपने उत्पादन को समायोजित करना होता है। अल्पकाल में इतना समय नहीं होता कि फर्म अपनी वस्तु के उत्पादन को घटा-वढाकर माग के अनुरूप कर सके, इसलिए अल्पकाल में एक फर्म का लाभ या सामान्य लाभ (क्षुब्ध लाभ) या हानि हो सकती है। इन तीनों स्थितियों की धारणा नीचे की जा रही है—

(१) अल्पकाल में लाभ की स्थिति—किसी फर्म को अल्पकाल में लाभ उस स्थिति में प्राप्त होगा जबकि औसत आगम (AR) औसत लागत (AC) से अधिक हो इसे चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है।

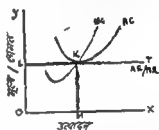


समस्त चित्र में फर्म के लिए मूल्य रेखा RT दी हुई रेखा है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म उद्योग में निर्धारित मूल्य को ग्रहण कर लेती है, स्वयं मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती। K बिन्दु साम्य बिन्दु है, क्योंकि इस बिन्दु पर सीमान्त लागत (MC) और सीमान्त आगम (MR) बराबर है, यही पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इस बिन्दु पर उत्पादन की मात्रा

4 "Economists generally describe the short run as the period within which the rate of supply from given plants is variable but the number and size of plants is fixed —Stigler

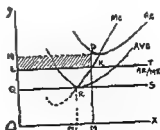
OM है। लाभ की स्थिति को ज्ञात करने के लिए औसत आगम (AR) और औसत लागत (AC) रेखाओं की दूरी ज्ञात करते हैं। उक्त चित्र में KL औसत लागत व औसत आगम रेखाओं की दूरी है, जो कि प्रति इकाई लाभ को व्यक्त करती है। इस प्रकार फर्म को कुल लाभ NLKR से ($LK \times OM = NLKR$) प्राप्त होगा।

(२) सामान्य लाभ की स्थिति—निम्न चित्र में LT मूल्य रेखा है जो कि दो हुई रेखा है। फर्म K बिन्दु पर साम्य की अवस्था में है, क्योंकि इस बिन्दु पर $MR = MC$ के है। इस अवस्था में हानि या लाभ की स्थिति की जानकारी औसत रेखाओं से करते हैं। K साम्य बिन्दु है अतः उत्पादन की मात्रा OM होगी। इस उत्पादन पर फर्म की औसत आय (AR) की रेखा औसत लागत (AC) रेखा को K बिन्दु पर स्पर्श करती है, अतः K बिन्दु पर औसत आय और औसत लागत बराबर है। चूँकि औसत लागत और औसत आय बराबर है इसलिए फर्म को कोई भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात् केवल सामान्य लाभ ही मिलेगा।



(३) हानि की स्थिति—अल्पकाल में एक फर्म को हानि भी हो सकती है, हानि उस स्थिति में होगी जबकि वस्तु की औसत लागत (AC) औसत आगम (AR) से अधिक हो। इसे चित्र से स्पष्ट किया गया है।

सलग्न चित्र में LT मूल्य रेखा है। K बिन्दु साम्य बिन्दु है, क्योंकि इस बिन्दु पर सीमान्त आगम व सीमान्त लागत बराबर है। इस प्रकार फर्म OM मात्रा का उत्पादन करेगी। हानि का पता लगाने के लिए औसत लागत (AC) तथा औसत आगम (AR) की दूरी मापना होगा। उपर्युक्त चित्र में औसत लागत रेखा मूल्य रेखा से ऊपर है, अतः हानि होगी। औसत लागत व औसत आगम की दूरी PK है, अर्थात् फर्म को एक इकाई पर हानि PK के बराबर प्राप्त होगी। उसको कुल हानि LKPN ($OM \times PK = LKPN$) होगी।



कोई भी फर्म अल्पकाल में हानि सहन करती हुई क्या उत्पादन कार्य करती रह सकती है ? इस सम्बन्ध में हमें लागतों की प्रवृत्ति को देखना होगा। कुल लागत में दो लागतें सम्मिलित रहती हैं, (अ) स्थिर लागत, (ब) परिवर्तनशील लागत। हानि को सीमा निर्धारित करने के लिए औसत परिवर्तनशील लागत (AVC) का सहारा लेते हैं। दीर्घ-काल में कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की उत्पादन लागत के बराबर प्राप्त करेगा। परन्तु अल्पकाल में, जबकि भाग वे अनुसार पूर्ति को समायोजित करना सम्भव नहीं होता, एक उत्पादक अपनी वस्तु को कुल लागत से कम मूल्य पर भी बेच सकता है। अल्पकाल में एक फर्म उत्पादक अपनी वस्तु के लिए मूल्य कम-से-कम परिवर्तनशील लागत के बराबर अवश्य प्राप्त करेगा, अन्यथा वह उत्पादन काम बन्द कर देगा। अतः कोई भी उत्पादक अल्पकाल में हानि अधिक-से अधिक स्थिर लागत के बराबर सहन कर सकता है।

चित्र में यदि मूल्य रेखा या AR रेखा QS हो जाती है तब वस्तु का मूल्य ठीक औसत परिवर्तनशील लागत (AVC) के बराबर होगा, अर्थात् RM' या OQ होगा। इस मूल्य से नीचे मूल्य पर फर्म अल्पकाल में उत्पादन बन्द कर देगी। इस बिन्दु को उत्पादन बन्द होने का बिन्दु (shut down point) कहते हैं। OM' अल्पकाल में न्यूनतम उत्पादन की मात्रा है तथा R बिन्दु से नीचे वस्तु की कोई पूर्ति नहीं होगी।

दीर्घकाल में फर्म का साम्य (Equilibrium of a Firm in the Long Period)

दीर्घकाल में समय इतना अधिक होता है कि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन पूर्णतया भाग के अनुरूप किये जा सकते हैं। अतः दीर्घकाल में कोई भी फर्म प्रतियोगिता के कारण अधिक लाभ नहीं कमा सकती और न ही कोई फर्म हानि ही उठाती है, अतः पूर्ण प्रतियोगिता में केवल सामान्य लाभ (शून्य लाभ) ही प्राप्त होता है। यदि फर्म को लाभ प्राप्त होता है, तो अन्य फर्म लाभ से आकर्षित होकर उत्पादन कार्य प्रारम्भ करेगी, परिणामस्वरूप वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होगी और कीमत (AR) घटकर लागत (AC) के बराबर हो जायेगी। यदि फर्म को हानि होगी तो अनेक फर्म उत्पादन कार्य बन्द कर देंगी, परिणामस्वरूप वस्तु की पूर्ति घट जायेगी और कीमत (AR) बढ़कर लागत (AC) के बराबर हो जायेगी। इस प्रकार दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही एक फर्म को प्राप्त होता है।

इस प्रकार दीर्घकाल में साम्य बिन्दु पर (a) सीमान्त आय (MR) = सीमान्त लागत (MC), (b) औसत आय (AR) = औसत लागत (AC) होता है। इस स्थिति को निम्नानुसार भी व्यक्त कर सकते हैं—

$$AR = MR = MC = AC$$

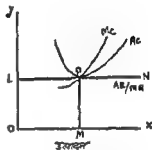
या

मूल्य (Price) = सीमान्त लागत (MC) = औसत लागत (AC)

चित्र म दीर्घकालीन साम्य की अवस्था को स्पष्ट किया गया है—

समतल चित्र म मूल्य रेखा LN है LMC दीर्घकालीन सीमान्त लागत रेखा तथा LAC दीर्घकालीन औसत लागत रेखा है। P बिन्दु साम्य बिन्दु है क्योंकि इस बिन्दु पर सीमान्त आगम (MR) तथा सीमान्त लागत (MC) दोनों बराबर है। उत्पादन की मात्रा OM है। इस प्रकार

POM वस्तु का मूल्य हुआ। P बिन्दु पर औसत लागत (AC) तथा औसत आगम (AR) बराबर है, अतः फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार दीर्घकाल की साम्य अवस्था म एक ही बिन्दु P पर सीमान्त आगम (MR) = सीमान्त लागत (MC) = औसत आगम (AR) = औसत लागत (AC) होता है।



पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग का साम्य (Equilibrium of an Industry Under Perfect Competition)

उद्योग एक ऐसी फर्मों का समूह (group) है जो एक समान वस्तु (homogeneous commodity) का उत्पादन करती है।

सैमुएलसन (Samuelson) के शब्दों में—‘पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत बहुत-सी स्पर्धात्मक फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं।’

औसती जोन रॉबिन्सन के अनुसार—‘एक उद्योग ऐसी फर्मों का समूह है जो कि केवल एक वस्तु का उत्पादन करती है।’

पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग म कोई भी फर्म इस स्थिति में नहीं होती कि वह उत्पादन म परिवर्तन करके मूल्य को प्रभावित कर सके, अर्थात् उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य ही वह ग्रहण करती है।

उद्योग की साम्य अवस्था

एक उद्योग उस समय साम्य की अवस्था में होता है जबकि इसके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता।

प्रो० बोल्डिंग के शब्दों में—'एक उद्योग साम्य की स्थिति में तब होता है जबकि उसके विस्तार या संकुचन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती।'^६

दूसरे शब्दों में उद्योग साम्य की स्थिति में तब होता है जबकि इसका कुल उत्पादन न तो बढ़ रहा हो और न ही घट रहा हो। संक्षेप में, उद्योग साम्य की स्थिति में उस समय होगा जबकि उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के बराबर हो।

अल्पकाल में साम्य उद्योग (Equilibrium of an industry in short period) —अल्पकाल में एक उद्योग साम्य की स्थिति में उस समय होता है जबकि उद्योग में कुल उत्पादन स्थिर रहता है। उद्योग की सभी फर्मों साम्य की स्थिति में होती हैं, अर्थात् सभी फर्मों साम्य की दशा ($MR=MC$) का पूरा करती हैं। अल्पकाल में यह संभव है कि एक फर्म साम्य की दशा को पूरा करती हो, फिर भी एक उद्योग में अल्पकालीन साम्य के साथ अधिक लाभ या हानि प्राप्त कर रही हो। इस प्रकार उद्योग के अल्पकालीन साम्य के साथ लाभ और हानि का सह-अस्तित्व (co-existence) हो सकता है।

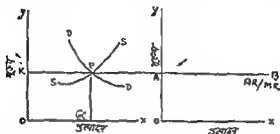
अल्पकाल में उद्योग के लिए किसी वस्तु की मांग उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग का कुल योग होता है। मांग रेखा यह प्रदर्शित करती है कि विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की कितनी मात्रा अग्र की जाती है।

सभी फर्मों की पूर्ति का योग उद्योग की पूर्ति रेखा होती है। उद्योग की पूर्ति रेखा बताती है कि विभिन्न मूल्यों पर सभी फर्मों वस्तु की कितनी मात्राएँ दे देने को तैयार हैं। इस प्रकार एक उद्योग की पूर्ति रेखा सभी फर्मों की पूर्ति रेखाओं का क्षैतिज योग है। व्यक्तिगत फर्मों की पूर्ति रेखाओं को ज्ञात करने के पश्चात् उद्योग की पूर्ति रेखा ज्ञात की जाती है।

अल्पकाल में मूल्य निर्धारण उस बिन्दु पर होता है जहाँ पर उद्योग की मांग तथा पूर्ति वक्र एक-दूसरे को काटते हैं, अर्थात् अल्पकाल में उद्योग के साम्य के लिये मांग और पूर्ति बराबर ($supply=demand$) होने हैं जैसा कि चित्र से स्पष्ट है।

6 "An industry is said to be in equilibrium when there is no tendency for it to expand or to contract" —Prof Boulding

चित्र में उद्योग की माग रेखा DD है तथा पूर्ति रेखा SS , है, ये दोनों एक-दूसरे को P बिन्दु पर काटते हैं। P उद्योग के अल्पकालीन साम्य को बताता है, क्योंकि इस बिन्दु पर उद्योग



के साम्य की दशा ($S=D$) पूरी होती है। इस प्रकार उद्योग की वस्तु की कीमत PQ या OK है तथा उत्पादन की मात्रा OQ है।

उद्योग के साथ ही फर्म की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य को ग्रहण करती है, अर्थात् प्रत्येक फर्म के लिए मूल्य रेखा ही हुई होती है। इस प्रकार AB रेखा OX के समानान्तर है, जहाँ पर बीसत आगम (AR) और सीमान्त आगम (MR) बराबर हैं। उद्योग में फर्मों की लागत रेखाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि उद्योग के अल्पकालीन साम्य के लिए प्रत्येक फर्म अल्पकालीन साम्य की स्थिति में होगी, परन्तु अल्पकालीन साम्य में लाभ या हानि का सह-अस्तित्व हो सकता है। दूसरे शब्दों में, फर्म में साम्य की दशा $MC=MR$ प्राप्त होगी, परन्तु $AC=AR$ का होना अल्पकालीन स्थिति में आवश्यक नहीं है।

दीर्घकाल में उद्योग का साम्य (Equilibrium of the Industry in the Long Period)—पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में उद्योग साम्य की अवस्था में उस समय होगा जबकि उद्योग का कुल उत्पादन स्थिर रहता है, इसमें कमी अथवा वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। दूसरे शब्दों में, उद्योग के साम्य की स्थिति में प्रत्येक फर्म की साम्य की स्थिति में होती है। पर यह उस स्थिति में सम्भव है जबकि सीमान्त लागत (MC) और सीमान्त आगम (MR) बराबर हों तथा सीमान्त लागत रेखा सीमान्त आगम रेखा को साम्य बिन्दु के ठीक नीचे से काटे।

दीर्घकाल में फर्मों की सख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता यह उस स्थिति में सम्भव है जबकि बीसत आगम (AR) और बीसत लागत (AC) बराबर हों अर्थात् फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा हो।

इस प्रकार उद्योग के दीर्घकालीन साम्य के लिए आवश्यक है कि

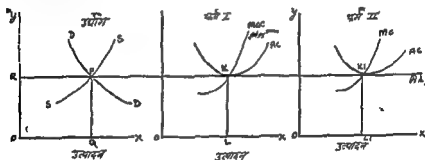
(१) $MR=MC$ (सीमांत आयम=सीमान्त लागत),

(२) $AR=AC$ (औसत आयम=औसत लागत),

की दशा में पूरी हो। दूसरे शब्दों में दीर्घकालीन साम्य के लिए अल्पकालीन साम्य भी स्थापित होना चाहिये।

दीर्घकालीन साम्य के लिए माग और पूर्ति ($D=S$) का बराबर होना भी आवश्यक है। यदि माग में परिवर्तन होता है तो उद्योग के आगार में परिवर्तन करके पूर्ति का माग से समायोजित किया जाता है। इस समायोजन में अर्थात् उद्योग से फर्मों के बहिर्गमन या प्रवेश से उत्पादन लागत में परिवर्तन होगा। लागत में परिवर्तन इस बात से प्रभावित होगी कि उद्योग बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत या घटती हुई लागतों पर स्थिर लागतों के अन्तर्गत उत्पादन कार्य कर रहा है।

दीर्घकाल में उद्योग और फर्म की साम्य की स्थिति को रेखाचित्र की सहायता से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।



उपर्युक्त चित्र में PQ मूल्य है जो कि उद्योग में निर्धारित होता है, P बिन्दु पर कुल माग व कुल पूर्ति बराबर है। PQ उत्पादन की मात्रा है। PQ या OR मूल्य की पहली तथा दूसरी फर्म दिया हुआ मान लेती है। फर्म इस दिए हुए मूल्य के आधार पर उत्पादन की मात्रा को समायोजित करती हैं। पहली फर्म OL मात्रा का तथा दूसरी फर्म OL' मात्रा का उत्पादन करती हैं। दोनों फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा में अन्तर है। पहली फर्म में K तथा दूसरी फर्म में K' साम्य बिन्दु है, यह बिन्दु दीर्घ कालीन साम्य की दोनों दशाय (१ $MR=MC$, २ $AR=AC$) पूरी करता है। इस प्रकार इस साम्य बिन्दु पर फर्म का आकार अनुकूलतम होता है क्योंकि साम्य औसत लागत रेखा के निम्नतम बिन्दु पर स्थित है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषतायें बताइये । पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण कैसे होता है ?
२. पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म के साम्य को स्पष्ट कीजिए ।
३. फर्म के साम्य से क्या अर्थ है ? पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म के साम्य की स्थिति समझाइए ।
४. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य कैसे निर्धारित होता है ।
५. 'फर्म के साम्य' एवं 'उद्योग के साम्य' में अन्तर समझाइए तथा पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत एक उद्योग के साम्य को समझाइए ।
६. उन स्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें अल्पकाल एवं दीर्घकाल में फर्म साम्य की अवस्था में होती है ।
७. इस कथन को स्पष्ट कीजिये कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म उस समय साम्य की अवस्था में होती है जबकि उसकी सीमान्त लागत (MC) सीमान्त भाग्य (MR) के बराबर होती है ।

— — — — —

अध्याय ११

★

एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण [Price Determination Under Monopoly]

★ ★ ★

एकाधिकार शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द 'Monopolein' से हुई है। 'Monopolein' का अर्थ है एक विक्रेता (single seller)। इस प्रकार एकाधिकार वह अवस्था है जिसमें वस्तु की पूर्ति पर किसी एक व्यक्ति अथवा फर्म का पूर्ण अधिकार रहता है। एकाधिकारी का वस्तु के मूल्य पर या पूर्ति पर पूर्ण नियन्त्रण रहता है तथा वह दूसरे उत्पादकों को उद्योग में प्रवेश नहीं करने देता। बाजार में केवल एक ही उत्पादक या फर्म रहने के कारण एकाधिकार में 'एक फर्म एक उद्योग' की स्थिति पायी जाती है।

जब बाजार में विक्रेताओं की संख्या दो होती है तो उसे **द्वैधिकार (duopoly)** कहते हैं। दो से कुछ अधिक विक्रेताओं की संख्या होने पर **अल्पविक्रेताधिकार (oligopoly)** की स्थिति उत्पन्न होती है।

एकाधिकार की विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषायें दी गई हैं, उनमें से कुछ उल्लेखनीय परिभाषायें निम्नलिखित हैं

प्रो० थॉमस (S E Thomas) के अनुसार—“विस्तृत अर्थ में एकाधिकार वस्तुओं तथा सेवाओं से प्रभावपूर्ण मूल्य नियंत्रण को व्यक्त करता है, चाहे वह भाग का हो या पूर्ति का समुचित रूप में इसका अर्थ उत्पादकों अथवा विक्रेताओं के ऐसे समूह से होता है जो कि वस्तुओं अथवा सेवाओं के पूर्ति मूल्य को नियंत्रित करते हैं।”¹

1 “Broadly, the term is used to cover any effective price control, whether of supply or demand, of services or of goods, narrowly it is used to mean a combination of manufacturers or merchants to control the supply price of commodities or services”

प्रो० मोल्डिंग के शब्दों में—'शुद्ध एकाधिकार वह फर्म है जो किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जिसका किसी अन्य फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में कोई प्रभाव-पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता। 'प्रभावपूर्ण' से आशय यह है कि मद्यवि एकाधिकारी असाधारण लाभ कमा रहा है, फिर भी अन्य फर्मों ऐसी स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करके, जो कि फोताओं को एकाधिकारी की वस्तु से दूर कर सकें, उक्त लाभों का अतिक्रमण नहीं कर सकती।'²

प्रो० बन्हम (Benham) के अनुसार—'एकाधिकारी वस्तु एकमात्र विज्ञेय होता है—और एकाधिकारी शक्ति वस्तु में पूर्ण नियन्त्रण पर आधारित होती है।'³

चैम्बरलिन (Chamberlin) के अनुसार—'एकाधिकार की स्थिति जो वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियन्त्रण रखती है।'⁴

स्टोनियर और हेग (Stonier & Hague) के अनुसार—'एकाधिकारी वह उत्पादक है जो किसी एक वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता।'⁵

इस प्रकार एकाधिकार की अनेक परिभाषायें दी गई हैं। इन परिभाषाओं से एकाधिकार की विशेषतायें स्पष्ट होती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं—

(१) एकाधिकारी अपनी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है।

2 "A pure monopolist, therefore, is a firm producing a product, which has no effective substitutes among the products of any other firm, 'effective' in the sense that even though the monopolist may be making abnormal profit, other firms cannot encroach in these profits by producing substitutes which might entice purchasers away from the product of the monopolist."

—K. E. Boulding

3 "A monopolist is literally a single seller and monopoly power is based entirely on control over supply"

—Prof Benham

4 "Monopoly refers to the control over supply"

—Prof Chamberlin

5 "The producer who controls the whole supply of a single commodity which has no close substitutes"

—Stonier & Hague

- (२) एकाधिकारी 'फर्म' और 'उद्योग' दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इस प्रकार एकाधिकार में एक फर्म उद्योग' (one firm industry) की स्थिति पायी जाती है।
- (३) एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई निकट स्वानापन्न वस्तु नहीं होती।
- (४) एकाधिकारी को वस्तु की मांग की लोच शून्य होनी है।
- (५) एकाधिकारी द्वारा दूसरी फर्मों के प्रवेश में प्रभावकारी रोकटोकें डाल दी जाती हैं।
- (६) एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है।

एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहने के कारण वह पूर्ति में कमी या वृद्धि करके वस्तु की मूल्य को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार एकाधिकारी की स्वयं की मूल्य नीति होती है।

एकाधिकारी का उद्देश्य (The Aim of the Monopolist)

प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। एकाधिकार में एकाधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी वस्तु को उत्पादन लागत से ऊँचे मूल्य पर बेचकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है।

प्रो० माशल के अनुसार—'अधिकतम सन्तुष्टि का सिद्धान्त एकाधिकारी वस्तुओं की मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में कमी लागू नहीं होता।'^६

एकाधिकारी का उद्देश्य "अधिकतम एकाधिकारी लाभ" (maximum monopoly gain) प्राप्त करना होता है।

माशल के ही शब्दों में—"एकाधिकारी का उद्देश्य मांग तथा पूर्ति के बीच हम प्रकार समायोजन (adjustment) करना नहीं है कि प्राप्त मूल्य से उसकी उत्पादन लागत पूरी हो जाय, अपितु इस प्रकार समायोजित करने से है कि उसे अधिकतम शुद्ध एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो।"^७

6 "The doctrine of maximum satisfaction has never been applied to the demand for and supply of monopolized commodities"

—Prof Marshall

7 "The prima facie interest of the owner of a monopoly is clearly to adjust the supply to the demand not in such a way that the price at which he can sell his commodity, shall just cover its expenses of production but in such a way as to afford him the greatest possible net revenue"

—Prof Marshall

Amal

धोमती जोन रॉबिन्सन (Mrs Joan Robinson) के अनुसार एकाधिकारी का उद्देश्य 'शुद्ध एकाधिकारी आय' (net monopoly gain) अधिकतम करना होता है। इस प्रकार एकाधिकारी का उद्देश्य प्रति इकाई लाभ को अधिकतम करना न होकर कुल लाभ को अधिकतम करना होता है।

मूल्य-निर्धारण (Value Determination)

एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियन्त्रण रहता है परन्तु क्रेताओं पर कोई नियन्त्रण नहीं रहना, अर्थात् माग पर एकाधिकारी नियन्त्रण का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार एकाधिकारी मूल्य तथा पूर्ति दोनों पर एक साथ नियन्त्रण नहीं रख सकता। यदि वह पूर्ति पर नियन्त्रण रखता है तो उसे माग की स्थिति के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारित करना होगा। यदि मूल्य पर नियन्त्रण रखता है तो श्रम-निर्धारित मूल्य पर वस्तु की जितनी माग होगी उसके अनुसार पूर्ति की मात्रा निश्चित करेगा। सामान्य रूप से एकाधिकारी पूर्णता और मूल्य में से मूल्य को ही चुनता है अर्थात् वह वस्तु का मूल्य निर्धारित कर देता है, उस मूल्य पर वस्तु की जितनी माग होती है उसके अनुसार वह वस्तु की पूर्ति निश्चित कर देता है।

एकाधिकार में मूल्य-निर्धारण अथवा सन्तुलन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है —

- (१) प्रो० मार्शल की रीति (Prof Marshall's method),
- (२) आधुनिक रीति (Modern method)।

प्रो० मार्शल की रीति (Prof Marshall's Method)

मार्शल के अनुसार एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारण 'माप और मूल्य' (trial and error) सिद्धान्त के आधार पर करता है। प्रो० मार्शल ने बताया कि एकाधिकारी को यह ज्ञात नहीं होता कि किस मूल्य पर उसे लाभ सबसे अधिक प्राप्त होगा। अतः वह अपनी वस्तु के भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारित कर प्राप्त होने वाले लाभों की तुलना करता है और जिस मूल्य पर उसे 'अधिकतम एकाधिकारी लाभ' प्राप्त होता है। उसी मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचता है तथा उत्पादन की मात्रा निश्चिन कर देता है। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए उसे अनेक बार मूल्य में परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए मार्शल के इसे 'माप और मूल्य' सिद्धान्त कहा गया है।

मार्शल के अनुसार एकाधिकारी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय दो बातों का ध्यान रखता है :—

(१) वस्तु की माग की लोच (Elasticity of demand),

(२) उत्पत्ति के नियम (Laws of returns) ।

(१) वस्तु की माग की लोच (Elasticity of demand)—एकाधिकारी मूल्य निर्धारित करते समय सबसे प्रथम वस्तु की माग की लोच की ओर ध्यान देता है ।

(a) यदि एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की माग लोचदार है तो वह वस्तु का मूल्य नीचा निश्चित करता है, क्योंकि वस्तु का मूल्य ऊँचा निश्चित करने से वस्तु की माग में मूल्य के उत्पात से अधिक कमी आ जायेगी । अतः लोचदार माग की स्थिति में एकाधिकारी वस्तु का मूल्य नीचा निर्धारित करके अपने कुल लाभ में वृद्धि करता है ।

(b) यदि एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की माग की लोच बेलोचदार है तो वस्तु के परिवर्तन का माग पर प्रभाव नहीं पड़ता है । अतः ऐसी स्थिति में एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य ऊँचा निश्चित कर अधिक लाभ प्राप्त करता है ।

(c) जब वस्तु की माग में इकाई लोच (unit elasticity) होती है, तब वस्तु का मूल्य में परिवर्तन से उपभोक्ताओं द्वारा किये जाने वाले कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात् कुल व्यय स्थिर रहता है । ऐसी स्थिति में एकाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य को उत्पत्ति के नियम प्रभावित करते हैं ।

(२) उत्पत्ति के नियम (Laws of returns)—वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय एकाधिकारी उत्पत्ति के नियमों को भी ध्यान में रखता है ।

(a) यदि वस्तु का उत्पादन 'उत्पत्ति द्वारा नियम' के अन्तर्गत हो रहा होता है तो एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य अधिक निश्चित करता है । क्योंकि मूल्य में कमी करने से वस्तु की माग में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक होगी, जबकि उत्पत्ति द्वारा नियम के अन्तर्गत प्रत्येक अगली इकाई को उत्पन्न करने में लागत बढ़ जायेगी । अतः इस स्थिति में एकाधिकारी वस्तु का उत्पादन कम कर लाभ में वृद्धि करता है ।

• • • (b) यदि वस्तु का उत्पादन 'उत्पत्ति वृद्धि नियम' के अन्तर्गत हो रहा है तो वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना एकाधिकारी के हित में होता है, इस स्थिति में प्रत्येक अगली इकाई का उत्पन्न करने में लागत कम आती है । अतः एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 'उत्पत्ति वृद्धि नियम' की स्थिति में अपनी उत्पादित वस्तु का मूल्य नीचा निश्चित करता है ।

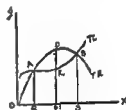
(c) यदि वस्तु का उत्पादन 'उत्पत्ति समता नियम' के अन्तर्गत हो रहा है, तब वस्तु की लागत स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में वस्तु के मूल्य का निर्णय माग की लोच पर निर्भर करता है।

मार्शल के अनुसार एकाधिकारी वस्तु की माग की लोच और उत्पत्ति के नियमों को ध्यान में रखकर ही मूल्य निर्धारित करता है। ऐसा करते समय वह 'जाच और भूल' (trial and error) के सिद्धान्त को अपनाता है।

कुल लागत तथा कुल आगम की रीति (Total Cost and Total Revenue Approach) :

कुछ विद्वानों ने मार्शल की रीति 'जाच और भूल' को समझने के लिए कुल आगम तथा कुल लागत रेखाओं का सहयोग प्राप्त किया है। इस रीति के अनुसार जिस बिन्दु पर कुल आगम (TR) तथा कुल लागत (TC) की दूरी अधिकतम होगी, वही पर एकाधिकारी का लाभ अधिकतम होगा अर्थात् एकाधिकारी साम्य की स्थिति में होगा। इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

समस्त चित्र में TC कुल लागत वक्र है तथा TR कुल आगम वक्र। यदि एकाधिकारी OR से कम या OS से अधिक उत्पादन करता है तो उसे हानि होगी क्योंकि दोनों ही स्थितियों में उसकी कुल लागत कुल आगम से अधिक है। RS के बीच उसे घनात्मक लाभ प्राप्त होगा। यदि एकाधिकारी OM मात्रा का उत्पादन करता है तो उसका लाभ अधिकतम होगा क्योंकि इस स्थिति में TR तथा TC के बीच की दूरी अधिकतम है इस बिन्दु पर ही एकाधिकारी साम्य की अवस्था में होगा। चित्र में A तथा B बिन्दु शून्य लाभ प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में कुल लागत तथा कुल आगम बराबर हैं।



प्रलोचना (Criticism) :

कुल लागत तथा कुल आगम रेखाओं की रीति भद्दी है क्योंकि :

- (१) कुल लागत तथा कुल आगम के बीच की छोटी दूरी को एक ही दृष्टि से नहीं जाना जा सकता।
- (२) इससे यह साब नहीं होता कि प्रति इकाई लागत क्या है ?

- (३) इस रीति द्वारा एकाधिकारी को यह ज्ञान नहीं होता कि वह किस मूल्य पर अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा ।

२ आधुनिक रीति (Modern Method)

‘जान और भूल’ रीति में अनेक दोष होने के कारण एकाधिकारी ने साम्य निर्धारण के लिए आधुनिक रीति का प्रयोग किया गया । इस रीति को ‘सीमान्त और औसत रेखाओं की रीति’ (marginal and average curves approach) भी कहते हैं । श्रीमती जोन रॉबिन्सन तथा अन्य आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एकाधिकारी के साम्य के लिए सीमान्त आगम (MR) और सीमांत लागत (MC) का बराबर होना आवश्यक है । एकाधिकारी साम्य की स्थिति में उस समय होगा जबकि उसका कुल उत्पादन स्थिर रहे । कुल उत्पादन में स्थिरता उसी समय सम्भव है जबकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो, अधिकतम लाभ तब तक प्राप्त होगा जबकि सीमान्त आगम (MR) और सीमान्त लागत (MC) बराबर हो ।

प्रो० नाइट (Knight) ने इसे निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है — “अधिकतम आय प्राप्त करने के लिये एकाधिकारी को अपने उत्पादन तथा विप्री की शुन्य इकाइयों से अधिक तब तक बढ़ाते रहना चाहिये जब तक एक इकाई को बढ़ाने से कुल आय में होने वाली वृद्धि इस इकाई के उत्पादन में आई लागत की वृद्धि के बराबर न हो जाय ।”

हमारे शब्दों में, एकाधिकारी को उत्पादन तथा विप्री उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि सीमान्त आय तथा सीमान्त लागत बराबर न हो जाय ।

प्रो० बौलडिंग (Boulding) ने प्रो० नाइट के उपर्युक्त कथन का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि—यदि सीमान्त आय सीमान्त लागत से अधिक होगी तब उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि कुल आय को कुल लागत से अधिक बढ़ा देगी जिसके परिणामस्वरूप ‘शुद्ध लाभ’ में भी वृद्धि हो जायेगी । यदि सीमान्त आय सीमान्त लागत से कम हुई तो उत्पादन में एक इकाई की कमी से कुल लागत कुल आय की तुलना में कम हो जायेगी, परिणामस्वरूप ‘शुद्ध आय’ बढ़ जायेगी । इस प्रकार ‘शुद्ध एकाधिकारी आय’ उसी स्थिति में अधिकतम होगी जबकि सीमान्त आय व सीमान्त लागत बराबर हो जाय है ।

४ “The monopolists should keep increasing his output and sales beyond zero unit, until the addition to the total revenue caused by adding one more unit just equals the addition to the total cost caused by adding this unit.”
—Prof Knight

मांग पक्ष—प्रो लॉर के अनुसार 'एकाधिकारी का अभिप्राय उस विक्रेता से होता है जिस पर मांग वक्र गिरता हुआ होता है।' अर्थात् एकाधिकारी के निचे अपनी वस्तु की मांग रेखा (AR) नीचे की ओर गिरती हुई होती है तथा सीमान्त आमद (MR) मूल्य रेखा (AR) से नीचे (या कम) रहता है।

गिरती हुई मांग रेखा (AR) से अभिप्राय है कि यदि एकाधिकारी अपनी वस्तु की अधिक मात्राएँ बेचना चाहता है तो उसे वस्तु का मूल्य घटाना होगा।

सीमान्त आय (MR) औसत आय (AR) से कम होती है इसका कारण यह है कि एकाधिकारी को वस्तु अधिक मात्रा में बेचने के लिए कीमत घटानी पड़ती है परिणामस्वरूप सीमान्त आय मूल्य (AR) से कम रह जाती है। एकाधिकारी मूल्य निर्धारित करते समय मांग की लोच को ध्यान में रखता है।

पूर्ति पक्ष—एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। एकाधिकार में लागत रेखाओं की प्रवृत्ति पूर्ण प्रतियोगिता के समान हो रहती है।

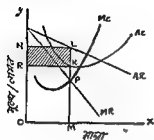
एकाधिकार में मूल्य निर्धारण को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं —

- (१) अल्पकाल में मूल्य निर्धारण या अल्पकाल में एकाधिकारी का साम्य,
- (२) दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण या दीर्घकाल में एकाधिकारी का साम्य।

१ अल्पकाल में मूल्य निर्धारण

अल्पकाल में एकाधिकारी की उत्पादन क्षमता निश्चित होती है। अर्थात् मांग में जिस अनुपात में परिवर्तन होने हैं उसी अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन करना एकाधिकारी के लिए सम्भव नहीं होता। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी को 'लाभ' या सामान्य लाभ (शून्य लाभ) प्राप्त हो सकता है तथा 'हानि' भी हो सकती है। सामान्यतः एकाधिकारी को अल्पकाल में 'हानि' या सामान्य लाभ की सम्भावना कम ही रहती है परन्तु अल्पकाल में जब एकाधिकारी की वस्तु की मांग काफी कम हो जाती है तब उसकी वस्तु की कीमत इतनी कम रह सकती है कि उसे हानि प्राप्त हो।

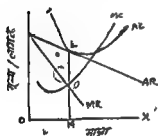
लाभ की स्थिति—एकाधिकारी को लाभ उस स्थिति में प्राप्त होगा जबकि औसत आय (AR) औसत लागत (AC) से अधिक हो। एकाधिकारी साम्य उस बिन्दु पर स्थापित होगा जहाँ पर $MR = MC$ है।



औसत लागत KM है। अतः एकाधिकारी को अपनी वस्तु बेचने से KL (LM—KM) लाभ प्राप्त होगा। कुल लाभ KLMNR होगा।

सामान्य लाभ या शून्य लाभ की स्थिति

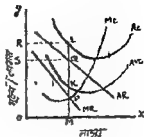
चित्र म एकाधिकारी को शून्य लाभ प्राप्त हो रहा है।



चित्र म P साम्य बिन्दु है। अतः उत्पादन की मात्रा OM निश्चित हुई। PM रेखा को ऊपर धकाया जोकि AR रेखा को L बिन्दु पर काटती है। इस बिन्दु पर औसत लागत और औसत आय बराबर हैं। इस प्रकार मूल्य LM हुआ तथा वस्तु को बेचने से प्राप्त होने वाली आय भी LM हुई। अतः एकाधिकारी को शून्य लाभ प्राप्त हुआ।

हानि की स्थिति—अल्पकाल में एकाधिकारी मूल्य औसत लागत की अपेक्षा कम हो सकता है, लेकिन यह तभी सम्भव होगा जबकि एकाधिकारी की वस्तु की माग बहुत कमजोर हो। इस स्थिति में एकाधिकारी को हानि होगी। अल्पकाल में एकाधिकारी उस समय तक उत्पादन करता रहेगा। जब तक कि उसे औसत परिवर्तनशील लागत (AVC) के बराबर मूल्य प्राप्त होता रहेगा। औसत परिवर्तनशील लागत से कम मूल्य प्राप्त होने पर एकाधिकारी उत्पादन कार्य बन्द कर देगा। अतः एकाधिकारी को अधिक से अधिक हानि औसत स्थिर लागत (AFC) के बराबर प्राप्त होगी। सामान्यतः अल्पकाल में भी एकाधिकारी के लिए हानि की सम्भावना कम रहती है।

चित्र में P बिन्दु पर सीमान्त लागत व सीमान्त आय बराबर है। इस बिन्दु से ऊपर की ओर रेखा नीचे से L बिन्दु पर ओसत लागत रेखा को स्पर्श करती है अतः LM ओसत लागत हुई। QM प्रति इकाई मूल्य है। इस प्रकार OM उत्पादन की मात्रा पर एक इकाई वेचन से एकाधिकारी को LQ ($LM - QM = LQ$) के बराबर हानि होती है। कुल हानि QLSR होगी।

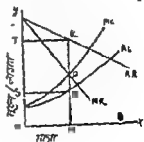


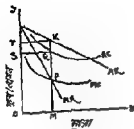
२. दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण

दीर्घकाल में एकाधिकारी को लाभ प्राप्त होता है। इस काल में एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन मांग के अनुसार कर लेता है। पूर्ति में परिवर्तन वह प्लांटों की उत्पादन क्षमता में कमी या वृद्धि करके या प्लांटों को सत्पा में कमी या वृद्धि करके करता है। दीर्घकाल में एकाधिकारी उद्योग के विस्तार या संकुचन की पूर्ण सम्भावनाओं रहती है। इसलिए उद्योग की उत्पादन लागत पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव पड़ता है। उत्पत्ति के तीनों नियमों—(i) लागत वृद्धि नियम (Law of increasing cost), (ii) लागत ह्रास नियम (Law of decreasing cost) तथा लागत स्थिरता नियम (Law of constant cost) के अन्तर्गत एकाधिकारी मूल्य तथा उत्पादन के निर्धारण को नीचे चित्रों द्वारा स्पष्ट किया गया है।

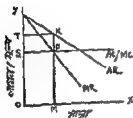
(१) लागत वृद्धि नियम—किन्नाकिन चित्र में एकाधिकारी लागत वृद्धि नियम के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। इसलिए लागत रेखाएँ नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हुई हैं।

नलम्ब चित्र में P साम्य बिन्दु है। इस बिन्दु से सीधी आन वाली लंबी रेखा मूल्य रेखा (AR) को K बिन्दु पर स्पर्श करती है। तथा OX अक्ष को M बिन्दु पर काटती है। अतः OM उत्पादन की मात्रा तथा KM वस्तु का मूल्य होगा। प्रति इकाई लागत RM है अतः एक इकाई पर लाभ KR (AR और AC का अंतर) है तथा कुल लाभ RKTS ($KR \times TS = RKTS$)।





KM मूल्य हुआ। AR तथा AC के बीच की दूरी प्रति इकाई लाभ को दर्शाती है। इस प्रकार प्रति इकाई लाभ KR (KM—RM=KR) है तथा कुल लाभ RKTs।



- (१) सापत स्थिरता नियम—एकाधिकारी सापत स्थिरता नियम के अन्तर्गत कार्य कर रहा है इसलिए इस बिजु म सापत रेखाएँ नीचे हुई रेखा के द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। P बिन्दु साम्य बिन्दु है अतः OM उत्पादन की मात्रा और KM मूल्य है। प्रति इकाई लाभ KP है तथा कुल लाभ KPST।

यदि एकाधिकारी मूल्य सदैव प्रतिस्पर्धिता मूल्य \parallel ऊँचा होता है (Is monopoly price always higher than competitive price)

साधारणतः एकाधिकारी अपनी वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धिता मूल्य से ऊँचा मूल्य होता है। एकाधिकारी अपने क्षेत्र में अकेला उत्पादक रहता है तथा उसे प्रतिस्पर्धिता का भय नहीं रहता है इसलिए वह सदैव अपने लाभ का अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि एकाधिकारी मूल्य सदैव ऊँचा होगा। वास्तव में कभी-कभी ऐसी स्थितिमा उत्पन्न हो जाती है कि एकाधिकारी मूल्य प्रतिस्पर्धिता मूल्य की अपेक्षा नीचा रह जाता है।

- (१) यदि एकाधिकारी की वस्तु की माग अधिक लोचदार है तब एकाधिकारी वस्तु का मूल्य नीचा निश्चित करता है, जिससे कि वह वस्तु की अधिक मात्राएँ उबकर कुल लाभ में वृद्धि करता है।
- (२) यदि वस्तु का उत्पादन 'सापत ह्रास नियम' के अन्तर्गत हो रहा है तो एकाधिकारी वस्तु का अधिक उत्पादन करके उसे नीचे मूल्य पर बेचना वसन्द करेगा।

(३) यदि एकाधिकारी वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर करता है जिसके फलस्वरूप उस बड़े पैमाने की वृत्तों प्राप्त होती है तब एकाधिकारी का उत्पादन व्यय घट जायेगा और वस्तु का मूल्य भी कम हो जायेगा ।

इनके अतिरिक्त एकाधिकारी शक्ति की सीमाएँ करने वाले तब भी एकाधिकारी मूल्य की नीचा करने में सक्षम होते हैं ।

एकाधिकारी शक्ति की सीमाएँ

एकाधिकारी की दृष्टि का विषय में सामान्यतः कहा जाता है—

“एकाधिकारी और मोसम में एक समानता है, आप इनके विरुद्ध बलवत् प्रस्ताव व्यक्त कर सकते हैं परन्तु कुछ बिगड़ नहीं सकते ।”

एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर लगभग पूर्ण नियन्त्रण होता है क्योंकि वह अपने क्षेत्र में अकेला उत्पादक होता है । लेकिन एकाधिकारी का वस्तु की माग पर नियन्त्रण नहीं होता । एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य इच्छानुसार ऊँचा निश्चित नहीं कर पाता क्योंकि अनेक तब एकाधिकारी शक्ति की सीमाएँ कर दते हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) विरोधी जनमत—यदि एकाधिकारी अपनी वस्तु का बहुत ऊँचा मूल्य रखता है तब उपभोक्ताओं द्वारा उस वस्तु का बहिष्कार कर दिया जाता है । अन्य जनता द्वारा बहिष्कार के भय से वह वस्तु का मूल्य बहुत ऊँचा निश्चित नहीं करता ।

(२) स्थानावधि वस्तुओं का भय—यदि एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य ऊँचा रखकर अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है तो एकाधिकारी को इस बात का भय रहता है कि अन्य उत्पादक उसकी वस्तु के स्थान पर निवृत्त स्थानापन्न का उत्पादन प्रारम्भ न कर दें ।

(३) प्रतिप्रोदितता का भय—यदि एकाधिकारी अधिक लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ से प्रभावित होकर कुछ प्रतिप्रोदित उत्पादक प्रतिद्वन्द्वी बनकर उसके क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें उसका एकाधिकार समाप्त हो सकता है य प्रतिद्वन्द्वी या तो विदेशी उत्पादक हो सकते हैं या देश के अन्दर ही उत्पन्न हो सकते हैं । इस भय के कारण ही एकाधिकारी मूल्य को अधिक ऊँचा नहीं रख पाता है ।

(४) राज्य द्वारा हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण का भय—राज्य द्वारा हस्तक्षेप व नियन्त्रण

9 “Monopoly has one thing common with the weather You may complain but you cannot do much about it”

किये जाने के भय से एकाधिकारी वस्तु का मूल्य अधिक ऊँचा निश्चित नहीं करता है। क्योंकि सरकार सामाजिक हित को ध्यान में रखकर एकाधिकारी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण लगा सकती है या एकाधिकारी के मूल्यों पर नियन्त्रण लगा सकती है। यदि आवश्यक हो तो सरकार उस वस्तु के उत्पादन को अपने नियन्त्रण में लेती है।

- (५) **उत्पत्ति वृद्धि नियम**—जब वस्तु की माँग लोचदार होती है और उद्योग में 'उत्पत्ति वृद्धि' नियम अर्थात् लागत ह्रास नियम लागू होता है तब एकाधिकारी अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तु का मूल्य निश्चिन करता है।

Important **मूल्य विभेद अथवा भेदपूर्ण एकाधिकार** (Price Discrimination or Discriminating Monopoly)

जब एकाधिकारी अपनी आय को अधिकतम करने के लिए अपनी एक ही वस्तु के लिए विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है तो इसे भेदपूर्ण एकाधिकार या मूल्य विभेद कहते हैं। मूल्य विभेद की परिभाषा श्रीमती जोन राबिन्सन (Mrs Joan Robinson) ने निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत की है—

“एक ही वस्तु, जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है, को भिन्न-भिन्न ग्राहकों को भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया को भेदपूर्ण एकाधिकार कहते हैं।”^{१०}

प्रो० डॉमस (Prof Thomas) के शब्दों में—“एकाधिकारी नीति की एक विशेषता है कि एक ही वस्तु या सेवा की पूर्ति के लिए विभिन्न भागों के उपभोक्ता से भिन्न भिन्न मूल्य लिया जाता है। इस प्रकार का मूल्य विभेद विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न व्यापारों, विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न वर्गों में हो सकता है।”^{११}

10 “The act of selling the same article, produced under a single control at different prices to different buyers is known as price discrimination”
—Mrs Joan Robinson

11 But a characteristic of monopolist policy is that different prices are charged for different portions of the supply of the same commodity or service. Such price discrimination may be in respect of different persons, different trades or different areas in the same community or in different communities

मूल्य विभेद की शर्तें (Conditions of Price Discrimination)

पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य विभेद सम्भव नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी इकाइयाँ समान होती हैं तथा उन समान इकाइयों को समान मूल्य पर ही बेचा जाता है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता और मूल्य विभेद का सह अस्तित्व सम्भव नहीं है। श्रीमती जोन रॉबिन्स के अनुसार 'मूल्य विभेद की नीति अपूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेष स्थितियों में ही सफलता प्राप्त कर सकती है।' (एकाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक रूप है) जिस वस्तु का बाजार जितना अधिक अपूर्ण होता है मूल्य विभेद उतना ही अधिक सम्भव होता है। लेकिन मूल्य विभेद अपूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तें नहीं हैं। स्टोनियर और हैग (Stonier and Hague) ने मूल्य विभेद की सफलता के मध्यम में लिखा है—

“यदि मूल्य विभेद को सफल होना है तो एकाधिकारी बाजार के निम्न-लिखित क्षेत्रों में क्षेत्रों के मध्य सम्पर्क असम्भव या अत्यंत कठिन होना चाहिए। टेक्नीकल भाषा में, विभेदात्मक एकाधिकारी के विभिन्न बाजारों में किसी प्रकार की रिसन (seepage) नहीं होनी चाहिए।”^{१२}

प्रो. टामस ने मूल्य विभेद की शर्तों को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है—

“मूल्य विभेद की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें यह हैं कि एकाधिकारी की वस्तु या सेवा एक बाजार से दूसरे बाजार में वितरित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा सम्भव हुआ तब व्यक्ति सस्ते बाजार से वस्तु खरीदकर महंगे बाजार में वस्तु को बेचना प्रारम्भ कर देंगे।”^{१३}

प्रो. जे. के. मेहता (Prof J K Mehta) ने मूल्य विभेद के लिये दो आवश्यक शर्तें बतायी हैं —

(१) भिन्न-भिन्न बाजार एक-दूसरे से पृथक् हों।

2 “So if price discrimination is to succeed, communication between buyers in different sectors of monopolist's market must be impossible, or at any rate extremely difficult. In technical language there must be no 'seepage' between the discriminating monopolist's different markets” —Stonier and Hague

13 “It is an essential condition of price discrimination that the commodity or service sold should not be transferable from one market to another, for, if this were possible, people would buy in the cheap market and sell in the dear one” —Prof Thomas

(२) वस्तु की मांग की लोच समाज के विभिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न हो।

उपपुक्त विस्लेषण के आधार पर मूल्य विभेद की आवश्यक सर्तें निम्न प्रकार हैं —

- (१) मूल्य विभेद करन वाली पक्ष एकाधिकारी की स्थिति में होनी चाहिए।
- (२) एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए बाजार दो या दो से अधिक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त एकाधिकारी द्वारा ली जान वाली कीमत पर विभिन्न बाजारों में वस्तु का मांग की लोच भी भिन्न भिन्न होना चाहिए।
- (३) उपभोक्ता वस्तु को क्रय करने के बाद बेचने (resale) की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
- (४) एकाधिकारी वस्तु के विभिन्न बाजारों के नेताओं के मध्य सम्पर्क का अभाव होना चाहिए।

मूल्य विभेद के प्रकार या भेदपूर्ण एकाधिकार का वर्गीकरण (Types of Price Discrimination or Classification of Discriminating Monopoly):

स्टोनिगर और हेंग ने तीन प्रकार मूल्य विभेद बताया है —

- (१) उपभोक्ताओं की विशेषताओं के कारण—इसमें तीन प्रमुख कारण हैं —
 - (अ) उपभोक्ता को जब यह ज्ञात नहीं होता कि दूसरे बाजार में वस्तु का मूल्य पर उलब्ध हो रही है।
 - (ब) उपभोक्ता के मन में यह गलत धारणा है कि वह वस्तु का मूल्य इस लिए अधिक दे रहा है कि उसकी वस्तु दूसरों की अपना अधिक अच्छी है।
 - (स) वस्तु के मूल्यों में अंतर इतना कम हो कि उपभोक्ता मूल्य के अंतर की कोई चिन्ता न करें।
- (२) वस्तु के स्वभाव के कारण इस प्रकार का मूल्य विभेद प्रत्यक्ष सेवाओं के सम्बन्ध में लागू होता है। ये सेवाएँ विनिमय साध्य नहीं होती, अतः मूल्य विभेद सरलता से किया जा सकता है, जैसे—बकील या डाक्टर की सेवा।
- (३) दूसरी तथा सीमा प्रतिबन्धों के कारण - मूल्य विभेद बाजारों की अधिक दूरी होने के कारण भी सम्भव होता है। तथा जब सीमान्त प्रतिबन्धों में दो देशों

के बाजारों को अलग कर दिया जाता है तथा उपभोक्ताओं के बीच प्रयुक्त दीवारें (tariff of walls) खो कर दी गई हों, तब एकाधिकारी मूल्य विभेद की नीति में नासानी से सफलता प्राप्त कर लेता है।

प्रो पीगू ने मूल्य विभेद की तीन श्रेणियाँ बतायी हैं —

- (१) प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेद—इस श्रेणी के मूल्य विभेद में एकाधिकारी उपभोक्ता की सामर्थ्य के अनुसार मूल्य लेता है। इससे उपभोक्ता को किसी प्रकार की वचन प्राप्त नहीं होती। खचटरो व नकोनो के लिए इस प्रकार का मूल्य विभेद सम्भव है।
- (२) द्वितीय श्रेणी का मूल्य विभेद—इस मूल्य विभेद में एकाधिकारी बाजार को विभिन्न वर्गों में विभाजित करता है और प्रत्येक वर्ग के सब सदस्यों से न्यूनतम मूल्य लिया जाता है। ये निर्धारित मूल्य निम्नतम दर पर रखे जाते हैं जिससे कि उपभोक्ताओं को कुछ वचन प्राप्त होती है। इसका उदाहरण रेलवे के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के विभाजन को ले सकते हैं।
- (३) तृतीय श्रेणी का मूल्य विभेद—इस श्रेणी के मूल्य विभेद में एक अधिकारी बाजार को विभिन्न श्रेणियों में बाट देता है और प्रत्येक बाजार में माग की लोच के अनुसार अलग अलग मूल्य लेता है। पीगू का विचार है कि इस प्रकार का मूल्य विभेद व्यवहार में बहुत अधिक पाया जाना है।

श्रीमती जोन रॉबिन्सन ने पीगू के उपर्युक्त वर्गीकरण की आलोचना की है। मूल्य विभेद का वर्गीकरण निम्न प्रकार से भी किया जा सकता है—

- (अ) व्यक्तिगत विभेद—इस विभेद में विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न दरों में मूल्य लिये जाते हैं। प्रो० टामस के अनुसार इस प्रकार का मूल्य विभेद प्रत्यक्ष सेवाओं में अधिक मिलता है।
- (ब) स्थानीय विभेद—जब एकाधिकारी विभिन्न बाजारों में एक ही वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य लेता है, तो उसे स्थानीय विभेद कहते हैं।
- (स) व्यवसायिक विभेद—जब एकाधिकारी विभिन्न व्यापारों में या वस्तु के प्रयोग जो प्रकृति के आधार पर मूल्य विभेद करता है तो इसे व्यवसायिक मूल्य विभेद कहते हैं, जैसे—विद्युत मण्डल उद्योगों के लिये कम व घरेलू उपयोग के लिये अधिक मजदूरी की दरें वसूल करती है।

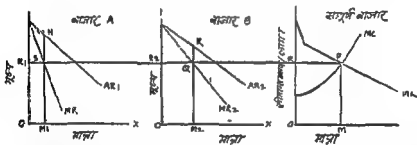
दो बाजार मान कर धर्नें, और दोनो बाजार A और B हैं तब उसकी दशा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं

$$M R (A) = M R (B) = M C$$

(A बाजार की सीमान्त आय = B बाजार की सीमान्त आय = कुल उत्पादन की लागत)

यदि A बाजार की सीमान्त आय कम है तथा B बाजार की सीमान्त आय अधिक है तो एकाधिकारी अपनी वस्तु को कुछ मात्रा A बाजार से हटाकर B बाजार में बेच देगा, जिससे उसके लाभ में वृद्धि होगी। ऐसी क्रिया वह उस समय तक करता रहेगा जब तक दोनों बाजारों की सीमान्त आय बराबर न हो जाय। दूसरे शब्दों में जिस बाजार में, वस्तु की माग बेसीचदार है उसमें अधिक मूल्य लेगा तथा जहाँ माग सोचदार है उसमें नीचा मूल्य प्रस्तुत करेगा। ऐसा करते समय वह ध्यान रहेगा कि दोनों बाजारों की सीमान्त आय बराबर हो जाय।

शेवपूर्ण एकाधिकारी की संतुलन की स्थिति की रेखा चित्रों से ध्यान दिया जाता है



उपर्युक्त चित्रों में बाजार A व बाजार B में औसत व सीमान्त आय के वक्रों को समस्त प्रदर्शित किया गया है। दोनों बाजार की आय रेखाओं की भिन्नता माग की लोच की भिन्नता दर्शाती है। बाजार A की सीमान्त और औसत आय की रेखाएँ MR_1 तथा AR_1 हैं इस बाजार में माग बेसीच है। बाजार B में सीमान्त और औसत आय की रेखाएँ MR_2 तथा AR_2 हैं, इस बाजार में माग सोचदार है। MR_1 व MR_2 जोड़कर कुल बाजार के लिये सीमान्त आय रेखा MR प्राप्त हो जाती है। एकाधिकारी के कुल उत्पादन की सीमान्त लागत रेखा MC है।

एकाधिकारी O M के बराबर कुल उत्पादन करेगा, क्योंकि इस उत्पादन की मात्रा $M \text{ II} = MC$ के है। P बिन्दु पर दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अतः O M उत्पादन साम्य उत्पादन (equilibrium output) को प्रकट करता है। एकाधिकारी इस

O M उत्पादन को दोनों बाजारों (A तथा B) में इस प्रकार बांटता कि दोनों बाजारों में सीमान्त आय बराबर हो जाय। इस नियम का पालन करते हुए एकाधिकारी O M₁ मात्रा को बाजार A में तथा O M₂ मात्रा को बाजार B में बेचेगा। इस प्रकार के वितरण से सीमान्त आय (O R) दोनों बाजारों की सीमान्त आय O R₁ तथा O R₂ में बराबर होगी। दोनों बाजारों में माग की लोच में भिन्नता होने कारण मूल्यो में भी भिन्नता होगी। बाजार A में एकाधिकारी वस्तु को N M₁ मूल्य पर बेचना है तथा O M₁ मात्रा का उत्पादन करता है, जबकि बाजार B में उसी वस्तु का K M₂ मूल्य पर बेचना है और O M₂ मात्रा का उत्पादन करता है। बाजार A में बाजार B की अपेक्षा मूल्य ऊँचा है क्योंकि बाजार B की अपेक्षा बाजार A में माग की लोच कम है।

राशिपातन (Dumping) Dumping

राशिपातन मूल्य-विभेद का महत्वपूर्ण रूप है। जब एकाधिकारी अपनी वस्तु के लिए विदेश में भिन्न-भिन्न बाजारों में अलग अलग मूल्य लेता है तो उसे राशिपातन की नीति कहते हैं। राशिपातन को मूल्य विभेद के ऐसे रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एकाधिकारी अपनी वस्तु को विदेशी बाजार में घरेलू बाजार की अपेक्षा सस्ते मूल्य पर बेचना है। कभी कभी मूल्य इतना कम लिया जाता है कि उस वस्तु की लागत भी नहीं निकल पाती। एकाधिकारी विदेशी बाजार में होने वाली हानि की पूर्ति स्वदेशी बाजार में अधिक ऊँचा मूल्य प्राप्त करके करता है।

प्रो थॉमस (Prof Thomas) ने राशिपातन की परिभाषा इस प्रकार दी है —

“राशिपातन का अर्थ साधारणतः दूसरे देशों के बाजारों में स्वदेशी बाजार की अपेक्षा वस्तु की सस्ते मूल्य पर बेचना अथवा उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचना होता है। इसका प्रयोग प्रायः उन एकाधिकारियों द्वारा किया जाता है जो कि दूसरे देशों के बाजारों पर अधिकार जमाना चाहते हैं अथवा जो माग का गलत अनुमान लगाने के कारण अतिरिक्त उत्पादन को बेचना चाहते हैं या जो उत्पत्ति वृद्धि नियम के लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं।”

- 14 “Dumping usually implies the selling of goods in a foreign market at a lower price than in the home market, or at a price which is below the expense of production. It is a device frequently resorted to by monopolistic undertakings, and may be adopted either to capture foreign markets, or to dispose of the surplus of goods produced as a result of an incorrect estimation of demand, or in order to obtain the benefits of increasing returns.”

—Prof Thomas

राशिपातन का उद्देश्य

एकाधिकारी राशिपातन को निम्नलिखित म ॥ किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना सबता है —

- (१) अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए — जब एकाधिकारी द्वारा माग का गलत अनुमान लगाय जाने के कारण उत्पादन अधिक मात्रा में हो जाता है तो इस अतिरिक्त उत्पादन को एकाधिकारी विदेशी बाजार में कम मूल्य पर बेचना अधिक उपयुक्त समझता है। यदि एकाधिकारी अतिरिक्त उत्पादन को स्वदेशी बाजार में ही बेचने का प्रयास करता है तो उसे कुल उत्पादन को सस्ते मूल्य पर बेचना होगा।
- (२) विदेशी बाजार में प्रतियोगियों को कुचलने के लिए — राशिपातन का एक उद्देश्य विदेशी बाजार में प्रतियोगियों को हतो साहित्य करना भी होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह विदेशी बाजारों में अपनी वस्तु को लागत से भी कम मूल्य पर बेचता है। इस प्रकार विदेशी प्रतियोगी कुचल दिये जाते हैं और एकाधिकारी के लिए रास्ता साफ हो जाता है और फिर एकाधिकारी मूल्य में वृद्धि कर देता है।
- (३) उत्पत्ति वृद्धि नियम का लाभ उठाने के लिए — उत्पात्ति वृद्धि नियम का लाभ उठाने के लिये एकाधिकारी राशिपातन का सहारा लेता है। इस नियम के अनुसार उत्पादन होने पर उत्पादन में वृद्धि करने से सीमान्त लागत व औसत लागत दोनों घट जाती है। घरेलू बाजार में माग बेवोच हावी है, अतः वह अधिक उत्पादन को विदेशी बाजार में बेच देता है।
- (४) विदेशी बाजारों में वस्तु की माग का सृजन करने ॥ लिए या वृद्धि करने के लिए — एकाधिकारी जब विदेशों में अपनी वस्तु की माग में वृद्धि कराना चाहता है या नई माग उत्पन्न कराना चाहता है तो वह घरेलू बाजार की अपेक्षा विदेशी बाजार में अपनी वस्तु को कम मूल्य पर बेचता है। जब विदेशों में वस्तु लोकप्रिय हो जाती है तब वह उसके मूल्य में वृद्धि कर देता है।

मूल्य विभेद का औचित्य (Justification of Price Discrimination)

सामान्यतः मूल्य विभेद की नीति को गलत माना जाता है तथा इसे सामाजिक न्याय की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना जाता क्योंकि यह उपभोक्ताओं के बीच भेद भाव की नीति का पालन करती है। परन्तु यह मानना कि मूल्य विभेद नीति सर्वदा सामाजिक न्याय के विपरीत है या अनुपयुक्त है एक गलत धारणा होगी। मूल्य विभेद की नीति का मूल्यांकन करने के लिए सम्बन्धित परिस्थितियों पर विचार करना होगा। कुछ परिस्थितियाँ जिनमें मूल्य विभेद लाभदायक होता है वे निम्नलिखित हैं —

- (१) सामाजिक उपयोगी सेवाओं में मूल्य विभेद का न्यायपूर्ण व. उचित कहा जाता है जैसे डाक्टर विभाग द्वारा पोस्टकार्ड की कीमत अपेक्षाकृत कम ली जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग निर्धन वर्ग द्वारा अधिक किया जाता है।
- (२) मूल्य विभेद के कारण वस्तु का उत्पादन उस स्थिति में भी सम्भव होता है जबकि औसत लागत सीमान्त उपयोगिता से अधिक होती है। एकाधिकारी वस्तु को बाजार में कभी कभी औसत लागत से कम मूल्य पर भी बच सकता है।
- (३) मूल्य विभेद के द्वारा देश के अतिरिक्त उत्पादन को विदेशों में बेचा जा सकता है। मूल्य-विभेद के कारण ही एकाधिकारी अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होता है, तथा उसे उत्पादन में आन्तरिक व बाह्य बचतें प्राप्त होने के कारण कम लागत पर उत्पादन प्राप्त होता है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को भी सस्ती कीमत पर वस्तु उपलब्ध हो जाती है।

संक्षेप में, मूल्य विभेद की नीति उनके लिये लाभदायक होती है जिनसे कम मूल्य प्राप्त किया जाता है, तथा उनके लिए हानिकारक है जिनको ऊँचा मूल्य देना पड़ता है। इस स्थिति में अमीरों की हानि से निर्धनों को लाभ प्राप्त होता है। मूल्य विभेद न होने की दशा में यह सम्भव है कि वस्तु का मूल्य इतना ऊँचा हो जाय कि निर्धन व्यक्ति उसके उपभोग से ही वंचित रह जायें।

मूल्य विभेद के दोष गम्भीर हैं। कुछ दशाएँ ऐसी हैं जिनमें यह नीति समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होती है।

- (१) मूल्य विभेद की नीति के कारण उत्पादन में साधनों का असमान वितरण हो जाता है। जिन उद्योगों में अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है वहाँ पर इन साधनों को प्रयुक्त किया जायेगा तथा कम लाभ वाले किन्तु आवश्यक उत्पादन के कार्यों में साधनों का प्रयोग कम हो जाता है।
- (२) एकाधिकारी मूल्य-विभेद की नीति के आधार पर अधिक लाभ कमाना अपना उद्देश्य बना लेता है, तथा देश के उपभोक्ताओं से ऊँचा मूल्य वसूल करता है। एकाधिकारी का यह व्यवहार अन्यायपूर्ण है।
- (३) मूल्य विभेद बहुधा राजपातन को जन्म देता है, और राजपातन से उन सभी वर्गों को हानि होती है, जिनके विरुद्ध यह किया जाता है।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल्य-विभेद की नीति को प्रत्येक दशा में उचित एवं न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक परिस्थिति के आधार पर इस नीति का मूल्यांकन करना होगा तभी इसके औचित्य और अनीचित्य का निर्णय किया जा सकेगा।

एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना

एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों की दृष्टाएँ एक-दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी दोनों ही स्थितियों के उत्पादकों का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। इस दृष्टि से दोनों ही साम्य की स्थिति में उस बिन्दु पर होते हैं जहाँ सीमान्त आगम और सीमान्त लागत ($MR=MC$) बराबर होते हैं। इस समानता के होने पर भी दोनों के मूल्य तथा उत्पादन के निर्धारण में अन्तर है, जो कि निम्नलिखित हैं :—

(१) पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, तथा उनमें स्वतन्त्रतापूर्वक प्रतियोगिता होती है। वस्तु का मूल्य बाजार में वस्तु की कुल माग व कुल पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार उद्योग द्वारा जो मूल्य निर्धारित होता है, उसे फर्म स्वीकार कर लेती है, अर्थात् पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म 'मूल्य ग्रहण करने वाली' होती है। फर्म द्वारा केवल उत्पादन की मात्रा सम-योजित (adjust) की जाती है, इसीलिए किसी विशेष समय में बाजार में केवल एक ही मूल्य प्रचलित होता है।

एकाधिकार में 'एक फर्म एक उद्योग' की स्थिति होती है, अर्थात् फर्म और उद्योग का अन्तर एकाधिकार में समाप्त हो जाता है। एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु के लिए क्रेताओं से अलग-अलग मूल्य भी ले सकती है और एक समान मूल्य भी। फर्म के द्वारा अपनी वस्तु का मूल्य स्वयं ही निर्धारित किया जाता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता।

(२) पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की औसत आगम रेखा (AR) ॥ माग रेखा एक पड़ी हुई रेखा होती है। यह रेखा पूर्णतया लोचदार होती है, इसका अर्थ है कि एक दी हुई कीमत पर फर्म वस्तु को जितनी मात्रा बेचना चाहे बेच सकती है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के लिये माग रेखा (AR) बायें से दायें नीचे की ओर गिरती हुई होती है।

एकाधिकार में फर्म और उद्योग का अन्तर समाप्त हो जाता है, अतः एकाधिकारी फर्म एवं उद्योग की एक ही माग रेखा होती है वह रेखा बायें से दायें नीचे की ओर गिरती हुई होती है।

- (३) पूर्ण प्रतियोगिता में सीमान्त आगम (MR) और औसत आगम (AR) बराबर होते हैं। बाजार में वस्तु का मूल्य समान रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है इसलिये सीमान्त आगम (MR) और मूल्य दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में सीमान्त आगम व औसत आगम ($MR=AR$) बराबर होते हैं तथा दोनों एक ही रेखा द्वारा व्यक्त किये जाते हैं।

एकाधिकार में सीमान्त आगम (MR) औसत आगम (AR) से कम होता है। एकाधिकारी यदि अपनी वस्तु की अधिक मात्रा में बेचना चाहता है तो उसे अपनी वस्तु का मूल्य कम करना होता है। इस प्रकार आगम रेखा को (MR) औसत आगम रेखा के नीचे की ओर गिरती हुई रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है।

- (४) पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य (AR) उसकी सीमान्त लागत (MC) के बराबर होता है अर्थात् पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य की स्थिति ($AR=MR=MC$) के होती है।

एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य (AR) और सीमान्त लागत (MC) में सामान्य अन्तर होता है। प्रायः एकाधिकारी फर्म द्वारा लिया जा रहा मूल्य सीमान्त लागत से अधिक होता है।

- (५) पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म सभी साम्य की स्थिति में होती है जबकि सीमान्त आगम रेखा (MC) सीमान्त आगम रेखा (MR) के नीचे से काटती है। एकाधिकारी फर्म की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। एकाधिकारी फर्म सभी प्रकार की लागत रेखाओं के साथ साम्य की स्थिति को प्राप्त कर सकती है चाहे वे रेखाएँ नीचे गिर रही हों, या स्थिर हों या ऊपर की ओर उठ रही हों।

- (६) अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों ही स्थितियों में फर्म को सामान्य लाभ तथा हानि प्राप्त हो सकती है, परन्तु एकाधिकारी का साधारणतः हानि व सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है जबकि एकाधिकारी को लाभ प्राप्त होना प्रायः निश्चित ही है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. एकाधिकारी मूल्य तथा प्रतियोगी मूल्य में अन्तर बताइए, और समझाइए कि एकाधिकार में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है।
२. एकाधिकारी का उद्देश्य लाभ तथा पूर्ति के बीच इस प्रकार का समन्वय बनाना

नही है कि प्राप्त मूल्य से उसकी उत्पादन लागत पूरी होजाय, अपितु इस प्रकार समायोजित करने से है कि उसे 'अधिकतम शुद्ध एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो।' —मावाल : व्याख्या कीजिये ।

३. एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है ? क्या एकाधिकारी मूल्य हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों से ऊँचे होते हैं ? उन सीमाओं का उल्लेख कीजिए, जिनके कारण एकाधिकारी अपने मूल्यों को बसीमित मात्रा तक बढ़ाने में असमर्थ होता है । (दिसो १९६५)
४. 'एकाधिकार से क्या अभिप्राय है ? एकाधिकारी मूल्य निर्धारित करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखता है ।
५. एकाधिकारी साम्य से आप क्या समझते हैं ? एकाधिकारी दीर्घकाल में अपनी वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित करता है ?
६. मूल्य विभेद की परिभाषा दीजिए । मूल्य-विभेद कब सम्भव, सामंदायक तथा सामाजिक दृष्टि से वाछनीय होता है ? (रविशंकर, आगरा, कानपुर १९६८)
७. विभेदात्मक एकाधिकार से आप क्या समझते हैं ? विभेदात्मक एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ?
८. राशिपातन पर टिप्पणी लिखिए ।



एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण

[Price Determination under
Monopolistic Competition]

★ ★ ★

वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार की स्थिति का पाया जाना सम्भव नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता एक सिरे की स्थिति है तो एकाधिकार दूसरे सिरे की। व्यवहार में अधिकांश बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। किसी एक बाजार में एकाधिकारों के तत्व अधिक प्रमाणाधीन हान हैं तो दूसरे में प्रतियोगी तत्व। अर्थशास्त्रियों ने बाजार की इस स्थिति को अपूर्ण प्रतियोगिता (imperfect competition) या 'एकाधिकारी प्रतियोगिता' (monopolistic competition) कहा है।

प्रो मेहता के अनुसार—अब यह बात पूर्णतया स्वीकार करनी गई है कि विनिमय की प्रत्येक दशा अपूर्ण एकाधिकार की दशा है, और यदि इसे इसी ओर से देखा जाय, तब यह अपूर्ण प्रतियोगिता ही है। ऐसी प्रत्येक दशा में प्रतियोगी तत्वों तथा एकाधिकारी तत्वों का मिश्रण पाया जाता है।¹

1 "It has since been more fully realized that the case of exchange is a case of what may be called partial monopoly. And partial monopoly is looked at from other side, a case of imperfect competition. There is a blending of both competition element and monopoly element in each situation."

थोमस जोन रॉबिन्सन ने 'अपूर्ण प्रतियोगिता' तथा प्रो चेम्बरलिन (Chamberlin) ने 'एकाधिकारी प्रतियोगिता' का विचार प्रस्तुत किया है। यद्यपि चेम्बरलिन ने इन दोनों में भेद किया है लेकिन दोनों एक ही मान लेते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता को 'समूह सन्तुलन' (Group Equilibrium) भी कहते हैं।

एकाधिकारी प्रतियोगिता में अभिप्राय

एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है लेकिन यह संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम होती है। भिन्न भिन्न विक्रेताओं द्वारा उत्पादित वस्तु में भिन्नता पाई जाती है, परन्तु ये वस्तुएँ एक दूसरे की निकट स्थानापन्न (close substitution) होती हैं। इन वस्तुओं में आपस में प्रतियोगिता पाई जाती है। स्टोनियर और हैग (Stonier and Hague) ने एकाधिकारी प्रतियोगिता के सम्बन्ध में लिखा है—

"पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान वस्तु पाई जाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के समान न तो वस्तु की इकाइयाँ एक सी ही होती हैं, और न एकाधिकार के समान निकट स्थानापन्न का अभाव होता है। इस सबका वास्तविक अर्थ यह है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत सब एकाधिकारी आपस में प्रतियोगिता करते हैं। ये प्रतिस्पर्धी एकाधिकारी समान वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं और न ही ऐसी वस्तुओं का जो कि पूर्ण रूप से भिन्न होती है। वस्तु विभेद का अर्थ यही है कि वस्तुओं के उत्पादन में किसी तरह की भिन्नता रहती है न कि वस्तुओं में पूर्णतया विभिन्नता।" २

- 2 "In perfect competition there is at any rate only one homogeneous commodity. In monopolistic competition there is differentiation of products. Products are not homogeneous as in the perfect competitions, but neither are they only remote substitutes as in monopoly. What this really means is that in monopolistic competition there are various 'monopolists' competing each other. These competing 'monopolists' do not produce identical goods. Neither do they produce goods which are completely different. Product differentiation means the products are different in some way, but not altogether so."

—Stonier & Hague

एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषतायें .

एकाधिकारी प्रतियोगिता की मुख्य-मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

- (१) फर्मों (या विभेताओं) की अधिक संख्या—एकाधिकारी प्रतियोगिता की पहली शर्त यह है कि बाजार में फर्मों की संख्या अधिक होनी चाहिये। (लेकिन यह संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की 'बहुत अधिक संख्या' से कम होती है) लेकिन एक फर्म या बिजना द्वारा कुल उत्पादन का एक छोटा सा अंश ही उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों का आकार बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन प्रत्येक फर्म का वस्तु की पूर्ति पर नियन्त्रण होना है और अपनी वस्तु का मूल्य स्वयं ही निर्धारित करती है।
- (२) वस्तु विभेद (Product differentiation)—एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है, अर्थात् एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ एक दूसरे की निकट स्थानापन्न होती हैं परन्तु वे पूर्ण स्थानापन्न (perfect substitutes) नहीं होती। प्रत्येक फर्म की वस्तु अन्य फर्मों की वस्तुओं से किसी न किसी रूप में (वास्तविक या काल्पनिक) भिन्न होती है। यह वस्तु विभेद दो प्रकार का होता है—
 - (a) वास्तविक वस्तु विभेद—इस विभेद में वस्तु की क्वालिटी (quality) में अन्तर होता है, यह अन्तर कच्चे माल, वस्तु के डिजाइन, कार्यशील या ट्रेडमार्क आदि के द्वारा किया जा सकता है।
 - (b) काल्पनिक वस्तु विभेद—इस विभेद में वस्तु की इकाइयों के मध्य कोई अन्तर नहीं होता लेकिन बिज्ञापन, प्रचार या प्रोपेगण्डा के द्वारा क्रेताओं की मनोवृत्ति को प्रभावित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप क्रेता यह सोचने के लिए बाध्य होता है कि इस फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु दूसरी फर्मों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है।
- (३) फर्मों का स्वतन्त्र प्रवेश व बहिर्गमन—एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत किसी भी फर्म को उद्योग में प्रवेश करने अथवा किसी फर्म को उद्योग से बाहर जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन वस्तु विभेद के कारण फर्मों का प्रवेश पूर्ण प्रतियोगिता के समान सुगम नहीं होता।
- (४) गैर मूल्य प्रतियोगिता (Non-price competition)—एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत वस्तु विभेद होने के कारण गैर-मूल्य प्रतियोगिता पाई जाती है। फर्मों

में आपस में प्रतियोगिता केवल मूल्यों पर ही आधारित नहीं होती, बल्कि वस्तु विभेदोत्प्रेरण तथा मिश्रण से सम्पन्नित दत्तांशों, विभाजन इत्यादि पर भी आधारित होती है।

एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत आगम तथा लागत रेखाएँ

(१) एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म के लिए वस्तु की माग रेखा (AR) नीचे गिरती हुई रेखा होती है—इसका अभिप्राय यह है कि यदि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म अपनी वस्तु की अधिक मात्राएँ बेचना चाहती है तो उसे अपनी वस्तु का मूल्य कम करना होगा। लेकिन यहाँ पर ओमत आगम रेखा एकाधिकारी फर्म की ओमत आगम रेखा के समान ढालू या नीचे की ओर गिरती हुई (slope) नहीं होती। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं होना जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का निकट स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध होता है। इसके परिणामस्वरूप एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म की वस्तु की माग मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। इसीलिए एकाधिकारी प्रतियोगिता में ओमत आगम रेखा (AR) एकाधिकार की स्थिति की अपेक्षा अधिक लोचदार होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि या कमी से फर्म की बिक्री में अत्यधिक कमी या अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी।

एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत ओमत आगम रेखा (AR) में लोच की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है।

(a) वस्तु विभेद का अंश

(b) समूह विशेष में फर्मों की संख्या

यदि वस्तु विभेद का अंश अधिक है अर्थात् वस्तु का निकट स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध नहीं है तो फर्म का ओमत आगम वक्र कम लोचदार (या बेतलोच) होगा। यदि वस्तु विभेद का अंश कम है अर्थात् निकट स्थानापन्न उपलब्ध है तो ओमत आगम वक्र अधिक लोचदार होगा।

एकाधिकारी प्रतियोगिता में ओमत आगम रेखा की शक्ल (shape) कार्यशील प्रतियोगी फर्मों की संख्या द्वारा भी प्रभावित होती है। बाजार में यदि प्रतियोगी फर्मों की संख्या अधिक है तो फर्म का ओमत आगम वक्र अधिक लोचदार होगा यदि बाजार में प्रतियोगी फर्मों की संख्या कम है तो उस फर्म का ओमत आगम वक्र कम लोचदार होगा।

(२) सीमान्त आगम रेखा (MR) औसत आगम रेखा (AR) \equiv नीचे रहती है—इसका कारण यह है कि अतिरिक्त इकाइयों को बेचने के लिए फर्म को अपनी वस्तु का मूल्य (AR) घटाना पड़ता है। अतिरिक्त इकाई को बेचने के लिए फर्म मूल्य को केवल अतिरिक्त इकाई पर ही नहीं घटाती है बल्कि पिछली सभी इकाइयों पर उसे मूल्य घटाना पड़ना है। इसलिए अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली आय (अर्थात् MR) औसत आगम (AR) से कम होती है।

(३) लागत रेखाएँ—एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत पूरे उद्योग के लिए लागत रेखाओं का सीक्ना काफी कठिन है। यद्यपि विभिन्न फर्मों के द्वारा लगभग समान उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग किया जाता है और उन साधनों का मूल्य भी लगभग समान दिया जाता है, लेकिन वस्तु विभेद के कारण विभिन्न फर्मों की लागतें भिन्न-भिन्न हो जाती हैं जिससे परिणामस्वरूप लागत रेखाएँ भी एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं।

इस प्रकार पूरे उद्योग के लिए लागत रेखाओं का सीक्ना काफी कठिन होता है क्योंकि बाजार में विभिन्न फर्मों की वस्तुओं की लागतों में समानता नहीं पाई जाती। अतः अध्ययन की सुविधा के लिये हम मान लेते हैं कि एकाधिकारी प्रति योगिता में समूह की सभी फर्मों की लागत समान होती है।

(४) विक्रय लागतें—‘गैर मूल्य प्रतियोगिता’ एकाधिकारी प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में देवदार अपने लाभ में वृद्धि करने के उद्देश्य से विज्ञापन, प्रचार, प्रोपेगण्डा आदि पर बड़ी मात्रा में व्यय करती है। इस प्रकार के व्ययों को अर्थशास्त्री ‘विक्रय लागतें’ (selling costs) कहते हैं। ये विक्रय लागतें कुल उत्पादन लागत का एक हिस्सा होती हैं। इस प्रकार एकाधिकारी प्रतियोगिता में लागत से अभिप्राय है

$$\begin{aligned}\text{कुल लागत} &= \text{स्थिर लागत} + \text{परिवर्तनशील लागत} + \text{विक्रय लागत} \\ &= \text{उत्पादन लागत} + \text{विक्रय लागत}\end{aligned}$$

एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण या फर्म का साम्य

एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। दूसरे शब्दों में फर्म अपनी वस्तु का मूल्य तथा उत्पादन की मात्रा इस प्रकार निश्चित करेगी कि उसे लाभ अधिकतम हो। अधिकतम लाभ तब प्राप्त होगा जबकि सीमान्त आगम (MR) और सीमान्त लागत (MC) बराबर हो। इस प्रकार

एकाधिकारी प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार तीनों दशाओं में साम्य उस बिन्दु पर स्थापित होता है जहाँ सीमान्त लागत और सीमान्त आय सम बराबर होते हैं ।

अतः एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में एक उत्पादक अपनी वस्तु के उत्पादन में उम सीमा तक वृद्धि करता है जब तक कि अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि उस वस्तु की इकाई पर आयी लागत में वृद्धि के बराबर नहीं हो जाती है । इस सीमा के बाद उत्पादक वस्तु का उत्पादन बन्द कर देता ।

एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म का अल्पकालीन साम्य

एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत वस्तु की मूल्य के आधार पर बेचा जाता है । यदि कोई फर्म किसी नयी तथा थोड़ा वस्तु का उत्पादन करके असाधारण लाभ प्राप्त करती है तो अन्य फर्मों भी उस वस्तु से मिलती-जुलती (स्थानापन्न) वस्तुओं का उत्पादन करेंगी । इस प्रकार प्रतियोगिता प्रारम्भ होगी और असाधारण लाभ स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे । परन्तु अल्पकाल में फर्म असाधारण लाभ प्राप्त कर सकती है क्योंकि यह अवधि इतनी कम होती है कि अन्य फर्मों स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाती । इस प्रकार अल्पकाल में फर्म लाभ प्राप्त कर सकती है परन्तु दीर्घकाल में लाभ प्राप्त करना सम्भव नहीं है । स्टोनियर और हग के शब्दों में—

‘अल्पकाल में, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता है और फर्मों की संख्या निश्चित है, वे असाधारण लाभ या हानि प्राप्त कर सकती हैं । लेकिन दीर्घकाल में उद्योग की स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता के समान ही होती है ।’³

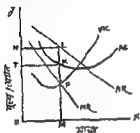
अतः एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी फर्म की अल्पकालीन स्थिति लगभग वैसी ही होती है जैसी कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में । फर्मों की संख्या का उनकी उत्पादकता में पूर्ण परिवर्तन करने के लिए ‘समय’ नहीं मिलता इसलिए फर्म (अ) सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है, (ब) केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है, या (स) हानि उठा सकती है । इस स्थिति में पूर्ण साम्य की स्थापना सम्भव नहीं है ।

अल्पकाल में एकाधिकारी प्रतियोगिता में औसत स्थिर लागत (average fixed cost), औसत परिवर्तनशील लागत (average variable cost), औसत कुल इकाई लागत या औसत लागत (average total unit cost or average cost) तथा सीमान्त

3 ' "In the short run, where there is monopolistic competition in an industry but the number of firms is fixed, can they all earn abnormal profits or losses. In the long run, however, the position will be similar to the long run position in a perfectly competitive industry "

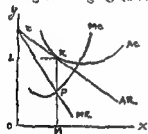
लागत (marginal cost) हो सकती है, परन्तु दीर्घकाल में फर्म को केवल औसत लागत व सीमान्त लागत हो सकती है।

अल्पकाल में लाभ की स्थिति—चित्र में लाभ की स्थिति को दर्शाया गया है। MR अल्पकालीन सीमान्त आगम रेखा है, AR अल्पकालीन औसत आगत रेखा। MC और AC अल्पकालीन सीमान्त लागत व औसत लागत रेखाएँ हैं। P बिन्दु साम्य बिन्दु है।

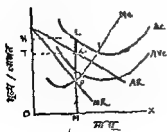


इस बिन्दु पर सीमान्त लागत व सीमान्त आगम एक-दूसरे के बराबर हैं। इस स्थिति में फर्म OM मात्रा का उत्पादन करेगी, तथा वस्तु का मूल्य LM के बराबर होगा। चूँकि मूल्य LM वस्तु की लागत KM से अधिक है, इसलिए उत्पादक को प्रति इकाई KL (LM - KM) लाभ प्राप्त होगा। कुल लाभ KLNT होगा।

सामान्य लाभ की स्थिति—चित्र में फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। P बिन्दु साम्य बिन्दु है, इस बिन्दु पर MC और MR बराबर है। OM उत्पादन की मात्रा है। K बिन्दु पर AR रेखा AC रेखा को स्पर्श करती है। इस प्रकार KM प्रति इकाई मूल्य भी है तथा प्रति इकाई लागत भी। दूसरे शब्दों में, मूल्य और लागत बराबर है। अतः उत्पादक को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है।



हानि की स्थिति—चित्र में हानि की स्थिति प्रदर्शित की गई है। P बिन्दु साम्य बिन्दु है, यहाँ $MR = MC$ के है। P बिन्दु से खींची रेखा खींची जा कि AR रेखा को K बिन्दु पर स्पर्श करती है, तथा AC रेखा को L बिन्दु पर। इस प्रकार अब उत्पादन OM होगा, जब लागत प्रति इकाई LM है, जबकि मूल्य KM। अतः उत्पादक को प्रति इकाई LK (LM - KM) हानि होगी। कुल हानि KLNT के बराबर प्राप्त होगी। उत्पादक अपनी वस्तु के लिये कम-से-कम KM के बराबर मूल्य प्राप्त करेगा, यदि इससे कम मूल्य प्राप्त होगा तो वह उत्पादन बन्द कर देगा।



दीर्घकालीन साम्य .

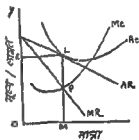
दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। यदि अल्पकाल में कोई फर्म असाधारण लाभ प्राप्त कर रही है तो उस लाभ से आकर्षित होकर नयी फर्म बाजार में प्रवेश करेंगी, जिससे प्रतियोगिता में वृद्धि होगी तथा नयी फर्म वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि करेंगी। इसके परिणामस्वरूप वस्तु का मूल्य गिरेगा, और उत्पादक को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा।

एकाधिकारी प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता के समान ही दीर्घकाल में 'दोहरी शर्त' को पूरा करना होता है —

$$(अ) \quad MR = MC$$

$$(ब) \quad AR = AC$$

दूसरी शर्त की पूर्ति ही सामान्य लाभ को जन्म देती है। चित्र में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है। चित्र में P बिन्दु पर $MR = MC$ के है, P बिन्दु से खड़ी रेखा खींचने पर यह रेखा AR रेखा को L बिन्दु पर काटती है। इस प्रकार मूल्य LM हुआ, तथा उत्पादन की मात्रा OM। L बिन्दु पर ही AR रेखा AC रेखा को स्पर्श करती है। अतः लागत भी LM है। L बिन्दु पर $AR = AC$ के है। इस प्रकार फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है।



दीर्घकालीन साम्य के सम्बन्ध में एक बात महत्वपूर्ण है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR रेखा एक गिरती हुई रेखा होती है, इसलिए वह AC रेखा को उसके न्यूनतम बिन्दु से पहले किसी बिन्दु पर (जो कि बाईं ओर होता है) स्पर्श करेगी। इसका अर्थ यह होता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म अनुकूलतम मात्रा (optimum output) से कम उत्पादन करती है, जिसके परिणामस्वरूप फर्म की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। इसके विपरीत पूर्ण प्रतियोगिता में AR रेखा AC रेखा को उसके न्यूनतम बिन्दु पर स्पर्श करती है, अर्थात् पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अनुकूलतम उत्पादन करती है।

अपूर्ण प्रतियोगिता (Imperfect Competition)

प्रस्तुत अध्याय में हम अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता को एक ही मानकर चर्चे में हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों में थोड़ा अन्तर है। बाजार की स्थितियों

का सही वर्गीकरण दो मुख्य विचारों पर आधारित है (अ) फर्मों की संख्या, (ब) फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु में एकरूपता या विभिन्नता। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसके सीरिय हो प्रत्येक फर्म द्वारा किया गया उत्पादन कुल उत्पादन का छोटा-सा अंश होता है, जो कि कुल पूंति को प्रभावित नहीं कर पाता। दूसरे, उद्योग की सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु एकरूप (homogeneous) होती है। यदि किसी बाजार में उपर्युक्त स्थितियों में से कोई एक या दोनों अनुपस्थित रहती हैं तो वह अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी। १

प्रो फेयर चाइल्ड के शब्दों में—“यदि बाजार उचित प्रकार से संगठित नहीं है, और क्र्रेताओं तथा विक्रेताओं के पारस्परिक सम्पर्क में कठिनाई उत्पन्न होती है, तथा वे ज्ञय की गई वस्तुओं और दिय गये मूल्यों की तुलना करने में असमर्थ हैं तो ऐसी स्थिति को अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं।” २

इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषतायें निम्नलिखित हैं —

- (१) विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है।
- (२) क्र्रेताओं को बाजार की स्थितियों का पता नहीं होता।
- (३) विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के मध्य काल्पनिक या वास्तविक अन्तर होता है, अर्थात् वस्तु विभेद पाया जाता है।
- (४) यातायात की असुविधाओं या अन्य बाधाओं के कारण वस्तु का आवागमन में असुविधा उत्पन्न होती है जिससे एक वस्तु के विभिन्न मूल्य प्रचलित हो सकते हैं।
- (५) कुछ क्र्रेताओं का कुछ विक्रेताओं के प्रति या विशेष वस्तु के प्रति अनुराग होता है।

उपर्युक्त विशेषताओं में से किसी एक की उपस्थिति ही अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म दे देती है।

अपूर्ण प्रतियोगिता के अनेक रूप हैं। लेकिन प्रमुख रूप तीन हैं

- 4 “If the market is not properly organized, if the buyers and sellers find it difficult to come into contact with each other and they are not able to compare the commodities purchased and the prices paid by others, we shall come across a case of imperfect competition”
—Fair Child

- (अ) एकाधिकार प्रतियोगिता—इस शब्द का प्रयोग चेम्बरलिन ने किया। (विस्तृत विवेचन इसी अध्याय में है।)
- (ब) अल्पाधिकार (Oligopoly)—अल्पाधिकार में कुछ ही फर्म होती हैं जो कि वस्तु की पूर्ति करती हैं। ये फर्म एकलव्य वस्तु का उत्पादन करती हैं या निकट स्थानापन्न वस्तु का। इसमें विभेदताओं की संख्या कम होने के कारण ये वस्तु के मूल्य और वस्तु की पूर्ति के प्रति सजग रहती हैं।
- (स) द्वैपाधिकार (Duopoly)—द्वैपाधिकार की स्थिति में बाजार में केवल दो ही उत्पादक होते हैं, दोनों उत्पादकों द्वारा समान या लगभग समान वस्तु का विपणन किया जाता है। दोनों स्वतन्त्रतापूर्वक उत्पादन काय करके प्रतियोगिता करते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता में पूर्ण समानता नहीं है बल्कि घेरा भन्तर है। एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप (form) मात्र है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में भन्तर बताइए।
- २ एकाधिकारी प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है? एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है।
- ३ एकाधिकारी प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म के अल्पकालीन व दीर्घकालीन साम्य की व्याख्या कीजिए।
- ४ पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य ऊँचा होता है?

अध्याय १३

★

प्रतिनिधि फर्म

[Representative Firm]

★ ★ ★

अर्थशास्त्र में प्रतिनिधि फर्म का विचार प्रो. मार्शल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मार्शल ने इसका प्रयोग स्थिर परिस्थितियों में उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of increasing return) के अन्तर्गत सामान्य मूल्य-निर्धारण की व्याख्या करने के लिये किया।

दीर्घकाल में किसी वस्तु का मूल्य सीमान्त उपयोगिता एवं सीमान्त लागत के समतुल्य द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत जब वस्तु का उत्पादन होता है तो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ सीमान्त लागत में समानान्तर घटती जाती है। इस स्थिति में, वस्तु का मूल्य सीमान्त लागत से अधिक होता है, अर्थात् मूल्य औसत लागत कम होती है, तथा कुछ फर्मों अकुशल होती है, जिनकी उत्पादन लागत के बराबर होना है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, मार्शल ने यह माना है, कि उद्योग विनियम में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसके साथ ही फर्मों के विकास की स्थिति में समान नहीं होती। कुछ फर्मों कुशल होती है जिनकी उत्पादन लागत अधिक होती है। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य में समानता पाई जाती है, इसलिये यह समस्या उत्पन्न होती है कि वस्तु का मूल्य किम फर्मों को उत्पादन लागत के आधार पर निर्दिष्ट किया जाय। यदि कुशल फर्मों के आधार पर मूल्य निर्धारित होता है तो कुछ फर्मों को, जो कि अकुशल हैं हानि होगी। यदि अकुशल फर्मों के आधार पर मूल्य निर्धारित होता है तो कुछ फर्मों को लाभ प्राप्त होगा। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में नतीजा फर्मों को लाभ प्राप्त होता है और न ही हानि, केवल सामान्यलाभ ही प्राप्त होता है। इस जटिल समस्या को हल करने के लिये मार्शल ने 'प्रतिनिधि फर्म' का विचार प्रस्तुत किया।

प्रतिनिधि फर्म से अभिप्राय

मूल्य-निर्धारण में फर्म के चुनाव की समस्या को हल करने के लिये मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म का सुझाव प्रस्तुत किया। उनके अनुसार दीर्घकाल में वस्तु का मूल्य प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर होता है। प्रो. मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म की परिभाषा निम्नांकित शब्दों में की है—

“प्रतिनिधि फर्म वह है जिसका जीवन काफी लम्बा रहा हो, जिसे पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई हो, जिसका प्रबन्ध सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाता हो, तथा जिसे बड़े पैमाने के उत्पादन की आन्तरिक एवं बाह्य बचनें प्राप्त होनी हों, जबकि उत्पादित वस्तु की श्रेणी, उसके विनियम की परिस्थितियां तथा आर्थिक वित्त-व्यय को ध्यान में रखा जाता हो।”

इस प्रकार मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जिसका आकार न तो बहुत बड़ा है और न बहुत ही छोटा, जो न तो विलुप्त नहीं है और न ही बहुत पुरानी, जिसका प्रबन्ध न तो बहुत अधिक कुशल व्यक्ति द्वारा किया जाता है और न ही अकुशल व्यक्ति द्वारा जिस न तो लाभ प्राप्त होता है और न ही हानि, जिसकी न तो विस्तार की प्रवृत्ति होती है और न संकुचन की। इस प्रकार मार्शल की प्रतिनिधि फर्म एक ‘औसत फर्म’ है जो कि सम्पूर्ण उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन मार्शल ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह औसत फर्म वर्तमान फर्मों की औसत फर्म नहीं होती बल्कि दीर्घकालीन औसत फर्म होती है। उन्हीं के शब्दों में—

“यह दीर्घकालीन औसत फर्म है जबकि वर्तमान प्रवृत्तियों का प्रभाव पूर्णरूप से नाश कर चुका हो।”

मार्शल ने औसत शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है, मार्शल ने इसे स्पष्ट करते हुये लिखा है—

1 “Our representative firm must be one which has had a fairly long life, and fair success, which is managed with normal ability, and which has normal access to the economics, external and internal, which belong to that aggregate volume of production, account being taken of the class of goods produced the conditions of marketing them and the economic environment generally” —Marshall

2 “It is a long period average firm under conditions when the present tendencies have worked out their effects in full” —Marshall

“प्रतिनिधि फर्म एक विशेष प्रकार की औसत फर्म है जिसकी आवश्यकता यह पता लगाने के लिये होती है कि उद्योग विशेष में आन्तरिक एवं बाह्य वचनों किस सीमा तक प्राप्त हो चुकी हैं। हम इन वचनों का अनुमान एक या दो फर्मों को देखकर नहीं लगा सकते, परन्तु व्यापक रूप से सर्वेक्षण करने के उपरान्त इस प्रकार की फर्म पाई जा सकती है जो किसी विशेष औसत का प्रतिनिधित्व करती हो।”³

मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म वास्तविक जगत में पाई जाती है। लेकिन प्रतिनिधि फर्म का आकार स्थिर दशाओं में अपरिवर्तित रहता है, जबकि अन्य फर्मों के आकार में वृद्धि होती है या संकुचन होता है। मार्शल ने इसे अधिक स्पष्ट करने के लिये एक जंगल का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मार्शल ने उद्योग की तुलना एक जंगल से की है। जंगल में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो वित्कुल नये होते हैं जो निरन्तर बढ़ते रहते हैं, कुछ पुराने होते हैं जिनका बढ़ना बन्द हो जाता है, और वह नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति की ओर अप्रसर हो रहे होते हैं, कुछ पेड़ पूर्ण विकसित अवस्था में होते हैं। जंगल के पेड़ों की तरह मार्शल ने एक उद्योग की फर्मों को तीन वर्गों में विभाजित किया है —

- (१) नई फर्में जिनमें बढ़ने की प्रवृत्ति है तथा जिनका साम बढ़ रहा है।
- (२) पुरानी फर्में जो अपनी कुशलता खो चुकी हैं, अतः पतन की ओर अप्रसर हैं, तथा
- (३) सुव्यवस्थित फर्में जो कि लम्बो अवधि प्राप्त कर चुकी हैं, और सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

मार्शल ने तीसरी श्रेणी की फर्म को औसत फर्म या प्रतिनिधि फर्म माना है, और इसी फर्म को सागत के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है।

प्रतिनिधि फर्म की विशेषतायें

मार्शल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधि फर्म की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं —

- 3 “And a representative firm, is that particular sort of average firm, at which we need to look in order to see how far the economics, internal and external, of production on a large scale have extended generally in the industry in question. We cannot see this by looking at one or two firms taken at random, but we can see it fairly well by selecting after a broad survey, a firm whether in private or in joint stock management that represents to the best of our judgement this particular averages”

—Marshall

- (१) प्रतिनिधि फर्म एक औसत फर्म होती है, जिसको सहायता से यह पता लगाने में उद्योग को आन्तरिक एवं बाह्य बचतें किस सीमा तक प्राप्त हो रही हैं।
- (२) यह न बहुत नई फर्म होती है और न बहुत पुरानी।
- (३) इसका प्रबन्ध सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाता है।
- (४) इस फर्म को न लाभ प्राप्त होता है न हानि बल्कि सामान्य लाभ प्राप्त होता है।
- (५) स्थिर दशाओं में फर्म का न विस्तार होता है न संकुचन।
- (६) दीर्घकालीन मूल्य इस फर्म की औसत लागत द्वारा निर्धारित होता है।
- (७) यह फर्म वास्तविक जगत में पाई जाती है तथा ऐसी फर्म एक या एक से अधिक हो सकती है।

प्रतिनिधि फर्म की आलोचना

मार्शल के प्रतिनिधि फर्म के विचार की कटु आलोचना की गई है। आलोचकों में प्रो रॉबर्टसन (Prof Robertson) प्रो रॉबिन्स (Prof Robbins) एवं प्रो काल्डोर (Prof Kaldor) के नाम उल्लेखनीय हैं। इन आलोचकों ने मार्शल के विचार की निम्न-लिखित आलोचनाएँ की —

- (१) प्रतिनिधि फर्म का विचार अस्पष्ट है—प्रतिनिधि फर्म के विचार में सरलता एवं स्पष्टता दोनों का अभाव पाया जाता है। प्रो रॉबिन्स ने बताया कि मार्शल ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिनिधि फर्म का सम्बन्ध किससे है। रॉबिन्स के शब्दों में—“मार्शल ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिनिधि फर्म से उसका तात्पर्य प्रतिनिधि व्यापारिक इकाई से है या प्रतिनिधि प्लांट से, या प्रतिनिधि तकनीकी इकाई से।”^४
- (२) प्रतिनिधि फर्म का विचार अवास्तविक है—प्रो रॉबिन्स का यह विचार है कि मार्शल का विचार अवास्तविक एवं भ्रांतिपूर्ण है, वास्तविक जगत में ऐसी कोई फर्म नहीं पाई जाती। प्रो निकोलस काल्डोर (Prof Nicholas Kaldor) ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है—

4 “Even the clearest statement given by Marshall of his so-called representative firm does not make it clear whether Marshall means by it a representative plant or a technical production unit or a representative business unit”
—Prof Robinson

- ✓ “मार्शल की प्रतिनिधि फर्म वास्तविकता का विश्लेषण न होकर भ्रष्टिष्क का एक यंत्र है।”^५
- (३) प्रतिनिधि फर्म का विचार आवश्यक है—प्रो रॉबिन्स ने इस विचार को अनर्गल और अनावश्यक बताया है, उनका विचार है कि अर्थशास्त्र में और विशेष रूप से विनिमय के क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल इसके बिना संभव न हो सके। रॉबिन्स ने इस सम्बन्ध में लिखा है—
- ✓ “जिस प्रकार हमें भूमि के प्रतिनिधि टुकड़े, प्रतिनिधि मशीन या प्रतिनिधि श्रमिक की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है उसी प्रकार प्रतिनिधि फर्म या प्रतिनिधि उत्पादक की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है।”^६
- (४) प्रतिनिधि फर्म का विचार अतार्किक है—रॉबिन्स के अनुसार यह विचार तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मार्शल के अनुसार दीर्घकाल में वस्तु का मूल्य प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के द्वारा निर्धारित होता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि जो फर्म प्रतिनिधि फर्म से कम कुशल है उनको हानि प्राप्त होगी, फिर भी वे उत्पादन काय करती रहेगी। लेकिन दीर्घकाल में कोई भी फर्म हानि प्राप्त नहीं करेगी। अतः यह विचार तर्कसंगत नहीं है।
- (५) पूर्ण प्रतियोगिता तथा जमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम असंगत है—आलाचको का विचार है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम के क्रियाशील होने की दशा में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति समाप्त हो जाती है, इस स्थिति में या तो अल्पाधिकार (oligopoly) या एकाधिकार (monopoly) की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। प्रो मेहता ने कहा है ‘प्रो मार्शल का यह विचार निरन्तर दोषपूर्ण है कि प्रतिनिधि फर्म हमेशा साम्य (equilibrium) की स्थिति में रहती है।’

5 “Marshall's representative firm is a tool of mind rather than an analysis of a concrete” —Prof Nicholas Kaldor

6 “There is no more need for us to assume a representative firm, or a representative producer, than there is for us to assume a representative piece of land, a representative machine or a representative worker” —Robbins

रॉबर्टसन ने भी मार्शल के इस विचार को खेदार माना है क्योंकि अधिक सिद्धांत में इस विचार का कोई विशेष महत्व नहीं है। रॉबर्टसन ने शब्दों में—

‘मेरे विचार में प्रतिनिधि फर्म को सम्पूर्ण उद्योग की प्रति रखा के एक सूक्ष्म रूप से कुछ अधिक मानना आवश्यक नहीं है।’⁷

प्रतिनिधि फर्म के विचार की पुनर्स्थापना (*Rehabilitation of the Concept of Representative firm*)

यद्यपि प्रतिनिधि फर्म के विचार को बट आलोचना की गई तथा इसे अवास्तविक, अव्यावहारिक और अतार्किक कहा गया। फिर भी वर्तमान समय में कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इस विचार को आलोचनाओं से मुक्त रखने का प्रयत्न किया गया है अब बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कि प्रतिनिधि फर्म को एक वास्तविकता मानते हैं। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार—

“मार्शल की प्रतिनिधि फर्म का विचार बेवस गतिस्थ की उपलब्धि है बल्कि यह एक वास्तविकता का विश्लेषण है।”⁸

इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार गतिशील अर्थशास्त्र के लिए यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है। १९१४ में सिडनी चैपमैन (Sydney Chapman) और ऐश्टन (Ashion) द्वारा व्यापारिक लक्ष्य के अध्ययन विषये गये थे, उन अध्ययनों से पता चलता है कि वास्तविक भाषिक जीवन में इस प्रकार की फर्मों का अस्तित्व है। चैपमैन तथा ऐश्टन के अध्ययनों से निष्कर्ष निकालते हुए प्रो. पीगू (Prof. Pigou) ने लिखा है—

“साधारणतया की हुई परिस्थितियों के अन्तर्गत उद्योगों में या उद्योगों की शाखाओं में पर्याप्त आकार की एक प्रतिनिधि अथवा विशेष इकाई होती है जिसके आधार पर उद्योग अवस्था अध्ययन में पुष्टि होती है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए एक सामान्य आधार और रूप होता है, उसी प्रकार व्यवसायों में भी सामान्य आधार एवं रूप होता है।”⁹

7 ‘In my opinion it is not necessary to regard it as anything other than a mathematical replica of the supply curve of the industry as a whole’ — Robertson

8 “Marshallian representative firm is not only a tool of the mind but is an analysis of the concrete”

9 “Generally speaking, there would seem to exist in the industries

अमेरिका के अनुभवों के आधार पर प्रो टॉसिग (Taussig) ने भी इस बात की पुष्टि की है कि प्रतिनिधि फर्म वास्तविक सत्कार से सम्बन्धित है।

प्रो मेहता ने भी इस विचार का दृढ़ता से समर्थन किया है। लेकिन उन्होंने प्रति निधि फर्म के विचार को नया अर्थ दिया है। प्रो मेहता ने बताया कि (a) प्रतिनिधि फर्म का विचार गतिशील अवस्था में लागू होता है तथा (b) प्रतिनिधि फर्म सदैव साम्य की शक्त में नहीं रहती अतः उद्योग में परिवर्तन के साथ-साथ इसमें भी परिवर्तन हो जाते हैं।

प्रो मेहता ने प्रतिनिधि फर्म की परिभाषा इस प्रकार की है—

“प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जिसमें उद्योग के साथ-साथ विस्तार एवं संकुचन की प्रवृत्ति पाई जाती है।”

प्रो मेहता ने बताया कि इस फर्म का बहुत अधिक व्यावहारिक महत्व है तथा यह वास्तविक जगत में पाई जाती है। उन्होंने बताया कि यदि प्रतिनिधि फर्म वास्तविक जीवन में नहीं मिलती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके अध्ययन को छोड़ दिया जाय। उन्होंने बताया कि हम व्यवहार में अनेक ऐसी बातों का अध्ययन करते हैं जो कि भौतिक जगत में वास्तविक रूप से विद्यमान नहीं होती। प्रो मेहता के शब्दों में,— इस प्रकार में बहुत सी ऐसी वस्तुएँ जिनके धारे में हम सब आतचित करत हैं अपना अस्तित्व नहीं रखती, फिर भी वे भौतिक वस्तुओं के समझने में सहायक होती हैं। प्रतिनिधि फर्म भी इसी प्रकार की है। जैसे पर्याप्तता वृत्त या सीधी रेखाएँ मसाल में कही नहीं पाई जाती, फिर भी उनकी अध्ययन में आदर्श माना जाता है। भौतिक सत्कार को काल्पनिक सत्कार की तुलना से ही मूलोत्पत्ति समझा जा सकता है। इस प्रकार प्रो मेहता ने माध्यम के प्रतिनिधि फर्म के विचार का जोरदार शब्दों में समर्थन किया।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रतिनिधि फर्म के विचार का व्यावहारिक महत्व है। इस महत्व के कारण ही प्रतिनिधि फर्म की पुनर्स्थापना की गई है।

or branches of industries of adequate size, under given sets of conditions, a typical or representative magnitude to which business tend to grow. As there is a normal size and form for a man, so, but less markedly are there normal sizes and forms of business.”

—Pigou

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ मार्शल के प्रतिनिधि फर्म के विचार की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा मूल्य निर्धारण में इसके प्रयोग को समझाइए ।
- २ 'प्रतिनिधि फर्म' पर एक नोट लिखिए ।
- ३ मार्शल के प्रतिनिधि फर्म के विचार की व्याख्या कीजिए तथा प्रो जे के मेहता के दृष्टिकोण का भी उल्लेख कीजिए ।

अध्याय १४

★

लगान

[Rent]

★ ★ ★

अर्थशास्त्र के अध्ययन में उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से लगान के सिद्धान्त का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साधारणतया लगान से अभिप्राय उस भुगतान से है जो कि मकान, मशीन, जेत आदि के प्रयोग के बदले में उसके स्वामी को दिया जाता है। अर्थशास्त्र में लगान से अभिप्राय उस भुगतान से है जो कि भूमिपति को भूमि के प्रयोग के बदले में दिया जाता है।

लगान की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार से की गई है। डेविड रिकार्डो (David Ricardo) के अनुसार —

“लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो कि भूमिपति को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है।”^१

कार्वर (Carver) के शब्दों में—“लगान भूमि के उपयोग के बदले में दिया गया मूल्य है।”^२

मार्शल (Marshall) के अनुसार—“भूमि तथा अन्य प्रकृति से प्राप्त निशुल्क उपहारों का स्वामी होने के कारण प्राप्त होने वाले आय को साधारणतया लगान कहते हैं।”^३

1 “Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil.” —Ricardo

2 “Rent is the price paid for the use of land” —Carver

3 “The income derived from the ownership of the land and other free gifts of nature is commonly called rent” —Marshall

इस प्रकार रिकार्डो, मार्शल आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने लगान का सम्बन्ध भूमि से स्थापित किया है। आधुनिक अर्थशास्त्री लगान का विश्लेषण केवल भूमि के सदर्म में ही नहीं करते बल्कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को इसके अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं जिनमें 'भूमि तत्व' (land element) या 'संमितता का गुण' पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, भूमि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भूमि की पूर्ति पूर्ण लोचदार नहीं होती। जिस उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति अल्पकाल में पूर्ण लोचदार नहीं होती वही पर लगान सामान्यतया प्राप्त होता है। स्टोनियर एंड हेन (Stonier and Hague) के शब्दों में—

“लगान से अभिप्राय उन उत्पत्ति के साधनों को किये गये भुगतानों से है जिनकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार नहीं होती।”

जिस साधन की पूर्ति जितनी अधिक बेलोचदार होगी उसे उतना ही अधिक लगान प्राप्त होगा। आधुनिक अर्थ में लगान से अभिप्राय किसी भी उत्पत्ति के साधन को किये गये उन भुगतान से है जो कि उस साधन को उसी कार्य में बनाये रखने हेतु किये जाने वाले न्यूनतम भुगतान से अधिक है।

भीमती जोन रॉबिन्सन के शब्दों में—“लगान के विचार का सार वह आधिक्य है जो कि उत्पत्ति के साधन की एक इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो कि उस साधन की इकाई को अपने कार्य को करते रहने के लिये आवश्यक है।”

इस प्रकार लगान के सम्बन्ध में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और आधुनिक अर्थशास्त्रियों में मौलिक अन्तर है।

रिकार्डो का लगान सिद्धान्त (Ricardian Theory of Rent)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सुविख्यात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो (१७७१-१८२३) द्वारा किया गया। यद्यपि रिकार्डो से पहले 'फिजियोक्रैट्स' (Physiocrats)

4 “The term rent is applied to payments made for factors of production which are imperfectly elastic supply”

—Stonier & Hague

5 “The essence of the conception of the rent is the conception of a surplus earned by a particular part of a factor of production over and above the minimum earning necessary to induce it to do its work.”

—Mrs Joan Robinson

एडम स्मिथ (Adam Smith) तथा माल्थस (Malthus) ने लगान के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किये थे। परन्तु रिकार्डों पहला अर्थशास्त्री है जिसने लगान के निर्धारण के सम्बन्ध में सुस्पष्ट, निश्चित एवं व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। रिकार्डों के अनुसार—

“लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो कि भूमिपति को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है।

रिकार्डों के अनुसार लगान केवल भूमि को ही प्राप्त हो सकता है, उत्पत्ति के दूसरे साधनों को नहीं। क्योंकि रिकार्डों का यह मत है कि भूमि में कुछ विलक्षणताएँ यदि पाई जाती हैं जो कि अन्य साधनों में नहीं होती। भूमि की प्रमुख विलक्षणताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) भूमि की मात्रा सीमित होती है।

(२) भूमि प्रकृति से प्राप्त नि शुल्क उपहार है।

(३) भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता होती है।

(४) भूमि में शक्तिशीलता नहीं पाई जाती।

भूमि की उपर्युक्त विलक्षणताओं को ध्यान में रखकर रिकार्डों ने लगान सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि ‘लगान एक भेदात्मक वचन है (Rent is a differential surplus)।

लगान एक भेदात्मक वचन है—रिकार्डों के अनुसार भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता होती है जिसके परिणामस्वरूप श्रेष्ठ भूमियों को घटिया श्रेणी की भूमियाँ की तुलना में अधिक उपज प्राप्त होती है। यह उपज का अतिरिक्त ही लगान है। दूसरे शब्दों में लगान वह अतिरिक्त है जो श्रेष्ठ भूमियों की कम उपजाऊ भूमियों की तुलना में प्राप्त होता है। इस प्रकार भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता व कारण ही लगान उत्पन्न होता है।

रिकार्डों के लगान या भेदात्मक वचन का अध्ययन सामान्यतः तीन भागों में किया जाता है —

(१) विस्तृत खेती के अन्तर्गत लगान ,

(२) गहरी खेती के अन्तर्गत लगान ,

(३) भूमि की स्थिति में अन्तर होने के कारण लगान।

(१) विस्तृत खेती के अन्तर्गत लगान—इसकी व्याख्या करने के लिए रिकार्डों ने एक ऐसे द्वीप का उदाहरण दिया है जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता। यदि कुछ व्यक्ति

वहा जाकर रहने लगे तो वे सबसे पहले वहा की सर्वश्रेष्ठ भूमि पर खेती करना प्रारम्भ करेंगे । उत्पन्नात जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ घटिया श्रेणी की भूमियों पर खेती की जाने लगेगी ।

प्रारम्भ में जब जनसंख्या कम होती है तब प्रथम श्रेणी की भूमि से ही खाद्यान्न की गमस्त आवश्यकता की पूर्ति करली जाती है । ऐसी स्थिति में लगान शून्य होता है, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है और खाद्यान्न की माग भी बढ़ जाती है तब उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए घटिया श्रेणी की भूमि पर खेती की जाती है । यदि जनसंख्या में और अधिक वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप पड़ोसी हुई माग को पूरा करने के लिए उससे भी घटिया श्रेणी की भूमि पर खेती की जाती है । इस प्रकार यदि भूमि की इन विभिन्न श्रेणियों के समान टुकड़ों पर समान मात्रा में साधन की इकाइया लगायी जाती हैं तो श्रेष्ठ भूमियों से प्राप्त उत्पादन घटिया श्रेणी की भूमियों की अपेक्षा अधिक होता है ।

किसी समय विशेष पर खेती की जाने वाली भूमियों में सबसे घटिया श्रेणी की भूमि को 'सीमान्त भूमि' (marginal land) कहते हैं । सीमान्त भूमि से श्रेष्ठ भूमियों (superior lands) को पूर्व-सीमान्त भूमिया (intra marginal lands) कहते हैं ।

बाजार में वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वह सीमान्त भूमि की औसत लागत के बराबर होता है । यदि मूल्य इससे कम होता है तो कृषक इस भूमे पर खेती नहीं करेगा । पूर्व सीमान्त भूमियों की लागत उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के मूल्य से कम होगी । (क्योंकि पूर्व-सीमान्त भूमियों की उपजाऊ शक्ति सीमान्त भूमि की अपेक्षा अधिक होती है) अतः पूर्व सीमान्त भूमियों की वचत प्राप्त होती है । यही वचन समान है ।

विलियम फैलनर (W. Fellner) ने लिखा है—“पूर्व सीमान्त भूमियों की कीमत तथा लागत का अन्तर ही रिकार्डों का समान है ।”⁶

उत्पादक की वचन की फैलनर ने मीट्रिक रूप में व्यक्त किया है, जबकि रिकार्डों में इसे उत्पादन के रूप में । अतः वचन की दोनों ही रूपों में प्रयुक्त किया जा सकता है ।

उपज का मूल्य सीमान्त भूमि की औसत लागत के बराबर होता है, इसलिये सीमान्त भूमि की कोई वचन प्राप्त नहीं होती है । अतः सीमान्त भूमि समान रहित भूमि (no rent land) होती है ।

6 “The difference between price and cost of production of intra-marginal lands is the Ricardian rent.” —W. Fellner

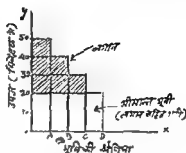
उपयुक्त विश्लेषण को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। हम उदाहरण में लगान की मॉडिक और उत्पादन दोनों ही रूपों में व्यक्त किया गया है।

भूमि की श्रेणियाँ	A श्रेणी की भूमि	B श्रेणी की भूमि	C श्रेणी की भूमि	D श्रेणी की भूमि या सीमान्त भूमि
कुल उत्पादन (बैर के रूप में)	५० बिघा	४० बिघा	३० बिघा	२० बिघा
लगान (उत्पादन के रूप में)	(५०—२०) = ३० बिघा	(४०—२०) = २० बिघा	(३०—२०) = १० बिघा	(२०—२०) = ० या लगान सहित भूमि
कुल लागत (मुद्रा के रूप में)	१००० रु०	१००० रु०	१००० रु०	१००० रु०
बाजार मूल्य	५० रु०	५० रु०	५० रु०	$\frac{१०००}{२०} = ५०$
कुल आय	(५० × ५०) = २५०० रु०	(५० × ४०) = २००० रु०	(५० × ३०) = १५०० रु०	(५० × २०) = १००० रु०
लगान (रुद्र के रूप में)	(२५००—१०००) = १५०० रु०	(२०००—१०००) = १००० रु०	(१५००—१०००) = ५०० रु०	(१०००—१०००) = ० अर्थात् लगान रहित भूमि

रिक्तियों के लगान सिद्धान्त को रेखाचित्र द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है।

समान चित्र में OX अक्ष पर भूमि को चार श्रेणियों में A, B, C तथा D दिखाई गई है। तथा OX अक्ष पर विभिन्न भूमि की श्रेणियों से प्राप्त उपज को दिखाया गया है। समान मात्रा में साधन की इकाइया लगान पर A भूमि से ५० बिघा B से ४०,

C से ३० व D से २० क्विन्टल उपज प्राप्त होती है। D भूमि सीमान्त भूमि है इसलिए इस भूमि पर कोई लगान नहीं लगता है। A भूमि से ३०, B से २० और C से १० क्विन्टल लगान प्राप्त होता है।



जैसा कि पूर्व में ही कहा गया है कि कृषि उपज का बाजार मूल्य सीमान्त भूमि की उत्पादन लागत के बराबर होता है। यदि उपज का मूल्य सीमान्त भूमि की उत्पादन लागत से कम होता है तो सीमान्त भूमि पर उत्पादन कार्य बन्द हो जायेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हानि उठाकर उत्पादन कार्य करना पसन्द नहीं करेगा। जिसके परिणामस्वरूप वस्तु की पूर्ति में कमी हो जायेगी और यदि माग अपरिवर्तित रहती है तो बाजार में वस्तु के मूल्य बढ़ जायेंगे। इसी प्रकार यदि बाजार मूल्य सीमान्त भूमि की उत्पादन लागत से अधिक हो जाते हैं तो अधि सीमान्त भूमि (sub marginal land) पर खेती की जाने लगेगी। इस स्थिति में अब तक की सीमान्त भूमि पूर्व-सीमान्त भूमि बन जायेगी। यदि माग अपरिवर्तित रहती है तो वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बाजार में वस्तु के मूल्य गिर जायेंगे। अतः कृषि उपज का बाजार मूल्य हमेशा सीमान्त भूमि की उत्पादन लागत के बराबर होता है।

- (२) गहरी खेती के अन्तर्गत लगान—रिक्तियों के सिद्धान्त के अनुसार लगान गहरी खेती में भी लागू होता है। गहरी खेती के अन्तर्गत भूमि की विभिन्न ध्रेणियों पर खेती नहीं की जाती बल्कि बड़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए एक ही भूमि पर धम और पूँजी की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से रिक्तियों के अनुसार प्रारम्भ में सीमान्त उपज बढ़ती है लेकिन धीमे-धीमे उपज कम होती जाती है। अन्त में एक स्थिति ऐसी आ जाती है जबकि धम और पूँजी की सीमान्त मात्रा से प्राप्त उपज (या उपज का मूल्य) उस साधन की लागत के बराबर हो जाती है। इस मात्रा को सीमान्त मात्रा (marginal dose) कहते हैं। सीमान्त मात्रा होने के कारण यह लगानरहित मात्रा (no rent dose) होती है। इससे पूर्व की सभी मात्राएँ पूर्व-सीमान्त मात्राएँ (super-marginal doses) होती हैं। इन सभी पूर्व-सीमान्त मात्राओं से प्राप्त उपज सीमान्त मात्रा की उपज से अधिक होती है, सीमान्त मात्रा से अधिक जितनी उपज पूर्व-सीमान्त मात्राओं की

प्राप्त होती है, वही लगान है। इस प्रकार गहरी खेती में भी लगान भेदात्मक बचत है।

विस्तृत खेती के मन्दर्भ में खींचा गया रेखा चित्र गहरी खेती में लगान को भी प्रदर्शित कर सकता है यदि हम भूमि की श्रेणियों के स्थान पर उसे थम और पूँजी की मात्राएँ मान लें। पहली थम व पूँजी को मात्रा लगाने पर उपज ५० बिबटल प्राप्त होती है, दूसरी से ४०, तीसरी से ३० और चौथी मात्रा से २० बिबटल उपज प्राप्त होती है। चौथी मात्रा सीमान्त मात्रा है, अतः लगान रहित मात्रा होगी। दोप पहली, दूसरी व तीसरी मात्राओं पर लगान क्रमशः ३०, २० और १० बिबटल संयोग।

(३) भूमि की स्थिति में अन्तर होने के कारण लगान—रिकाडों के अनुसार—

“समने अधिक उपजाऊ एवं सबसे अच्छी स्थित भूमि पर खेती सबसे पहले की जायेगी। यदि सभी भूमियों की उपजाऊ शक्ति समान है तो लगान उस समय तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि किसी भूमि की स्थिति का लाभ प्राप्त नहीं हो।”^७

इस प्रकार रिकाडों के अनुसार जब सभी भूमि समान उपजाऊ हो तब भूमि की स्थिति में अन्तर होने पर ही लगान उत्पन्न होगा।

समान उपजाऊ भूमियाँ की स्थिति में जो भूमि मण्डी के अधिक पास है वह श्रेष्ठ भूमि होगी तथा जो सबसे अधिक दूर है वह सीमान्त भूमि होगी। मण्डी के पास वाली भूमियों का मातावात व्यय सीमान्त भूमि (अथवा मण्डी से अधिक दूर स्थित भूमि) की अपेक्षा कम होगा। अतः ये भूमियाँ पूँव सीमान्त भूमियाँ होंगी। इस प्रकार पूर्व सीमान्त भूमियों को सीमान्त भूमि की तुलना में बचत प्राप्त होगी। यही वचन लगान होगा।

रिकाडों के सिद्धान्त की मान्यताएँ (Assumptions)

रिकाडों का लगान सिद्धान्त अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धान्तों के समान कुछ मान्यताओं पर आधारित है। रिकाडों के सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताएँ निम्नलिखित हैं—

- 7 “The most fertile and the most favourably situated land will be cultivated first. If all lands are equally fertile, rent will not arise unless a particular land enjoys the advantage of situation.”

—Ricardo

- (१) अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्तों के समान रिकार्डों का लगान सिद्धान्त भी दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है ।
- (२) यह सिद्धान्त मानकर चलता है कि प्रत्येक देश में सीमान्त भूमि (लगान रहित भूमि) पाई जाती है ।
- (३) रिकार्डों यह मानकर चलता है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता पाई जाती है तथा सेतो सबसे पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर की जाती है, उसके बाद उससे घटिया श्रेणी की भूमि पर । दूसरे शब्दों में सेतो अवरोही क्रम (descending order) में की जाती है ।
- (४) इस सिद्धान्त की यह मान्यता है कि भूमि सीमित होती है ।
- (५) रिकार्डों के अनुसार लगान केवल भूमि से ही प्राप्त होता है ।
- (६) रिकार्डों के अनुसार भूमि में "मौलिक तथा अविनाशी शक्तियाँ" पाई जाती हैं जो कि भय साधनों में नहीं होती । भूमि की इन शक्तियों के कारण ही लगान उत्पन्न होता है ।
- (७) रिकार्डों के सिद्धान्त की प्रमुख मान्यता यह है कि भूमि में 'कमामत उत्पत्ति ह्रास नियम' (Law of Diminishing Return) क्रियाशील होता है ।
- (८) यह सिद्धान्त मानकर चलता है कि जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहनी है । इस प्रकार रिकार्डों का लगान सिद्धान्त उपर्युक्त मान्यताओं पर आधारित है ।

रिकार्डों के लगान सिद्धान्त के प्रमुख तत्व

रिकार्डों द्वारा प्रतिपादित लगान सिद्धान्त ने निम्नलिखित तत्व हैं—

- (१) लगान प्रकृति की कृपणता या कमजोरी के कारण उत्पन्न होता है, न कि उदारता के कारण—रिकार्डों ने बताया कि लगान इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि प्रकृति अनुदार है । अधिक उपजाऊ भूमि सीमित मात्रा में पाये जाने के कारण ही घटिया श्रेणी की भूमि पर सेतो की जाती है । इसी प्रकार गहरे सेतो के अन्तर्गत जैसे जैसे श्रम और पूँजी की इकाइयाँ अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं तो प्राप्त उपज कम होती जाती है । इसका कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति सीमित अवकाशित होना है ।
- (२) लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है । भूमि की जितनी अधिक उपजाऊ शक्ति होगी उतना ही अधिक लगान होता है ।

- (३) लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता बल्कि मूल्य लगान को प्रभावित करता है—रिकाडों के अनुसार लगान मूल्य में सम्मिलित नहीं होता और न ही मूल्य को निर्धारित करता है बल्कि मूल्य द्वारा लगान का निर्धारण होता है। रिकाडों के अनुसार उपज का मूल्य निर्धारण सीमान्त भूमि की लगान के आधार पर होता है। रिकाडों के अनुसार—

“अनाज का मूल्य इसलिए ऊँचा नहीं है क्योंकि लगान दिया जाता है, अपितु लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि अनाज का मूल्य ऊँचा है।”^६

इस प्रकार लगान में परिवर्तन उसी स्थिति में होने हैं जबकि अनाज के मूल्य में परिवर्तन होता है। यदि अनाज का मूल्य ऊँचा हो जायेगा तो लगान की मात्रा पूर्व-सीमान्त भूमियों पर बढ़ जायेगी, यदि मूल्य गिर जाते हैं तो लगान की मात्रा पूर्व-सीमान्त भूमियाँ पर घट जायेगी।

- (४) लगान अनाजित आय (Rent unearned income) —रिकाडों के अनुसार लगान भूमिपति के प्रयत्नों के कारण प्राप्त नहीं होता बल्कि भूमे का स्वामी होने के कारण प्राप्त होता है। लगान इसलिये उत्पन्न होता है क्योंकि उपज का मूल्य उत्पादन लागत से अधिक होता है। अन लगान अनाजित आय है।

रिकाडों के सिद्धान्त की आलोचनायें :

यद्यपि अर्थशास्त्र में रिकाडों का लगान सिद्धान्त अत्यन्त लोकप्रिय है फिर भी आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा इस सिद्धान्त की कटु आलोचना की गई है। रिकाडों के सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं—

- (१) रिकाडों का यह विचार उचित नहीं कि भूमि में मौलिक और अविनाशी शक्तियाँ पाई जाती हैं—आलोचकों का यह विचार है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अचछे साधनों का प्रयोग करके वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार यदि भूमि का उपयोग अविवेकपूर्ण ढंग से किया जाय तो उसकी उर्वरता भी शोध नष्ट हो जाती है। इस प्रकार न तो भूमि में मौलिक शक्तियाँ पाई जाती हैं और न ही अविनाशी।

प्रो हेने (Prof Hancey) ने रिकाडों के पक्ष का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि भूमि में कुछ इस प्रकार के तत्त्व पाये जाते हैं जिनको मनुष्य के

प्रयत्नों के द्वारा न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है।
प्रो हेंने (Hancey) के शब्दों में—

“भूमि में कुछ सत्व जैसे जलवायु आदि ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान स्थिति में न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उन्हें बनाया जा सकता है।”^९

- (२) रिकार्डों का कृषि-क्रम ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है—अमरीकी अर्थशास्त्री हेनरी कैरे (Henry Carey) के अनुसार रिकार्डों का यह दृष्टिकोण कि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर सबसे पहले खेती की जाती है गलत है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। प्रो० कैरे ने बताया कि सबसे पहले थोड़ी भूमि पर खेती नहीं की जाती बल्कि उस भूमि पर खेती की जाती है जहाँ पर सुविधा अधिक प्राप्त होती है। कैरे के अनुसार अमरीका में कम उपजाऊ भूमि पर पहले और अधिक उपजाऊ भूमि पर बाद में खेती की गई।

रिकार्डों के समर्थकों का यह विचार है कि रिकार्डों के सिद्धान्त की सत्यता कृषि क्रम पर निर्भर नहीं है। इस कृषि क्रम का उदाहरण केवल विभिन्न भूमियों की उपजों के बीच अन्तर को स्पष्ट करने के लिये दिया गया है।

- (३) रिकार्डों की लगान रहित भूमि (Non-rent Land) या सीमांत भूमि की मान्यता गलत है—आलोचकों का यह विचार है कि व्यवहार में लगान रहित भूमि का सभी देशों में पाया जाता आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिये अधिक जनसंख्या वाले देश में, जहाँ पर कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, सबसे कम उपजाऊ भूमि भी लगान उत्पन्न करती है। इन प्रकार कोई भी भूमि लगान रहित नहीं होती।

- (४) रिकार्डों का सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं है—अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्तों की तरह रिकार्डों का लगान सिद्धान्त भी पूर्ण प्रतियोगिता और दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है। आलोचकों के अनुसार वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता कहीं भी देखने को नहीं मिलती। प्रायः जमींदार या भूमिपति द्वारा किसान से लिया जाा वाला लगान आर्थिक लगान से भी अधिक होता है। इसी प्रकार लगान के निर्धारण में अल्पकाल की उपेक्षा की गई है। जबकि लगान निर्धारण की मान्यता अर्थशास्त्र की अपेक्षा अर्थशास्त्र में अधिक सामने आनी है।

9 “There are certain elements that go with the land, such as climate which in the present state can neither be destroyed nor made”
—Prof Hancey

- (५) रिकार्डों का यह दृष्टिकोण कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता, गलत है—रिकार्डों के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता बल्कि स्वयं मूल्य से प्रभावित होता है। आलोचकों ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान भी मूल्य को प्रभावित करता है। मिल (Mill) तथा अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी विशेष उद्योग अथवा उपयोग की दृष्टि से लगान मूल्य में सम्मिलित रहता है।
- (६) लगान भूमि की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होता है, न कि उत्पादकता के कारण—रिकार्डों के अनुसार लगान भूमि की उपजाऊ शक्ति के कारण होता है। जितनी भूमि अधिक उपजाऊ होगी उतना ही लगान अधिक होगा। आलोचकों ने रिकार्डों के इस दृष्टिकोण को गलत ठहराया है, और कहा है कि लगान का कारण भूमि की सीमितता या दुर्लभता है। उनके अनुसार यदि भूमि की पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक है तो लगान नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही पूर्ति की प्रवृत्ति मांग में बढ़ि हो जाती है तो लगान लगने लगेगा। आलोचकों का विचार है कि यदि सभी भूमियाँ समान रूप से उपजाऊ हैं तब भी उत्पत्ति द्वारा नियम के प्रभावशील रहने के कारण लगान उत्पन्न होगा। इस प्रकार रिकार्डों दुर्लभता लगान (scarcity rent) को सही रूप में स्पष्ट नहीं कर सके हैं।
- (७) लगान केवल भूमि की ही विशेषता नहीं है—रिकार्डों के अनुसार लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है, उत्पत्ति के अन्य साधनों को नहीं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डों के इस दृष्टिकोण की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि लगान केवल भूमि को ही प्राप्त नहीं होता बल्कि उन सभी साधनों को प्राप्त होता है जिनकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार (perfectly elastic) नहीं होती। दूसरे शब्दों में, जिन साधनों की पूर्ति को अल्पकाल में आवश्यकतानुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन साधनों को लगान प्राप्त होता है। श्रीमती रॉबिन्सन के शब्दों में—

‘उत्पत्ति के साधनों की विभिन्न इकाइयाँ भी जो कि श्रम, साहस तथा पूँजी की विस्तृत श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं, लगान प्राप्त कर सकती हैं।’^{१०}

- 10 ‘Particular units of factors of production which belong to the other three broad categories—labour, entrepreneurship and capital, may also earn rent’
—Mrs Robinson

- (८) लगान-निर्धारण के लिए धलप से सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है—आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान-निर्धारण के लिए अलग से सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधनों का हिस्सा निश्चित होता है, उसी प्रकार भूमि का पुरस्कार अर्थात् लगान निश्चित होता है। मन रिकार्डों का अलग से लगान का निर्धारण अधिक महत्व नहीं रखता।

निष्कर्ष :

८

अथपि रिकार्डों के लगान सिद्धान्त की कटु आलोचनाओं को गई है और इसे अध्या-वहारिक और असत्य कहा गया है, फिर भी यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रॉबर्टसन (Robertson) का कहना है कि 'आज भी लगान का प्रतिष्ठित सिद्धान्त शक्तिशाली एक शिक्षाप्रद है।' रिकार्डों के सिद्धान्त में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमेशा सत्य प्रतीत होती हैं।

- (१) रिकार्डों का यह निष्कर्ष सत्य है कि जनसंख्या में वृद्धि होने से उसकी मांग को पूरा करने के लिए घटिया धेनी की भूमि पर खेती को जाने लगती है।
- (२) कृषि क्षेत्र में कितनी ही प्रगति कर ली जाय लेकिन उत्पत्ति द्वारा नियम की क्रिया-शीलता की पूर्णतः समाप्ति नहीं किया जा सकता। यह सम्भव है कि कृषि में सुधार करके इसको छोटे समय के लिए स्थगित कर दिया जाय। जीड एच रिस्ड ने रिकार्डों के सिद्धान्त के महत्व के बारे में लिखा है—

“रिकार्डों का सिद्धान्त अभी अप्रचलित हो सकता है जबकि अन्न का उत्पादन वैज्ञानिक रीति में होने लग जाय। लेकिन उस समय तक यह प्रभावपूर्ण बना रहेगा।”^{११}

- (३) “प्रो रिकार्डों का विचार कि लगान एक अनाजित आय है” ने अर्थशास्त्रियों और विचारकों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसी विचार से प्रभावित होकर बहुत से देशों में अमीदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। समाजवादी विचारक रिकार्डों के सिद्धान्त को सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते हैं क्योंकि यह सिद्धान्त ‘सामूहिक अर्थ-व्यवस्था की आधारशिला है।’ आधुनिक अर्थशास्त्री रिकार्डों के सिद्धान्त को सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से ही ‘सीमितता के गुण’ को ‘भूमि तत्व’ कहते हैं।

11 “When alburnen can be scientifically produced then will the Ricardian theory become obsolete Until then it holds good”

—Prof. Gide and Rust

लगान का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Rent)

रिकार्डों के अनुसार लगान केवल भूमि को ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भूमि में कुछ विश्व गुण पाये जाते हैं जो कि उत्पत्ति के दूसरे साधनों में नहीं होते। इसलिए रिकार्डों ने लगान निर्धारण के लिए अपना अलग से सिद्धान्त प्रतिपादित किया। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री रिकार्डों के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान को भूमि का एकाधिकार नहीं माना जा सकता क्योंकि उत्पत्ति के दूसरे साधनों—धन, पूँजी आदि में भी सीमितता तथा स्थिरता का गुण पाया जाता है, इसलिए अन्य साधन भी लगान प्राप्त कर सकते हैं। अतः आधुनिक अर्थशास्त्री अलग से लगा सिद्धान्त की आवश्यकता को महसूस नहीं करते और माग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त को ही लगान का सिद्धान्त भी मानते हैं।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार रिकार्डों का सिद्धान्त केवल यह व्याख्या करता है कि एक भूमि को दूसरी भूमि की अपेक्षा कम या अधिक लगान क्यों प्राप्त है। लगान उत्पन्न होने का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर रिकार्डों ने नहीं दिया। आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार लगान माग की तुलना में भूमि की सापेक्षिक दुर्लभता (scarcity) के कारण उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, लगान उत्पन्न होने का कारण भूमि की माग की पूर्ति की तुलना में अधिक होना है। पूर्ति की तुलना में माग जितनी अधिक होगी, उतना ही लगान अधिक होगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि और उत्पत्ति के अन्य साधनों में समानता होने के कारण, अन्य साधनों का हिस्सा भी लगान के समान ही निर्धारित होता है।

भूमि की माग व्युत्पन्नित माग (derive demand) होती है। भूमि की माग उपज की माग से सम्बंधित होती है, अर्थात् उपज की माग में कमी या वृद्धि होने से भूमि की माग में भी कमी या वृद्धि हो जाती है। यदि माग बढ़ जाती है तो लगान में भी वृद्धि हो जाती है।

भूमि की पूर्ति समाज की दृष्टि से स्थिर है, परन्तु निजी व्यक्ति (या उद्योग विशेष) की दृष्टि से पूर्ति में परिवर्तन किये जा सकते हैं। परन्तु यह परिवर्तन भी अधिक मात्रा में नहीं किये जा सकते। सामान्यतः भूमि की पूर्ति को बेचोखदार माना जाता है। अतः लगान में होने वाले परिवर्तन भूमि की पूर्ति को प्रभावित नहीं करते।

वान वीजर (Von Wieser) ने उत्पत्ति के साधनों को दो भागों में बाँटा है (a) विशिष्ट साधन (specific factors), (b) अविशिष्ट साधन (non specific

factors) विशिष्ट साधन वे साधन हैं जो कि एक ही कार्य में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। जिनमें गतिशीलता नहीं पाई जाती हो तथा जिनका दूसरे कार्यों में प्रयोग करना सम्भव नहीं हो। आवश्यक साधन वे साधन होते हैं जिनको कई कामों में प्रयुक्त किया जा सके। इनमें पर्याप्त गतिशीलता पाई जाती है।

बीजर का यह मत है कि विशिष्टता एक गुण है जिसे कोई भी साधन प्राप्त कर सकता है। जो साधन एक समय विशिष्ट है वह दूसरे समय अविशिष्ट हो सकता है तथा जो साधन अविशिष्ट है वह दूसरे समय विशिष्ट हो सकता है। वास्तविक रूप में कोई साधन न तो पूर्णरूप से गतिशील होता है और न ही पूर्णरूप से अगतिशील। दूसरे शब्दों में, एक साधन आंशिक रूप से विशिष्ट साधन होता है और आंशिक रूप से अविशिष्ट।

बीजर के उपर्युक्त दृष्टिकोण के आधार पर ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान विशिष्टता का भुगतान है। क्योंकि एक साधन आंशिक रूप से विशिष्ट होता है और आंशिक रूप से अविशिष्ट, इसलिए एक साधन में लगान का भ्रंश उस सीमा तक होता है जिस 'सीमा तक' कि उसमें विशिष्टता का भ्रंश होता है। यदि साधन पूर्णतः अविशिष्ट है तो उसे लगान प्राप्त नहीं होगा।

लगान की परिभाषा तथा व्याख्या

लगान के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या थीमती जोन रॉबिन्सन ने स्पष्ट रूप से की है तथा प्रो. बौलिंग ने इसका मर्ममन किया है। ये दोनों अर्थशास्त्री लगान की व्याख्या में केवल भूमि को ही सम्मिलित नहीं करते। थीमती जोन रॉबिन्सन के शब्दों में—

“लगान के विचार का सार यह आधिक्य है जो कि उत्पत्ति के साधन की एक इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो कि उस साधन की इकाई को अपने कार्य को करने रहने के लिए आवश्यक है।”

प्रो. बौलिंग (Prof. Boulding) ने लगान की निम्न परिभाषा दी है—“आर्थिक लगान वह भुगतान है जो कि साम्य की स्थिति में उद्योग में किसी उत्पत्ति के साधन की एक इकाई को दिया जाता है और वह उस न्यूनतम राशि से अधिक है जो कि उस साधन को उसी व्यवसाय में बनाये रखने के लिए आवश्यक है।”¹²

- 12 “Economic rent may be defined as a unit of a factor of production, in an industry in equilibrium, which is in excess of minimum amount necessary to keep that factor in present occupation.”
—Prof. Boulding

उपयुक्त दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि लगान उत्पत्ति के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है। श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार लगान के उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि साधन की पूर्ति मांग की तुलना में वेलोच हो। दूसरे शब्दों में, लगान उत्पन्न होने का कारण पूर्ति की लोचहीनता है।

आधुनिक लगान सिद्धांत भी रिकार्डों के लगान की तरह लगान को एक प्रकार का 'आविष्य' मानता है। लेकिन रिकार्डों का आधिपत्य से अभिप्राय पूर्व सीमान्त भूमि एक सीमान्त भूमि की उपज का अन्तर है जबकि श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार 'लगान न्यूनतम पूर्ति मूल्य (minimum supply price) के ऊपर आधिपत्य है।' न्यूनतम पूर्ति मूल्य वह मूल्य है जिससे कम धर कोई भी साधन अपनी सेवायें देने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरे शब्दों में, न्यूनतम पूर्ति मूल्य साधन का न्यूनतम पारित्यमिक होता है, जो कि उस साधन को कार्य में बनाये रखने के लिए देना पड़ता है। इस न्यूनतम पूर्ति मूल्य से अधिक प्राप्त होने वाली आय को ही लगान कहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि एक फर्म में किसी एक श्रमिक को मजदूरी ३०० रु प्राप्त होती है, यदि उस श्रमिक को ऐसे ही कार्य के लिए २५० रु मिल सकते हैं तो उसकी वर्तमान मजदूरी का न्यूनतम पूर्ति मूल्य २५० रु है। यदि वर्तमान फर्म का मालिक इस श्रमिक की सेवाओं को अपनी फर्म में लाना चाहता है तो उसे कम से कम २५० रु मजदूरी देनी होगी। यदि उस श्रमिक को २५० रु से कम मजदूरी प्राप्त हाती है तो वह श्रमिक वर्तमान फर्म से नौकरी छोड़ देगा और दूसरी फर्म में कार्य करने लगेगा, जहां पर उसे २५० रु प्राप्त होते हैं। वर्तमान में उसे क्योंकि ३०० रु प्राप्त हो रहे हैं तथा उसका न्यूनतम पूर्ति मूल्य २५० रु है। इस प्रकार उसे ५० रु का आधिपत्य प्राप्त है। अतः लगान ५० रु होगा।

उत्पत्ति के साधन के न्यूनतम पूर्ति मूल्य का आधुनिक अर्थशास्त्री हस्तांतरण आय (transfer earnings) या अवसर लागत (opportunity cost) भी कहते हैं। हस्तांतरण आय या अवसर लागत से अभिप्राय उस शीघ्रिक आय से है जो कि उत्पत्ति के साधन को दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग से प्राप्त होती है।

प्रो बेनहम (Benham) के शब्दों में—“द्रव्य की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त कर सकती है, उसे कभी कभी हस्तांतरण आय कहते हैं।”^{१३}

- 13 "The amount of money which any particular unit could earn in its best paid alternative use is sometimes called its transfer earnings"
—Benham

धोमती रॉबिन्सन ने हस्तांतरण आय की परिभाषा इस प्रकार दी है—“वह मूल्य जो साधन की एक दो हुई इकाई को किसी उद्योग में बनाने रखने के लिए आवश्यक है, हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य कहा जाता है।”¹⁴

किसी भी उत्पादित के साधन की आय दो प्रकार की हो सकती है, उसकी वास्तविक आय (या वर्तमान आय) तथा हस्तांतरण आय। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार समान एक शब्द है जो किसी साधन की इकाई की उसकी हस्तांतरण आय के ऊपर प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, वास्तविक आय एवं हस्तांतरण आय का अन्तर ही समान है। सूत्र के रूप में,

समान = वास्तविक आय (actual earnings)—हस्तांतरण आय (transfer earnings)

उदाहरण के लिए, किसी एक कृषक को एक हेक्टर भूमि पर कपास की खेती करने से ५०० रु की आय प्राप्त होती है, यदि वह किसान उसी भूमि को दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग अर्थात् चावल के उत्पादन में लगा देता है तो उसे ४५० रु की आय प्राप्त होती है। इस प्रकार ४५० रु उस भूमि खण्ड की हस्तांतरण आय है। भूमि कि उस एक हेक्टर का समान ५० रु ($५०० - ४५० = ५०$) होगा। समान के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि 'समान एक शब्द है, इसलिये वह श्रृंखलात्मक नहीं हो सकता।' —

यदि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भूमि को लें, तो भूमि के वैकल्पिक उपयोग सम्भव नहीं है। वैकल्पिक उपयोग न होने के कारण भूमि की हस्तांतरण आय शून्य रहेगी। ऐसी स्थिति में भूमि की कुल आय ही समान बन जाती है। यदि एक उद्योग की दृष्टि से भूमि को लें तो भूमि के अनेक वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं अतः एक उद्योग की दृष्टि से भूमि में हस्तांतरण आय पाई जाती है और समान उत्पन्न होता है।

जैसा कि पूर्व में ही कहा जा चुका है कि समान विनिष्टता का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, समान तब उत्पन्न होगा जबकि साधन की पूर्ति बेलाचदार (inelastic) हो या साधन की पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम (less than perfectly elastic) हो। पूर्ति की लोच के दृष्टिकोण से तीन अवस्थाएँ सम्भव हैं

(१) साधन की पूर्ति पूर्ण लोचदार हो।

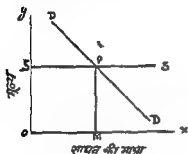
14 “The price which is necessary to retain a given unit of a factor in a certain industry may be called its transfer earnings or transfer price”

(२) साधन की पूर्ति पूर्ण वेलोचदार हो ।

(३) साधनों की पूर्ति इन दो चरम सीमाओं (extremes) के बीच हो अर्थात् लोचदार हो या वेलोचदार ।

उपर्युक्त तीन अवस्थाओं को रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है ।

(१) साधन की पूर्ति पूर्ण लोचदार हो—जब साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो तो कोई लगान प्राप्त नहीं होगा । इस स्थिति में वास्तविक आय एवं हस्तांतरण आय



समान होती है । अतः वचत या आविश्यक प्राप्त नहीं होता । साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होने का अर्थ यह है कि एक विशेष मूल्य पर साधन की कितनी भी इच्छा प्राप्त की जा सकती है और यदि मूल्य में थोड़ी सी कमी आती है तो साधन की पूर्ति शून्य हो जाती है ।

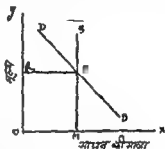
साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होने की स्थिति में साधन की पूर्ति रेखा OX अक्ष के समानान्तर होती है जैसा कि चित्र से स्पष्ट है ।

उपर्युक्त चित्र में DD मांग रेखा है और SS पूर्ति रेखा जो कि OX अक्ष के समानान्तर है क्योंकि साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है अतः साधन पूर्णतया अविशिष्ट है । मांग एवं पूर्ति रेखा P बिन्दु पर काटती है । इसमें प्रयुक्त साधन की मात्रा OM है । इस चित्र में साधन की कुल आय OMPS ($OM \times PM = OM \times PS$) है यही हस्तांतरण आय भी है । अतः कोई वचत प्राप्त नहीं होती अर्थात् लगान शून्य रहता है ।

(२) साधन की पूर्ति पूर्ण वेलोचदार हो—जिस साधनों की पूर्ति पूर्ण वेलोचदार है अर्थात् पूर्ण विशिष्ट है उन साधनों की पूर्ति स्थिर रहती है, क्योंकि ऐसी साधन केवल एक ही प्रयोग में प्रयुक्त किये जाते हैं । चूंकि साधन एक ही प्रयोग में प्रयुक्त किये जा सकते हैं, इसलिये उन साधनों की हस्तांतरण आय शून्य होती है । अतः पूर्ण वेलोचदार साधन की कुल आय ही लगान है ।

साधन की पूर्ति पूर्ण वेलोचदार होने के कारण पूर्ति रेखा OX अक्ष पर खड़ी रेखा होती है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है ।

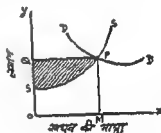
उपर्युक्त चित्र में DD माग रेखा है तथा SM पूर्ति रेखा, जो कि स्थिर है। P बिन्दु पर माग और पूर्ति बराबर है अतः साधन का मूल्य PM हुआ। यदि साधन को PM से कम मूल्य प्राप्त होता है तब भी वह साधन दूसरे व्यनसाय में नहीं जायेगा। अतः साधन की कुल आय OMPR (OM × PR) हस्तांतरण आय शून्य होने के कारण लगान होगी।



(३) साधन की पूर्ति दो चरम सीमाओं में

धीमी हो—यदि साधन की पूर्ति न तो पूर्ण लोचदार है और न ही पूर्ण बेलोचदार अर्थात् पूर्ण लोचदार से कम है। अर्थात् साधन आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अवशिष्ट है तो साधन की समस्त आय या मूल्य का एक भाग लगान होगा। ऐसे साधन की पूर्ति रेखा बायीं ओर से दायीं ओर ऊपर की ओर उठी हुई होती है। इस स्थिति को चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

उपर्युक्त चित्र में SS पूर्ति रेखा है जो कि पूरा लोचदार से कम है तथा DD माग रेखा है। P साम्य बिन्दु है। अतः साधन की आय या मूल्य PM या OQ है तथा साधन की मात्रा OM। इस स्थिति में साधन की कुल आय OMPQ है तथा हस्तांतरण आय OMPQ। इस प्रकार लगान QPS (OMPQ—OMPS) होगा। यही हस्तांतरण आय पर आधिक्य है अथवा वचत है। इस चित्र से यह स्पष्ट है कि साधन OS से कम मूल्य लेने को तैयार नहीं होगा अर्थात् OS मूल्य तक उसकी पूर्ति शून्य होगी। जैसे-जैसे साधन के मूल्य या आय में वृद्धि होगी, वैसे-वैसे उसकी पूर्ति भी बढ़ती जायेगी।



उपर्युक्त विवेचन से लगान के आधुनिक सिद्धान्त की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं—

- (१) लगान केवल भूमि को ही प्राप्त नहीं होता बल्कि उत्पात्ति के प्रत्येक साधन को प्राप्त हो सकता है जिसकी पूर्ति सीमित है।
- (२) लगान हस्तांतरण आय या अन्तर लगान पर अधिक है अर्थात् वास्तविक आय में से हस्तांतरण आय घटाने के बाद लगान बच रहता है।

- (३) लगान उत्पन्न होने का कारण साधन की विशिष्टता है अर्थात् लगान उत्पन्न होने के लिए साधन की पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम होना आवश्यक है ।
- (४) लगान का आधुनिक एक सामान्य सिद्धांत है ।

रिकाडों का लगान सिद्धांत एवं आधुनिक लगान सिद्धांत की तुलना

(Comparison of Ricardian Theory of Rent and Modern Theory of Rent)

रिकाडों द्वारा प्रतिपादित लगान सिद्धान्त की अनेक मूल मान्यताओं का स्वीकार करके आधुनिक लगान सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ । फिर भी दोनों सिद्धान्तों में मूलभूत अन्तर हैं—

- (१) रिकाडों के अनुसार लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है । उनके अनुसार लगान भूमि की मौलिक और अविनाशोपयोगी शक्तियों के उपयोग के बदले में दिया जाता है ।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान प्रत्येक साधन में उत्पन्न हो सकता है यदि उस साधन की पूर्ति सीमित है । इस प्रकार लगान पर भूमि का एकाधिकार नहीं है ।

- (२) रिकाडों के अनुसार लगान उत्पन्न होने का कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता तथा भूमि की स्थितियों में अन्तर है । रिकाडों के अनुसार सीमान्त भूमि से श्रेष्ठ भूमियां लगान प्राप्त करती हैं ।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान 'विशिष्टता' का परिणाम है अर्थात् लगान उत्पन्न होने का कारण किसी साधन की पूर्ति 'पूर्ण लोचदार से कम' होना है ।

- (३) रिकाडों के अनुसार लगान सीमान्त भूमि और पूर्व सीमान्त भूमि की उपज का अन्तर है । इस प्रकार लगान सीमान्त भूमि की लागत की तुलना में मापा जाता है । सीमान्त भूमि समानरहित भूमि होती है । इस प्रकार लगान एक 'आधिक्य' है ।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार वास्तविक आय में से हस्तांतरण आय या अवसर लागत घटा देने पर लगान प्राप्त होता है । इस प्रकार यहाँ भी लगान एक 'आधिक्य' है ।

- (४) रिकाडों के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता । सीमान्त भूमि लगान-रहित भूमि होती है और बाजार में वस्तु का मूल्य सीमान्त भूमि की लागत के

बराबर होता है। अतः लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता अपितु मूल्य से प्रभावित होता है।

आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार कई दशाब्दों में लगान लागत का प्रश्न होता है अतः लगान मूल्य को प्रभावित करता है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. रिकार्डों के लगान सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
२. लगान से क्या अभिप्राय है? आर्थिक लगान किस प्रकार निर्धारित होता है।
३. लगान के आधुनिक सिद्धान्त का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
४. रिकार्डों के लगान सिद्धान्त को समझाइए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त में क्या संशोधन और परिवर्तन किए हैं।
५. लगान के आधुनिक सिद्धान्त को समझाइए। क्या आधुनिक सिद्धान्त रिकार्डों के लगान सिद्धान्त का एक सुधार है?
६. "लगान विधिगता का परिणाम है" इस कथन की व्याख्या कीजिए।
७. लगान मूल्य में सम्मिलित नहीं होता। रिकार्डों के सिद्धान्त के आधार पर इस कथन की व्याख्या कीजिए।
८. "लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो कि भूमिपति को भूमि की मौलिक और निविदाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए।
९. "भनाज का मूल्य इसलिए ऊँचा नहीं है कि लगान दिया जाता है बल्कि लगान इसलिए ऊँचा है क्योंकि उपज का मूल्य ऊँचा है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।
१०. लगान सभी उत्पन्न होता है जबकि साधन की पूर्ति सोचदार से कम हो। इस कथन की विवेचना कीजिए।
११. 'लगान केवल भूमि को ही प्राप्त नहीं होता बल्कि उत्पत्ति के सभी साधनों को प्राप्त होता है; इस कथन को स्पष्ट कीजिए। रिकार्डों के लगान सिद्धान्त तथा आधुनिक सिद्धान्त की तुलना कीजिए।

अध्याय १५

★

मजदूरी [Wages]

★ ★ ★

श्रम उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। अर्थशास्त्र में श्रम को मिलने वाले पुरस्कार को मजदूरी कहते हैं। दूसरे शब्दों में मजदूरी वह भुगतान है जो कि श्रमिक को उसकी सेवाओं के बदले दिया जाता है। मजदूरी को परिभाषा कुछ विद्वानों ने इस प्रकार दी है—

प्रो. बेनहम (Prof Benham) के शब्दों में—“मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो कि समझौते के अधीन सेवायोजक द्वारा श्रमिक को उसकी सेवाओं के बदले दिया जाता है।”^१

प्रो जीड (Prof Gide) के अनुसार—“मजदूरी उस श्रम का मूल्य है जो कि साहसी द्वारा बिराये पर लेकर प्रयोग में लाया जाता है।”^२

प्रो. टॉसिग (Prof. Taussig) के विचार में—“मजदूरी उन निश्चित धन के रूप में भुगतान है जो कि सेवायोजक द्वारा श्रमिक को दिया जाता है।”^३

-
- 1 “A wage may be defined as a sum of money paid under contract by an employer to a worker in exchange for services rendered”
—Prof. Benham
 2. “It (wages) should in a word, be defined as a price of labour hired and employed by an entrepreneur.” —Prof. Gide
 - 3 “Wages is the payment of stipulated amounts by an employer”
—Prof. Taussig

उपर्युक्त परिभाषाओं में यद्यपि मजदूरी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु सभी परिभाषाएँ मजदूरी को सङ्कुचित रूप में लेती हैं। ये परिभाषाएँ मजदूरी की व्याख्या धन के रूप में ही करती हैं, अतः पूर्ण नहीं हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप में किया है, उनके अनुसार —“राष्ट्रीय आय का वह भाग जो श्रमिक को दिया जाता है उसे मजदूरी कहते हैं।” दूसरे शब्दों में—“श्रम की सेवा के लिये दिया गया मूल्य मजदूरी है।”

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण को समझने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है—

- (१) अर्थशास्त्र में ‘श्रम’ शब्द से अमिषाय शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के श्रम से है। अतः मजदूरी दोनों प्रकार के श्रम के लिए दिया गया भुगतान है।
- (२) अर्थशास्त्री ‘श्रम’ को व्यापक अर्थ में लेते हैं जबकि मजदूरी का अर्थ निम्न वर्ग के भुगतान से लेते हैं।
- (३) वेतन शब्द का प्रयोग विभिन्न फर्मों पर फँदित्रों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के सम्बन्ध में किया जाता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से वेतन तथा मजदूरी में कोई अन्तर नहीं है।
- (४) वकील, प्राध्यापक या डॉक्टर आदि व्यावसायिक व्यक्तियों का पुरस्कार भी मजदूरी के अन्तर्गत आता है।
- (५) छोटे-छोटे व्यापारी तथा हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों की सेवाओं का पुरस्कार भी मजदूरी है।
- (६) बोनस, रायल्टी, कमीशन इत्यादि को भी आधुनिक अर्थशास्त्री मजदूरी के अन्तर्गत लेते हैं।

इस प्रकार अर्थशास्त्र में मजदूरी शब्द अत्यन्त व्यापक है।

मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत (Theories of Wage Determination)

राष्ट्रीय आय का वह भाग जो श्रमिकों को दिया जाता है, उसे मजदूरी कहते हैं। राष्ट्रीय आय से श्रमिकों को मिलने वाले इस भाग को निर्धारित करने के लिए समय-समय पर अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व

मजदूरी निर्धारण का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, परन्तु जैसे जैसे नई व्यवस्था से जटिलतायें उत्पन्न होने लगी वैसे वैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा मजदूरी निर्धारण के लिए अनेक सिद्धांत दिये जाने लगे। यद्यपि आधुनिक सिद्धांत के प्रतिपादन के फलस्वरूप प्राचीन सभी सिद्धांत असत्य कर दिये गये हैं। फिर भी अध्ययन की पूर्णता के लिए प्राचीन सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक है। मजदूरी निर्धारण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

- १ मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत
(The subsistence theory of wages),
- २ मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत
(Standard of living theory of wages),
- ३ मजदूरी कोष सिद्धांत
(The wage fund theory)
- ४ मजदूरी का अवशेष अधिशारी सिद्धांत
(Residual climate theory),
- ५ मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत
(The marginal productivity theory of wages),
- ६ मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत
(Modern theory of wages)।

१ मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत (The Subsistence Theory of Wages)

इस सिद्धांत का प्रतिपादन १८वीं शताब्दी के प्रकृतिवादी (Physiocrats) अर्थशास्त्रियों ने किया। मारबस के 'जनसंख्या के सिद्धांत' के प्रकाश में आने के बाद इस सिद्धांत के समर्थकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। जर्मनी के अर्थशास्त्री लार्साली (Larsalie) ने इस सिद्धांत का समर्थन किया तथा प्रो रिवाडों ने इसका समर्थन और स्पष्टीकरण किया।

मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है—

- (१) इस नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों में लगातार वृद्धि की जाय, तो कुछ समय पश्चात् इसमें कमी होती जानी है, अर्थात् यह नियम 'उत्पत्ति ह्रास नियम' पर आधारित है।
- (२) जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती रहती है।

इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार मजदूरी प्राकृतिक नियम द्वारा निर्धारित होती है ।

प्रो रिकार्डों के शब्दों में “श्रम का प्राकृतिक मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिक को एक दूसरे के साथ निर्वाह करने के लिए तथा अपनी जाति की मिना वृद्धि अपना कमी के, स्थिर बनाये रखने के लिये आवश्यक होता है ।”

रिकार्डों का विचार था कि मजदूरी साद्य पदार्थों और अनिवार्य वस्तुओं के रूप में समान रहती है । इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी श्रमिकों को इतनी दी जानी चाहिये जो जीवन निर्वाह के बराबर हो । दीर्घकाल में मजदूरी न इससे कम होती है और न इससे अधिक । मजदूरी में स्थिरता के कारण ही लैसली (Lassalle) ने इस सिद्धांत को “मजदूरी का लोह नियम” (Iron law of wages) कहा है ।

इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी समय मजदूरी जीवन निर्वाह से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक में प्रतियोगिता बढ़ेगी, और मजदूरी गिरकर जीवन निर्वाह के स्तर तक आ जायेगी । यदि मजदूरी जीवन निर्वाह से कम है तो श्रमिकों की संख्या में कमी होगी, परिणामस्वरूप श्रमिकों की पूर्ति न कमी होगी और मजदूरी बढ़कर जीवन निर्वाह तक पहुँच जायेगी । इस प्रकार, इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी जीवन निर्वाह के स्तर के बराबर होती है ।

प्रो जोड (Prof Gode) के अनुसार यह सिद्धांत बहुत अधिक निराशावादी व आशावादी दोनों दृष्टिकोणों को लिए हुये है । निराशावादी इसलिए क्योंकि यह श्रमिक के लिए श्रमिक सुविधाओं को सम्भावनाओं को अस्वीकार कर देता है । आशावादी इस दृष्टिकोण से कि यह सिद्धांत मजदूरी का न्यूनतम स्तर निर्धारित कर देता है जिससे कम श्रमिकों को मजदूरी नहीं दी जा सकती । इसी तथ्य के आधार पर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया ।

सिद्धांत की आलोचना (Criticism) :

मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत को अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई है, इनमें से प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

१. यह सिद्धांत माँग पक्ष की अपेक्षा करता है । यह सिद्धांत मजदूरी निर्धारण

4 “The natural price of labour is that price which is necessary to enable the labourers one with another to subsist and perpetuate their race without either increase or diminution”

—Ricardo

की केवल श्रमिकों की पूर्ति की दशाओं के आधार पर ही व्याख्या करता है, जबकि साधन के मूल्य निर्धारण के लिए दोनों पक्षों माग व पूर्ति का विचार करना होता है। श्रमिकों की माग उनकी उत्पादकता पर आधारित होती है अतः मजदूरी का सम्बन्ध उत्पादकता से होना आवश्यक है परन्तु यह सिद्धांत इस पक्ष की अवहेलना करता है।

२. यह सिद्धांत 'जनसंख्या सिद्धांत' पर आधारित है। अतः दोषपूर्ण सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इस सिद्धांत में दोष स्वतः ही आ जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी में वृद्धि से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। परन्तु अनुभव इसके विपरीत है मजदूरी में वृद्धि होने से जीवन स्तर ऊँचा उठता है जो कि जन्म दर में कमी कर देता है।

३. यह सिद्धांत श्रमिकों की कार्यक्षमता पर ध्यान नहीं देता है। सामान्यतः कार्यक्षमता में वृद्धि होने से श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। जिसके फलस्वरूप मजदूरी में भी वृद्धि होना आवश्यक है।

४. यह सिद्धांत निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत मानकर चलता है कि श्रमिकों के भविष्य के सुधार करना सम्भव नहीं है। परन्तु व्यवहार में, श्रमिकों के जीवन स्तर में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

५. यह सिद्धांत विभिन्न व्यवसायों, व्यक्तियों तथा क्षेत्रों में पाई जाने वाली मजदूरी की भिन्नता की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत सबके लिए एक ही मजदूरी की कल्पना करता है।

६. यह सिद्धांत मजदूरी निर्धारण में श्रमिक सघों के प्रभाव को स्थान नहीं देता है।

इस सिद्धांत में अनेक दोष हैं, जिसके कारण अब इस सिद्धांत का केवल ऐतिहासिक महत्व रह गया है।

२. मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत (Standard of Living Theory of Wages)

जीवन निर्वाह सिद्धांत की आलोचना के उपरांत कुछ अर्थशास्त्रियों ने 'जीवन स्तर सिद्धांत' का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत जीवन निर्वाह के सिद्धांत पर एक सुधार है। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी श्रमिकों के जीवन स्तर द्वारा निर्धारित होती है। जीवन स्तर से अमित्राय केवल आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति से ही नहीं होता अपितु इसमें शिक्षा, विधाम आदि की सुविधायें भी सम्मिलित होती हैं जिनका कि उपयोग करने का

श्रमिक अभ्यस्त हो जाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी में स्थिर रहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। जीवन स्तर में परिवर्तन होने से मजदूरी में भी परिवर्तन हो जाते हैं और इस परिवर्तन से श्रमिक की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है।

इस सिद्धांत के अनुसार यदि श्रमिकों को मजदूरी जीवन स्तर से कम दी जाती है तो घटुआ से श्रमिक शादी करने में असमर्थ होंगे, जिससे उनकी सख्या में कमी हो जायेगी। श्रमिकों की सख्या में कमी होने से श्रमिकों की पूर्ति में कमी होगी परिणामस्वरूप मजदूरी बढ़कर जीवन स्तर के बराबर हो जायेगी यदि। मजदूरी जीवन स्तर से अधिक होगी तो श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जायेगी और मजदूरी घटकर जीवन स्तर के बराबर हो जायेगी।

सिद्धांत की आलोचना (Criticism) .

यद्यपि यह सिद्धांत जीवन निर्वाह के सिद्धांत की अपेक्षा श्रेष्ठ है फिर भी यह सिद्धांत अपूर्ण है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचनाय की है

- (१) जीवन निर्वाह के सिद्धांत के समान ही यह सिद्धांत भी केवल पूर्ति पर जोर देता है जबकि मजदूरी का निर्धारण केवल जीवन स्तर द्वारा नहीं होता अपितु श्रमिक की उत्पादकता (या माग) भी मजदूरी को प्रभावित करती है।
- (२) आलोचकों के अनुसार जीवन स्तर नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कि श्रमिक आदी हो जाता है। वास्तव में जीवन स्तर परिवर्तनशील है जो कि समय या परिस्थिति के साथ बदलता रहता है।
- (३) इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण जीवन स्तर से होता है। आलोचकों के अनुसार यह भी सत्य है कि मजदूरी से भी जीवन स्तर प्रभावित होता है। वास्तव में दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत आंशिक रूप से ही सत्य है।
- (४) आलोचकों के अनुसार यह सत्य है कि जीवन स्तर का प्रभाव श्रमिकों की माग और पूर्ति पर पड़ता है परन्तु यह प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से मजदूरी का निर्धारण श्रमियों की माग और पूर्ति के द्वारा ही होता है।

इस प्रकार यह सिद्धांत भी अनेक दोषों से युक्त है, अतः अर्थशास्त्रियों ने दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

मजदूरी कोष सिद्धांत (The Wage Fund Theory)

इस सिद्धांत के सम्बन्ध में प्रारम्भ में अनेक प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार दिये हैं, परन्तु जे एस मिल (J S Mill) ने इस व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। अतः मजदूरी कोष सिद्धांत का सम्बन्ध जे एस मिल से ही जोड़ा जाता है। मिनर अनुसार श्रमिकों का मजदूरी देने के लिए पूँजीपतियों द्वारा पूँजी का एक भाग अलग रख दिया जाता है। इस अलग रखे हुए भाग को 'मजदूरी कोष' (Wage Fund) कहते हैं। मिल के अनुसार 'मजदूरी कोष' की मात्रा और जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करती है।

जे एस मिल के शब्दों में— 'मजदूरी मुख्यतः श्रमिकों की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है, यद्यपि जैसा कि प्रायः यह कहा जाता है कि मजदूरी जनसंख्या और पूँजी के अनुपात पर निर्भर करती है।'^१

मजदूरी कोष श्रमिकों की मांग को प्रभावित करता है। कोष की मात्रा अधिक होने पर श्रमिकों की मांग अधिक होगी। तथा कम होने पर श्रमिकों की मांग कम होगी। मजदूरी कोष का निर्माण पिछली वषटों के द्वारा होता है। यह कोष सामान्यतः अपरिवर्तित तथा स्थिर रहता है। मजदूरी कोष के स्थिर रहने के कारण मजदूरी प्रत्यक्षतः श्रमिकों की संख्या (या पूर्ति) पर निर्भर करती है। यदि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है तथा मजदूरी कोष स्थिर रहता है तो मजदूरी घट जायेगी। इसके विपरीत यदि श्रमिकों की संख्या में कमी होती है और 'कोष' स्थिर रहता है तो मजदूरी बढ़ जायेगी। इस प्रकार मजदूरी कोष में श्रमिकों की संख्या का भाग देन पर सामान्य मजदूरी की दर प्राप्त हो जाती है।

इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी की दर में वृद्धि दो ही स्थितियों में सम्भव है—

- (a) मजदूरी कोष की वृद्धि की जाय, या
- (b) श्रमिकों की संख्या में कमी की जाय।

जे एस मिल के शब्दों में— "मजदूरी, जो कि सामान्य दर है, में वृद्धि बिना उस कोष की मात्रा में वृद्धि किए हुए जो कि श्रमिकों को किराये पर रखने के लिए निश्चित करदी गई है या किराये पर रखे जाने वाले प्रतियोगियों (श्रमिकों) की

5 "Wages depend mainly upon the supply and demand of labour or as it is often expressed, on the proportion between population and capital"
—J S Mill

सख्या में कमी किये हुए नहीं बढ़ायी जा सकती और न ही उस कोष में बिना कमी किये हुए या बिना श्रमिकों की सख्या में वृद्धि किये हुये मजदूरी को कम किया जा सकता है ।”^६

चूँकि मजदूरी कोष निम्नलिखित बच्चों का परिणाम है और यह समय विशेष में स्थिर रहता है । इसलिए मजदूरी में वृद्धि करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि श्रमिक अपनी सख्या में कमी कर दें । इस प्रकार यह सिद्धांत श्रम सत्रों द्वारा मजदूरी में वृद्धि करवाने के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों को भी अस्वीकार कर देता है ।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism) *

यद्यपि ‘मजदूरी कोष सिद्धांत’ मान्य तथा पुष्टि दोनों पक्षों के आधार पर मजदूरी निर्धारण की बात करता है फिर भी इसकी अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई है । इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि ‘मजदूरी कोष कहाँ से आता है और इस कोष की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है । यह केवल व्याख्या करता है कि मजदूरी कोष में श्रमिकों की सख्या का भाग देने से मजदूरी की दर ज्ञात हो जाती है ।
- (२) आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत सभी श्रमिकों को समान मान लेता है अर्थात् श्रमिकों की कार्यक्षमता पर कोई ध्यान नहीं देता । यदि श्रमिकों की कार्यक्षमता अधिक है तो उत्पादन में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप श्रमिक अधिक मजदूरी प्राप्त कर सकेंगे और मजदूरी कोष की मात्रा बढ़ जायेगी । इस प्रकार श्रमिकों की कार्यक्षमता में अन्तर होने पर मजदूरी की दर में भी अन्तर आ जाता है ।
- (३) मजदूरी कोष सिद्धान्त भवैज्ञानिक और तर्कहीन है क्योंकि पहले यह मजदूरी कोष की बात करता है और बाद में मजदूरी निर्धारण की समस्या पर विचार करता है । जबकि पहले मजदूरी की दर को ज्ञात करना चाहिए बाद में मजदूरी कोल ज्ञात किया जाना चाहिए ।

6 “Wages meaning of the course general rate cannot but by an increase of the aggregate funds employed in hiring labour, or a diminution in the number of competitors for hire, not fall, except by a diminution of the funds devoted to paying labour, or by an increase in the number of labourers to be paid

- (२) यह सिद्धान्त मान लेता है कि श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि श्रमिकों की सख्या में कमी या मजदूरी कोष में वृद्धि के कारण ही सम्भव है, यह अवास्तविक है। आलोचकों के अनुसार मजदूरी में वृद्धि पूँजीपतियों में प्रतिस्पर्धा के कारण होती है जबकि यह सिद्धान्त इस तथ्य को नहीं समझा पाता।
- (५) यह सिद्धान्त यह नहीं समझा पाता कि विभिन्न उद्योगों में मजदूरी की दर में भिन्नता क्यों पाई जाती है।
- (६) इस सिद्धान्त की यह मान्यता तर्कसंगत नहीं है कि मजदूरी में वृद्धि पूँजीपतियों के लाभ को कम कर देती है तथा मजदूरी में कमी लाभ में वृद्धि कर देती है। आलोचकों के अनुसार श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि तथा उत्पत्ति वृद्धि निम्न के क्रियाशील होने के परिणामस्वरूप कुल उत्पादन में अधिक वृद्धि हो जाती है जिससे कि श्रमिकों की मजदूरी तथा पूँजीपतियों के लाभ दोनों ही बढ़ जाते हैं।
- (७) इस सिद्धान्त के कथन तथा स्पष्टीकरण में अन्तर है। यह सिद्धान्त प्रारम्भ में यह बताता है कि मजदूरी श्रम की भाग और पूँति से निर्धारित होती है। बाद में बताता है कि श्रम की भाग पूँजी पर निर्भर करती है, जो कि स्थिर है। अनिष्कर्ष निकलता है कि मजदूरी पूँति से ही प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में, 'मजदूरी कोस' स्थिर रहने के कारण मजदूरी निर्धारण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता, वास्तव में श्रमिक की पूँति ही मजदूरी निर्धारित करती है।

उद्धृत आलोचनाओं से स्पष्ट है कि मजदूरी कोष सिद्धान्त में अनेक दोष हैं। इन दोषों के कारण ही मिल ने बाद में इस सिद्धान्त को त्याग दिया।

४ मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (The Residual Claimant Theory of Wages)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अमेरिकन अर्थशास्त्री वाकर (Walker) ने किया है। वाकर ने कुल उत्पादन को चार भागों में बाँटा है—लगान, व्याज, मजदूरी और लाभ। उद्योग के कुल उत्पादन में से लगान, व्याज और लाभ निकाल देने के बाद जो शेष रह जाता है उस पर श्रमिक का अधिकार होता है। इस प्रकार वाकर के अनुसार श्रमिक उद्योग के उत्पादन के अवशेष का अधिकारी होता है, इसलिए इसे अवशेष अधिकारी सिद्धान्त कहते हैं।

वावर के ही शब्दों में—“कुल उत्पादन में से लगान, ब्याज और लाभ घटा देने के बाद जो शेष बचता है, मजदूरी उसी के बराबर होती है।”^७

वावर के अनुसार लगान, ध्याज तथा लाभ का भुगतान कुल उत्पादन के आधार पर न किया जाकर कुछ निश्चित नियमों के द्वारा किया जाता है। मजदूरी निर्धारण के लिए कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है। कुल उत्पादन में से लगान, ब्याज और लाभ का भुगतान करने के उपरान्त जो कुछ शेष बचता है वह मजदूर का हिस्सा होता है।

इस प्रकार श्रमिक को बचे हुए भाग का अधिकारी मानकर वावर मजदूरी को श्रमिक की कार्यक्षमता या उत्पादकता से सम्बन्धित कर देता है। दूसरे शब्दों में, कार्यक्षमता या उत्पादकता में परिवर्तन होने पर मजदूरी में भी परिवर्तन होगा। यदि कार्यक्षमता बढ़ जाती है तो कुल उत्पादन बढ़ेगा और मजदूरी श्रमिकों को अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। कार्यक्षमता घटने पर मजदूरी भी घट जायेगी।

मजदूरी का सम्बन्ध कार्यक्षमता से स्थापित कर वाकर निराशावादी दृष्टिकोण से मुक्त हो गया है। यह सिद्धांत मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का आधार भी है।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism)

यद्यपि यह सिद्धान्त पूर्व के सिद्धान्तों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, फिर भी दोषरहित नहीं है। इसकी प्रमुख आलोचनाय निम्नलिखित हैं —

- (१) यह सिद्धान्त मांग पक्ष अर्थात् श्रमिकों की उत्पादकता पर ध्यान देता है, पूर्ति पक्ष की उपेक्षा करता है। इस प्रकार यह सिद्धान्त एकपक्षीय है।
- (२) इस सिद्धान्त के अनुसार लगान, ब्याज तथा लाभ उत्पादन की मात्रा से अलग निश्चित नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं, अर्थात् उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी इन मापनों का हिस्सा स्थिर रहता है, परन्तु अनुभव इससे विपरीत है। उत्पादन की स्थिति में परिवर्तन होने पर लाभ की मात्रा में परिवर्तन होता रहते हैं।
- (३) इस सिद्धान्त के अनुसार श्रमिक उत्पादन अवशेष का अधिकारी होता है जबकि अब सभी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि लाभ वास्तव में बचत है और सभी मापनों के मूल्य प्रायः स्थिर रहते हैं।

7 “Wages are equal to the whole product minus rent, interest and profit”
Walker

(४) इस सिद्धान्त में मजदूरी पर श्रमिक सघों के पड़ने वाले प्रभाव की उपेक्षा की गई है।

५. मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory of Wages)

मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त अलग से कोई सिद्धान्त न होकर वितरण के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का मजदूरी के क्षेत्र में प्रयोग मात्र है।

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का निर्धारण श्रम की सीमान्त उत्पादकता के द्वारा होता है। साम्य की स्थिति में मजदूरी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है। उत्पादक किसी भी कार्य में उस सीमा तक श्रमिकों को लगाते हैं जहां पर कि इनसे प्राप्त सीमान्त आय इस पर किये गये व्यय के बराबर हो।

श्रम की सीमान्त उत्पादकता का पता एक इकाई कम या एक इकाई अधिक लगाकर लगाते हैं, दूसरे शब्दों में, श्रम की अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह श्रम की सीमान्त उत्पादकता होती है। यदि मजदूरी सीमान्त उत्पादकता से अधिक मिलती है तो उत्पादकों को हानि होगी अतः वह श्रमिकों की माँग कम कर देंगे। यदि मजदूरी सीमान्त उत्पादकता से कम है तो उत्पादकों को लाभ होगा और वे अधिक श्रमिकों की माँग करेंगे। साम्य की स्थिति में मजदूरी ठीक सीमान्त उत्पादकता के बराबर होगी।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism)

इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) यह सिद्धान्त केवल श्रमिक की माँग (उत्पादकता) पर विचार करता है, पूर्ति पक्ष की अवहेलना करता है।
- (२) इस सिद्धान्त के अनुसार श्रम की सभी इकाइयाँ समान होती हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं पाया जाता।
- (३) यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है।
- (४) यह सिद्धान्त मानकर चलता है कि श्रम की सीमान्त उत्पादकता का आसानी से पता लगाया जा सकता है। परन्तु समुक्त प्रयत्नों के द्वारा उत्पादन की स्थिति में या साधन के निश्चित अनुपात के प्रयोग की स्थिति में सीमान्त उत्पादकता का पता लगाना कठिन है।

(५) यह सिद्धान्त पूर्ण गतिशीलता की मान्यता पर आधारित है। व्यवहार में श्रम में पूर्ण गतिशीलता नहीं पाई जाती।

यद्यपि इस सिद्धान्त की काफी आलोचना की गई है, परन्तु यह मजदूरी निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

६ मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Wages)

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी निर्धारण के पुराने सभी सिद्धान्तों को अमान्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि मजदूरी श्रम की सेवाओं का मूल्य है। श्रम का मूल्य भी वस्तु के मूल्य के समान माग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धान्त ही मजदूरी निर्धारण का सिद्धान्त है। परन्तु श्रम की अपनी विशिष्टताएँ होती हैं, इस कारण मजदूरी के निर्धारण का अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है।

आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार एक उद्योग में मजदूरी उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहाँ पर कि श्रमिकों की कुल माँग रेखा तथा कुल पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती है।

मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धान्त का अध्ययन हम दो शीपों के अन्तर्गत करेंगे —

(१) पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण।

(२) अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण।

(१) पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण (Wage Determination under Perfect Competition)

जैसा कि पूर्व में ही कहा गया है कि मजदूरी का निर्धारण श्रम की माग और पूर्ति के द्वारा होता है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी निर्धारण का अध्ययन करने के लिए माग और पूर्ति रेखा का निर्माण करना आवश्यक है।

श्रम की माग (Demand for Labour),

किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिये उत्पादकों द्वारा श्रम की माग की जाती है, अर्थात् श्रम की माँग इसलिए की जाती है क्योंकि श्रम में उत्पादकता है। कोई भी साहसी

या उत्पादक श्रम की माग करते समय श्रम की सीमान्त उत्पादकता के मौद्रिक मूल्य या सीमान्त उत्पादकता के मूल्य (value of marginal product) को ध्यान में रखता है। जब उत्पादक द्वारा श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उत्पत्ति ह्रास नियम त्रियाशील होने के कारण श्रम की सीमान्त उत्पादकता घटती जाती है। उद्योग में एक उत्पादक श्रमिकों की माग उस सीमा तक करेगा जहाँ तक कि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी और सीमान्त उत्पादकता का मूल्य बराबर होता है। कोई भी उत्पादक श्रम की उत्पादकता से अधिक मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से उसको हानि होती है। अतः श्रम की सीमान्त उत्पादकता का मूल्य या श्रम की सीमान्त उत्पादकता उत्पादकों द्वारा की जाने वाली श्रम की माग की अधिकतम सीमा है।

एक निश्चित समय एक मूल्य पर उत्पादक द्वारा मागी गई श्रम की मात्रा ही श्रम की माग है। श्रम की माग अथवा श्रम की माग की लोच के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं —

- (१) श्रम की माग व्युत्पादित माग (derived demand) होती है। अर्थात् श्रम द्वारा उत्पादित वस्तु की माग के आधार पर ही श्रम की माग की जाती है। श्रम द्वारा उत्पादित वस्तु की माग में कमी या वृद्धि हो जाने से श्रमिकों की माग में भी कमी या वृद्धि हो जाती है।
- (२) श्रम की माग उत्पत्ति के दूसरे साधनों की कीमतों पर भी निर्भर करती है। यदि अन्य सहयोगी साधनों की कीमत अधिक बढ़ जाती है तो श्रम का प्रयोग अधिक होने लगता है। तथा अन्य साधनों की कीमत घट जाने पर श्रम का प्रयोग कम होता है।
- (३) श्रम की माग उत्पत्ति की तकनीकी दशाओं पर निर्भर करती है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन में श्रम तथा अन्य साधनों के मिलने का अनुपात स्थिर रहता है जबकि अन्य वस्तुओं के उत्पादन में यह अनुपात परिवर्तनशील होता है। इस सम्बन्ध के साथ ही माग में परिवर्तन होते रहते हैं।

श्रम की माग रेखा मजदूरी की विभिन्न दरों पर मागी जाने वाली श्रम की मात्रा को बताती है। साधारणतया उद्योग में माग रेखा बायीं से दायीं ओर नीचे की



युक्तता हुई होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह रेखा बताती है कि यदि मजदूरी की दर अधिक है तो श्रमिकों की मांग कम होगी, तथा मजदूरी कम होने पर श्रमिकों की मांग अधिक होगी। इस प्रकार मजदूरी तथा श्रम की मांग में उल्टा सम्बन्ध होता है।

श्रम की पूर्ति (Supply of Labour)

श्रम की पूर्ति से अभिप्राय श्रमिकों की उस संख्या से है जो कि मजदूरी की भिन्न भिन्न दरों पर कार्य करने के लिए तत्पर रहती है तथा श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्य के उन घण्टों एवं दिनों से है जिन्हें प्रत्येक श्रमिक देने के लिये तैयार रहता है। इस प्रकार श्रम की पूर्ति से अभिप्राय विशेष प्रकार के श्रम के उन दिनों एवं घण्टों में है जिन्हें मजदूरी की विभिन्न दरों पर कार्य करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

साधारणतया मजदूरी और पूर्ति में सीधा सम्बन्ध होता है, अर्थात् मजदूरी में वृद्धि होने पर श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाती है, कमो होने पर पूर्ति घट जाती है। जिस प्रकार उत्पादक का उद्देश्य अपनी वस्तु के लिए कम से कम उस वस्तु की उत्पादन लागत के बराबर मूल्य प्राप्त करने का होता है, उसी प्रकार श्रमिक का उद्देश्य भी अपनी सेवाओं के बदले कम से कम सीमान्त त्याग (marginal sacrifice) के बराबर मजदूरी प्राप्त करने का होता है। दूसरे शब्दों में, श्रमिक कम से कम इतनी मजदूरी प्राप्त करना चाहता है जिससे कि वह अपना तथा अपने परिवार का जीवनयापन उस स्तर पर कर सके, जिसका कि वह अभ्यस्त हो गया है। इस प्रकार मजदूरी की न्यूनतम दर जीवन स्तर या सीमान्त त्याग है, जिससे कम मजदूरी लेने के लिए श्रमिक तैयार नहीं होगा।

श्रमिकों की पूर्ति अनेक अनाधिक और आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। इनमें से निम्नलिखित तत्व उल्लेखनीय हैं —

श्रम की पूर्ति जनसंख्या का आकार, वर्तमान रोजगार की स्थिति, वातावरण के प्रति मोह आदि अनार्थिक कारणों से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक स्थानान्तरण (occupational shift) श्रम की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। यदि किसी उद्योग में मजदूरी बढ़ जाती है तो अन्य उद्योगों एवं व्यवसायों से श्रमिक संख्या में श्रमिक इस उद्योग की ओर आकर्षित होते हैं। यदि उद्योग विशेष में मजदूरी घट जाती है तो दूसरे उद्योगों और व्यवसायों में श्रमिक चले जाते हैं।

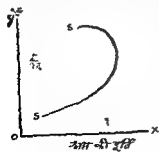
श्रमिकों की कार्यकुशलता (efficiency) भी पूर्ति को प्रभावित करती है। कार्य-

कुशलता में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि करती है। उत्पादन में वृद्धि कार्य कुशलता के द्वारा उसी प्रकार होती है जैसे कि थमिक की सहाय में वृद्धि के द्वारा होती है। साधारणतया ऊँची मजदूरी थमिकों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि कर कार्य कुशलता में वृद्धि करती है तथा नीची मजदूरी कार्यकुशलता में कमी कर देती है। इस प्रकार पूर्ति वक्र सामान्यतः नीचे से ऊपर बायी ओर से दायी ओर को उठता हुआ होता है। संक्षेप में थम की पूर्ति और मजदूरी का सम्बन्ध सीधा होता है।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार कार्य-आराम अनुपात (work-leisure ratio) थम की पूर्ति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। जब मजदूरी में वृद्धि होती है तो उसके दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं—

- (१) प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution effect)—जब मजदूरी में वृद्धि होती है जो थमिक अधिक कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं अर्थात् आराम के स्थान पर कार्य का प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। यह प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है।
- (२) आय प्रभाव (Income effect)—मजदूरी में वृद्धि होने से थमिकों की आय में वृद्धि हो जाती है। आय बढ़ जाने के कारण थमिक आराम करना चाहते हैं, अर्थात् कार्य के स्थान पर आराम का प्रतिस्थापन होता है। आय प्रभाव हमेशा ऋणात्मक (negative) होता है।

इस प्रकार मजदूरी में वृद्धि का प्रभाव धनात्मक होता है। दूसरा ऋणात्मक। थम की पूर्ति किस प्रकार प्रभावित होती है हमको ज्ञात करना अत्यन्त कठिन है सामान्यतः मजदूरी में वृद्धि थमिकों की पूर्ति में वृद्धि कर देती है अर्थात् थमिक पहले की अपेक्षा अधिक घण्टा कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। परन्तु मजदूरी में एक सीमा के बाद वृद्धि,



आय प्रभाव के कारण, थमिक को कम काम और अधिक आराम के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार थमिकों की पूर्ति रेखा धनात्मक प्रभाव के कारण प्रारम्भ में तो बढ़ती है परन्तु एक सीमा के बाद आय प्रभाव के कारण पूर्ति घट जाती है अर्थात् पूर्ति रेखा प्रारम्भ में ऊपर की ओर उठनी हुई होती है किन्तु एक सीमा के बाद वह बायें को पीछे की ओर झुक जाती है जैसा कि चित्र में स्पष्ट किया गया है।

मजदूरी का निर्धारण (Wage Determination)

पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण की व्याख्या करते समय हम यह मानकर चलते हैं कि थम बाजार में श्रम की पूर्ति एवं माग में एकाधिकारी तत्त्व का अभाव पाया जाता है। उत्पादकों की संख्या पर्याप्त होती है और वह श्रम की माग स्वतन्त्रता प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या भी अधिक होती है और सब श्रमिक व्यक्तिगत आधार पर (न कि संगठन के अनुसार) अपनी सेवाएँ उत्पादकों को देते हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है।

उपरोक्त सर्वत्र में, मजदूरी उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहाँ पर कि थम की माग व श्रम की पूर्ति बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक उद्योग में मजदूरी की दर की अधिकतम सीमा माग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के संतुलन से निर्धारित होती है। इस तथ्य को प्रो टामस (Prof Thomas) ने निम्न लिखित शब्दों में व्यक्त किया है—

‘एक उत्पादक अपने श्रमिकों की आर्थिक मजदूरी देना चाहता है, वह मजदूरी प्रचलित स्थितियों में श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है, और जिसे कि उद्योग द्वारा दिया जा सकता है। दूसरी ओर श्रमिक सामाजिक मजदूरी बढाये रखना चाहता है यह मजदूरी सामाजिक कारणों से, विशेष रूप से उस वर्ग के जीवन स्तर से निर्धारित होती है जिस वर्ग का श्रमिक सदस्य है।’^८

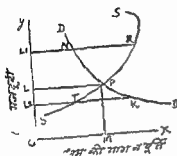
प्रो टामस ने मजदूरी की न्यूनतम सीमा जीवन स्तर स्वीकार की है, तथा उच्चतम सीमा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता। लेकिन प्रो सिल्वरमन (Silverman) ने जीवन निर्वाह का मजदूरी की न्यूनतम सीमा बताया है। उन्हीं के शब्दों में—

- 8 ‘The employer seeks to pay his worker an economic wage, i.e., a wage that is determined by reference to marginal productivity of the worker under existing conditions and a wage that the industry can afford to pay. The worker on the other hand seeks to obtain and maintain a social wage, determined by reference to social consideration, and particularly to the customary standard of living of the group to which he belongs’

—Prof Thomas

“मजदूरी उन दो सीमाओं के बीच में, जिनमें जीवन निर्वाह की सीमा न्यूनतम है और अधिक की उत्पादकता की सीमा उच्चतम है, श्रमिकों और उत्पादकों की जमा-सोदा करने की शक्ति के आधार पर बदलती रहती है।”^९

• इस प्रकार जहाँ पर श्रमिकों की माग अर्थात् सीमान्त उत्पादकता तथा श्रमिकों की पूर्ति अर्थात् सीमान्त त्याग बराबर हो जाते हैं वही पर मजदूरी निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में, साम्य की स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि श्रमिकों की माग व पूर्ति बराबर होती है। इन स्थिति को गरम विन के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है।



उपर्युक्त चित्र में DD श्रमिकों की माग रेखा व SS श्रमिकों की पूर्ति रेखा है। इस स्थिति

में उद्योग में मजदूरी P बिन्दु पर निर्धारित होगी क्योंकि इस बिन्दु पर श्रमिकों की माग व उसकी पूर्ति बराबर हैं अर्थात् P साम्य बिन्दु है। इस प्रकार मजदूरी PM या OL होगी क्योंकि इस मजदूरी की दर पर श्रमिकों की माग तथा पूर्ति OM है। यदि मजदूरी बढ़कर OL' हो जाती है, इस स्थिति में श्रमिकों की पूर्ति L'R है जबकि माग केवल L'N, अर्थात् NR श्रमिक अतिरिक्त हैं। श्रमिकों की पूर्ति अधिक होने के कारण मजदूरी की दर घट जायेगी और घटकर उस बिन्दु पर पहुँच जायेगी जहाँ पर माग व पूर्ति बराबर हैं। इसी प्रकार यदि मजदूरी की दर OL से घटकर OL₂ हो जाती है, उस स्थिति में श्रमिकों की पूर्ति L₂T है तथा माग L₂K, अर्थात् माग की अपेक्षा पूर्ति कम है। श्रमिकों की पूर्ति कम होने के कारण मजदूरी की दर में वृद्धि होगी और मजदूरी बढ़कर OL के बराबर हो जायेगी। सन्तुलन में मजदूरी उसी बिन्दु पर निर्धारित होगी जहाँ पर माग व पूर्ति बराबर हैं।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार पुण प्रतियोगिता की स्थिति में मजदूरी निर्धारण के सम्बन्ध में दो बातें ध्यान में रखनी चाहिये—

(१) साम्य की स्थिति में मजदूरी हमेशा सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है। यदि

9 'Wages may vary between the minimum set by the cost of subsistence and the maximum set by the productivity of the worker, according to the bargaining strength of workers and employers respectively'

—Prof Silverman

मजदूरी सीमान्त उत्पादकता से अधिक है तो उत्पादक श्रमिकों की माग कम करेंगे तथा श्रमिक अपनी पूर्ति में वृद्धि के लिए उत्तर रहेंगे। इसके विपरीत यदि मजदूरी सीमान्त उत्पादकता से कम है तो उत्पादक श्रमिकों की माग अधिक करेंगे जससे श्रमिक अपनी पूर्ति कम करेंगे। इस प्रकार जब तक सीमान्त उत्पादकता के बराबर मजदूरी श्रमिकों को प्राप्त नहीं होगी तब तक साम्य दर स्थापित नहीं हो सकेगी, और श्रमिकों की माग तथा पूर्ति में परिवर्तन होत रहेंगे।

व्यवहार में यह सम्भव है कि मजदूरी सीमान्त उत्पादकता से कम हो या अधिक परन्तु मजदूरी की प्रवृत्ति हमेशा सीमान्त उत्पादकता के बराबर होने की रहती है।

- (२) हम यह मान्यता लेकर चले हैं कि सभी श्रमिकों की कार्यक्षमता समान होती है इसलिए बाजार में मजदूरी की दर समान होती है। परन्तु व्यवहार में श्रमिकों की कुशलता में अन्तर होता है और मजदूरी की दर भी समान नहीं होती। ऐसी स्थिति में कुशलता की दृष्टि से समान श्रमिकों के विभिन्न वर्ग बन जाते हैं, और प्रत्येक वर्ग के लिए मजदूरी की दर समान रहती है। इस स्थिति में भी मजदूरी की दर प्रत्येक वर्ग की माग और पूर्ति से निर्धारित होगी तथा साम्य बिन्दु पर मजदूरी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है।

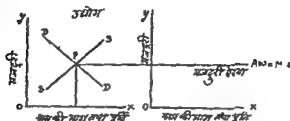
एक व्यक्तिगत फर्म की दृष्टि से मजदूरी का निर्धारण

उद्योग में कुल माग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित मजदूरी को व्यक्तिगत फर्म द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। जिस प्रकार पूँज प्रतियोगिता की स्थिति में उद्योग द्वारा निर्धारित वस्तु के मूल्य को एक फर्म ग्रहण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार उद्योग में निर्धारित मजदूरी को एक फर्म स्वीकार कर लेती है। इसी कारण श्रम की पूर्ति रेखा (मजदूरी रेखा) OX अक्षांश के समांतर होती है अर्थात् पूर्ति रेखा एक पट्टी हुई रेखा होती है।

एक फर्म के लिए श्रमिकों की पूर्ति रेखा पूर्णतया लोचसार होती है, इनका अर्थ यह है कि एक ही हुई मजदूरी पर एक फर्म चाहे जितनी मात्रा में श्रमिक प्राप्त कर सकती है।

उपर्युक्त विवरण से एक बात स्पष्ट होती है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी की दर समान रहती है इसलिए यदि एक फर्म का उत्पादक अपनी फर्म में श्रम को एक इकाई मनु-दरवा चाहता है तो उसे मजदूरी (सीमान्त मजदूरी या marginal wage)

औसत मजदूरी (average wage) के बराबर देनी होगी। दूसरे शब्दों में, इस स्थिति में सीमान्त मजदूरी (M W) और औसत मजदूरी (A W) बराबर होती हैं। इसे रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है।



एक व्यक्तिगत फर्म के उत्पादक का उद्देश्य लाभ को अधिकतम प्राप्त करना होता है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह उद्योग द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर पर श्रमिकों की उत्तमी मात्रा प्रयुक्त करेगा जहां पर श्रमिकों की सीमान्त आयम उत्पादकता (Marginal Revenue Product : e , MRP) श्रमिकों की सीमान्त मजदूरी (Marginal Wage) के बराबर हो। इस प्रकार फर्म साम्य की अवस्था में उस समय होगी जबकि MRP बराबर हो MW के।

यदि सीमान्त आयम उत्पादकता सीमान्त मजदूरी से अधिक ($MRP > MW$) है तो इसका अभिप्राय है कि श्रम की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल आय में होने वाली वृद्धि सीमान्त मजदूरी की अपेक्षा अधिक होगी। अतः इस स्थिति में फर्म को लाभ होगा। फर्म अतिरिक्त इकाइयों को उस सीमा तक प्रयुक्त करेगी जहां पर कि $MRP = MW$ है।

यदि सीमान्त आयम उत्पादकता सीमान्त मजदूरी से कम ($MRP < MW$) है तो इसका अर्थ है कि श्रम की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल आय में होने वाली वृद्धि सीमान्त मजदूरी की अपेक्षा कम होगी, इस प्रकार अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से फर्म का हानि होगी। इस प्रकार फर्म उस सीमा तक श्रमिकों की सख्या काम पर लगावगी जहां पर $MRP = MW$ है। यही साम्य की स्थिति है।

अस्पष्टता में एक फर्म को श्रमिकों के प्रयोग की दृष्टि से सामान्य लाभ, लाभ या हानि तीनों ही स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। हानि या लाभ की स्थिति का अध्ययन करने के लिए औसत रेखाओं पर ध्यान देना पड़ता है अर्थात् औसत आयम उत्पादकता (Average Revenue Product : e , ARP) और औसत मजदूरी (Average Wage,

1 =, AW) को स्थिति को देखना होता है। अल्पकाल में साम्य उसी बिन्दु पर स्थापित होता है जहाँ कि $MRP = MW$ है।

- (a) यदि श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी (औसत मजदूरी) औसत आगम उत्पादकता (ARP) से अधिक है तो फर्म को हानि होगी।
- (b) यदि औसत मजदूरी औसत आगम उत्पादकता से कम है तो फर्म को लाभ प्राप्त होगा।
- (c) यदि औसत मजदूरी और औसत आगम उत्पादकता बराबर है तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा।

इस प्रकार, अल्पकाल में फर्म को तीनों स्थितियाँ प्राप्त हो सकती हैं। दीर्घकाल में उद्योग तथा फर्म दोनों ही साम्य की अवस्था में होने हैं तथा फर्म को न तो लाभ प्राप्त होता है और न ही हानि, अर्थात् सामान्य लाभ प्राप्त होता है।

यदि किसी फर्म में औसत मजदूरी औसत आगम उत्पादकता से अधिक है तो फर्म के द्वारा उत्पादन स्थगित कर दिया जायेगा, फलस्वरूप श्रमिकों की माग में कमी होगी, और मजदूरी में भी कमी होगी। दूसरी ओर, फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु का उत्पादन कम होगा, जिससे वस्तु का मूल्य बढ़ेगा और श्रम की औसत आगम उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार अन्त में $ARP = AW$ हो जायेगी।

यदि किसी फर्म में औसत मजदूरी औसत आगम उत्पादकता से कम है तो फर्म को लाभ प्राप्त होगा। लाभ से आकर्षित होकर नयी फर्म उद्योग में आकर्षित होगी। इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की माग में वृद्धि होगी, जो कि मजदूरी में वृद्धि करेगी। दूसरी ओर वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने से वस्तु के मूल्य में कमी होगी, अतः श्रम की औसत आगम उत्पादकता भी घट जायेगी। इसके परिणामस्वरूप दीर्घकाल में लाभ समाप्त हो जायेगा और साम्य की दशा स्थापित होगी, जहाँ पर कि फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा।

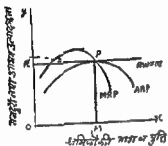
दीर्घकाल में साम्य की स्थिति में औसत मजदूरी और सीमान्त मजदूरी दोनों बराबर होती हैं इसके साथ ही औसत आगम उत्पादकता सीमान्त आगम उत्पादकता के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में दीर्घकाल में एक फर्म दो चतुर्तों को एक साथ धूँस करती है।

- (a) $ARP = AW$,

$$(b) \quad MRP = MW,$$

$$\text{साम्य बिन्दु पर मजदूरी} = AW = MW = ARP = MRP$$

इस स्थिति को चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है



सबसे कम बिन्दु P बिन्दु साम्य बिन्दु है क्योंकि इस बिन्दु पर $MW = MRP$ है, अर्थात् श्रमिकों की OM मात्रा प्रयुक्त की जायेगी, तथा मजदूरी PM होगी। इस स्थिति में फर्म साम्य की इच्छा का पूरा करती है, अर्थात् P बिन्दु पर $MW = MRP$ है तथा $AW = ARP$ है। अतः मजदूरी की दर PM पर फर्म की सबसे सामान्य लाभ प्राप्त होगा।

अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण (Wage Determination Under Imperfect Competition)

वास्तविक जीवन में श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता प्राप्त नहीं पाई जाती बल्कि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि व्यवहार में उत्पादकों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। यदि संख्या अधिक भी है तो वे अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य से आपस में मिलकर संगठन का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार मजदूरी को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रभावित कर लेते हैं। दूसरी ओर श्रम बाजार में श्रमिक भी असाठित नहीं होते। श्रमिक अपने हितों के लिए श्रम संघ बना लेते हैं और श्रम की पूर्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। अतः श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है और मजदूरी की दर दोनों (मालिकों और श्रमिकों) की सोझ करने की शक्ति पर निर्भर करती है।

यदि श्रमिकों की सोझ करने की शक्ति अधिक है तो मजदूरी सीमान्त उत्पादकों के पास होगी। यदि उत्पादकों की सोझ करने की शक्ति अधिक है तो मजदूरी जीवन स्तर के पास निर्धारित होगी।

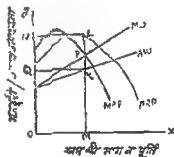
श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, इसलिए जीवन मजदूरी ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता के समान पड़ी हुई रेखा न होकर नीचे में ऊपर की ओर से दायाँ ओर, ऊपर की ओर उठती हुई होती है तथा सीमान्त मजदूरी रेखा भी नीचे में ऊपर की ओर उठती हुई होती है। सामान्यतः सीमान्त मजदूरी रेखा जीवन मजदूरी रेखा के ऊपर रहती है।

उपर का उल्टो हुई मजदूरी रेखा यह स्पष्ट करती है कि यदि उत्पादक अधिक सरया म श्रमिकों को प्रयुक्त करना चाहता है तो उसे मजदूरी अधिक देनी होगी।

अपूर्ण प्रतियोगिता में श्रमिकों की मांग रेखा (सीमान्त आगम उत्पादकता) पूर्ण प्रतियोगिता के समान हो रहती है।

पूर्ण प्रतियोगिता के समान ही अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य बिन्दु वह बिन्दु होता है जहाँ पर कि सीमान्त मजदूरी (MW) और सीमान्त आगम उत्पादकता (MRP) बराबर है। दूसरे शब्दों में तब तक श्रमिकों की उतनी ही मात्रा प्रयुक्त करेगा जहाँ पर कि सीमान्त मजदूरी और सीमान्त आगम उत्पादकता बराबर ह। इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकेगा।

समान चित्र में MRP सीमान्त आगम उत्पादकता रेखा है तथा ARP ओसत आगम उत्पादकता रेखा। AW व MW क्रमशः औसत मजदूरी व सीमान्त मजदूरी रेखाएँ हैं। फलस्वरूप साम्य उम बिन्दु पर स्थापित होगा जहाँ पर $MW = MRP$ है, अतः साम्य बिन्दु P है। उत्पादन श्रमिकों की OM मात्रा प्रयुक्त करेगा जबकि श्रमिकों की दो जाने वाली मजदूरी KM या OQ है। इस स्थिति में फल को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस स्थिति में मजदूरी KM सीमान्त आगम उत्पादकता PM से कम है तथा औसत आगम उत्पादकता LM भी कम है इस प्रकार प्रति इकाई लाभ LK ($LM - KM = LK$) प्राप्त होता है।



उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि औसत मजदूरी LM सीमान्त आगम उत्पादकता PM से कम है। इसका अभिप्राय यह है कि जितना श्रमिकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उससे कम मजदूरी दी जा रही है, अतः श्रमिकों का शोषण हो रहा है। श्रमिकों और रॉबिन्सन के अनुसार जब औसत मजदूरी सीमान्त आगम उत्पादकता से कम होती है तब श्रमिकों का शोषण होता है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

२. निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों का मूल भाग एवं पूर्ण को अनिवार्य द्वारा निर्धारित होता है उसी आधार पर।

प्रकार श्रम का मूल्य (मजदूरी) भी माग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है'; व्याख्या कीजिए ।

३. मजदूरी से क्या अभिप्राय है ? मजदूरी के सीमान्त उत्पादनता सिद्धांत (Marginal productivity theory) की संविस्तार व्याख्या कीजिए ।
 ४. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण को समझाइये ।
 ५. मजदूरी निर्धारण के सबसे मान्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए ।
 ६. "पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी श्रम की सीमान्त एवं औसत आगम उत्पादनता के बराबर होती है ।" विवेचना कीजिए ।
 ७. अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण को समझाइये ।
-

कीन्स (Keynes) के अनुसार—“व्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है।”^४

विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य है, परन्तु सभी परिभाषाएँ एक तथ्य को स्वीकार करती हैं कि व्याज द्रव्य या पूँजी से सम्बन्धित है। इस प्रकार, अर्थशास्त्र में व्याज से अर्थ ‘पूँजी के उपयोग के बदले दिये जाने वाले प्रतिकूल से है’। अर्थशास्त्र की दृष्टि से व्याज को दो रूपों में प्रयुक्त किया जाता है— शुद्ध व्याज और कुल व्याज।

शुद्ध व्याज और कुल व्याज

(Net Interest and Gross Interest)

शुद्ध व्याज और कुल व्याज में अन्तर है। साधारणतया राष्ट्रीय लाभ का वह भाग जो कि पूँजीपति को केवल पूँजी के उपयोग के बदले दिया जाता है, शुद्ध व्याज कहलाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त शब्द व्याज से अभिप्राय कुल व्याज से होता है। कुल व्याज वह है जो ऋणी द्वारा पूँजीपति को पूँजी के उपयोग के बदले दिया जाता है। इसमें शुद्ध व्याज के अतिरिक्त जोखिम का प्रतिकूल तथा असुविधाओं का प्रतिकूल आदि सम्मिलित रहता है। इस प्रकार शुद्ध व्याज एक प्रकार से कुल व्याज का अंग है।

प्रो चैपमैन (Prof Chapman) ने शुद्ध व्याज की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है—“शुद्ध व्याज उधार ली गई पूँजी का भुगतान है, जबकि ऋणदाता को किसी प्रकार का जोखिम या असुविधा नहीं होती। पूँजी के उपयोग के बदले किये गये इस भुगतान को शुद्ध व्याज, विशुद्ध व्याज या आर्थिक व्याज कहते हैं।”^५

प्रो मार्शल ने शुद्ध व्याज और कुल व्याज का अंतर बताते हुए लिखा है—“जब हम व्याज को केवल पूँजी का प्रतिफल बताते हैं तो हमारा अभिप्राय शुद्ध व्याज से होता है, किन्तु सामान्य रूप से इसके अतिरिक्त अन्य तत्व भी सम्मिलित रहते हैं और इसे कुल व्याज कहते हैं।”^६

4 “Interest is the reward of parting with liquidity for a specified period”
—Keynes

5 “Net interest is a payment of loan of capital, when no risk nor inconvenience and no work is entailed on the lender. This payment is termed as pure interest, net interest or economic interest.”
—Prof Chapman

6 “The interest of which we speak when we say the interest is the earning of capital simply, or the reward of waiting simply, is

कुल व्याज में शुद्ध व्याज के बतिरिक्त अनेक भुगतान सम्मिलित रहने हैं । प्रो टामस (Prof Thomas) ने कुल व्याज में शुद्ध व्याज के बतिरिक्त निम्नलिखित तीन बातें सम्मिलित की हैं

- (१) जोखिम का भुगतान (Payment for risk) ,
- (२) असुविधाओं का प्रतिफल (Remuneration for inconvenience)
- (३) व्यवस्था का प्रतिफल (Remuneration for management) ।

१ जोखिम का भुगतान

ऋणदाता को ऋण देते समय अनेक जोखिम उठाने पड़ते हैं अतः उसे इन जोखिमों का भुगतान प्राप्त होता है । प्रो भाशस ने जोखिम को दो भागों में बाटा है

- (१) व्यक्तिगत जोखिम (Personal risk)—यह जोखिम ऋण लेने वाले व्यक्ति के आचरण से सम्बन्धित है । यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति वैईमान हो जाय, उधार ली गई पूँजी को वापिस न करे, तो पूँजीपति को जोखिम उठाना पड़ता है ।
- (२) व्यावसायिक जोखिम (Trade risk)—जब ऋणदाता द्वारा व्यक्ति को व्यावसायिक कामों के लिए पूँजी उधार दी जाती है तो उसमें यह जोखिम रहता है कि जिस व्यवसाय के लिये पूँजी दी गई है, यदि वह व्यवसाय फेन हो जाता है तो पूँजी वापिस आने की सम्भावना कम रहती है । इस प्रकार ऋणदाता व्याज में इन जोखिमों का प्रतिफल या भुगतान सम्मिलित कर लेता है ।

२ असुविधाओं का प्रतिफल

ऋणदाता को ऋण देते समय अनेक असुविधायें उठानी पड़ती हैं । यह सम्भव है कि ऋणी द्वारा ऋणदाता को ठीक समय पर भुगतान न किया जाय या वह उस समय भुगतान करे जबकि ऋणदाता को पूँजी की कोई आवश्यकता ही न हो । इसके अतिरिक्त ऋणदाता अपनी आवश्यकता के समय तत्काल ऋणी से पूँजी वापिस प्राप्त नहीं कर सकता । इस प्रकार ऋणदाता को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है अतः वह व्याज में इन असुविधाओं का प्रतिफल सम्मिलित कर लेता है ।

net interest, but what commonly passes by the name of interest includes other elements besides this, and may be called gross interest ' —Marshall

३ ध्यदाता का प्रतिफल -

ऋणदाता जब ऋण प्रदान करता है तो उस उसका हिसाब किताब रखना होता है, तथा ऋण वसूल करने का प्रयत्न करना होता है। यदि ऋण वसूल नहीं हो पाये तो उसे न्यायालय आदि की शरण लेना पड़ती है अतः इस व्यवस्था पर उसका व्यय होता है। ऋणदाता ध्याज में इस व्यवस्था पर किये जाने वाले खर्च को भी सम्मिलित करता है।

इस प्रकार कुल ध्याज में शुद्ध ध्याज के अनिरिक्त जोखिम का भुगतान, असुविधाओं का प्रतिफल और व्यवस्था का प्रतिफल सम्मिलित रहता है। संक्षेप में

कुल ध्याज = शुद्ध ध्याज + जोखिम का भुगतान + असुविधाओं का प्रतिफल + व्यवस्था का प्रतिफल

शुद्ध ध्याज = कुल ध्याज - (जोखिम का भुगतान + असुविधाओं का प्रतिफल + व्यवस्था का प्रतिफल)

= केवल पूँजी के प्रयोग का प्रतिफल।

ध्याज का स्वभाव

प्रो मेहुता ने पूँजी की प्रकृति की विशेषताओं को बताते हुए लिखा है -

- (१) ध्याज पूँजी के उपयोग की कीमत है,
- (२) ध्याज स्वाग अथवा प्रतीक्षा का प्रतिफल है, तथा
- (३) ध्याज समय पसन्दगी (time-preference) को व्यक्त करता है।

इस प्रकार ध्याज एक कीमत है जो कि पूँजी के उपयोग के बदले प्राप्त होती है, साथ ही-साथ ध्याज एक आय भी है, क्योंकि ध्यक्ति के द्वारा पूँजी का विनयोग आय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही किया जाता है, और यह आय ही ध्याज है।

ध्याज निर्धारण के सिद्धान्त (Theories of Interest)

अर्थशास्त्र में ध्याज का सिद्धान्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारम्भ से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में ध्याज के सम्बन्ध में विद्वानों और अर्थशास्त्रियों द्वारा कुछ न कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं, परन्तु इन विचारों में समय परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तन आते-पड़ते हैं।

जैसा कि हेबरलर ने कहा है—“ध्याज का सिद्धान्त अर्थशास्त्र में एक लम्बे समय से कमजोरी रही है और आज भी ध्याज की व्याख्या और ध्याज की दर के निर्धारण

के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में इतना अधिक मतभेद है जितना अर्थशास्त्र के अन्य किसी भी सिद्धांत के विषय में नहीं है।⁷

• ब्याज निर्धारण के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद रहा है इसलिए ब्याज निर्धारण के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये। इन सिद्धांतों का यदि हम वर्गीकरण करना चाहें तो इनको दो भागों में बांट सकते हैं (अ) वास्तविक सिद्धांत (Real theories), (ब) मौद्रिक सिद्धांत (Monetary theories)। वास्तविक सिद्धांत ब्याज के पुराने सिद्धांत हैं और ये सिद्धांत वास्तविक तत्वों पर अधिक जोर देते हैं। मौद्रिक सिद्धांत अपेक्षाकृत नवीन सिद्धांत हैं, तथा ये मौद्रिक तत्वों पर जोर देते हैं। परन्तु सिद्धांतों का यह वर्गीकरण ऐसा नहीं है कि एक वर्ष का दूसरे वर्ष से कोई सम्बन्ध न हो। अतः इस कठिनाई से बचने के लिए इस सिद्धांतों का वर्गीकरण न करके सभी प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे।

ब्याज निर्धारण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

- (१) ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त (Marginal productivity theory of interest),
- (२) ब्याज का त्याग या प्रतीक्षा का सिद्धान्त (Abstinence or waiting theory of interest),
- (३) ब्याज का एग्रियो या आस्ट्रियन सिद्धान्त (The Agio or the Austrian theory of interest),
- (४) फिशर का समय पसन्दगी सिद्धान्त (Fisher's theory of time preference),
- (५) ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Classical theory of interest),
- (६) ब्याज का तरलता पसन्दगी सिद्धान्त (Liquidity preference theory of interest),
- (७) ब्याज का उधार देय कोष सिद्धान्त या नव-प्रतिष्ठित सिद्धान्त (The loanable fund theory of interest or neo-classical theory),
- (८) ब्याज का आधुनिक सिद्धान्त (Modern theory of interest)।

7 "The theory of interest has for long been a weak spot in the science of economics, and the explanation and determination of the interest rate still gives rise to more disagreement among economists than any other branch of general economic theory"

—Haberler

१ व्याज की सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory of Interest)

यह सिद्धांत व्याज निर्धारण का सबसे पुराना सिद्धान्त है। इसका समर्थन सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री टर्गो (Turgot) ने किया। बाद में इस सिद्धांत का समर्थन माल्टस, जे. बी. से, कैर (Carey) तथा वॉन थुनेन (Von-Thunen) आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। इन समर्थक अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि जिस प्रकार भूमि या धन में उत्पादकता पाई जाती है, उसी प्रकार पूँजी में भी उत्पादकता पाई जाती है, अर्थात् पूँजी भी उत्पादन कार्य में सहायक होती है।

इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज की दर का निर्धारण पूँजी की उत्पादकता के आधार पर होता है, अर्थात् व्याज की दर पूँजी की सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है। व्याज न तो सीमान्त उत्पादकता से कम होगा और न ही अधिक। यदि व्याज की दर सीमान्त उत्पादकता से कम है तो अनेक नये व्यक्ति उत्पादन क्षेत्र में आ जायेंगे और पूँजी की माग करना प्रारम्भ कर देंगे, इसके फलस्वरूप व्याज की दर में वृद्धि होगी और वह सीमान्त उत्पादकता के बराबर हो जायेगी। यदि व्याज की दर सीमान्त उत्पादकता से अधिक है तो उत्पादकों को कठिनाई होगी, और अनेक उत्पादक पूँजी की माग कम करेंगे, जिससे फलस्वरूप व्याज की दर घटकर सीमान्त उत्पादकता के बराबर हो जायेगी। इस प्रकार दीर्घकाल में व्याज की दर ठीक सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है, न इससे कम और न ही इससे अधिक।

सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की एक विशेषता है कि इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। व्याज की दर उसी स्थिति में ऋणात्मक होगी जबकि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता ही ऋणात्मक (negative) हो। सामान्य स्थितियों में चूँकि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता सदैव धनात्मक होती है अतः व्याज भी धनात्मक होता है।

आलोचना (Criticism) .

इस सिद्धान्त की अनेक आलोचनाएँ की गई हैं, जिनमें से प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) यह सिद्धान्त एकपक्षीय है। यह सिद्धान्त व्याज की दर का निर्धारण केवल माग पक्ष से ही करता है, पूर्ति पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा करता है। आलोचकों के अनुसार व्याज की दर का निर्धारण पूँजी की माग व पूर्ति दोनों की शक्तियों द्वारा होता है।

- (२) यह सिद्धान्त माग वष की व्याख्या भी पूरी नहीं करता । यह सिद्धान्त बताता है कि पूजा में उत्पादकता है, इसलिए व्याज दिया जाता है । लेकिन पूजा की माग अनुत्पादक एवं उपभोग के कार्यों के लिये भी की जाती है, और उस पर उत्पादक कार्यों की माग के समान ही व्याज दिया जाता है । यह सिद्धान्त अनुत्पादक कार्यों के लिये ली गई पूजा के व्याज निर्धारण की व्याख्या नहीं करता ।
- (३) आसोचको के अनुसार केवल उत्पादकता ही व्याज का कारण नहीं है, बल्कि पूजा की पूति, मोद्रिक परिस्थितिया, ऋणी व ऋणदाता का सम्बन्ध आदि बातें भी व्याज की दर के निर्धारण को प्रभावित करती हैं । व्यवहार में हम देखते हैं कि विभिन्न व्यवसायों में पूजा की उत्पादकता भिन्न भिन्न होने पर भी व्याज की दर लगभग समान रहती है ।^१ जबकि इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज की दर उत्पादकता पर निर्भर करती है और उत्पादकता में परिवर्तन होने से व्याज की दर में भी परिवर्तन हो जाते हैं । व्यवहार में इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती ।
- (४) पूजा की सीमान्त उत्पादकता का पता लगाना कठिन है, यदि पूजा व प्रयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है, तो यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है कि उत्पादन की यह वृद्धि पूजा के फलस्वरूप है या श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि के कारण है या संगठन में परिवर्तन के कारण ।

२ व्याज का त्याग या प्रतीक्षा का सिद्धान्त (Abstinence or Waiting Theory of Interest)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री सीनियर (Senior) ने किया, बाद में कैरनोज (Cairnes) तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसका समर्थन किया । सीनियर के अनुसार जब व्यक्ति वसत करते हैं तो उन्हें त्याग करना होता है, क्योंकि वचन उसी स्थिति में सम्भव है जबकि व्यक्ति द्वारा वर्तमान उपयोग में नमी की जाय, अर्थात् वर्तमान उपयोग का त्याग किया जाय । इस त्याग के कारण ही व्याज प्राप्त होता है । सीनियर ने लिखा है—

“त्याग धन का निर्माण नहीं करता, अपितु धन के निर्माण करने का अधिकार देता है, क्योंकि इसमें भी श्रम के समान त्याग तथा कष्ट होता है ।”^८

सीनियर द्वारा प्रतिपादित इस विचार की बहुत आलोचना की गई । वास्तेयन (Voltaire) तथा कार्ल मार्क्स (Karl Marx) जैसे विद्वान विचारकों ने बताया कि अमीर

8 “Abstinence does not create wealth, but it constitute a title to wealth, because it involves sacrifice and pain just as labour does”
—Senior

व्यक्तियों के पास इतना अधिक धन होता है कि उन्हें बचत करने में किसी प्रकार का कष्ट या त्याग नहीं करना पड़ता, अतः मार्क्स का विचार है कि व्याज में त्याग का अंश सम्मिलित नहीं होता।

मार्शल (Marshall) ने इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से त्याग के स्थान पर 'प्रतीक्षा' (waiting) शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि बचत करने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि बचत करने के लिये व्यक्ति को अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति को अर्थात् 'वर्तमान उपयोग' को भविष्य के लिये स्थगित करना पड़ता है। इस प्रकार वह वर्तमान में भविष्य के उपयोग के लिये प्रतीक्षा करता है। सामान्यतः अधिकांश व्यक्ति प्रतीक्षा करना नहीं चाहते हैं, अतः उन्हें बचत करने के लिये प्रोत्साहित करने को कुछ-कुछ प्रलोभन आवश्यक है। मार्शल के अनुसार व्याज ही यह प्रलोभन है अर्थात् प्रतीक्षा का पुरस्कार है।

आलोचना (Criticism) :

सीनियर एवं मार्शल दोनों ही के दृष्टिकोणों की अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा कटु आलोचना की गई है।

- (१) यह सिद्धान्त केवल पूर्ति पक्ष से ही व्याज निर्धारण की बात करता है, मांग पक्ष की उपेक्षा करता है। अतः यह सिद्धान्त एकपक्षीय (one-sided) है।
- (२) इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज का कारण 'त्याग' है लेकिन आलोचकों के अनुसार केवल 'त्याग' ही व्याज का कारण नहीं होता। यदि बचत करने वाला व्यक्ति उस बचत को गतिहीन रखता है तो उसे व्याज प्राप्त नहीं होगा। अतः बचत के साथ-साथ उसे गतिशीलता भी प्रदान करनी होगी।
- (३) यह सिद्धान्त स्वीकार करता है कि 'बचत में त्याग करना होता है। मार्क्स एवं अनेक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह सदैव सत्य नहीं है। क्योंकि अमीरों को बचत करने में कोई त्याग नहीं करना पड़ता, फिर भी उनकी व्याज प्राप्त होता है।

३. व्याज का एजियो या ऑस्ट्रियन सिद्धान्त (The Aigio or the Austrian Theory of Interest) :

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन १८३४ में जोन रे (John Rae) द्वारा किया गया। ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री ब्रॉवर बोरवार्क (Brower Bowmark) ने इसमें सुधार कर गतिष्क सिद्धान्त प्रदान किया। इस सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (psychological theory) भी कहते हैं।

मनुष्य स्वभावतः भविष्य की अपेक्षा वर्तमान की अधिक पसन्द करता है क्योंकि उसे वर्तमान में आवश्यकता को पूरा करने से प्रत्यक्ष लाभ या वर्तमान में ही सतुष्टि प्राप्त होती है। अतः वर्तमान की वस्तुमें भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखती है। क्योंकि वर्तमान आवश्यकताओं की सतुष्टि से मिलने वाला सुख भविष्य में प्राप्त सतुष्टि की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसी स्थिति में, यदि कोई व्यक्ति पूँजी दूसरे व्यक्ति को उधार देता है तो उसे वर्तमान सतुष्टि से प्राप्त होने वाले सुख की त्यागना पड़ता है। अतः व्यक्ति उधार सभी दौं (अर्थात् वर्तमान सतुष्टि का त्याग सभी करेगा) जबकि उनको इस त्याग का पुरस्कार प्राप्त हो। अतः डॉम-बॉवर्क के अनुसार व्याज वर्तमान सतुष्टि के त्याग का पुरस्कार है।

डॉम-बॉवर्क के इस दृष्टिकोण की कि वर्तमान में प्राप्त होने वाली सतुष्टि की अपेक्षा भविष्य में प्राप्त होने वाली सतुष्टि कम होती है, कुछ विद्वानों ने आलोचना की। अपने इस विचार की पुष्टि के लिये डॉम बॉवर्क ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये —

- (१) मनुष्य की वर्तमान की आवश्यकताएँ भविष्य की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती हैं।
- (२) भविष्य दूर और अनिश्चित होता है, इस अनिश्चितता के कारण ही व्यक्ति भविष्य की अपेक्षा वर्तमान को अधिक महत्त्व प्रदान करता है।
- (३) वर्तमान वस्तुओं में भविष्य की वस्तुओं की अपेक्षा 'तकनीकी श्रेष्ठता' (technical superiority) प्राप्त होती है। क्योंकि भविष्य में वस्तुओं का संप्रदाय अधिक मात्रा में हो जाने के कारण उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता (उपयोगिता ह्रास नियम के कारण) भी घट जाती है।

इस प्रकार डॉम-बॉवर्क के अनुसार वर्तमान की वस्तुमें भविष्य की अपेक्षा अधिक भ्रष्ट होती है। और उनमें उपयोगिता भी अधिक होती है।

आलोचना (Criticism)

इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) यह सिद्धान्त एकापक्षीय है क्योंकि यह सिद्धान्त व्याज की व्याख्या पूर्ण पक्ष से ही करता है, अर्थात् यह सिद्धान्त केवल पूँजी की पूर्ति पर ही ध्यान देता है, मांग पक्ष की अवहेलना करता है।
- (२) आलोचकों के अनुसार डॉम-बॉवर्क की यह मान्यता गलत है कि वर्तमान की वस्तुओं में भविष्य की वस्तुओं की अपेक्षा तकनीकी श्रेष्ठता पाई जाती है।

- (३) बीन्स के अनुसार वचत करने में कोई त्याग नहीं करना होना, वरन् वचत व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। अतः इस दृष्टि से वचत के लिये किसी प्रकार के पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है।

४ फिशर का समय-पसन्दगी सिद्धान्त (Fisher's Theory of Time Preference)

प्रो फिशर (Fisher) ने डॉन बॉवर्क के एजियो मिद्धात की मान्यताओं पर ही अपना समय पसन्दगी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। लेकिन फिशर और डॉन-बॉवर्क के सिद्धांत में अन्तर है। डॉन बॉवर्क ने भविष्य की वस्तुओं की अपेक्षा वर्तमान वस्तुओं की तकनीकी श्रेष्ठता को अधिक महत्व दिया है जबकि फिशर इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। फिशर के अनुसार समय पसन्दगी के कारण ही व्याज प्राप्त होता है। व्यक्ति स्वभावतः वर्तमान में प्राप्त होने वाली सतुष्टि या सुख की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इसी कारण व्यक्ति वर्तमान की सतुष्टि को प्राथमिकता प्रदान करते हैं और भविष्य की आवश्यकताओं की सतुष्टि के प्रति अधिक उत्तरता नहीं दिखाते। यदि व्यक्ति बचन करके वर्तमान के सतोप या सुख का त्याग करते हैं तो उन्हें कुछ पुरस्कार प्राप्त होना चाहिये। इस प्रकार व्याज समय पसन्दगी की क्षति पूर्ति है। वर्तमान में सतुष्टि की मात्रा भविष्य की अपेक्षा जितनी अधिक होगी, व्याज की दर उतनी ही अधिक होगी। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक त्याग होगा उतनी ही व्याज की दर भी अधिक होगी। फिशर के शब्दों में—

“व्याज वह भुगतान है जो व्यक्ति को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान समय-पसन्दगी के त्याग के बदले दिया जाता है। यह समय की कीमत है, इसका कारण नया इनकी मांग सतुष्टि का त्याग है।”^९

फिशर के अनुसार व्यक्ति अपनी आय को वर्तमान में ही व्यय करना चाहत है, इसके कई कारण हैं —

- (१) आय की मात्रा—आय की मात्रा और व्यय करने की आतुरता या उत्तरता का गहरा सम्बन्ध है। जितनी आय कम होती है उतना ही व्यक्ति वर्तमान में सतुष्टि को भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। आय कम होने के कारण व्यक्ति का आत्मनियंत्रण कम रहता है और वह वर्तमान आवश्यकताओं की सतुष्टि को अधिक महत्व देता है। आय अधिक होने पर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को

9 “Interest is the payment which man requires in order to equate future with present values. It is the price of time, its cause and its measure is impatience to enjoy” —Fisher

वर्तमान म आसानी से सतुष्ट कर सजना है, इसलिये वर्तमान मे व्यय की आतुरता कम हो जाती है ।

(२) समयानुसार धाय का वितरण—वर्तमान मे व्यय करने की आतुरता समयानुसार धाय क वितरण पर भी निभर करती है । यदि व्यक्ति की आय जीवनपमन्त समान रहेगी तो उसकी व्यय की तत्परता धाय की मात्रा, व्यक्ति के स्वभाव तथा उसके चरित्र से निर्धारित होनी है । यदि व्यक्ति की आय भविष्य मे बढ़नी चली जायगी तो व्यक्ति की वर्तमान म व्यय करने की आतुरता अधिक रहती है । तथा यदि व्यक्ति की आय भविष्य मे कम होत जाने की सम्भावना रहती है तो उसकी वर्तमान व्यय म व्यय करने की तत्परता कम होती है ।

(३) भविष्य मे धाय की निश्चितता—फिशर के अनुसार भविष्य म आय की निश्चितता भी समय-पसन्दगी को प्रभावित करती है । यदि व्यक्ति की भविष्य मे आय के सम्बन्ध मे अनिश्चितता है तो वह वर्तमान म कुछ न कुछ बचाकर रखेगा, अर्थात् वर्तमान म व्यय करने की आतुरता कम होगी । यदि भविष्य की आय म निश्चितता है तो समय पसन्दगी अधिक होनी है ।

(४) व्यक्ति का स्वभाव व चरित्र—व्यक्ति का स्वभाव व चरित्र भी व्यय करने की आतुरता को प्रभावित करता है । एक दूरदर्शी व्यक्ति की समय-पसन्दगी कम होगी जबकि अदूरदर्शी एक अपव्ययी व्यक्ति की समय-पसन्दगी अधिक होगी ।

अतः फिशर के अनुसार समय-पसन्दगी पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है ।

मालोखना (Criticism)

फिशर द्वारा प्रतिपादित समय पसन्दगी सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं—

(१) यह सिद्धान्त केवल पूर्ति पक्ष पर ही विचार करता है, माग व.ज की उपेक्षा करता है । अतः एकपक्षीय है ।

(२) यह सिद्धान्त केवल यह स्वीकार करता है कि पूजो की पूर्ति व्यय करने की आतुरता और समय-पसन्दगी से ही प्रभावित होती है । जबकि व्यवहार म पूजो की पूर्ति पर अनेक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है ।

(३) यह सिद्धान्त दो मान्यताओं पर आधारित है प्रथम, फिशर द्रव्य की त्रय शक्ति को स्थिर मानकर चलत है, द्वितीय, बचत करने वाले व्यक्तियों की दक्षियों, स्वभाव व परिस्थितियों मे कोई परिवर्तन नहीं होता । ये दोनों मान्यतायें अवास्तविक हैं,

क्योंकि वास्तविक जगत में द्रव्य की क्रय शक्ति में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति की रुचि, स्वभाव तथा उससे सम्बन्धित परिस्थितियाँ भी लगातार बदलती रहती हैं। अतः गलत मान्यताओं पर आधारित होने के कारण यह सिद्धान्त वास्तविक नहीं हो सकता।

५. ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Classical Theory of Interest)

ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धान्त को 'ब्याज की मांग और पूर्ति' का सिद्धान्त भी कहते हैं। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किया, वाद में मार्शल (Marshall) पीगू (Pigou), वालरस (Walras), टॉसिग (Tausig) तथा नाइट (Knight) आदि अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त को सशोधित किया।

इस सिद्धान्त के अनुसार ब्याज की दर पूँजी की मांग और पूँजी की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। ब्याज की दर उस बिन्दु पर निर्धारित होगी, जहाँ पर कि पूँजी की मांग पूँजी की पूर्ति के बराबर होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार पूँजी की मांग विनियोग (investments) से सम्बन्धित है, जबकि पूँजी की पूर्ति बचत (savings) से। अब हम यह भी कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ब्याज की दर का निर्धारण विनियोग मांग सूची (investment demand schedule) तथा बचत अनुसूची (saving schedule) की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा होता है।

पूँजी की मांग (Demand for Capital)

पूँजी की मांग विनियोगों के लिये की जाती है, अर्थात् उत्पादक वर्ग पूँजी की माँग करता है। पूँजी की माँग इसलिये की जाती है क्योंकि पूँजी में उत्पादकता है। लेकिन पूँजी सभी उपयोगों में समान रूप से उत्पादक नहीं होती। सामान्यतः पूँजी की पूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, इसलिये पूँजी का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि प्रतिफल अधिक प्राप्त हो। यदि पूँजी की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो उसे कम उत्पादक कार्यों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Return) क्रियाशील होने के कारण जैसे-जैसे पूँजी का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है वैसे-वैसे उसकी सीमान्त उत्पादकता (marginal productivity) घटती जाती है। लेकिन पूँजी के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि पूँजीगत वस्तुओं का प्रयोग एक लम्बे समय तक किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उत्पादक पूँजीगत वस्तु को चाटू रखने की लागत निकालकर उसकी अनुमानित वास्तविक लागत को ध्यान में रखता है।

फर्म की पूँजी की सीमान्त उत्पादकता रेखा (माँग रेखा) बायें से दायें नीचे की ओर गिरती हुई होती है। एक फर्म का उत्पादक पूँजी का उपयोग उस सीमा तक करता है जहाँ

पर कि पूँजी की सीमात उत्पादकता और व्याज की दर बराबर हो जाती है। यदि व्याज की दर अधिक है तो उत्पादकों द्वारा पूँजी की माग कम की जायेगी। यदि बाजार की दर नीची है तो उत्पादक पूँजी की माग अधिक मात्रा में करेंगे। इस प्रकार पूँजी की माग और व्याज की दर में उल्टा सम्बन्ध होता है। इसलिए माग रेखा बायें से दायें नीचे की ओर गिरती हुई होती है।

पूँजी की पूर्ति (Supply of Demand)

पूँजी की पूर्ति समाज की वृद्धि पर निर्भर करती है, अर्थात् व्यक्तियों कमों तथा सरकार द्वारा की गई वृद्धि पर पूर्ति निर्भर करती है। समाज के द्वारा की गई वृद्धि पर आय का स्तर, जीवन स्तर, दूरदर्जिता, श्रिचार के प्रति स्नेह तथा व्याज की दर आदि तत्वों का प्रभाव पड़ता है। यदि सभी स्थितियों को स्थिर मान लिया जाय तो व्याज की दर ही पूँजी की पूर्ति को सर्वाधिक प्रभावित करेगी। साधारणतया जब व्याज की दर ऊँची होना है तब व्यक्तियों द्वारा अधिक वृद्धि की जाती है तथा व्याज की दर नीची रहने पर वृद्धि कम मात्रा में होती है। लेकिन समाज में एक वय ऐसा भी होता है जो व्याज की दर पर ध्यान नहीं देता और अपनी वृद्धि करता रहता है जिससे कि भविष्य में एक निश्चित आय उनको प्राप्त होती रहे। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम होते हैं। सामान्य वृद्धिकर्ता व्याज की दर से प्रभावित होता है, अर्थात् ऊँची दर पर अधिक वृद्धि और नीची व्याज दर पर कम वृद्धि करता है। इसीलिए पूँजी की पूर्ति रेखा बायें से दायें नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई होती है। पूँजी की पूर्ति रेखा को वृद्धि की पूर्ति रेखा भी कहते हैं।

जब कोई व्यक्ति वृद्धि करता है तो उसे अपने वर्तमान उपभोग को स्थगित करना पड़ता है। इस स्थगन के कारण उनको त्याग करना होता है क्योंकि वर्तमान की आवश्यकतायें भविष्य की अनेक अधिक तीव्र होती हैं। अतः कोई भी व्यक्ति उस समय तक वृद्धि नहीं करेगा जब तक कि उसे 'त्याग' का प्रतिकर अर्थात् व्याज प्राप्त न हो। प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार पूँजी की पूर्ति की दृष्टि से व्याज की दर इतनी ऊँची होनी चाहिए कि सीमान्त वृद्धिकर्ता (marginal saver) को वृद्धि के लिए प्रोत्साहित कर सके।

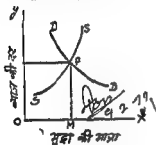
व्याज का निर्धारण (Determination of Interest)

इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज का निर्धारण उस बिन्दु पर होता है जहाँ पर कि पूँजी की माग व पूँजी की पूर्ति बराबर हो जाती है। जिस बिन्दु पर माग और पूर्ति बरा-

वर होती है, उसे सन्तुलन बिन्दु कहते हैं। सन्तुलन बिन्दु पर बचत और विनियोग बराबर होते हैं।

जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि पूँजी की माग रेखा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता को भी व्यक्त करती है। यदि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता व्याज की दर से कम है तो उत्पादको द्वारा पूँजी की माग कम की जाएगी। माग कम हो जाने के कारण व्याज की दर गिरेगी और व्याज की दर गिरकर सीमान्त उत्पादकता के बराबर हो जाएगी। इसके विपरीत यदि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता व्याज की दर से अधिक है तो उत्पादको द्वारा पूँजी की माग अधिक होगी। अधिक माग होने के कारण व्याज की दर बढ़ेगी और बढ़कर सीमान्त उत्पादकता के बराबर हो जाएगी। इन प्रकार सन्तुलन की स्थिति में व्याज की दर हमेशा सीमान्त उत्पादकता के बराबर होगी।

पूँजी की पूर्ति रेखा बचतों की पूर्ति को व्यक्त करती है। इस सिद्धांत के अनुसार



सन्तुलन की स्थिति में बचत तथा विनियोग में समानता रहती है। यदि किसी समय विशेष में बचत तथा विनियोग में असन्तुलन स्थापित होता है तो व्याज की दर में परिवर्तन होगा तथा व्याज की दर का यह परिवर्तन बचत तथा विनियोग में समानता स्थापित कर देगा। व्याज की दर में निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है—

उपरोक्त चित्र में DD पूँजी की माग रेखा तथा SS पूँजी की पूर्ति रेखा है। माग व पूर्ति रेखा (विनियोग व बचत रेखा) एक दूसरे को P बिन्दु पर काटती हैं। अतः P सन्तुलन बिन्दु हुआ तथा PM व्याज की दर। इसी व्याज की दर पर बचत और विनियोग में सन्तुलन स्थापित होगा।

मालोचना (Criticism)

व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धान्त को अनेक आलोचनायें की गई हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं—

- (१) इस सिद्धान्त के अनुसार विनियोग तथा बचत में समानता व्याज की दर से स्थापित होती है, लेकिन कीन्स (Keynes) इस विचार से सहमत नहीं हैं। कीन्स के अनुसार बचत और विनियोग में समानता आय के स्तर से स्थापित होती है।
- (२) इस सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर और बचत तथा विनियोग में प्रयत्न तथा महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है अर्थात् व्याज की दर में परिवर्तन होने से बचत और

विनियोग में परिवर्तन हो जाते हैं। परन्तु अनुभव यह सिद्ध करता है कि व्याज और विनियोग में प्रयत्न सम्बन्ध नहीं होता। जैसे एक निर्यन्त देश में व्याज की दर में वृद्धि होने पर भी बचनों में अधिक मात्रा में वृद्धि नहीं होती, इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि व्याज की दर अधिक हो, फिर भी विनियोगों के लिये पूँजी की माग अधिक मात्रा में की जाय। अतः व्याज की दर और बचत का सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहीं होता, यह सही है कि व्याज की दर कुछ सीमा तक बचनों की मात्रा को प्रभावित करती है। आलोचकों के अनुसार व्याज की दर की अपेक्षा आय के स्तर का प्रभाव बचतों पर अधिक पड़ता है।

(१) इस सिद्धांत के अनुसार 'व्याज त्याग का प्रतिफल है'। कोन्स ने बताया कि यह विचार उचित नहीं क्योंकि यदि एक व्यक्ति को अपने पूर्वजों से पूँजी प्राप्त होती है तब भी उसे उस पूँजी पर व्याज प्राप्त होता है जबकि उसको त्याग नहीं करना पड़ता। अतः कोन्स ने कहा है कि—“व्याज उपभोग त्यागने का पुरस्कार नहीं है अपितु तरलता के परित्याग का पुरस्कार है।”

(४) यह सिद्धांत आय पर विनियोग के प्रभाव की उपेक्षा करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्याज की दर ऊँची होगी, तो अधिक व्यक्ति बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता। जैसे—यदि व्याज की दर ऊँची होती है तो कम विनियोग होंगे, परिणामस्वरूप कम आय होगी और व्यक्तियों को कम रोजगार प्राप्त होगा। इस सबका परिणाम यह होगा कि आय कम होने के कारण बचत भी कम हो जायेगी, भले ही व्याज की दर ऊँची है।

(५) इस सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर अनिर्धारित रह जाती है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर पूँजी की माग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन पूँजी की पूर्ति निर्धारित करना सम्भव नहीं है इसलिए व्याज की दर भी निर्धारित नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर निर्धारित करने के लिए बचतें ज्ञात होनी चाहिये और बचतों का ज्ञान करने के लिए व्याज की दर मालूम होनी चाहिये। इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है।

(६) कोन्स ने इस सिद्धांत की आलोचना की है कि यह सिद्धांत व्याज की दर के निर्धारण में मुद्रा की मात्रा, बैंक साख, पिछली बचतें आदि के महत्व की उपेक्षा करता है।

(७) यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। कोन्स तथा अन्य अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि वास्तविक समाज में साधनों का पूर्ण उपभोग सम्भव नहीं अर्थात् समाज में पूर्ण से कम रोजगार पाया जाता है।

६ व्याज का तरलता पसन्दगी सिद्धांत (Liquidity Preference Theory of Interest)

लाइड कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'General Theory of Employment, Interest and Money' में व्याज के 'तरलता पसन्दगी सिद्धांत' का प्रतिपादन किया। व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत से भिन्न कीन्स का यह सिद्धांत व्याज का मौद्रिक सिद्धांत (monetary theory) है। उस सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की माग एवं पूर्ति के द्वारा होता है।

कीन्स के अनुसार — 'व्याज वह कीमत है जो धन को नकद रूप में रखने की इच्छा तथा प्राप्त नकदी की मात्रा में समानता स्थापित करती है।'^{१०}

इस प्रकार कीन्स के अनुसार—व्याज बचत करने का पुरस्कार नहीं है अपितु "व्याज निश्चित अवधि के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है।"^{११}

कीन्स के अनुसार जिस प्रकार वस्तु का मूल्य वस्तु की माग व पूर्ति से निर्धारित होता है उसी प्रकार व्याज की दर भी मुद्रा की माग व पूर्ति से निर्धारित होती है। मुद्रा की माग तरलता पसन्दगी (liquidity preference) से सम्बन्धित है तथा मुद्रा की पूर्ति समाज में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा से।

मुद्रा की माग या तरलता पसन्दगी (Demand for Money or Liquidity Preference)

कीन्स के अनुसार मुद्रा की माग से अभिप्राय मुद्रा की उस मात्रा से है जिसे व्यक्ति अपने पास तरल रूप में रखना चाहता है अर्थात् तरलता पसन्दगी ही मुद्रा की माग है।

कोई भी व्यक्ति जिसे आय प्राप्त होती है वह मजस्त आय को व्यय नहीं करता। वह निर्णय लेता है कि आय का कितना भाग उपभोग कार्यों में व्यय किया जाय और कितना भाग बचा कर रखे। बचत की भी कई रूपों में रखा जा सकता है, परन्तु कीन्स का यह विश्वास है कि मुद्रा सबसे अधिक तरल है अतः सामान्यतः व्यक्ति अपनी आय के बचे हुए भाग को तरल रूप में ही रखना पसन्द करते हैं। यदि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने इस बचे हुए भाग को देता है तो उसे तरलता का परित्याग करना पड़ता

10 "It is the price which equilibrates the desire to hold wealth in the form of cash with the available quantity of cash"

—Keynes

11 "Interest is the reward for parting with liquidity for a specified period of time"

—Keynes

है। अतः उस व्यक्ति को तरलता के परित्याग का पुरस्कार प्राप्त होना चाहिये। कीन्स के अनुसार तरलता के परित्याग का पुरस्कार ही व्याज है।

तरलता परन्तु उत्पन्न होने का कारण क्या है? इस सम्बन्ध में कीन्स का विचार है कि व्यक्ति समाज में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पास तरल रूप में मुद्रा रखना चाहता है। तरल रूप में मुद्रा, कीन्स के अनुसार निम्नलिखित तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रखी जाती है।

१. कार्य-सम्पादन उद्देश्य या लेन-देन उद्देश्य (Transactions motive),
२. आन्तरिक कार्यों का उद्देश्य या सतर्कता उद्देश्य (Precautionary motive),
३. सट्टा उद्देश्य (Speculative motive)।

१. कार्य सम्पादन उद्देश्य या लेन-देन का उद्देश्य (Transactions Motive) :

प्रत्येक व्यक्ति की आय का एक निश्चित समय होता है किन्तु उसे व्यय प्रतिदिन करने पड़ता है, इसलिए व्यक्ति दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अपने पास मुद्रा तरल रूप में रखना चाहता है। कार्य सम्पादन के उद्देश्य से वह तरल रूप में मुद्रा को इष्टिकोण से रखता है—

(१) आय उद्देश्य (Income motive)—जब एक उपभोक्ता अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए मुद्रा तरल रूप में रखता है तो उसे आय उद्देश्य कहा जाता है। क्योंकि व्यक्ति को आय एक निश्चित समय के बाद ही प्राप्त होती है अतः कुछ मुद्रा तरल रूप में रखना आवश्यक हो जाता है। कार्य सम्पादन हेतु कोई उपभोक्ता मुद्रा की कितनी मात्रा तरल रूप में रखेगा, यह उपभोक्ता की आय के आकार और उसको प्राप्त होने वाली आय की समयावधि पर निर्भर करता है।

(२) व्यवसाय उद्देश्य (Business motive)—जब उत्पादक या साहसी द्वारा कच्चा माल, श्रमिकों की मजदूरी, यन्त्राधान व्यय या अन्य बाह्य व्ययों का भुगतान करने के लिए अपने पास मुद्रा तरल रूप में रखी जाती है तो उसे व्यवसाय उद्देश्य कहते हैं। व्यवसाय उद्देश्य के लिए तरल रूप में रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा फर्म के 'क्रय-विशेष' पर निर्भर करती है।

इस प्रकार आय उद्देश्य और व्यवसाय उद्देश्य दोनों मिलकर कार्य सम्पादन उद्देश्य का निर्माण करते हैं। कीन्स के अनुसार इस उद्देश्य के लिये तरल रूप में रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा, प्रत्यक्ष रूप से व्याज की दर से प्रभावित नहीं होती।

२. आकस्मिक कार्य का उद्देश्य या सतर्कता उद्देश्य (Precautionary Motive) :

व्यक्ति अपनी आय के एक भाग को तरल रूप में अप्रत्याशित आवश्यकताओं की सतुष्टि के लिए रखना चाहता है। दूसरे शब्दों में, बीमारो, बेरोजगारी या अन्य आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए व्यक्ति मुद्रा की कुछ मात्रा तरल रूप में रखता है। इस उद्देश्य के लिए तरल रूप में रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा व्यक्तियों के आय के स्तर पर निर्भर करती है। कीन्स के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा भी प्रत्यक्ष रूप से व्याज की दर से प्रभावित नहीं होती।

३. सट्टा उद्देश्य (Speculative Motive) :

कुछ व्यक्तियों द्वारा मुद्रा तरल रूप में इस उद्देश्य से रखी जाती है कि यदि भविष्य में व्याज की दरों में वृद्धि हुई तो वे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सट्टे के उद्देश्य के बारे में कीन्स ने लिखा है—

“भविष्य की घटनाओं के सम्बन्ध में साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक जानकारी होने के कारण लाभ कमाने के उद्देश्य को ही सट्टा उद्देश्य कहते हैं।”^{१२}

कीन्स के अनुसार कार्य सम्पादन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य तथा सट्टा उद्देश्य तीनों मिलकर मुद्रा की कुल माग को निर्धारित करते हैं। यदि नकद मुद्रा की कुल माग को L के द्वारा व्यक्त किया जाय तथा प्रथम दो उद्देश्य कार्य सम्पादन उद्देश्य तथा सतर्कता उद्देश्य की नकद मुद्रा की माग को L_1 के द्वारा व्यक्त किया जाय तथा सट्टा उद्देश्य के लिए नकद मुद्रा की मात्रा को L_2 के द्वारा व्यक्त किया जाय तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं

$$L = L_1 + L_2$$

कीन्स के अनुसार L_1 व्याज की दर से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता, यह सामान्यतः आय के स्तर पर निर्भर करता है। L_2 व्याज की दर से प्रभावित होता है अर्थात् सट्टे के उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नकद मुद्रा की माग व्याज की दर में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। कीन्स ने व्याज की दर को निर्धारित करने के लिये मुद्रा की इसी माग (L_2) पर अधिक जोर दिया है।

व्याज की दर तथा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की माग में उल्टा सम्बन्ध होता है, इसलिए मुद्रा की माग रेखा (या तरलता पसन्दगी रेखा) बायें से दायें नीचे की ओर गिरती हुई होती है।

12 “Speculative motive is a motive of earning profit by knowing better than market what the future will bringforth” —Keynes

मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money) -

मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय मुद्रा की उस मात्रा से है जिसे व्यक्ति अपने पास रखना चाहते हैं। सामान्यतः मुद्रा की कुल पूर्ति में बैंक साख पत्र-मुद्रा तथा सिक्के सम्मिलित रहते हैं। मुद्रा की पूर्ति एक प्रवाह (flow) न होकर एक स्टॉक (stock) है। मुद्रा की पूर्ति पर मुद्रा प्रचिकारी (या केन्द्रीय बैंक) का नियन्त्रण होता है इसलिए समय विशेष में मुद्रा की कुल पूर्ति लगभग स्थिर रहती है।

समय विशेष में मुद्रा की कुल पूर्ति (M) स्थिर रहने के कारण पूर्ति रेखा एक लंबी रेखा (vertical line) होती है।

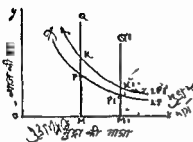
व्याज की दर का निर्धारण (Determination of the Rate of Interest)

व्याज की दर का निर्धारण उस बिन्दु पर होता है जहाँ कि मुद्रा की माग रेखा (तरलता पसन्दगी रेखा) तथा मुद्रा की पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती हैं। व्याज निर्धारण के सम्बन्ध में कीन्स का विचार है कि—

- (१) यदि तरलता पसन्दगी (मुद्रा की माग) स्थिर रहती है और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो व्याज की दर गिर जायेगी, तथा यदि मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है तो व्याज की दर बढ़ जायेगी।
- (२) यदि मुद्रा की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता और तरलता पसन्दगी बढ़ जाती है तो व्याज की दर भी बढ़ जायेगी। यदि तरलता पसन्दगी घट जाती है तो व्याज की दर भी घट जायेगी।
- (३) यदि तरलता पसन्दगी और मुद्रा की पूर्ति दोनों में परिवर्तन होता है तब व्याज की दर का निर्धारण दोनों सन्तुलन द्वारा होगा। यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि तथा तरलता पसन्दगी में वृद्धि समान अनुपात में होती है तो व्याज की दर अप्रभावित रहेगी। यदि मुद्रा की पूर्ति तरलता पसन्दगी के अनुपात से अधिक बढ़ जाती है तो व्याज की दर घटेगी तथा यदि मुद्रा की पूर्ति के अनुपात से तरलता पसन्दगी बढ़ जाती है तो व्याज की दर बढ़ेगी।

सामान्यतः मुद्रा की पूर्ति व्याज की दर को प्रभावित करती है परन्तु व्याज की दर मुद्रा पूर्ति को प्रभावित नहीं करती।

कीन्स के व्याज सिद्धांत को रेखा चित्र की सहायता से भी स्पष्ट किया जा सकता है।



समस्त विश्व में LP तरलता पसन्दगी रेखा है अर्थात् मुद्रा की माग को व्यक्त करती है। OM मुद्रा की पूर्ति है जिसे QM रेखा द्वारा प्रदर्शित किया है, क्योंकि मुद्रा की कुल मात्रा को हम स्थिर मानकर चलें हैं। अर्थात् व्याज की दर में होने वाले परिवर्तनों का मुद्रा की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थिति में जबकि LP मुद्रा की माग रेखा है और QM पूर्ति रेखा, दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को P बिन्दु पर काटती हैं। अतः व्याज की दर PM होगी। इस व्याज की दर पर माग व पूर्ति बराबर हैं।

यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है और तरलता पसन्दगी बढ़कर LP_1 हो जाती है, उस स्थिति में व्याज की दर PM से बढ़कर KM हो जायेगी। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़कर OM_1 हो जाती है और तरलता पसन्दगी LP रहती है अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं होता तो व्याज की दर घटकर P_1M_1 हो जाती है। यदि तरलता पसन्दगी में भी परिवर्तन होता है अर्थात् LP से बढ़कर LP_1 हो जाती है तथा मुद्रा की पूर्ति भी बढ़कर OM से OM_1 हो जाती है, तब व्याज की दर K_1M_1 होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि साम्य की स्थिति में तरलता पसन्दगी और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती हैं।

प्रो. कीन्स के अनुसार— 'साम्य की अवस्था वह है जिसमें व्याज की दर मुद्रा की माग तथा व्यक्तियों की मुद्रा की तरल रूप में रखने की इच्छा के बराबर होती है।' १३

तरलता पसन्दगी सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Liquidity Preference Theory)

कीन्स का सिद्धांत यद्यपि पूर्व के सिद्धान्तों की अपेक्षा थोड़ा है फिर भी यह दोष-रहित नहीं है। विभिन्न व्यंशास्त्रियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इस सिद्धांत की आलोचना की है।

- 13 "At the equilibrium position, the rate of interest will be just as the level necessary to equate the quantity of money in existence with the aggregate amount wanted by the people to hold"

— Keynes

प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं —

- (१) प्रो हेन्सन (Prof Hanson) के अनुसार—‘कीन्स के सिद्धांत में वही आलोचना लागू होती है जो कि कीन्स ने प्रतिष्ठित सिद्धांत के सम्बन्ध में की थी ।’^{१४}

हेन्सन के अनुसार सिद्धांत में भी व्याज की दर अनिवारित रहती है, क्योंकि इन सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर का निर्धारण तरलता पसन्दगी और मुद्रा की पूर्ति से होता है। परन्तु तरलता पसन्दगी आय के स्तर से प्रभावित होती है और आय का स्तर व्याज की दर पर निर्भर करता है। क्योंकि व्याज की दर का प्रभाव विनियोगों पर पड़ता है और विनियोगों के परिवर्तन आय के स्तर में परिवर्तन ला देते हैं अतः व्याज की दर का पता लगाने के लिए आय के स्तर को जानना होगा तथा आय के स्तर का पता लगाने के लिए व्याज की दर का पता होना चाहिए। इस प्रकार कीन्स का सिद्धांत भी व्याज की दर को ठीक तरह से निर्धारित नहीं कर पाता।

- (२) प्रो हेनरी हेजलिट (Henry Hazlitt) के अनुसार कीन्स व्याज के निर्धारण में केवल मौद्रिक तत्वों पर ही अतिव्रत और देता है और उत्पादकता तथा समय पसन्दगी जैसे वास्तविक तत्वों की उपेक्षा करता है। अतः यह सिद्धांत पूर्ण नहीं है जैसा कि प्रो. विकसेल (Prof Wickseil) ने कहा है कि—“उस समय तक कोई सिद्धान्त पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि उसमें दोनों तत्वों, मौद्रिक और वास्तविक का समावेश न हो।”

- (३) कीन्स का सिद्धांत पूँजी की उत्पादकता को महत्व प्रदान नहीं करता। बेनहम (Benham) के अनुसार पूँजी की मात्रा पर पूँजी की सीमांत-उत्पादकता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पूँजी की मात्रा केवल इस उद्देश्य के लिए नहीं की जाती कि उसे तरल रूप में रखा जाय बल्कि इसलिए भी की जाती है कि पूँजी का विनियोग कर वस्तु का उत्पादन किया जाय।

- (४) कीन्स ने तरलता के परित्याग को व्याज का आधार माना है लेकिन जेबब विनर (Jacob Viner) के अनुसार रिना बचत के तरलता का परित्याग नहीं किया जा सकता। अर्थात् पहले बचत करनी होती है उसके बाद ही तरलता का त्याग सम्भव है। अतः कीन्स द्वारा बचत की उपेक्षा करना गलत है।

- (५) कीन्स का सिद्धांत संकुचित है क्योंकि यह सिद्धांत तरलता पसन्दगी को केवल तीन उद्देश्यों से ही सम्बन्धित करता है, जबकि व्याज की दर पर प्रभाव उत्पादकता, वचन और उपयोग की प्रवृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है।

यह सिद्धांत तरलता पसन्दगी अर्थात् मांग का अधिक महत्व प्रदान करता है तथा मुद्रा की पूर्ति का यह समय विशेष में मौद्रिक अधिकारी द्वारा नियन्त्रित मान लेता है। इस प्रकार यह सिद्धांत दोनों पक्षों—मांग व पूर्ति—को समान महत्व प्रदान नहीं करता।

- (६) यह सिद्धांत अल्पकाल में व्याज निर्धारण की व्याख्या करता है। दीर्घकाल में व्याज की दर क्या होगी इसकी व्याख्या नहीं करता।

- (७) कीन्स का सिद्धांत व्यावहारिक तत्वों के विपरीत है। कीन्स के सिद्धांत के अनुसार मन्दी की स्थिति में व्याज की दर अधिक ऊँची होनी चाहिए क्योंकि उस समय व्यक्तियों की तरलता पसन्दगी अधिक होती है तथा तेजी की स्थिति में व्याज की दर नीची होनी चाहिए क्योंकि तरलता पसन्दगी कम होती है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि मन्दी की स्थिति में व्याज की दर नीची होती है तथा तेजी की स्थिति में व्याज की दर ऊँची। इस प्रकार यह सिद्धांत वास्तविक स्थिति की व्याख्या करने में असमर्थ है।

७ व्याज का उधार देव बोध सिद्धांत या व्याज का नव-प्रतिष्ठित सिद्धांत (Loan able Fund Theory of Interest or Neo-classical Theory of Interest)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्वीडन के अर्थशास्त्री विकसेल (Wicksell) ने किया। बाद में ओहलिन (Ohlin), गुन्नार मिडल (Gunnar Myrdal), हेन्सन (Hanson) तथा लिण्डल (Lindahl) आदि स्वीडन के अर्थशास्त्रियों ने इसमें सुधार किया। इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्टसन (Robertson) ने भी इस सिद्धांत के विकास में सहयोग दिया है।

यह सिद्धान्त व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का सुधार हुआ रूप है, इसलिए इसे नव प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धान्त में व्याज के निर्धारण के लिये मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों ही प्रकार के तत्वों को सम्मिलित किया गया है, जबकि प्रतिष्ठित सिद्धांत केवल वास्तविक तत्वों (अमौद्रिक तत्वों) से सम्बन्धित है और कीन्स का केवल मौद्रिक तत्वों से।

उधार-देय कोष से अभिप्राय उस मुद्रा से होना है जिसकी मुद्रा बाजार में माग और पूर्ति होती है अर्थात् ऋण लेने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार में जितनी मुद्रा की माग की जाती है तथा ऋण देने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार में जितनी मुद्रा प्रस्तुत की जाती है, वह उधार-देय कोष नहीं जाती है।^{१५}

प्रो. हेन्सन (Hanson) के अनुसार—“उधार-देय कोष विश्लेषण के अनुसार ध्याज की दर का निर्धारण उधार-देय कोष की माग सूची एवं पूर्ति सूची के संतुलन द्वारा होता है।”^{१६}

दूसरे शब्दों में, ध्याज का निर्धारण उस बिन्दु पर होगा है जहाँ कि उधार देय कोषों की माग एवं पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। उधार-देय कोष सिद्धान्त के दोनों पक्ष—माग और पूर्ति—प्रतिष्ठित सिद्धान्त की तुलना में अधिक विस्तृत हैं।

उधार-देय कोषों की मांग (Demand of Loanable Funds)

मुद्रा की माग उत्पादक तथा उपयोग दोनों ही कार्यों के लिये की जाती है। उधार-देय कोष सिद्धान्त इन दोनों की माग में सम्मिलित करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार उधार-देय कोष की माग के चार स्रोत हैं—(१) उत्पादक तथा व्यापारियों द्वारा माग, (२) उपभोक्ताओं द्वारा माग, (३) सरकार द्वारा माग, तथा (४) संचय करने के लिए माग।

(१) उत्पादक तथा व्यापारियों द्वारा माग—उधार-देय कोषों की उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर माग की जाती है। उत्पादक तथा व्यापारी पूँजीगत वस्तुओं की क्रय करने के लिए मुद्रा की माग करते हैं। क्योंकि उत्पादक तथा व्यापारी पूँजीगत वस्तुओं के लिये मुद्रा की माग करते हैं इसलिए इन कोषों की माग पूँजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। सामान्यतः जब ध्याज की दर कम होती है उस समय उत्पादक तथा व्यापारियों द्वारा उधार देय कोषों की माग अधिक होती है तथा ध्याज की दर अधिक होने पर माग कम की जाती है। इस प्रकार ध्याज की दर और उत्पादक तथा व्यापारियों द्वारा की जाने वाली पूँजी की माग में उल्टा सम्बन्ध होता है।

15 ओहलिन ने उधार-देय कोष के स्थान पर साख्त अद का प्रयोग किया है तथा हेबरलर (Haberler) ने विनियोजन योग्य कोष (investable funds) शब्द का।

16 “According to loanable funds analysis the rate of interest is determined by the intersection of the demand schedule for loanable funds with the supply schedule”
—Hanson

- (२) उपभोक्ताओं द्वारा माग—उपभोक्ताओं द्वारा उधार-देय कोषों की माग उस समय की जाती है जबकि वे अपनी आय और साधनों से अधिक उपयोग की वस्तुओं पर व्यय करना चाहते हैं। उपभोक्ता प्रायः उधार-देय कोषों की माग दिखाऊ वस्तुओं का श्रय करने के लिये करते हैं, जैसे—स्कूटर, टेलीविजन, रेडियो आदि। उपभोक्ताओं की माग व्याज की दर से काफी प्रभावित होती है। यदि व्याज की दर अधिक है तो माग कम होती है तथा नीची व्याज की दर पर माग अधिक होती है।
- (३) सरकार द्वारा माग—सरकार द्वारा भी उधार-देय कोषों की माग की जाती है। सरकार द्वारा माग सङ्कलन परिस्थितियों में तथा विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक की जाती है। सामान्यतः ऊँची व्याज की दर पर सरकार उधार-देय कोष की माग कम करती है तथा नीची व्याज की दर पर अधिक। परन्तु सबकाल में सरकार की माग पर व्याज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- (४) संचय करने के लिए माग—उधार-देय कोषों की माग उन व्यक्तियों के द्वारा भी की जाती है जो कि मुद्रा को सुरक्षित रूप में रखना चाहते हैं। यदि व्याज की दर कम है तो कोष की माग अधिक होगी तथा ऊँची व्याज की दर पर माग कम होगी।

इस प्रकार

उधार-देय कोष की कुल माग = उत्पादक तथा व्यापारी + उपभोक्ता + सरकार + संचय
के लिये की जाने वाली माग

Total demand for loanable funds = Demand by producers &
businessmen + consumers +
Government + Hoarders

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उधार-देय कोषों की माग तथा व्याज की दर में उल्टा सम्बन्ध होता है। अतः उधार-देय कोषों की कुल माग रेखा दाएँ से बाएँ नीचे की ओर गिरती हुई होती है।

उधार-देय कोषों की पूर्ति (Supply of Loanable Funds)

उधार-देय कोष की पूर्ति के निम्नलिखित स्रोत हैं—

- (१) बचतें (Savings)—उधार-देय कोष की पूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बचतें हैं। बचतें व्यक्तियों द्वारा तथा व्यावसायिक फर्मों द्वारा की जाती हैं।

व्यक्ति अपनी वाप का कुछ भाग बचाकर रखता है। रॉबटसन के अनुसार व्यक्तियों द्वारा वचत वर्तमान आय में से नहीं की जाती बल्कि 'प्रयोग योग्य आय' से वचत की जाती है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा वर्तमान में किये गये प्रयत्न या कार्य का प्रतिफल वर्तमान में ही प्राप्त नहीं होता बल्कि भविष्य में प्राप्त होता है। सामान्यतः ऊँची व्याज की दर पर अधिक वचत होती है और नीची व्याज की दर पर कम।

व्यावसायिक फर्मों द्वारा भी वचते की जाती हैं, लेकिन इन फर्मों द्वारा की जाने वाली वचतें प्रायः अपने ही विनियोग कार्यों के लिये होती हैं। इसलिए उनकी बाजार में माग व पूर्ति नहीं होती। अतः फर्मों द्वारा की गई वचतें पूर्ति को प्रभावित नहीं करती।

- (२) बैंक साख (Bank credit)—उधार देय कोषों की पूर्ति सरकार द्वारा नोट छापकर या बैंकों द्वारा साख का निर्माण करके की जाती है।
- (३) विद्युती वचतो का विसंग्रह (Dishoarding for past savings)—जब व्यक्तियों द्वारा भूतकाल में की गई वचतों का विसर्ज्य किया जाता है तो उधार-देय कोषों की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। सामान्यतः जब व्याज की दर ऊँची होती है तब व्यक्तियों द्वारा विसर्ज्य अधिक मात्रा में किया जाता है।
- (४) अविविनियोग (Disinvestment)—जब फर्मों या व्यावसायिक संस्थाएँ 'विसावट कोष' तथा अन्य कोष में रखी जाने वाली राशि को बाजार में प्रस्तुत कर देती हैं तब उधार देय कोषों की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है।

इस प्रकार

उधार-देय कोषों की कुल पूर्ति = वचत + बैंक साख + विसंग्रह + अविविनियोग

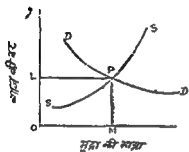
(Total Supply of Loanable Funds = Savings + Bank credit + Dishoarding + Disinvestment)

उपरोक्त विस्तरेण से स्पष्ट है कि उधार-देय कोषों की पूर्ति और व्याज की दर का सम्बन्ध सीधा होता है। अतः उधार-देय कोषों की कुल पूर्ति रखा बायें से दायें ओर बढ़ती हुई होती है।

व्याज की दर का निर्धारण (Determination of the Rate of Interest) :

इस सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर का निर्धारण उस बिन्दु पर होता है जहाँ पर उधार-देय कोषों की कुल माग और कुल पूर्ति बराबर होती है। यदि उधार देय कोषों की

माग और पूर्ति में असन्तुलन स्थापित हो जाता है तो व्याज की दर ॥ भी परिवर्तन होगा, और व्याज की दर का यह परिवर्तन उधार-देय कोषों की माग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित कर देगा। इसे निम्न चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।



समस्त चित्र में DD उधार-देय कोषों की कुल माग रेखा है तथा SS पूर्ति रेखा। P बिन्दु पर माग और पूर्ति बराबर हैं अतः PM व्याज की दर है और OM कुल माग और कुल पूर्ति की मात्रा।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Theory)

उधार देय कोष सिद्धांत व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत पर एक सुधार है क्योंकि

इसमें माग पक्ष में व्यापारियों तथा उत्पादकों द्वारा की जाने वाली माग के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं, सरकार और सचय के लिये की जाने वाली माग को भी सम्मिलित किया गया है। पूर्ति पक्ष में बचतों के अतिरिक्त वित्तबचय, अविनियोग और बैंक साज को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार यह सिद्धांत मौद्रिक और वास्तविक दोनों तत्वों को सम्मिलित करता है। फिर भी यह सिद्धान्त दोषरहित नहीं है, इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत बचतों पर ब्याज दर के पड़ने वाले प्रभाव की अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या करता है। व्यवहार में व्याज की दर बचतों को इतना अधिक प्रभावित नहीं करती। जैसे अमीर व्यक्ति स्वतः ही बचत करेंगे, चाहे व्याज की दर दुर्गम हो क्योंकि उनकी आय इतनी अधिक होती है कि वे समस्त आय को व्यय नहीं कर पाते। इसी प्रकार मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी आवश्यक कार्यों की पूर्ति हेतु बचत करते हैं तथा गरीब व्यक्ति व्याज की दर ऊँची होने पर भी बचत करने की स्थिति में नहीं होते। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बचतों पर व्याज की दर का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि यह सिद्धांत मानता है।
- (२) प्रतिष्ठित सिद्धांत के समान यह सिद्धांत भी आय पर विनियोग के पड़ने वाले प्रभाव की उपेक्षा करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्याज की दर अधिक होती है

तब व्यक्तियों के द्वारा अधिक बचने की जाती है, परन्तु यह बात व्यवहार में सही प्रतीत नहीं होती। क्योंकि जब व्याज की दर अधिक होती है तो विनियोग कम होना है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों को कम रोजगार प्राप्त होता है तथा आय भी कम हो जाती है जो कि बचनों को कम कर देती है। इस प्रकार ऊँची व्याज की दर पर वचन कम होती है।

(३) यह सिद्धांत आय के स्तर को स्थिर मानता है, जो कि गलत है। व्यवहार में, जब विनियोग में परिवर्तन होते हैं, तो आय के स्तर में भी परिवर्तन आ जाते हैं।

(४) प्रतिष्ठित सिद्धांत के समान यह सिद्धांत भी व्याज की दर को अनिर्धारणीय (indeterminate) मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर उधार-क्षेप कोषों की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। उधार-क्षेप कोषों की पूर्ति में वचन एक महत्वपूर्ण श्रेण है। वचनों को ज्ञात करने के लिये व्याज की दर मालुम होनी चाहिए। इस प्रकार व्याज की दर को निर्धारित करने के लिए वचन मालुम होनी चाहिए और वचन को ज्ञात करने के लिए व्याज की दर मालुम होनी चाहिए, अतः यह सिद्धान्त स्वयं ही एक कुचूड़ में फँस जाता है, जिससे व्याज की दर का निर्धारण नहीं हो पाता।

(५) इस सिद्धांत में वास्तविक व भौतिक दोनों तत्वों को मिलाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आलोचकों के अनुसार वचन और विनियोग जैसे वास्तविक तत्वों और बैंक साख तथा तरलता पसन्दगी जैसे भौतिक तत्वों का समायोजन करना अनुपयुक्त है।

व्याज का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Interest)

उपरोक्त सभी सिद्धान्तों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनमें से कोई भी सिद्धान्त व्याज निर्धारण की सतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता। आधुनिक अर्थशास्त्री हिक्स (Hicks) तथा लर्नर (Lerner) ने प्रतिष्ठित सिद्धांत और बोन्स के तरलता पसन्दगी सिद्धान्त के महत्वपूर्ण तत्वों को मिलाकर एक नवीन सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसे व्याज का आधुनिक सिद्धान्त कहते हैं।

व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धान्त में वास्तविक तत्वों—वचन तथा विनियोग—को महत्व प्रदान किया गया था, जबकि बोन्स ने केवल भौतिक तत्वों—तरलता पसन्दगी और मुद्रा की पूर्ति—को ही प्राथमिकता दी। इस प्रकार दोनों ही सिद्धान्त व्याज के निर्धारण की

सही व्याख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे । आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक व मौद्रिक दोनों ही तत्वों को महत्व प्रदान किया और उनका समन्वय कर नया सिद्धान्त दिया । यद्यपि उच्चार-क्षेत्र कोष सिद्धान्त में भी वास्तविक और मौद्रिक तत्वों का समन्वय किया गया है लेकिन उन्ना प्रयत्न अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सका । इस प्रकार आधुनिक सिद्धान्त कीम्स के तरलता पसन्दगी सिद्धान्त और प्रतिष्ठित सिद्धान्त का सम्मिलित रूप है ।

आधुनिक सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर निर्धारित करने के चार निर्धारण तत्व हैं—वचत, विनियोग, तरलता पसन्दगी तथा मुद्रा की मात्रा । इनके अतिरिक्त आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने एक और तत्व 'आय' को भी सम्मिलित किया । आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रतिष्ठित सिद्धान्त का यह विचार कि व्याज की दर वचत और विनियोग में साम्य स्थापित करती है, तर्कसंगत है । इसी प्रकार कीम्स का विचार कि व्याज की दर तरलता पसन्दगी और मुद्रा की मात्रा से साम्य स्थापित करती है, उचित है । यदि इन चार तत्वों में आय तत्व को और सम्मिलित कर लिया जाय तो व्याज निर्धारण का एक सतोषजनक सिद्धान्त प्राप्त हो जाता है ।

इस सिद्धांत के अनुसार व्याज की दर का निर्धारण उस बिन्दु पर होगा जहाँ पर वचत और विनियोग रेखा तथा तरलता पसन्दगी और मुद्रा की पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती है । इस बिन्दु पर (अर्थात् साम्य की स्थिति में) चारों तत्वों—वचत, विनियोग, तरलता पसन्दगी तथा मुद्रा की मात्रा बराबर होता है ।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. शुद्ध व्याज तथा कुल व्याज में क्या अन्तर है ? शुद्ध व्याज किस प्रकार निर्धारित होती है ?
२. "व्याज प्रतीक्षा का प्रतिफल है ।" इस कथन की व्याख्या कीजिए ।
३. व्याज के एजियो या आस्ट्रियन सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।
४. "व्याज पूंजी-वचतों की पूर्ति एवं पूंजी विनियोगों के बीच समानता स्थापित करता है ।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए ।
५. व्याज के माग व पूर्ति सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।
६. व्याज के तरलता पसन्दगी सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।

- ७ उधार-देय कोष सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।
- ८ "उधार-देय कोष सिद्धान्त व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धान्त पर एक सुधार है ।" व्याख्या कीजिए ।
- ९ कोन्स के तरलता पसन्दगी सिद्धान्त और उधार देय कोष सिद्धान्त के अन्तर को स्पष्ट कीजिए ।
१०. आधुनिक सिद्धान्त व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धान्त और तरलता पसन्दगी सिद्धान्त का सम्मिलित रूप है ।" क्या आप इससे सहमत हैं ?
११. "व्याज शुद्ध प्रतीक्षा का मुद्रस्वरूप है । यह एक निश्चित समय में पूँजी के प्रयाग की प्रीति है और इसलिए व्याज की दर पूँजी को माय और पूँति द्वारा निर्धारित होती है ।" स्पष्ट कीजिए ।



अध्याय १७

★

लाभ [Profit]

★ ★ ★

राष्ट्रीय आय का वह भाग जो साहसी को उत्पादन कार्य में जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है उसे लाभ कहते हैं। लेकिन लाभ शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है इसलिये उल्लेखन में पड़ जाने का भय रहता है, जैसा कि प्रो नाइट (Prof Knight) ने लिखा है —

“लाभ को छाड़कर अर्थशास्त्र में घायब ही और कोई शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ हो।”

लाभ के अर्थ को समझने के लिए हम कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का लेते हैं।

प्रो जे के मेहता के अनुसार—“इस गतिशील विश्व में मानव के उत्पादन कार्यों में अनिश्चितता तब एक चौथे प्रकार का त्याग उत्पन्न करता है। यह त्याग जोखिम उठाना अथवा अनिश्चितता बहन करना है, जिसको लाभ द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।”¹

एच एम क्रूम (H M Croome) के शब्दों में—“लाभ उन खतरों का पुरस्कार है जिनका बीमा नहीं हुआ है।”²

1 “The element of uncertainty introduces a fourth category of sacrifices in the productive activities of men in this dynamic world. This category is risk taking or uncertainty bearing. It is remunerated by profit.” —J K Mehta

2 “Profit is the reward for uninsured risks” —H. M Croome

प्रो लेफ्टविच (Prof Leftwich) के अनुसार—“आर्थिक लाभ पद की कुल उत्पादन लागतों के ऊपर कुल प्राप्तियों का शुद्ध अवशेष या अतिरेक है।”³

प्रो हेनरी ग्रेसन (Prof Henry Grayson) के अनुसार—“लाभ नवप्रवर्तन के लिए पुरस्कार है, जोखिम और अनिश्चितता स्वीकार करने का पुरस्कार है तथा बाजार के छांचे की अपूर्णताओं का परिणाम है। स्पष्ट है कोई एक दशा या तीसरी दशाओं का कोई भी मिश्रण आर्थिक लाभ को जन्म दे सकता है।”⁴

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि लाभ के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों के विचारों में भिन्नता है। लाभ को सही रूप में समझने के लिए कुल लाभ व शुद्ध लाभ का अध्ययन आवश्यक है।

कुल लाभ एवं शुद्ध लाभ (Gross Profit and Net Profit)

साधारणतः जब लाभ पद का प्रयोग किया जाता है तो उसका अभिप्राय कुल लाभ से होता है। कुल लाभ एक आधिक्य है जो कि साहसी की कुल आय में से कुल व्यय घटा देने के बाद प्राप्त होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री कुल व्यय के अन्तर्गत केवल उन्हीं साधनों पर किये गये व्यय को सम्मिलित करते हैं जिनकी कि साहसी क्रय करता है। दूसरे शब्दों में, कुल आय में से स्पष्ट लागत घटा देने के बाद जो बचता है वह कुल लाभ है। कुल लाभ में निम्नलिखित मदें सम्मिलित रहती हैं—

(१) प्रस्पष्ट लागत—अर्थात् साहसी द्वारा स्वयं के लगाए गए साधनों का पुरस्कार—जब साहसी द्वारा अपने ही ध्यवसाय में अपनी पूँजी लगाई जाती है या स्वयं की भूमि पर उत्पादन कार्य करता है या स्वयं ही प्रबन्ध कार्य करता है, ऐसी दशा में उसकी अपनी पूँजी पर प्राप्त होने वाला व्याज, भूमि का लगान और प्रबन्धक के रूप में मिलने वाला वेतन कुल लाभ में सम्मिलित होगा। क्योंकि यदि साहसी इन

3 “Economic profit is a pure surplus or excess of total receipts over all costs of production incurred by the firm”

—Prof Leftwich

4 “Profit may be considered as a reward for making innovations, a reward for accepting risks and uncertainties, and a result of imperfections in the market structure. Evidently, any one or any combination of the three conditions can give rise to economic profits”

—Prof Henry Grayson

साधनो को दूसरे उत्पादक को देता है तो उसको इन साधनो का पुरस्कार प्राप्त होता है।

(१) मशीन आदि का घिसावट व्यय—उत्पादन कार्य में मशीन, यंत्र आदि पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग करने से उनमें घिसावट होती है और कुछ समय बाद वे उत्पादन कार्य के योग्य नहीं रह पाती। ऐसी स्थिति में साहसी कुल लाभ में से एक भाग अलग से रख देता है जिससे कि नयी मशीनें, यंत्र आदि त्रय किय जा सकें। कुल लाभ में घिसावट व्यय तथा बीमा व्यय आदि सम्मिलित रहते हैं।

(२) एकाधिकारी लाभ—कभी-कभी बाजार में किसी वस्तु के उत्पादक को एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात् एक उत्पादक बाजार में वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। ऐसी स्थिति में वह उपभोक्ताओं को ऊँचे मूल्य पर वस्तु बेचता है जिससे उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह लाभ कुल लाभ में सम्मिलित रहता है।

(३) घाकस्मिक लाभ (Windfall or chance gain) कभी-कभी युद्ध के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हो जाती है जिसके कारण साहसी को काफी लाभ प्राप्त होता है। यह लाभ भी कुल लाभ में सम्मिलित रहता है।

(४) शुद्ध लाभ—उपयुक्त सभी मदों को कुल लाभ में से घटाने के बाद जो शेष बचता है वही शुद्ध लाभ है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार शुद्ध लाभ साहसी द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित कार्यों का प्रतिफल है।

(a) समन्वय करना—साहसी ही उत्पादन के कार्य का संगठन तथा साधनो का समन्वय करता है। साहसी ही उत्पादन की योजना बनाता है और उसे नियामित करता है।

(b) जोखिम उठाना—पूँजीवादी व्यवस्था में साहसी को काफी अधिक जोखिम उठाना पड़ती है। साहसी लागत और आय के बारे में अनुमान लगाता है। यह अनुमान गलत निकलते हैं तो उसे हानि प्राप्त हो सकती है।

(c) नवप्रवर्तन का पुरस्कार—साहसी द्वारा उत्पादन पद्धतियों में नये नये प्रयोग किये जाते हैं तथा नयी नयी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण लाभ प्राप्त होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुद्ध लाभ कुल लाभ का ही एक भाग है। शुद्ध लाभ एवं कुल लाभ को संक्षेप में हम कह सकते हैं —

- (१) कुल लाभ = कुल आय — कुल स्पष्ट लागतें
 = स्पष्ट लागतों का प्रतिफल + घिसावट का धन्य + एकाधिकारी लाभ
 + आवस्मिक लाभ + शुद्ध लाभ
- (२) शुद्ध लाभ = कुल आय — (स्पष्ट लागतें + अस्पष्ट लागतें)
 = कुल लाभ — अस्पष्ट लागतें
 = कुल लाभ — (स्पष्ट लागतें + घिसावट धन्य + एकाधिकारी लाभ + आवस्मिक लाभ)

उपयुक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि लाभ की एक उचित एवं सर्वमान्य परिभाषा देना काफी कठिन है। लाभ की प्रकृति अन्य साधनों से भिन्न है अतः अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आय से कुछ भिन्नता रखता है।

- (१) लाभ उत्पादक भी हो सकता है यर्थात् साहसी की हानि भी प्राप्त हो सकती है जबकि अन्य साधनों की हानि प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं होती।
- (२) लाभ में अनिश्चिततायें रहती हैं तथा उतार चढ़ाव (fluctuation) अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक होते हैं। तेजी या मन्दो की स्थिति में मजदूरी, लगान या ब्याज में होने वाले परिवर्तनों की मर्यादा लाभ में परिवर्तन अधिक होते हैं।
- (३) लाभ अन्य साधनों की आय की तरह किसी समझौते पर आधारित नहीं होते जिनको कि पहले से ही निर्धारित कर लिया गया हो। लाभ अनिश्चित बना हुआ भाग है जो कि भूमि, श्रम व पूँजी के समझौते के आधार पर निश्चित आय प्रदान करने के बाद बचता है।

लाभ के सिद्धान्त (Theories of Profit)

लाभ निर्धारण के सिद्धान्त के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में प्रारम्भ से ही मतभेद रहे हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोणों के आधार पर लाभ सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इन विभिन्न सिद्धान्तों में विचारों की भिन्नताओं के साथ साथ अपूर्णताएँ भी हैं। लाभ का ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है जिसे सर्वमान्यता प्राप्त हो। लाभ निर्धारण के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं —

- ✓ १ लाभ का लगान सिद्धान्त (Rent theory of profit),
- ✓ २ लाभ का मजदूरी सिद्धान्त (Wage theory of profit),
- ✓ ३ लाभ का जोखिम सिद्धान्त (Risk theory of profit),

- ✓ ४ लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धान्त (Uncertainty bearing theory of profit) ,
- ✓ ५ लाभ का गतिशील सिद्धान्त (Dynamic theory of profit) ,
- ६ लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धान्त (Innovation theory of profit) ,
- ७ लाभ का समाजवादी सिद्धान्त (Socialist theory of profit) ,
- ✓ ८ लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धान्त (Marginal productivity theory of profit) ,

१ लाभ का लगान सिद्धान्त (Rent Theory of Profit)

लाभ के लगान सिद्धान्त का पूर्ण विकास वाकर (Walker) ने किया। इस सिद्धान्त के पूर्व ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे एस मिल और सीनियर ने इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। वाकर के अनुसार 'लाभ योग्यता का लगान है'। जिस प्रकार भूमि की विभिन्न श्रेणियों की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता पाई जाती है, उसी तरह वाकर ने बताया कि साहसिया की योग्यता में भी अंतर होता है। जो साहसी अधिक योग्य होता है वह कम योग्य साहसी की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करता है।

प्रो वाकर के शब्दों में—“जिस प्रकार लगानरहित भूमि होती है जिसकी उम्र केवल लागत को ही पूरा करती है, उसी प्रकार एक साहसी या लाभरहित कर्म होती है जिससे प्राप्त आय केवल उत्पादन लागत को पूरा करती है, और जिस प्रकार लगान यह आधिक्य है जो लगानरहित भूमि के ऊपर प्राप्त होता है, तथा मूल्य में सम्मिलित नहीं होता उसी प्रकार लाभ भी आधिक्य है जो कि सीमान्त फर्म के ऊपर प्राप्त होता है।”^५

इस प्रकार वाकर का सिद्धान्त रिगडों के लगान सिद्धान्त पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार साहसियों की योग्यता में अंतर होता है, और सीमान्त साहसी को लाभ प्राप्त नहीं होता जबकि श्रेष्ठ साहसियों को उनकी योग्यता के अनुसार लाभ प्राप्त होता है।

- 5 “Just as there is a no rent land whose produce just covers the price, so there is a no profit firm or entrepreneur whose income just covers the cost of production, and just as rent of a price of land is surplus above the no rent land and does not enter into price, as profit of a firm is surplus above the no profit firm”

—Walker

वाकर के अनुसार लाभ एक वस्तु है अतः वह सगुण के समान वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं करता बल्कि स्वयं मूल्य से प्रभावित होता है। यदि वस्तु का मूल्य अधिक है तो लाभ भी अधिक प्राप्त होगा यदि मूल्य कम है तो लाभ भी घट जायेगा।

लाभ और लगान में एक अन्तर है। लगान एक स्थायी आय है अतः अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में ही लगान रहता है। लाभ दीर्घकाल में द्रुम रहता है क्योंकि दीर्घकाल में साहसियों की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। साहसियों की पूर्ति में वृद्धि होने से उत्पादन बढ़गा परिणामस्वरूप मूल्य कम होगा और लाभ भी कम हो जायेगा। यह लाभ उस सीमा तक कम होते जायेंगे जब तक कि वे शून्य तक नहीं पहुँच जायेंगे। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। अपूर्ण प्रतियोगिता में साहसी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism)

वाकर के सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं —

- (१) यह सिद्धान्त लाभ और लगान में समानता स्थापित करता है जो कि गलत है। क्योंकि लगान हमेशा धनात्मक होता है या द्रुम होता है वह शून्यात्मक नहीं होता जबकि लाभ शून्यात्मक भी होता है।
- (२) यह सिद्धान्त लाभ निर्धारण में जोखिम और अनिश्चितता जैसे महत्वपूर्ण तत्वों का महत्व प्रदान नहीं करता। आलोचना के अनुसार लगान योग्यता का लगान नहीं है बल्कि जोखिम और अनिश्चितताओं का प्रतिफल है।
- (३) इस सिद्धान्त के अनुसार लाभ साहसी की योग्यता के कारण उत्पन्न होता है जबकि आलोचकों के अनुसार लाभ पर योग्यता के अतिरिक्त अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है जैसे एकाधिकार या साहसी की अनुकूल परिस्थितियों के कारण भी लाभ उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह सिद्धान्त लाभ के सभी कारणों की व्याख्या नहीं करता है।
- (४) लगान स्थिर व गतिशील दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है जबकि लाभ केवल गतिशील अवस्था में ही सम्भव है, क्योंकि लाभ उत्पन्न होने का कारण जोखिम और अनिश्चितता है।
- (५) इस सिद्धान्त की यह मायता ठीक नहीं है कि लाभ लागत में सम्मिलित नहीं रहता। आलोचकों के अनुसार सामान्य लाभ लागत का अंग है और लाभ में सम्मिलित रहता है।

- (६) आलोचकों के अनुसार यह सम्भव है कि व्यवहार में लगानरहित भूमि मिल जाय, परन्तु लाभरहित साहसी का पाया जाना सम्भव नहीं है। यदि साहसी को दीर्घ-काल में लाभ प्राप्त नहीं होता तो वह उस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में चला जायेगा।

2 लाभ का मजदूरी सिद्धान्त (Wage Theory of Profit)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रो टॉमिग (Prof Taussig) ने किया तथा इसका समर्थन डेवन्पोर्ट (Davenport) द्वारा किया गया है। प्रो टॉमिग के अनुसार लाभ एक प्रकार की मजदूरी है जो कि साहसी को उसके द्वारा प्रदत्त निरन्तर सेवाओं के बदले दिया जाता है।

प्रो टॉमिग के शब्दों में—'लाभ केवल सयोग से ही प्राप्त नहीं होता बल्कि यह विशेष प्रकार की योग्यता के प्रयोग का परिणाम है, एक प्रकार का मानसिक श्रम है जो कि कबीलों और न्यायाधीशों के श्रम से अधिक भिन्न नहीं होता।'^६

इस सिद्धान्त के अनुसार लाभ और मजदूरी में समानता है। इन दोनों में केवल यह अन्तर है कि श्रमिक को शारीरिक श्रम के बदले मजदूरी प्राप्त होती है जबकि लाभ साहसी को मानसिक श्रम के बदले प्राप्त होता है।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism)

इस सिद्धान्त की यह विशेषता है कि यह लाभ के औचित्य (justification) और स्वभाव पर प्रकाश डालता है, फिर भी इस सिद्धान्त में अनेक दाव हैं इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) यह सिद्धान्त लाभ और मजदूरी के अन्तरो पर ध्यान नहीं देता, जैसे—

(अ) साहसी का मुख्य कार्य जोखिमों और अनिश्चितताओं को वहन करना होता है जबकि मजदूरी या निश्चित वेतन प्राप्त करने का न किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनिश्चितता या जोखिम का साहसी के समान सामना नहीं करना पड़ता।

■ "Profits are not due to mere chance, they are the outcome of the exercise of special ability, a sort of mental labour not much different from the labour of lawyers and judges"

(ब) साहसी के लाभ में संयोग (chance) और अवसरों (opportunities) का अधिक महत्व होता है जबकि श्रमिक केवल अपने परिश्रम से ही मजदूरी में वृद्धि कर सकता है।

(२) यह सिद्धान्त इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाता कि संयुक्त पूँजी कंपनी में भागीदारों (shareholder's) को लाभ क्यों प्राप्त होता है, जबकि भागीदारों के द्वारा किसी प्रकार का धर्म नहीं किया जाता।

(३) लाभ नैतिक और दृश्य दोनों हो सकता है, जबकि मजदूरी कभी दृश्य नहीं होती।

३. लाभ का जोखिम सिद्धान्त (Risk Theory of Profit)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रो हॉले (Prof Hawley) द्वारा किया गया। मार्शल ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। प्रो हॉले के अनुसार 'लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है'। साहसी जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है, उसमें किसी व किसी प्रकार का जोखिम अवश्य रहता है। उत्पत्ति के अन्य साधनों का पुरस्कार निश्चित रहता है अर्थात् उत्पादन में लाभ हो या हानि, दूसरे साधनों को प्रतिफल अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है, परन्तु साहसी का प्रतिफल अनिश्चित रहता है। अतः कोई भी साहसी उसी अवस्था में उत्पादन कार्य करेगा जबकि उसे जोखिम का प्रतिफल प्राप्त हो।

हॉले के अनुसार—“किसी व्यवसाय का लाभ व्यवस्था या सम्पन्न का पुरस्कार नहीं है, बल्कि जोखिम तथा उत्तरदायित्व उठाने का पुरस्कार है जिसे उस व्यवसाय को चलाने वाला प्राप्त करता है।”

हॉले के मत में जोखिम उठाना साहसी का प्रमुख कार्य है। जहाँ पर जोखिम अधिक होता है, वहाँ लाभ अधिक होता है तथा कम जोखिम वाले व्यवसायों में लाभ कम होता है। जोखिम में भिन्नता के कारण ही विभिन्न व्यवसायों में लाभ भी भिन्न-भिन्न रहता है।

सिद्धान्त की बालोचना (Criticism)

हॉले के सिद्धान्त की प्रमुख बालोचनाएँ निम्नलिखित हैं —

१) प्रो माइट के अनुसार साहसी को लाभ सभी प्रकार के जोखिमों से प्राप्त नहीं

7 “The profit of an undertaking is not the reward for management or co-ordination, but for risks and responsibilities that the undertaker subjects himself to”
—Hawley

होता। लाभ केवल उन्ही जातिमों से प्राप्त होना है जो कि अनिश्चित और अज्ञात ह।

- (२) जालोचकों के अनुसार साहसी को लाभ प्राप्त होना का कारण जोखिम उठाना नहीं है बल्कि अपनी योग्यता और कुशलता से जोखिम को कम कर देना है।

जैसा कि बाबेंबर ने कहा है—“लाभ इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि जातिम उठाई जाती है बल्कि इसलिए प्राप्त होता है कि साहसी अपने बुद्धि वीर्य से अपने व्यवसाय के जोखिम को कम कर देता है।”

- (३) इस सिद्धांत की यह मान्यता गलत है कि लाभ और जोखिम का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। कभी कभी साहसी अपनी रचि के अनुसार उस व्यवसाय को भी अपना लेता है, जहां पर जोखिम अधिक होता है और लाभ कम।

- (४) जालोचकों के अनुसार जोखिम उठाना लाभ के अनेक कारणों में से एक है, जब कि यह सिद्धान्त जोखिम को ही लाभ का एकमात्र कारण मान लेता है।

४ लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धान्त (Uncertainty Bearing Theory of Profit)

लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धान्त का प्रतिपादन अमरीकी अर्थशास्त्री प्रो नाइट (Prof Knight) ने किया। नाइट ने बताया कि साहसी या उत्पादक को लाभ इसलिए प्राप्त होता है कि वह अनिश्चितता वहन करता है। प्रो नाइट न जोखिम का दो भाग मान बांटा है

(अ) ज्ञात जोखिम या बीमा योग्य जोखिम,

(ब) अज्ञात जोखिम या बीमा अयोग्य जोखिम।

ज्ञात जोखिम वह जोखिम है जिसका पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है अतः ऐसे जोखिम का पहले से ही बीमा कराया जा सकता है। इसलिए नाइट ने इसे बीमा योग्य जोखिम कहा है। नाइट के अनुसार इस प्रकार का जोखिम साहसी के लिए अनिश्चितता उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि जोखिम साहसी के स्थान पर बीमा कंपनियां को भेलना पड़ता है। अतः ज्ञात जोखिम लाभ उत्पन्न नहीं करता।

अज्ञात जोखिम वह जोखिम है जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अतः ऐसे जोखिम का पहले से बीमा भी नहीं कराया जा सकता। पूर्व में ही बीमा न होने

के कारण इसे बीमा अयोग्य जोखिम कहा जाता है। बीमा अयोग्य जोखिम या अज्ञात जोखिम को नाइट न अनिश्चितता कहा है। प्रो नाइट के अनुसार लाभ अज्ञात जोखिम के कारण ही उत्पन्न होना है। बीमा अयोग्य जोखिम या अज्ञात जोखिम आधुनिक व्यवसायो में निम्न प्रकार पाये जा सकते हैं —

- (१) नई फर्में उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करें तो पुरानी फर्मों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप उन पुरानी फर्मों के लाभ में कमी आ जायेगी।
- (२) यदि नई उत्पादन विधि का प्रयोग होन लगे या गई प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाय, तो कुछ फर्में इन नये तरीकों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पायी जिसके कारण उनको हानि उठानी पड़ती है।
- (३) यह सम्भव है सरकार वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित कर दे या उद्योग का ही अपने नियन्त्रण में ले ले।
- (४) समय-समय पर बाजार में मन्दी या तेजी की स्थिति आती रहती है, जिससे वस्तु के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और ये परिवर्तन लाभ को प्रभावित करते हैं। मन्दी की स्थिति में साहसी की हानि होने की सम्भावना रहती है।

इस प्रकार प्रो नाइट के अनुसार उपर्युक्त जोखिम वह जोखिम है जिनका पूरा बीमा किया जाना सम्भव नहीं है। प्रो नाइट लाभ और अनिश्चितता बहनों के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करते हैं, अर्थात् जितनी अधिक अनिश्चितता होगी उतना ही लाभ अधिक होगा। अतः इस सिद्धांत के अनुसार लाभ जोखिम का प्रतिफल न होकर अनिश्चितता बहन करने का प्रतिफल है।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism)

इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) इस सिद्धान्त के अनुसार अनिश्चितता बहन करना ही साहसी का एकमात्र कार्य है, जबकि साहसी को इसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य करने होते हैं, जैसे—संगठन करना, साधनों में संपन्न्य स्थापित करना, नव प्रवर्तन का कार्य करना आदि। इस प्रकार अनिश्चितता केवल लाभ उत्पन्न करने वाले कारणों में से एक है।
- (२) इस सिद्धान्त के अनुसार लाभ अनिश्चितता उत्पन्न का प्रत्यक्ष कारण है लेकिन आलोचकों के अनुसार कभी-कभी साहसी अनिश्चितता बहन करते हुए भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। इस स्थिति की व्याख्या यह सिद्धान्त नहीं करता।

- (३) यह सिद्धांत अनिश्चितता वहन को उत्पादन का एक प्रथम साधन मानता है अर्थात् व्यवहार में इस प्रकार का कोई साधन नहीं पाया जाता। आलोचकों के अनुसार यह उत्पादन का अन्त से कोई साधन नहीं है बरन साहसों की विशेषताओं को ही व्यक्त करता है।
- (४) आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत केवल आकस्मिक लाभ की ही व्याख्या करता है, शुद्ध लाभ की व्याख्या नहीं करता।

५. लाभ की गतिशील सिद्धांत (Dynamic Theory of Profit)

इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रो जे बी क्लार्क (Prof J B Clark) ने किया। प्रो क्लार्क के अनुसार 'लाभ विक्री मूल्य और लागत मूल्य का अन्तर है।' उन्होंने बताया कि लाभ केवल गतिशील अवस्था में ही सम्भव है, क्योंकि स्थिर अवस्था में न तो कोई जोड़िंग उठाना पड़ता है और न ही किसी प्रकार की अनिश्चितता रहती है। इस प्रकार क्लार्क के अनुसार लाभ परिवर्तनों का परिणाम है।

वास्तविकता यह है कि समाज गतिशील है, उसमें कुछ न-कुछ परिवर्तन अवश्य हो रहे हैं। प्रो क्लार्क के अनुसार समाज में पाँच प्रकार के परिवर्तन लगातार हो रहे हैं।

- (a) जनसंख्या के आकार में परिवर्तन,
- (b) पूँजी की पूर्ति में परिवर्तन,
- (c) उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन,
- (d) औद्योगिक संगठनों के रूपों में परिवर्तन,
- (e) मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन।

गतिशील समाज में उपर्युक्त परिवर्तन हाँते रहने के कारण ही लाभ उत्पन्न होता है। सामान्यतः ये परिवर्तन समाज में अपने आप ही हो रहे रहते हैं, लेकिन कभी-कभी ये परिवर्तन औद्योगिक संगठनों या व्यावसायिक कर्मों के द्वारा जान-बूझकर भी किये जाते हैं। इन परिवर्तनों से वस्तु की माँग और पूर्ति में परिवर्तन होता रहता है, जिससे लाभ उत्पन्न होता है।

स्थिर अवस्था में उपर्युक्त पाँचों प्रकार के परिवर्तनों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण अनिश्चितता और जातिम भी नहीं रहते। इनके अभाव में विनी मूल्य और लागत मूल्य का अन्तर समान हो जाता है, परिणामस्वरूप लाभ उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार क्लार्क के अनुसार लाभ के मूल्य के लिए समाज में गतिशीलता आवश्यक है।

सिद्धांत की आलोचना (Criticism) :

क्लाक के सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाये निम्नलिखित है :—

- (१) प्रो. नाइट ने बताया कि सभी प्रकार के परिवर्तन लाभ उत्पन्न नहीं करते । उन्होंने बताया कि लाभ केवल उन परिवर्तनों के परिणाम है जिनको पहले से ज्ञात नहीं किया जा सकता । अतः प्रो. नाइट के अनुसार लाभ अविद्यमानता के कारण उत्पन्न होते हैं ।
- (२) प्रो. टॉसिंग के अनुसार यह सिद्धांत प्रबन्धकों के वेतन और लाभ के बीच अनावश्यक और कृत्रिम भेद उत्पन्न करता है ।
- (३) आलोचकों के विचार में क्लार्क की आर्थिक गतिशीलता (economic dynamics) वास्तव में तुलनात्मक स्थिरता है । आर्थिक गतिशीलता से अभिप्राय निरन्तर होने वाले परिवर्तनों से होता है । किंतु प्रो. क्लार्क द्वारा व्यक्त गतिशीलता शीघ्र हो रुक जाती है, जिससे लाभ का सीप हो जाता है ।

६. लाभ का नव-प्रवर्तन सिद्धान्त (Innovation Theory of Profit) :

इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रो. शुम्पीटर (Schumpeter) ने किया । यह सिद्धांत प्रो. क्लार्क के सिद्धांत से मिलता-जुलता है, क्योंकि शुम्पीटर भी लाभ की गतिशील परिवर्तनों का कारण मानते हैं । लेकिन इन दोनों में एक भिन्नता है, क्लार्क गतिशीलता या परिवर्तनों की ही लाभ का कारण मानते हैं जबकि शुम्पीटर के अनुसार नव-प्रवर्तन के द्वारा लाभ उत्पन्न होते हैं, अर्थात् नये-नये आविष्कारों, वस्तु के विक्रय की नई रीतियों तथा वितरण की व्यवस्था आदि में परिवर्तन करने से लाभ उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार नव-प्रवर्तन सिद्धांत क्लार्क के गतिशील सिद्धांत से अधिक व्यापक है ।

नव-प्रवर्तन का उद्देश्य वस्तु की उत्पादन लागत में कमी कर देना है जिसके परिणाम-स्वरूप वस्तु के मूल्य और उसकी लागत में अन्तर हो जाता है, यह अन्तर ही लाभ होता है । इस प्रकार लाभ नव-प्रवर्तन का कारण और परिणाम दोनों है । क्योंकि लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही नव-प्रवर्तन निभे जाते हैं, अतः लाभ नव-प्रवर्तन को प्रभावित करता है ।

एक सफल नव प्रवर्तन से केवल अस्थायी रूप से ही लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जैसे ही दूसरी फर्मों इसका अनुकरण करती हैं तो उससे प्राप्त होने वाला लाभ समाप्त हो जाता है । इस प्रकार जब एक नये प्रयोग या आविष्कार से प्राप्त होने वाला लाभ रुक जाता है तो दूसरा प्रयोग किया जाता है और पुनः लाभ प्राप्त होने लगता है । शुम्पीटर के अनुसार लाभ प्राप्त होता है और समाप्त होता है और फिर प्राप्त होने लगता है । उन्होंने

वताया कि कोई भी आविष्कार, विचार या प्रयोग उस समय तक नव-प्रवर्तन नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसको व्यवहार में न अपना लिया जाय।

प्रो शुम्पीटर के अनुसार लाभ केवल उसी को प्राप्त होता है जो कि नव-प्रवर्तन का प्रयोग करता है। लाभ उसे प्राप्त नहीं होता जो कि नया विचार प्रस्तुत करता है, या आविष्कार करता है या नई व्यवस्था के लिए विभीषण सहायता प्रदान करता है।

प्रो क्लार्क की तरह शुम्पीटर का यह विचार है कि लाभ जोखिम का प्रतिफल नहीं है, क्योंकि साहसी जोखिम नहीं उठाना। जोखिम तो पूंजीपति को उठाना पड़ता है क्योंकि साहसी जिम उपक्रम के लिए पूंजी उधार लेता है, यदि वह असफल हो जाता है तो हानि पूंजीपति को होती है न कि साहसी को।

सिद्धांत की आलोचना (Criticism)

शुम्पीटर के सिद्धांत की आलोचनाएँ प्रायः वही हैं जो कि क्लार्क के गतिशील सिद्धांत की हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) यह सिद्धांत केवल नव प्रवर्तन को ही लाभ का कारण मानता है, दूसरे तत्वों को उपेक्षा करता है। यह बात सही है कि नव-प्रवर्तन लाभ को प्रभावित करता है, लेकिन यही लाभ का एकमात्र कारण नहीं है।
- (२) यह सिद्धांत लाभ के निर्धारण में जोखिम और अनिश्चितता जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा करता है। शुम्पीटर का यह विचार उचित नहीं कि जोखिम पूंजीपति उठाता है, साहसी नहीं। वास्तविकता इससे विपरीत है, अर्थात् पूंजीपति जोखिम नहीं उठाते अपितु साहसी जोखिम उठाता है।
- (३) यह सिद्धांत साहसी के कार्यों के प्रति सङ्कुचित दृष्टिकोण अपनाता है, क्योंकि साहसी का कार्य केवल नव-प्रवर्तन तक ही सीमित नहीं रहता। साहसी को इसके अतिरिक्त सङ्गठनात्मक कार्य भी करने होते हैं।

७ लाभ का समाजवादी सिद्धांत (Socialist Theory of Profit)

इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स (Karl Marks) ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार लाभ प्राप्त होने का कारण यह है कि उत्पादकों या पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है, वह उनके कार्य के अनुपात में बहुत कम होती है। इस प्रकार पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है, यह शोषण ही लाभ का कारण है।

मार्क्स के अनुसार वस्तु का मूल्य उसमें लगाये गये धन से निर्धारित होता है। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के प्रतिकूल और पुरस्कार (ज्यादा मजदूरी) को हटाय कर लिया जाता

है, जिससे उनको लाभ प्राप्त होता है। इस दृष्टि से समाजवादियों ने लाभ को 'कानूनी डाक' कहा है। मार्क्स ने बताया कि लाभ श्रमिकों के शोषण पर आधारित होने के कारण मानवीय और कानूनी दोनों ही दृष्टियों से अनुचित है, इसलिये इसे समाप्त कर देना चाहिए।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism)

मार्क्स के सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) यह सिद्धांत मार्क्स के मूल्य के श्रम सिद्धांत (labour theory of value) पर आधारित है, जो कि नेपल अप्रत्याशित लाभ के सम्बन्ध में ही उचित है, क्योंकि यह सिद्धांत साहसी के पुरस्कार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता।
- (२) इस सिद्धांत के अनुसार लाभ श्रमिकों के शोषण का परिणाम है। आलोचकों के अनुसार यह विचार उचित नहीं है, क्योंकि लाभ साहसी को जोखिम उठाने के कारण या अनिश्चितता सहन करने के कारण प्राप्त होता है।
- (३) आलोचकों के अनुसार पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवस्था में सभी श्रमिकों को समान मजदूरी का भुगतान किया जाता है। यदि अल्पकाल में साहसी को हानि प्राप्त होती है, उस स्थिति में भी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पहले वाली दरों पर किया जाता है।

मार्क्स का सिद्धांत यद्यपि आज के समार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, फिर भी यह लाभ के निर्धारण की समस्या को पूर्णतः हल नहीं कर सका है।

घ. लाभ का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory of Profit) :

इस सिद्धांत के अनुसार लाभ साहसी की उत्पादकता के द्वारा निर्धारित होता है। साहसी चूक उत्पत्ति का एक साधन है इसलिये इस साधन का हिस्सा भी उत्पत्ति के दूसरे साधनों के समान ही इसकी सीमान्त उत्पादकता (या सीमान्त आयम उत्पादकता—MRP) के द्वारा निर्धारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार साहसी की सीमान्त उत्पादकता जिनो अधिक होगी, उतना ही लाभ अधिक होगा। दूसरे शब्दों में, सामान्यतः जिन उद्योगों में साहसी की पूर्ति कम होती है, वहां साहसी की सीमान्त उत्पादकता अधिक होने के कारण लाभ अधिक प्राप्त होता है तथा जिन उद्योगों में साहसी की पूर्ति अधिक होती है, साहसी की सीमान्त उत्पादकता कम होने के कारण लाभ भी कम प्राप्त होता है।

सिद्धांत की आलोचना (Criticism)

सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत को प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं —

- (१) यह सिद्धांत पूर्ण नहीं है, क्योंकि लाभ निर्धारण की केवल माग पक्ष से ही व्याख्या करता है, पूर्ति पक्ष की उपेक्षा करता है।
- (२) साहसी की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना अत्यन्त कठिन है। एक फर्म या व्यवसाय में साहसी केवल एक ही होता है अतः उसकी सीमांत उत्पादकता ज्ञात नहीं की जा सकती। यदि हम सैद्धांतिक दृष्टि से इसे स्वीकार भी कर लें, तो फर्म या व्यवसाय में एक और साहसी लगाना होगा, जबकि व्यवहार में साहसी समान रूप से कुशल नहीं होते।
- (३) यह सिद्धांत आकस्मिक लाभों की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार के लाभों का साहसी की सीमांत उत्पादकता से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

उपर्युक्त सभी सिद्धांतों का अध्ययन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि इनमें कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिस पूरे सिद्धांत या सतोपपन्न सिद्धांत कहा जा सके। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से लाभ की व्याख्या की है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लाभ निर्धारण के लिये माग और पूर्ति सिद्धांत की ही सर्वश्रेष्ठ माना है। उनके अनुसार जिस प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधनों का पुरस्कार उस साधन की माग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, ठीक उसी प्रकार साहसी का पुरस्कार साहसी की माग और पूर्ति के द्वारा निश्चित होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लाभ निर्धारण में सामान्य लाभ को ही प्रमुखता प्रदान की है।

सामान्य लाभ का निर्धारण (Determination of Normal Profit)

इसे लाभ का माग और पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। आधुनिक विश्व में लगातार परिवर्तन होत रहते हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पकाल व दीर्घकाल में अनिश्चितता बनी रहती है। अनिश्चितता होने के कारण यह आवश्यक है कि साहसी को उत्पादन कार्य में बनावे रखने के लिये न्यूनतम पुरस्कार प्राप्त हो। यह न्यूनतम पुरस्कार ही सामान्य लाभ है।

“सामान्य लाभ शुद्ध लाभ का ही एक अंग है जिसको साहसी प्राप्त करना चाहता है। यह अनिश्चितता वहन करने का कम न होने या न्यूनतम पुरस्कार है जो कि

एक निश्चित समयावधि में साहसियों को उद्योग विधेय में बनाये रखने के लिए आवश्यक है।^९

यदि साहसी को उद्योग विधेय में सामान्य लाभ भी प्राप्त नहीं होता है तो वह दूसरे उद्योग या व्यवसाय में चला जायेगा। यह सम्भव है कि अल्पकाल में साहसियों को सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्राप्त हो, परन्तु दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है।

जिस प्रकार अन्य साधनों का हिस्सा (पुरस्कार) उस साधन की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्दिष्ट होता है उसी प्रकार साहसी का लाभ भी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्दिष्ट होता है।

साहसी की मांग

साहसी की मांग उसकी सीमात उत्पादकता के कारण की जाती है। सीमात आगम उत्पादकता अधिक होने पर साहसियों की मांग अधिक होती है तथा कम होने पर मांग कम। साहसी की मांग सीमात उत्पादकता के अतिरिक्त औद्योगिक विकास का स्तर, जोखिम की मात्रा आदि से प्रभावित होती है। परन्तु इनका प्रभाव मांग पर परोक्ष रूप से ही पड़ता है।

अन्य साधनों की अपेक्षा साहसी की सीमात उत्पादकता (या सीमात आगम उत्पादकता) का पता लगाना काफी कठिन है क्योंकि एक कम में केवल एक ही साहसी रहता है। इस समस्या को हल करने के लिये साहसी की सीमात उत्पादकता का एक कम के सदर्भ में विचार न करके सम्पूर्ण उद्योग के सदर्भ में विचार करते हैं।

एक उद्योग विधेय में जितनी कमियाँ होती हैं उतने ही साहसी होने हैं। उद्योग में कमियों की संख्या में वृद्धि होने से कमियों को प्राप्त होने वाले लाभ में कमो आ जायेगी, (क्योंकि कमियों की संख्या में वृद्धि से उत्पादन बढ़ेगा जिससे नम्बु की कीमत घटेगी), अतः कमियों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप साहसियों की सीमात उत्पादकता कम होगी आनी है। अतः सीमात आगम उत्पादकता रेखा (MRP) बायें से दायें नीचे की ओर गिरती हुई होती है। यदि सभी उद्योगों के साहसियों की सीमात आगम उत्पादकता रेखाओं को जोड़ लिया जाय, तो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये साहसियों की मांग ज्ञान की जा सकती है।

9 "Normal profits is that part of pure profits, which is expected by entrepreneur. It is an irreducible minimum reward for uncertainty bearing, which entrepreneurs will require over a period of time, to induce them to stay in a particular industry."

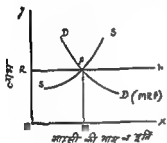
साहसी की पूर्ति

साहसी की पूर्ति कई तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे— समाज की दशा, जनसंख्या का आकार, व्यवसाय में जोखिम की मात्रा आदि ।

सामान्य लाभ साहसी का पूर्ति मुख्य है । अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता को वहन करने के लिये साहसी की पूर्ति बनाये रखने के उद्देश्य से कम से कम सामान्य लाभ के बराबर साहसी को पुरस्कार देना आवश्यक है । सामान्यतः यदि अर्थव्यवस्था में लाभ की दर ऊँची है तो साहसियों की पूर्ति अधिक होगी, यदि लाभ दर नीची है तो पूर्ति कम होगी । इस प्रकार लाभ दर और साहसी की पूर्ति का सम्बन्ध सीधा होता है, इसलिये सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए साहसी की पूर्ति रेखा बायें से दायें ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है ।

सामान्य लाभ का निर्धारण (Determination of Normal Profit)

पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्य लाभ का



निर्धारण उस बिन्दु पर होगा, जहाँ पर साहसियों की माग रेखा तथा पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती हैं । इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

समान चित्र में DD सीमान्त आगम उत्पादकता रेखा है तथा SS पूर्ति रेखा है । दोनों रेखायें एक-दूसरे को P बिन्दु पर काटती हैं, अतः सामान्य लाभ PM होगा और साहसियों की माग तथा पूर्ति OM । सामान्य लाभ को RN रेखा

द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक उद्योग सामान्य लाभ के इस स्तर को प्राप्त करेगा ।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- सामान्य लाभ तथा अतिरिक्त लाभ में अन्तर बनाइए । क्या साहसी का पुरस्कार उत्पादन लागत में प्रवेश करता है ?
- “लाभ का सिद्धांत अर्थशास्त्र का सबसे अधिक विवादग्रस्त एवं असंतोषजनक सिद्धांत है ।” व्याख्या कीजिये ।
- प्रो क्लार्क के लाभ के गतिशील सिद्धांत की व्याख्या कीजिये ।
- “लाभ का आधुनिक सिद्धांत उत्पादन प्रक्रिया में साहसी का वह योगदान बताता है

कि वह बोमा अयोग्य जोखिमो तथा अनिश्चितताओ को सहन करता है ।" विवेचना कीजिए ।

५. कुल लाभ एवं शुद्ध लाभ में अन्तर बताइए । लाभ के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।

६. लाभ के विभिन्न सिद्धान्तों को समझाइए । इनमें कौनसा सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ है ? कारण बताइए ।

७. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए —

(a) "लाभ योग्यता का लक्षण है ।"

(b) लाभ "कनूनी डाका" है ।

(c) लाभ गतिशील समाज में पाया जाता है, स्थिर समाज में समाप्त हो जाता है ।

८. 'लाभ का वही सिद्धान्त सत्य है जिसमें लाभ के यतिशोल सिद्धान्त और जोखिम के सिद्धान्त का सामंजस्य हो ।' इस कथन की व्याख्या कीजिए ।

द्वितीय खण्ड

व्यापक-अर्थशास्त्र

[Macro Economics]

अध्याय १

★

स्थिर एवं गतिशील अर्थशास्त्र

[Static and Dynamic Economics]

★ ★ ★

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्थिर (static) और गतिशील (dynamic) शब्दों का प्रयोग

बहुत अधिक होने लगा है। इन शब्दों के महत्व में वृद्धि के कारण ही अर्थशास्त्र को अब दो भागों—स्थिर अर्थशास्त्र एवं गतिशील अर्थशास्त्र—में बाटा जाने लगा है। लेकिन अर्थशास्त्रियों में इन दोनों शब्दों के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में काफी मतभेद पाया जाता है। स्थिर एवं गतिशील अर्थशास्त्र का उचित एवं सही स्पष्टीकरण न होने के कारण ही प्रो नाइट (Prof Knight) ने कहा है :

“स्थिर और गतिशील जैसे दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों के प्रयोग से व्यर्थ का भ्रम उत्पन्न हो गया है।”^१

परन्तु अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री प्रो. नाइट के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और वे अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को स्थिर एवं गतिशील दो भागों में विभाजित करना उचित समझते हैं, तथा इस प्रकार के अध्ययन को अर्थशास्त्र के विकास के लिए उपयोगी समझते हैं। जैसा कि प्रो हारोड (Harrod) के विचार से स्पष्ट है

‘स्थिर और गतिशील अर्थशास्त्र के बीच विभाजन की सही रेखा बनाने से आर्थिक विचारों की प्रगति को सहायता प्राप्त होती है।’^२

स्थिर या स्थैतिक अर्थशास्त्र Static Economics)

स्थिर अर्थशास्त्र का अर्थ (Meaning of static economics)—भौतिकशास्त्र में

- 1 “Needless confusion has been caused by the unfortunate use of the terms “Static and Dynamic” — Prof Knight
- 2 “The correct charting of a line of demarcation between them should have beneficial result on the progress of economics” — Prof Harrod

स्थिर शब्द गतिहीनता अथवा विकाय (rest) की अवस्था के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थशास्त्र में स्थिर शब्द से अभिप्राय गतिहीन या मृत अवस्था से नहीं होता, अपितु उस अवस्था से होता है जिसमें गति तो रहती है परन्तु यह गति निश्चित, नियमित और शांतिपूर्ण रहती है। दूसरे शब्दों में, स्थिर अवस्था में गति तो रहती है परन्तु अचानक झटके नहीं लगते अर्थात् इसमें अनिश्चितता का अभाव रहता है। प्रो हारोड (Prof Harrod) ने स्थिर अवस्था को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है

“स्थिर साम्प्र से अर्थ विज्ञान की अवस्था से नहीं होता, वरन् उस अवस्था से होता है जिसमें दिन-प्रतिदिन और वर्ष-प्रतिवर्ष कार्य निरन्तर हो रहा हो, परन्तु उसमें कमी या वृद्धि न हो रही हो। इस सक्रिय किन्तु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को ही स्थिर अवस्था कहा जा सकता है।”³

स्थिर अर्थशास्त्र के अर्थ के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है, अतः सही अर्थ समझने के लिए इन विभिन्न दृष्टिकोणों का समझना आवश्यक है।

डॉ माशॉल (Dr Marshall) ने स्थिर अवस्था के लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखा है

“स्थिर अवस्था में सभी महत्वपूर्ण लक्षण ऐसे स्थान पर दृष्टिगोचर होत हैं जहां जनसंख्या और धन दोनों में वृद्धि हो रही हो तथा दोनों में वृद्धि की दर समान हो, और जहां पर भूमि की कोई कमी नहीं होती। उत्पत्ति की विधियों और दशाओं में बहुत कम परिवर्तन होता है तथा जहां मनुष्य का चरित्र स्वयं स्थिर रहता है।”⁴

प्रो पीगू (Pigou) के शब्दों में—“जिन वृद्धों से निश्चय भरना घनता है वे सदा बदलती रहती हैं, किन्तु भरने का रूप अपरिवर्तित रहता है। इसी प्रकार स्थिरता की अवस्था में परिवर्तन तो होते रहते हैं परन्तु ये परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।”

इस प्रकार पीगू के अनुसार स्थिर अवस्था में समग्र रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि छोटे-छोटे तत्व बदलत रहते हैं। प्रो मैकफार्ड (Prof Macfie) ने स्थिर अर्थ अवस्था की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में की है

“स्थिर अवस्था एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें वह साधन जो उपभोग, उत्पादन विभिन्न और वितरण पर नियंत्रण करते हैं, स्थिर हो या स्थिर मान लिये गये हों।

3 “Thus a static equilibrium by no means implies a state of idleness, but one in which the work is steadily going forward day-by-day and year-by-year, but without increase or diminution ... that it is to this active but unchanging process that the expression static economics should be applied” —Prof Harrod

जनसंख्या में न तो वृद्धि होती है और न कमी तथा आय समूहों (age groups) में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन के तरीके और कुल उत्पादन भी समान रहता है, और यदि जनसंख्या बढ़ती है तो कुल उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है।¹¹⁴

प्रो. हिक्स (Prof Hicks) के अनुसार आर्थिक सिद्धान्त के वे भाग स्थिर हैं जिनमें तिथि (dating) का ध्यान नहीं रखते।¹¹⁵

प्रो. हैरोल्ड के तिथिकरण (dating) के इस विचार से प्रो. हिक्स ने असहमति व्यक्त इसके अतिरिक्त टिनबर्गेन (Tinbergen), स्टिग्लर (Stigler), कीन्स (Keynes) तथा क्लार्क (J. B. Clark) आदि अर्थशास्त्रियों ने स्थिर अर्थव्यवस्था के आधार पर अध्ययन किया है तथा इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

प्रो. जे. के. मेहता ने स्थिर अर्थशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं :—

- (१) इस अवस्था में लाभ का घन शून्य होता है।
- (२) उत्पादन की इकाइयों में विस्तार या संकुचन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती।
- (३) अर्थव्यवस्था में विकास या ह्रास की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती।
- (४) साम्य एक निश्चित अवधि के आगे तक विस्तृत रहता है।

गतिशील या ग्रांथेगिक अर्थशास्त्र

(Dynamic Economics)

गतिशील अर्थशास्त्र का अर्थ (Meaning of Dynamic Economics)

- 4 "Nearly all the distinctive features of a stationary state may be exhibited in a place where population and wealth are both growing, provided they are growing at about the same rate and there is no scarcity of land, provided also, the methods of production and the conditions change very little, and above all, where the character of man himself is a constant quantity" —Marshall
- 5 "The stationary state is an economic system in which the factors which control production and consumption, distribution and exchange are constant, or assumed to be constant. Population is regarded as neither increasing nor decreasing and its age composition does not alter. Methods of production and the total output remain the same, or at least if population grows, total output must be regarded as growing at the same rate" —Prof Macfie

गतिशास्त्र में 'गतिशील' से अभिप्राय परिवर्तन की दर से होता है, अर्थशास्त्र में भी गतिशीलता से अभिप्राय उत्पादन की दर और मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से है। इस प्रकार गतिशील अर्थशास्त्र में अर्थ-व्यवस्था में होने वाले निरन्तर परिवर्तनों, इन परिवर्तनों की प्रक्रियाओं तथा परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। गतिशील अर्थशास्त्र की परिभाषा के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद नहीं है। कुछ परिभाषायें निम्नलिखित हैं —

✓ प्रो हिक्स (Prof Hicks) के अनुसार — “गतिशील अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धान्त के उस भाग से सम्बन्धित है जिसमें कि तिथिकरण महत्वपूर्ण है।”⁷

इस प्रकार प्रो हिक्स ने तिथिकरण (समय तत्त्व) का विशेष महत्व दिया है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि प्रो हिक्स ने तिथिकरण (dating) से सम्बन्ध स्थापित कर गतिशील अर्थशास्त्र के क्षेत्र को काफी विस्तृत कर दिया है।

• प्रो हेरोड (Prof Harrod) के अनुसार “गतिशील अर्थशास्त्र का सम्बन्ध विशेष रूप से निरन्तर परिवर्तन के प्रभावों और निर्दिष्ट किये जाने वाले मूल्यों की परिवर्तन की दर से होता है।”⁸

• मि बौमोल (Mr Baumol) के शब्दों में — “आर्थिक गतिशीलता भूतकालीन और भविष्य की घटनाओं से सम्बन्धित आर्थिक तथ्यों का अध्ययन है।”⁹

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि गतिशील अर्थशास्त्र अर्थ व्यवस्था में होने वाले निरन्तर परिवर्तनों, उन परिवर्तनों की दरों और उनके प्रभाव व कारणों का अध्ययन करना है। जे बी क्लार्क (J B Clark) ने गतिशील अर्थ व्यवस्था की पाँच विशेषताएँ बताई हैं —

- (१) जनसंख्या में वृद्धि होती है,
- (२) पूँजी की मात्रा में वृद्धि होती है,
- (३) उत्पादन की विधियों में सुधार हो रहा होता है,

7 “Economic dynamic refers to those parts of economic theory where the problem of ‘dating’ is conspicuously important”

—Prof Hicks

8 “Dynamics will specially be concerned with the effects of continuing changes and with rates of changes in the values that have to be determined”

—Prof Harrod

9 “Economic dynamics is the study of economic phenomena in relation to preceeding and succeeding events”

—Baumol

(४) औद्योगिक संस्थाओं (Industrial establishments) के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा होता है अर्थात् अकुशल इकाइयों के स्थान पर कुशल इकाइयों का अस्तित्व कायम होता है ।

(५) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है ।

प्रो क्लार्क का विचार है कि जिस अर्थ व्यवस्था में इन विशेषताओं का अभाव हो वह गतिशील अर्थ-व्यवस्था न होकर स्थिर होगी ।

स्थिर तथा गतिशील अर्थशास्त्र में अन्तर .

उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन कर लेने के उपरान्त इन दोनों का अन्तर समझ लेना भी आवश्यक है ।

स्थिर अर्थशास्त्र का सम्बन्ध किसी-समय विशेष की स्थिति से होता है, जबकि गतिशील अर्थशास्त्र का सम्बन्ध समयावधि-से होता है । स्थिर अर्थशास्त्र में कम तथा समय का कोई महत्त्व नहीं होता जबकि गतिशील अर्थशास्त्र में कम और समय का अन्तर महत्त्वपूर्ण होता है । गतिशील अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में होने वाले निरन्तर परिवर्तनों से सम्बन्धित होता है, जिसमें जनसंख्या, पूँजी, उत्पादन की विधि, उपभोक्ता की मांग तथा औद्योगिक इकाइयाँ सभी परिवर्तित होती रहती हैं, जबकि स्थिर अर्थशास्त्र में ये सभी तत्व निरन्तर परिवर्तन की अवस्था में नहीं होते ।

प्रो. जे. के. मेहता ने दोनों का अन्तर बताते हुए कहा है कि स्थिर अवस्था वह है जो कि निश्चित समय के बाद भी उसी क्रम में बनी रहती है जबकि गतिशील अवस्था में समय के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता रहता है ।

प्रो हिक्स के शब्दों में—“स्थिर अर्थशास्त्र वह है जहाँ तिथिकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती परन्तु गतिशील अर्थशास्त्र में तिथिकरण अत्यन्त आवश्यक है ।”

स्थिर अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्त्व (Scope and Importance of Static Economics) :

स्थिर शब्द से सम्बन्धित मान्यताओं से इसके प्रयोग क्षेत्र की काफी सीमा तक सीमित कर दिया है, किन्तु अर्थशास्त्र की बहुत-सी विषय-सामग्री का अध्ययन केवल स्थिर विश्लेषण के आधार पर ही किया जा सकता है । टिनबर्गेन (Tinbergen) का विचार है कि जो बातें दीर्घ कालीन प्रवृत्तियों से सम्बन्धित होती हैं तथा जिनमें वस्तुस्थिति अपरिवर्तनीय रहती है उनका अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र के द्वारा ही किया जाना सम्भव है । इस विश्लेषण का महत्त्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जायेगा ।

१ अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा भाग स्थिर विश्लेषण पर आधारित है। इनमें से प्रमुख समस्याएँ व विश्लेषण इस प्रकार है—

- (१) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार (free trade) का सिद्धांत स्थिर विश्लेषण पर ही आधारित है।
- (२) प्रो रॉबिन्स (Prof Robbins) द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा स्थिर अर्थशास्त्र पर ही आधारित है।
- (३) मूल्य-निर्धारण में औसत लागत की अवस्था सीमान्त लागत से अधिक सहायक की जाती है। सीमांत लागत का अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र के अन्तर्गत ही होता है।
- (४) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है जबकि यह सिद्धांत विभिन्न देशों के साधनों की गतिशीलता पर आधारित है।
- (५) तुलनात्मक लागत का सिद्धांत एक चरण का सिद्धांत आदि, जिनमें समय का अधिक महत्त्व नहीं है, स्थिर अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आते हैं।
- (६) व्यापार चक्र (trade cycles) का सिद्धांत 'स्थिर' तथा 'गतिशील' दोनों की सीमाओं पर स्थित है। इसके कुछ सिद्धांत स्थिर अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आते हैं और कुछ गतिशील अर्थशास्त्र में।

२ परिवर्तनशील अध्ययन-वस्था के अध्ययन के लिए आवश्यक—यदि स्थिर अर्थशास्त्र की सहायता न ली जाय तो परिवर्तनशील अध्ययन-वस्था का अध्ययन करने में अनेक जटिलताएँ आ जायेंगी। आर्थिक परिवर्तनों की प्रवृत्ति काफी जटिल होती है अतः परिवर्तनशील अध्ययन-वस्था का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिये उसे छोटी छोटी स्थिर अवस्थाओं में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसा करने से अध्ययन काफी सुविधाजनक हो जाता है। इस प्रकार स्थिर अवस्था गतिशील अवस्था की एक दशा बन जाती है। इस सम्बन्ध में प्रो मेहता का कथन उल्लेखनीय है—

“गतिशील अर्थशास्त्र स्थिर अर्थशास्त्र पर एक लगातार टीका (running commentary) है इसलिये स्थिर अर्थशास्त्र के नियम गतिशील अर्थशास्त्र पर लागू होने चाहिए।”^{१०}

10 “Dynamic economics is, as it was a running commentary on static economics. The laws of static economics must, therefore, apply to dynamics.”
—Prof. Mehta

दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि स्थिर अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का सरलीकरण प्रस्तुत कर देता है।

स्थिर अर्थशास्त्र की सीमाएँ (Limitation of Static Economics)

स्थिर अर्थशास्त्र का व्यापक महत्व है फिर भी यह विश्लेषण एक सीमा तक आर्थिक समस्याओं के मुल्यज्ञान में सहायक सिद्ध होता है। इसके सीमित प्रयोग के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

- (१) **अवास्तविक मान्यता पर आधारित**—यह विश्लेषण अवास्तविक मान्यताओं, जैसे—पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रतिबोधिता आदि पर आधारित है, जबकि व्यावहारिक जगत में ये मान्यताएँ नहीं पाई जाती हैं।
- (२) **परिवर्तनशील तत्वों को स्थिर मान लेना**—यह विश्लेषण आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्वों को स्थिर मान लेता है, जैसे—रचि, साधन, प्रविधि (technology) आदि। जबकि वास्तविक जीवन में ये निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं।
- (३) **स्थिर अवस्था का स्थानिक है**—वास्तविक संसार जो कि गतिशील और परिवर्तनशील है, उसको स्थिर मानना केवल भ्रम उत्पन्न करता है। इसी कारण कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने इसे सैद्धांतिक कल्पना कहा है। एजवर्थ (Edgeworth) के शब्दों में:—“परिवर्तनशील को स्थिर मान लेने के कारण अर्थशास्त्र में अनेक भ्रम उत्पन्न हो गये हैं।”^{११}

प्रो. हिक्स ने भी स्थिर अवस्था को महत्व प्रदान नहीं किया है। उनका विचार है कि वास्तविक समस्याओं के समाधान में स्थिर विश्लेषण का प्रयोग बहुत सीमित रूप में ही किया जा सकता है। उन्हीं के शब्दों में—

✓ “स्थिर अवस्था अन्त में और कुछ नहीं बरन् वास्तविकता से दूर जाना है।”

गतिशील अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व (Scope and Importance of Dynamic Economics)

गतिशील अर्थशास्त्र वास्तविक जीवन की परिवर्तनशील आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिये परम आवश्यक है। स्थिर अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी विचार गतिशील अर्थ-व्यवस्था

11 “The treating as constant of what is variable is the source of most of the follies in political economy.” —Edgeworth

क विचार की अवस्था काफी पुराने हैं, फिर भी पुराने अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में 'गतिशीलता' से सम्बन्धित अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। रिकार्डों की 'विनरण की समस्या' और माल्थस का 'जनन-रथा का सिद्धान्त' गतिशील दृष्टिकोण पर ही आधारित हैं। परन्तु मासल व उसके सहायियों ने (नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने) स्थिर अर्थशास्त्र को अपनाया। इस प्रकार स्थिर दृष्टिकोण का महत्व प्रगट हुआ।

गतिशील अर्थशास्त्र का वास्तविक प्रयोग प्रो. मार्जॉन के बाद ही हुआ। गतिशील अर्थशास्त्र को प्रो. रॉस (Prof. Ross), प्रो. कालेकि (Kalecki) और टिनबर्गेन (Tinbergen) आदि अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न किया। तत्पश्चात् हेरोड, रॉबर्टसन (Robertson) हैनसन (Hansan) आदि अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रयोग कर गतिशील विश्लेषण के महत्व में वृद्धि की। अधिकांश आधुनिक शास्त्री गतिशील विश्लेषण प्राथमिकता प्रदान करते हैं।

गतिशील अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है —

- १ गतिशील अर्थशास्त्र वास्तविकता के अधिक समीप है—गतिशील अर्थशास्त्र के वास्तविकता के समीप होने के दो कारण हैं —
 - (१) यह विश्लेषण अवास्तविक मान्यताओं, जैसे—पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रतिवागिता आदि पर आधारित नहीं है।
 - (२) यह आर्थिक व्यवहार के निर्धारक तत्वों, जैसे—दिवि, सामना व प्रविधि को अपरिवर्तनशील नहीं मानता।
- २ बहुत सी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन केवल गतिशील अर्थशास्त्र में ही सम्भव है—आधुनिक आर्थिक समस्याएँ जो मनोविज्ञान पर आधारित हैं उनका सरलता से अध्ययन गतिशील अर्थशास्त्र में ही किया जा सकता है—
 - (a) निरन्तर परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याओं का अध्ययन गतिशील अर्थशास्त्र में ही सम्भव है।
 - (b) व्यापार चक्र जैसी उच्च समस्याओं का अध्ययन पूर्ण तथ्यों के साथ गतिशील अर्थशास्त्र ही प्रस्तुत करता है।
- ३ गतिशील विश्लेषण लचीला (flexible) है—गतिशील अर्थशास्त्र अपनी धारणा में अत्यन्त लचीला है। इसके कारण अर्थशास्त्री सभी प्रकार की सम्भावनाओं की जाँच के लिए अर्थिक से अधिक नमून चुन सकता है और समस्याओं का विश्लेषण कर सकता है।

प्रो. रॉबिन्स (Robbins) ने गतिशील अर्थशास्त्र के चार महत्वपूर्ण कारण बताये हैं—

- (१) यह बहुत से आर्थिक सिद्धांतों की सत्यता और त्रियाशीलता को जांच करता है ।
- (२) यह स्थिर अर्थशास्त्र की बवास्तविक मान्यताओं को अलग करता है और ठोस तथा वास्तविक मान्यताओं प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर अध्ययन किया जाता है ।
- (३) यह उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है जहां पर कि स्थिर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में सुधार किया जाना चाहिए ।
- (४) यह नवीन तत्वों पर प्रकाश डालता है ।

गतिशील अर्थशास्त्र की सीमाएँ (Limitations of Dynamic Economics)

गतिशील अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी तथा आवश्यक है । लेकिन इसमें जटिलता होने के कारण इसकी अनेक सीमाएँ हैं ।

- (१) इस विश्लेषण का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हो पाया है जिसके कारण इसके प्रयोग में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं ।
- (२) गतिशील अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिये उच्च गणित तथा इकोनोमेट्रिक्स (Econometrics) का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है । इस कारण यह विश्लेषण काफी कठिन हो जाता है, और सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर है ।
- (३) वास्तविक जगत में परिवर्तन काफी तेजी से होते हैं जब समस्याओं का अध्ययन शुद्ध गतिशील दृष्टिकोण से करना काफी कठिन हो जाता है ।

गतिशील अर्थशास्त्र की जटिलताओं के कारण ही अनेक अर्थशास्त्रियों ने स्थिर अर्थशास्त्र का पक्ष प्रस्तुत किया है । जैसा कि प्रो लर्नर (Prof Lerner) का विचार है

“जब हम स्थिर अर्थशास्त्र को छोड़ देते हैं तो आर्थिक समस्याएँ अस्पष्ट प्रतीत होने लगती हैं ।”^{१२}

परन्तु इस दृष्टिकोण से गतिशील अर्थशास्त्र के महत्व में कोई कमी नहीं आती है ।

12 “When we leave the stationary economy (static economics) thing (economic problems) become somewhat less neat”

निष्कर्ष (Conclusion)

उपपुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दोनों ही विश्लेषणों की कुछ सीमाएँ हैं तथा दोनों ही विश्लेषण अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिये किसी भी विश्लेषण को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अनेक आर्थिक समस्याएँ ऐसी हैं जिनका अध्ययन केवल स्थिर अर्थशास्त्र द्वारा ही हो सकता है तथा कुछ ऐसी भी आर्थिक समस्याएँ हैं जिनका समाधान केवल गतिशील अर्थशास्त्र में ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त वास्तविक जगत में कुछ ऐसी भी आर्थिक समस्याएँ हैं जिनका संश्लेषणक समाधान किसी एक के द्वारा सम्भव नहीं है बल्कि दोनों—स्थिर व गतिशील—की आवश्यकता होगी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में दोनों ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ स्थिर व गतिशील अर्थशास्त्र की परिभाषा कीजिये। दोनों के गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए।
- २ स्थिर व गतिशील विश्लेषण के विचार की व्याख्या कीजिए तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन में गतिशील विश्लेषण के महत्व को समझाइए।
- ३ स्थिर और गतिशील अर्थशास्त्र में क्या अन्तर है? स्थिर अर्थशास्त्र की उपयोगिता क्या है?
- ४ स्थिर व गतिशील अर्थशास्त्र की उपयोगिता एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए। इनमें से कौन सी प्रणाली अधिक सामान्य और मौलिक है?
- ५ 'स्थिर व गतिशील दोनों ही विश्लेषण अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं।' व्याख्या कीजिए।



अध्याय २

★

राष्ट्रीय आय [National Income]

★ ★ ★

राष्ट्रीय आय का विचार अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने विचार प्रस्तुत किये, परन्तु उनका विचार अस्पष्ट था। बीसवीं शताब्दी में इस विचार को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट रूप में प्रयुक्त कर वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। साम्प्रतिक राष्ट्रीय आय से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा से है जो कि एक वर्ष में किसी राष्ट्र में उत्पादित की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में मशीनों की घिसावट को घटा दिया जाता है।

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं लेकिन हम केवल प्रो माशल, प्रो पीगू (Prof Pigou) तथा प्रो फिशर (Prof Fisher) द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

मार्शल की परिभाषा (Definition of Prof Marshall)

प्रो मार्शल ने अपनी प्रस्तुत 'Principles of Economics' में राष्ट्रीय लाभार्थ या राष्ट्रीय आय की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी है

“किसी देश की पूँजी एवं श्रम का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सेवाओं का एक शुद्ध योग (net aggregate) उत्पन्न करते हैं। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध आय, या आमय या राष्ट्रीय लाभार्थ है।”¹

- 1 “The labour and capital of the country, acting on its natural resources, produce annually a certain net aggregate of some commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is true net annual income, or revenue of the country, or the national dividend”
—Marshall

माशल के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर हो की जाती है। उनके अनुसार देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के योग में से घिसावट व्यय आदि घटा दन के बाद राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए —

- (१) राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जानी चाहिए।
- (२) राष्ट्रीय आय की गणना करने समय कुल उत्पादन में से मशीनों की घिसावट तथा टूट फूट व्यय निचाल देना चाहिए।
- (३) विदेशों में किये गये विनियोगों से प्राप्त होने वाली मुद्रा आय इसमें जोड़ देनी चाहिए।
- (४) उन सभी सेवाओं की, जिन्हें व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों का बिना किसी मूल्य के प्रदान करता है, राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना चाहिए।
- (५) निजी सम्पत्ति और सावजनिक सम्पत्ति से प्राप्त होने वाले लाभ को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना चाहिए।

मार्शल की परिभाषा की आलोचना (Criticism of Marshall's Definition)

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में प्रो. मार्शल के विचार सैद्धांतिक दृष्टिकोण में तो उचित प्रतीत होते हैं, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इसमें अनेक कठिनाइयाँ प्रतीत होती हैं। प्रो. मार्शल की परिभाषा की प्रमुख जानी-बनाये निम्नलिखित हैं —

- (१) कुल उत्पादन की सांख्यिकी माप करना बहुत कठिन है, क्योंकि एक वष में एक देश में उत्पादित की जान वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। अतः इन सभी वस्तुओं की माप करना अत्यन्त कठिन है।
- (२) व्यक्तिगत उपभोग के लिए रखी गई वस्तुओं की गणना करना कठिन है, अर्थात् वे वस्तुएँ जो बाजार में विनिमय के लिए उपलब्ध नहीं होती, उनकी गणना करना कठिनाई आती है।
- (३) वस्तुओं तथा सेवाओं की दोहरी गणना (double counting) की सम्भावना रहती है, क्योंकि यह सम्भव है कि पहले किसी एक वस्तु की गणना एक स्थान पर करें, और उसके रूप में परिवर्तन होने पर उसकी गणना दूसरे स्थान पर भी कर लें, जैसे—कृषि उत्पादन की गणना करते समय कपास की मात्रा का सम्मिलित कर लिया जाय, तत्पश्चात् औद्योगिक उत्पादन की गणना करते समय उस कपास से बनाये गये वस्त्र की गणना कर लें। इस प्रकार दोहरी गणना के कारण राष्ट्रीय आय की सही-सही गणना नहीं हो पाती।

यद्यपि मार्शल की परिभाषा की आलोचना की गई है, फिर भी इसमें सरलता और व्यापकता (comprehensiveness) का गुण पाया जाता है।

पीगू की परिभाषा (Definition of Prof Pigou),

प्रो पीगू की राष्ट्रीय आय की परिभाषा में भी मार्शल के समान उत्पादित वस्तु और सेवाओं को राष्ट्रीय आय का आधार माना है, परन्तु पीगू ने अपनी परिभाषा को व्यावहारिक बना दिया है।

पीगू के शब्दों में—“राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुनिष्ठ आय (objective income) का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित रहती है।”^२

पीगू ने अपनी परिभाषा में दो बातों पर जोर दिया है

(१) पीगू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय लाभ (राष्ट्रीय आय) में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जायेगा, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है अर्थात् जिनका विनिमय किया जाया है। इस प्रकार जो सेवाएँ मनुष्य स्वयं करता है या अपने परिवार के लिए निःशुल्क करता है, राष्ट्रीय आय में नहीं सम्मिलित होगी।

(२) देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किये गये विनियोगों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना चाहिए।

प्रो पीगू की परिभाषा मार्शल की परिभाषा से थोड़ा दिखाई पड़ती है क्योंकि पीगू ने राष्ट्रीय आय की गणना करने लिए व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत किया है।

मालोचना (Criticism)

यद्यपि पीगू की परिभाषा में निश्चितता तथा वास्तविकता पाई जाती है, परन्तु इसमें भी अर्थशास्त्रियों में अनेक दोष बताये हैं

(१) प्रो पीगू ने वस्तुओं के बीच कृत्रिम भेद किया है, उन्होंने वस्तुओं को दो भागों में एक, जिन वस्तुओं का मुद्रा में विनिमय होता है, दूसरी, जिन वस्तुओं का मुद्रा में विनिमय नहीं होता। यह भेद सही नहीं है, अनौचित्यपूर्ण है।

2 “The National Dividend is that part of the objective income of the community, including, of course, income derived from abroad, which can be measured in money”
— Pigou

- (२) यदि पीगू के दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाय तो इसमें केवल उन्ही वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जायेगा जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय होना है। ऐसा करने से राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो सकेगी तथा अनेक बटिनाइया उपस्थित हो जायेंगी, जैसे—पीगू के अनुसार हो एक नौकरानी की सेवायें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जायेंगी क्योंकि उसे अपनी सेवा का पारिश्रमिक प्राप्त होता है, यदि मालिक अपनी नौकरी से श्राद्धी कर लेता है तो उसकी सेवायें राष्ट्रीय में शामिल नहीं होंगी।
- (३) पीगू की परिभाषा सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में समान रूप से लागू नहीं होती। यह केवल उन देशों में लागू होती है जहाँ पर विनिमय केवल मुद्रा के माध्यम से ही होता है। अर्द्धविकसित या अविकसित देशों की अर्थ व्यवस्थाओं में जहाँ पर वस्तु विनिमय का चलन होता है वहाँ यह परिभाषा उपयोगी सिद्ध नहीं होती। यदि एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जहाँ पर मुद्रा का चलन बिल्कुल न हो तो पीगू के इस विचार के आधार पर उस देश की राष्ट्रीय आय शून्य रह जायेगी। अतः यह विचार केवल विकसित देशों के लिए ही उपयोगी है।

फिशर की परिभाषा (Definition of Fisher)

फिशर की राष्ट्रीय आय की परिभाषा माशुल और पीगू की परिभाषाओं से कुछ भिन्न है। माशुल और पीगू दोनों ने ही राष्ट्रीय आय की गणना 'उत्पादन' के आधार पर करने को कहा है, जबकि फिशर ने राष्ट्रीय आय का 'उपभोग' से सम्बन्धित किया है।

श्री फिशर के शब्दों में—“राष्ट्रीय लाभदायक या आय में केवल वही सेवायें सम्मिलित की जाती हैं जो कि अन्तिम रूप से उपभोक्ताओं का प्राप्त होनी हैं, चाहे वे भौतिक या मानवीय वातावरण से प्राप्त हों। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, वरन् वह केवल पूँजी में वृद्धि है। केवल वही सेवायें जो इनके प्रयोग से मुझे इस वर्ष प्राप्त होंगी, आय कहलायेंगी।”³

- 3 “The national dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from the human environment. Thus, a piano or over coat made for me this year is not a part of this year's income, but an addition to capital. Only the services rendered to me during this year by these things are income.” —Fisher

आलोचना (Criticism)

यद्यपि किशर भी परिभाषा अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि यह राष्ट्रीय आय में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उपयोग के मौद्रिक मूल्यों को ही सम्मिलित करती है लेकिन इस परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी। इस परिभाषा की प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं —

- (१) प्रो. किशर की परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि हमने एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का योग ज्ञात करना होगा। उपयोग का क्षेत्र अत्याधिक विस्तृत होने के कारण इसकी गणना करना अत्यन्त कठिन कार्य है।
- (२) इस पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए टिकाऊ वस्तुओं के 'जीवनकाल' को ज्ञात करना पड़ेगा। बिना 'जीवनकाल' ज्ञात किये किसी वस्तु के किसी विशिष्ट वर्ष में हुए उपयोग का मौद्रिक मूल्य का पता नहीं लगा सकते। वस्तुओं और सेवाओं के जीवनकाल की गणना करना असम्भव सा प्रतीत होता है।
- (३) टिकाऊ वस्तु के जीवनकाल का पता लगाना कठिन है लेकिन यदि किसी प्रकार यह पता भी लगा लिया जाय तो उस स्थिति में जबकि वस्तु हस्तांतरित होती है अर्थात् कई हाथों से गुजरती है तब उसकी सही कीमत और उत्पादन तिथि का पता लगाना अत्यन्त कठिन होता है।

किशर की आलोचनाओं से स्पष्ट होता है कि उपयोग के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना अत्यन्त कठिन है, इस प्रकार किशर के दृष्टिकोण का व्यावहारिक महत्त्व काफी सीमित रह जाता है।

तीनों परिभाषाओं की तुलनात्मक उपयुक्तता (Relative Suitability of the three Definitions)

राष्ट्रीय आय की मापन, पीगू और किशर द्वारा दी गई परिभाषाओं का हमने अभी तक विवेचन किया है। इन तीनों परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा श्रेष्ठ है, इसका उत्तर देना कठिन है। उपर्युक्त तीनों परिभाषाओं में कोई भी पूर्ण नहीं है तीनों परिभाषाओं के गुण और दोष हैं। परिभाषा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए हमें उद्देश्य को सामने रखना होगा अर्थात् राष्ट्रीय आय का किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

यदि हमारा उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के आर्थिक कल्याण को मापना है या जीवन स्तर की तुलना करनी है तो फिशर की परिभाषा अधिक श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा जिनका कि उपभोग एक देश में रहने वाले व्यक्ति करते हैं। यदि हमको यह ज्ञात करना हो कि युद्ध की स्थिति में एक देश में कितनी सामग्रियाँ मिल सकती हैं तब भी फिशर की परिभाषा श्रेष्ठ साबित होगी। क्योंकि इसके लिए यह पता लगाना होगा कि देश में कितनी सामग्रियाँ बचाई जा सकती हैं और कितनी सामग्रियों का उपभोग होगा।

जब आग्निकाल में हमारा उद्देश्य यह ज्ञात करना हो कि आर्थिक कल्याण को कौन-कौनसे तत्व प्रभावित कर रहे हैं तब भी मार्शल तथा प्रो पीगू की परिभाषाएँ श्रेष्ठ नहीं जायेंगी, क्योंकि दीर्घकाल में आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अधिक वृद्धि करना आवश्यक होता है।

माशुल और प्रो पीगू की परिभाषाओं में माशुल की परिभाषा विस्तृत है जबकि प्रो पीगू की परिभाषा अधिक व्यावहारिक और सरल है।

राष्ट्रीय आय का साधनिक विचार

मानुषिक अभशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय आय के अर्थ का समझने के लिए दो विचारों को समझ लेना आवश्यक है

- (१) कुल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product, i.e. G N P),
- (२) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (Net National Product, i.e. N N P)।

(१) कुल राष्ट्रीय उत्पादन (G N P)—किसी देश में एक वर्ष में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनमें कुल मौद्रिक मूल्य को (बाजार की कीमतों पर) कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में केवल अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही सम्मिलित रहता है, अर्थात् इसमें इन मध्यवर्ती (intermediate) वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता जिनका प्रयोग अन्तिम वस्तु के उत्पादन में किया जाता है।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन में अग्रयज्ञ कर भी सम्मिलित रहते हैं, क्योंकि कुल राष्ट्रीय आय की गणना बाजार की कीमतों पर होती है और बाजार की कीमतों में अग्रयज्ञ कर सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक मोटर कपड़े पर उत्पादन लागत ₹०) ५ आती है, उस पर ₹१) ५ उत्पादन कर है तो कपड़े का बाजार मूल्य ₹१) ५ मोटर होगा।

विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (N N P) विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अभिप्राय एक वर्ष में किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के विशुद्ध (net) उत्पादन से होता है। जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उस मशीन और अन्य अचन सम्पत्ति का कुछ न कुछ ह्रास (Depreciation) अवश्य होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से मशीनों की पितावट आदि का व्यय घटा देने से जो शेष बचता है वह विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है।

समीच में

विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन = कुल राष्ट्रीय उत्पादन — पितावट व्यय।

$$(N, N P) = (G N P) - \text{Depreciation charges}$$

आधुनिक आर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित कुल राष्ट्रीय उत्पादन तथा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के अतिरिक्त तीन अन्य धारणाओं का भी अध्ययन करते हैं। ये धारणाएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) राष्ट्रीय आय (National Income),
- (२) व्यक्तिगत आय (Personal Income),
- (३) व्यय योग्य आय (Disposable Income)।

(१) राष्ट्रीय आय (National Income) — राष्ट्रीय आय से अभिप्राय भूमि, श्रम, पूँजी तथा सगठन सभी उत्पादन के साधनों को मिलने वाले आय स्रोतों के योग से होता है। इसे साधन लागतों पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। यद्यपि आधुनिक अर्थशास्त्री विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, परन्तु कुछ अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय को सकृ-चित रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से अप्रत्यक्ष कर घटा देने के बाद जो शेष बचता है वही राष्ट्रीय आय है। कुछ अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय में विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अप्रत्यक्ष कर घटा देने के बाद उपदान (subsidies) जोड़ देते हैं, इस प्रकार

$$\begin{aligned} \text{राष्ट्रीय आय} &= \text{विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन} - \text{अप्रत्यक्ष कर} \\ (\text{National Income}) &= (\text{Net National Product}) - (\text{Indirect Taxes}) \\ &+ \text{उपदान} \\ &+ (\text{subsidies}) \end{aligned}$$

(२) व्यक्तिगत आय (Personal Income) — व्यक्तिगत आय से अभिप्राय एक देश में एक वर्ष में व्यक्तियों अथवा परिवारों को वास्तविक रूप में प्राप्त होने वाली आय से होता है। व्यक्तिगत आय के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय आय में से उन राशियों को निचालना होता है जिनका उत्पादन के साधनों में विवरण नहीं किया जाता, जैसे — आयकर कम्पनियों

का अतिरिक्त लाभ, सामाजिक सुरक्षा वसदान (social security contribution) आदि, तथा उन भुगतानों को जोड़ दिया जाता है जो सरकार द्वारा जनता को दिया जाता है जैसे—सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत मिलने वाला लाभ तथा प्रतिभूतियों पर मिलने वाला ध्यान आदि ।

(२) **व्यय योग्य आय (Disposable Income)**—व्यय योग्य आय से अभिप्राय उस आय से होता है जिसका व्यक्ति वास्तविक रूप में उपयोग कर सकता है । व्यक्ति को प्राप्त हान वाली सम्पूर्ण आय व्यय करने के लिए प्राप्त नहीं होती, अतः उस आय में से कुछ अंश व्यक्तियों द्वारा प्रयोजन करों के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है । इस प्रकार व्यक्तिगत आय में से प्रयोजन कर चुका देने के बाद जो धन बचता है वही व्यय योग्य आय है ।

राष्ट्रीय आय की गणना (Calculation of National Income)

राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रो कुज़नेट्स (Prof Kuznets) ने तीन रीतियाँ बनायी हैं —

- (१) वस्तु सेवा रीति (Commodity service method) ,
- (२) आय प्राप्त रीति (Income received method) ,
- (३) उपभोग बचत रीति (Consumption saving method) ,

कुज़नेट्स के अतिरिक्त अन्य वर्षाभाषियों ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिये अनेक रीतियाँ सुझायी हैं, उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं —

- (४) व्यावसायिक गणना रीति (Occupational method) ,
- (५) सामाजिक लेखांकन विधि (Social accounting method) ।

प्रो वी के आर वी राव (Prof. V K R V Rao) ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन और आय गणना रीति का सामूहिक प्रयोग किया है ।

(१) **वस्तु सेवा रीति (Commodity service method)**—इस रीति को 'उत्पादन गणना रीति' (census of production method) भी कहते हैं । इस रीति में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य (net value) ज्ञात किया जाता है और उनको जोड़ने के बाद राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है । इस प्रकार जो मूल्य (total) प्राप्त किया जाता है उसे 'अन्तिम उत्पादन योग' (final products total) कहा जाता है ।

इस रीति से गणना करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है —

- (१) वस्तुओं तथा सेवाओं की दृढ़री गणना से बचने के लिये केवल अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का ही मूल्य ज्ञात किया जाता है ।
- (२) कुल उत्पादन में से अचन सम्पत्ति का पितावट व्यय घटा दिया जाता है ।
- (३) विदेशों से लेन-देन का समायोजन (adjustment) कर लिया जाता है । अर्थात् आयात और निर्यात के मूल्यों की गणना की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिये आयात और निर्यात का अन्तर लिया जाता है ।

(२) आय-प्राप्त रीति (Income-received method) — इस रीति को 'आय गणना रीति' (income census method) भी कहते हैं । इस रीति द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए व्यक्तियों तथा व्यवसायिक फर्मों द्वारा एक वर्ष में प्राप्त शुद्ध आय को ज्ञात किया जाता है और उनकी आयों को जोड़ लिया जाता है । दूसरे शब्दों में, इस रीति के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त मजदूरी, वेतन, लाभ, सवान और ब्याज आदि को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है ।

इस रीति द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिये निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है —

- (१) इसमें हस्तांतरण भुगतानों (transfer payments) को सम्मिलित नहीं किया जाता, अर्थात् उन भुगतानों को जो किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता जैसे बृद्धावस्था पेन्शन, बेरोजगारी भत्ता आदि ।
- (२) जिन वस्तुओं और सेवाओं के लिये मौद्रिक भुगतान नहीं किया जाता उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता ।
- (३) अविनिरत लाभ को राष्ट्रीय आय में जोड़ लिया जाता है ।
- (४) सेवायोजक या उत्पादक द्वारा उत्पादन में लगाये गये स्वयं के साधनों के गृहस्कारों को बाजार कीमत के आधार पर राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है ।

(३) उपभोग-बचत रीति (Consumption-saving method) — इस रीति को 'व्यय गणना रीति' (census of expenditure method) तथा 'उपभोग विनियोग रीति' (consumption investment method) भी कहते हैं ।

इस रीति की यह मान्यता है कि व्यक्ति अपनी आय में से कुछ भाग बचाकर रख लेते हैं और शेष भाग व्यय कर देते हैं, अतः राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिये देश के समस्त व्यक्तियों की कुल बचतों तथा कुल व्ययों को जोड़ लिया जाता है । कुल बचत

कुल विनियोग के बराबर होती है, इसलिए इस रीति को दत्त विनियोग रीति कहते हैं। इस रीति की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि व्यक्तियों की वक्तों और व्ययों के विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त नहीं हो पाते।

(४) व्यावसायिक गणना रीति (Occupational method)—इन रीति में राष्ट्रीय आय की गणना देश में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवसायों के आधार पर की जाती है। इस रीति में सर्वप्रथम कृषि, उद्योग कच्चे, बैंकिंग, यातायात तथा व्यवसायों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की आय की तालिकाएँ बनायी जाती हैं, तत्पश्चात् इन विभिन्न व्यवसायों की तालिकाओं का योग प्राप्त कर इनको जोड़ लिया जाता है। इन विभिन्न तालिकाओं का जोड़ से प्राप्त योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं।

स्टाम्प के अनुसार इस रीति में उन आयों को सम्मिलित नहीं किया जाता चाहिए जो कि किसी व्यवसाय से प्राप्त नहीं होती है जैसे—बूढ़ावस्था पेन्शन, शुद्ध के विनाश भत्ते आदि।

(५) सामाजिक लेखांकन रीति (Social accounting method)—इस रीति का प्रतिपादन रिचर्ड स्टोन (Richardstone) ने किया। इस रीति के अनुसार विभिन्न प्रकार के लेखाओं और भेन देन को विभिन्न वर्गों में बाँट दिया जाता है। समान आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एक ही वर्ग में रखा जाता है और विभिन्न वर्गों की औसत आय मासुम करके उस वर्ग के व्यक्तियों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त विभिन्न वर्गों के योग को जोड़ कर राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है।

उत्पादन गणना रीति तथा आय गणना रीति का सम्मिश्रण (Both Method Mixed)

प्रो वी के आर वी रव (Prof V K R V. Rao) ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन गणना रीति तथा आय गणना रीति दोनों का सहारा लिया है। इस रीति के अनुसार जहाँ पर उत्पादन के विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध होते हैं, वहाँ उत्पादन गणना रीति और जहाँ पर आय के विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर आय गणना रीति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं होते वहाँ पर स्वयं सर्वेक्षण करके आँकड़े तथा सूचनार्थ प्राप्त की जाती हैं।

राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ (Difficulties in Calculation of National Income)

राष्ट्रीय आय की गणना करना किसी भी देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, परन्तु राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं जिनके कारण राष्ट्रीय आय की सही-सही गणना नहीं हो पाती। ये कठिनाइयाँ निम्नलिखित देशों की अपेक्षा अधिकतर और

अल्पविकसित देशों में अधिक आती है, क्योंकि इन देशों में विश्वस्तरीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं —

(१) राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आंकड़े एकत्रित करने में काफी कठिनाई आती है। अल्पविकसित और अविकसित देशों में प्राप्त आंकड़े अविश्वस्तरीय तथा अपर्याप्त भी होते हैं जिससे सही गणना नहीं हो पाती।

(२) राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, लेकिन ऐसे देशों में जहाँ पर उपादन का एक बड़ा भाग बाजार में नहीं पहुँच पाता, वहाँ राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई आती है।

(३) राष्ट्रीय आय की गणना करने में द्रव्य-सौ वस्तुओं और सेवाओं की दूहरी गणना होने की सम्भावना बनी रहती है, जिसके कारण सही राष्ट्रीय आय प्राप्त नहीं हो पाती।

(४) अल्पविकसित और अविकसित देशों में आय के सम्बन्ध में सही जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है। विशेष रूप से जन व्यक्तियों की आय ज्ञात करने में ज़रा भी कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त भारत जैसे देश में जहाँ पर व्यक्ति (कृषक) एक व्यवसाय में अपनाकर अनेक व्यवसायों में लगा रहता है।

(५) विभिन्न वर्गों की राष्ट्रीय आय की तुलना करने के लिए मूल्य स्तर (price level) में परिवर्तन के अनुसार समायोजन (adjustment) करना होता है। इसके लिए निदेशाङ्क के प्रयोग करना पड़ता है, जबकि स्वयं निदेशाङ्क के निर्माण में भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। अतः सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती।

राष्ट्रीय आय विश्लेषण का महत्व (Significance of National Income Analysis)

राष्ट्रीय आय के आँकड़ों को 'अर्थ व्यवस्था का लेखा (account of economy)' भी कहा जाता है। इसकी सहायता से विभिन्न भागों में बँटी हुई राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था का सम्पूर्ण अध्ययन किया जाता है। अबत, विनियोग, पूँजी निर्माण औद्योगिक उत्पादन, जीवन-स्तर तथा आर्थिक वित्तीय आदि का अध्ययन करने में सहयोग प्रदान करता है। प्रो शूप (Prof Shoup) ने इसके महत्व को दर्शाते हुए लिखा है

“अर्थशास्त्र की अधिकांश आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए राष्ट्रीय आय और उसकी प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करना चाहिए।”

राष्ट्रीय आय का महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है -

- (१) राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक प्रगति की सूचक है। इस विश्लेषण के द्वारा यह पता लगता है कि उत्पादन में किस प्रकार और कितनी वृद्धि हो रही है। यह सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की उन्नति और अवनति की ओर संकेत करती है तथा देश में उपलब्ध साधनों के प्रयोग की स्थिति को भी दर्शाती है।
- (२) राष्ट्रीय आय की सहायता से देश की आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
- (३) सरकार की सही आर्थिक नीति के निर्धारण में सहयोग देते हैं। सरकार अपनी मौद्रिक नीति, प्रशुल्क नीति, आर्थिक सहायता आदि नीतियों के निर्माण में राष्ट्रीय आय विश्लेषण का सहारा लेती है।
- (४) आर्थिक नियोजन (economic planning) के लिए राष्ट्रीय आय का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि योजनाओं के निर्माण के लिए राष्ट्र में उपलब्ध साधनों, प्रगति की स्थितियों तथा विनियोग और बचत का अध्ययन आवश्यक होता है।
- (५) राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक कल्याण की सूचक होती है मासल में बनाया है कि राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उस देश का आर्थिक कल्याण भी उतना अधिक होता है।
- (६) राष्ट्रीय आय विश्लेषण के प्रयोग से अर्थ व्यवस्था के दोषों की जानकारी प्राप्त हो जाती है जिससे विकास की दर को तीव्र करने के लिए उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है।

राष्ट्रीय आय विश्लेषण की सीमाएँ (Limitation of National Income Analysis)

राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। आधुनिक ज्ञान में अधिकांश कठिनाइयाँ दूर की जा चुकी हैं, लेकिन अल्प विवक्षित देशों में अब भी अनेक कठिनाइयाँ राष्ट्रीय आय की गणना करने में उपस्थित हो जाती हैं। राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित आठों विकसित और अल्प विकसित तथा अर्द्ध विकसित देशों में पूर्ण सही चित्र प्रस्तुत न करके एक मोटा अनुमान प्रस्तुत कर देते हैं। इस विश्लेषण की कुछ सीमाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं —

- (१) विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि विभिन्न देशों का आर्थिक स्तर, उपभोगों की

आवश्यकतायें उनका उपयोग त्रुटि अलग-अलग होना है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय की गणना अपने ही ढंग से करता है, अतः राष्ट्रीय आय की गणना की रीतियों में भिन्नता होने के कारण भी विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करना वैज्ञानिक नहीं है ।

(२) राष्ट्रीय आय की गणना भुद्रा म की जाती है । सही गणना के लिए उत्पादन सागत का सही ज्ञान आवश्यक है, परन्तु व्यवहार में वास्तविक उत्पादन सागत का पता लगाना कठिन है ।

(३) कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि राष्ट्रीय आय का केवल तुलनात्मक महत्व है ।

राष्ट्रीय आय विश्लेषण की अनेक सीमायें होने के बावजूद भी राष्ट्रीय आय के महत्व में कोई कमी नहीं आती । आज के युग में जबकि अधिकांश सरकारें अपनी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करने के लिए योजनाओं का सहारा ले रही हैं, इस विश्लेषण का महत्व बड़ा बढ़ गया है ।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं ? राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है ?
२. राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में मार्शल, पीगू और फिशर के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।
३. कृण राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product) तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (Net National Product) में अन्तर बताइए ।
४. मार्शल, फिशर तथा पीगू द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं का परीक्षण कीजिए । इन परिभाषाओं में कौन-सी परिभाषा श्रेष्ठ है और क्यों ?
५. राष्ट्रीय आय के महत्व को समझाइए । राष्ट्रीय आय की गणना करने में आने वाली कठिनाइयों का भी उल्लेख कीजिए ।

अध्याय ३

★

आर्थिक प्रणाली के कार्य

[Functions of the Economics System]

★ ★ ★

मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक आर्थिक क्रियाएँ करता है। उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि क्रियाएँ आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु करता है। इन आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक व भौतिक साधनों तथा सामाजिक और राजनैतिक संगठनों का प्रभाव पड़ता है। उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि की क्रियाओं के संचालन के लिए परिस्थिति के अनुसार नियमों तथा सिद्धान्तों का विकास होना रहता है तथा अनेक समस्याओं का निर्माण हो जाता है। ये नियम, सिद्धान्त तथा स्थायें एक आर्थिक प्रणाली का ढांचा तैयार करती हैं और यह ढांचा ही आर्थिक प्रणाली का आधार है, जिसके अन्तर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है।

आर्थिक प्रणाली से आमतौर पर वैधानिक तथा संस्थागत ढांचे (legal and institutional frame work) से है जिसके अन्तर्गत आर्थिक क्रियाएँ संचालित होती हैं। आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण सम्बन्धी क्रियाओं से होता है। ये सम्पूर्ण आर्थिक क्रिया-कलाप मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किये जाते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति में कहीं-न कहीं सरकार का काम या अधिक हस्तक्षेप अवश्य रहता है, इसलिए किसी देश की आर्थिक प्रणाली उस देश की सरकार द्वारा किये जाने वाले नियंत्रण व हस्तक्षेप की मात्रा एवं सीमा पर निर्भर करती है।

आर्थिक प्रणाली की परिभाषा सूक्ष्म एवं सटीक रूप में देना काफी कठिन है क्योंकि इसमें अनेक रूप हो सकते हैं। फिर भी अर्थशास्त्रियों ने इसे परिभाषित करने की चेष्टा की है।

विलियम एन लुक्स (William N. Loucks) के शब्दों में—आर्थिक प्रणाली के अन्तर्गत वे स्थायें आती हैं, जिनके अंतर्गत या राष्ट्र या समूह द्वारा चुना

जाना है या स्वीकार किया जाता है तथा जिनके माध्यम से उनके साधनों को मानवीय आवश्यकताओं की सतृप्ति हेतु प्रयोग में लाया जाता है।¹

आर्थिक प्रणाली की एक थोड़ा परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है —

“आर्थिक प्रणाली समस्याओं का एक ढांचा है जिसके द्वारा उत्पात्ति के साधनों तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग पर सामाजिक नियंत्रण किया जाता है।”²

आर्थिक प्रणाली के कार्य (Function of Economic System)

प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को (पूरा जीवाद, समाजवाद, या मिश्रित अर्थ व्यवस्था) कुछ आवश्यक एवं आधारभूत कार्य करने पड़ते हैं। यद्यपि इनकी कार्य पद्धति तथा प्रणाली में भिन्नता होने के कारण भिन्नता आ जाती है। आर्थिक प्रणाली के आधारभूत एवं मौलिक कार्यों की संख्या के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद नहीं है। प्रो फेर्ग्युसन तथा क्रैप्स (Ferguson and Kreps) तथा प्रो सेम्युलसन (Prof Samuelson) ने आर्थिक प्रणाली के तीन कार्य बताये हैं। प्रो स्टिगलर (Stigler) ने चार, प्रो हॉल (Prof Halm) ने पाँच तथा प्रो नाइट (Prof Knight) और लेफ्टविच (Leftwich) ने पाँच आधारभूत कार्य बताये हैं।

प्रो. सेम्युलसन के अनुसार आर्थिक प्रणाली के आधारभूत कार्य केवल तीन होते हैं, उन्हीं के शब्दों में

“प्रत्येक अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार तीन मूलभूत आर्थिक समस्याओं को हल करना होता है। सभी सम्भावित वस्तुओं और सेवाओं में से किस प्रकार की और किन्ती वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जायेगा। इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये आर्थिक साधनों का किस प्रकार प्रयोग होगा तथा वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जायेगा अर्थात् विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों में आव का वितरण किन प्रकार का होगा।”³

- 1 “An economic system consists of those institutions which a given people, or nation or group of nations, has chosen or accepted as the means through which their resources are utilised for the satisfactions of human wants”—William N Loucks
- 2 “Economic system is the frame work of institutions by which the use of the means of production and of their products is socially controlled” —Quoted from K. P. Jain's book ‘समाजशास्त्र के सिद्धांत’
- 3 “Every economy must some how solve the three fundamental economic problems ‘What kind and quantity shall be produced of all possible goods and services?’ How economic resources’

स्म्युलसन के इस मत से सभी अर्थशास्त्री सहमत हैं कि ये तीन आधारभूत कार्य आर्थिक प्रणाली को चलाने होते हैं, परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसमें पांच कार्य बताये हैं। ये पांच कार्य निम्नलिखित हैं

- (१) किस वस्तु का उत्पादन किया जाय ? (What is to be produced ?),
- (२) वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाय ? (How shall the goods be produced),
- (३) वस्तुओं का उत्पादन किमके लिये किया जाय ? (For whom shall the goods be produced ?),
- (४) साधनों का पूर्ण उपयोग (Full utilisation of Resources),
- (५) आर्थिक अनुरक्षण तथा विकास (Economic Maintenance and growth)।

उपर्युक्त प्रथम तीन अवस्थाओं का किसी भी अर्थ-व्यवस्था के लिए हल करना आवश्यक है, बिना इन अवस्थाओं का हल किये कोई भी अर्थ-व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती। बाद की दो अवस्थाओं के हल से अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप प्रकट होता है।

१. किस वस्तु का उत्पादन किया जाय ? (What is to be produced ?)

किसी भी अर्थ-व्यवस्था के सामने सबसे पहला कार्य यह निर्धारण करना है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाय। यह कार्य इसलिए करना होता है क्योंकि साधन मनुष्य की आवश्यकताओं की तुलना में सीमित मात्रा में पाये जाते हैं। अतः अधिकतम आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए साधनों के वितरण के सम्बन्ध में निर्णय लेना होता है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न उत्पादन सम्भावनाओं के बीच यह निर्णय लेना होता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाय और किस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाय।

‘किस वस्तु का उत्पादन किया जाय’ में दो बातें निहित हैं —

- (१) किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाय ?
- (२) इन वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाय ?
- (अ) किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाय ? — एक अर्थ-व्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो कि समाज की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। अतः अर्थ-व्यवस्था या समाज को वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव

shall be used in producing base goods" For whom the goods shall be produced, & what the distribution of income among different individuals and classes is to be "

—Samuelson

करना होता है, कि वह उपयोग वस्तुओं (consumer goods) का उत्पादन करे या पूंजीगत वस्तुओं (capital goods) का उत्पादन करे। इसके बाद उसे निर्णय करना होता है कि उपयोग वस्तुओं में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करे या विलासता की वस्तुओं का। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के सम्बन्ध में निर्णय विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में यह निर्णय कीमत यंत्र (price mechanism) द्वारा लिए जाते हैं जबकि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

- (व) वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाय—वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव करने के बाद प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था का यह निर्णय लेना होता है कि वह इन वस्तुओं और सेवाओं को कितनी मात्रा उत्पादित करे। उसे यह निर्णय करना होता है कि कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे और कितनी मात्रा में उपयोग वस्तुओं का। वास्तव में यह निर्णय देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रणाली से प्रभावित होता है।

एक अर्थ व्यवस्था जब उत्पादन के सम्बन्ध में निर्णय लेती है तो उसके सामने दो बातें रहती हैं। पहली, यह कि कुछ वस्तुओं के उत्पादन में यदि वृद्धि की जाती है तो दूसरी कुछ वस्तुओं के उत्पादन में कमी आजायेगी। इसका कारण साधनों की सीमितता है। दूसरी, यदि एक ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में साधनों की मात्राओं में वृद्धि की जाती है तो अतिरिक्त साधनों से प्राप्त उत्पादन वृद्धि घटता जायेगा। अतः अर्थ-व्यवस्था को उत्पादन करते समय वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्षिक महत्व पर अनिवार्य रूप से विचार करना होता है। उसे यह निर्णय करना होता है कि वह पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं, जैसे—मशीनों और मनों का उत्पादन कितनी मात्रा में करे, और उपयोग की वस्तुओं, जैसे—बपड़ा, चीनी, रेडियो आदि का उत्पादन कितनी मात्रा में करे। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 'भविष्य की आवश्यकताओं' से सम्बन्धित है, जबकि उपयोग वस्तुओं का उत्पादन 'वर्तमान की आवश्यकताओं' से। यदि उत्पादन के साधनों को उपयोग की वस्तुओं में अधिक लगा दिया जायेगा तो इसका प्रभाव यह होगा कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधन अधिक उपलब्ध होने के कारण भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधन कम मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे। इससे भविष्य में उत्पादन कम प्राप्त होगा, जिससे अर्थ-व्यवस्था का उचित विकास सम्भव नहीं हो पायेगा। इसके विपरीत यदि पूंजीगत वस्तुओं में अधिक साधन प्रयुक्त किये जाते हैं तो वर्तमान उपयोग के लिए कम वस्तुएँ उपलब्ध हो सकेंगी। अतः प्रत्येक अर्थ व्यवस्था वर्तमान व भविष्य

की आवश्यकताओं के महत्व के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का नियंत्रण होती है।

२ वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाय (How shall the goods be produced?)

एक अर्थ व्यवस्था का दूसरा कार्य यह नियंत्रण देना होता है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाय ? अर्थात् उत्पादन के समष्टि के सम्बन्ध में नियंत्रण देना होता है। उत्पादन के समष्टि में सम्बन्धित कार्य निम्नाल्लिखित हैं —

- (१) सामर्थ्य का उपयोग उन उद्योगों में किया जाय जो कि उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिनको कि उपभोक्ता अधिक पसन्द करते हैं तथा साधनों का उन उद्योगों में जाने से रोका जाय जिनकी वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता कम पसन्द करते हैं। दूसरे शब्दों में उपभोक्ताओं की पसन्द की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए अधिक साधनों को प्रयुक्त किया जाय।
- (२) विभिन्न फर्मों द्वारा (जो कि नियोजित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं) साधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाय।
- (३) उत्पत्ति के साधनों को (जिसमें श्रम भी सम्मिलित है) उन प्रयोगों में लगाया जाय जो कि सबसे अधिक उत्पादक हों।

उत्पादन के समष्टि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ता साधनों का कुशलतम उपयोग (most efficient use) हो जिससे प्रति इकाई व्यय लागत कम हो जाय।

३ वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाय (For whom shall the goods be produced?)

एक अर्थ व्यवस्था का तीसरा महत्वपूर्ण नियंत्रण यह करना होता है कि उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाय। दूसरे शब्दों में, कुल उत्पादन को विभिन्न आर्थिक इकाइयों में किस प्रकार बांटा जाय। इसके अनिश्चित यह भी नियंत्रण करना पड़ता है कि कुल उत्पादन में से विभिन्न आर्थिक इकाइयों का हिस्सा उनकी योग्यतानुसार दिया जाय या उनकी आवश्यकतानुसार। यह नियंत्रण देश की आर्थिक प्रणाली (economic system) से प्रभावित होता है। सामाजिक प्रत्यक्ष व्यवस्था के यह निर्धारित करना होता है कि कुल उत्पादन का वितरण कुशल तथा न्यायसंगत हो जिससे कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति सुखी व सम्पन्न रहें। परन्तु इस प्रकार का नियंत्रण कठिन आर्थिक वातावरण से प्रभावित नहीं होता, इस पर राजनीतिशास्त्र तथा नीतिशास्त्र के तत्त्वों का भी प्रभाव पड़ता है।

अर्थ-व्यवस्था का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वहाँ के व्यक्तियों को उपयोग के लिए कितनी वस्तुएँ उपलब्ध होती है। वहाँ के शक्तियों का रहन सहन का स्तर भीसा है, वहाँ के नागरिकों को ऐसी सुविधायें प्राप्त हैं या नहीं जो उनकी स्वस्थ व सुखी बनाने के साथ-साथ देश के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करती है। परन्तु विभिन्न देशों में अपनायी जाने वाली आर्थिक प्रणालियों में भिन्नता होने के कारण वितरण के उद्देश्य में समानता नहीं पाई जाती, जिसके फलस्वरूप इस आधार पर मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है।

उपर्युक्त तीनों समस्याएँ अर्थ-व्यवस्था की आधारभूत समस्याएँ हैं जिनको प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था द्वारा हल किया जाना आवश्यक है। इन तीनों के मूल में समस्या 'साधनों की सीमितता' है। यदि साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो 'कितनी वस्तु का उत्पादन किया जाय?' या 'वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाय?' की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। साधनों की सीमितता के कारण ही उपभोग, उत्पादन और वितरण में 'बुनाव' करना होता है।

४. साधनों का पूर्ण उपयोग (Full Utilisation of Resources)

प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग कर प्रत्येक देश की सरकार या समाज इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है कि उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग हो। परन्तु यह देखा जाता है कि सामान्यतः प्रत्येक देश में कुछ न कुछ साधन अप्रयुक्त (unutilised) रह जाते हैं जिससे बेरोजगारी या अर्ध-रोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था इस बात के लिए भरसक प्रयत्न करती है कि कोई भी साधन अप्रयुक्त न रहे अर्थात् 'पूर्ण रोजगार' की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है।

जो देश या समाज अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति करना चाहता है, वह भौतिक और मानवीय दोनों ही साधनों का तीव्रता से प्रयोग करेगा। इस स्थिति में जब भौतिक साधनों के शोषण की गति तेज होती है तो वर्तमान में उत्पादन बढ़ जाता है लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कम साधन ही उपलब्ध हो पाते हैं। अतः प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था में साधनों के प्रयोग का स्तर नियंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन देशों में जहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि की दर अधिक है, वहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए अधिक-से-अधिक रोजगार की सुविधा प्रदान करने के प्रयत्न किये जाते हैं। यह रोजगार की सुविधा उसी स्थिति में प्राप्त होगी जबकि साधनों का अधिकतम विकास किया जाय।

५ आर्थिक प्रनुरक्षण तथा विकास (Economic Maintenance and Growth)

वर्तमान समय में प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था का यह उद्देश्य होता है कि वह अधिक-से-अधिक विकास करे जिससे कि समाज को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके। अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए यह आवश्यक है कि जो उत्पादन क्षमता वर्तमान में है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आये, तथा साधनों की मात्रा और विस्म में वृद्धि करके देश के उत्पादन में वृद्धि की जाय। अनुरक्षण तथा विकास से आशय उत्पादन क्षमता में कमी न होने देने तथा उत्पादन की तकनीकों में सुधार और साधनों के प्रयोग में वृद्धि से है।

प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था उस समय तक विकास नहीं कर सकती अथवा अपने समाज को अधिकतम वस्तुयें उपलब्ध नहीं करा सकती जब तक कि नई वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता। नई वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन विधि में निरन्तर सुधार किया जाता है तथा वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षा का विस्तार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादन की कुशलतम व नवीन रीतियों का प्रयोग किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था को पाँच कार्य अनिवार्य करने होते हैं और ये सभी कार्य 'साधनों की सीमितता' से सम्बन्धित हैं। ये सभी कार्य एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। किसी भी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति को ज्ञान करने के लिए उपर्युक्त पाँचों कार्यों की स्थिति का देखा जाता है, अर्थात् यदि उपर्युक्त सभी कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न किये जाते हैं, तो वह अर्थ-व्यवस्था विकसित अवस्था में होती है। लेकिन विभिन्न देशों में आर्थिक प्रणालियों में भिन्नता होने के कारण इन पाँचों समस्याओं के हल के लिए अलग-अलग नियम व तरीके अपनाये जाते हैं।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है? एक आर्थिक प्रणाली कौन-कौनसे कार्य सम्पन्न करती है?
२. आर्थिक प्रणाली के कार्यों की व्याख्या कीजिए।
३. किसी भी आर्थिक प्रणाली की मूलभूत समस्या क्या है? इन समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाता है?

अध्याय ४

★

पूँजीवाद [Capitalism]

★ ★ ★

आर्थिक प्रणालियों में पूँजीवाद का अपना विशिष्ट स्थान है। पूँजीवाद के महत्त्व के कारण ही इसके गुण, दोष और भविष्य के सम्बन्ध में विद्वानों और अर्थशास्त्रियों में विवाद काफी समय से चला आ रहा है। वर्तमान युग में विश्व के अनेक देशों ने पूँजीवादी व्यवस्था को अपनाया है।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था औद्योगिक प्रगति को देन है। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक प्रगति से पूर्व वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन छोटी मात्रा में होता था। उत्पादन करने के लिये उत्पात के साधनों का प्रयोग कम होता था तथा उनमें कम पूँजी की आवश्यकता होती थी, अतः उत्पादन काय सामान्य व्यक्ति की पहुँच से बाहर नहीं था। परन्तु औद्योगिक प्रगति के पश्चात् उत्पादन का स्वरूप बदल गया। उत्पादन में मशीनों, यन्त्रों व शक्ति का प्रयोग होने लगा, फलस्वरूप उत्पादन का आकार बढ गया। इस स्थिति में उत्पादन करने के लिए अधिक मात्रा में पूँजी, धन व दूसरे उत्पात के साधनों की आवश्यकता पड़ी। इन साधनों को एकत्रित करने और उनकी उत्पादन कार्य में लगाने के लिए जितनी पूँजी, कुशलता व योग्यता की आवश्यकता हुई वह साधारण उत्पादक के लिए जुटा पाना सम्भव नहीं रहा। अतः उत्पादन काय कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में चला गया, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे पूँजी उन्ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होनी चली गई। पूँजी के केन्द्रीकरण के कारण समाज में आर्थिक विषमतायें काफी बढ गईं।

पूँजीवाद की परिभाषा (Definition of Capitalism)

पूँजीवाद वह आर्थिक अवस्था है जिसमें उत्पात के साधनों पर कुछ ही व्यक्तियों

- १ पूँजीवाद को अनियोजित अर्थ व्यवस्था (unplanned economy) या स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था (free economy) भी कहते हैं।

(निजी व्यक्तियों या व्यक्तिगत संस्थाओं) का स्वामित्व या नियंत्रण होता है, तथा जिन्हा उपयोग के स्वतन्त्रतापूर्वक अपने लाभ में वृद्धि के लिए करते हैं। पूजीवाद की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। यहाँ पर हम पूजीवाद की कुछ प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

✓ प्रो पीगू (Prof Pigou) ने पूजीवाद की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी है —

“पूजीवादी अर्थ व्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर अधिकार निजी व्यक्तियों का होता है या उनके द्वारा किराये पर लिये जाते हैं, तथा उनके आदेशानुसार इस प्रकार उपयोग में लाये जाते हैं कि वे जिन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहयोग देते हैं, उनको लाभ पर बेचा जा सके।”²

लुक्स और हुट (Loucks and Hoot) के अनुसार—‘पूजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसकी विशेषता निजी स्वामित्व तथा मनुष्य कृत एवं प्राकृतिक पूँजी का निजी लाभ के लिए प्रयोग है।’³

प्रो सिडनी एब वेब (Prof Sydney and Webb) के शब्दों में — ‘पूजीवाद या पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था या पूजीवादी संस्था से अभिप्राय उन उद्योगों या वैधानिक संस्थाओं के विकास की उस अवस्था से है जिसमें अधिकार अधिक धन धारकों उत्पत्ति के साधनों के स्वामित्व से वंचित मानते हैं और उनकी स्थिति उन मजदूरों के समान हो जाती है जिनका जीवन निर्वाह, सुरक्षा, वैयक्तिक स्वतन्त्रता आदि राष्ट्र के एक छोटे से समूह की इच्छा पर निर्भर हो जाती है, अर्थात् उन लोगों पर जो अपने वैधानिक स्वामित्व द्वारा भूमि, मशीनरी और समान की श्रम शक्ति के मालिक बन

2 “A capitalist industry is one in which the material instrument of production are owned or hired by private persons and are operated at their orders with a view to selling at a profit the goods and services that they help to produce” — Prof Pigou

3 ‘Capitalism is a system of economic organisation featured by private ownership and use for private profit of man made and natural resources’ — Loucks and Hoot

जाते हैं। ये उनके संगठन पर नियन्त्रण रखते हैं तथा लेना करने का उनका उद्देश्य निजी और व्यक्तिगत लाभ कमाना होता है।”^४

प्रो डी मेकराइट (Prof D Macwright) के अनुसार—“पूँजीवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आर्थिक संगठन का एक बड़ा भाग और विशेष तौर पर विमुक्त तथा विनियोग निजी (गैर-सरकारी), इकाइयों द्वारा सक्रिय तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता की दशा में लाभ प्राप्ति की भांति से किया जाता है।”^५

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूँजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के मापनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तथा वे इन साधनों का प्रयोग लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। संक्षेप में, पूँजीवाद का आधार निजी सम्पत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता है।

पूँजीवाद की विशेषताएँ (Salient Feature of Capitalism)

पूँजीवाद या अनियोजित अर्थ व्यवस्था के विकास के साथ-साथ इसकी विशेषताएँ हमारे सामने प्रकट होने लगीं। अद्ययावतता द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं से पूँजीवाद की विशेषताओं का पता लगता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

- 4 “By the term ‘capitalism’ or the ‘capitalist system’, or as we prefer, the ‘capitalist civilisation’, we mean the particular stage in the development of industries and legal institutions in which the bulk of the workers find themselves divorced from the ownership of the instruments of production in such a way as to pass into the position of wage earners whose subsistence, security and personal freedom seem dependent on the will of a relatively small proportion of the nation namely those who own and through their legal ownership control the organisation of the land, the machinery and labour force of the community and do so with the object of making for themselves individual and private gains

—Sydney and Webb

- 5 “Capitalism is a system in which, on average, much of the greater portion of economic life and particularly of net new investment is carried on by private (i.e. non government) units under conditions of active and substantially free competition, and avowedly of the least, under the incentive of a hope for profit”

—Prof D Macwright

- (१) निजी सम्पत्ति का अधिकार (Right of private property)—पू जीवादी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निजी सम्पत्ति का अधिकार है। इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति एवं धनानुसार निजी सम्पत्ति का निर्माण कर सकता है तथा उस अपनी इच्छानुसार उत्तराधिकारियों को दे सकता है। पू जीवादी व्यवस्था में निजी सम्पत्ति के अधिकार को सुरक्षा सरकार द्वारा की जाती है। व्यक्ति को इस सम्पत्ति के उपभोग की स्वतन्त्रता होती है और वह यदि इस सम्पत्ति का उपयोग और अधिक आय प्राप्त करने के लिये करना चाहता है तो उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाती है। इस प्रकार व्यक्ति को निजी सम्पत्ति रखने, उसका उपभोग तथा उसे उत्तराधिकारियों को देने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है।
- (२) आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic freedom)—पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था में व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता रहती है कि वह अपनी इच्छानुसार व्यवसाय का चुनाव कर सके, और वह इस व्यवसाय में जब चाहे तब परिवर्तन भी कर सके। इनके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु को क्रय करने की स्वतन्त्रता रहती है, अर्थात् वह अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं का चुनाव कर सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी दूसरे व्यक्ति से अनुबन्ध या प्रसविदा (contract) कर सकता है। संक्षेप में, व्यक्ति को - (अ) व्यवसाय की स्वतन्त्रता, (ब) चुनाव की स्वतन्त्रता तथा (स) प्रसविदा की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। आर्थिक स्वतन्त्रता में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता।
- आज के युग में परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता पू जीवादी देशों में नहीं पाई जाती है। उसमें समाज के हित का ध्यान में रखते हुए तथा देश की आवश्यकतानुसार कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों और नियमों के अन्तर्गत ही व्यक्तियों की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। जैसा कि डी एच रॉबर्टसन (D H Robertson) ने कहा है — “कानून द्वारा स्वीकृत विस्तृत सीमाओं तथा सामाजिक बानावरण द्वारा निर्धारित सीमाओं के बीच प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने जीवन तथा अपनी आय को प्रयोग में ला सकता है।”^{१६}
- (३) लाभ उद्देश्य (Profit motive)—पू जीवादी व्यवस्था को प्रमुख विशेषता-लाभ

■ “Within the wide limits allowed by the law, and the stricter bounds set by social opportunity, each man is at liberty to spend both his life and his income as he chooses” — D H Robertson

उद्देश्य है। इस व्यवस्था में जिनकी भी आर्थिक क्रियायें की जाती हैं, उनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। प्रो जी डी एच कोल (Prof G D H Cole) के शब्दों में — "सम्भावित लाभ वह धुरी है जिस पर सम्पूर्ण पू.जीवादी व्यवस्था घूमती है।"⁷

अतः पू.जीवादी व्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियायें व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण करता है। अपने साधनों का उपयोग करते समय कोई भी व्यक्ति सामाजिक हित को ध्यान में नहीं रखता।

(४) प्रतियोगिता (Competition) — पू.जीवादी व्यवस्था में समाज में प्रतियोगिता पाई जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन कार्य करने के लिये स्वतन्त्र रहता है, वे अपनी समस्त क्रियायें अधिक लाभ प्राप्ति करने के उद्देश्य से संचालित करते हैं अतः एक ही वस्तु के अनेक उत्पादक हो जाते हैं जिससे उनमें प्रतियोगिता प्रारम्भ हो जाती है। पू.जीवादी अर्थ-व्यवस्था में प्रतियोगिता केवल उत्पादकों या विक्रेताओं में ही नहीं पाई जाती बल्कि उपभोक्ताओं में भी वस्तु का प्रयोजन करने की प्रतियोगिता रहती है। इसके अतिरिक्त नेतारों और विक्रेताओं के मध्य भी प्रतियोगिता रहती है। उत्पादक या विक्रेता अपनी वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचना चाहता है जबकि क्रेता उससे लिये कम मूल्य देना चाहता है। इस प्रकार पू.जीवादी अर्थ-व्यवस्था प्रतियोगितापूर्ण अर्थ-व्यवस्था बन जाती है।

(५) वर्ग संघर्ष (Class conflict) — पू.जीवादी अर्थ-व्यवस्था की एक और विशेषता वर्ग-संघर्ष है। इस व्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है — एक, पू.जीवति वर्ग, दूसरा, श्रमिक वर्ग अथवा अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए इन दोनों वर्गों में संघर्ष चलता रहता है। पू.जीवति वर्ग अपने-अपने लाभ में वृद्धि करने के उद्देश्य से श्रमिकों का शोषण करता है, अधिक श्रमिक अधिकाधिक सुविधायें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तथा पू.जीवति के शोषण से बचने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रकार संघर्ष पू.जीवाद का 'धम' बन जाता है। परिस्थितियाँ इस प्रकार उत्पन्न हो जाती हैं कि प्रचलित व्यवस्था में इस संघर्ष का कोई समाधान दिखाई नहीं देता।

✓ (६) मूल्य यंत्र (Price mechanism) — पू.जीवादी अर्थ-व्यवस्था में कोई भी केन्द्रीय सत्ता नहीं होती जो कि उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण रखती हो। इस व्यवस्था में

7 "Expected profit is the pivot on which the entire capitalistic system turns"
—C D H Cole

सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण 'मूल्य यंत्र' के द्वारा किया जाता है। समाज में वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में होगा, तथा जिन वस्तुओं का उत्पादन होगा, यह मूल्य यंत्र द्वारा निर्धारित होता है। इसके अनिर्नित उपभोग भी मूल्य यंत्र से प्रभावित होते हैं। पू जीवादी व्यवस्था में मूल्ययंत्र की इस भट्ठा के कारण ही इसे 'मूल्य द्वारा शासित प्रणाली' भी कहते हैं।

(७) समन्वय का अभाव (Lack of co ordination)—पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक क्रियाओं में समन्वय का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि 'जिस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार समन्वय का कार्य करती है, उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में समन्वय करने के लिए कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं होती।' अतः केन्द्रीय निर्देशन या नियोजन के अभाव में उपभोक्ताओं की मांग तथा पूर्ति में कोई समन्वय स्थापित नहीं होता, यह सब मूल्य यंत्र द्वारा संचालित होता है। यदि कहीं निर्देशन या नियंत्रण होता है तो वह अपर्याप्त होता है।

(८) व्यापार चक्र (Trade cycles)—पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था की एक और प्रमुख विशेषता व्यापार चक्र का पाया जाना है, अर्थात् इसमें नियमित रूप से तेजी व मंदी (boom and depression) आती रहती है। जब उत्पादन वर्ष द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि किसी वस्तु या सेवा की मांग अधिक है तो वह लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी अधिकतम पूँजी का विनियोग कर देता है। इसी प्रकार अन्य उत्पादक भी मही करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का उत्पादन मांग की तुलना में अधिक हो जाता है। अतः अति-उत्पादन (over production) की स्थिति पैदा हो जाती है।

इसके विपरीत यदि कम उत्पादन हो जाता है तो उपभोक्ताओं को वस्तुएँ प्राप्त करने में कठिनाई आती है, और वस्तु के लिए ऊँचा मूल्य देना पड़ता है। इस प्रकार पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था में 'अधिक उत्पादन' और 'कम उत्पादन' का चक्र चलता रहता है।

(९) साहसी का महत्व (Importance of entrepreneur)—पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था में साहसी को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसका कारण यह है कि इस व्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता अधिक पाई जाती है, जिससे उत्पादन का कार्य जटिलमय हो जाता है। साहसी इन जोखिमों को झेवता है। वह उत्पत्ति के माध्यमों को उत्पादन कार्य में लगाये रखता है तथा उनके समन्वय स्थापित करता है।

(१०) आत्मघाती प्रकृति (Self destructive nature)—पू जीवादी व्यवस्था स्वयं आत्मघाती होती है अर्थात् यह व्यवस्था 'स्वयं अपने विनाश के बीज बोये रहती है'। इस व्यवस्था में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील रहता है। लाभ

कमाने के लिये वह विनियोग अधिक करता है तथा इस बात का प्रयत्न करता है कि अधिक-से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कम लागत पर कर सके। इसके परिणामस्वरूप अधिक उत्पादन (over-production) हो जाता है और मन्दी की स्थिति आ जाती है। इससे उत्पादक को हानि उठानी पड़ती है।

दूसरी ओर पू जीवादी व्यवस्था में सम्पत्ति कुछ ही हाथों में केन्द्रित होती जाती है। अमीर ओर अधिक अमीर बन जाता है गरीब ओर अधिक गरीब। इसमें श्रमिकों की समस्या बढ़ती जाती है, ओर पू जीवविषयों की सट्टा कम होती जाती है, जिससे श्रमिक संगठित होकर पू जीवविषयों द्वारा किये जा रहे शोषण के विरुद्ध उठ खड़े होने हैं और पू जीवादी व्यवस्था को तहस नहस कर नई व्यवस्था समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना करत हैं। इस तरह पू जीवाद को समाप्ति का कारण पू जीवाद ही है। मार्क्स (Marx) ने इन 'स्वचालित विनाश का नियम' कहा है।

पू जीवादी अर्थ व्यवस्था के गुण (Merits of Capitalist Economy) ^{अथवा} **हानियाँ**

पू जीवाद के समर्थकों द्वारा इन व्यवस्था में निम्नलिखित गुण बताये जाते हैं —

✓(१) स्वयं संचालित (Automaticity) — पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था स्वयं संचालित अर्थ-व्यवस्था होती है, आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए किसी केन्द्रीय नियंत्रण इकाई की आवश्यकता नहीं होती। इस व्यवस्था में उत्पादक लाभ की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। किस वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन होना चाहिए इसका निर्णय उत्पादक मूल्य यंत्र (price mechanism) की सहायता से करता है। मूल्य यंत्र एक अदृश्य हाथ (invisible hand) की तरह कार्य करता है, और स्वयं ही बायिक इकाइयों में समन्वय स्थापित हो जाता है।

✓(२) बड़ी मात्रा में उत्पादन 'Large scale production' — पू जीवादी व्यवस्था में उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। उत्पादक हमेशा यह प्रयत्न करता है कि बाजार में वह अपनी वस्तुओं को अधिकतम मात्रा में बेचकर लाभ अर्जित करे। इसके लिए वह नयी-नयी तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करता है। उत्पादन अधिक मात्रा में करने से एक तो उसका बाजार पर नियंत्रण स्थापित होता है, दूसरी ओर वस्तु के उत्पादन में बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में उपभोक्तृओं को भी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उपभोक्तृ वस्तु को सस्ते मूल्य पर प्राप्त कर लेते हैं।

✓(३) जीवन-स्तर में वृद्धि (Improvement in the standard of living) — पू जीवादी व्यवस्था की महत्वपूर्ण सफलता यह है कि इसके द्वारा अधिक प्रगति तेजी में होती है तथा नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार होता है। इस व्यवस्था में उत्पादन बड़ी

माना में होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं की सरया भी काफी अधिक होती है, जिससे उपभोक्ताओं का वस्तुओं उपभोग के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उत्पादक लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है, अतः उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिससे प्रत्येक उत्पादक बाजार में नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर उत्पादित करने के लिये प्रयत्नशील रहता है, इससे उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है जिससे उपभोक्ता के रहन सहन में वृद्धि होती है।

प्रो शुम्पीटर (Prof Schumpeter) के अनुसार—“सस्ते सूती एवं रेशमी वस्त्र, जूते, मोटरकार आदि ऐसी वस्तुएँ हैं जो पू जीवादी उत्पादन की विशिष्ट देन हैं, और यह ऐसी वस्तु नहीं है जो केवल धनी व्यक्तियों तक ही सीमित हो। ...

पू जीवादी प्रणाली आकस्मिक कारणों से नहीं बल्कि अपनी कार्य-प्रणाली की विशिष्टता के कारण जनसाधारण के जीवन-स्तर में वृद्धि करती है।”

✓(४) लचीलापन (Flexibility)—पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था का प्रमुख गुण इसका लचीलापन है। पू जीवादी व्यवस्था परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर स्वयं में भी परिवर्तन करके परिस्थितियों के अनुकूल बना लेती है। इसका कारण यह है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है अतः आवश्यकतानुसार परिस्थितियों के अनुकूल उनका उपयोग करते हैं, जिससे साधनों में पर्याप्त गतिशीलता आ जाती है।

लुक्स तथा हूट (Luxes and Hoot) के शब्दों में—पू जीवादी व्यवस्था में लचीलापन तथा समय-अनुकूलता होती है जिसके कारण ही इसने परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों का अनुकूल अपनी रीतियों और विधियों को ढाल लिया है।”

✱(५) उपभोक्ता की सार्वभौमिकता (Consumer's sovereignty)—पू जीवादी अर्थ व्यवस्था में उत्पादक निजी लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। उसे लाभ अधिकतम उसी स्थिति में प्राप्त होगा जबकि वह वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ताओं की रचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप करे। अतः उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत देव रेख की जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता की प्रभुता स्थापित हो जाती है।

(६) साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग (Fullest use of resources)—पू जीवादी अर्थ व्यवस्था में उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त

8 “It has possessed a flexibility, an adoptability and a resiliency which have permitted it to mould its forms and processes into conformity with innumerable changes in the environmental setting”

—Luxes and Hoot

करने के उद्देश्य से उत्पादन के नये-तरीकों और विधियों को अपनाते हैं, जिससे कि उत्पादन लागत कम हो जाय। इसके साथ ही उत्पादकों का यह प्रयास होता है कि अवशिष्ट पदार्थों का भी अधिकतम उपयोग हो सके। पूँजीपति या उत्पादक स्वयं भी मितव्ययता को अपनाता है। इन सबके फलस्वरूप उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होती है तथा समाज और राष्ट्र को भी लाभ प्राप्त होता है।

✓ (३) योग्यता की विजय (Survival of the fittest)—पूँजीवादी व्यवस्था प्रतियोगिता (competition) पर आधारित है। प्रतियोगिता में बहो विजयी हो सकता है जो योग्यता से या सबसे अधिक बलशाली हो। अब उत्पादन के क्षेत्र में केवल वे ही साहसी टिक पाते हैं जो कि योग्य, कुशल और दूरदर्शी हों। इस प्रकार साधनों का दुरुपयोग नहीं हो पाता क्योंकि अकुशल और अयोग्य साहसी बाजार में नहीं रहते। इसके अतिरिक्त समाज को भी लाभ प्राप्त होता है।

✓ (८) आर्थिक स्वतंत्रता (Economic freedom)—पूँजीवादी वर्ग व्यवस्था में सरकार द्वारा मनुष्य की क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता, अर्थात् व्यक्तियों को आर्थिक व राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार व्यवसाय का चुनाव करता है तथा उपभोक्ता अपनी पसन्द की वस्तुओं का उपभोग करता है।

डॉ० कुमारप्पा (Dr. Kumarappa) के शब्दों में—“इस प्रणाली की सबसे आकर्षक विशेषता यह है कि व्यक्ति को कार्य का चुनाव करने की स्वतंत्रता को स्वीकार किया जाता है, और इसे ही केन्द्र बनाया जाता है।”

आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ इस व्यवस्था में राजनैतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। इस स्वतंत्रता में इस बात को महत्व प्राप्त होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण न हो सबको सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक न्याय प्राप्त हो।

✓ (९) वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति (Scientific and technological progress)—पूँजीवादी व्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित है। बाजार में बहो साहसी टिक पाता है जो कि कुशल हो तथा अपनी वस्तु को कम लागत पर उत्पादित कर उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर श्रेष्ठ वस्तु उपलब्ध करा सके। अब हम व्यवस्था में प्रत्येक साहसी दूसरे साहसी से अग्रिम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यह प्रयत्न करता है कि वह अपनी फर्म या कारखाने में अन्वेषण (invention) और अनुसंधान (research) कार्य कराये। जिससे उसे नये-नये तरीकों का ज्ञान हो सके और उत्पादन में उनका प्रयोग करके कम लागत पर वस्तु बाजार में ले आये। यदि साहसी इसमें सफल नहीं हो पाता है तो थोड़े समय पश्चात्

उसे बाजार से बाहर जाना होता है। इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था में निरन्तर तकनीकी प्रगति होती रहती है।

(१०) पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन तथा अधिक उत्पादन (Encouragement to capital formation and more production) पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में निजी सम्पत्ति का अधिकार रहता है जो कि बचत और विनियोग दोनों को प्रोत्साहित करता है। लाभ प्राप्ति की स्वतन्त्रता के कारण व्यक्ति अधिक बचत करके उत्पादन कार्यों में लगा देता चाहता है, जिससे कि उसके लाभ में वृद्धि हो सके। इस प्रकार इस व्यवस्था में बचत व उत्पादन दोनों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

(११) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (International co-operation)—पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन घटे पैमाने पर किया जाता है तथा मधे-मधे अधिकारों व तकनीक का प्रयोग करके लागत को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ एक देश तक ही सीमित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त एक देश का साहसी अपनी वस्तु के लिये कच्चा माल आदि सामग्री दूसरे देशों से भी प्राप्त करता है। इस प्रकार आपस सहयोग में वृद्धि होती है और सम्भावनापूर्ण वातावरण बनता है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि आज विश्व के अनेक देशों में पूँजीवादी व्यवस्था पाई जाती है।

पूँजीवाद के दोष (Demerits of Capitalism) :

पूँजीवाद में अनेक गुण हैं लेकिन ये गुण सैद्धान्तिक अधिक हैं। व्यवहार में पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के दोष इतने गम्भीर हैं कि कोई भी विकासशील या अल्पविकसित देश इस व्यवस्था को अपनाने का साहस नहीं जुटा पाता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख दोष पाये जाते हैं—

(१) आर्थिक असमानता (Economic inequalities)—पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह व्यवस्था आर्थिक असमानता को जन्म देती है तथा जैसे-जैसे इसका विकास होता जाता है वैसे वैसे आर्थिक असमानताएँ और अधिक बढ़ती जाती हैं। इस आर्थिक असमानता का कारण व्यक्ति को सम्पत्ति प्राप्त करने की स्वतन्त्रता, उत्तराधिकार के नियम तथा समाज में अवसरों की असमानता है। इस व्यवस्था में अमीर और अधिक अमीर बन जाता है तथा गरीब और अधिक गरीब। अतः समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में—अमीर (haves) तथा गरीब (have nots)—में बंट जाता है। गरीब वर्ग में श्रमिक होते हैं जिनको जीवनयापन की सुविधायें प्राप्त करने में भी कठिनाई आती है, जबकि धनी ऐशो-व्याराम की जिन्दगी व्यतीत करते हैं।

जी डी एच कोल (G D H Cole) के शब्दों में — “उद्योग के मन्दिर में सुन के नाम पर पुजारी तथा दासों में जमीन आसमान का अन्तर पाया जाता है । ”

यह असमानता का जन्म निरन्तर चलता रहता है, और इसका प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ी (next generation) पर भी पड़ता है ।

२) वर्ग-संघर्ष (Class conflict)—पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभक्त हो जाता है—सम्पन्न वर्ग (haves तथा असम्पन्न (have nots) । एक के पास अधिक शक्ति होती है दूसरा कम शक्ति का होता है जो कि निषेध होता है । इन दोनों वर्गों का उद्देश्य अपने अपने हितों की पूर्ति करना होता है । दोनों वर्गों में हितों में अन्तर होने के कारण आपस में संघर्ष होता रहता है जिसके कारण औद्योगिक तथा सामाजिक अस्थिरता बनी रहती है ।

(३) व्यापार चक्र (Trade cycles)—पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था का एक प्रमुख दोष समाज में व्यापार चक्र का पाया जाना है । व्यापार चक्र उत्पन्न होने का कारण माग और पूर्ति का असमायोजन है । इस व्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सत्ता का अभाव होता है । प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से उत्पादन करता है । इसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और कभी तेजी (booms) और कभी मन्दी (depression) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार पूजीवादी व्यवस्था में मन्दी व तेजी एक निश्चित समय के बाद आती रहती है, तथा यह अर्थ-व्यवस्था का एक सामान्य स्वभाव बन जाती है ।

(४) असंतुलित विकास (Unbalanced growth)—पूजीवादी व्यवस्था में उत्पादक स्वतन्त्रतापूर्वक अपने लाभ में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते हैं । प्रायः उन्हीं क्षेत्रों में उद्योग घरे स्थापित करते हैं जहाँ पर कि उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण हो तथा उनके लिए लाभशायक हो । इस तरह एक ही स्थान पर उद्योग घरे केन्द्रित हो जाते हैं, तथा दूसरे क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता । इसके अतिरिक्त उत्पादक सभी प्रकार के उद्योग घरे में रुचि न रखकर उन्हीं उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं जिनमें लाभ का प्रतिशत अधिक प्राप्त होता है । अतः कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों का विकास अधिक हो

9 'There is a world of difference in terms of happiness between the high priest and the slaves in the temple of industry'

—Prof G D H Cole

जाता है, जबकि दूसरे उद्योग उपेक्षित रहते हैं। इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था में पर्याप्त क्षेत्रीय असमानताये पाई जाती हैं।

- (५) एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ (Monopolistic tendencies)—यद्यपि पूर्ण प्रतिযোগिता पूँजीवादी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, परन्तु व्यवहार में एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ देसने को अधिक मिलती हैं। उत्पादक प्रायः प्रतियोगिता से बचने के लिए तथा अपने लाभों में वृद्धि करने के उद्देश्य से एकाधिकारी संघों या औद्योगिक संघों की स्थापना कर लेते हैं। इससे प्रतियोगिता कम हो जाती है, और उपभोक्ता से अपने उत्पादों का ऊँचा मूल्य वसूल किया जाता है।

- (६) आर्थिक शोषण (Economic exploitation)—पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादकों का प्रधान उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे श्रमिकों को उनका पारिश्रमिक कम देते हैं तथा उनसे कार्य अधिक लेते हैं। इस प्रकार श्रमिकों का शोषण कर अपने लाभ में वृद्धि करते हैं। उत्पादकों द्वारा श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्य बहुत कम किये जाते हैं जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। इसके साथ ही उत्पादकों द्वारा एकाधिकारी संघों की स्थापना कर ली जाती है, जिससे श्रमिकों को वस्तुओं उचित मूल्य पर प्राप्त नहीं हो पाती। इस प्रकार इस व्यवस्था में मानवीय पक्ष का अभाव पाया जाता है।

प्रो० लेबिस (Prof. Lewis) के शब्दों में—“वाज़ार तन्त्र के मजदूरी सम्बन्धों (wage relations) में मानवीयता का अभाव पाया जाता है।”^{१०}

- (७) बेरोजगारी (Unemployment)—पूँजीवादी व्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या निरन्तर बनी रहती है। यह इस व्यवस्था का एक प्रमुख दोष है।

प्रो० पीगू (Prof. Pigou) के शब्दों में—“पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था का सबसे गम्भीर दोष बेरोजगारी है।”^{११}

इसका कारण यह है कि व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के लिए थोड़े से पूँजीपतियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये पूँजीपति अपनी स्वार्थप्रेरित योजना के अनुसार ही कार्य करते हैं। प्रायः यह दृष्टा जाता है कि पूँजीपति श्रमिकों को कभी भी अपने

10 “The market mechanism does not harmonise the wage relations”

—Prof Lewis

11 “The most serious evil in the capitalist economic system is the evil of unemployment”

—Prof Pigou

रोजगार से अलग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में स्वतन्त्रता का अधिकार हास्यास्पद बन जाता है। पूँजीवादी व्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त करने में सर्वत्र असमर्थ रही है। सर्वाधिक विकसित देश अमेरिका में भी बेरोजगारों की संख्या काफी है। इसी कारण आधुनिक समय में अधिकांश देश समानवाद की ओर झुक रहे हैं।

(८) अपव्यय (Wastage)—पूँजीवादी व्यवस्था में प्रतियोगिता पाई जाती है। इस प्रतियोगिता के कारण उत्पादकों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में साधनों का अपव्यय प्रचार तथा विज्ञापन आदि पर किया जाता है। कभी-कभी घनेक फर्मों के द्वारा एक-सी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जिससे साधनों का अपव्यय होता है। इसके अतिरिक्त बड़ी फर्में दूसरी प्रतिযোগी फर्मों को समाप्त करने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में अधिक साधनों का दुरुपयोग करती हैं। इस प्रकार यह अपव्यय समाज के हित में नहीं होता।

(९) सामाजिक परजीविता (Social parasitism)—पूँजीवादी व्यवस्था में एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो कि बिना कुछ कार्य किये अपनी जीविका खलाता रहता है। इसका कारण यह है कि कुछ व्यक्तियों को अपने पूर्वजों से वन में सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वे अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं इस प्रकार ये 'परजीवी' बन जाते हैं।

(१०) समाज कल्याण का अभाव (Lack of social welfare)—पूँजीवादी व्यवस्था में प्रत्येक कार्य 'निजी लाभ' के लिए किया जाता है, समाज कल्याण के कार्यों की ओर कोई ध्यान देने की तैयारी नहीं होती। इस प्रकार, इस व्यवस्था में कल्याणकारी उद्देश्यों का अभाव पाया जाता है।

(११) उपभोक्ता की सार्वभौमिकता मिथ्या है (Consumer's sovereignty is a myth)—पूँजीवादी व्यवस्था का यह गुण बताया जाता है कि यहाँ पर उपभोक्ता 'राजा' होता है। परन्तु व्यवहार में यह पूर्णतः असत्य सिद्ध होता है। पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं को विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से किसी वस्तु विशेष की ओर आकर्षित किया जाता है जिससे उपभोक्ता की पसन्द को प्रभावित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादक एकाधिकारी संघों की स्थापना कर लेते हैं जिससे उपभोक्ता को वस्तु के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। अतः उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूँजीवादी व्यवस्था में अनेक दोष हैं।

निष्कर्ष (Conclusion) •

पू जीवादी आर्थिक व्यवस्था के दोषों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रणाली अधिक समय तक नहीं चल सकती। परन्तु वास्तविकता यह है कि आज के युग में पुराने पू जीवाद का केवल सैद्धांतिक महत्व रह गया है। पू जीवादी व्यवस्था का प्रमुख गुण परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल लेना है। आज के पू जीवाद में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं जिनके कारण ही आज यह जीवित है। आज पू जीवादी देशों में आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। बाजार व्यवस्था में सरकार का घुसग रहता है तथा सरकार सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए अनेक नीतियाँ निर्धारित करती है तथा उनका कठोरतापूर्वक पालन कराती है। श्रमिकों का शोषण कम करने तथा उनके कल्याण में वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएँ बनाती है।

अतः पू जीवादी व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हो जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पू जीवाद का निवृत्त भविष्य में लोप होना सम्भव नहीं है।

पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था और मूलभूत आर्थिक समस्याएँ (Capitalist Economy and Fundamental Economic Problems)

प्रत्येक अर्थ व्यवस्था की कुछ मूलभूत समस्याएँ होती हैं, जिनको कि उसे हल करना होता है। हल करने का तरीका आर्थिक प्रणाली में भिन्नता होने के कारण भिन्न भिन्न हो जाता है। पू जीवादी अर्थ व्यवस्था जिसे स्वतन्त्र उपक्रम अर्थ-व्यवस्था (free enterprise economy) भी कहते हैं, इस की अपनी कुछ अलग से विशेषताएँ होती हैं। इस व्यवस्था में व्यक्ति को आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है तथा निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार प्राप्त होता है। अतः पू जीवादी व्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाएँ 'लाभ' प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं। इस व्यवस्था में समन्वय या नियंत्रण हेतु केन्द्रीय सत्ता नहीं होती, अपितु समस्त आर्थिक क्रियाएँ 'मूल्य यन्त्र' (price mechanism) द्वारा संचालित होती हैं।

नीचे विस्तार से इस बात की व्याख्या की गई है कि किस प्रकार 'मूल्य यन्त्र' अर्थ-व्यवस्था की मूलभूत आर्थिक समस्याओं (आर्थिक प्रणाली के आधारभूत कार्यों) को हल करता है —

१ किस वस्तु का उत्पादन किया जाय ? (What is to be produced)

पू जीवादी व्यवस्था में मूल्ययन्त्र द्वारा ही यह निर्धारण होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाय। इस व्यवस्था में कीमतों के द्वारा उपभोक्तियों की रचियों तथा आवश्यकताओं का पता लगना है। उत्पादक का उद्देश्य 'लाभ' प्राप्त करने का होता है अतः वह उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जो कि उपभोक्तियों द्वारा पसन्द की जाती हैं।

उपभोक्ताओं की पसन्दगी या रचियों की बाजार कीमतों में व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः उपभोक्ता उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक मूल्य देने को तैयार होगा जिनको वह अधिक पसन्द करता है, तथा उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए कम मूल्य देने को तैयार होगा, जो कि उसकी रचि या पसन्द के अनुसूल नहीं है। अतः उत्पादकों द्वारा उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जायेगा जिनको उपभोक्ताओं द्वारा प्रिय किया जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसी ही वस्तुमें उत्पादक को अधिक मूल्य प्रदान करती है।

कितनी वस्तु के लिए दिये जाने वाले अधिक मूल्य दो स्थितियों को स्पष्ट करते हैं :—

- (१) उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक पसन्द करते हैं और इच्छा व्यक्त करते हैं कि वह वस्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध हो।
- (२) ऊँचे मूल्य उत्पादकों को अधिक लाभ की संभावना व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक मात्रा में उत्पादन करने से प्रति इकाई लागत भी कम हो जाती है।

पूँजीवादी व्यवस्था में, जहाँ पर आर्थिक क्रियायें मूल्य यन्त्र द्वारा संचालित होती हैं, उपभोक्ता की प्रभुता प्राप्त होती है क्योंकि उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जो उपभोक्ता चाहते हैं तथा उन वस्तु का उत्पादन नहीं करते जिस वस्तु की माग कम होती है। परन्तु इसकी कुछ सीमायें हैं —

- (१) उपभोक्ता की भाग की विज्ञापन व प्रसार के द्वारा उत्पादक प्रभावित करते हैं, अतः उपभोक्ता पूर्ण स्वतन्त्र होकर निर्णय नहीं ले पाता।
- (२) उपर्युक्त विश्लेषण केवल यह बताता है कि 'मूल्य यन्त्र' द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं करता कि वस्तुओं का निर्धारण (वस्तुओं का मूल्यांकन) कैसे होना चाहिए, यह प्रश्न नैतिक है, जिसकी मूल्य सिद्धांत व्याख्या नहीं करता। परन्तु इस दृष्टिकोण की अपेक्षा करना उचित नहीं है। मूल्य यन्त्र की क्रियाओं द्वारा यह सम्भव है कि इसमें निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा धनी व्यक्तियों की वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो, दूसरे शब्दों में, कम आय वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को वस्तुओं के स्थान पर अधिक आय वाले व्यक्तियों की विलासता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो। इस स्थिति को प्रो. सेप्टविच ने स्पष्ट किया है।

प्रो० सेप्टविच के शब्दों में—“मूल्य प्रणाली पूर्ण रूप से कार्य करते हुए ऐसे

सामाजिक परिणाम ला सकता है जिह कि हम अवाछनीय समझे और राजनैतिक प्रक्रिया के द्वारा सुधारने का प्रयत्न करें।^{१२}

२ वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाय ? (How shall the good be produced ?)

पू जीवादी अथ व्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन संगठन 'मूल्य प्रणाली' के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर यह नियम करना होता है कि उत्पादन काय किन विधियों और तरीकों से किया जाय। इस व्यवस्था में उत्पादक उन विधियों और तरीकों का प्रयोग करता है जो अधिकतम लाभ प्रदान करें। अब एक बार उत्पादक ऊँचा मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तथा दूसरी ओर लागत घटाने का प्रयत्न करता है, ऐसी दशा में —

- (१) जिन उद्योगों में वस्तु की माग अधिक होगी, उन उद्योगों की वस्तु के मूल्य भी ऊँचे होंगे और उत्पादक अपने साधनों को इन उद्योगों में प्रयुक्त करेंगे। तथा जिन उद्योगों की वस्तु की माग कम होगी वहाँ पर साधन भी कम प्रयुक्त किए जाएंगे।
- (२) प्रतिस्पर्धा होने के कारण बाजार में वही फर्क रह पाती है जो कि कुशलतापूर्वक उत्पादन करती है। इस व्यवस्था में साधना का खुद बाजार हाथ है, और प्रत्येक साधन का बाजार मूल्य होता है। अब इन बाजार मूल्यों के आधार पर उत्पादक विभिन्न विधियों की जाँच की तुलना कर लेते हैं, और जिस विधि के द्वारा अधिकतम लाभ मिलेगा उसी विधि के द्वारा उत्पादन किया जाता है।

३ वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाय ? (For whom shall the goods be produced ?)

पू जीवादी अथ व्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का वितरण भी मूल्य प्रणाली के द्वारा होता है। वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है और बाजार में वस्तुयें वही क्रय कर सकेंगे जिनके पास क्रयशक्ति होगी, अर्थात् उत्पादन का वितरण वैयक्तिक आय (personal income) पर निर्भर करता है। इस व्यवस्था में जिनके पास अधिक सम्पत्ति है पर जिनकी आय अधिक है वे अधिक वस्तुयें प्राप्त करेंगे तथा जिनकी आय कम है वे कम वस्तुयें प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार साधन सम्पन्न वर्ग कुल उत्पादन का एक बड़ा भाग प्राप्त करता है तथा साधनहीन वर्ग को अधिक बड़ा होता है, कुल उत्पादन का छोटा भाग प्राप्त करता है।

- 12 'The price system in such a situation, though working perfectly, may lead to social consequences that we consider undesirable and attempt to rectify through the political process'

— Prof Leftwich

उत्पादन के वितरण के सम्बन्ध में मूल्य प्रणाली का वाई नैतिक बलव्य नहीं होता अतः आय के वितरण की असमानता होने के कारण उत्पादन के वितरण में भी काफी अधिक विषमता पाई जाती है। अर्थात् साधनों का वितरण असमान होने से उत्पादन का वितरण अत्यन्तपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार का वितरण सामाजिक व नैतिक दृष्टि से उचित नहीं होता। इसलिए पूजीवादी अथ व्यवस्था में सरकार द्वारा कुछ सरोजन किए जाने हैं परन्तु इन सरोजनो में मूल्य प्रणाली के कार्य को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया जाता। सरकार के द्वारा आय का पुनर्वितरण करने के उद्देश्य से प्रगतिशील कर लगाये जाते हैं तथा कल्याणकारी कार्यों पर अधिक व्यय किया जाता है।

उपरोक्त सीमा समस्याएँ एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और पूजीवादी व्यवस्था में इन सीमा का संचालन मूल्य प्रणाली द्वारा किया जाता है। परन्तु वर्तमान में पूजीवादी अथ व्यवस्था के रूप में परिवर्तन होने के कारण कुछ सीमा तक सरकारी हस्तक्षेप भी रहता है। सरकारी हस्तक्षेप का प्रमुख कारण कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करना होता है।

१ अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ पूजीवादी अथ व्यवस्था से क्या अभिप्राय है ? पूजीवाद के गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए।
- २ पूजीवाद की परिभाषा कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
- ३ पूजीवाद की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ? क्या पूजीवाद आज के युग में व्यावहारिक है ?
- ४ एक आर्थिक प्रणाली के क्या कार्य हैं ? पूजीवादी अथ व्यवस्था में ये कार्य किस प्रकार सम्पन्न किये जाते हैं ?
- ५ निम्नलिखित विवेचन कीजिए
 - (अ) पूजीवाद औद्योगिक क्रान्ति की देन है।
 - (ब) पूजीवाद में साधनों का अपव्यय होता है।
 - (स) पूजीवाद स्वयं अपने विनाश के बीज बोए रहता है।
 - (द) पूजीवाद में नाश का उद्भव ही सर्वोपरि है।

अध्याय ५

★

समाजवाद

[Socialism]

★ ★ ★

समाजवाद का जन्म मुख्यतः पूँजीवादी व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक विषमता और शोषण, बेरोजगारी, बर्ग-भेद आदि दोष पाये जाते हैं, जिनके विरोध में इंग्लैंड, फ्रांस व जर्मनी ने विज्ञान विचारकों ने आवाज उठाई। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। मार्क्स के बाद इस विचारधारा का विस्तार हुआ और आज सत्तर के प्रत्येक कोने से समाजवाद के समर्थकों की आवाज आती है। विद्वान का अपने से अधिक भाग आज समाजवादी हो चुका है।

समाजवादी विचारधारा के प्रारम्भ से लेकर आज तक जितने प्रवक्ता एवं विचारक हुए हैं, उनके विचारों में काफी विभिन्नता पाई जाती है। जिनके कारण आज समाजवाद के सम्बन्ध में सामान्य परिभाषा देना सम्भव नहीं है।

प्रो जोड (Prof C E M Joad) ने इस स्थिति को दलकर कहा है—
“समाजवाद के अनेक प्रवक्ताओं के कारण, जिनमें राजनैतिक विचारक भी सम्मिलित हैं, समाजवाद का साहित्य इतना विशद हो गया है कि यह बताना भी कठिन हो जाता है कि समाजवाद क्या है? संक्षेप में समाजवाद एक ऐसी दौरी की तरह है जिसकी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के पहचान के कारण निगूढ़ गई है।”

‘As the advocates of socialism are very numerous and many of them have been first rate political pamphleteers, the literature of the subject is enormous, with the result that it is hard to say in what exactly it is that socialism consists. Socialism in short, is like a hat that has lost its shape because everybody wears it.’

—Prof C E M Joad

विचारों की मिश्रता के कारण विभिन्न विद्वानों ने समाजवाद की विभिन्न परिभाषायें दी हैं। इनमें से कुछ परिभाषायें निम्नलिखित हैं।

तुगन बरानोवस्की (Tugan Baranowsky) के अनुसार— 'समाजवाद का सार यह है कि इससे अन्तर्गत समाज में किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होता। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था लाभ पर आधारित है, लेकिन समाजवाद में उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण का होता है। बस्तुओं का उत्पादन समाज की उपयोगिता के आधार पर ही किया जाता है।'^२

इस परिभाषा में शोषणरहित समाज एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण को समाजवाद का आधार माना गया है। यह परिभाषा उचित प्रतीत होती है।

प्रो वेब एव वीमबी वेब (Prof Webb and Mrs Webb) के शब्दों में— "सामाजीकरण का मूल्य लक्षण यह है कि उद्योगों एवं सेवाओं तथा उत्पादन के साधनों, जिनकी आवश्यकता हो, पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व नहीं होना चाहिए तथा औद्योगिक एवं सामाजिक प्रशासन का सगठन निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए।"^३

यह परिभाषा दो बातें स्पष्ट करती है —(१) उत्पादन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए तथा (२) कार्य लाभ के उद्देश्य से नहीं होने चाहिए।

प्रो डिकिन्सन (Prof Dickenson) के अनुसार— "समाजवाद समाज का एक ऐसा अधिक सगठन है, जिसमें उत्पादन के भौतिक साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है और उनका संचालन एक सामान्य योजना के अन्तर्गत ऐसी सहायकों द्वारा किया जाता है जो नि समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा समाज के प्रति उत्तर-

- 2 "The essence of socialism lies in the absence of exploitation of any individual in the society. The present economic system is based on the profit motive. But under socialism it aims at the maximum welfare of all. The production of commodities is on the basis of their utility of the community."

—Prof Tugan Baranowsky

- 3 "The essential feature in socialisation is that industries and services, with the instruments of production, which they require, should not be owned by individuals and that industrial and social administration should not be organised for the purpose of obtaining private profit"

—Prof. Webb and Mrs. Webb

दायी होती है। सामाजिकृत नियोजित उत्पादन से जो लाभ प्राप्त होते हैं उनको समाज के सभी व्यक्ति समानता के आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं।^{१४}

यह परिभाषा तीन बातें स्पष्ट करती है —(अ) उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व, (ब) एक सामान्य योजना के अनुसार उत्पादन, (स) समानता के आधार पर आम का वितरण। इन विशेषताओं के कारण ही डिक्किन्सन की परिभाषा को एक श्रेष्ठ परिभाषा माना जाता है।

उपरोक्त परिभाषाओं से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि समाजवादी व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था से पूर्णतः भिन्न है। समाजवादी व्यवस्था में निजी स्वामित्व को कोई स्थान प्राप्त नहीं होता तथा समस्त आर्थिक क्रियाएँ सम्पूर्ण समाज के लाभ के लिए संचालित की जाती हैं।

समाजवाद की विशेषताएँ (Salient Features of Socialism)

समाजवाद की उपरोक्त परिभाषाओं में यद्यपि भिन्नता है फिर भी इनसे समाजवाद की प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं। समाजवाद की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व (Social or Government's ownership on the factors of production) — समाजवादी व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उत्पादन के साधनों पर सरकार या समाज का स्वामित्व होता है। इसमें व्यक्तियों को प्रायः निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं होता और न ही निजी लाभ के उद्देश्य से उत्पादन के साधनों का उपयोग राज्य द्वारा सामूहिक हित के लिए किया जाता है।

परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि समाजवाद में सभी वस्तुओं और साधनों पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होना। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र रह सकता है परन्तु वह महत्वहीन होता है।

- 4 Socialism is an economic organisation of society in which the material means of production are owned by the whole community and operated by organs representative of and responsible to the community according to a general plan all members of the community being entitled to benefits from the results of such socialised planned production on the basis of equal rights "

—Prof Dickinson

प्रो. लुक्स (Prof. Loucks) के अनुसार — “केवल बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, छोटे पैमाने पर सीमित मात्रा में उत्पादन निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।”

(२) आर्थिक नियोजन (Economic planning)—नियोजन समाजवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि हम कहे कि बिना नियोजन के समाजवाद सम्भव नहीं है तो अनिश्चयिता नहीं होगी। समाजवादी व्यवस्था पूर्णतः योजनाबद्ध होती है। इसका कारण यह है कि इस व्यवस्था में ‘मूल्य यंत्र’ (price mechanism) का संघर्ष अभाव होता है। इस व्यवस्था में उत्पादन करने का उद्देश्य सामाजिक लाभ में वृद्धि करना होता है, यद्यपि उन वस्तुओं का उत्पादन बन्द कर दिया जाता है जिनसे कम लाभ प्राप्त होता है और उन उद्योगों का विकास किया जाता है जहाँ लाभ में वृद्धि करते हैं। इस कार्य को नियोजन अधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

(३) सामाजिक कल्याण (Social welfare)—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन समाज के कल्याण में वृद्धि करने का उद्देश्य से किया जाता है। अतः आर्थिक क्रियाओं को पूँजीवादी व्यवस्था के समान स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जाता बल्कि उन क्रियाओं के निर्देशन और उनके बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य केन्द्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा एक निश्चित योजना के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार इस व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन न किया जाकर उपयोग के लिये उत्पादन किया जाता है जो कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि करता है।

(४) आर्थिक समानता (Economic equality)—समाजवादी व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर देना है। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत सम्पत्ति और लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे असमानताएँ अधिन नहीं होती। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत ‘प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वापस देना तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध कराना है।’ यद्यपि व्यवहार में आर्थिक असमानताएँ पूर्णतः समाप्त नहीं की जा सकती, परन्तु इस व्यवस्था में पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की अनेक समानता स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं।

(५) शोषण का निराकरण Elimination of exploitation)—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है तथा सरकार

अधिकतम कल्याण के उद्देश्य से उत्पादन कार्य करती है, अतः इस व्यवस्था में समाज पूँजीवादो अर्थात् व्यवस्था की तरह दो वर्गों—पूँजीपतियों और श्रमिकों—में विभाजित नहीं होता। इस कारण श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं हो पाता। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है तथा इसी को ध्यान में रखकर पारिश्रमिक दिया जाता है।

(६) प्रतियोगिता का अन्त (Elimination of competition)—समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन साधनों पर नियन्त्रण सरकार का होता है। सरकार या केन्द्रीय नियोजन सत्ता उत्पादन की मात्रा, वस्तुओं के प्रकार तथा उनकी कीमत का निर्धारण करती है। अतः इस व्यवस्था में बाजार में प्रतियोगिता नहीं पाई जाती।

(७) अर्जित आय की समाप्ति (End of unearned income)—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार कार्य करता है और उसे इसी आधार पर पारिश्रमिक प्रप्त होता है। जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है उसे आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अर्जित आय प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता।

(८) वर्ग संघर्ष की समाप्ति (Elimination of class-struggle)—समाजवादी व्यवस्था में समाज दो वर्गों पूँजीपति व श्रमिकों—में विभक्त नहीं होना, क्योंकि उत्पादन कार्य सरकार द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। अतः मालिकों व श्रमिकों में संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार औद्योगिक शांति बनी रहती है।

समाजवादी अर्थ व्यवस्था के गुण (Merits of Socialist Economy)

समाजवाद की ओर आज अधिकांश लोग आकृष्ट हुए हैं, इसका कारण पूँजीवाद के दोष हैं। समाजवाद के समर्थक विचारकों एवं अर्थशास्त्रियों का विचार है कि समाजवाद पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं —

(१) अधिक साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग (Maximum utilisation of economic resources)—समाजवादी अर्थ व्यवस्था में केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु देश के प्राकृतिक और आर्थिक साधनों का सतुलित ढंग से प्रयोग किया जाता है। निषाजित ढंग से साधनों का प्रयोग होने के कारण सभी साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता का जगह होता है, प्रत्येक व्यक्ति लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उत्पादन कार्य करता है। इसका परिणाम यह होता है

कि अनेक उत्पादक काम प्राप्त करने के लिये उत्पादन कार्य करना है, जिससे उत्पादन में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता तथा साधनों का अप्रयय भी होता है।

(२) सतुलित विकास (Balanced development) — समाजवादी अर्थ व्यवस्था में उत्पादन 'निजी लाभ' के लिए न किया जाकर सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अतः सामाजिक दृष्टि से लाभदायक सभी उद्योगों के विकास की योजना तैयार की जाती है, जिससे पिछड़े हुए भागों का भी विकास समान रूप से किया जाता है। आर्थिक नियोजन का सहारा लेने के कारण देश का विकास सतुलित ढंग से तो होना ही है, साथ ही-साथ विकास की गति भी तेज होनी है।

(३) व्यापार चक्रों का अन्त (Elimination of trade cycles) — समाजवादी अर्थ व्यवस्था में आर्थिक स्थिरता अधिक रहता है। इस व्यवस्था में केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और उनकी मांग में समन्वय स्थापित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप 'अधिक उत्पादन' (over production) या 'कम उत्पादन' (under production) की समस्या नहीं रहती, अर्थात् मंदी और तेजी की सम्भावनाएँ काफी कम हो जाती हैं। इस तरह समाजवादी व्यवस्था में व्यापार चक्रों का अन्त हो जाता है।

(४) बेरोजगारी का निराकरण (Elimination of unemployment) — समाजवादी अर्थ व्यवस्था में नियोजित ढंग से सभी कार्य होने के कारण बेरोजगारी की समस्या नहीं पैदा होती है। इस व्यवस्था में मुख्य उद्देश्य ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि और बेरोजगारी के निवारण का होना है। इसके विपरीत पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में व्यापार चक्रों की उपस्थिति के कारण बेरोजगारी की समस्या सदैव बनी रहती है। प्रो पीगू (Prof Pigou) ने इस सम्बन्ध में अपना मत निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है —

“बेरोजगारी की समस्या के समाधान में केन्द्रीय नियोजन से मुक्त समाजवादी व्यवस्था पूँजीवाद की तुलना में निश्चित रूप से लाभदायक स्थिति में है।”

(५) सामाजिक कल्याण में अधिकतम वृद्धि (Maximisation of social welfare) — समाजवादी अर्थ व्यवस्था में उत्पादन 'लाभ के उद्देश्य' से न किया जाकर 'व्यक्तियों के कल्याण' के उद्देश्य से किया जाता है इस व्यवस्था में उत्पादन करने समय जनता की

5 “For tackling the problem of unemployment, a socialist system with central planning has definite advantage over a capitalist one”
—Prof Pigou

आवश्यकता की वस्तुओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त समाजवादी व्यवस्था में नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, जैसे—वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी में सुरक्षा आदि की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है।

(६) आर्थिक असमानताओं में कमी (Reduction in economic inequalities)—पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था का प्रमुख दोष आय के वितरण की अत्यधिक विषमता है। समाजवाद इस दोष को दूर कर देता है। समाजवाद का प्रबल उद्देश्य आय के वितरण की असमानताओं को कम करना है। इस व्यवस्था के उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार का होता है, इसलिए केन्द्रीय सत्ता इस प्रकार आर्थिक नियमों का संचालन करती है कि आय असमानतायें न्यूनतम हो जायें। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तियों की आय में अन्तर केवल कार्यक्षमता के अन्तर में बराबर होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को समानता के आधार पर कार्य करने और विकास करने के अवसर प्राप्त होते हैं।

(७) शोषण का अन्त (Elimination of exploitation)—समाजवादी व्यवस्था में सभी आर्थिक साधनों पर सरकार का स्वामित्व या नियन्त्रण होता है, जिसके कारण समाज दो वर्गों में विभक्त नहीं हो पाता। राज्य आर्थिक साधनों का प्रयोग अधिकतम कल्याण के लिये करता है इसलिए व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण नहीं हो पाता।

(८) वर्ग-संघर्ष की समाप्ति (Elimination of class-struggle)—पूँजीवादी व्यवस्था में वर्ग-संघर्ष निरन्तर चलता रहता है, क्योंकि पूँजीपतियों और श्रमिकों के हित अलग अलग होते हैं। परन्तु समाजवादी व्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है अतः वर्ग विभाजन नहीं होता। वर्ग-विभाजन (पूँजीपति और श्रमिक) न होने के कारण औद्योगिक शांति भी बनी रहनी है।

(९) परजीविता का अन्त (End of parasitism)—समाजवाद में धननिगम सम्पत्ति पर नियन्त्रण लगा दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्तराधिकार में सम्पत्ति या धन किसी व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं होता। अतः कोई भी व्यक्ति अनाजित आय पर जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य अनिवार्य रूप से करना पड़ना है।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के दोष (Demerits of Socialist Economy) .

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के गुणों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह

व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, परन्तु यह व्यवस्था भी दोषरहित नहीं है। इसके प्रमुख दोष उल्लिखित हैं :—

(१) कुशलता तथा उत्पादकता में कमी (Lack of efficiency and productivity)—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में कुशलता तथा उत्पादकता का निम्न स्तर रहता है। इसका कारण यह है कि इस व्यवस्था में उद्योगों तथा व्यवसायों पर नियन्त्रण सरकारी अधिकारियों का रहता है और इन अधिकारियों का कोई निजी स्वार्थ न होने के कारण वे उत्पादन कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते। सरकारी कार्यों में साल पीतायाही (red-tapism) होने के कारण शीघ्र निर्णय भी नहीं लिये जा सकते तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा साहसपूर्ण जोखिम भी नहीं उठाया जाता। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की आय उनकी कुशलता और योग्यता के आधार पर प्राप्त नहीं होती बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित वितरण नीति के आधार पर दी जाती है। इन सभी कारणों से समाजवादी व्यवस्था में कुशलता तथा उत्पादकता का स्तर पूँजीवादी व्यवस्था की तुलना में निम्न रहता है।

(२) साधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग (Irrational utilisation of resources)—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादित के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि इसमें पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के समान कोई स्वचालित यन्त्र नहीं होता। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन की मात्रा, प्रकार आदि का निर्धारण केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय अधिकारियों को सभी आर्थिक निर्णय लेने होते हैं, इसलिए यह सम्भावना बनी रहती है कि मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाये। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का विचार है कि समाजवादी व्यवस्था में साधनों का वितरण किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया जाता बल्कि मनमाना होता है। इस कारण साधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग होता है।

(३) उपभोक्ता की सार्वभौमिकता में कमी (Loss of consumer's sovereignty)—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता समाप्त हो जाती है क्योंकि इन व्यवस्था में सरकार या केन्द्रीय सत्ता द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है कि किस वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन होगा। उपभोक्ता को केवल वे वस्तुएँ उपभोग के लिए प्राप्त होती हैं जो कि सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। जबकि पूँजीवाद व्यवस्था में उपभोक्ता की पसन्द तथा श्रृंखला के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है।

समाजवादी विचार इस आलोचना से सहमत नहीं है। उनका विचार है कि इस व्यवस्था में वित्तीयता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि उपभोक्ता

की सामान्य आवश्यकताओं को देखकर उत्पादन किया जाता है। जिससे साधनों का अपव्यय रहता है तथा उन वस्तुओं का उत्पादन भी नहीं होता जो कि समाज के लिए हानिकारक हैं या जो व्यक्तियों की कार्यक्षमता को कम कर देती है।

- (४) **व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अभाव (Loss of individual freedom)**—समाजवादी अर्थ व्यवस्था में व्यक्तियों की स्वतन्त्रता लगभग समाप्त हो जाती है। इस व्यवस्था में समस्त साधनों का उपयोग राज्य के आदेशानुसार होता है। अतः उत्पादन, उपभोग तथा वितरण में राज्य का नियन्त्रण होता है, और व्यक्ति का आर्थिक जीवन भी स्वतन्त्र नहीं होता। पूर्ण नियोजित अर्थ व्यवस्था होने के कारण सम्पूर्ण निर्णय कन्द्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तानाशाही को प्रोत्साहन मिलता है। इस व्यवस्था में किसी व्यक्ति को सरकार के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है तथा सरकार की आज्ञाकारी करने वालों को कठोर दण्ड भी दिया जाता है। विख्यात समाजवादी विचारक ट्रॉट्स्की (Trotasky) के शब्दों में

“वह देश जिसमें राज्य ही केवल नियोजता (employer) है, विरोध का अर्थ घेरे-घेरे झूठे रहकर मरना है। पुराना सिद्धांत है कि ‘जो कार्य नहीं करेगा नहीं खायेगा’ का स्थान नया सिद्धांत ले लेता है कि ‘जो आज्ञापालन नहीं करेगा नहीं खायेगा’।”^६

समाजवाद के प्रालोचकों का विचार है कि इस व्यवस्था में आर्थिक समानता के लिए प्रयत्न किये जाते हैं परन्तु ये प्रयत्न केवल दुःख और कठिनाइयों में ही समानता लाते हैं।

- (५) **प्रेरणा का अभाव (Absence of incentive)**—समाजवादी अर्थ व्यवस्था में उत्पादन के काम निजी लाभ के उद्देश्य से नहीं किये जाते इसलिए उत्पादन कार्यों में प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन कार्यों में नयी विधियों और आविष्कारों को भी अधिक प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादक को निश्चित वेतन प्राप्त होता है। अतः वह साहसपूर्वक जोखिम भी नहीं उठाता।

6 “In a country where the sole employer is the State, opposition means death by slow starvation. The old principle, he who does not work shall not eat has been replaced by a new one, he who does not obey shall not eat.”

समाजवादी विचारकों के अनुसार यह विचार प्रमात्‍मक है। उनका विचार है कि इस व्यवस्था में राष्ट्रीयता, देशप्रेम तथा स्वाभिमान आदि ऐसी प्रेरणाएँ हैं जो कि व्यक्ति को उत्पादन कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमतानुसार वेतन प्राप्त होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुशलता में वृद्धि करने के लिए प्रयत्‍नशील रहता है।

(६) निर्णयों का अभाव (Absence of decision making) — समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन, वितरण आदि के सभी निर्णय केन्द्रीय सत्ता द्वारा लिये जाते हैं और ये निर्णय नीकरशाही पर निर्भर करते हैं। नीकरशाही में अनेक दोष होने के कारण तथा व्यक्तिगत लाभ के अभाव में आर्थिक निर्णय शीघ्र नहीं लिये जाते जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन प्रभावित होता है।

समाजवादी विचारक इस बात से सहमत नहीं हैं, उनके अनुसार व्यवहार में यह बात पूर्णतः गलत सिद्ध हो जाती है। प्रायः समाजवादी देशों में विकास की गति अन्य देशों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, और यह तभी सम्भव है जबकि व्यक्तियों द्वारा निर्णय सही समय पर तथा तत्परता से किये जाते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होना है कि समाजवादी अर्थ व्यवस्था में अनेक दोष पाये जाते हैं, परन्तु जब पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था से इसकी तुलना करते हैं तो यह व्यवस्था अष्ट प्रतीत होती है। व्यवहार में यह देखने को मिला है कि समाजवादी व्यवस्था में देश के विकास की गति काफी तेज रहती है जिससे देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है तथा उसने नागरिकों का जीवन स्तर भी ऊँचा उठ जाता है। इसमें 'मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण' भी नहीं होता तथा प्रत्येक व्यक्ति को समानता के आधार पर सुविधायें प्रदान की जाती हैं। प्रो. शुम्पेटर (Schumpeter) ने समाजवादी व्यवस्था को पूँजीवादी व्यवस्था की तुलना में श्रेष्ठ बताया है। उनके अनुसार इस व्यवस्था में चार गुण पाये जाते हैं —

- (१) समाजवाद में राजकीय प्रवृत्ति के अन्तर्गत अधिक कुशलता पाई जाती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।
- (२) समाजवाद में व्यापार चक्रों का अभाव रहता है।
- (३) समाजवाद में एकाधिकारी आचरण (monopolistic practices) का अभाव पाया जाता है।
- (४) समाजवाद में आर्थिक असमानताएँ कम पाई जाती हैं जिससे आर्थिक कल्याण अधिक होता है।

समाजवाद की थोड़ना के कारण ही सत्सार के अधिकतर व्यक्तियों का मुक्त समाजवाद की ओर है। आज पूँजीवादी देशों में भी जनक प्रचलन आर्थिक समानताओं को कम करने के लिये किये जा रहे हैं जिससे कि उनके स्वरूप में भी समाजवादी तत्वों का धीमे धीमे प्रवेश होना जा रहा है। यह सब कारण समाजवाद की थोड़ना को प्रभावित करते हैं।

समाजवाद के विभिन्न स्वरूप (Different forms of Socialism)

उपयुक्त अध्ययन में हमने समाजवाद के सामान्य स्वरूप की व्याख्या की है। स्पेक्टाटोर में राबर्ट ओवन (Robert Owen) से लेकर आज तक के समाजवादी विचारकों ने इसका अनेक रूपों में प्रतिष्ठित किया है। प्रारम्भ से लेकर आज तक की समाजवादी विचारवादाओं को हम दो भागों में बाँट सकते हैं —

(१) विकासवादी समाजवाद (Evolutionary socialism),

(२) क्रान्तिकारी समाजवाद (Revolutionary socialism)।

दोनों ही विचारधारा के समाजवादियों के आदर्श व उद्देश्य समान हैं परन्तु उन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों में भिन्नता पाई जाती है। विकासवादी समाजवाद के विचारकों अपने उद्देश्यों की पूर्ति धीरे धीरे, शान्तिपूर्ण एवं वैधानिक तरीकों से करना चाहते हैं। क्रान्तिकारी समाजवादी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में हिंसा व क्रान्तिकारी रीतियों के प्रयोग को भी उचित मानते हैं। ट्रिग्न की लेकर पार्टी का समाजवाद विकासवादी समाजवाद है जबकि रूस चीन, आदि साम्यवादी देशों का समाजवाद क्रान्तिकारी समाजवाद है।

समाजवाद के अनेक रूप हैं जिनमें से मुख्य रूप निम्नलिखित हैं।

(१) समूहवाद या राजकीय समाजवाद (Collectivism or State socialism) —

राजकीय समाजवाद का जन्मदाता रोडबर्टस (Rodbertus) है। इस प्रकार के समाजवाद में उत्पादन के समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तथा राज्य द्वारा ही धन की उत्पत्ति और उसका वितरण होता है। इस व्यवस्था में निजी व्यक्ति की उत्पादन कार्य करने और लाभ प्राप्त करने की स्वतन्त्रता नहीं होती। राजकीय समाजवाद में उत्पादन से जो लाभ प्राप्त होता है वह जनता के हित में व्यय कर दिया जाता है।

मान्यवाद और समूहवाद या राजकीय समाजवाद में प्रमुख अन्तर यह है कि राजकीय समाजवाद में वैधानिक तथा संसदीय ढंग से राज्य सत्ता प्राप्त की जाती है जबकि मान्यवाद में क्रान्ति और विद्रोह के द्वारा समाजवाद की स्थापना की जाती है।

(२) मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद (Marxism or scientific socialism) —

वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स (Karl Marx) है इसलिए इसे

मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्स से पूर्व समाजवाद का एक आदर्शवादी तथा काल्पनिक रूप था इसलिए इसे काल्पनिक समाजवाद भी कहा जाता था। मार्क्स ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 'दास केपिटल' (Das Capital) में सन् १८६७ में समाजवाद के सिद्धान्त को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया और वैज्ञानिक समाजवाद के विकास में एन्गल्स (Engels) का सहयोग प्राप्त किया।

मार्क्स के अनुसार—“समाजवाद से अभिप्राय आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व स्थापित होना, उत्पादन शक्तियों का तेजी से उन्नति करना और उत्पादन का एक योजना के अनुसार तगड़िन किया जाना है।”

मार्क्सवादी समाजवाद के दो मुख्य आधार हैं — (अ) मूल्य का धर्म सिद्धांत (labour theory of value), (ब) इतिहास की भौतिक व्याख्या (material interpretation of history)।

मार्क्स का 'मूल्य का धर्म सिद्धांत' यह बताता है कि श्रमिकों को उत्पादन मूल्य की अपेक्षा मजदूरी बहुत कम मिलती है। इस अतिरिक्त (surplus) को पूँजीपतियों द्वारा हड़प कर लिया जाता है, और वे श्रमिकों का शोषण करते हैं। अतः मार्क्स ने बताया कि इस 'शोषण' या 'छूट' का कारण 'निजी सम्पत्ति' है। अतः निजी सम्पत्ति को समाप्त कर देना चाहिए और उत्पादन तथा उपभोग में समस्त साधनों पर सरकार या राज्य का स्वामित्व होना चाहिए।

मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है, उसमें बताया है कि सभी ऐतिहासिक घटनाओं का कोई-न-कोई आर्थिक आधार अवश्य होता है। देश का राजनैतिक संगठन भी आर्थिक संगठन पर आधारित होता है। उन्होंने बताया कि देश में युद्ध, आन्दोलन, उपद्रव आदि सब कारणों से होते हैं। मार्क्स ने इतिहास की भौतिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए आगे बताया कि पूँजीवाद स्वयं विनाश के बीज बोए रहता है। उन्होंने बताया कि पूँजीवाद में दो वर्ग—पूँजीपति (haves) और श्रमिक (have-nots) पाये जाते हैं। कालान्तर में पूँजीपतियों की संख्या कम होनी जाती है तथा श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इनमें आपस में सदैव संघर्ष चलता रहता है, अतः एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि श्रमिकों की अधिक संख्या थोड़े-से पूँजीपतियों को समाप्त कर देती है। इस प्रकार पूँजीपतियों की समाप्ति के साथ ही पूँजीवाद का अन्त होगा और वर्गहीन समाज (class-less society) की स्थापना होगी। इस प्रकार पूर्ण समाजवाद (full blooded socialism) की स्थापना हो जायेगी।

(३) श्रमिक सघवाद (Syndicalism)—श्रमिक सघवाद का जन्म फ्रांस में हुआ। इस मत के विचारकों का मत है कि सरकारी अधिकारी कुसन्ततपूर्वक उत्पादन कार्य

सही करते, उनमें नौकरशाही की प्रवृत्ति पाई जाती है। सरकारी श्रमचारी जनहित के लिए कार्य न करके मनमानी करते हैं, इसलिये श्रमिक सघवाद में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियन्त्रण नहीं होता बल्कि प्रत्येक फर्म या कारखाने के श्रमिकों के सघ उसके मालिक होते हैं और वे ही इनका संचालन करते हैं। अपने आर्थिक या राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये हिंसा का भी प्रयोग करते हैं।

(४) शिल्प समाजवाद (Guild socialism)—शिल्प समाजवाद श्रमिक सघवाद से थोड़ा भिन्न है। इसमें उत्पादन के साधनों तथा उद्योगों पर राज्य का नियन्त्रण रहता है, यह उत्पादन की विस्म, मूल्य-निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेता है। परन्तु इनका ध्वन्य तथा संचालन प्रत्येक फर्म व कारखाने में कार्य करने वाले सभी प्रकार के मजदूर सघों के हाथ में रहता है। इन सघों को 'गिल्ड' (guild) कहते हैं।

(५) साम्यवाद (Communism)—साम्यवाद श्रमवादी समाजवाद का उन्नत रूप है। साम्यवाद को सर्वसत्तावादी सामूहिकवाद (totalitarian collectivism) भी कहते हैं, क्योंकि साम्यवाद में उत्पादन, उपभोग आदि सभी पर 'समूह' का नियन्त्रण होता है। इस व्यवस्था में 'सामूहिक संगठन' (या राज्य) यह निर्धारित करता है कि किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाय तथा वस्तुओं का वितरण राज्य के द्वारा किया जाता है। भोजन, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि सभी की व्यवस्था राज्य या सामूहिक संगठन द्वारा की जाती है। व्यक्तियों द्वारा वही कार्य किये जाते हैं जो सरकार द्वारा उन्हें करने के लिए दिये जाते हैं। इस प्रकार यह व्यवस्था उन अधिकारों को छीन लेती है जो कि व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिये या दूसरों के शोषण के लिए प्रयोग में लाता है।

साम्यवाद का आधार अन्तर्राष्ट्रीय है तथा यह जाति, रंग, धर्म आदि के भेदों को स्वीकार नहीं करता। इस व्यवस्था में कोई भी 'पराधीन' जाति या समाज नहीं होता। साम्यवाद का अन्तिम उद्देश्य जाति द्वारा वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है।

समाजवादी धर्म-व्यवस्था और मूलभूत आर्थिक समस्याएँ (Socialist Economy and Fundamental Economic Problems)

समाजवादी धर्म-व्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर राज्य या सरकार का नियन्त्रण होता है, अतः राज्य इस प्रकार से कार्य करता है कि इन साधनों का अनुकूलतम उपयोग

हो। इन साधनों के उपयोग के लिए तथा जनता के कल्याण के लिए समाजवाद में नियोजन का सहारा लिया जाता है। समाजवादी व्यवस्था में अधिक निर्णय लेने के लिए एक केन्द्रीय नियोजन अधिकारी (Central Planning Authority) की नियुक्ति की जाती है और इसी के द्वारा अर्थ-व्यवस्था की तीनो मूलमूल समस्याओं—(१) किस वस्तु का उत्पादन किया जाय ? (२) वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाय ? तथा (३) वस्तुओं का उत्पादन किसके लिये किया जाय ?—को हल किया जाता है। केन्द्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा उत्पादन इकाइयों के व्यवस्थापकों तथा समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों में समन्वय स्थापित किया जाता है।

(१) किस वस्तु का उत्पादन किया जाय ? (What is to be produced ?)—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में अन्य अर्थ-व्यवस्थाओं के समान उत्पादन की कुछ सम्भावनाएँ होती हैं, जिनमें से चुनाव किया जाता है। प्रायः इसी उत्पादन सम्भावना को चुना जाता है जो अधिकतम उपयोगिता प्रदान करती है। केन्द्रीय योजना अधिकारी ही लाभ को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लेता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाय। योजना अधिकारी यह निर्णय समाज की आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर लेता है। समाजवादी व्यवस्था में किसी वर्ग विशेष की आवश्यकताओं को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सम्पूर्ण समाज का समानता के आधार पर आका जाता है। अतः इस व्यवस्था में आवश्यक आवश्यकताओं की प्राथमिकता प्रदान की जाती है, और इन्हीं उत्पादनों के लिए साधनों का वितरण किया जाता है।

कुछ आलोचकों की यह धारणा है कि समाजवादी व्यवस्था में उपभोक्ताओं को वही वस्तुएं प्राप्त हो पाती हैं जिनको कि केन्द्रीय अधिकारी पसन्द करते हैं। परन्तु यह धारणा उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि इस व्यवस्था में सामूहिक हित को महत्व प्रदान किया जाता है।

(२) वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाय ? (How shall the goods be produced ?)—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन का संगठन केन्द्रीय योजना अधिकारी या सरकार द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था में उन विधियों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादन की मात्रा अधिकतम हो। इस व्यवस्था में उत्पादन इकाइयों के लिए उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर दी जाती है, तथा उनको उत्पादन के साधन मुलभ कर दिये जाते हैं। यदि उत्पादन की मात्रा निर्धारित उत्पादन से कम है तो उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए अनेक उपाय

किये जाते हैं। यदि उत्पादन की मात्रा निर्धारित उत्पादन से अधिक है तो प्रोत्साहन देने के लिए 'बोनस' आदि की सुविधा प्रदान की जाती है।

इस व्यवस्था में नई विधियों और तकनीकों के प्रयोग को महत्व दिया जाता है तथा उत्पादन कार्य में अनुसंधान आदि के नये विशेष सुविधायें भी उपलब्ध करा दी जाती हैं।

- (१) **वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाय ?** (For whom shall the goods be produced?) — समाजवादी व्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के वितरण की विषय समस्या उत्पन्न नहीं होती। चूंकि उत्पादित वस्तुओं का वितरण भाव पर निर्भर होता है इसलिए समाजवादी व्यवस्था में भाव के वितरण में अधिक असमानता न होने के कारण सभी व्यक्तियों के लिए समान आधार पर उत्पादन किया जाता है। व्यक्तियों की स्थिति में भिन्नता होने के कारण वितरण में आवश्यकतानुसार कुछ असमानता अवश्य आ जाती है। इस प्रकार, यह व्यवस्था सम्पूर्ण समाज की इच्छाओं को समान प्राथमिकता प्रदान करती है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ समाजवाद से आप क्या समझते हैं ? समाजवाद की विशेषताओं को बताइए।
- २ समाजवाद की परिभाषा दीजिये तथा उसके गुणों व दोषों की व्याख्या कीजिए।
- ३ समाजवाद तथा पूँजीवाद में अन्तर स्पष्ट कीजिए। क्या समाजवाद पूँजीवाद के दोषों को दूर करता है ?
- ४ समाजवाद के विभिन्न स्वरूप बताइए तथा किसी एक स्वरूप (form) की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
- ५ समाजवाद पर एक निबंध लिखिये।
- ६ आर्थिक प्रणाली के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिये। समाजवादी प्रणाली किस प्रकार से इन कार्यों को पूरा करती है, समझाइये।

अध्याय ६

★

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था [Mixed Economy]

★ ★ ★

मिश्रित अर्थ व्यवस्था वर्तमान युग की देन है। इस अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन, वितरण तथा आर्थिक विकास के साधनों पर न तो सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है और न ही निजी व्यक्तियों का। यह वह अर्थ-व्यवस्था है जिसमें देश के विकास में सरकार व साहसी दोनों ही समान रूप से सहयोग प्रदान करते हैं।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की धारणा का विकास (Evolution of the Concept of Mixed Economy)

मिश्रित अर्थ व्यवस्था का विचार सारे विश्व के लिए एक नया विचार है। एडम स्मिथ (Adam Smith), जे बी से (J. B Say), रिकार्डो (Ricardo), जे एस मिल (J S Mill) आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने राज्य के हस्तक्षेप को व्यापार संचालन आदि के लिए अनुचित बताया। इस प्रकार उन्होंने स्वतन्त्र व्यापार और अहस्तक्षेप की नीति (Laissez Faire) का समर्थन किया। इस नीति का थोड़े समय तक (मुख्यतः प्रथम विश्वयुद्ध से पहले तक) बोलबाला रहा, परन्तु स्वतन्त्र व्यापार की नीति में अनेक दोषों— (१) गलाकाट प्रतियोगिता, (२) वितरण की असमानता, (३) धर्मिकों का शोषण, (४) व्यापार चक्रों की उपस्थिति—के कारण इस व्यवस्था से व्यक्तियों का ध्यान हटने लगा। उस समय के विचारकों का ध्यान समाजवाद की ओर आकृष्ट हुआ। पूँजीवादी देशों में इस स्थिति को देखकर सरकार ने भी कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों और व्यवसायों को अपने नियन्त्रण में लेना प्रारम्भ कर दिया, इस प्रकार मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की शुरुआत हुई।

प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व ही यद्यपि स्वतंत्र व्यापार की नीति का पतन होना प्रारम्भ हो गया था, परन्तु १९१७ की रूसी क्रांति ने पूँजीवाद (स्वतंत्र उपक्रम अर्थ व्यवस्था) के विरोध में व्यक्तियों को आवृष्ट किया। अविनाश अर्थशास्त्री समाजवाद के सम्बन्ध में चर्चा करने लगे। लार्ड कीन्स (Lord Keynes) ने अपनी पुस्तक 'स्वतन्त्र व्यापार का अन्त' (End of Laissez Faire) में जो कि १९२६ में प्रकाशित हुई, पूँजीवाद (स्वतंत्र व्यापार की नीति) की कटु आलोचना की। इसके अतिरिक्त १९२९-३० की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दो से उत्पन्न हुए आर्थिक संकटों को देखते हुए अनेक अर्थशास्त्री समाजवाद के समर्थक हो गये। इन अर्थशास्त्रियों ने कीन्स के विचारों का समर्थन किया। पीगू (Pigou) ने कीन्स के विचार का समर्थन करते हुए लिखा है

“आर्थिक शांति के लिए उत्पादन के साधनों का समाजीकरण आवश्यक है और जितना ही शीघ्र हो उतना ही अच्छा है।”

इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के समय तक विश्व में दो प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाएँ विद्यमान थीं (१) पूँजीवाद, (२) समाजवाद। ये दोनों ही एक-दूसरे की विरोधी थीं। इन दोनों व्यवस्थाओं में एक कमी यह थी कि वे एक-दूसरे के लाभों को सम्मिलित नहीं कर पाती थीं। इसके अतिरिक्त इन दोनों ही व्यवस्थाओं में अनेक दोष थे।

लार्ड कीन्स ने इस स्थिति को देखकर एक महत्वपूर्ण विचार दिया कि एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था होनी चाहिए जो पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के सहयोग के आधार पर कार्य करती हो। इस प्रकार कीन्स ने पूँजीवाद और समाजवाद के बीच एक समझौते की नींव डाली। यही वाद में मिश्रित अर्थ व्यवस्था के रूप में विकसित हुई।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का अर्थ (Meaning of Mixed Economy)

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पूँजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। इस अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में सरकार द्वारा स्वयं उत्पादन कार्य किये जाते हैं तथा कुछ क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों को उत्पादन कार्य करने की स्वतन्त्रता रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर उत्पादन कार्य करते हैं।

- 1 “Socialisation of means of production was sine-qua-non of economic peace and the sooner it was adopted the better”

—Pigou

- 2 हेमसन (Hansen) ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को द्वैध अर्थ-व्यवस्था (Dual Economy) तथा लर्नर (Lerner) ने नियमित अर्थ व्यवस्था (Controlled Economy) कहा है।

है। इस अर्थ व्यवस्था में उद्योगों के क्षेत्रों का विभाजन एक निश्चित योजना के अन्तर्गत होता है। सामान्यतः क्षेत्रों का विभाजन उस देश की आर्थिक नीति और सरकार द्वारा उद्देश्यों से प्रभावित होता है।

मिश्रित अर्थ व्यवस्था की परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप पर मतभेद है। कुछ अर्थशास्त्री, जैसे—सेम्युअलसन (Samuelson) अमेरिका की अर्थ व्यवस्था को भी मिश्रित अर्थ व्यवस्था मानते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की मिश्रित अर्थ व्यवस्था है। वास्तविकता यह है कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार द्वारा नियमित एवं संचालित उद्योग एवं व्यवसाय) का अस्तित्व होता है तथा समाजवादी व्यवस्था में निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है। परन्तु पूँजीवाद में सार्वजनिक क्षेत्र को और समाजवाद में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं होता, अतः इस प्रकार की व्यवस्था को मिश्रित अर्थ व्यवस्था के नाम से पुकारना तर्कसंगत नहीं होगा।

मिश्रित अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही का अस्तित्व रहता है, इसके साथ ही दोनों क्षेत्रों को अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में नियन्त्रित (controlled) तथा स्वतन्त्र (free) दोनों ही प्रकार के उद्योगों का सह-अस्तित्व होता है और दोनों ही अर्थ व्यवस्था में विषास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था की सर्वोपयुक्त परिभाषा अभी तक कोई नहीं है, फिर भी निम्नलिखित परिभाषा को उचित परिभाषा माना जा सकता है —

“मिश्रित अर्थ-व्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है दोनों के कार्यकरण का क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है तथा दोनों क्षेत्र मिलकर देश के आर्थिक विकास के लक्ष्य से कार्य करते हैं।”

संक्षेप में, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ट रूप से संवर्धित होते हैं तथा दोनों एक इकाई के दो भागों के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय योजना आयोग के विचार इसी प्रकार के हैं।³

3 “In a planned economy the distinction between the public and private sector is one of relative importance. The two sectors are and must function as part of a single organism”

मिश्रित अर्थ व्यवस्था की विशेषताएँ (Salient Features of Mixed Economy) :

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को सही रूप में समझने के लिए इसकी विशेषताओं को जानना आवश्यक है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

(१) **निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व (Co-existence of private and public sector)**—मिश्रित अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व पाया जाता है और इस व्यवस्था में दोनों ही क्षेत्रों का पर्याप्त महत्व रहता है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र चार भागों में बंटा रहता है —

- (१) सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector) ,
- (२) निजी क्षेत्र (Private sector) ,
- (३) संयुक्त क्षेत्र (Joint sector) ,
- (४) सहकारी क्षेत्र (Co-operative sector) ।

(१) **सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector)**—इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों पर स्वामित्व व नियन्त्रण सरकार का होता है। सरकार जिन उद्योगों को देश की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए आवश्यक समझती है, अपने नियन्त्रण में ले लेती है। इन उद्योगों में प्रायः कोयला, लोहा एवं इस्पात, खनिज तेल आदि आधारभूत उद्योग तथा सुरक्षा, सम्पत्ती उद्योग एवं यातायात के साधन आदि रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन उद्योगों को भी रखा जाता है जिनमें निजी व्यक्ति कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाता, लेकिन वे देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं।

(२) **निजी क्षेत्र (Private sector)**—इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों पर स्वामित्व एवं नियन्त्रण निजी व्यक्ति का होता है। इस क्षेत्र में प्रायः उपभोग वस्तुओं के उद्योगों को रखा जाता है। इन उद्योगों की सरकार की नीतियों तथा आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। सरकार द्वारा इन उद्योगों पर अप्रत्यक्ष नियन्त्रण लगाये जाते हैं।

(३) **संयुक्त क्षेत्र (Joint sector)**—इस क्षेत्र के अन्तर्गत वे उद्योग होते हैं जिनका संचालन तथा नियन्त्रण सरकार एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस क्षेत्र के अस्तित्व का प्रमुख कारण सरकार द्वारा निजी व्यक्तियों की कुशलता तथा अनुभव का देश के विकास के लिए प्रयोग करना

है। सामान्यतः इन उद्योगों में प्रयुक्त पूँजी में ५१ प्रतिशत हिस्सा सरकार का होता है, शेष निजी व्यक्तियों या उद्योगपतियों का।

- (४) सहकारी क्षेत्र (Co operative sector).—सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत वे उद्योग आते हैं जो कि सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाते हैं। इस क्षेत्र में प्रायः उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

एक बात यह बताना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न क्षेत्रों को विभाजन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न ही इस विभाजन के सम्बन्ध में स्थिर दृष्टिकोण ही अपनाया जाता है। परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं में परिवर्तन होने पर इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। एक ही प्रकार का उद्योग सार्वजनिक एवं निजी दोनों में ही हो सकता है, जैसे—लोहा एवं इस्पात उद्योग, लकड़ उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि भारत में दोनों क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

- (२) आर्थिक नियोजन (Economic planning) —मिश्रित अर्थ व्यवस्था में देश के आर्थिक विकास के लिये आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। उद्योगों तथा व्यवसायों का संचालन एक निश्चित योजना के आधार पर किया जाता है। इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में भी लोकतंत्रीय नियोजन (democratic planning) को अपनाया जाता है।

- (३) वितरण की असमानताओं में कमी (Reduction in the inequalities of distribution) —मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में वितरण की समानता स्थापित करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जाते हैं। इस व्यवस्था में निजी व्यक्तियों को उत्पादन कर लाभ प्राप्त करने की छूट होती है तथा सम्पत्ति का अधिकार होता है, लेकिन यह स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर भी लाभ की मात्रा और सम्पत्ति की सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इसके साथ ही एकाधिकारी शक्तियों पर रोक लगा दी जाती है और सरकार द्वारा अधिक्त मात्रा में कल्याणकारी कार्य किये जाते हैं। इन सब कार्यों से वितरण की असमानताओं में कमी कर देते हैं।

- (४) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का नियम (Regulation of individual freedom)—मिश्रित अर्थ व्यवस्था में यद्यपि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहती है परन्तु उसे सामाजिक हित में नियमित कर दिया जाता है।

मिश्रित अर्थ व्यवस्था को अपनाये जाने के कारण (Reasons for the Adoption of Mixed Economy)

आज ससार में अधिकांश देश मिश्रित अर्थ व्यवस्था को महत्व प्रदान करते हैं, इसका मुख्य कारण इस प्रणाली के गुण हैं। अर्द्ध-विकसित एवं अविकसित देशों में तो प्रत्येक इसी प्रणाली को अपनाया जा रहा है। इस प्रणाली को अपनाय जाने के निम्नलिखित कारण हैं —

(१) पूँजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुण — मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पूँजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुणों को लेकर चलती है तथा इनके दोषों को ठोड़ देती है, क्योंकि इन व्यवस्था में पूँजीवाद को एक निश्चित सीमा के अन्दर ही कार्य करने दिया जाता है, जिससे निजी लाभ, शोषण आदि पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। इसके साथ ही, साधनों में समान वितरण हेतु प्रयत्न किये जाते हैं जिसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बनाये रखा जाता है।

(२) निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही उद्योगों के पास पूँजी का अभाव — विकासशील एवं अविकसित देशों में पूँजी का पर्याप्त अभाव पाया जाता है। कोई भी जन-निजी या सार्वजनिक — इस स्थिति में नहीं होता कि वह देश में आर्थिक विकास हेतु वांछित पूँजी विनियोजन कर सके, अतः देश के आर्थिक विकास के लिए निजी एवं सार्वजनिक — दोनों क्षेत्रों में अधिक-से अधिक माना में पूँजी प्राप्त करने में प्रयत्न किया जाता है।

(३) कुशल व्यक्तियों का अभाव — मिश्रित अर्थ व्यवस्था अपनाये जाने का कारण विकासशील एवं अविकसित देशों में कुशल व्यक्तियों का कम माना में पाया जाना है। कोई भी देश इस व्यवस्था में नहीं मानता कि वह निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से पर्याप्त माना में कुशल व अनुभवी व्यक्ति प्राप्त कर सके, अतः देश में आर्थिक विकास के लिए सभी प्रयासों द्वारा कुशल एवं विशिष्ट शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं।

(४) देश की आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र का विभाजन — मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में देश की आर्थिक क्रियाओं का संचालन किसी एक इकाई द्वारा न किया जाकर इसका सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है। इस विभाजन से कार्य-संचालन अधिक सुविधापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था को पूर्णतः स्वतन्त्र भी नहीं छोड़ा जाना और न ही पूर्ण नियंत्रण होता है, इससे विकास की गति तेज होती है।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के गुण (Merits of Mixed Economy) :

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य पूँजीवाद एवं समाजवाद के गुणों को प्राप्त करना है तथा उनके दोषों से बचना है। अधिकांश देशों ने इसके गुणों के कारण ही इसे अपनाया है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं :—

- (१) निजी सम्पत्ति, लाभ उद्देश्य तथा मूल्य यंत्र (Private property, profit motive and price mechanism)—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में निजी सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त होता है तथा साहसी लाभ के उद्देश्य से उत्पादन कार्य कर सकता है। इस प्रकार साहसी एवं उत्पादकों को कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही, इस व्यवस्था में मूल्य यंत्र भी कार्य करता रहता है, परन्तु सरकार इस प्रकार से हस्तक्षेप करती है कि उत्पादक एवं साहसी निजी लाभ एवं सम्पत्ति के उद्देश्य से श्रमिकों का शोषण न कर सके।
- (२) पर्याप्त स्वतन्त्रता (Adequate freedom)—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तियों को पर्याप्त आर्थिक व राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं को अपनी आय को व्यय करने की स्वतन्त्रता होती है तथा व्यक्तियों को अपने व्यवसाय को चुनने की भी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। यद्यपि सरकार द्वारा हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण लगा दिये जाते हैं तथा कुछ व्यवसायों को सरकार विकास के उद्देश्य से अधिक प्रोत्साहन दे देती है।
इस व्यवस्था में विचार अभिव्यक्ति की भी स्वतन्त्रता रहती है परन्तु राष्ट्रीय हित में कभी-कभी सरकार प्रतिबन्ध लगा देती है।
- (३) तीव्र आर्थिक विकास (Rapid economic development)—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में देश का विकास तीव्र गति से होता है। इस व्यवस्था में नियोजित ढंग से विकास किया जाता है तथा विकास योजनाएँ बनाने से पूर्व देश में उपलब्ध सम्पूर्ण साधनों का सर्वेक्षण किया जाता है। तदुपरांत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का कार्य करण धेन निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार साधनों में कुशलतम प्रयोग के लिए हर समय प्रयत्न किये जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप देश का विकास तीव्र गति से होता है।
- (४) आर्थिक असमानताओं में कमी (Reduction in economic inequalities)—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक असमानताएँ काफी कम हो जाती हैं। क्योंकि इस प्रणाली में निजी लाभ तथा सम्पत्ति पर एक सीमा के बाद नियन्त्रण लगा दिये जाते हैं तथा एकाधिकारों प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण व रोक लगा दी जाती है। असमानताओं

को बम करने के लिए सम्पन्न वर्ग पर कर अधिक मात्रा में लगा दिये जाते हैं तथा निचले वर्गों को अनेक प्रकार, जैसे— शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में, सरकार द्वारा निचले वर्ग के लिये कल्याणकारी कार्य किये जाते हैं।

- (५) आर्थिक नियोजन की सफलता (Success of economic planning)—मिश्रित अर्थ व्यवस्था में नियोजन कार्य काफी सुगम हो जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा नियोजन कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाती, अपितु विकास कार्यों के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है।

मिश्रित अर्थ व्यवस्था के दोष (Demerits of Mixed Economy)

मिश्रित अर्थ व्यवस्था में अनेक गुण हैं परन्तु यह भी दोषों से रहित नहीं है। इस व्यवस्था की पूँजीवादी व समाजवादी दोनों ही पक्षों से आलोचना की जाती है। इसके बारे में प्रायः कहा जाता है—'यह प्रणाली दो फोड़ों पर पैर रखकर चलने वाले सवार की तरह है, जिसकी गिरने की संभावना अधिक रहती है।' इन प्रणाली की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) अकुशल प्रणाली (Inefficient system)—मिश्रित अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में आलोचना की जाती है कि यह प्रणाली कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती। इस व्यवस्था में पूँजीवाद की तरह न तो मुख्य यंत्र ही पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ नियाशील रह पाता है और न ही समाजवाद की तरह पूर्ण नियोजन होता है, तथा इन दोनों स्थितियों के अभाव में समन्वय की आवश्यकता होती है। दोनों में उचित समन्वय स्थापित करना काफी कठिन कार्य है। उचित समन्वय के अभाव में विकास की गति काँटों से घेर ली जाती है।

कुछ आलोचकों का विचार है कि यह व्यवस्था दोनों क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती जिससे मानवीय अवतार में काफी वृद्धि हो जाती है। आचार्य अवधूत (Acharya Avadhut) के शब्दों में

“मिश्रित अर्थ व्यवस्था केवल प्रभावहीन और व्यर्थ ही नहीं है अपितु खतरनाक भी है। यह मानवता में नैराश्य को गहरा कर देती है।”

- 4 'Mixed economy is not only ineffective and useless but is also dangerous. It tends to deepen the frustration of humanity'

— Acharya Avadhut

(२) अस्थिरता (Instability)—आलोचकों का मत है कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था कभी भी स्थायी रूप धारण नहीं कर सकती। ऐसा भी हो सकता है कि निजी क्षेत्र का महत्व धीरे-धीरे बढ़ता जाकर अर्थ व्यवस्था में प्रमुख स्थान प्राप्त कर ले और सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान गौण रह जाय। इसके विपरीत यह भी संभव है कि सरकार द्वारा नियंत्रणों की मात्रा में धीरे-धीरे वृद्धि होती जाय और सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान प्रमुख हो जाय तथा निजी क्षेत्र का गौण। आलोचकों का विचार है कि कालान्तर में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पूँजीवादी या समाजवादी व्यवस्था के रूप में बदल जाती है, इसका अस्तित्व स्थायी नहीं होता। आचार्य आवादहूत के शब्दों में :

“वास्तव में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था एक हस्यास्पद असंगति है। शेर एवं बकरे की बिरह्याधी मित्रता की कल्पना करना भूल्यंता है।”

(३) लोकतंत्र को खतरा (Danger to democracy)—आलोचकों का मत है कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में धीरे-धीरे सरकार हस्तक्षेप में वृद्धि करती जाती है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि समाजवादी शक्तियाँ शक्तिशाली हो जाती हैं। इससे सरकार में तानाशाही की प्रवृत्ति आ जाती है तथा जनतंत्रीय रूप समाप्त होने लगता है। व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की विद्वानों द्वारा की गई आलोचनाओं में सत्यता का अंश अवश्य है, परन्तु यह कहना नितान्त असंगत होगा कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था व्यवहार में देश के विकास में सहयोग प्रदान नहीं कर सकती। वास्तविकता यह है कि आज सत्तार के अनेक देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है, और वे दोनों 'घोत्रों' में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने में सफल हुए हैं। इस प्रणाली को अधिकांश विकासशील व अविकसित देश अपना रहे हैं, तथा अपना विकास कर रहे हैं। यदि इस प्रणाली में कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा कार्य संचालन किया जाय तो समाजवाद व पूँजीवाद, दोनों ही प्रणालियों के लाभ प्राप्त हो सकते हैं तथा देश अपने साधनों का सतुलित रूप से प्रयोग कर विकास पथ पर आगे बढ़ सकता है।

■ “But in reality mixed economy is ludicrously absurd. It is preposterous to think of lasting friendship between a goat and tiger.”

—Acharya Avadhoot

भारत में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy in India)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करने तथा नागरिकों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नियोजन तथा मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया। १९४८ की औद्योगिक नीति के साथ ही भारत में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को चार श्रेणियों में बाँटा गया, जिसमें सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया। सरकार द्वारा इस लोकतंत्रीय समाजवाद (democratic socialism) का लक्ष्य निर्धारित करने से १९५६ में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया —

प्रथम श्रेणी में १७ उद्योग रखे गये जिनके विकास का पूर्ण दायित्व केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया। इसमें अस्त्र-शस्त्र, परमाणु शक्ति, लोहा एवं इस्पात, खनिज तेल, वायुयान निर्माण आदि सम्मिलित हैं।

द्वितीय श्रेणी में १२ उद्योगों को रखा गया जिनका भविष्य में नये कारखाने आदि खोलने के लिए सरकार स्वयं कार्य करेगी, लेकिन इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सहयोग बनाये रखने पर जोर दिया गया है। इसमें अल्युमिनियम, इस्पात रबर आदि उद्योग सम्मिलित हैं।

तृतीय श्रेणी में उन उद्योगों को रखा गया जिनका विकास सामान्यतः निजी साहसियों द्वारा किया जायेगा।

सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के साहसियों को प्रोत्साहित करने तथा सहयोग देने के लिए अनेक कार्यक्रम भी अपनाये गये। इन तीन क्षेत्रों के अनिश्चित सरकार ने यह भी निश्चय किया कि सहाकारी क्षेत्र का भी विकास किया जाय। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाना है जिससे कि एकाधिकारी प्रभुत्व को प्रोत्साहन प्राप्त न हो।

इस प्रकार भारत में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को महत्व दिया गया है तथा परस्पर सहयोग को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इन दोनों क्षेत्रों के महत्व व सहयोग के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए एक सातबहादुर शास्त्री ने कहा :—

“मैं इस बात की अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ कि व्यापारियों और उद्योगपतियों तथा सरकार के बीच परस्पर चर्चा, सहयोग एवं सद्भावना रहनी चाहिए।”^६

अधिकांश भारतीय विद्वान व अर्थशास्त्री दोनों क्षेत्रों के सहयोग और समन्वय को देश के आर्थिक विकास के लिए उचित मानते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति भरत राम के शब्दों में—

“दोनों क्षेत्रों में विभिन्न बिन्दुओं पर सहयोग होना आवश्यक है, यदि दोनों में उच्च स्तर की सद्भाव स्थापित नहीं किया जाता है तो एक क्षेत्र के विकास की धीमी गति दूसरे क्षेत्र के विकास की सम्भावनाओं को प्रभावित करेगी, जिसका प्रभाव सम्पूर्ण देश की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा।”^७

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था और मूलभूत अर्थव्यवस्थाएँ (Mixed Economy and its Fundamental Economic Problems)

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन कार्य सरकार एवं निजी साहसी दोनों के द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं।

प्रो लर्नर (Lerner) के शब्दों में—“इस व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत यह है कि किसी विशेष स्थिति में जिस तराके से अधिकतम सामाजिक कल्याण हो, उसी की भनना चाहिये।”^८

अतः इस व्यवस्था में दोनों ही क्षेत्रों में साधनों का कुशलतम प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है तथा व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जाता है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में यद्यपि दोनों क्षेत्रों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, फिर भी सरकार

6 “I regard it as a matter of highest importance that there should be increasing deliberations, co operation and goodwill between businessmen and industrialists on the one hand, and government on the other”
—Lal Bahadur Shastri

7 “There has essentially to be close association between the two sectors at different points and unless a higher degree of harmony is achieved, the slow rate of growth of one sector will itself depress the potential growth of the other and, therefore, of the economy as a whole”
—Bharat Ram

8 “Its fundamental principle of organisation is that in any particular instance the mean that serves the society best should be one that prevails”
—Lerner

द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी एक क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दे दिया जाता है, जैसे—भारत में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार वृद्धि करती जा रही है।

इस व्यवस्था में भी पूँजीवाद व समाजवाद की तरह तीन मूलभूत आर्थिक समस्याएँ हैं—

- (१) किस वस्तु का उत्पादन किया जाय ?
- (२) वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाय ?
- (३) वस्तुओं का उत्पादन किस के लिए किया जाय ?

(१) किस वस्तु का उत्पादन किया जाय ?—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में 'मूल्य यंत्र' तथा सरकार दोनों ही यह निर्धारित करते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाय। निजी साहसियों द्वारा उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो कि उपभोक्ताओं द्वारा पण्य की जाती हैं तथा जहाँ पर लाभ प्राप्त होने की सम्भावना अधिक रहती है। सरकार द्वारा उन वस्तुओं में उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है जो कि अति आवश्यकता की है तथा जो सामान्य उपभोक्ता द्वारा प्रयाग में लाई जाती हैं। सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर नियंत्रण लगा दिये जाते हैं जो कि हानिकारक हैं या जो मनुष्य के कल्याण में वृद्धि नहीं करती। सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिन्हें कि सरकार चाहती है। इस व्यवस्था में सामान्यतः उत्पादन प्राथमिकताओं के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है।

(२) वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाय ?—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन का संगठन सरकार व निजी साहसी दोनों के द्वारा किया जाता है। दोनों का यह प्रयत्न होता है कि उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाय, क्योंकि निजी साहसी लाभ में वृद्धि करने के निम्ने लागत घटाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं, जबकि सरकार उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्न करती है। इस प्रकार, दोनों ही क्षेत्रों में नई तकनीक व विधियों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसके साथ ही अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को भी महत्व प्रदान किया जाता है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में दोनों क्षेत्रों में समन्वय एवं सहयोग हमेशा बनाय रखा जाता है, अन्यथा माँग व पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पूरव्त्त उनका विशेष महत्व नहीं रहा । का जोषण नहीं हो पाता । सरकार द्वारा नियंत्रण होने से सम्बन्धित है । आर्थिक विकास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता । ३ । कुछ अर्थशास्त्रियों ने

- (१) वस्तुओं का उत्पादन किस के लिए किया जाय ?—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था ४ ने प्रति व्यक्ति का वितरण पूरव्त्त प्रणाली के द्वारा होता है । बाजार में उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वस्तु त्रय की जाती हैं जिनके पास क्रय शक्ति होती है, वत वे व्यक्ति अधिक वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं जिनके पास क्रय शक्ति अधिक होती है । सरकार का उद्देश्य अधिकतम कल्याण का होता है, इसलिये सरकार निम्न वर्ग को वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये राशनिंग आदि की व्यवस्था करती है तथा वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण लगा देती है । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्ग पर कर आदि लगा दिये जाते हैं जिससे उनके पास क्रय शक्ति कम रह जाती है और निर्धन वर्ग के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं, फिर भी इस व्यवस्था में आय की असमानता के कारण उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में काफी असमानता होती है । मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सम्पूर्ण समाज की इच्छाओं को प्राथमिकता प्रदान करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं ।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. मिश्रित अर्थ-व्यवस्था से क्या अभिप्राय है ? इस व्यवस्था के प्रादुर्भाव एवं विकास के कारणों को व्याख्या कीजिये ।
२. मिश्रित अर्थ व्यवस्था की परिभाषा दीजिये तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए ।
३. "मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पूँजीवाद एवं समाजवाद का मिश्रित रूप है ।" व्याख्या कीजिये ।
४. मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के गुणों व दोषों की व्याख्या कीजिये ।
५. किसी एक अर्थ व्यवस्था की मुलभूत आर्थिक समस्याएँ क्या हैं ? मिश्रित अर्थ-व्यवस्था उन समस्याओं को कैसे हल करती है ?
६. मिश्रित अर्थ व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये । क्या यह प्रणाली भारत के पाजनाबद्ध विकास के लिये उपयुक्त है ?

अध्याय ७

★

आर्थिक विकास की परिभाषा व महत्व

[Definition and Importance of
Economic Growth]

★ ★ ★

वर्तमान युग आर्थिक विकास का युग है। प्रत्येक देश की सरकार का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा उठाना और उनकी अधिकतम सुख-सुविधायें उपलब्ध कराना होता है। अर्द्ध विकसित तथा अल्प विकसित देश 'विकास' की ओर अधिक महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इन देशों का उद्देश्य राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। आर्थिक विकास के महत्व में वृद्धि के कारण ही अधिकांश अर्थशास्त्रियों के चिन्तन का यह विषय बन गया है। साधारणतः विकास से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने से होता है। परन्तु कुछ अर्थशास्त्री इसको अधिक व्यापक मानते हैं, उनके अनुसार विकास से अभिप्राय राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके देश के नागरिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करना तथा उनकी निधनता का दूर करना है।

आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषायें¹

(Meaning and Definition of Economic Growth)

आर्थिक विकास का विचार २०वीं शताब्दी की देन है, यद्यपि इससे पूर्व भी कुछ

- 1 कुछ अर्थशास्त्रियों ने 'आर्थिक विकास' (Economic Development) 'आर्थिक वृद्धि' (Economic Growth) तथा 'आर्थिक प्रगति' (Economic Progress) को अलग अलग माना है और उनकी परिभाषायें अलग अलग दी हैं। प्रो. मायर एवं बॉल्डविन (Myer and Baldwin) ने इन तीनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग

अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार इस सम्बन्ध में दिये थे, परन्तु उनका विशेष महत्व नहीं रहा। आज के सभी अर्थशास्त्री किसी न-किसी प्रकार इस विचार से सम्बन्धित हैं। आर्थिक विकास के अर्थ और परिभाषा के बारे में अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने देश की कुल वास्तविक आय में सुधार को आर्थिक विकास माना है तो कुछ ने प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को आर्थिक विकास माना है। हम यहाँ पर दोनों ही प्रकार के विचारों से सम्बन्धित अर्थशास्त्रियों की प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

मिअर एण्ड बॉल्डविन (Mier and Baldwin) के अनुसार—“आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें कि एक अर्थ व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।”^१

प्रो ए जे यंगसन (Prof A J. Youngson) के मतानुसार—‘आर्थिक प्रगति से अभिप्राय एक समाज से सम्बन्धित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि से है।’

प्रो एच एफ विलियमसन (Prof H F Williamson) के शब्दों में—“आर्थिक विकास या वृद्धि से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के व्यक्ति उपलब्ध साधनों का प्रयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के लिए करते हैं।”^२

प्रो डी ब्राइट सिंह (Prof D Bright Singh) के अनुसार—‘आर्थिक वृद्धि से अर्थ एक देश या समाज के उस परिवर्तन से है जो निम्न स्तर (Under develop-

किया है। यद्यपि इन तीनों शब्दों में पर्याप्त अन्तर है, परन्तु व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए तीनों को एक ही समझा जाय तो उपयुक्त रहेगा। हमने तीनों शब्दों को समानार्थी मानकर ही अध्ययन किया है तथा इनके अन्तर का अध्ययन अलग से किया है।

- 2 “Economic development is a process whereby an economy is real national income increases over a long period of time”

—Mier and Baldwin

- 3 “Economic progress is a increase of the power to achieve economic aims of the community concerned”

—A J Youngson

- 4 “Economic development or growth refers to the process whereby the people of the country or region come to utilize the resources available, to bring about a sustained increase in per capita production of goods and services”

—H F Williamson

ment) से उच्च आर्थिक स्तर की ओर अग्रसर होता है ।^५

उपर्युक्त परिभाषायें दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से सम्बन्धित हैं, फिर भी इन परिभाषाओं में तीन बातें समान हैं —

- (१) प्रक्रिया (Process) ;
- (२) वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ;
- (३) दीर्घकालीन या निरन्तर वृद्धि ।

(१) प्रक्रिया (Process) .

सभी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है । प्रक्रिया शब्द से अर्थ कुछ शक्तियों के कार्यशील रहने से है । ये शक्तियाँ कार्यशील रहकर आर्थिक मूल्यों (economic variables) में परिवर्तन कर देती हैं । शक्तियों की कार्यशीलता के कारण अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा साधनों की माँग और उनकी पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात् जनसंख्या में वृद्धि होती है, उत्पादन की नवीनतम विधियों का प्रयोग किया जाता है, कुशलता और तकनीक में सुधार होता है तथा आय के स्तर और उसके वितरण की स्थिति में परिवर्तन होता है, उपभोक्ताओं की रुचियों और पसन्दगियों में अन्तर आ जाता है तथा सड़कें आदि में भी परिवर्तन हो जाते हैं । माँग और पूर्ति के स्वरूप में होने वाले ये परिवर्तन एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं । ये परिवर्तन आर्थिक विकास के कारण और परिणाम दोनों हैं । इन परिवर्तनों की सीमा आर्थिक विकास की गति पर निर्भर करती है ।

(२) वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

मायर एव बौलडविन के अनुसार आर्थिक विकास का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है । वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से होता है, न कि मौद्रिक आय (money income) में वृद्धि से । किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी सम्भव है जबकि उस देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो, इस वृद्धि के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो जायेगी । वास्तविक राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन (G N. P) में ऋण सम्पत्ति का घिसावट व्यय (depreciation charges) घटा दिया जाता है ।

5 "Economic growth means the transformation of society or a country from a state of under-development to a high level of economic achievement"

(३) दीर्घकालीन या निरन्तर वृद्धि :

आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि निरन्तर होती रहे, अर्थात् आर्थिक विकास का सम्बन्ध अल्पकाल से न होकर दीर्घकाल से होता है। यदि किसी देश में परिस्थिति अनुकूल रहने के कारण एक या दो वर्षों के लिए उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो यह वृद्धि आर्थिक विकास के अन्तर्गत नहीं आयेगी। आर्थिक विकास को मापने के लिए १०, १५ या २० वर्षों की सम्बन्धी अवधि होती है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास से अभिप्राय वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि से है, लेकिन आर्थिक विकास का प्रभाव उस देश के नागरिकों के जीवन-स्तर पर भी गहरा आवश्यक है, अर्थात् वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में भी वृद्धि होना आवश्यक है, क्योंकि यह संभव है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बाद भी (यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक है) प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि न हो। इसलिये कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से सम्बन्धित किया है।

आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अन्तर (Difference Between Economic Development and Economic Growth)

सामान्यतः आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अन्तर नहीं किया जाता है। इस विषय की पुष्टि अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं से होती है। मायर एण्ड बॉल्डविन (Mier and Boldwin) ने आर्थिक विकास, यंगसन (Youngson) ने आर्थिक प्रगति और विलियमसन (Williamson) तथा डी ब्राइट सिंह (D. Bright Singh) ने आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों ने इन शब्दों में मूलभूत अन्तर स्थापित किया है, जिसमें प्रथम अर्थशास्त्री शुम्पीटर (Schumpeter) है।

प्रो. शुम्पीटर के अनुसार 'आर्थिक विकास (economic development) एक स्वतः (spontaneous) तथा रुक रुक कर होने वाला परिवर्तन है जिसके लिए विशेष प्रयत्न किये जाते हैं और प्रयत्नों के द्वारा तथा विकास की भावना से जिसमें गति आती है। आर्थिक वृद्धि वह है जो कि क्रमिक और दीर्घकाल में निरन्तर (steady) होती है जिस पर जनसंख्या और वचन जैसे साधनों का प्रभाव पड़ता है।' प्रो. शुम्पीटर ने इसको अधिक स्पष्ट करते हुए बताया है कि—

“आर्थिक वृद्धि में ‘विकास’ परम्परागत और नियमित घटनाओं का परिणाम होता है जिसमें किसी नवीनता का सृजन होना आवश्यक नहीं है। जबकि आर्थिक विकास में

नवीन शक्तियों का सूजन होता है तथा प्रवर्धित स्थितियों में निरन्तर सुधार करने के प्रयत्न किये जाते रहते हैं।”

प्रो बोने (Prof Bonne) ने वृद्धि तथा विकास में अन्तर बताते हुए लिखा है—
‘आर्थिक वृद्धि के लिए विक्रय प्रयत्न नदी किये जाते बल्कि वह स्वतः (spontaneous) होती है, जबकि आर्थिक विकास के लिए निर्देशन, नियमन तथा मार्गप्रदर्शन की आवश्यकता होती है।’

प्रो बोने के अनुसार आर्थिक विकास का महत्व अर्द्ध-विकसित देशों के लिए अधिक है।

किण्डले बर्जर (Kindley Berger) ने दोनों का अन्तर निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है—“आर्थिक वृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन से है जबकि आर्थिक विकास से अर्थ अधिक उत्पादन तथा उस तकनीकी व वैधानिक परिवर्तनों से है जिन्हें द्वारा यह (अधिक उत्पादन) प्राप्त किया जाता है।”⁶

श्रीमती उर्सला हिक्स (Mrs Ursula Hicks) ने कहा है—“वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए करना चाहिए तथा ‘विकास’ शब्द का प्रयोग उन देशों के लिए करना चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।”

प्रो ब्राइट सिंह श्रीमती हिक्स के विचार से सहमत हैं।

यद्यपि उपर्युक्त दृष्टिकोणों से अधिकांश अर्थशास्त्री सहमत हैं फिर भी आज के युग में इन दोनों शब्दों को अधिक विस्तृत रूप में लिया जाता है। आर्थिक विकास मानव के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित है, जैसा कि समुक्त राष्ट्र सच (U N O) की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है —

विकास मनुष्य की वैश्व भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उनकी सामाजिक दशाओं में सुधार भी सम्बन्धित है। इस प्रकार विकास केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, स-सागर तथा आर्थिक परिवर्तनों की भी सम्मिलित किया जाता है।”⁷

6 “Economic growth means more output and economic development implies both more output and changes in the technical and constitutional arrangements by which it is produced”

—Kindley Berger

7 “Development concerns not only man's material needs but also the improvement of the social conditions of his life. Development is therefore, not only economic growth, but growth plus change social, cultural, and institutional as well as economic”

—U N N

आर्थिक विकास का महत्व (Importance of Economic Development)

आज हम विश्व के सभी देशों को दो भागों में बांट सकते हैं—विकसित एवं अर्द्ध-विकसित। विकसित देश वे हैं जो कि विकास की आखिरी सीमा पर पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर भोग विलास, सुख सम्पन्न सभी कुछ है। अर्द्ध-विकसित देश आज भी अपने नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयत्नों के बावजूद भी उन देशों में गरीबी, बेरोजगारी पूँजी का अभाव, निम्न जीवन स्तर आदि भयंकर समस्याएँ हैं। आर्थिक विकास के मुख्यतः अर्द्ध-विकसित देशों से ही सम्बन्धित किया जाता है। आर्थिक विकास मानवीय कल्याण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है गरीबी, बेरोजगारी, पूँजी का अभाव, निम्न जीवन स्तर, क्षेत्रीय असंतुलन आदि सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए या इन्हें कम करने के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है। आर्थिक विकास करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयत्न करने होते हैं, अर्थात् आर्थिक विकास के लिए आर्थिक आयोजन (economic planning) आवश्यक है। आर्थिक आयोजन से राष्ट्रीय आय, रोजगार, पूँजी निर्माण तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है और बेरोजगारी, आय की विषमताओं, शोषण, एकाधिकारी प्रवृत्ति, गरीबी आदि में कमी आती है।

प्रो लुईस (Prof Lewis) ने आर्थिक विकास के निम्नलिखित लाभ बताये हैं —

- (१) आर्थिक विकास से नये क्षेत्रों तथा नये उद्योगों का विकास होता है, जिसके फल-स्वरूप व्यक्ति को अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार कार्य का चुनाव करने की स्वतन्त्रता रहती है।
- (२) आर्थिक विकास से मनुष्य को अपने वातावरण पर अधिक नियन्त्रण प्राप्त होता है जिससे उसकी स्वतन्त्रता बढ़ती है।^६
- (३) आर्थिक विकास आयोजित अथ व्यवस्था से किया जाता है जहाँ पर सामाजिक व आर्थिक विषमताओं को दूर करना आवश्यक समझा जाता है।
- (४) आयोजित ढंग से विकास करने से परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है, व्यापार चक्र कम हो जाते हैं तथा वितरण में अधिक तकसत और न्यायपूर्ण बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त देश में

“The case for Economic growth is that it gives man greater control over his environment and thereby increases his freedom”

W A Lewis

उपलब्ध साधनों का पूर्ण शोषण (विदोहन) किया जाता है जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तथा जहाँ तक सम्भव होता है प्रतिस्पर्धा के अपव्ययों पर रोक लगायी जाती है ।

(५) आर्थिक विकास से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि व्यक्तियों के जीवन-स्तर में वृद्धि कर देती है और गरीबी से छुटकारा मिलता है ।

(६) आर्थिक विकास अधिक मानवीय व उदार भावना को जन्म देता है । जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो समाज से शोषण, वैमनस्य, लूट लुटोटा आदि अनैतिक कृत्य स्वतः ही काफी कम हो जाते हैं और स्नेह, सहयोग व सह-भावना में वृद्धि होती है ।

लुईस के शब्दों में—“आर्थिक सम्पन्नता मनुष्य के आर्थिक व सामाजिक कल्याण के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।”

आज के युग में आर्थिक विकास अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारणों से भी आवश्यक माना जाता है । आज की स्थिति में कोई भी राष्ट्र उसी स्थिति में अपनी स्वतन्त्र नीतियाँ निर्धारित कर पाता है जो कि आर्थिक रूप से विकसित है ।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, रोजगार के अधिक अवसर पैदा किये जा सकते हैं तथा वृद्धि की दर में वृद्धि की जा सकती है । इन सब के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की खुशहाल बनाया जा सकता है ।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए ।
- २ आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अन्तर बताइए तथा आर्थिक विकास के महत्व को समझाइए ।
- ३ आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है ? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अन्तर है ?

अध्याय ८

★

आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व

[Determinants of Economic Growth]

★ ★ ★

आर्थिक विकास की दर व उसके स्वरूप पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है।

इन तत्वों को हम आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आदि श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। देश में रहने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण, उनकी आदतें, योग्यता व ज्ञान, विकास करने की इच्छा आदि तत्व आर्थिक विकास को काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं। पी. टी. बाबर (P. T. Bauer) के अनुसार—

“आर्थिक प्रगति और उपलब्धि मानवीय गुणों और दृष्टिकोणों तथा इन पर आधारित सामाजिक व राजनैतिक संस्थाओं, प्राकृतिक साधनों तथा ऐतिहासिक अनुभवों और अनेक तत्वों पर आधारित होती है।”

इन तत्वों की स्थितियों में अन्तर होने के कारण ही प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में अन्तर पाया जाता है। सामान्यतः आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों को अर्थशास्त्रियों ने दो प्रकार से वर्गीकृत किया है —

(१) प्रधान चालक तत्व एवं अनुपूरक तत्व (Prime mover and supplementary factors),

(२) आर्थिक एवं अनार्थिक तत्व (Economic and non-economic factors)।

प्रधान चालक तत्व एवं अनुपूरक तत्व

जो तत्व देश के आर्थिक विकास के कार्य को प्रारम्भ करते हैं उन्हें प्रधान चालक तत्व कहते हैं तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जिन तत्वों द्वारा सहयोग दिया जाता है उन्हें अनुपूरक या सहायक तत्व कहते हैं। सहायक तत्व विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं।

प्रधान कारक तत्वों में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं —

- १ प्राकृतिक साधन
- २ मानवीय सधन ,
- ३ सामाजिक तत्व ,
- ४ सांस्कृतिक व सव्यागत तत्व ।

अनुपूरक या सहायक तत्वों में अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया है —

- १ जनसंख्या की वृद्धि की दर
- २ तकनीकी विज्ञान की दर
- ३ पूँजी निमाण की दर ।

प्रधान व सहायक तत्वों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद महसूस पाया जाता है । इसके साथ ही कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक विकास में प्रधान तत्वों को महत्व प्रदान करते हैं तो कुछ सहायक तत्वों को ।

२ आर्थिक एवं अनार्थिक तत्व (Economic and Non economic Factors)

कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को आर्थिक व अनार्थिक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया है । उनका वर्गीकरण इस प्रकार है —

आर्थिक तत्व (Economic factors)—इसमें निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं —

१. जनसंख्या ,
- २ प्राकृतिक साधन ,
३. पूँजी निर्माण ,
- ४ वैज्ञानिक प्रगति
- ५ उद्यमशीलता (Entrepreneurship) ,
- ६ संगठनात्मक एवं व्यावसायिक ढांचा ,
- ७ विदेशी पूँजी ।

अनार्थिक तत्व (Non-economic factors)—आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अनार्थिक तत्व निम्नलिखित हैं —

१. सामाजिक तत्व ,
२. सांस्कृतिक तत्व ,

३. सस्यागत तत्व ,

४. स्थिर तथा कुशल प्रशासन ।

आर्थिक विकास में निर्धारित तत्वों में उपर्युक्त सभी तत्वों को अविकीर्ण अर्थशास्त्री सही मानते हैं परन्तु इनके वर्गीकरण के सम्बन्ध में एकमत नहीं है । उन आधुनिक अर्थ-शास्त्री वर्गीकरण की जटिलता में न फसकर सामान्य निर्धारक तत्वों को ही महत्व प्रदान करते हैं । प्रो. मायर एवं वॉलडविन का विचार है कि यदि निर्धारक तत्वों को सही सूची बनायी जाय तो एक सम्बन्धी सूची तैयार हो जायेगी । उन्होंने बताया कि वास्तविक रूप में निर्धारक तत्वों को चार श्रेणियों में रखा जा सकता है —

१ जनसंख्या ,

२. प्राकृतिक साधन ,

३ तकनीकी प्रगति ,

४ साधनों का लचीलापन (Flexibility of resources) ।

कुछ अर्थशास्त्री इन सक्षिप्त वर्गीकरण से सहमत नहीं हैं क्योंकि इसमें समाजिक व सस्यागत तत्वों को सम्मिलित नहीं किया गया है । संक्षेप में, आर्थिक विकास में सर्वमान्य निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं —

१ प्राकृतिक साधन ,

२ मानवीय साधन (जनसंख्या) ,

३ पूँजी निर्माण ,

४ तकनीकी प्रगति ,

५. उद्यमशीलता (Entrepreneurship) ,

६ सामाजिक एवं सस्यागत तत्व ,

■ स्थिर तथा कुशल प्रशासन ,

८. अनुसूत बाह्य परिस्थितियाँ ।

आर्थिक विकास के उपर्युक्त निर्धारण तत्वों का वर्णन संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है ।

(१) प्राकृतिक साधन (Natural resources)—प्राकृतिक साधन वे भौतिक व नैसर्गिक वस्तुएँ हैं जो कि प्रकृति से निशुल्क प्राप्त होती हैं । भूमि, जल, पदार्थ, वन सम्पदा, जल, अन्वायु भौगोलिक स्थिति आदि प्राकृतिक साधनों के अन्तर्गत आती हैं । प्राकृतिक साधन किसी भी देश के आर्थिक विकास को काफी अधिक प्रभावित करते हैं । प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में सामान्य धारणा यह है कि जिस

देश में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे उस देश का आर्थिक विकास तीव्रता से होगा, लेकिन केवल प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता ही आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। विकास के लिये यह आवश्यक है कि जो साधन उपलब्ध हैं उन साधनों का पूर्ण विवास किया जाय तथा उनका दोहन हो। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर प्राकृतिक साधन अधिक उपलब्ध नहीं है वहाँ पर विकास भी नहीं होना। वास्तविकता यह है कि प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता केवल विकास की निया की सुगम व सरल बना देती है।

- (२) मानवीय साधन (Human resources)—मानवीय साधन से अभिप्राय जनसंख्या से होता है। देश के विकास के लिये अनिवार्य है। वास्तविक रूप में मानवीय धन पर ही देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। प्रो. व्हिप्ल (Prof Whipple) के शब्दों में —

“किसी देश का वास्तविक धन उसकी भूमि या पानी, जंगलों या खानों, पक्षियों या पशुओं के झुण्डों में नहीं है और न ही डालरों में है, बल्कि उस देश के स्वस्थ और सम्पन्न स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों में है।”

देश में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण बिना जनसंख्या के सम्भव नहीं है। देश के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिये, जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिये व्यक्तियों का शिक्षित होना, रहने की उचित व्यवस्था होना तथा सतुलित भावना प्राप्त होना आवश्यक है, यदि ये सुविधायें उपलब्ध नहीं हों तो श्रम अकुशल होगा और उसकी कार्यक्षमता कम होगी।

यदि जनसंख्या कम है तो अन्य बातें समान रहने पर प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, जनसंख्या अधिक होने की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय कम हो जायेगी। विकसित देशों के विकास में जनसंख्या ने उन्हें सहयोग प्रदान किया है वही अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या की अविश्वसनीयता का कारण विकास की प्रक्रिया बाधों घेरती हो गई है। इसका कारण यह है कि अधिक जनसंख्या के कारण देश में उपलब्ध भूमि तथा खेतों पर भार अधिक हो जाता है तथा दूसरी ओर वृत्त, पूँजी निर्माण और प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है,

- 1 “A nation's true wealth is not in its lands and waters, not in its forests and mines, not in its flocks and herds, not in its dollars, but in its wealthy and happy men, women and children”

—Prof Whipple

जिससे कम उत्पादन होता है, बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और जीवन-स्तर भी गिरने लगता है ।

(३) पूँजी निर्माण (Capital formation)—प्रो नर्कसे (Prof Nurkse) के अनुसार—पूँजी निर्माण आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकता (pre requisite) है । जब तक देश में पर्याप्त मात्रा में पूँजी व पूँजी निर्माण नहीं होगा तब तक औद्योगीकरण, कृषि का आधुनिकीकरण यातायात के साधनों आदि का विकास सम्भव नहीं है । पूँजी निर्माण के महत्व के कारण ही वर्णशास्त्रियों ने इसे आर्थिक विकास की कुंजी कहकर पुकारा है, क्योंकि पूँजी के द्वारा ही उत्पादन में नवीनतम विधियों और तकनीकों का प्रयोग सम्भव है, इसी के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करके व्यक्तियों की आय में वृद्धि की जा सकती है । सलेप में, देश के आर्थिक विकास के लिए प्रो कुजनेट्स (Prof Kuznets) के अनुसार पूँजी एवं पूँजी संचय एक अनिवार्य आवश्यकता है । किसी भी देश के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए पूँजी निर्माण की दर अधिक होना आवश्यक है । यही कारण है कि अर्द्ध विकसित देशों का विकास पूँजी निर्माण की धीमी गति के कारण अधिक तेजी से नहीं हो पा रहा है ।

(४) तकनीकी प्रगति (Technological progress)—देश के आर्थिक विकास के लिए पूँजी निर्माण के साथ-साथ तकनीकी प्रगति होना भी आवश्यक है । वास्तव में 'पूँजी और प्रविधि (technology) एक' प्रक्रिया में संयुक्त आधार है ।^{१२} इसका अभिप्राय यह है कि पूँजी और तकनीक या प्रविधि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में साथ साथ रहते हैं । तकनीकी ज्ञान उत्पादन की विधियों में परिवर्तन लाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करता है । अर्द्ध विकसित देशों में विकास की धीमी गति का एक कारण यह भी है कि इन देशों में श्रेष्ठ तकनीकी ज्ञान का अभाव है जिसके कारण उत्पादन की पुरानी विधियों का प्रयोग ही अधिक होता है जबकि विकसित देशों में नयी तकनीक और नवप्रवर्तन के प्रयोग के कारण विकास की दर अपेक्षाकृत अधिक रहती है ।

(५) उद्यमशीलता (Entrepreneurship)—नयी तकनीक तथा नये आविष्कारों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिये साहसी या उद्यमी की आवश्यकता होती है । प्रो शुम्पीटर ने आर्थिक विकास के सिद्धांत में उद्यमी को केन्द्रीय स्थान दिया है

2 "Capital and technology are joint inputs in one process"

तथा उद्यमियों के आर्थिक विकास की संचालन शक्ति (driving force) कहा है, क्योंकि प्रो गिल के शब्दों में किसी देश में तकनीकी ज्ञान आर्थिक दृष्टि से तभी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जबकि उसे नवप्रवर्तन (innovations) के रूप में प्रयुक्त किया जाय और जिसकी पहल (initiative) साहसी या उद्यमी द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास में साहसिया की दक्षता और जोखिम उठाने की क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

वर्तमान समय में जबकि विशेष रूप से अर्द्ध-विकसित देशों में जहाँ पर विकास यात्राबद्ध तरीके से सरकार द्वारा किये जाते हैं, वहाँ पर साहसियों का महत्व कम होना जा रहा है, क्योंकि सरकार एक निर्णयकर्ता (decision maker) के रूप में कार्य करती है अतः सरकार की आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका होनी है। आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए साहसी की तरह सरकार का दखल बंधन होना आवश्यक है, अन्यथा साधनों का अप्रयोज्य होगा, नवीन तकनीक का प्रयोग नहीं हो सकेगा, उचित निर्णयों के अभाव में विकास की गति भी मन्द पड़ जायेगी।

- (६) सामाजिक एवं संस्थागत तत्त्व (Social and institutional factors)—किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सामाजिक तथा संस्थागत वातावरण का होना उसी प्रकार आवश्यक होता है जिस प्रकार कि आर्थिक वातावरण। आर्थिक और सामाजिक तथा संस्थागत तत्त्व परस्पर सम्बन्धित होते हैं, तथा वे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास को तेज करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत तत्त्वों का विकास के अनुकूल होना आवश्यक है। यदि समाज नवीन मूल्यों और संस्थाओं को नहीं अपना पाता तो उस देश का विकास भी तबो से होना संभव नहीं है। अनार्थिक तत्त्व (non-economic factors) आर्थिक तत्त्वों की उत्प्रेरक शक्तियाँ हैं अतः अनार्थिक तत्त्वों का आर्थिक तत्त्वों से सम्बन्ध काफी घनिष्ठ होता है। प्रो नर्कसे (Prof Nurkse) के शब्दों में—

“आर्थिक विकास का मानवीय मूल्यों (human endowments) सामाजिक अभिरूचियों, राजनैतिक दशाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है।”^३

अर्द्ध विकसित देशों में नवीन मूल्यों और संस्थाओं को पूर्ण ग्रहण करने की प्रवृत्ति न होने के कारण ही उनकी विकास की गति काफी धीमी है। दूसरी ओर विकसित

3 “Economic development has much to do with human endowments, social attitudes, political conditions and historical accidents”
—Ragner Nurkse

देश बिना किसी हिचक के नवीन मूल्यों को अपनाने है, जिससे विकास तीव्र गति से होना है। रिचर्ड गिल (Richard Gill) न उचित ही कहा है—

“आर्थिक विकास एक यन्त्रीकृत प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवी उद्यम (human enterprise) है। इसलिए इसका फल अन्तिम रूप से मनुष्य के गुणों उसकी कायकुशलता और उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है।”^४

अतः हम कह सकते हैं कि किसी देश का विकास तब तक तीव्र गति से सम्भव नहीं है जब तक कि उस समाज में प्रगति करने की इच्छा, विकास के लिए तत्परता तथा नवीन व अधिक बुद्धि विधियों को अपनाने की क्षमता न हो।

(७) स्थिर तथा कुशल प्रशासन (Stable and efficient administration)—किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के शासन और उसकी नीतियों से काफी प्रभावित होता है। देश में स्थिर शासन व कुशल प्रशासन विकास की प्रक्रिया को तेज कर देता है, क्योंकि आज के युग में आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व शासन पर ही अधिक होता है। स्थिर शासन व कुशल प्रशासन के साथ साथ सरकार की नीतियों के प्रति विश्वास तथा विकास के प्रति रुचि होना भी आवश्यक है। यदि किसी देश में कुशल व सुगठित प्रशासन व्यवस्था नहीं है, कमचारियों और अधिकारियों में ईमानदारी का अभाव है तथा सरकार में उत्तरदायित्व की भावना की कमी है, तो उस देश में विकास की प्रक्रिया काफी धीमी हो जायगी। विकास के लिए जन सहयोग आवश्यक होता है। जन सहयोग तभी प्राप्त होगा जबकि शासन तत्त्व ईमानदार व कुशल हो।

(८) अनुकूल बाह्य परिस्थितियाँ (Favourable external circumstances)—आर्थिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है। प्रगति-विकसित देशों का विकसित देशों से वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग तथा सहायताओं की आवश्यकता होती है। यह सहयोग व सहायता राजनैतिक शक्ति की स्थिति में ही प्राप्त हो पाते हैं। विद्वानों का विचार है कि राजनैतिक स्थिति, पड़ोसी देशों का व्यवहार, विदेशी व्यापार की संभावनाएँ, विकसित देशों की नीति तथा विदेशी पूँजी का प्रवाह आदि किसी देश के आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

4 “Economic development is not a mechanical process it is a human enterprise. And like all human enterprises, its outcome will depend finally on the skill, quality and attitudes of the men who undertake it.”
—Richard Gill

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी देश का आर्थिक विकास किसी एक तत्व पर निर्भर ■ करके अनेक तत्वों से प्रभावित होता है। इन विभिन्न निर्धारक तत्वों में कौन-सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। देश के आर्थिक विकास में इन सभी तत्वों का अपना-अपना महत्व है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए।
 - २ किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए।
 ३. आर्थिक विकास में आर्थिक तथा अनार्थिक तत्व कौन-से हैं ? ये तत्व आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
-

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था

[Under-developed Economy]

★ ★ ★

वर्तमान समय में विकास की दृष्टि से विश्व की अर्थ-व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा जाता है—विकसित अर्थ-व्यवस्था (developed economy) तथा अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था (under-developed economy) परन्तु विकसित और अर्द्ध-विकसित की श्रेणी में देशों को बांटना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि अभी तक कोई सर्वमान्य मापदण्ड नहीं है जिससे सही-सही विभाजन किया जा सके। एक देश जो अपने से निर्धन देशों के सामने विकसित है वहीं अत्यधिक विकसित देशों के सामने अर्द्ध-विकसित हो जाता। अर्द्ध-विकसित एक सापेक्षिक शब्द है इसलिए इसकी सर्वमान्य तथा तपे-तुले शब्दा में परिभाषा देना अत्यन्त कठिन कार्य है। इस सम्बन्ध में प्रो. सिंगर (Prof H W Singer) का विचार काफी महत्व रखता है। उन्होंने बताया है कि अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की परिभाषा का कोई भी प्रयास समय व धन का अपव्यय है। उन्हीं के शब्दा में

“एक अर्द्ध-विकसित देश गिराफ के समान है, जिसका वर्णन करना कठिन है लेकिन जैसे ही उसे देखते हैं समझ जाते हैं।”¹

अनेक विद्वानों और अर्थशास्त्रियों ने अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की परिभाषायें दी हैं जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषायें निम्नलिखित हैं —

1 “An under-developed country is like a giraffe, difficult to describe, but you know when you see one”—Prof H W. Singer

संयुक्त राष्ट्रसंघ (U N O) की एक रिपोर्ट के अनुसार—“अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम हो।”^२

संयुक्त राष्ट्रसंघ की यह परिभाषा पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक तथ्य ‘गरीबी’ को ही सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त इस परिभाषा में दोष हैं—

- (a) यह सम्भव है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो फिर भी वह अर्द्ध-विकसित हो, जैसे कुवेत।
- (b) यह सम्भव है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय कम हो और फिर भी विकसित हो।

२ प्रो. जेकब वाइनर (Prof Jacob Viner) ने परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी है—“एक अर्द्ध-विकसित देश वह देश है जिसमें अधिक पूँजी अथवा अधिक श्रमशक्ति या अधिक उपलब्ध साधना या इन सब का उपभोग करने की सम्भावनाएँ हैं जिन्होंने वर्तमान जनसंख्या के जीवन-स्तर को जँचा उठान में सहायक हो और यदि प्रति व्यक्ति आय का स्तर पढ़ने से ही अधिक ऊँचा^३ तो अधिक जनसंख्या का, रहन-सहन में स्तर में कमो किम्विना, जीवन निर्वाह किया जा सके।”^३

जेकब वाइनर ने अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध जीवन-स्तर से स्थापित किया है। उनके अनुसार अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था वह है जिसमें व्यक्तियों का जीवन-स्तर नीचा हो, तथा इनके जीवन स्तर को जँचा उठान के लिए पर्याप्त साधन हों, और उन साधनों का उपभोग किया जा सके।

2 “An under-developed country is one in which per capita real income is low when compared with the per capita real income of U S A, Canada, Australia and Western Europe”

—U N O Report

3 “An under-developed country is a country which has good potential prospects for using more capital or more labour or more available resources, or all of these to support its present population at a higher level of living, or if its per capita income level is already very high, to support a larger population on a not lower level of living”

—Jacob Viner

“यूजीन स्टेनले (Eugene Stanley) ने अर्द्ध-विकसित देश को परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में की है—“अर्द्ध-विकसित देश वह है जहाँ बड़े पैमाने पर गरीबी है जो कि अल्पकालीन दुर्भाग्य (misfortune) का परिणाम न होकर स्थायी (chronic) है, तथा परम्परागत पुराने उत्पादन के तरीकों और सामाजिक संगठनों के कारण है। इसका अर्थ यह है कि गरीबी केवल प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि गरीबी को उन तरीकों से कम किया जा सकता है जो कि दूसरे देशों में अपनाये गये हैं।”^४

स्टेनले जेबन्स ने अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था में केवल तीन बातें सम्मिलित की हैं (a) गरीबी, (b) समष्टि उत्पादन के तरीके व सामाजिक संगठन, तथा (c) प्राकृतिक साधनों की कमी। इस प्रकार यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है।

भारतीय योजना आयोग के प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी है—“एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसमें एक ओर मानवीय शक्ति का कम प्रयोग या बिल्कुल भी प्रयोग न हुआ हो तथा दूसरी ओर अशोषित (unexploited) प्राकृतिक साधनों का कम या अधिक मात्रा में सह-अस्तित्व हो।”^५

यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक साधनों का शोषण क्यों नहीं होता।

उपरोक्त सभी परिभाषाओं में कोई भी परिभाषा सर्वमान्य नहीं है। आजकल अर्थशास्त्री अर्द्ध-विकसित व विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को तकनीकी शब्द (technical word) के रूप में प्रयुक्त करता है। सामान्यतः अर्द्ध-विकसित देश यह है —

4 “A country characterised by mass poverty which is chronic and not result of some temporary misfortune, and by absolute methods of production and social organisation, which means that poverty is not entirely due to poor natural resources and hence could presumably be lessened by methods already proved in other countries”
—Eugene Stanley

5 “An under-developed country is that which is characterised by the co-existence, in greater or less degree, of utilised or unutilised man power on the one hand, and of unexploited natural resources on the other” —Indian First Five Year Plan

- (१) जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होती है।
- (२) जहाँ पर प्राकृतिक साधन उपलब्ध हो लेकिन उनका पूर्ण उपयोग न हुआ हो।
- (३) उत्पादन की विधियाँ परम्परागत हो, जिससे विकास तेजी से न हो सके।
- (४) पूँजी निर्माण की गति धीमी हो, जिसके कारण विनियोग कम हो।
- (५) जनसंख्या की वृद्धि की दर अधिक हो।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ (Characteristic of Under-developed Economy)

अर्द्ध-विकसित देशों में पर्याप्त भिन्नताएँ पायी जाती हैं, इसलिए इनकी सर्वमान्य विरासतों को बताना अत्यन्त कठिन है। अर्थशास्त्रियों ने अर्द्ध-विकसित देशों की कुछ सामान्य विशेषताएँ बताई हैं जो कि अर्द्ध-विकसित देशों में प्रायः पायी जाती हैं, लेकिन इन विशेषताओं का सभी देशों में पाया जाना आवश्यक नहीं होता है।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के स्वभाव को देखते हुए प्रो. हार्वे लिबेन्सुएन तथा प्रो. हिलिग्न (Prof Harvey Lebensuen and B Higgins) ने इनकी विरासतों को चार भागों में बाँटा है —

- (१) **आर्थिक विशेषताएँ (Economic characteristics)**—इसमें उन्होंने कृषि की प्रगति, प्रति व्यक्ति कम आय कम बचत दर, छिपी हुई बेरोजगारी (disguised unemployment), आय का अधिकांश भाग भोजन पर व्यय करना, साव व निपणन की कम सुविधाएँ होना तथा कृषि का पिछड़ा हुआ होना आदि विशेषताएँ बताई हैं।
- (२) **जनसंख्या लक्षणों की विशेषताएँ (Demographic characteristics)**—इस श्रेणी में उन्होंने ऊँची जन्म तथा मृत्यु दर का होना, पौष्टिक भोजन का अभाव होना, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा औसत आयु कम होना आदि को सम्मिलित किया है।
- (३) **प्राविधिक विशेषताएँ (Technological characteristics)**—इस श्रेणी में उन्होंने उत्पादन की पुरानी तथा परम्परागत विधियों का प्रयोग, वैज्ञानिक व तकनीकी सुविधाओं का कम होना, प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं का कम होना आदि को सम्मिलित किया है।
- (४) **सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विशेषताएँ (Cultural and political characteristics)**—इस श्रेणी में उन्होंने जनता का अशिक्षित होना, पुरानी परम्पराओं और

रठियों की प्रशानता, बच्चों का शैक्षिक के रूप में कार्य करना, स्त्रियों का समाज में उचित स्थान न होना आदि को सम्मिलित किया है।

प्रो. मायर एंव बाल्डविन (Prof. Maer and Baldwin) ने अर्द्ध-विकसित देशों की विशेषताएँ बतलाई हैं

- (१) प्राथमिक उत्पादन अर्थ-व्यवस्था (Primary producing economy)
- (२) जनसंख्या का दबाव (Population pressures),
- (३) अउपेक्षित या अर्द्ध-उपेक्षित प्राकृतिक साधन (Unutilised or under-utilised natural resources),
- (४) गरीबी की निर्धनता (Poverty of the people),
- (५) पूँजी का अभाव (Paucity of capital),
- (६) विदेशी व्यापार पर निर्भरता (Foreign trade oriented)।

उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर अर्द्ध-विकसित देशों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नानुसार है —

- (१) कृषि पर निर्भरता (Dependence on agriculture)—अविकसित और अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था में कृषि की प्रधानता रहती है। अर्थात् इन दोनों देशों की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर करती है। इसके साथ ही प्रायः कृषि में व्यापारिक दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है। कृषि पर निर्भरता की स्थिति निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट होती है।

विकसित तथा अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि

अर्द्ध विकसित देश		विकसित देश	
देश	कृषि पर आश्रित जनसंख्या (%)	देश	कृषि पर आश्रित जनसंख्या (%)
भारत	७०	कनाडा	१६
सं.रा.	५३	ऑस्ट्रेलिया	१६
मलाया	६४	अमेरिका	६
पोलैन्डिया	७२	इंग्लैण्ड	४

उप्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकसित देशों की अपेक्षा अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत काफी अधिक रहता है। कृषि पर आश्रित जनसंख्या होने के कारण राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान भी अधिक रहता है। सामान्यतः सभी अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि से प्राप्त होने वाली आय का अनुमान उद्योगों से प्राप्त होने वाली आय की अपेक्षा अधिक होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का ४८.५७ % भाग^६ केवल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान केवल ४ % है। और कनाडा का ७ %। प्रो. बेयर तथा यामे के अनुसार—

“अर्द्ध-विकसित देशों में समस्त आर्थिक उत्पादन क्रियाओं में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा कृषि क्षेत्रों में निर्माण, सुधार एवं विकास में ही अधिकांश राष्ट्रीय साधन लगा दिये जाते हैं।”

- (२) प्रति व्यक्ति कम आय (Low per capita income)—प्रो. कुरिहारा (Prof. Kurihara) के अनुसार ‘अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का कम होना है। प्रो. रोस्टोव (Prof. Rostow) के अनुसार ‘अल्पविकसित देश वृद्ध है जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय २०० डॉलर से कम है’। इन प्रकार प्रति व्यक्ति आय की ग़ुनग़ाही ही अर्द्ध-विकसित देशों की प्रमुख विशेषता है। इसके साथ ही इन देशों में आय में वृद्धि की दर काफी धीमी होती है। एक अनुमान के अनुसार विकसित देश अमेरिका, कनाडा तथा स्विटजरलैंड की प्रति व्यक्ति आय २५०० डॉलर से अधिक है जबकि अर्द्ध-विकसित देश भारत, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश आदि देशों की आय १०० डॉलर से भी कम है।
- (३) पूँजी निर्माण की निम्न दर (Low rates of capital formation)—अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की दर प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण नीची रहती है, क्योंकि व्यक्तियों के पास उपभोग करने के बाद आय का बहुत थोड़ा भाग ही बच पाता है, इसके कारण देश के विकास के लिए (उत्पादन कार्यों के लिये) कम पूँजी प्राप्त हो पाती है। विनियोग कम होने के कारण उत्पादन में वृद्धि भी धीमी गति से होती है, अर्थात् विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। प्रो. नर्कसे (Nurkse) ने इसे निम्नता का दुष्चक्र (Vicious circle of poverty) कहा है

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये, प्रो. लुइस (Prof. Lewis) के अनुसार पूँजी निर्माण की दर १२ से १६ प्रतिशत के बीच होना आवश्यक है।

परन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में यह दर कम रहती है जबकि विकसित देशों में अधिक । यह स्थिति निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होती है —

देश	पूँजी निर्माण की दर (प्रतिशत में)
कनाडा	२४.५
जापान	२८.५
पश्चिमी जर्मनी	२३.६
अमेरिका	२०.८
भारत	६.३
संका	११.०

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विकसित देशों की अपेक्षा अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की दर कम है, इसके कारण देश का विकास तेजी से नहीं हो पाता ।

(४) जनसंख्या में तेजी से वृद्धि (Rapid growth in population)—अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि की दर तेज है जिससे अधिकतर देशों में जनप्रियता की समस्या है । सामान्यतः अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर २-२% से अधिक है जबकि विकसित देशों में यह दर २% से कम है जनसंख्या की अधिकांशता के कारण गरीबी, बेरोजगारी, कम आय, कम पूँजी का निर्माण, कम वस्तुओं का उपयोग, स्वास्थ्य में गिरावट आदि समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं ।

अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण ऊँची जन्म दर तथा कम मृत्यु दर का होना है इसके साथ ही शिक्षा, अन्ध-विश्वास व रूढ़ियों के कारण परिवार में बच्चों की वृद्धि को दायित्व (liability) न मानकर सम्पत्ति (assets) के रूप में लिया जाता है । इस धारणा के फलस्वरूप ही आज अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में "जनसंख्या विस्फोट" (population explosion) की स्थिति है ।

- (५) प्राकृतिक साधनों का पूर्ण शोषण न होना (Under utilised natural resources)—अर्द्ध-विकसित देशों में जो प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं उनका उचित ढंग से शोषण या विदोहन (Exploitation) नहीं हो पाता। पूर्ण विदोहन न होने के कारण विकास की गति मन्द रहती है और अधिकांश उत्पादन कार्य परम्परागत तरीकों से होते रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार यूरोप के विकसित देशों में उपलब्ध जनशक्ति का ६०% भाग उपयोग में लिया जाता है जबकि एशिया के देशों में १३% प्रतिशत और मध्य अमेरिका में केवल ५% भाग ही उपयोग में आता है प्राकृतिक साधनों का पूर्ण शोषण न होने का कारण इन देशों में विद्यमान सन्ध्यागत अवरोध, दोषपूर्ण सामाजिक संगठन तथा सरकार की नीतियाँ, पूँजी का अभाव आदि हैं।

भारत में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, परन्तु इन साधनों का विकास न होने के कारण देश आज भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, तथा यहाँ के पञ्च म व्यक्तियों का जीवन-स्तर नीचा है।

- (६) आर्थिक विषमता (Economic disparities)—अर्द्ध-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का वितरण काफी असमान (inequal) होता है। राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग अमीरों के हाथ में केन्द्रित रहता है जबकि निर्धन वर्ग को एक छोटा हिस्सा ही प्राप्त हो पाता है, इसका कारण यह है कि अमीर वर्ग अधिक मात्रा में बचत कर लेता है जिससे उस वर्ग के पास पूँजी अधिक मात्रा में संचित हो जाती है। अर्द्ध-विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा एवं कल्याणकारी कार्यों पर कम मात्रा में व्यय हो पाने के कारण भी निर्धन वर्ग को अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। साइमन कुज़नेट्स (Simon Kuznets) के अनुसार 'अर्द्ध-विकसित देशों में अमीरों के पास राष्ट्रीय आय का जितना हिस्सा था विकसित देशों में उनसे कम ही था। इसके विपरीत निर्धन व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय आय का कम भाग था जबकि विकसित देशों में निर्धन व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय आय का अनेकानेक अधिक भाग था'।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अर्द्ध-विकसित देशों में अमीरों को मिलने वाला राष्ट्रीय आय का भाग अधिक है जबकि गरीबों को मिलने वाला भाग कम है। सर यूजीन स्टेनले (Eugene Stanley) ने सप्ताह के देशों के आय वितरण पर निम्नलिखित निकाला 'सप्ताह की ७०% जनसंख्या अर्द्ध-विकसित देशों में रहती है तथा इस जनसंख्या का विश्व की कुल आय का २०% भाग प्राप्त होता है'।

साइमन कुजनेट्स के आय वितरण के अनुमान

देश	सम्पूर्ण आय का प्राप्त होने वाला प्रतिशत	
	समीर (जनसंख्या का २०%)	गरीब (जनसंख्या का ६०%)
विकसित देश		
संयुक्त राज्य अमेरिका	४४	३४
ब्रिटेन	४५	३५
अर्द्ध-विकसित देश		
भारत	३५	२८
श्रीलंका	५०	३०

प्रो महालनोबिस Prof Mahalanobis) ने भारत में राष्ट्रीय आय के वितरण की प्रवृत्ति का अध्ययन करके बताया कि भारत में ५% जनसंख्या का राष्ट्रीय आय का २३% भाग प्राप्त होता है, १ प्रतिशत जनसंख्या को ११% तथा २५% गरीब जनता को राष्ट्रीय आय का केवल १०% भाग ही प्राप्त होता है।

(७) बेरोजगारी की समस्या (Problem of unemployment)—अर्द्ध-विकसित देशों के सामने एक गंभीर समस्या बेरोजगारी को हल करने की रहती है।

प्रो. गुन्नार मिर्दोल (Prof Gunnar Myrdal) के अनुसार—“बेरोजगारी तथा छिपी बेरोजगारी (disguised unemployment) अर्द्ध-विकसित देशों का मुख्य आभूषण है।”

प्रो नर्से के अनुसार सामान्यतः २० से २५% तक जनसंख्या छिपी बेरोजगारी से पीड़ित होती है। बेकारी के कारण व्यक्तियों को कार्य देने के आवश्यक सहयोगी उत्पादन के साधन अपर्याप्त होते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में बेरोजगारी तथा छिपी बेरोजगारी के अतिरिक्त अर्द्ध-बेरोजगारी की भी समस्या है। इन देशों की भूमि पर

कार्य करने वाले व्यक्तियों के एक भाग को यदि हटाकर दूसरे व्यवसाय में लगा दिया जाय तो भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आयेगी, क्योंकि कृषि पर लगे अतिरिक्त व्यक्तियों की सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है। भारत तथा कुछ अन्य देशों में यह समस्या काफी जटिल है।

बायर तथा यामे (Bayer and Yamey) के अनुसार सभी अर्द्ध-विकसित देशों की बेरोजगारी या छिगे हुई बेरोजगारी विशेषतः नहीं है। संयुक्त अमेरिका तथा अफ्रीका के कुछ देशों में जहाँ कम जनसंख्या है, वहाँ अधिक जनसंख्या या बेरोजगारी की समस्या नहीं है।

- (८) प्राविधिक पिछड़ापन (Technological backwardness)—प्राविधिक या तकनीकी पिछड़ापन अर्द्ध विकसित देशों की प्रमुख विशेषता है। इन देशों में कुशल श्रमिकों का अभाव तथा तकनीकी प्रगति के अभाव में साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग न होने के कारण उत्पादन लागत अधिक आती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक साधनों का पूरा व उचित उपयोग नहीं हो पाता। साइमन कुजनेट्स के अनुसार तकनीकी विकास के चार महत्वपूर्ण चरणों—वैज्ञानिक खोज, आविष्कार नवप्रवर्तन (innovation) तथा सुधार का इन देशों में प्रायः अभाव पाया जाता है। पूँजी के अभाव के कारण विनियोगों में भी बाधा आ जाती है, तकनीकी विकास कम हो पाता है, तथा पूँजी का प्रतिस्थापन थम से किया जाता है। थम का अधिक प्रयोग होने के कारण उत्पादन लागत अधिक रहती है, तथा देशों का विकास भी धीमी गति से हो पाता है।

- (९) विदेशी व्यापार पर निर्भरता (Dependence on foreign trade)—अर्द्ध-विकसित देश निर्यातों पर काफी निर्भर रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सर्वेक्षण के अनुसार 'अर्द्ध' विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का ३०% भाग निर्यातों से प्राप्त होता है। कुछ देशों में यह भाग इससे भी अधिक है। इसके अतिरिक्त इन देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाला अधिकांश भाग कच्चे मान के रूप में होता है। निर्यातों पर निर्भर रहने के कारण आर्थिक संकट का भय रहता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों में उल्लास-व्यवधान होते रहते हैं।

- (१०) दोषयुक्त प्रायिक संगठन (Defective economic organisation)—अर्द्ध-विकसित देशों में प्रायिक इकाइयों का संगठन दोषपूर्ण है। इन देशों में प्रायः आवश्यक वित्तीय संस्थाओं तथा साम्य सुविधाओं का अभाव रहता है। मुद्रा बाजार अस्थिर होना है। इन देशों में विकसित तथा पिछड़े दोनों प्रकार के क्षेत्र रहते हैं। प्रो लुईस (Prof Lewis) के मॉडल में 'पिछड़ेपन' के समुद्र के बीच विकास के कूट टापू रहते

है। अर्थात् एक क्षेत्र जो कि छोटा होता है विकसित रहता है, तथा दूसरा क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र) जो कि बड़ा है अविकसित रहता है। विकसित क्षेत्र में विकसित देशों की सभी विशेषताएँ रहती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ होता है। इस अर्थ-व्यवस्था के दुहरेपन के कारण विकास में अवराम उत्पन्न हो जाते हैं।

(११) परम्परावादी समाज (Traditional society)—अर्द्ध-विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या कृषिवादी, परम्परावादी तथा साम्यवादी होती है, इसका मुख्य कारण लोगों की अधिक धार्मिकता तथा अशिक्षा है। व्यक्तियों की पुरानी परम्पराओं के प्रति आस्था होने के कारण नये मूल्यों को वे जल्दों ही अपना नहीं पाते तथा नयी तकनीक व विधियों के प्रयोग में विशेष रुचि भी नहीं दिखाते। इनके अतिरिक्त पूँजी की कमी के कारण आधुनिकतम वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने में असमर्थ रहते हैं, इसके परिणामस्वरूप विकास की गति काफी धीमी रह जाती है।

(१२) सामाजिक व राजनैतिक चेतना का अभाव (Lack of social and political consciousness)—अर्द्ध-विकसित देशों में अधिकांश व्यक्ति गरीब होते हैं तथा शिक्षा का अभाव पाया जाता है। इन दोनों कारणों से यहाँ का व्यक्ति सामाजिक व राजनैतिक स्थितियों के प्रति उदासीन हो जाता है। अधिकांश व्यक्तियों की अपनी स्वतन्त्र विचारधारा नहीं रहती। सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को वह अपिष्ट महत्त्व प्रदान नहीं करते।

उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त विद्वानों ने अर्द्ध विकसित देशों की कुछ अन्य विशेषताएँ भी बतायी हैं। उनके अनुसार अर्द्ध-विकसित देशों में उद्यमशीलता का अभाव, मानवीय पूँजी का अविकसित होना, श्रम की निम्न उत्पादकता, पौष्टिक आहार की कमी, बकूल प्रशासन, औद्योगीकरण का अभाव तथा निर्धनता का कुचक्र (vicious circle of poverty) आदि विशेषताएँ पायी जाती हैं। जैसा कि पूर्व में ही कहा गया है, सभी देशों में उपर्युक्त सभी विशेषताएँ पायी जाना सम्भव नहीं है, लेकिन अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में एक बड़ी मात्रा में उपर्युक्त विशेषताएँ पायी जाती हैं।

आज विश्व के सभी अर्द्ध-विकसित देश अपनी अर्थ व्यवस्था में सुधार करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, लेकिन विकास की अनेक समस्याएँ होने के कारण गति काफी धीमी है।

क्या भारत एक अर्द्ध-विकसित देश है ?

(Is India an Under-developed Country ?)

अर्द्ध-विकसित देशों की उपर्युक्त विशेषताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत एक अर्द्ध-विकसित देश है। भारत की अर्थ व्यवस्था में अर्द्ध विकसित देशों की सभी

विशेषतायें पायी जाती हैं। कृषि की प्रधानता, जनसंख्या का आधिक्य, पूँजी निर्माण की कमी, निम्न जीवन-स्तर, बेरोजगारी की समस्या, तकनीकी पिछड़ापन, औद्योगीकरण का अभाव, जनता में अज्ञानता, अंधविश्वास व रूढ़िवादिता, आर्थिक विकास की घीमी दर, कुशल प्रशासन का अभाव यदि सभी विशेषतायें पायी जाती हैं।

पिछले कुछ समय से भारत में विकास की गति को तेज करने के लिए तथा पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। देश में उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में यंत्रों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया है। पूँजी निर्माण की गति में वृद्धि के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। इनके परिणामस्वरूप भारत विकास की गतिशील (dynamic) अवस्था में प्रवेश कर गया है। इस स्थिति के परिवर्तन के कारण ही कुछ अर्थशास्त्रियों व विद्वानों का मत है कि हम इसे अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था के स्थान पर यदि विकासशील अर्थ व्यवस्था (developing economy) कहे तो उपयुक्त होगा। यह वेद निर्विवाद है कि भारत में प्रगति होने के बावजूद भी इसे विकसित देशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ अर्द्ध विकसित अर्थ व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था की विशेषतायें बताइए।
- २ अर्द्ध विकसित देशों की प्रमुख विशेषतायें बताइये। क्या ये विशेषतायें सभी देशों में लागू होती हैं?
- ३ अर्द्ध-विकसित अर्थ व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या भारतीय अर्थ-व्यवस्था अर्द्ध-विकसित की श्रेणी में आती है?

विकसित अर्थ-व्यवस्था [Developed Economy]

* * *

विकसित अर्थ-व्यवस्था वह है जिसमें विकास 'पूर्णता' को प्राप्त कर चुका होता है। इसमें व्यक्तियों की आय का ऊँचा स्तर, अधिकतम उत्पादन, पूँजी निर्माण की ऊँची दर, पूर्ण औद्योगिक व तकनीकी विकास, बचत व निवेश में सतुलन तथा रोजगार के उत्तम अवसर आदि विशेषताएँ पाई जाती हैं।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की तरह ही विकसित अर्थ व्यवस्था की सक्षिप्त और सर्वमान्य परिभाषा देना अत्यन्त कठिन है। 'विकसित' शब्द भी निरपेक्ष नहीं होकर सापेक्ष है। यह सम्भव है कि एक देश को किसी दृष्टि से 'विकसित' की श्रेणी में रखें वही देश दूसरी दृष्टि से अर्द्ध-विकसित की श्रेणी में आ जाता है, जैसे—रूस एक विकसित देश है क्योंकि वह सम्पन्न है, उसका औद्योगिक व तकनीकी विकास अन्तिम चरण में है, लेकिन रूस अभी तब विकास की प्रक्रिया में है, अतः इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। परन्तु इस प्रकार के विचार एक प्राप्ति पैदा करते हैं, क्योंकि कोई भी देश विकास के अन्तिम चरण पर पहुँचने के बाद भी स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता। इसका कारण तकनीकी ज्ञान और विज्ञान में लगातार प्रगति होना है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक देश विकास के लिए सदैव तत्पर रहता है।

संयुक्तराष्ट्र तथा की एक रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों को विकसित देश माना है तथा यह मान्यता रखी है कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय इन देशों से कम होगी वह अर्द्ध विकसित की श्रेणी में होंगे, परन्तु यह विचार भी तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरता। इसका कारण यह है कि प्रत्येक देश के विकास की अपनी सीमाएँ होती हैं, उस देश के विकास को दूसरे देश से तुलना करना

उचित प्रतीत नहीं होता। जो देश अपने उपलब्ध साधनों का पूर्ण शोषण व विकास करते उसे विकसित देश की श्रेणी में लिया जा सकता है।

विकसित देश की परिभाषा देना कठिन है, परन्तु इसकी विशेषताओं के आधार पर हम निम्न कर सकते हैं कि कौन-सी अर्थ व्यवस्था विकसित है।

विकसित अर्थ व्यवस्था की विशेषताएँ (Characteristics of Developed Economy)

विकसित देशों की सर्वमान्य विशेषताओं को बताना कठिन है, परन्तु अधिकांश देशों में कुछ सामान्य विशेषताएँ पायी जाती हैं, ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर (High level of per capita income) — विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय अर्द्ध-विकसित देशों की अपेक्षा काफी अधिक होती है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय ५०० डॉलर से अधिक होती है, परन्तु कुछ विशेषज्ञ १००० डॉलर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने वाले देश को विकसित देशों की श्रेणी में लेते हैं। विकसित देश अमेरिका, कनाडा तथा स्विटजरलैंड की आय एक अनुमान के अनुसार २५०० डॉलर से भी अधिक है।

विकसित देश निम्न की कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग प्राप्त करते हैं जबकि गरीब देश बहुत कम। इसकी पुष्टि निम्नांकित तालिका से होती है—

आय का स्तर	विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत	विश्व की आय का प्रतिशत
उच्च आय वाले देश	१८	६७
मध्यम आय वाले देश	१५	१८
निम्न आय वाले देश	६७	१५

विकसित देशों में प्रति व्यक्ति अधिक होने के साथ साथ राष्ट्रीय आय भी अधिक होती है, इसका कारण देश में उपलब्ध साधनों का पूर्ण शोषण व व्यक्तियों की कार्यक्षमता का अधिक होना है।

- (२) प्राकृतिक साधनों का पूर्ण शोषण (Fully utilised natural resources) — विकसित देशों के बारे में सामान्य धारणा है कि उनके पास प्राकृतिक साधनों का

पर्याप्त भंडार रहता है, लेकिन यह बात हर विकसित देश के लिये लागू होना आवश्यक नहीं है। परन्तु जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उन साधनों का पूर्ण शोषण होता है, जिसके परिणामस्वरूप विकास की दर में वृद्धि होती है, और राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विकसित देशों में उपलब्ध जनशक्ति का ६०% भाग का उपयोग होता है जबकि अर्द्ध-विकसित देशों में ६ से १३% तक उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग होता है। इन साधनों के अधिक शोषण का कारण पूँजी की अधिकता, विकसित उत्पादन प्रणाली तथा कुशल साहसी और प्रशिक्षित श्रमिकों का होना है।

- (२) पूँजी निर्माण की ऊँची दर (High rate of capital formation)—विकसित देशों में पूँजी निर्माण की दर अर्द्ध-विकसित देशों की अपेक्षा अधिक ऊँची रहती है। पूँजी निर्माण की ऊँची दर का कारण प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना है। विकसित देशों में व्यक्ति अपनी आय में से एक भाग आसानी से बचाकर रख लेते हैं, जिससे यह भाग विनियोग कार्यों के लिए उपलब्ध हो जाता है। विकसित देशों की पूँजी निर्माण की दर को निम्नांकित तालिका द्वारा दर्शाया गया है—

देश	पूँजी निर्माण
कनाडा	२४.५
जापान	२०.५
संयुक्त राज्य अमेरिका	२३.६
पश्चिमी जर्मनी	२०.८

पूँजी निर्माण की दर अधिक होने से विनियोग के लिए अधिक पूँजी प्राप्त होती है जिससे अधिक उत्पादन होता है और पुनः आय में वृद्धि हो जाती है।

- (४) रहन सहन का उच्च स्तर (High level of standard of living)—विकसित देशों में रहन सहन का स्तर उच्च होता है, अर्थात् वहाँ के नागरिक अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। आवश्यक व आरामदायक के अतिरिक्त विलासता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी सम्भव होती है। परन्तु प्रत्येक नागरिक

की ऐसी स्थिति का होना आवश्यक नहीं है, सम्भव है कुछ नागरिक ऐसे भी हो जिनका जीवन स्तर नीचा है। अतः इन देशों में औसत रूप में जीवन-स्तर ऊँचा होता है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था रहती है तथा आवास की समस्या प्रायः नहीं होती। मनोरंजन और सुख सुविधाओं के पर्याप्त साधन उपलब्ध रहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं, मनोरंजन के साधन तथा पौष्टिक आहार की उपलब्धि के कारण व्यक्तियों की औसत आयु (life expectancy) भी अधिक होती है। विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा ६५ से ७३ वर्ष तक है जबकि भारत में केवल ५० वर्ष।

- (५) औद्योगिक सर्व-व्यवस्था (Industrial economy)—विकसित देशों में उद्योग-धंधों का प्रमुखता प्राप्त होती है, तथा राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि का योगदान अधिक होता है। विकसित देशों में अद्यपि कृषि पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का अनुपात कम होता है तथा राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान भी कम होता है, फिर भी कृषि का विकसित रूप देखन में आता है। विकसित देशों में अधिकांश कृषि आधुनिकतम यंत्रों द्वारा की जाती है। विकसित देशों में कृषि व उद्योग-धंधों का राष्ट्रीय आय में योगदान निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होता है—

राष्ट्रीय आय में योगदान

(प्रतिशत में)

देश	कृषि का योगदान	निर्माण उद्योगों का योगदान
स २१ अमेरिका	६	३०
इंग्लैंड	५	३८
कनाडा	८	२६

विकसित देशों में मूल व भारी उद्योग विकसित अवस्था में होने के साथ-साथ उनकी इकाइयां बहुत होती हैं। अधिकांश उत्पादन कार्य बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े यंत्रों द्वारा किये जाते हैं। प्रयोग्य वस्तुओं के साथ ही उपभोग वस्तुओं (consumer goods) के उत्पादन को महत्व दिया जाता है।

(६) तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति (Technological and scientific progress)—विकसित देशों में प्रगति की दर अधिक होने का कारण तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति है। विकसित देशों के पास पूँजी का अभाव न होने के कारण तकनीकी व वैज्ञानिक अनुसंधानों में काफी धन व्यय करते हैं। प्रशिक्षण आदि की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। यंत्रों के अधिक होने के कारण विनियोग के लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध हो जाती है और उस पूँजी को अधिक उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है। प्रशिक्षण व अनुसंधान कार्य की सुविधायें तथा विकास की प्रेरणायें होने के कारण तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास होता चला जाता है।

(७) प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार का उच्च स्तर (Effective demand and high level of employment)—विकसित देशों में पूँजी निर्माण अधिक होता है, जिससे विनियोग अधिक मात्रा में होते हैं। विनियोग अधिक होने के कारण उत्पादन कार्य अधिक होते हैं, जिससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें उपलब्ध होती हैं। रोजगार में वृद्धि होने के फलस्वरूप व्यक्तियों की प्रभावी मांग में वृद्धि होती है और यह पुनः रोजगार में वृद्धि कर देती है।

रोजगार का उच्च स्तर होने का कारण यह भी है कि औद्योगीकरण के द्वारा विकास होता है, तथा देश में उपलब्ध साधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अधिक व्यापक रूप में अर्थ-व्यवस्था विकसित हो सके, अतः रोजगार की सुविधायें व्यक्तियों को अधिक प्राप्त होती हैं। सामान्यतः अर्द्ध-विकसित देशों में जो बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है वह विकसित देशों में नहीं रहती।

(८) विकसित आर्थिक संगठन (Developed economic organisation)—विकसित देशों में आर्थिक इकाइयाँ पूर्णतः होती हैं। इन देशों में वित्तीय सुविधायें तथा साख सुविधायें आवश्यकतानुसार प्राप्त रहती हैं। ये सुविधायें केवल शहरी तक ही सीमित नहीं होती अपितु पूरे देश में फैली होती हैं। मुद्रा बाजार संगठित होता है, इसके कारण सरकार व केन्द्रीय बैंक की नीतियों का पालन प्रभावपूर्ण ढंग से होता है।

(९) जनसंख्या वृद्धि की निम्न दर (Slow growth rate of population)—विकसित देशों में अर्द्ध-विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि की दर कम होती है। इसका कारण यह है कि शिक्षा का प्रसार अधिक होने के कारण व्यक्ति अवविश्वासी व रुढ़िवादी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधायें और मनोरंजन की अधिक सुविधायें उपलब्ध होने के कारण तथा जीवन-स्तर ऊँचा होने के कारण जन्म दर कम होती है।

विकसित देशों में मृत्यु दर भी जट्ट-विकसित देशों की अपेक्षा कम होती है, परन्तु जन्म दर कम होने के कारण शुद्ध वृद्धि दर कम रहनी है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर २% से भी कम है।

- (१०) अत्याधिक उपभोग की ग्रन्थ-व्यवस्था (Economy of mass consumption)—विकसित देशों में व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग काफी अधिक मात्रा में करते हैं। व्यक्तियों का केवल अच्छा भोजन, मकान व वस्त्र ही उपलब्ध नहीं होते बल्कि उपभोग की टिकाऊ वस्तुएँ (रेडियो, टेलीविजन, कार, साज-सामान आदि) भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। व्यक्तियों की आय अधिक होने के कारण वे उपभोग वस्तुओं का आसानी से क्रय कर लेते हैं। इससे अनिश्चित भौतिक विकास व तकनीकी प्रगति के कारण वस्तुएँ अपने मूल्य पर भी उपलब्ध हो जाती हैं। विकसित अर्थ व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों को वे सुविधायें उपलब्ध हों। यह सम्भव है इस अर्थ-व्यवस्था में भी गरीब लोग हों, जिनको इतनी अधिक उपभोग सामग्री प्राप्त न हो, परन्तु अविवाश व्यक्तियों की स्थिति काफी अच्छी होती है।

- (११) स्वचालित और स्वयं स्फूर्त अर्थ व्यवस्था (Self generating and self-sustained economy)—विकसित देशों में यह विशेषता पाई जाती है कि अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए तथा उमड़े गति प्रदान करने के लिए किसी बाह्य दबाव या विशेष नियोजन की आवश्यकता नहीं होती। इस स्थिति में आधुनिकतम उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है, यातायात तथा संचार की पर्याप्त सुविधायें रहती हैं, पर्याप्त वित्तीय व साज-सुविधायें उपलब्ध होती हैं, जिनके कारण साहसी भी अग्रिम रहते हैं। श्रमिक व साहसी दोनों ही कुशल हान के कारण उत्पादन अग्रिम होता है, और यह उत्पादन बड़े पैमाने पर ही होता है। विकसित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन वृद्धि स्वतः ही होती जाती है और यह अर्थ व्यवस्था का एक स्वाभाविक लक्षण बन जाती है।

उपर्युक्त विशेषताओं के अनिश्चित विकसित अर्थ-व्यवस्था में उच्च पूँजी उत्पादन अनुपात (high capital output ratio), पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों की अग्रिम उत्पादकता, यातायात तथा संचार के विकसित साधन आदि विशेषताएँ पायी जाती हैं। परन्तु इन सभी विशेषताओं का सभी विकसित देशों में पाया जाना आवश्यक नहीं है।

विकसित और जट्ट-विकसित अर्थ व्यवस्था में अन्तर (Difference Between Developed and Under developed Economy)

विकसित व जट्ट विकसित अर्थ व्यवस्थाओं के अध्ययन करने के उपरान्त इन दोनों में निम्नलिखित अन्तर प्रतीत होता है

अर्द्ध-विवर्तित अर्थ-व्यवस्था	विवर्तित अर्थ-व्यवस्था
१ कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था होती है, तथा अधिकांश व्यक्ति कृषि पर आश्रित होते हैं।	उद्योग प्रधान अर्थ-व्यवस्था होती है, तथा जनसंख्या का छोटा भाग कृषि पर आश्रित होता है।
२ कृषि पुराने तरीकों व यंत्रों से होती है। नये यंत्रों व विधियों का प्रयोग कम होता है।	आधुनिकतम यंत्रों द्वारा कृषि की जाती है।
३ उद्योग-प्रधो का पर्याप्त विकास नहीं होता तथा इनका राष्ट्रीय आय में कम योगदान होता है।	पूर्ण विवर्तित उद्योग होते हैं, तथा राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
४ निम्न जीवन स्तर होता है तथा निम्न उपभोग का स्तर होता है। प्राकृतिक साधनों का पूर्ण शोषण नहीं हो पाता।	उच्च जीवन स्तर होता है उपभोग का स्तर उच्च होता है। प्राकृतिक साधनों का पूर्ण शोषण होता है।
५ तकनीकी व वैज्ञानिक प्रगति कम होती है तथा भ्रम-प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाता है।	तकनीकी व वैज्ञानिक विकास का स्तर ऊँचा होता है तथा पूँजी-प्रधान तकनीक का प्रयोग होता है।
६ जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होती है।	जनसंख्या वृद्धि की दर कम होती है।
७ पूँजी निर्माण की दर कम होती है, जिससे विनियोग कार्यों की अल्प-पूँजी उपलब्ध हो पाती है।	पूँजी निर्माण की उच्च दर होती है तथा विनियोग कार्यों के लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध हो जाती है।
८ श्रमिकों की कार्यक्षमता कम होती है।	श्रमिकों की कार्यक्षमता अधिक होती है।
९ श्रमिकों की कार्यक्षमता कम होने व पूँजी के अभाव के कारण विकास की दर धीमी होती है।	विकास की दर तेज होती है।
१० बेरोजगारी की समस्या रहती है।	उच्च रोजगार का स्तर रहता है।
११ बहुत अधिक आर्थिक विषमताएँ पायी जाती हैं।	आर्थिक विषमताएँ अपेक्षाकृत कम होती हैं।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ विकसित अर्थ-व्यवस्था से क्या अभिप्राय है ? विकसित अर्थ-व्यवस्था की विशेषतायें बताइये ।
 - २ विकसित और अर्द्ध-विकसित अर्थ व्यवस्था की परिभाषा दीजिये तथा इन दोनों का अन्तर समझाइये ।
 - ३ विकसित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।
-

अध्याय ११

★

आर्थिक नियोजन की परिभाषा एवं विशेषतायें

[Definition and Characteristics of
Economic Planning]

★ ★ ★

आज के युग में आर्थिक नियोजन देश के विकास और प्रगति के लिये 'सामान्य' समझा जाता है। प्रत्येक देश चाहे वह पूँजीवादी है या समाजवादी या मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का समर्थक है, किसी-न-किसी रूप में आर्थिक नियोजन को अवश्य अपनाता है, इसलिए आज के युग को 'नियोजन का युग' (Age of Planning) कहा जाता है।

आर्थिक नियोजन २०वीं शताब्दी की देन है। पूँजीवादी व्यवस्था के शोष, रूस की क्रांति, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, एशिया तथा अफ्रीका के देशों के सामने विकास की समस्याओं तथा विश्वयुद्ध से जर्जरित राष्ट्रों की पुनर्निर्माण की समस्याओं ने इसके महत्व में अभ्रमशायित वृद्धि की है। सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में आर्थिक नियोजन की नीति को रूस द्वारा अपनाया गया पक्षपात अन्य देशों ने भी इसे स्वीकार कर लिया।

आर्थिक नियोजन की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से कृत की है, इसलिए इन परिभाषाओं में काफी भिन्नता है, अतः आर्थिक नियोजन की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा दे पाना अत्यन्त कठिन है। हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का ही अध्ययन करेंगे।

स्व. जवाहरलाल नेहरू ने नियोजन की परिभाषा इन शब्दों में की थी — "नियोजन एक निरन्तर प्रक्रिया है। नियोजन का अर्थ केवल वस्तुओं में प्राथमिकताओं का निर्माण नहीं है, बल्कि अधिक गहरा और विस्तृत है। नियोजन के बारे में पहली बात है

कि तत्वीर स्पष्ट होनी चाहिए कि हम कहा जा रहे हैं। किन्तु यह नस्वीर लोचनी नही होनी चाहिए।”^१

भारतीय योजना आयोग (Indian Planning Commission) के अनुसार—
‘आर्थिक नियोजन साधनों के उपयोग और संचालन की एक विधि है जिसमें साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। नियोजन के विचार के दो प्रमुख अंग हैं—(१) उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी गई प्रणाली, और (२) प्राप्त साधनों और उनके अनुकूलतम आवंटन (optimum allocation) के बारे में ज्ञान।’^२

हारमन लवी (Harman Levy) के अनुसार—‘आर्थिक नियोजन से अर्थ उत्पादन तथा वितरण अथवा दोनों पर एक विचारपूर्ण तथा चेतनापूर्ण नियन्त्रण रखकर मांग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करना है, न कि अदृश्य और अनियमित स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ देना।’^३

श्री एच डी डिकिन्सन (H D Dickinson) ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा इन शब्दों में की है—“आर्थिक नियोजन से अनिवार्य प्रमुख आर्थिक निर्णय करना है। एक केन्द्रीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार

1 “Planning, of course, is a continuous process. Planning does not mean merely giving priorities to things. It is something wider and deeper, the first thing about planning is to have a definite picture of where we are going. This picture must not be very rigid.”
—Jawaharlal

2 ‘Economic planning is essentially a way of organising and utilising resources to maximum advantage in terms of defined social ends. The two main constituents of the concept of planning are—

- (i) a system of ends to be pursued, and
- (ii) knowledge as to available resources and their optimum allocation.”

—Indian Planning Commission (First Five-Year Plan)

3 ‘Economic planning means securing a better balance between demand and supply by a conscious and thoughtful control either of production or of distribution or of both, rather than having this balance to be effected by automatically working invisible and uncontrolled force.”
—H Lev

पर यह विचारपूर्ण निर्णय करना कि क्या और कितना उत्पादन करना है तथा किसको इसका वितरण करना है ।' ४

श्रीमती उटन (Mrs Wootton) के शब्दों में—“आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बाजार यंत्र को स्वेच्छपूर्वक कार्य करने के लिए स्वतन्त्र न छोड़कर इस प्रकार संयुक्त किया जाता है कि वह एक आदर्श बन जाय ।’ ५

प्रो मांरिस डॉब (Prof Maurice Dobb) के अनुसार—‘नियोजन आर्थिक निर्णयों को समन्वित करने का एक यंत्र (mechanism) है—योजना वह विधि है जिसमें अर्थ व्यवस्था के लिए समुक्त निर्णय लिया जाता है जिससे सभी भाग्य-इकाइया एक साथ समायोजित हो सकें ।’ ६

प्रो गुन्नार मिर्डल (Prof Gunnar Myrdal) के शब्दों में—“आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की वह कार्यविधि है जिसमें बाजार की शक्तियों में इस प्रकार हस्तक्षेप करती है जिससे सामाजिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके ।’ ७

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्रियों ने नियोजन को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है । अर्थशास्त्रियों में नियोजन के अर्थ व

- 4 “Economic planning is the making of major economic decisions—what and how much is to be produced and to whom it is to be allocated by the conscious decision of a determinate authority, on the basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole”
—H D Dickinson
- 5 “Economic planning is a system in which the market mechanism is deliberately manipulated with the object of producing a pattern other than which would have resulted from its spontaneous activity”
—Mrs Wootton
- 6 “Planning is a mechanism for co-ordinating economic decisions .. a plan is a method of taking a combined decision about all so that all the separate parts harmonise or fit together”
—Prof Maurice Dobb
- 7 “Economic planning is a programme for the strategy of a national government in applying a system of state interference with the play of market forces, thereby conditioning them in such a way as to give an upward push to the social process”
—Gunnar Myrdal

उद्देश्य के सम्बन्ध में इतना मतभेद है कि सामान्य व्यक्ति नियोजन को सही रूप में समझ नहीं पाता। इन परिभाषाओं में कोई परिभाषा ऐसी नहीं है जो कि आर्थिक नियोजन के अर्थ व उद्देश्य को पूर्णतः स्पष्ट कर सके। प्रत्येक देश ने अपनी परिस्थिति के अनुसार इसे अपना लिया है। केवल इस बात से सभी अर्थशास्त्री सहमत हैं कि नियोजन का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए देश में उपलब्ध साधनों और शक्तियों का प्राथमिकता के आधार पर समुचित उपयोग करना है। देश का विकास सुसंगठित तथा सुसम्बद्ध प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।

आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ (Characteristics of Economic Planning) :

डुबिन (E. F. M. Durbin) ने आर्थिक नियोजन की विशेषताओं को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है —

“नियोजन विभिन्न उद्योगों के स्वेच्छापूर्वक कार्य करने वाले दृष्टिकोण को तनिक भी प्रोत्साहित नहीं करता है। नियोजन भविष्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित दृढ़ सिद्धांत नहीं बताता है। भावी मानवीय इच्छाओं, कलात्मक आविष्कार, सुरक्षा तथा छुट्टी-हाली का वर्णन विस्तारपूर्वक नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी योजनाओं को बनाना मूर्खतापूर्ण है जो कि समाज को आवश्यकताओं तथा परिवर्तनों की ध्यान में रखकर सीधे ही परिवर्तित नहीं की जा सकनी। फिर आयोजन की वास्तविक विशेषता क्या और कहा है? सर्वसाधारण की नवीन योजनाओं पर यदि विचार किया जाय तो हम कह सकते हैं कि नियोजन इच्छाओं के विस्तार को विस्तृत करने का तथा उसके परिणामस्वरूप उसके क्षेत्र को व्यापक करने का प्रवन्ध है।”

विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अवलोकन करने पर नियोजन की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार प्रतीत होती हैं —

- (१) नियोजन आर्थिक संगठन और विकास की एक प्रणाली है।
- (२) नियोजन का निश्चित उद्देश्य होता है। नियोजन के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं जिनकी पूर्ति हेतु नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन के उद्देश्य में समानता होना आवश्यक नहीं है, ये उद्देश्य प्रायः देश की आवश्यकताओं, उपलब्ध साधनों और विकास के स्तर के आधार पर निश्चित किये जाते हैं। लेकिन सभी देशों में

नियोजन द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि उत्पादन में कुशलता प्राप्त हो, वितरण में विषमता कम हो तथा आर्थिक स्थायित्व बना रहे ।

- (३) नियोजित अर्थ-व्यवस्था में केन्द्रीय योजना अधिकारी या केन्द्रीय नियोजन सत्ता (Central Planning Authority) की उपस्थिति होती है । इस सत्ता द्वारा देश के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर आर्थिक विकास के सम्बन्ध में निर्णय लेती है, तथा निर्धारित उद्देश्यों के साथ समन्वय स्थापित करती है । यह अधिकारी या सत्ता स्वयं सरकार होती है या सरकार द्वारा मिली सत्ता की नियुक्ति की जाती है, जैसे—कि भारत में योजना आयोग (Planning Commission) की नियुक्ति की गई है ।
- (४) आर्थिक नियोजन में सम्पूर्ण आर्थिक कार्य योजना के अनुसार सम्पन्न किये जाते हैं । नियोजन का उद्देश्य किसी एक विशेष पहलु का नियोजन न होकर सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का नियोजन होता है ।
- (५) आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत कार्य अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति हेतु किये जाते हैं । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाता है ।
- (६) नियोजित अर्थ व्यवस्था में वर्ग-संघर्ष (class-conflict) का अभाव पाया जाता है, क्योंकि नियोजित अर्थ व्यवस्था में सम्पूर्ण समाज की आवश्यकताओं को महत्व प्रदान किया जाता है ।
- (७) नियोजन एक दीर्घकालीन तथा निरन्तर (continuous) प्रक्रिया है । इसमें अल्पकालीन योजनाओं या दीर्घकालीन योजना के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है ।
- (८) आर्थिक नियोजन के सफल संचालन के लिये जनता का सहयोग आवश्यक है ।
- (९) नियोजन की सफलता और असफलता का समय-समय पर मूल्यांकन करते रहने के लिए मूल्यांकन तंत्र (evaluation machinery) भी रहता है ।

आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं लोकप्रियता के कारण (Need of Economic Planning and causes of its popularity)

प्रो. राबिन्सन का विचार है—“हम सब भले ही समाजवादी न हों परन्तु लगभग हम सभी निश्चिन्त रूप से नियोजन के समर्थक हैं ।”

आज का युग नियोजन का युग है। सभी देश चाहे वह समाजवादी हों या पूँजीवादी या मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के समर्थक हों किसी न-किसी रूप में नियोजन का सहारा अवश्य लेते हैं। इसका कारण यह है कि देश में उपलब्ध साधनों का विकास करने के लिये, उत्पादन में वृद्धि करने और बरोज़गारी की समस्या को हल करने के लिए तथा समाज की विषमताओं को दूर करने के लिए नियोजन ही एकमात्र सहारा है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में न तो साधनों का अपव्यय होता है और न ही कोई साधन बेकार पड़ा रहता है। आर्थिक नियोजन के महत्व में वृद्धि के निम्नलिखित कारण प्रमुख हैं —

(१) पूँजीवाद के दोष (Evils of capitalism)—पूँजीवादी व्यवस्था जिसमें कि अहस्तक्षेप की नीति (Laissez Faire) को अपनाया जाता है, काफी पुरानी व दोषपूर्ण व्यवस्था है। इसमें पूँजी का कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होना, श्रमिकों और गरीबों का शोषण, धन का अपव्यय, वर्ग-संघर्ष आदि दोष पाये जाते हैं, इन दोषों को नियोजन द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

डर्बिन (Durbin) के शब्दों में—“केवल नियोजन ही पूँजीवाद के दोषों को दूर करने का एकमात्र साधन और आशा है।”^१

अतः नियोजन द्वारा पूँजीवाद की बुराइयों को दूर किये जाने के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

(२) अनियोजित अर्थ-व्यवस्था के दोष (Evils of unplanned economy)—अनियोजित अर्थ व्यवस्था में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं —

(अ) व्यापार चक्रों की उपस्थिति अर्थात् कम उत्पादन व अधिक उत्पादन की समस्या।

(ब) प्राकृतिक साधनों का असन्तुलित शोषण तथा उनका अदूरदर्शी उपयोग।

(स) समाज में उपभोग की वस्तुओं का अभाव।

उपरोक्त सभी समस्याओं का हल नियोजन प्रस्तुत करता है। क्योंकि इसमें केन्द्रीय सत्ता द्वारा व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर मांग व पूर्ति में सामंजस्य स्थापित होता है। जास्यचानुसार साधनों का शोषण किया जाता है, तथा उपयोग दीर्घकालीन दृष्टिकोण के आधार पर होता है।

■ “Planning alone provides hope and means of remedying the ill-effects of capitalism”
— Robbins

(३) सोवियत रूस की अभूतपूर्व सफलता (Remarkable achievements of Soviet Russia)—सर्वप्रथम रूस ने पूर्ण आर्थिक नियोजन को १९२८ में अपनाया। रूस ने नियोजित ढंग के स्थायी आधार पर स्वीकार कर देश के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण किया। रूस की अल्पकाल में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति को देखकर अन्य देश भी इसको अपनाने लगे।

(४) आर्थिक महामन्दी (Economic depression)—१९२९ में त्रिवार्षिकी मन्दी फैलने से विश्व के अधिकांश देशों की स्थिति खराब हो गई तथा आर्थिक नियामों काफ़ी सीमित हो गई। तब विश्व के अर्थशास्त्रियों तथा विद्वानों का ध्यान पूँजीवादी व्यवस्था की बुराइयों की ओर गया तथा निरोधन के पक्ष में अधिकांश अर्थशास्त्री हो गये। उसी अवधि में नियोजित ढंग से उत्पादन में वृद्धि की गई तथा आर्थिक संकट से दृढ़ता मिली।

(५) विश्व युद्ध (World-wars)—दो विश्वयुद्धों के प्रभाव के कारण भी नियोजन के महत्व में वृद्धि हुई, क्योंकि युद्ध से पीड़ित देशों को विकास करने के लिए तथा अपनी अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिये नियोजन का सहारा लेना पड़ा। नियोजित ढंग से कार्य करने के कारण ही ये देश पुनर्विस्तारित अवस्था में पहुँच सके।

(६) अर्द्ध-विकसित देशों का उदय (Emergence of under-developed countries)—द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् एशिया और अफ्रीका के बहुत-से देशों को राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद उनमें आर्थिक विकास की प्रबल इच्छा जाग्रत हुई। इन देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया। इन देशों का यह विचार था कि पूँजीवादी व्यवस्था के आधार पर विकास करना सम्भव नहीं है, अतः उपलब्ध साधनों का अधिकतम शोषण करने के लिए तथा समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए नियोजन पद्धति को अपनाया।

(७) आधुनिक आर्थिक विचारधारा (Modern economic ideology)—आधुनिक युग में अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक आयोजन और समाजवाद का समर्थन किया है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने सरकारों को नियोजन को स्वीकार करने की सलाह दी है। शुम्पेटर (Schumpeter) टेलर (Taylor), मॉरिस डब (Maurice Dobb) तथा लर्नर (Lerner) आदि प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक नियोजन के पक्ष में

आज के युग में नियोजन विश्व की अर्थ-व्यवस्थाओं का अविभाज्य अंग बन गया है। आज प्रश्न यह नहीं है कि नियोजन क्यों हो, बल्कि यह है कि नियोजन क्यों नहीं ? आज प्रायः सभी देशों द्वारा आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं ? आधुनिक युग में आर्थिक नियोजन का महत्व क्या बढ़ता जा रहा है ?
 २. आर्थिक नियोजन की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए।
 ३. नियोजन से क्या अभिप्राय है ? आर्थिक नियोजन की कुछ परिभाषायें दीजिए।
 ४. आर्थिक नियोजन की परिभाषा दीजिए तथा इसकी लाक्षणिकता में वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए।
-

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य [Objectives of ~~the~~ Economic Planning]

★ ★ ★

नियोजन एक सतत प्रयत्न है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास करना तथा सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाना है। हमारे लक्ष्य में, उपलब्ध साधनों को इस प्रकार प्रयोग में लाना है जिससे कि उत्पादन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल किया जा सके तथा जीवन-स्तर (standard of life) को ऊँचा उठाया जा सके। नियोजन का उद्देश्य केवल आर्थिक ही नहीं होता बल्कि राजनैतिक व सामाजिक भी होता है। सामान्यतः नियोजन का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन, उचित वितरण, पूर्ण रोजगार, अक्षर की समानता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता आदि तत्वों को प्राप्त करना है। संक्षेप में, नियोजन का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य के सम्बन्ध में सभी अर्थशास्त्रियों में मतभेद नहीं है। किसी अर्थशास्त्री ने अधिकतम उत्पादन को महत्व दिया है तो किसी ने आर्थिक समानता को। किसी ने पूरा रोजगार को प्राथमिकता प्रदान की है तथा किसी ने सामाजिक न्याय को। ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न विचारों को समझ लेना उचित होगा।

बी० सी० घोष (B C Ghosh) ने आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य बताये हैं —

- 1 (a) Planning as we shall understand, means production and distribution with social purpose—not only for a short period but also for a long period
- (b) The attainment of full employment as well as the progressive improvement in the standard of living of the people
- (c) Industrialisation of the country” —B C Ghosh

- (अ) "नियोजन सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन तथा वितरण का अत्यन्त कालीन हो नहीं बल्कि दीर्घकालीन साधन है।
- (ब) पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, साथ-ही-साथ व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर में निरन्तर सुधार।
- (स) देश का औद्योगीकरण।^१

प्रो वी के एच राव (Prof V K R V. Rao) के अनुसार—
एक पूर्ण नियोजित व्यवस्था से अभिप्राय आर्थिक निष्कासों के सम्पूर्ण क्षेत्र—
उत्पादन, उपभोग वितरण तथा मुद्रा आवि—पर पूर्ण नियन्त्रण से है।^२

(मॉरिस डॉब (Mauris Dobb) ने आर्थिक नियोजन के तीन उद्देश्य बताये हैं—

- (अ) आर्थिक जीवन में स्थिरता बनाये रखना,
- (ब) उत्पादन के क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करना,
- (स) वितरण की समानता।

प्रो ए दलाल (Prof A Dalal) के शब्दों में—'नियोजन का उद्देश्य मुख्य रूप से उत्पादन का अधिकतम सीमा तक विकास करना तथा जनता के जीवन रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना है।'^३

भारतीय योजना आयोग के अनुसार भारत में नियोजित विकास के दो उद्देश्य हैं—

- (अ) उत्पादन वृद्धि तथा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, तथा
- (ब) स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्र के मूल्यों के आधार पर ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विकास करना जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओं में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक ग्याप प्राप्त हो।

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न दृष्टिकोणों में दृष्टि भिन्नता है फिर भी वे किसी-न-किसी रूप में सम्बन्धित अवश्य हैं। सामान्यतः नियोजन के उद्देश्य का निर्धारण उस देश की अर्थ व्यवस्था उसने स्वरूप तथा उसकी आवश्यकताओं

2 "A full-fledged planned economy would mean complete control over the entire field of economic activity—production, consumption, distribution, money etc —V K R V Rao

3 "The object of planning is mainly to improve the production to the greatest extent possible and to raise the standard of living of the masses" —A. Dalal

के आधार पर होता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को चार भागों में बांटा जा सकता है —

- (१) आर्थिक उद्देश्य,
- (२) सामाजिक उद्देश्य,
- (३) राजनैतिक उद्देश्य,
- (४) अन्य उद्देश्य ।

१ आर्थिक उद्देश्य (Economic Objectives)

आर्थिक नियोजन में सबसे अधिक महत्व आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति है। प्रारम्भ से ही नियोजन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाने और सम्पन्नता में वृद्धि करने का रहा है। आर्थिक उद्देश्य में निम्नलिखित उद्देश्य सम्मिलित किये जाते हैं —

- (अ) पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास,
- (ब) पूर्ण रोजगार,
- (स) अधिकतम उत्पादन,
- (द) आय की समानता,
- (य) अवसर की समानता,
- (र) प्राथमिक सुरक्षा,
- (ल) पुढोत्तरकालीन पुनर्निर्माण ।

(अ) पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास (Development of backward areas)—आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों का विकास करना होता है, उसी के साथ विकसित क्षेत्रों का और अधिक विकास करना होता है, जिससे कि घब-यवस्था में सभी क्षेत्रों का पर्याप्त विकास हो सके। अथ-यवस्था में सर्वांगीण विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राधानता प्राप्त होती है, जिससे कि सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन-स्तर में समानता आ जाय। अर्द्ध-विकसित देशों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है जैसा कि भारत, चीन तथा अन्य देशों की योजनाओं की देखने से स्पष्ट होता है।

(ब) पूर्ण रोजगार (Full employment)—अर्द्ध-विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या एक प्रमुख समस्या होती है, इस समस्या से छुटकारा पाने के

लिए तथा सभी प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं के विकास के लिए पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना आवश्यक है। प्रो कीन्स का कथन कि "विकास के लिए पूर्ण रोजगार का होना अत्यन्त आवश्यक है", पूर्णतः सत्य है। अतः प्रत्येक नियोजित अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करना होता है। बिना पूर्ण रोजगार प्राप्त किये अधिकतम उत्पादन तथा आर्थिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त करना भी सम्भव नहीं है।

(स) अधिकतम उत्पादन (Maximum production)—प्रत्येक नियोजित अर्थ-व्यवस्था का प्रधान व विशिष्ट उद्देश्य अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। किसी भी देश के व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि उसी स्थिति में सम्भव है जबकि उत्पादन अधिक मात्रा में हो। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किये जाते हैं जिनमें से प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं —

- (अ) मानव शक्ति एवं राष्ट्रीय साधनों का उपयोग उचित प्रकार से किया जाय।
- (ब) उत्पत्ति के साधनों का विवरूपपूर्ण तथा वैज्ञानिक ढंग से पुनर्वितरण।
- (स) नवीनतम तकनीकी ज्ञान, कुशल श्रम तथा योग्य साहसियता का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि करना।
- (द) एकाधिकारी प्रतियोगिता को समाप्त करना तथा अनावश्यक प्रति योगिता पर नियन्त्रण लगाना।
- (इ) श्रमिकों व मालिकों में सघर्ष को कम करना तथा पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना।
- (फ) वचनों को प्रोत्साहित कर अधिक मात्रा में पूँजी विनियोग करना तथा आर्थिक स्थिरता बनाये रखना।

इन विभिन्न उपायों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जाती है, जिससे कि व्यक्तियों को आय में वृद्धि हो और रटन सहन का स्तर ऊँचा हो सके।

(द) आय की समानता (Equality of income)—आधुनिक विश्व में प्रत्येक देश की सरकार का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की आय की असमानता को कम करना हो गया है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण तभी सम्भव है जबकि

आय की असमानताएँ कम हो, अतः आधुनिक सरकार अनेक प्रकार के उपायों द्वारा वितरण की असमानता को कम करने का प्रयत्न करती है। व्यवहार में पूर्ण समानता स्थापित होना सम्भव नहीं है इसलिए कार्य के अनुसार आय-वितरण को समान बनाने का प्रयास किया जाता है। आय-वितरण की असमानता को कम करने के लिए सरकार की नीति—श्रमिकों को भूतन्त्र मजदूरी निर्धारण, मूल्य नियन्त्रण, राशनित व्यवस्था, अधिकतम सम्पत्ति की सीमा निर्धारण आदि उपाय करती है।

(घ) अवसर की समानता (Equality of opportunity)—अवसर की समानता स्थापित करना नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अवसर की समानता का अर्थ देश के समस्त नागरिकों को बाँट कर, विकास करने और जोषिकीपाजन के समान अवसर प्रदान करना है। अवसर की समानता न होने के कारण समाज का एक वर्ग अधिक आय प्राप्त करता है जबकि दूसरा वर्ग कम, इससे समाज दो वर्गों में विभक्त हो जाता है अतः सभी व्यक्तियों को शिक्षण, प्रशिक्षण व विकास के समान अवसर प्रदान कर असमानता को कम करना होता है।

(ग) आर्थिक सुरक्षा (Economic security)—आर्थिक सुरक्षा से अभिप्राय उत्पादन कार्य में लगे सभी साधनों को उचित वार्षिकिक देना तथा ऐसी व्यवस्था करना होता है जिससे कि एक साधन द्वारा दूसरे साधनों का शोषण न हो सके। नियोजन द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि साधनों का शोषण न हो सके। इसके द्वारा श्रमिकों को उचित मजदूरी, साहयिकों के लिए उचित लाभ, पूँजीपतियों के लिए उचित धनाज व भूमिपति के लिए उचित लगान दिवाने के लिए नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं।

(घ) युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण (Post war reconstruction)—युद्ध से अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, मातामृत व सवार के साधन, उद्योग-धन्यो आदि को अपार क्षति होती है। युद्ध की समाप्ति के बाद अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। प्रायः सभी देशों द्वारा पुनर्निर्माण कार्य नियोजन के माध्यम से ही किए जाये हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों ने अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन का ही सहारा लिया। आज युद्ध से प्रभावित सभी देश अपने नागरिकों के जीवन को सुधारने के लिये उद्योग-धन्यो की पुनर्स्थापना के लिए तथा अपने साधनों को विकसित करने के लिए नियोजन का ही माध्यम अपनाते हैं।

२ सामाजिक उद्देश्य (Social Objectives)

आर्थिक उद्देश्यों के साथ-साथ नियोजन के अन्तर्गत सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति का भी लक्ष्य रखा जाता है। सामाजिक उद्देश्य से अभिप्राय 'अधिकतम जनता का अधिकतम कल्याण' से होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति नियोजन द्वारा ही सम्भव है। सामान्यतः सामाजिक उद्देश्यों में दो तत्व सम्मिलित किये जाते हैं

(अ) सामाजिक सुरक्षा,

(ब) सामाजिक समानता।

- (अ) सामाजिक सुरक्षा (Social security)—सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य जन समूह के लिए ऐसी सुविधाओं की उपलब्धि से होता है जिससे कि जनता आवश्यक विपत्तियों से सुरक्षित रह सके। आवश्यक विपत्तियों में बीमारी, बेकारी, बुढ़ावस्था, मृत्यु आदि को रखा जाता है। इन विपत्तियों से सुरक्षा प्रदान करना सामाजिक उद्देश्यों के अन्तर्गत आता है। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा (social insurance) तथा सामाजिक सहायता (social assistance) के द्वारा प्रदान की जाती है। समाजवादी देश रूस के अनिश्चित अन्य विकसित देशों—अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि में इन उद्देश्यों को आजकल प्रधानता प्राप्त है। अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी के अभाव के कारण अभी इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है, यद्यपि सभी देश इस ओर प्रयत्नशील हैं तथा अपने नागरिकों को अधिक-से-अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं।

- (ब) सामाजिक समानता (Social equality)—सामाजिक उद्देश्य के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक समानता को भी महत्व प्रदान किया जाता है। सामाजिक समानता के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों को उचित आदर, सम्मान व स्थान दिलाया जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार समाज के सर्वांगीण विकास के लिये सामाजिक समानता आवश्यक है। समाजवादी देशों में इस प्रकार की समस्या ही नहीं रहती है, जबकि पूँजीवादी देशों में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किये जाते हैं। भारत में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में महत्व प्रदान किया गया है।

३ राजनैतिक उद्देश्य (Political Objectives)

आर्थिक नियोजन के विकास के प्रारम्भिक अवस्था में बहुत-से देशों ने योजनाओं राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनायी थी। रूस की प्रथम योजना तथा जर्मनी में नाजियों

को नियोजित अर्थ-व्यवस्था को धुस्सात राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर हुई थी। आज भी अनेक देशों द्वारा इसी उद्देश्य को पूर्ण हेतु योजनायें बनायी जाती हैं। राजनैतिक उद्देश्य प्रमुख रूप से दो हैं —

(१) सुरक्षा ,

(२) शान्ति ।

(१) सुरक्षा (Security)—किसी भी देश के सामने देश की सुरक्षा करना प्रथम उद्देश्य होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व रूस, जर्मनी आदि देशों की योजनायें सुरक्षा-प्रधान योजनायें थीं। रूस की तृतीय योजना में सुरक्षा को और अधिक महत्व प्रदान किया गया। आज अधिकांश देश अपनी योजनाओं में सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। भारत में १९६२ में चीनी आक्रमण तथा १९६५ और १९७१ के पाकिस्तानी आक्रमणों से पञ्चवर्षीय योजनाओं में सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया है, जिससे कि राष्ट्र को विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों से सुरक्षित रखा जा सके।

(२) शान्ति (Peace)—सामाजिक सुरक्षा के अनिश्चित नियोजन में आंतरिक शान्ति का बनाये रखने को भी महत्व दिया जाता है। देश के विकास के लिये आंतरिक शान्ति रहना परमावश्यक है, इसलिए आजकल 'शान्ति के लिए नियोजन' (Planning for peace) को महत्व दिया जाता है। शान्ति के महत्व में वृद्धि के कारण ही रूस, अमेरिका, भारत आदि देश विश्वशांति के लिए प्रयत्नशील हैं।

कुछ लोग आक्रमण को भी नियोजन के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं, परन्तु आज के युग में इसका महत्व नहीं है। इसका कारण यह कि अब साम्राज्यवाद का युग समाप्त हो चुका है, विश्व में पहले से अधिक जाग्रति है अतः शान्ति के लिए अधिक प्रयत्न किए जाते हैं।

४. अन्य उद्देश्य (Other Objectives) :

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनिश्चित नियोजन के अन्य अनेक उद्देश्य होते हैं, ये उद्देश्य उम देश की स्थिति, वातावरण व साधनों से विद्योप रूप से सम्बन्धित होने हैं। इन उद्देश्यों में प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

(१) जिन देशों में अधिक जनसंख्या है वे जनसंख्या की वृद्धि को दर को कम करने के लिए तथा जिन देशों में कम जनसंख्या है वे जनसंख्या वृद्धि के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाते हैं।

- (२) देश के स्वयं के साधनों का विवास करते आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली बनने के लिए नियोजन अपनाया जाता है।
- (३) देश के सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर को विकसित करने व आधुनिक बनाने के लिए नियोजन को अपनाया जाता है।
- (४) देश के उपलब्ध साधनों के दूरदर्शी उपयोग व उनके सतुलित विकास के लिए नियोजन अपनाया जाता है।
- (५) देश के नागरिकों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्र का विकास करने के लिये नियोजन अपनाया जाता है।

इस प्रकार आर्थिक नियोजन के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा अन्य अनेक उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक देश अपनी क्षमता व साधनों के अनुरूप उनका प्राप्त करने के लिए भरमवर प्रयत्न करता है, जिससे कि उनके नागरिकों के कल्याण में अधिकतम वृद्धि हो सके।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों का समझाइये।
- २ आर्थिक नियोजन में आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिये।
- ३ आर्थिक नियोजन का उद्देश्य मात्र आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति न होकर सामाजिक व राजनैतिक उद्देश्यों को भी प्राप्त करना है।
- ४ आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।

आर्थिक नियोजन के प्रकार एवं तकनीक

[Types and Techniques of Economic Planning]

* * * *

आज का युग नियोजन का युग है। प्रत्येक देश अपना आर्थिक विकास करने

तथा उपलब्ध साधनों के अनुकूलतम प्रयोग के लिए नियोजन को अपनाता है। अर्थ-व्यवस्थाओं की भिन्नता तथा आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक पृष्ठभूमि में अन्तर होने के कारण विभिन्न देशों में नियोजन के विभिन्न स्वरूपों को अपनाया है। रॉबिन्स ने कहा है कि 'आज समस्या इस बात की नहीं है कि नियोजन हो या न हो, बल्कि नियोजन के विभिन्न रूपों के सम्बन्ध में है'।¹ वास्तविकता यह है कि प्रत्येक देश ने अपनी परिस्थिति व आवश्यकतानुसार नियोजन को अपना लिया है जिससे इसके रूप बहुत से हो गये हैं।

वर्तमान समय में आर्थिक नियोजन के वर्गीकरण का कोई सर्वमान्य व वैज्ञानिक आधार नहीं है। जिस अर्थ-व्यवस्था के लिए कौन-सा प्रकार सर्वोत्तम होगा, इस सम्बन्ध में भी भर्त्सक नहीं है, इसका कारण है यह है कि प्रत्येक देश ने नियोजन का चुनाव अपनी सुविधानुसार तथा अपनी आवश्यकतानुसार किया है। इस प्रकार सर्वमान्य वर्गीकरण के अभाव में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण को ले रहे हैं।

डॉ. तंला, प्रो. मेहता एव जैन ने आर्थिक नियोजन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है —

1 "The issue is not between a plan and no plan, it is between different kinds of plans"
—L. Robbins

१ आर्थिक कार्य क्षेत्र के अनुसार —आर्थिक कार्य क्षेत्र के अनुसार नियोजन चार प्रकार का होता है—

- (अ) सामान्य एवं आर्थिक नियोजन,
- (ब) क्रियात्मक एवं संरचनात्मक नियोजन,
- (स) सुधारवादी एवं विकासवादी नियोजन,
- (द) क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नियोजन ।

२ आर्थिक संगठन की प्रकृति के अनुसार (According to nature of economic organisation)—आर्थिक संगठन की प्रकृति के आधार पर भी नियोजन को चार भागों में बाटा है—

- (अ) पूँजीवादी नियोजन,
- (ब) समाजवादी नियोजन
- (स) प्रजातन्त्रीय नियोजन,
- (द) सर्वोदयी या माधोवादी नियोजन ।

३ आर्थिक निर्णयों के संचालन के अनुसार (According to implementation of economic decisions)—इसके अंतर्गत नियोजन को तीन भागों में बाटा है—

- (अ) धानाभूतल एवं प्रोत्साहन मूलक नियोजन,
- (ब) केन्द्रित एवं विकेंद्रित नियोजन,
- (स) 'ऊपर' से नियोजन एवं 'नीचे' से नियोजन ।

४ कार्यक्रमों की निर्धारित क्रम के अनुसार —कार्यक्रमों की निर्धारित करने के अनुसार नियोजन को एक वर्ग में बाटा है

भौतिक एवं वित्तीय नियोजन ।

५ नियोजन काल की अवधि के अनुसार (According to planning period)—इस आधार पर नियोजन को दो भागों में बाटा है—

- (अ) अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नियोजन,
- (ब) स्थायी एवं आपतकालीन नियोजन ।

उपरोक्त वर्गीकरण सर्वमान्य वर्गीकरण नहीं है केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ही लिया गया है । विभिन्न विद्वानों और अर्थशास्त्रियों ने वर्गीकरण के अनेक आधार

दिये हैं। नियोजन के उपर्युक्त विभिन्न प्रकारों (types) का अब अलग-अलग अध्ययन करेंगे।

१. आर्थिक कार्य क्षेत्र अनुसार

(घ) सामान्य एवं आंशिक नियोजन (General and partial planning).—सामान्य नियोजन सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए अपनाये गये नियोजन को कहते हैं जबकि आंशिक नियोजन किसी क्षेत्र या समस्या विशेष के लिये किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों और भागों के विकास के लिए किया जाने वाला नियोजन सामान्य नियोजन है तथा विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए किया जाने वाला नियोजन आंशिक नियोजन कहा जाता है। प्रो. लेविस (Lewis) ने आंशिक नियोजन को खण्डित नियोजन (piece-meal planning) कहा है। अधिकांश व्यवशास्त्री आंशिक नियोजन का 'अधूरा' मानते हैं तथा देश में विकास के लिए इसे पर्याप्त नहीं मानते।

प्रो. रॉबिन्स (L. Robbins) के शब्दों में—“आंशिक नियोजन की स्थिति, नियोजन के अभाव की स्थिति से भी खराब होती है।”^१

अतः सामान्य नियोजन को ही वास्तविक नियोजन मानते हैं।

एववहार में सामान्य नियोजन रूस, चीन, भारत आदि देशों ने अपनाया है, जबकि आंशिक नियोजन अमेरिका (न्यू डील पालिसी), जर्मनी आदि ने अपनाया है।

(ग) क्रियात्मक एवं संरचनात्मक नियोजन (Functional and structural planning).—क्रियात्मक नियोजन वह नियोजन है जिसमें प्रचलित अर्थ-व्यवस्था के अस्तित्व ही विकास कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। संरचनात्मक नियोजन में अर्थ-व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन करके नये विकास कार्यक्रम बनाये जाते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रियात्मक नियोजन में अर्थ-व्यवस्था को संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता जबकि संरचनात्मक नियोजन में अर्थ-व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया जाता है।

क्रियात्मक नियोजन के सम्बन्ध में डा. ज़्वैग (Dr. Zweig) का विचार है—
क्रियात्मक नियोजन केवल सुधार का प्रयत्न है एक नया रूप नहीं दे सकता,

2 “Where there is a partial planning, the position is worse than it would be with no planning at all”
—L. Robbins

यह केवल विद्यमान अर्थ-व्यवस्था को सुधार सकता है न कि उसे आगे बढ़ा सकता है।³

किसी भी देश के सम्पूर्ण आर्थिक विकास के लिए सरचनात्मक नियोजन आवश्यक है। भारत द्वारा इसी को अपनाया गया है। पूँजीवादी देशों में कहीं-कहीं क्रियात्मक नियोजन को अपनाया गया है। अर्थशास्त्रियों का विचार है कि एक सीमा के बाद क्रियात्मक और सरचनात्मक नियोजन का अन्तर समाप्त हो जाता है। यह प्रायः उस अवस्था में होता है जबकि एक देश विकास में उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है, जैसे—इस में वर्तमान में इन दोनों रूपों में अंतर नहीं किया जाता।

(स) सुधारवादी एवं विकासवादी नियोजन—(Corrective planning and developmental planning)—सुधारवादी नियोजन विकसित पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में अपनाया जाता है जबकि विकासवादी नियोजन उन देशों में जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम है। सुधारवादी नियोजन अस्थायी प्रवृत्ति का होता है, इसका प्रयोग किसी समस्या विशेष से छुटकारा पाने के लिए या अर्थ-व्यवस्था के दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, इसलिए हिगिन्स (Higgins) ने इसे 'बाधा निवारक नियोजन' (trouble shooting planning) कहा है। विकासवादी नियोजन अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में अपनाया जाता है जहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र के विकास की तीव्र आवश्यकता महसूस की जाती है।

(द) क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन (Regional national & international planning)—क्षेत्रीय नियोजन से अभिप्राय उस नियोजन से है 'जो कि किसी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत किया जाता है।' कभी-कभी क्षेत्रीय नियोजन से अभिप्राय एक क्षेत्र के लिए पूर्णतः स्वतंत्र आर्थिक नियोजन से होता है।

राष्ट्रीय नियोजन से अभिप्राय सम्पूर्ण देश के समस्त क्षेत्रों के विकास से होता है। सामान्यतः नियोजन से अभिप्राय राष्ट्रीय नियोजन से होता है। इसके अन्तर्गत उपलब्ध साधनों का अनुकूलनम उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है।

3 "Functional planning will only repair not build a new, it will improve the work of the existing order, but not supercede it"

—Dr. Zweig

अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन से अभिप्राय उस नियोजन से है जिसमें एक से अधिक राष्ट्रों की सम्पत्ति व साधनों की सम्मिलित सम्पत्ति व साधन मानकर उनके विकास की योजनायें बनायी जाती हैं। इस प्रकार नियोजन का अंश एक राष्ट्र से बढ़कर अन्तर्राष्ट्रीय हो जाता है। परन्तु इसका केवल सैद्धान्तिक महत्व ही है, व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन सम्भव नहीं है।

२ आर्थिक समूहों की प्रकृति के अनुसार

(अ) पूँजीवादी नियोजन (Capitalist planning)—पूँजीवादी नियोजन यह है जो कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाता है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था जो कि अधिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप की नीति तथा स्वतन्त्र प्रतियोगिता पर आधारित होती है, और आर्थिक नियोजन को परस्पर एक-दूसरे का विरोधी माना जाता है। इसका कारण यह है कि नियोजन में हस्तक्षेप व नियन्त्रण आवश्यक है जबकि पूँजीवादी में इनको कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। परन्तु अनुभव इस बात को सिद्ध करता है कि पूँजीवाद व नियोजन का सह-अस्तित्व सम्भव है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में नियोजन क्रियात्मक (functional) तथा सुधारवादी (corrective) ही होता है। जैसे—अमेरिका द्वारा १९३० व १९४६ में मन्दी निवारक नियोजन तथा बेरोजगारी निवारक नियोजन अपनाया गया। इंग्लैंड द्वारा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (१९६५-७०) की घोषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीवाद व नियोजन साथ-साथ चल सकते हैं। नियोजन द्वारा सर्वांगीण विकास के लिये अर्थ-व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है।

(ब) समाजवादी नियोजन (Socialist planning)—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर सरकार का नियन्त्रण होता है तथा सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार होता है। उपभोक्ताओं की स्वतन्त्रता सीमित कर दी जाती है और निजी क्षेत्र का महत्व काफी कम हो जाता है। इस अवस्था में नियोजन जनता के अधिकतम कल्याण के लिए किया जाता है तथा आर्थिक गतिविधियों का संचालन सरकारी नियंत्रण में होता है।

साम्यवादी नियोजन (Communist planning)—साम्यवादी नियोजन समाजवादी नियोजन का बढोतर रूप है। इसके अन्तर्गत उत्पादन के सभी साधन सरकारी नियन्त्रण में होते हैं तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया जाता है। व्यक्तियों को निजी सम्पत्ति रखने की छूट नहीं होती है। इस प्रकार समस्त आर्थिक क्रियाओं पर नियन्त्रण सरकार द्वारा होता है, साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन भी नियमित व निर्देशित होता है। इस साम्यवादी नियोजन का

घेष्ट उदाहरण हैं। इसमें समस्त साधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि देश का विकास शीघ्र हो सके और व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके।

दिकिन्सन सम्यवादी नियोजन को घेष्ट मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार इसमें साधनों पर समाज का एकाधिकार हो जाता है और इन साधनों को निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाया जाता है।

पीपु के शब्दों में—“यदि समाजवादी नियोजन पद्धति का सगठन प्रभावपूर्ण है तो यह वर्तमान प्रणाली से कई अर्थों में अधिक पसन्द की जायेगी।”^४

- (स) **प्रजातन्त्रीय नियोजन (Democratic planning)**—समाजवादी व समाजवादी नियोजन का मिश्रित रूप प्रजातन्त्रीय नियोजन है। प्रजातन्त्रीय नियोजन प्रायः मिश्रित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में अपनाया जाता है। इसमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण नहीं लगाये जाते और न ही दबाव का प्रयोग होता है। सरकार या केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण उद्योग-धर्मों और व्यवसायों को सरकार अपने नियन्त्रण में ले लेती है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सहयोग करता है।

प्रजातन्त्रीय नियोजन में नियोजन के उद्देश्य, तरीक़ों आदि का निर्धारण ऊपर से न किया जाकर जनता की राय से व जनता द्वारा किया जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूर्णतः प्रजातन्त्रीय तरीक़ों का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोगों का विचार है कि प्रजातन्त्र में नियोजन सम्भव नहीं है, परन्तु यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता। आज विश्व के अधिकांश मिश्रित अर्थ व्यवस्था वाले देश जो कि प्रजातन्त्र पर आस्था रखते हैं, आर्थिक नियोजन को अपनाये हुए हैं, और अपने देश का विकास नियोजन के माध्यम से ही कर रहे हैं। यहाँ श्री गुन्नार मिर्दल (Gunnar Myrdal) का कथन उल्लेखनीय है, उन्हीं के शब्दों में—

“मैंने इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा है जहाँ पर अत्याधिक नियोजन और राज्य हस्तक्षेप के द्वारा प्रजातन्त्र नष्ट हुआ हो किन्तु इससे विपरीत अनेक उदाहरण हैं।”^५

4 “The system of socialist control planning, if it could be effectively organised, would in many respects be preferable to our existing system”
—Prof Pigou

5 “I find no example in history where democracy has been lost because of too much planning and State intervention, but plenty of examples of the contrary”
—Gunnar Myrdal

(द) सर्वोदयी या गांधीवादी नियोजन (Servodaya or Gandhian planning)—सर्वोदयी या गांधीवादी नियोजन भारत की देन है। गांधीवादी विचारों पर आधारित नियोजन को गांधीवादी या सर्वोदयी नियोजन कहते हैं। यह नियोजन आर्थिक तथा आध्यात्मिक दशन पर आधारित है। आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, धन का समान वितरण, वर्गहीन समाज, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, आत्मनिर्भरता इस नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं। इस उद्देश्यों को सत्य, अहिंसा, श्रम की महत्ता, सहयोग आदि सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। सर्वोदयी नियोजन में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे प्रत्येक ग्राम आत्मनिर्भर हो और देश का सन्तुलित विकास हो सके।

३ प्राथमिक निर्णयों के संचालन के अनुसार

(भ) आज्ञामूलक एवं प्रोत्साहन मूलक नियोजन (Planning by direction and planning by inducement)—प्रोत्साहन के अनुसार नियोजन दो प्रकार से हो सकता है—आज्ञामूलक नियोजन तथा प्रोत्साहनमूलक नियोजन। आज्ञामूलक नियोजन में सरकार प्रत्यक्ष रूप से नियोजन का कार्य-व्ययन करती है जबकि प्रोत्साहनमूलक नियोजन में सरकार अप्रत्यक्ष रूप से नियोजन के उद्देश्यों को पूरती है।

आज्ञामूलक नियोजन को 'निर्देशन द्वारा नियोजन' (planning by direction) भी कहते हैं। इसमें केन्द्रीय नियोजन सत्ता (central planning authority) द्वारा सक्षय व उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए आदेश प्रसारित किये जाते हैं। इस प्रकार के नियोजन में व्यक्तियों की स्वतन्त्र इच्छा समाप्त हो जाती है। व्यवसाय का चुनाव, सामानों का वितरण आदि केन्द्रीय सत्ता द्वारा ही निर्धारित होता है। किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा और उसका वितरण किस प्रकार होगा, यह नियोजन सत्ता पर ही निर्भर करता है। वास्तव में इस प्रकार के नियोजन में आदेश प्रसारित कर दिये जाते हैं, तथा सक्षयों तथा उद्देश्यों की पूर्ति बलपूर्वक (by force) कराई जाती है।

प्रोत्साहनमूलक नियोजन सहयोग, प्रोत्साहन एवं प्रलोभन पर आधारित होता है। इसमें भी उद्देश्य एवं लक्ष्य केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित होते हैं, परन्तु इनकी पूर्ति हेतु आदेश या बल का प्रयोग नहीं होता। प्रोत्साहन एवं प्रलोभन द्वारा जनता या सहसियों को उस दिशा में कार्य करने को प्रेरित किया जाता है। इसमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन नहीं होता। सत्ता उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मौद्रिक व प्रचुरता नीतियों तथा अन्य विधियों का सहारा लेती है। इसमें बाजार

व्यवस्था को प्रायः स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने दिया जाना है। सामान्यतः आज्ञामूलक नियोजन साम्यवादी देशों में अपनाया जाता है तथा प्रोत्साहनमूलक नियोजन पूँजीवादी व मिश्रित अर्थ व्यवस्था वाले देशों में।

आज्ञामूलक नियोजन की विशेषताएँ

आज्ञामूलक नियोजन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

- (क) नियोजन का कार्य जनता की स्वतन्त्र इच्छा पर नहीं छोड़ा जाता बल्कि आदेशों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य कराया जाता है।
- (ख) केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा कार्य कराया जाता है।
- (ग) प्रारम्भ में नियोजन की रूपरेखा तैयार करते समय जनता की राय प्राप्त की जाती है, परन्तु नियन्त्रण में जनता की उपेक्षा की जाती है।
- (घ) इसमें विकास की गति अधिक तन्त्र रहती है।
- (ङ) यह साम्यवादी व समाजवादी देशों द्वारा अपनाया जाता है।

आज्ञामूलक नियोजन के दोष

प्रो. लैबिन्स के अनुसार इसमें निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं जिसके कारण इसकी सफलता पर सन्देह होता है —

- (क) आज्ञामूलक नियोजन के अन्तर्गत यथार्थ व पूर्णतः ठीक निर्णयों का लिया जाना आवश्यक है। परन्तु व्यवहार में इस प्रकार के निर्णय करना अत्यन्त कठिन है।
- (ख) इस नियोजन में पुनर्विचार व संशोधन का अभाव पाया जाता है, जिससे लौचहीन हो जाता है।
- (ग) आज्ञामूलक नियोजन का नियन्त्रण केन्द्रीय सत्ता द्वारा नियुक्त बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अतएव नौकरशाही का बोल-वाला होता है और यह व्यवस्था महंगी पड़ती है।
- (घ) इस नियोजन में व्यक्ति की उपयोग की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है तथा व्यवसाय के चुनाव आदि की स्वतन्त्रता भी निषिद्ध होती है। इसमें तानाशाही प्रवृत्ति के कारण सफलता की कम सम्भावना रहती है।
- (ङ) आज्ञामूलक नियोजन में विकास की गति हमेशा तेज नहीं होती। यह सम्भव है कि कठोर नियन्त्रण व परिणामस्वरूप विकास की गति प्रोत्साहनमूलक नियोजन की अपेक्षा धीमी हो।

प्रोत्साहनमूलक नियोजन की विशेषताएँ -

प्रोत्साहनमूलक नियोजन की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

- (क) इसमें केन्द्रीय सत्ता उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाते हैं तथा उनकी पूर्ति हेतु अप्रत्यक्ष तरीकों का प्रयोग किया जाता है।
- (ख) इस नियोजन में नियन्त्रण सगाये जाते हैं, परन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन नहीं होता।
- (ग) उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनसहयोग प्राप्त किया जाता है तथा यह सहयोग प्रलोभन तथा प्रोत्साहन के आधार पर लिया जाता है।
- (घ) प्रोत्साहनमूलक नियोजन पूँजीवादी व मिश्रित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में अपनाया जाता है। साम्यवादी देशों में जहाँ पर कठोर नियन्त्रण रहता है, वहाँ यह सम्भव नहीं है।

प्रोत्साहन मूलक नियोजन के दोष

प्रोत्साहन मूलक नियोजन में अनेक दोष पाये जाते हैं, जिनमें प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं :

- (क) प्रोत्साहन मूलक नियोजन में प्रायः भाग व पूर्ति के मध्य ठीक समतुलन स्थापित नहीं हो पाता जिससे कम या अधिक उत्पादन की समस्या रहती है।
 - (ख) इसके साधनों में कम गतिशीलता की समस्या पाई जाती है। यह समस्या भाव-नात्मक, भौतिक एवं भौगोलिक कठिनाइयों के कारण रहती है, जिसे प्रोत्साहन के द्वारा हल किया जा सकता है।
 - (ग) जनता पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण के अभाव में सफलता की सम्भावना कम रहती है।
- दोनों में कौन-सी प्रणाली श्रेष्ठ है ?

आज्ञामूलक नियोजन श्रेष्ठ है या प्रोत्साहनमूलक नियोजन, इस सम्बन्ध में निश्चित मत नहीं दिया जा सकता। साम्यवादी देश आज्ञामूलक को अपनाते हैं और श्रेष्ठ मानते हैं जबकि पूँजीवादी प्रोत्साहनमूलक को श्रेष्ठ समझते हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, दोनों में कुछ गुण हैं तथा कुछ दोष। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में प्रोत्साहनमूलक नियोजन श्रेष्ठ होगा क्योंकि इसमें व्यक्ति की उपभोग व उत्पादन की स्वतन्त्रता बनी रहती है। इसमें अधिक दबाव नहीं होते व्यक्ति अपनी इच्छानुसार व्यवहार

का चुनाव कर सकता है। उपभोक्ता की स्वतन्त्रता की रक्षा तथा चुनाव की स्वतन्त्रता के कारण प्रोत्साहनमूलक प्रणाली को प्रेष्ठ माना जाता है।

वास्तव में कोई भी देश न तो पूर्ण आज्ञामूलक नियोजन को अपना सकता है और न ही पूर्ण प्रोत्साहनमूलक नियोजन को। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति और पर्याप्त सफलता के लिए दोनों का समिश्रण आवश्यक है। प्रोत्साहनमूलक नियोजन आंशिक नियोजन है जबकि आज्ञामूलक कठोर नियन्त्रण, अतः व्यवहार में आवश्यकतानुसार इन दोनों का प्रयोग होना चाहिए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रोत्साहन मूलक थी, लेकिन द्वितीय योजना से सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ आज्ञामूलक नियोजन का प्रारम्भ हुआ। आज का नियोजन दोनों का सम्मिलित रूप है।

केन्द्रित नियोजन एवं विकेन्द्रित नियोजन (Centralised planning and decentralised planning)—केन्द्रीय नियोजन से अभिप्राय उस नियोजन से है जिसमें मुख्य निर्णय केन्द्रीय सत्ता द्वारा लिये जाते हैं। विकेन्द्रित नियोजन में कुछ निर्णय केन्द्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं तथा शेष निर्णय सरकार व निजी व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। केन्द्रित नियोजन उन देशों में अपनाया जाता है जहाँ उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का नियन्त्रण रहता है, जबकि विकेन्द्रित नियोजन प्रजातन्त्रीय देशों में जहाँ मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पायी जाती है, अपनाया जाता है। मॉरिस डाव विकेन्द्रित नियोजन को नियोजन का शुद्ध स्वरूप नहीं मानते हैं। वर्तमान युग में शुद्ध केन्द्रित या विकेन्द्रित नियोजन का पाया जाना कठिन है। आज अधिकांश देश अपनी अर्थ-व्यवस्थानुसार केन्द्रित व विकेन्द्रित नियोजन को स्वीकार करते हैं।

(स) **ऊपर से नियोजन एवं नीचे से नियोजन (Planning from above and planning from below)**—‘ऊपर’ से नियोजन से अभिप्राय उस नियोजन से है जो कि संगठित और अर्द्ध-संगठित आर्थिक क्षेत्रों को और अधिक विकसित करने के लिये किया जाता है। ‘नीचे’ से नियोजन से अभिप्राय उस नियोजन से है जो कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाता है। ऊपर से नियोजन में सम्पन्न वर्ग को अधिक लाभ प्राप्त होने हैं, जबकि नीचे से नियोजन में निम्न वर्ग को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। नीचे से नियोजन वास्तव में विकेन्द्रित नियोजन होता है। ‘नीचे से नियोजन’ ‘ऊपर से नियोजन’ की अपेक्षा थोड़ा समझा जाना है, क्योंकि ऊपर से नियोजन इस प्रकार होता है कि “The first will get first and the last will get or not, it is always uncertain” जबकि नीचे से नियोजन में “The last will get first” का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है।

भारत ■ चार पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात् भी सामान्य आदमी की स्थिति अच्छी नहीं हुई है, इसलिए कुछ विद्वानों व अर्थशास्त्रियों का विचार है कि भारत में 'नीचे से नियोजन' के सिद्धान्त में स्वीकार किया जाना चाहिये । महात्मा गांधी का विचार भी इसी प्रकार का रहा है ।

४ कार्यक्रमों को निर्धारित करने ■ अनुसार

भौतिक नियोजन एवं वित्तीय नियोजन (Physical planning and financial planning)—जब नियोजन करते समय नियोजन अधिकारी भौतिक साधनों को ध्यान में रखता है तो उसे भौतिक नियोजन कहते हैं, तथा जब वित्तीय साधनों को ध्यान में रखता है तो उसे वित्तीय नियोजन कहते हैं । भौतिक नियोजन में देश के भौतिक साधन सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा उपलब्धियों के अध्ययन के आधार पर नियोजन कार्यक्रम निर्धारित होते हैं । इसमें देश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में न रखकर भ्रम, झगड़ार, वस्तुयें और मशीनों को ध्यान में रखा जाता है ।

वित्तीय नियोजन में वित्तीय साधनों पर अधिक जोर दिया जाता है । इसके अनुसार नियोजन सत्ता को नियोजन की वित्तीय आवश्यकता को देखकर ही व्यवस्था की जाती है । योजना आयोग के शब्दों में

“वित्तीय नियोजन का सार इस बात में है कि मांग व पूर्ति को इस प्रकार समायोजित किया जाय कि मूल्य ढांचे (price structure) में बिना किसी बड़े तथा अनियोजित परिवर्तन के भौतिक साधनों का पूर्ण उपयोग हो सके ।”^६

आर्थिक विकास तभी सम्भव है जबकि अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाय । केवल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से विकास होना सम्भव नहीं है, क्योंकि यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाय और वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़े तो यह केवल मुद्रा प्रसार की ही जगह देगा । परन्तु मुद्रा का महत्व यह कि उत्पादन में सहयोग देने वाले विभिन्न साधनों को इसी के माध्यम से उत्पादन कार्य में लगाया जा सकता है ।

देश के विकास के लिए कुछ विद्वान भौतिक नियोजन पर जोर देते हैं तथा कुछ वित्तीय नियोजन पर । सामान्यतः पूँजीवादो व्यवस्था में वित्तीय नियोजन को प्राथमिकता

6 “The essence of finance planning is to ensure that the demand and supplies are matched in a manner which exploits physical potentialities as fully as possible without major and unplanned change in the price structure”
—Planning Commission

प्राप्त है जबकि समाजवादी में भौतिक नियोजन को । भारत में भी अर्थशास्त्री दो वर्गों में बंटे हैं—प्रो बी शर्मा शिनाय (Prof B R Shenoy) वित्तीय नियोजन का उचित बताते हैं, जबकि प्रो पी सी महालनगोस भौतिक नियोजन को । स्व. पंडित नेहरू ने भौतिक नियोजन को अधिक महत्व दिया यद्यपि उन्होंने वित्तीय पहलु को नजरअन्दा नहीं किया । आज अधिकांश देश वित्तीय व भौतिक दोनों को ही आवश्यकतानुसार महत्व देते हैं, क्योंकि दोनों ही विकास की सही स्थिति का पता लगाने और विकास को गति देने के लिए आवश्यक है । वास्तव में, भौतिक व वित्तीय नियोजन का विवाद भी निरर्थक है । दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं । अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों में समुलन रखना आवश्यक है । डा बालकृष्णन (Dr Balkrishnan) का कथन इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । उन्हों के शब्दों में

“भौतिक व वित्तीय नियोजन का विवाद आवश्यक है क्योंकि दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं । भौतिक नियोजन अपने प्रयत्नों में छुट्ता सान के लिये परमाश्रय है । लेकिन भौतिक नियोजन को गति देने वाला वित्त है । दोनों में से किसी एक के द्वारा वस्तुएँ ठीक नहीं की जा सकती जब तक कि दोनों में समन्वय न हो ।”

नियोजन काल की भवधि के अनुसार

(घ) अल्पकालीन एवं दीर्घ कालीन नियोजन (Prospective and perspective planning)—प्रो लेविस ने योजना काल के अनुसार तीन प्रकार की योजनाएँ बताई हैं—अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन । अल्पकालीन नियोजन की अवधि एक वर्ष की होती है, मध्यकालीन नियोजन तीन से सात वर्ष तक तथा दीर्घकालीन नियोजन १० से २० वर्ष तक का होता है । अल्पकालीन योजनाएँ प्रायः तात्कालिक समस्याओं के निवारण हेतु बनाई जाती हैं तथा इनमें कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं कि वे दीर्घकालीन सद्व्यवस्था की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकें । दीर्घकालीन योजनाएँ व्यापक विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं । सामान्यतः प्रारम्भ में अधिकांश देश तीन से पांच वर्षीय योजनाएँ

“The controversy between financial and physical planning is needless as the two are not really contradictory Physical planning is absolutely essential for giving correctness to effort But finance is the mobiliser of physical planning Neither financial nor physical planning by itself can set things going without an integration between them ”

—Dr Balkrishnan

बनाते हैं, क्योंकि इसमें योजना के आधार पर विकास की प्रगति का सही लेखा-जोखा हो जाता है। इसके अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण भी दीर्घकालीन योजनाएँ बनाना संभव नहीं हो पाता।

- (ब) स्थायी एवं आपत्कालीन नियोजन (Permanent and emergency planning)—स्थायी नियोजन वह नियोजन है जो कि किसी देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि में रखकर किया जाता है यह नियोजन बाद में अर्थ-व्यवस्था का एक अंग बन जाता है। सामान्यतः दीर्घकालीन नियोजन ही स्थायी नियोजन में परिणित हो जाता है।

आपत्कालीन नियोजन अल्पकालीन नियोजन होता है जो कि किसी समस्या विशेष का निराकरण करने के लिये अपनाया जाता है। इस प्रकार के नियोजन प्रायः अस्थायी प्रकार के होते हैं। आपत्कालीन नियोजन उन देशों के द्वारा अपनाया जाने है जिनका नियोजन पर विश्वास नहीं होता है। स्थायी नियोजन संरचनात्मक नियोजन (structural planning) के सिद्धान्त पर आधारित हैं, और आपत्कालीन नियोजन सुधारवादी नियोजन (corrective planning) पर आधारित है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ आर्थिक नियोजन की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकार बताइये।
- २ आर्थिक नियोजन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
- ३ आजीवन नियोजन एवं प्रोत्साहन मूलक नियोजन में क्या अन्तर है, और क्यों?
- ४ आजीवन नियोजन एवं प्रोत्साहन मूलक नियोजन में क्या अन्तर है? इन दोनों के गुणों व दोषों की व्याख्या कीजिये।
- ५ भौतिक नियोजन तथा वित्तीय नियोजन में क्या अन्तर है।
- ६ निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये —

(अ) क्रियात्मक एवं संरचनात्मक नियोजन (Functional and structural planning) ,

- (व) सुधारवादी एवं विकासवादी नियोजन (Corrective and developmental planning) ,
 - (ख) पूंजीवादी एवं समाजवादी नियोजन (Capitalist and socialist planning) ,
 - (द) केन्द्रित एवं विकेन्द्रित नियोजन (Centralised and decentralised planning) ,
 - (घ) अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नियोजन (Prospective and perspective planning) ।
-

प्रथम पंचवर्षीय योजना [First Five Year Plan]

* * *

भारत एक अर्द्ध-विकसित देश है। यहाँ पर प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर भी राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। व्यक्तियों का उत्पादन तथा उपभोग का स्तर नीचा है। बेरोजगारी, अशिक्षा, निधनता, धन के वितरण की असमानता, असतुलित आर्थिक विकास आदि की समस्याएँ हैं। इन समस्याओं को दूर करने तथा देश में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नियोजन एक आवश्यक शक्ति है, अतः भारत में इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिये नियोजन का सहारा लिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कहा गया है—

“एक अर्द्ध-विकसित देश के सामने केवल वर्तमान आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के छाये में भीतर और अधिक परिणाम प्राप्त करने का ही प्रश्न नहीं होता, बल्कि उन्हें इस तरह ढालने और बनाने की समस्या होगी है जिससे वे और अधिक विस्तृत और गहरे सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति में प्रभावशाली ढंग से योगदान कर सकें। इन उद्देश्यों की पूर्ति आर्थिक नियोजन के माध्यम से ही सम्भव है।

भारत में स्वतन्त्रता-पूर्व किए गए आर्थिक नियोजन सम्बन्धी प्रयत्न
(Pre-Independence Attempts of Economic Planning in India)

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा था, अतः उस समय अनेक विद्वानों, राजनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने इस ओर प्रयत्न किये, परन्तु उन प्रयत्नों में सफलता प्राप्त नहीं हुई।

सर्वप्रथम १९३४ में भारतीय इन्जीनियर एव राजनीतिज्ञ विवेकेश्वरैया ने नियोजन की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने अपनी पुस्तक 'नियोजित अर्थ व्यवस्था' (Planned Economy) में आर्थिक विकास के सम्बन्ध में योजना की रूप-रेखा प्रस्तुत की और यह बताया कि देश का आर्थिक विकास नियोजित ढंग से हो किया जा सकता है। १९३४-३५ में भारतीय आर्थिक सम्मेलन (Indian Economic Conference) की वार्षिक बैठक में इस पुस्तक में दिये गए आर्थिक सुझावों पर खुलकर चर्चा हुई, परन्तु परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण कुछ समय के लिये यह विचार स्थगित हो गया।

९ अक्टूबर १९३८ को कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि गरीबों, बेरोजगारी आर्थिक पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये औद्योगीकरण आवश्यक है। अतः बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास को महत्व दिया गया तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए भी प्रोत्साहन की नीति अपनायी गई। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्व पण्डित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning Committee) की स्थापना की गई। इस समिति ने आर्थिक नियोजन को व्यवहार रूप देने तथा देश के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये। परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने के कारण इस समिति के कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

जनवरी सन् १९४४ में भारत में प्रमुख आठ उद्योगपतियों ने १५ वर्षीय आर्थिक विकास की योजना तैयार की। इसे 'बम्बई योजना' के नाम से पुकारते हैं। बम्बई योजना में जो कि १५ वर्ष के लिए बनाई गई थी, इसे तीन चरणों में पूरा करना था। इस योजना में १०,००० करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान था। यह योजना मुख्यतः पूँजीवादी योजना थी, इसका उद्देश्य औद्योगीकरण द्वारा सतृप्त अर्थ व्यवस्था स्थापित करना था। परन्तु यह योजना भी व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर सकी।

अग्रे १९४४ में एम. एन. राय ने एक दस वर्षीय योजना प्रस्तुत की। इस योजना का 'जन योजना' (The People's Plan) का नाम दिया गया। इस योजना में १५,००० करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया।

सन् १९४४ में ही थोमसरायण द्वारा 'गांधीवादी योजना' (The Gandhian Plan) प्रस्तुत की गई। यह योजना एक आदर्शवादी योजना थी जो कि विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था, कुटीर-उद्योग एवं गांवों की स्वावलम्बी बनान पर अधिक धोर देती थी। यह योजना दस वर्षीय थी जिसमें ३५०० करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान था।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में आर्थिक नियोजन

(Economic Planning in India after Independence)

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तीनों योजनाओं—वर्म्बर्इ योजना, जर्न—योजना एवं गांधीवादी योजना—में से कोई भी योजना, योजना—स्तर की भाँगी को पूरा नहीं करती थी, किन्तु इन योजनाओं ने एक दिशा अवश्य दी, जो कि आगे नीति निर्धारित करने में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।

दिसम्बर १९४६ में 'सलाहकार योजना मण्डल' (Advisory Planning Board) ने 'योजना आयोग' (Planning Commission) तथा सलाहकार समिति (Consultative Body) की स्थापना का सुझाव दिया। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा मार्च १९५० में योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में वास्तविक रूप से आर्थिक नियोजन का युग प्रारम्भ हुआ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

(First Five Year Plan)

भारत में देश के आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग द्वारा प्रथम योजना मार्च वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई। यह योजना १ अप्रैल १९५१ से ३१ मार्च १९५६ तक के लिए थी। यद्यपि यह योजना १ अप्रैल १९५१ से प्रारम्भ हो गई परन्तु इस योजना को अन्तिम रूप दिसम्बर १९५२ में दिया गया।

सरकार का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का था, अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (mixed economy) अपनायी गई, जिससे कि सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध भौतिक व मानवीय साधना का अधिकतम उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि की जाय। तथा व्यक्तियों की आय में वृद्धि के साथ-साथ जीवन-स्तर भी ऊँचा उठ सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग एवं समन्वय का विशेष ध्यान रखा गया।

उद्देश्य (Objectives)

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये —

- (अ) युद्ध एवं देश के विभाजन से उत्पन्न आर्थिक असन्तुलन को दूर करना।
- (ब) अर्थ-व्यवस्था को इस प्रकार विकसित करना जिससे कि आर्थिक असन्तुलन दूर किया जा सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तथा जनता का जीवन-स्तर ऊँचा उठ सके।

(स) प्रथम योजना से पूर्व की योजनाओं के कार्य क्रमों को पूरा करना ।

इस योजना में तात्कालिक समस्याओं को हल करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया ।

योजना की प्राथमिकताएँ (Priorities in the Plan) -

प्रथम योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं का क्रम निम्न प्रकार था —

- (अ) इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई । इसके अन्तर्गत भूमि सुधार, सिंचाई की सुविधाएँ, आधुनिक उपकरण, उन्नतशील बीज, खाद आदि सम्मिलित किया गया ।
- (ब) हमरा स्थान बिद्युत को दिया गया । इसके साथ ही औद्योगिक विकास को भी आवश्यक समझा गया ।
- (स) ग्रामीण श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम (community development programme) को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर ध्यान दिया तथा रेलों का विकास भी आवश्यक समझा गया ।
- (द) मानवीय क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा आदि कार्यों को महत्व प्रदान किया गया ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा गया—

“प्रथम पंचवर्षीय योजना के दो उद्देश्य थे—पहला, युद्ध और विभाजन के कारण अर्थ-व्यवस्था में उत्पन्न हुए असंतुलन को ठीक करना । दूसरा, सभी क्षेत्रों का समुचित विकास करना जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और जीवन-स्तर में सुधार हो ।”¹

1 “The First Five Year Plan had a twofold objectives Firstly, it aimed at correcting the disequilibrium in the economy caused by the war and the partition of the country Secondly, it proposed to initiate simultaneously a process of all round balanced development which would ensure a rising national income and a steady improvement in living standards over a period”

प्रथम योजना में व्यय (Allocation of Resources)

प्रथम योजनाकाल में देश का आर्थिक विकास करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय करने के लिये २०६६ करोड़ रुपये रये गये परन्तु बाद में यह राशि वृद्ध कर २३७६ करोड़ रुपये करनी गई। इस योजना में वास्तविक व्यय केवल १८६० करोड़ रुपये हो हुआ। वास्तविक व्यय विनियोग विभिन्न श्रेणियों पर निम्न प्रकार से हुआ —

प्रथम योजना में वास्तविक व्यय

व्यय की मद	कुल व्यय (करोड़ रु. में)	प्रतिशत (कुल व्यय का)
१ कृषि तथा सामुदायिक विकास	२६१	१५
२ सिंचाई एवं बिजली	५७०	२६
३ मातायात और संचार	५२३	२७
४ उद्योग एवं खनिज	११७	६
५ सामाजिक सेवायें	४१२	२१
६ अन्य	४७	२
योग	१८६०	१००

इस योजना में उद्योग धंधा का विकास मुख्य रूप से निजी उद्योगपतियों पर छोड़ दिया गया। निजी उद्योगपतियों ने १६०० करोड़ रुपये के विनियोग की योजना बनाई जो कि बाद में विनियोग बढ़कर १८०० करोड़ रुपये हुआ। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग १५६० करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में १८०० करोड़ रुपये हुआ। प्रथम योजना में कुल विनियोग ३३६० करोड़ रुपये हुआ।

प्रथम योजना की वित्त व्यवस्था (Financial Resources of the Plan)

इस योजना में वास्तविक व्यय १८६० करोड़ रुपये हुआ, जिसकी वित्त व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई —

योजना की वित्त-व्यवस्था

वित्तीय साधन	राशि (करोड़ रु० में)	प्रतिशत
१ करारोपण एवं रेलों से प्रचन (सार्वजनिक बचत)	७५२	३८
२ अल्प बचत तथा भ्रम क्रण	३०४	१५
३ जनता से क्रण	२०५	१०
४ पूंजीगत खाते से प्राप्ति	६१	५
५ विदेशी सहायता	१८८	१०
६ घाटे की अर्थव्यवस्था	४२०	२१
योग	१९६०	१००

सार्वजनिक क्षेत्र में इस योजना में १९५१-५२ में २५६ करोड़ रु., १९५२-५३ में २७३ करोड़ रु., १९५३-५४ में ३४० करोड़ १९५४-५५ में ४७६ करोड़ तथा १९५५-५६ में ६१२ करोड़ रुपये खर्च हुए। इस प्रकार पांच वर्षों में कुल व्यय १९६० करोड़ रु. हुआ।

योजना के वित्तीय साधनों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं —

- (अ) बजट के साधन (Budgetary resources),
- (ब) विदेशी साधन (External resources),
- (स) घाटे की अर्थ-व्यवस्था (Deficit financing)।

(अ) बजट के साधन (Budgetary resources)—सरकार को प्रथम योजना में बरोंसे कुल १७५ करोड़ रु. प्राप्त हुए इसमें निजान्त करों से प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित नहीं थी। अतिरिक्त करों से ८० करोड़ रु. प्राप्त हुए तथा राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को २६६ करोड़ रु. प्राप्त हुये। इस योजना में अल्पबचत से सरकार को २३७ करोड़ रु. प्राप्त हुये। इस प्रकार इस योजना में वित्तीय स्रोतों के सम्बन्ध में कुछ सफलता हासिल हुई।

(ब) विदेशी साधन. (External resources)—यू.एन.ओ. म. अथवा, एस्कार. को. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, (World Bank) तथा अमेरिका,

कनाडा, इंग्लैंड आदि देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड आदि देशों से वित्तीय और प्राविधिक (technical) सहायता प्राप्त हुई। इस योजना में कुल विदेशी सहायता ३७८ करोड़ रु की प्राप्त हुई। परन्तु योजनाकाल में केवल १६७ करोड़ रु ही ध्यान किये गये, शेष राशि १८१ करोड़ रु द्वितीय योजना के लिये सुरक्षित रख दी गई। विदेशी सहायता का एक बड़ा भाग गेहूँ तथा विकास योजनाओं के लिए सामान खरीदने में व्यय किया गया।

- (स) घाटे की अर्थ-व्यवस्था (Deficit financing) देश में पहली बार घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रयोग प्रथम योजना में प्रारम्भ हुआ। इस योजना में प्रारम्भ में २८० करोड़ रु के घाटे की अर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया, परन्तु योजना के अन्त तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था ४२० करोड़ रु तक पहुँच गई जो कि कुल योजना व्यय की २१% थी। लेकिन इतनी घाटे की अर्थ-व्यवस्था होने पर भी मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई, इसका कारण देश में उत्पादन की मात्रा में आशासीत वृद्धि होना था।

प्रथम योजना की उपलब्धियाँ (Achievements of First Five Year Plan)

प्रथम योजना स्वतन्त्रता प्राप्ति के छोटे समय पश्चात् ही प्रारम्भ हो गई थी, अतः उस समय की आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। इस कारण योजना निर्माताओं के सामने एक गम्भीर चुनौती थी, अतः सरकार ने इस घोर काफ़ी सतर्कता रखी। प्रथम योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये वे उनका प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। यह सफलता भविष्य की योजनाओं के लिये एक शुभ संकेत था, तथा योजना निर्माताओं के लिए आत्मविश्वास पैदा करने वाली महत्वपूर्ण बात। इस योजना में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ तथा सफलताएँ इस प्रकार रही —

- (१) राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय (National income and per-capita income)—इस योजना में राष्ट्रीय में वृद्धि का लक्ष्य ११% रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि १७.५% हुई। लेकिन यह वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न वर्गों में समान रूप से नहीं हुई। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि १०.५% हुई। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय २१० रुपये से बढ़कर २६८ रुपये हो गई। प्रति व्यक्ति उपभोग के स्तर में ८% वृद्धि हुई।

- (२) कृषि एवं सामुदायिक विकास (Agriculture and community development)—योजना के प्रारम्भ में खाद्यान्नों का उत्पादन ५४० लाख टन था, जिसे बढ़ाकर १६५५-५६ II ६१६ लाख टन करना था। योजना के अन्त में यह उत्पादन

वढकर ६४६ लाख टन हो गया, अर्थात् लक्ष्य से ३३ लाख टन अधिक । इस योजना में कृषि उत्पादन में १६ % वृद्धि हुई । सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास किया गया । सिंचित क्षेत्र १६५०-५१ में ५१ मिलियन एनड था जो योजना के अन्त में बढ़कर ६५ मिलियन हो गया, लेकिन यह लक्ष्य से कम था ।

इस योजना में अच्छे बीज व खाद का प्रयोग, ट्रैक्टरों का उपयोग तथा जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन, किसानों के लिए ऋण व्यवस्था, शक-बन्दी, भूमिहीनों को भूमि दिलाने आदि के अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न किये गये । इसी योजना में सहकारी कृषि को प्रोत्साहन देने की भी योजनायें बनायी गई ।

- (३) **यातायात एवं शक्ति (Transport and power)**—योजना में कृषि व सिंचाई के बाद यातायात व शक्ति को स्थान दिया गया, क्योंकि तीव्र आर्थिक विकास के लिए इन क्षेत्रों का विकास आवश्यक है । रेलों में सुधार, सड़कों का विकास, नए यातायात के लिए जहाजों का निर्माण किया गया । इसके साथ ही हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तथा दो निगमों (Corperations) की स्थापना की गई ।

इस योजना में बिजली की कुल क्षमता में ११ लाख किलोवाट की वृद्धि हुई जबकि लक्ष्य १३ लाख किलोवाट का था ।

- (४) **सामाजिक सेवाएँ (Social services)**—योजना व्यय का २३% सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया गया । शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि कल्याणकारी कार्यों का विकास किया गया । इसमें करीब ४५६ करोड़ रु० व्यय किये गये ।

- (५) **औद्योगिक विकास (Industrial development)**—इस योजना में औद्योगिक विकास की कृषि की अपेक्षा बहुत कम महत्व दिया गया । औद्योगिक क्षेत्र में कुल व्यय ११७ करोड़ रु० हुआ जो कि योजना व्यय का करीब ६ प्र. स था । निजी क्षेत्र (private sector) में २३६ करोड़ रु० की पूंजी लगाई गई ।

इस योजना में औद्योगिक उत्पादन में ४० प्र स वृद्धि हुई । मिलों द्वारा उत्पादित वस्त्रों का उत्पादन ३७ अरब गज से बढ़कर योजना के अन्त में ५५ अरब गज हो गया, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक था । जूट का माल, सोमेट, कागज, सिलाई मशीनें, मशीन, स्प्रिंग, स्थापना आदि के उत्पादन में तेजोपजनक प्रगति हुई । सांकेतिक क्षेत्र में अनेक नये कारखाने—चिनरजन लोकोमोटिव वर्क, सिंदरो का खाद का कारखाना,

हिन्दुस्तान गिपपाइं, हिन्दुस्तान केन्स फौस्ट्री, हिन्दुस्तान मशीन टूलम आदि लोने गये तथा इनमे उत्पादन कार्य प्रारम्भ हुआ ।

(६) मुद्रास्फीति एवं मूल्य स्तर (Inflation and price level)—योजनाकाल में मुद्रा की मात्रा में १०% की वृद्धि हुई । परन्तु उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं हुई । योजना के अन्त तक मूल्य स्तर योजना के प्रारम्भ की तुलना में १३ प्र. स. कम था ।

(७) रोजगार (Employment)—प्रथम योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य रोजगार की सुविधाओं का विस्तार करना तथा नागरिकों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना भी था । ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या अधिक गम्भीर होने के कारण इन क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या के हल के लिए छोटे बड़े सिंचाई के साधनों के विस्तार पर जोर दिया गया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगीकरण, नये रोजगारों का निर्माण आदि के प्रयत्न किये गये । इसके अतिरिक्त रोजगार की अधिक सुविधायें जुटाने के लिए कुटीर उद्योग-धन्यों के विकास को महत्व दिया गया ।

योजना के प्रारम्भ में लगभग ४० लाख व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान लगाया गया, और यह आशा व्यक्त की गई कि योजना के अन्त तक अधिकांश बेरोजगारों को काम पर लगाया जा सकेगा, परन्तु यह आशा पूरी नहीं हो सकी । १९५३ में शहरी क्षेत्रों में स्थिति में काफी गिरावट आयी । सरकार ने स्थिति पर निष्पत्ति रखने और रोजगार की अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए ३०० करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था की, परन्तु इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई । योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई । कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या १९५६ के अन्त तक ५३ लाख थी, जिसमें २५ लाख शहरी थे तथा २८ लाख गांवों में व्यक्ति बेरोजगार थे । इनका कारण श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने के अनुपात में नये रोजगारों के अवसरों में कम वृद्धि होना था ।

प्रथम योजना की प्रालोचना (Criticism) :

प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए जो नश्य निर्धारित किए गए थे, उनमें अधिकांश लक्ष्यों को योजना के अन्त तक प्राप्त कर लिया गया । इस दृष्टि से यह योजना सफल माना जा रहा । इस योजना से देश के विकास को एक मुहूर्त आधार प्राप्त हुआ । फिर भी इस योजना में कुछ कमियाँ रह गयीं, जो कि निम्नलिखित हैं —

(१) योजना का सौमित्र आकार—प्रथम योजना का आकार देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काफी छोटा था, जिससे कि उस समय की समस्याओं को ठीक प्रकार से

मुलझाया नहीं जा सका। इसके अतिरिक्त जो व्यय सक्ष्य पूर्व में २३७८ करोड़ ६० का निर्धारित किया गया था, वास्तविक व्यय उससे भी कम हुआ, अतः विकास की आवश्यकताओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया।

- (२) पूंजी निर्माण की घीभी गति—प्रथम योजना में यह अनुमान लगाया गया था कि अतिरिक्त आय का करीब ३०% भाग पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होगा, परन्तु राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के उपरान्त भी वचत और नियोजन में वृद्धि नहीं हुई।
- (३) औद्योगिक विकास को कम महत्व—प्रथम योजना में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए औद्योगिक विकास को कम महत्व दिया गया। इसके कारण आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं हो पाया जिससे औद्योगिक व आर्थिक विकास तीव्र गति से करने के लिए ठोस आधार प्राप्त नहीं हुआ।
- (४) बेरोजगारी की समस्या—इस योजना में यह सक्ष्य रखा गया था कि रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा अधिकांश व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें उपलब्ध होंगी। परन्तु योजना काल में अतिरिक्त व्यय करने के उपरान्त भी बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हो गई। योजना के अन्त में बेरोजगारी की संख्या ५३ लाख थी जबकि योजना के प्रारम्भ में ४० लाख, इस प्रकार योजना रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रही।
- (५) सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति न होना—इस योजनाकाल में सामान्य नागरिकों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पाया। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद आर्थिक विषमताओं में और अधिक वृद्धि हो गई तथा धन के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।
- (६) प्रशासकीय कुशलता एवं अनुभव का अभाव—इस योजनाकाल में सरकार का प्रशासकीय पहलू काफी कमजोर रहा। इस योजना में वित्तीय साधनों को अधिक महत्व दिया गया तथा मानवीय और भौतिक साधनों को उपेक्षित छोड़ दिया। इस प्रकार सम्बन्ध के अभाव में साधनों का उचित विकास नहीं हो सका। इस सब का प्रमुख कारण सरकार का नियोजन एवं प्रशासन सम्बन्धी अनुभवों का अभाव था।

प्रथम योजना में नियोजन सम्बन्धी अनुभव के अभाव के कारण कुछ प्रमुख एवं आधारभूत बातों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा सका। परन्तु यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही तथा आगे के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार भी इसने प्रदान किया। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। जहाँ से कि विकास कार्यक्रम आसानी से अपनाये जा सकें।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पर एक लेख लिखिये ।
 २. प्रथम योजना के उद्देश्य क्या थे ? उद्देश्यों के सदर्भ में प्रथम योजना की सफलता तथा असफलता की समझाइये ।
 ३. प्रथम योजना के वित्तीय साधनों और स्रोतगार की स्थितिओं पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए ।
-

अध्याय १२

★

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

[Second Five Year Plan]

★ ★ ★

प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना १ अप्रैल १९५६ से ३१ मार्च १९६१ तक के लिए बनाई गई। द्वितीय योजना के निर्माण का भार प्रो पी सी महालनोबिस (Prof P C Mahalanobis) को सौंपा गया। प्रथम योजना ने नियोजित आर्थिक विकास को एक ठोस आधार को प्रदान किया। द्वितीय योजना में इस आधार को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयास किये गये। प्रथम योजना की सफलताओं से प्रभावित होकर द्वितीय योजना को बहु-वांछाशी होता स्वाभाविक था। इस योजना में व्यय का लक्ष्य प्रथम योजना की अपेक्षा दुगुना कर दिया गया तथा ऐसी सम्भावना प्रकट की गई कि १९६७ तक भारतीय अर्थ व्यवस्था स्वयं-संपूर्ण अवस्था (take off stage) को प्राप्त कर लेगी।

१९५४ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में समाजवादी ढंग से समाज (Socialistic Pattern of Society) की स्थापना का लक्ष्य रखा गया तथा भारतीय संसद द्वारा आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि होता स्वभाविक था इन सत्र घटनाओं से द्वितीय योजना के उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ। स्व० प जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय योजना में उद्देश्यों के सम्बन्ध में कहा

“हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करना, भारत की औद्योगिक प्रवृत्ति को नीबू रखना, जनता के कमजोर तथा अपेक्षाकृत अधिकारहीन वर्ग की उन्नति के अवसर प्रदान करना व देश के सभी भागों का समुचित विकास करना है।”

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए द्वितीय योजना में कृषि के स्थान पर जाधारभूत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई।

द्वितीय योजना के उद्देश्य (Objectives of the Second Five Year Plan) :

योजना आयोग के अनुसार—“द्वितीय योजना का मुख्य उद्देश्य पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय में २५% वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या पर धन-शक्ति को खपाया जा सके तथा औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है जिससे कि आगे की योजनाओं के तीव्र विकास के लिये पृष्ठभूमि तैयार हो सके।”

द्वितीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

- (१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य २५ निर्धारित किया गया जिससे कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होकर नागरिक जीवन-स्तर ऊँचा उठ सके।
- (२) औद्योगीकरण—द्वितीय योजना में औद्योगीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य तीव्र औद्योगिक विकास करना था, जिससे कि मूल व भारी उद्योगों का विकास हो तथा औद्योगिक प्रगति को एक ठोस आधार प्राप्त हो।
- (३) रोजगार के अवसरों में वृद्धि—प्रथम योजना में रोजगार के साधनों में आवश्यकता-नुसार वृद्धि न हो पाने के कारण बेरोजगारी की समस्या में काफी वृद्धि हो गई, अतः द्वितीय योजना में रोजगार देने वाले साधनों में विकास करने का लक्ष्य रखा गया जिससे कि बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में ८० लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया।
- (४) सामाजिक असमानता दूर करना—समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिये द्वितीय योजना में आय तथा धन की असमानता को कम करने तथा उनके उचित वितरण की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया।

इस प्रकार द्वितीय योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास

-
- 1 “The main task is to secure an increase of about 25% over the five years, to enlarge employment opportunities at a rate sufficient to absorb the increase in labour force consequent on the increase in population and to take a major stride forward in the direction of industrialisation so as to prepare the ground for more rapid advance in the plan periods to come”

—Planning Commission

विकास करना तथा जनता को अधिकधिक रोजगार की सुविधायें उपलब्ध कराकर समाज की सामाजिक व आर्थिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ना था ।

द्वितीय योजना में प्राथमिकतायें (Priorities in the Second Plan)

द्वितीय योजना में उद्योगों पर सबसे अधिक महत्व दिया गया जबकि प्रथम योजना में कृषि को यह स्थान प्राप्त था । दूसरा स्थान सिंचाई व शक्ति के विकास को दिया गया, तीसरा तथा चौथा स्थान नगरीय परिवहन, सड़क तथा सामाजिक सेवाओं को दिया गया ।

इस योजना में उद्योगों को महत्व प्रदान करने के कई कारण थे —

- (a) प्रथम योजना में कृषि की अधिक महत्व दिया गया था ।
- (b) संतुलित विकास के लिये उद्योगों का विकास करना अनिवार्य था ।
- (c) देश के लघु विकास के लिये औद्योगिकरण आवश्यक था ।
- (d) देश में उद्योग बन्दे पिछड़ी हुई अवस्था में थे ।

इस प्रकार द्वितीय योजना एक भौतिक योजना (physical plan) थी जिसमें वस्तुओं की प्राप्ति पर अधिक बल दिया गया ।

द्वितीय योजना में व्यय (Expenditure in the Second Plan)

द्वितीय योजना में प्रारम्भ में ७२०० करोड़ रु० व्यय करने का प्रावधान रखा गया था, जिसमें से ४५०० करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र और २४०० करोड़ रु० निजी क्षेत्र में व्यय करने की व्यवस्था थी । सार्वजनिक क्षेत्र के ४५०० करोड़ रुपये में से ३८०० करोड़ रु० उत्पादक सम्पत्ति (productive assets) के रूप में व्यय करने से तथा १००० करोड़ रुपये जानू विकास कामों पर व्यय किये जाने थे । परन्तु इस योजनाकाल में मूल्य-स्तर में वृद्धि, स्वेज सकट आदि कारणों से मूल योजना में कुछ संशोधन किये गये । इस योजना की शुरुआत में दो भागों में बांटा गया, प्रथम भाग में उन कार्यों को सम्मिलित किया गया जिनकी पूर्ति करना आवश्यक था । द्वितीय भाग में उन कार्यों को सम्मिलित किया गया जिनकी पूर्ति उसी अवस्था में की जानी थी जबकि वित्तीय साधन उपलब्ध हों । इस प्रकार प्रथम भाग में ४५०० करोड़ रु० तथा द्वितीय भाग में ३०० करोड़ रु० रखे गये । बाद में सरकार ने प्रथम भाग पर राशि बढ़ाकर ४६५० करोड़ रु० कर दी ।

परन्तु इस योजना में वास्तविक व्यय सार्वजनिक क्षेत्र में ४६०० करोड़ रु० हुआ तथा निजी क्षेत्र में ३३०० करोड़ रु० हुआ ।

योजना में व्यय [सार्वजनिक क्षेत्र में]

(करोड़ ₹० में)

व्यय की मद	प्रस्तावित व्यय		वास्तविक व्यय	
	कुल व्यय	प्रतिशत	कुल व्यय	प्रतिशत
१ कृषि एवं सामुदायिक विवास	५६८	११.८	५३०	११.०
२ सिंचाई एवं बिजली	६१३	१६.०	६५८	१६.०
३ उद्योग एवं खनिज	८६०	१८.५	१०७५	२४.०
४ परिवहन एवं संचार	१३८३	२८.६	१३००	२८.३
५ सामाजिक सेवाएँ	६४५	१६.७	२३०	१.८
६ विविध	६६	२.१		
योग	४८००	१००.०	४६००	१००.०

द्वितीय योजना में निजी क्षेत्र में व्यय विनियोग

(करोड़ ₹० में)

व्यय की मदें	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय
१ संगठित उद्योग एवं खान	५७५	७००
२ कृषि एवं सिंचाई	२७५	६७५
३ मानायात (रिजो को छोड़कर)	८५	१३५
४ शक्ति	४०	४०
५ प्रामाणिक तथु उद्योग	१००	२२५
६ भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण	६२५	१,०००
७ मजदूर	४००	५२५
योग	२४००	३३००

उपयुक्त व्यय एवं विनियोग के आकड़ों से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में उद्योग एवं खनिज पर सर्वाधिक बल दिया गया। संचार एवं यातायात को भी प्राथमिकता प्रदान की गई। कृषि पर किया जाने वाला व्यय अपेक्षाकृत कम था, अतः द्वितीय योजना का व्यय नमः प्रथम योजना की अपेक्षा बदला हुआ था। प्रथम एवं द्वितीय योजना में सांख्यिक क्षेत्र में किए गए व्यय का अन्तर निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होता है —

प्रथम एवं द्वितीय योजना में व्यय

वास्तविक व्यय (करोड़ रु० में)

व्यय की मदें	प्रथम योजना		द्वितीय योजना	
	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत
१. कृषि एवं सामुदायिक विकास	२६१	१५	५३०	११
२. सिंचाई और विजली	५७०	२६	८६५	१६
३. उद्योग एवं खनिज	११७	०६	१०७५	२४
४. परिवहन एवं संचार	५२३	२७	१२००	२८
५. सामाजिक सेवाएँ तथा विविध	४५६	२३	८३०	१८
योग	१६६०	१००	४६००	१००

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना में कृषि एवं सामुदायिक विकास पर १५ प्र. श. व्यय था जबकि द्वितीय योजना में केवल ११ प्र. श.। सिंचाई एवं विजली पर प्रथम योजना में २६ प्र. श. व्यय किया गया जबकि द्वितीय योजना में केवल १६ प्र. श.। इस प्रकार कृषि एवं सिंचाई पर प्रथम योजना की तुलना में द्वितीय योजना में बहुत कम व्यय किया गया। उद्योग एवं खनिज पर प्रथम योजना में ६ प्र. श. व्यय हुआ जबकि द्वितीय योजना में इस मद में २४ प्र. श. व्यय किया गया। इस प्रकार द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास पर काफी व्यय किया गया। अतः द्वितीय योजना औद्योगीकरण को महत्व प्रदान कर देश के विकास में तेजी से विकास करने का लक्ष्य रखा गया।

योजना के वित्तीय साधन (Financial Resources of Second Plan)

द्वितीय योजना प्रथम योजना की अपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षी थी। इस योजना में भौतिक मध्यमों की प्राप्ति को महत्व दिया गया, वित्तीय साधनों के लिए 'जहाँ वही से प्राप्त हो' की नीति का सहारा लिया गया। इस योजना के वित्तीय साधनों की दो भागों में बांटा जा सकता है—सार्वजनिक एवं निजी। द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय व्यवस्था निम्न प्रकार थी—

द्वितीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्रों में वित्तीय साधन

(करोड़ ₹० में)

साधन	प्रस्तावित प्राप्ति	वास्तविक प्राप्ति
१. बालू भाय खाना	३५०	—५०
२. अनिश्चित करारोपण	८५०	१०५२
३. जनता से ऋण	—	—
(अ) बाजार ऋण	७००	७८०
(ब) सघु वचत	१००	४००
४. रेलवे अशदान	१५०	१५०
५. प्रोवीडेंड फंड तथा अन्य जमा	२५०	२३०
६. विदेशी सहायता	८००	१०६०
७. घाटे की अव्यवस्था	१२००	६४८
योग	४८००	४६००

वित्तीय व्यवस्था के तीन प्रमुख साधनों का हम अलग से अध्ययन करेंगे

- (१) बजट के साधन (Budgetary resources)—द्वितीय योजना में ८०० करोड़ रुपये परों से प्राप्त होने का अनुमान था तथा ४०० करोड़ रुपये अपूर्वता की मद से

पूरे होने थे। इस योजना में बरो से प्राप्त होने वाली राशि लक्ष्य से कहीं अधिक थी। जनता से प्राप्त ऋण और बचतों लक्ष्य के लगभग बराबर थी। इस मद में ११०० करोड़ रुपये प्राप्त हुए। रेलों से १५० करोड़ रुपये प्राप्त हुए तथा प्राचीन ऋण से २३० करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

२ विदेशी सहायता (External resources)—इस योजना में विदेशी सहायता ८०० करोड़ रु. का प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। वास्तविक सहायता १०६० करोड़ रु. की प्राप्त हुई। इस प्रकार विदेशी सहायता लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई।

३ घाटे की अथ व्यवस्था (Deficit financing)—घाटे की अथ व्यवस्था के सम्बन्ध में द्वितीय योजना के अनुमान गणतः साबित हुए। इस योजना में १२०० करोड़ रु. की घाटे की व्यवस्था का प्रावधान था जबकि इस मद से ६४८ करोड़ रु. की व्यवस्था की गई। यह राशि कुल योजना व्यय की २५% थी जबकि प्रथम योजना में घाटे की व्यवस्था कुल व्यय का २१% थी।

द्वितीय योजना में रोजगार (Employment in Second Plan)

प्रथम योजना के अन्त में ५३ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। द्वितीय योजनाकाल में ३८ लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा ६२ लाख शहरी क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले नये व्यक्तियों की वृद्धि का अनुमान था। इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए १५३ लाख व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। इस योजना में करीब एक करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का प्रावधान रखा गया, जिसमें ८० लाख व्यक्तियों का कृषि क्षेत्र में बाहर रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना था। इस प्रकार योजना का उद्देश्यपूर्ण रोजगार की स्थिति की प्राप्त करने का नहीं रखा गया।

इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा—‘पूर्ण रोजगार के उद्देश्य की पूर्ति आयोजित प्रयत्ना की एक सम्बन्धी प्रक्रिया द्वारा ही की जा सकती है, जिसकी अवधि दूसरी योजना से अधिक लम्बी होगी।

द्वितीय योजना में निम्नलिखित बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने की महत्त्व प्रदान किया गया। इस योजना में १४५ लाख निम्नलिखित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था की गई। फिर भी करीब ५५ लाख निम्नलिखित व्यक्तियों की समस्या थी।

योजना के अन्त में ६५ लाख व्यक्तियों को ही कृषि में आंतरिक रोजगार प्राप्त हुआ, इस प्रकार योजना के अन्त में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की समस्या करीब ६० लाख थी।

योजना की उपसम्पिया (Achievements of the Plan)

द्वितीय योजना की विभिन्न योजना में सफलताएँ एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं —

- १ औद्योगिक क्षेत्र (Industrial field)—द्वितीय योजना में औद्योगिक प्रगति सतोषजनक रही। इस योजना के अन्त में औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक १६४ (सन् १९५०-५१=१००) पहुँच गया जबकि प्रथम योजना के अन्त में निर्देशांक १३६ था। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में ७ प्र.श. की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में तीन इस्पात के कारखाने (भिलाई, झरकेला, दुर्गापुर) सावजनिक क्षेत्र में स्थापित किये गये। निजी क्षेत्र के दो इस्पात कारखानों का विस्तार किया गया। इस्पात का उत्पादन १३ लाख टन से २२ लाख टन हो गया। सीमेंट का उत्पादन ४० लाख टन से बढ़कर ८५ लाख टन हो गया तथा मशीन टूल्स का उत्पादन ३४ करोड़ रुपये से बढ़कर ५५ करोड़ रु. का हो गया। खाद, नागज, सूती वस्त्र उत्पादन आदि क्षेत्रों में प्रगति सतोषजनक रही।
- २ राष्ट्रीय आय (National income)—द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि २० प्र.श. की हुई जबकि लक्ष्य २५ प्र.श. वृद्धि का था। प्रति व्यक्ति आय में लगभग ६ प्र.श. वृद्धि हुई। भूत की दर ७ प्र.श. से बढ़कर ८.५७ प्र.श. हो गई तथा विनिर्माण की दर ७.३ प्र.श. से बढ़कर ११ प्र.श. हो गई। इस प्रकार इस दिशा में भी सफलता सतोषजनक रही।
- ३ कृषि (Agriculture)—इस योजना के अन्त में खाद्यान्नों का उत्पादन ६५ = मिलियन टन से बढ़कर ७६ मिलियन टन^२ हो गया। उत्पादन लक्ष्य ८४ लाख मिलियन टन का था। इस वृद्धि से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का उपभोग १७२ औंस से बढ़कर १८३ औंस हो गया। योजनाकाल के दो वर्ष १९५७-५८ १९५९-६० खाद्यान्नों के उत्पादन की दृष्टि से सराबोर रहे। इस योजना में पी.एस. ४८० के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात का सम्भोधा किया गया। कपास, जूट, गन्ना, तिलहन के उत्पादन में यद्यपि वृद्धि हुई, परन्तु लक्ष्य से कम रही।
- ४ ग्रामीण एवं सघु उद्योग (Village and small industries)—द्वितीय योजना में ग्रामीण एवं सघु उद्योगों के विकास को महत्व दिया गया। इसके परिणाम

२ संशोधित आकड़ों (Economic Survey, 1972-73) के अनुसार योजना के अन्त में खाद्यान्न का उत्पादन ८२.२ मिलियन टन था।

स्वरूप विभिन्न उद्योगों में २५ से ५० प्रतिशत तक वृद्धि हुई। हाथ करपा वस्त्र का उत्पादन तथा खादों का उत्पादन काफी बढ़ा। इस योजना में हम मद में १७५ कराच रुपये व्यय किये गये जिनमें २०० करोड़ रु के व्यय का प्रावधान था। १९५५ में स्थापित कर्वे समिति की सिफारिशों के आधार पर लघु उद्योगों में विकास हेतु ३३ विस्तार केन्द्र तथा ६० औद्योगिक वस्तियों की स्थापना की गई।

५. सिंचाई एवं शक्ति (Irrigation and power)—इस योजना में नहरों, तालाब तथा बायों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र में वृद्धि की गई। इस योजनाकाल में भाखरा गांधी नगर, रिहद, होराकुण्ड, भाताटीना आदि बायों के पूर्ण हो जाने से सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि हुई तथा जल विद्युत का विस्तार भी हुआ। इस काल में विद्युत का उत्पादन ५७ लाख किनावाट हुआ जो कि उत्पादन लक्ष्य ६॥ लाख किलोवाट में कम था। इस काल में गांधी तथा कम्पों में बिजली पट्टाई गई।

६. यातायात और संचार (Transport and communication)—इस योजना में रेल, सड़क एवं जहाजरानी के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम अपनाये गये। अनेक रेलों का विकास पर ११२१५ करोड़ रुपये व्यय किये गये। देश रेल के इतिहास, डिजाइन तथा अन्य सामान की दृष्टि से आगे निर्भर हो गया। नई रेल लाइनों का विकास किया गया, ८००० मील रेल लाइन को मुरादा गया तथा १३०० मील लम्बी लाइन का सुरूरा किया गया। मडगा के विकास के लिए २० वर्षों का यात्रा स्वीकार की गई। इन सभी कार्यों में सुरक्षात्मक विकास मार्गों को प्राथमिकता प्रदान की गई।

७. सामाजिक सेवाएँ (Social services)—इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया परन्तु उपरलिखित गोपित ही रही। इस योजना के अन्त में स्कूल जाग बानें वृद्धि की गयी ४३५ करोड़ हो गई तथा करीब १३६०० तकनीकी शिक्षा में रही। चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया गया तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए करोड़ ४ करोड़ रु व्यय किये गये।

द्वितीय योजना की आलोचना (Criticism of Second Plan)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उपरलिखित की स्थिति के बाद यह स्पष्ट हो जाना है कि इस योजना में आगावीन गणनाएँ प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि यह योजना काफी

सोचपूर्ण थी। परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर लक्ष्यो एवं साधनों में संशोधन भी किये गये, परन्तु अनेक विद्वानों एवं अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की। इस योजना की प्रमुख असफलताएँ एवं आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं —

१. अधिक महत्वाकांक्षी (Over-ambitious) — द्वितीय योजना के निर्माण के समय ही अनेक विद्वान अर्थशास्त्रियों ने इसकी अव्यावहारिकता की ओर संकेत किया था। वास्तव में इस योजना में भौतिक लक्ष्यों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। वित्तीय साधनों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अतः भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। योजना आयोग के सदस्य श्री के. सी. नेगी (K C Neogi) ने उसी समय कहा था —

“दूसरी योजना अव्यावहारिक एवं अधिक महत्वाकांक्षी है, और इसका भण्ड भवन कमजोर नींव पर खड़ा है।”^३

वास्तविकता यह है कि साधनों के अभाव के कारण यह योजना महत्वाकांक्षी थी, परन्तु देश की आवश्यकताओं को देखते हुए अ व्यावहारिक नहीं थी।

२. कृषि के उत्पादन में कमी (Less production in agricultural sector) — इस योजना में कृषि को कम महत्त्व दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कम वृद्धि हुई तथा कृषि का विकास भी अधिक नहीं हो सका। प्रथम दो वर्षों में उत्पादन में वृद्धि हुई परन्तु बाद के तीन वर्षों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही।

३. उद्योग वर्गों के विकास पर अधिक बल (More emphasis on industrial development) — द्वितीय योजना में बड़े उद्योगों तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास की अत्यधिक महत्त्व दिया। अतः पूँजी या रनिव्योग का भी अधिक ध्यान परन्तु उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप अनेक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो गई।

४. बेरोजगारी में वृद्धि (Problem of unemployment) — द्वितीय योजना में बेरोजगारी की समस्या में कमी होने के स्थान पर वृद्धि हो गई। द्वितीय योजना के

3 “The Second Plan is unrealistic and over ambitious and its massive super-structure is raised on precarious foundation”

प्रारम्भ में ५२ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, जबकि योजना के अन्त में इनकी संख्या बढ़कर करोड़ ६० लागू हो गई। इस प्रकार यह योजना रोजगार की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने में असफल रही।

- (१) विदेशी विनिमय संकट (Crisis of foreign exchange)—योजना के प्रारम्भ में ही आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हो गई जबकि निर्यातों से वृद्धि का अनुपात घीमा रहा। इससे भुगतान संतुलन की प्रतिभूतता बच गई और विदेशी विनिमय का संकट उत्पन्न हो गया। योजना के पांच वर्षों में भुगतान संतुलन की प्रतिभूतता का अनुमान ११०० करोड़ २० लगाया गया था, परन्तु प्रथम दो वर्षों में ही भुगतान प्रतिभूतन ५०२६ करोड़ ६० थी। षोडश पावनों की राशि जो पांच वर्षों तक चलनी चाहिए थी केवल १३ वर्ष में ही समाप्त हो गई। इस सबके कारण विनिमय संकट गम्भीर हो गया।
- (६) धन के वितरण की असमानता (Unequal distribution of wealth)—इस योजना में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का उद्देश्य रखा गया, परन्तु मूल्यों में अधिक वृद्धि एवं सरकार के कुशल क्रियान्वयन के अभाव के कारण केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। गरीब वर्ग की स्थिति पहले से अधिक खराब हो गई जबकि अमीर और अधिक अमीर हो गये। इसके कारण कल्याणकारी कार्यों में भी अधिक वृद्धि नहीं हो पायी।
- (७) घाटे की अर्थ-व्यवस्था (Deficit financing)—इस योजना में घाटे की अर्थ-व्यवस्था को जनिष्ठ महत्व दिया। आर्थिक साधनों के अभाव के कारण अनेक भौतिक लक्ष्यों का प्राप्त करने में असफलता ही हाथ लगी तथा कुल व्यय का २५% घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा पूरा किया जाना के कारण मूल्यों में वृद्धि को भी प्रोत्साहन मिला।
- (८) समन्वय का अभाव (Lack of co-ordination)—इस योजना में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों में समन्वय एवं सहयोग का अभाव रहा। इसके अतिरिक्त प्रभार की सुव्यवस्था न होने से जनता का उत्पन्न सहयोग भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त कुशल प्रशासकों एवं प्रबन्धकों के अभाव के कारण योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक नहीं हो सका। जिसके परिणामस्वरूप योजना में पूर्ण निमग्न नहीं हो सका और पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

द्वितीय योजना में मूल्यों में वृद्धि, साक्षरता की समस्या, भुगतान में असंतुलन की समस्या आदि कारणों से देश में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया। इन समस्याओं के उत्पन्न

होने के कारण जनता का विश्वास नियोजित अर्थ व्यवस्था के प्रति कम होने लगा । इन सब समस्याओं के बावजूद भी द्वितीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति हुई और औद्योगिक विकास का आधार दृढ़ हुआ । द्वितीय योजना भी समस्याओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने देश की प्रगति के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया ।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर एक लेख लिखिए ।
 २. "द्वितीय योजना के अधिकांश सद्यों को प्राप्त करने में असफल रही है ।" इस कथन को दृष्टिगत रखते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए ।
 ३. द्वितीय योजना में वित्तीय साधन और रोजगार की स्थिति पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए ।
-

अध्याय १६

*

तृतीय पंचवर्षीय योजना

[Third Five Year Plan]

* * *

प्रथम दो योजनाओं ने देश में आर्थिक नियोजन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिया। तृतीय योजना में इन योजनाओं के अनुभव से लाभ उठाकर वर्तमान की समस्याओं को दूर करने और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठोस कार्यक्रम अपनाये गये। यह योजना १ अप्रैल १९६१ से प्रारम्भ होकर ३१ मार्च १९६६ की समाप्त हो गई।

तृतीय योजना का आकार द्वितीय योजना की अपेक्षा काफी बड़ा था। इस योजना में सावजनिक क्षेत्र में ७५०० करोड़ रु. का व्यय करने का प्रावधान रखा गया। इस योजना में स्वयम्-सफुल अर्थ व्यवस्था (Self generating economy) की ओर एक कदम रखा गया।

योजना के उद्देश्य

(Objectives)

तृतीय योजना स्वयम् सफुल अर्थ व्यवस्था की प्राप्ति हेतु एक कदम था अतः इसमें औद्योगिक विकास तथा विकास के दिग्गज अधिक शक्तिशाली प्रयत्नों पर जोर दिया गया। अतः इस योजना में कृषि के विकास औद्योगिक प्रगत यानायात तथा शक्ति का विकास और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। जिससे कि सन्तुलित आर्थिक विकास हो सके और समाजवादी समाज की स्थापना की जा सके। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये —

- (१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—इस योजना में राष्ट्रीय आय में ५ प्र. श. वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। विनियोग इस प्रकार करना जिसमें कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का क्रम आगे भी जारी रह सके।

- (२) कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता—इस योजना में खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा गया। यह निर्धारित किया गया कि कृषि उत्पादन में इतनी वृद्धि की जाय कि उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाय तथा निर्यात किया जाय।
- (३) आधारभूत उद्योगों का विस्तार—आधारभूत उद्योगों, जैसे—इस्पात, ईंधन, रासायनिक उद्योग का विकास करना तथा मशीन निर्माण क्षमता या इतना विस्तार करना जिससे कि आगे के दस वर्षों में देश के औद्योगीकरण की आवश्यकताएँ देश के साधनों में ही पूर्ण की जा सकें।
- (४) देश की श्रम-शक्ति का पूर्ण उपयोग तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि—योजना में देश की श्रम-शक्ति का पूर्ण उपयोग करने तथा रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।
- (५) धन व सम्पत्ति के वितरण में असमानता को कम करना—योजना में धन व सम्पत्ति के वितरण में असमानता को कम करना, तथा अवसरों की समानता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के सम्बन्ध में कहा गया

“तीसरी योजना दीर्घकालीन विकास के कार्यक्रम का पहला सोपान है। यह कार्यक्रम अगले पन्द्रह वर्ष या उससे अधिक अवधि का होगा। इस अवधि में भारत की अर्थ-व्यवस्था का केवल तेजी से विस्तार ही नहीं करना है, बल्कि साथ ही साथ उसे आत्मनिर्भर और आत्मवाहक भी बनाना है। इस दीर्घकालीन मार्ग निर्धारण का उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनों के विकास, कृषि तथा उद्योगों की उन्नति और सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन का स्तम्भ खींचना है और यह प्रादेशिक और राष्ट्रीय विकास की एकीकृत योजना पेश करता है।”^१

योजना में प्राथमिकताएँ (Priorities in the Plan) -

तृतीय योजना में प्राथमिकताओं का क्रम निम्न प्रकार रहा -

- (१) कृषि के विकास को प्रथम स्थान दिया गया। कृषि के विकास पर कुल व्यय का १४ प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया।
- (२) दूसरा स्थान श्रम-शक्ति के सर्वोत्तम उपयोग को दिया गया, जिससे कि उनकी कार्य के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकें।

(३) तीसरा स्थान आचारभूत उद्योगों के विकास तथा मशीनों के निर्माण को दिया गया।

(४) चौथा स्थान सघु व कुटीर उद्योग-धन्धों के विकास को दिया गया।

इस योजना में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि सभी क्षेत्रों का विकास हो जिससे कि मविध्य में देश के विकास की गति को तीव्र किया जा सके।

योजना में व्यय (Expenditure in the Plan)

तृतीय योजना का आकार प्रथम व द्वितीय योजना की अपक्षा बहुत बड़ा था। इन योजना में सावजनिक क्षेत्र में ७५०० करोड़ रु व्यय का प्रावधान था जबकि प्रथम योजना में सावजनिक क्षेत्र में १६६० करोड़ रु व द्वितीय योजना में ४६०० करोड़ रु व्यय किये गये। इस योजना में निजी क्षेत्र में ४१०० करोड़ रु व्यय करने का सक्ष्य रखा गया। इस प्रकार योजनाकाल में ११६०० करोड़ रु के व्यय के कार्यक्रम निश्चित किये गये। सावजनिक क्षेत्र के व्यय ७५०० करोड़ रु में से १००० करोड़ रु खास व्यय के लिए थे, अन्य वास्तविक रूप में विनियोग के लिये ६५०० करोड़ रु ही उपलब्ध होने थे। इस प्रकार योजनाकाल में कुल विनियोग १०४०० करोड़ रु का सक्ष्य रखा गया।

तृतीय योजना में सावजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय ८५७७ करोड़ रु का हुआ। व्यय की व्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है

तीसरी योजना में व्यय (सावजनिक क्षेत्र में)

(करोड़ रु में)

मर्दें	प्रस्तावित व्यय	प्रतिशत	वास्तविक व्यय	प्रतिशत
१ कृषि एवं सामुदायिक विकास	१०६८	१४	१०१६	१३
२ सिंचाई	६५०	६	६६३७	६
३ बिजली	१०१२	१३	१२५२३	१३
४ ग्रामीण एवं लघु उद्योग	२६४	४	२४०८	३
५ उद्योग एवं खनिज	१५२०	२०	१७२६३	२०
६ परिवहन एवं संचार	१४१६	२०	२१११७	२५
७ सामाजिक सेवायें तथा विविध	१५००	२०	१४६३४	१७
योग	१७५००	१००	८५७७२	१००

उपरोक्त व्योरे से स्पष्ट है कि कृषि एवं मिर्चाई को पर्याप्त महत्व दिया गया तथा समष्टि उद्योगों एवं लघु उद्योगों को भी महत्व प्राप्त हुआ। इस योजना के अन्तर्गत वृद्धि का कारण वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का होना था।

तृतीया योजना के निजी क्षेत्र में विनियोग ४१०० करोड़ का होना था, इनका व्योरा निम्न प्रकार है —

निजी क्षेत्र में विनियोग

(करोड़ रु में)

मर्दें	अनुमानित व्यय
१ कृषि एवं सामुदायिक विकास	६००
२ बिजली	५०
३ ग्रामीण लघु-उद्योग	२७५
४ उद्योग एवं खनिज	१०५०
५ परिवहन एवं संचार	२५०
६ समाज सेवाएँ एवं विविध	१६७५
योग	४१००

तृतीय योजना के वित्तीय साधन (Financial Resources of Third Plan)

तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को पूरा करने के लिये निम्नलिखित साधनों से प्राप्त करने की व्यवस्था की गई —

(करोड़ रु में)

साधन	प्रस्तावित	वास्तविक
१ चालू राजस्व से वचत (अतिरिक्त करारोपण को छोड़कर)	५५०	४१६
२ रेलवे भ्रशदान	१००	६२
३ सरकारी उद्योगों से वचत	४५०	३७३
४ जनता से ऋण	८००	८२३
५ अल्पवचते	६००	५६५
६ प्रोविडेंट फंड	२६५	३३६
७ अनिवार्य जमा योजना	—	११७
८ इम्पान समानीकरण बोप	१०५	३४
९ पूर्योगत प्राप्तिवा	१७०	२३८
१०. अतिरिक्त करारोपण	३७१०	२८६२
११ विदेशी सहायता	२२००	२४२३
१२ घाट की अथ व्यवस्था	५५०	११३३
योग	७५००	८५७७

द्वितीय साधनों को हम तीन भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे —

- (१) **बजट के साधन (Budgetary resources)**—इस योजना में राजस्व खाते में ५५० करोड़ रु के आधिक्य का अनुमान लगाया गया था, परन्तु राजस्व खाते में आधिक्य के स्थान पर ४१६ करोड़ रु का घाटा रहा। रेलवे का भ्रशदान अनुमान की अपेक्षा कम रहा। जनता से ८२३ करोड़ रु के ऋण प्राप्त हुए जबकि अनुमान केवल ८०० करोड़ रु प्राप्त होने का था।

इस योजना में अतिरिक्त करारोपण से १७१० करोड़ रु प्राप्त होने का अनुमान था जिसमें से केन्द्र द्वारा ११०० करोड़ रु तथा राज्य सरकारों द्वारा ६१० करोड़ रु एकत्रित किए जाने थे। करारोपण की यह राशि द्वितीय योजना की तुलना में बहुत अधिक थी, फिर भी सरकार का करारोपण से प्राप्त राशि २८६२ करोड़ रु थी, जो कि अनुमान से ११८२ करोड़ रु अधिक थी।

- (२) विदेशी सहायता (External resources)—तृतीय योजना में २२०० करोड़ रु की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान था, परन्तु वास्तविक प्राप्ति २४२३ करोड़ रु. की हुई।
- (३) घाटे की अर्थ-व्यवस्था (Deficit financing)—द्वितीय योजना में घाटे की अर्थ-व्यवस्था को अपनाये जाने के कारण मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई थी। अतः तृतीय योजना में इससे न्यूनतम राशि प्राप्त करने की बात सोची गई। इस योजना में ५५० करोड़ रु. की घाटे की अर्थ-व्यवस्था अपनाये जाने का प्रावधान रहा परन्तु वास्तविक रूप में घाटे की अर्थ-व्यवस्था करीब ११३३ करोड़ रु की हुई।

तृतीय योजना में रोजगार (Employment in Third Plan)

द्वितीय योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या करीब ६० लाख थी। तृतीय योजना में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में १७५ लाख की वृद्धि होने का अनुमान था। अतः बेरोजगारी की समस्या को एक गम्भीर रूप में लिया गया तथा इसका सुलझाने में आवश्यक कदम उठाए गए। इस योजना में करीब १४५ लाख व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें उपलब्ध कराई गईं। इसमें से १०५ लाख व्यक्तियों का गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए तथा ४० लाख व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र में रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। इस प्रकार योजना के अन्त में रोजगार चाहने वालों की संख्या करीब १२० लाख थी। इसके अनिश्चित शायी क्षेत्रों में स्थिति और अधिक नराम थी, इन क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या थी। बेरोजगार व्यक्तियों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई।

इस दृष्टि से तृतीय योजना अधिक सफल नहीं रही क्योंकि इसमें रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी होने के स्थान पर वृद्धि और अधिक हुई।

तृतीय योजना की उपलब्धियाँ (Achievements of Third Plan)

तृतीय योजना की शुरुआत यद्यपि अच्युत वातावरण में हुई परन्तु योजनाबद्ध मंत्र अनेक अप्रत्याशित परिणामों सामने आये। इसी अवधि में दो बार विदेशी आक्रमण (चीन व पाकिस्तान) हुआ, प्राकृतिक प्रकोप हुए, मूल्यों में लगातार वृद्धि होती रही तथा विदेशी सहायता में भी अनिश्चितता बनी रही। इसके अनिश्चित जनसंख्या में तबो से वृद्धि हुई। दल, मंत्र, मन्त्रालयों, से, अर्थ-व्यवस्था, को, मन्त्रालय, वृद्धि और विकास, को, प्रतिष्ठ, छोड़ो, पड़ गई। अतः इस योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, फिर भी अनेक क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई।

- (१) राष्ट्रीय आय (National income)—वार्षिक तृतीय योजना में राष्ट्रीय आय में ५ प्र. स. वृद्धि का लक्ष्य रखा गया परन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा

सका। योजना काल में औसत वृद्धि २५ प्र.श. रही। प्रथम वर्ष में २५ प्र.श. द्वितीय में १७, तृतीय में ४६ प्र.श. तथा चौथे वर्ष में ७६ प्र.श. वृद्धि हुई परन्तु योजना के अन्तिम वर्ष में ४२ प्र.श. की गिरावट आयी। इस प्रकार राष्ट्रीय आय १९६०-६१ में १४१४० करोड़ रुपये से बढ़कर १९६४-६५ में १६,६३० करोड़ हो गई तथा १९६५-६६ में १५६३० करोड़ रु० (१९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर) रह गई।

प्रति व्यक्ति आय १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर) ३२६ रु० थी जो कि १९६४-६५ में बढ़कर ३४६ रु० हो गई, योजना के अन्तिम वर्ष में घटकर ३२५ रु० रह गई।

- (२) औद्योगिक क्षेत्र (Industrial field)—योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों में प्रगति सन्तुष्टजनक रही परन्तु आगे इसे जारी नहीं रखा जा सका, इसका प्रमुख कारण चीन व पाकिस्तान का आक्रमण रहा। इस योजना की अवधि में मशीनरी, रसायन आदि में १५६० वाणिज्य कृषि की दर रही। चीनी, सीमेंट, पेट्रोल, जूट की बनी वस्तुओं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।

औद्योगिक क्षेत्र में विकास की दर ७.६ प्र.श. रही जबकि लक्ष्य ११ प्र.श. वृद्धि का था।

- (३) कृषि (Agricultural field)—तृतीय योजना में कृषि के विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई। इस योजना में कृषि उत्पादन का लक्ष्य १०० मिलियन टन रखा गया। कृषि के विनाश के लिये अल्पकालीन व दीर्घकालीन श्रृणों की व्यवस्था की गई। हमके अतिरिक्त रासायनिक खाद में उत्पादन में १६ लाख टन तथा आर्गेनिक खाद में १५४ मि० टन की वृद्धि करना था। ३६ मि० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया था।

कृषि क्षेत्र में तृतीय योजना अधिक सफल नहीं रही। योजना के अन्तिम वर्ष में कृषि का उत्पादन केवल ७२.३ मि० टन था जबकि १९६४-६५ में उत्पादन ८६ मि० टन था जूट का लक्ष्य ६२ मिलियन गांठ था जबकि उत्पादन ५ मिलियन गांठों का हुआ। कपास का उत्पादन ५२ मिलियन गांठों हुआ जबकि लक्ष्य ७१ मिलियन गांठों था। उत्पादन में कमी के कारण ही २५ मिलियन टन खाद्यान्न, ३६ मि० गांठ कपास तथा १५ मि० गांठ जूट का आयात किया। रासायनिक खाद का उत्पादन भी लक्ष्य से कम हुआ।

- (४) सिंचाई तथा बिजली (Irrigation and Power)—तृतीय योजना में २५६ मिलियन एकड़ भूमि पर सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। योजनाकाल में ५५ मि० एकड़ भूमि पर बड़ी सिंचाई योजनाओं द्वारा १३१ मि० एकड़ भूमि पर लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई।

विद्युत उत्पादन की क्षमता में करीब ४६ लाख किनोवाट की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में योजना कुछ सीमा तक सफल रही।

(५) सामाजिक सेवायें (Social services)—सामाजिक सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस योजना में १६६७ करोड़ रु व्यय किये गये। इस योजना में समाज कल्याण व शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों में काफी सफलता प्राप्त हुई। इस अवधि में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में ४४५ लाख तथा कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या में ११ लाख की वृद्धि हुई।

देश में चिकित्सासुखों की संख्या ८६०० से बढ़कर १४६०० हो गई। चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि के कारण औसत आयु ३२ वर्ष से बढ़कर ५० वर्ष हो गई।

तृतीय योजना की असफलताएँ (Failures of Third Plan)

तृतीय योजना का निर्माण करते समय यह कहा गया था कि यह योजना स्व-सufficient अर्थ-व्यवस्था की प्राप्ति के लिये महत्वपूर्ण है। परन्तु यह योजना विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त करने में असमर्थ रही। इस योजना की कुछ कमियाँ या असफलताएँ निम्नलिखित हैं —

(१) विकास की धीमी गति (Slow rate of growth)—इस योजना में विकास काफी धीमी गति से हुआ। योजना में लक्ष्य ५ प्र श वार्षिक वृद्धि का था, जबकि वास्तविक विकास की दर केवल २ ५ प्र श रही।

(२) कृषि में आत्मनिर्भरता का अभाव (Lack of self-sufficiency in agriculture)—इस योजना में कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। योजना के अन्तिम वर्ष में उत्पादन में और गिरावट आ गई। इससे कारण साधान का बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ा जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग इस मद में खर्च हो गया। उत्पादन में कमी के कारण कृषि की अन्य वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती गई जिससे दूसरे लक्ष्यों की प्राप्ति करने में भी बाधा उत्पन्न हुई।

(३) मूल्यों में वृद्धि (Rise in prices)—तृतीय योजना में वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई और यह वृद्धि एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही। मूल्य वृद्धि से विनियोग प्रभावित हुये तथा प्रस्तावित कार्यों को पूरा करने में अधिक व्यय करना पड़ा। इस योजना विधि में खाद्यान्नों में ४८४ प्र श, औद्योगिक कच्चे माल में ३२६ प्र श, निर्मित माल में २२१ प्र श मूल्यों में वृद्धि हुई। इस प्रकार कुल वृद्धि ३६४ हुई। इस वृद्धि के कारण सामान्य जीवन बर्ष्टप्रद हो गया।

(४) जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि (Rapid increase in population)—इस योजना में जनसंख्या में २५ प्र श की दर से वृद्धि हुई। यह वृद्धि जनसंख्या नियन्त्रण के उपाय अपनाने के बावजूद हुई। जनसंख्या की इस वृद्धि के कारण विकास की गति धीमी पड़ गई।

(५) बेरोजगारी (Unemployment)—द्वितीय योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या करीब १० लाख थी जबकि तृतीय योजना के अन्त में यह बढ़कर १२० लाख हो गई। इस प्रकार यह योजना रोजगार की सुविधायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में असमर्थ रही।

(६) धन के वितरण की असमानता (Unequal distribution of wealth)—इस योजना में धन एवं सम्पत्ति के वितरण में असमता को कम करने का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु इस योजना में इस ओर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। अतः योजना अवधि में गरीब व अमीर के बीच की खाई और चौड़ी हो गई।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है। प्रो अलक घोष (Prof Alak Ghosh) ने तृतीय योजना की समीक्षा करते हुए लिखा है

“साधारण और असाधारण तत्वों के दबाव के उपरान्त भी तृतीय योजना उद्योग, मातायाँ एवं संचार तथा शिक्षा एवं चिकित्सा में महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफल रही है। परन्तु कृषि, सिंचाई और शक्ति के क्षेत्र में उपलब्धि असंतोषजनक रही।”^२

तृतीय योजना की धीमी प्रगति के कारण (Reasons of its Slow Progress)

तृतीय पंचवर्षीय योजना की धीमी प्रगति का कारण योजनाकाल में आयी अप्रत्याशित कठिनाईयाँ और बाधाएँ थी जिनके लिये अर्थ-व्यवस्था तैयार नहीं थी। प्रमुख बाधाएँ व कठिनाईयाँ निम्नलिखित थी—

(१) प्राकृतिक बाधाएँ (Natural obstacles)—इस योजना के पाँच वर्षों में से तीन वर्ष अनावृष्टि के कारण सूखे की स्थिति रही तथा कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण उत्पादन को काफी नुकसान हुआ। इस प्रकार जनवामु व वर्षा की अनिश्चित स्थितियों के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं किया जा सका।

2 “In spite of the pulls and pressures exerted by the ordinary and extra ordinary sector during the Third Plan period, we were generally successful in fulfilling some of the important targets in the field of industry, transport and communication, health and education. Our performances were, however, unsatisfactory in the field of agriculture, irrigation and power.” —Alok Ghosh

- (२) विदेशी आक्रमण (Foreign attack)—तीसरी योजना की अवधि में १९६२ में चीन तथा १९६५ में पाकिस्तान ने आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप सुरक्षात्मक कार्यों पर अधिक ध्यान करना पड़ा। अतः उत्पादन कार्यों से हटाकर सुरक्षात्मक कार्यों पर ध्यान करने से उत्पादन में गिरावट आयी तथा बर्च-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई।
- (३) विदेशी विनिमय की कठिनाई (Crisis of foreign exchange)—तृतीय योजना में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई आयी तथा अपेक्षित विदेशी विनिमय प्राप्त नहीं हो सका। योजना के अन्तिम वर्ष में विदेशी सहायता बहुत ही कम प्राप्त हुई जिससे विकास कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हुई।
- (४) सहयोग एवं समन्वय का अभाव (Lack of co operation and co-ordination)—तृतीय योजना में जनता से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण जनता में नियोजन के प्रति उत्साह कम था क्योंकि इससे पूर्व की योजनाओं से विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकारों में समन्वय का भी अभाव रहा। इसका प्रमुख कारण अधिकारियों की कार्य पद्धति का दोषपूर्ण होना था।

इसके अतिरिक्त मूल्यों में लगातार वृद्धि और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण योजना के अधिकांश कार्यक्रमों को पूरा नहीं किया जा सका।

तीन वार्षिक योजनायें (Three Annual Plans)

तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि ३१ मार्च १९६६ को समाप्त हो गई। इसके पश्चात् चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की जानी थी। इसके लिये १९६२ से ही निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका था परन्तु १९६६ तक इसकी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका, बाद में चतुर्थ योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। परन्तु विदेशी महायत्ना की अनिश्चितता, मूल्यों में लगातार वृद्धि, विदेशी आक्रमण के प्रभाव तथा आन्तरिक साधनों की कमी आदि कठिनाईयों के कारण चतुर्थ योजना १ अप्रैल १९६६ से लागू नहीं की जा सकी।

उपरोक्त स्थिति में योजना निर्माणकर्ताओं ने चतुर्थ योजना की कुछ समय के लिये स्थगित करने का निर्णय लिया। योजना क्रम को बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया गया। ये वार्षिक योजनायें १९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९ के लिये बनायी गईं।

वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत व्यय (Total outlay of Annual Plans)

१९६६ ६७ १९६७ ६८ तथा १९६८ ६९ में तीन वार्षिक योजनाओं वनी जिनमें कुल व्यय क्रमशः २१६५ करोड़ रु. २० ५ करोड़ रु. तथा २३७६ करोड़ रु. था। इन वार्षिक योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय चतुर्थ योजना के प्राक्ष्य में प्रस्तुत व्यय से काफी कम था। इसके कारण आंतरिक साधनों की कमी तथा विदेशी सहायता की कमी थी। इनके अतिरिक्त अवसूयन के कारण भी कुछ समय के लिये अनिश्चिन्ता का वातावरण बन गया था। अब ये तीन एकवर्षीय योजनाओं आंतरिक साधनों के आधार पर ही तैयार की गईं। इन वार्षिक योजनाओं में व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है —

वार्षिक योजना में व्यय^३

मर्दाने	१९६६ ६७	१९६७ ६८	१९६८ ६९
१ कृषि एव सामुदायिक विकास	३३४	३१८	४५९
२ बनी एव मध्य सिंचाई	१४९	१४४	१७५
३ विद्युत	४०४	३९२	४००
४ ग्रामीण एव नव उद्योग	४३	४४	४१
५ संगठित उद्योग एव खनिज	५१४	४७१	५६६
६ यातायात एव संचार	४२४	३९४	४०१
७ सामाजिक सहाय एव विविध	२९५	३२२	२६१
कुल योग	२१६५	२०८५	२३७६

इन तीन वार्षिक योजनाओं में कुल व्यय ६६२६ करोड़ रु. हुआ।

वार्षिक योजनाओं की उपलब्धियाँ (Achievements of Annual Plans)

१९६६ ६७ की वार्षिक योजना—इस वर्ष देश में सूखे व अनाज की स्थिति रही जिससे उत्पादन में कमी और अन्न-व्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस अवधि

म खाद्यान्न का उत्पादन ७४ २३ मि टन हुआ जबकि लक्ष्य ६७ मि टन का था । औद्योगिक उत्पादन में केवल ३ % की वृद्धि हुई ।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि १६ ■ श हुई जबकि प्रति व्यक्ति आय १९६५ ६६ के वर्ष से ० ५ प्र श कम थी । राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय का स्तर १९६४ ६५ की अपेक्षा नीचा था । इस योजना में मूल्यों में १६ प्र श की वृद्धि हुई ।

१९६७ ६८ की वार्षिक योजना—इस वार्षिक योजना से आर्थिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । इस अवधि में खाद्यान्न का उत्पादन ९५ मि टन हुआ जो कि १९६६ ६७ की अपेक्षा २८ प्र श अधिक था । सिंचाई व खादों का वि नार किया गया । औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि केवल २ प्र श हुई । परन्तु इस योजना में भारी को दूर करने के प्रभावशाली कदम उठाये गये जिनका सुप्रभाव १९६८ ६९ में देखने को मिला ।

राष्ट्रीय आय में ६३ प्र श की वृद्धि हुई । परन्तु विनियोग की दर केवल ११ ५ प्र श ही रही जबकि १९६६ ६७ में विनियोग दर १२ प्र श थी । इस वर्ष मूल्यों में ११ प्र श की वृद्धि हुई ।

१९६८ ६९ की वार्षिक योजना—इस योजना में खाद्यान्न का उत्पादन ९६ मि टन हुआ जबकि लक्ष्य १०२ मि टन का था । औद्योगिक उत्पादन में ६ प्र श की वृद्धि हुई परन्तु इससे तथा रासायनिक खाद के उत्पादन में कमी आई । राष्ट्रीय आय में वृद्धि केवल ० ७ प्र श हुई जबकि लक्ष्य ५ प्र श की वृद्धि का था । इस अवधि में खाद्यान्नो के मूल्यों में गिरावट आयी परन्तु मूल्य स्तर में वृद्धि हुई । बचत एवं विनियोग की दर भी कम रही ।

वार्षिक योजनायें केवल चतुर्थ योजना में विकास के रूप में बनायी गई थी इसलिये इनमें ठोस कार्यक्रमों का अभाव था । इन योजनाओं में लक्ष्यों का निर्धारण प्राथमिकताओं का निर्धारण तथा वित्तीय साधनों की व्यवस्था के लिये कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था । ये वार्षिक योजनायें बेरोजगारी की समस्या मूल्य वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने में असफल रही तथा उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी असमर्थ रही ।

यद्यपि ये वार्षिक योजनायें असफल रही फिर भी इन योजनाओं ने नियोजित विकास के क्रम को बनाए रखा तथा चतुर्थ योजना के लिये पृष्ठभूमि तैयार की ।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य उपलब्धियों को बताइए ।
 २. "तृतीय योजना अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही ।" इस कथन की घोर प्रगति के कारण बताइए ।
 ३. तृतीय योजना के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का वर्णन कीजिए तथा इसकी उपलब्धियों को बताइये ।
 ४. तृतीय योजना की वित्तीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए ।
 ५. तीनो वार्षिक योजनाओं (१९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९) के मुख्य तत्वों की व्याख्या कीजिये ।
-

अध्याय १७

★

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

[Fourth Five Year Plan]

★ ★ ★

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा तीन वार्षिक योजनाओं में देश के आर्थिक

विकास के लिये माग तो प्रशस्त हुआ परन्तु बेरोजगारी, गरीबी, वितरण की असमानता आदि समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका। अतः चतुर्थ योजना इसी उद्देश्य को लेकर बनाई गई। इन समस्याओं के निराकरण के लिये एक बड़ी राशि की आवश्यकता थी, अतः देश की आवश्यकताओं की ध्यान में रखते हुए चतुर्थ योजना में २४३६८ करोड़ रु के व्यय का प्रावधान रखा गया। परन्तु कुछ कारणों से चतुर्थ योजना की सशोधित रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसमें कुल व्यय बढ़ाकर २४८८२ करोड़ रु कर दिया। इसमें सावजनिक क्षेत्र के लिए १५६०२ करोड़ रु की राशि निर्धारित की गई तथा निजी क्षेत्र के लिए ८६८० करोड़ रु व्यय का प्रावधान रखा गया। यह योजना १ अप्रैल १९६६ से प्रारम्भ होकर ३१ मार्च १९७४ तक के लिए बनाई गई।

योजना के उद्देश्य (Objectives of the Plan) -

चतुर्थ योजना का उद्देश्य लोगों के जीवन-स्तर में उन उपायों से वृद्धि करना है जो कि समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करते हैं। इस योजना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए चतुर्थ योजना की रूपरेखा में कहा गया।

“इस योजना का आधारभूत उद्देश्य समानता तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के माध्यम से जनसाधारण के जीवन-स्तर को तेजी के साथ ऊँचा उठाना है। निर्मल वर्षों तथा कम आय वाले वर्गों के बहुमुद्दी उत्थान के लिये हर सम्भव प्रयत्न करना होगा। अर्थ-व्यवस्था को सक्रिय करने हेतु प्रत्येक प्रयास को गतिशील किया जावेगा ताकि स्थिरता के साथ तीव्र विकास किया जा सके। भारतीय अर्थ व्यवस्था स्वावलम्बी हो सके इसके लिये उपर्युक्त क्षमता और

जूटाये जानेवाले अतिरिक्त साधनों से निर्मित समता का अधिकतम उपयोग करने की व्यवस्था की जायगी।

सन्तुल्य म चतुर्थ योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास (growth with stability) करना तथा धन आय और आर्थिक शक्ति के बे-द्वितीयकरण को कम करना है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं —

- (१) राष्ट्रीय आय में ५५ प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि करना तथा कृषि उत्पादन में ५ प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन में ८ से १० प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि करना।
- (२) आमनिष्पत्ति प्राप्त करना।
- (३) विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी करना तथा P. L. ४८० के अन्तर्गत आयातों को न्यूनतम करना।
- (४) निर्यातों में वृद्धि ७ प्रतिशत वार्षिक की दर से करना तथा आयातों को न्यूनतम करना।
- (५) आर्थिक स्वायत्ति व स्वायत्ति करना।
- (६) आय तथा धन के वितरण की विषमता में कमी करना।
- (७) राजस्व के अवसरों में वृद्धि करना।
- (८) जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करना।

विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करना तथा उनकी विकास से प्राप्त लाभों से हिस्सा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना।

इस प्रकार चतुर्थ योजना का उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास के साथ साथ समानता और सामाजिक न्याय में निरंतर प्रगति करना है।

चतुर्थ योजना में व्यय (Total Outlay of the Plan)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल २४८८० करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान रखा गया इसमें से सावजनिक क्षेत्र में १५६०२ करोड़ रु. तथा निजी क्षेत्र में ८६८० करोड़ रु. व्यय का प्रावधान रखा। सावजनिक क्षेत्र के १५६०२ करोड़ रु. में से २२४७ करोड़ रु. चानू व्यय के लिये तथा शेष १३३६५ करोड़ रु. का विनियोग कार्यों पर व्यय करने के लिये रखा गया। चतुर्थ योजना में सावजनिक क्षेत्र में व्यय का व्यापक निम्न प्रकार है —

व्यय का विवरण (सार्वजनिक क्षेत्र में)

(करोड रु. में)

मर्दे	चालू व्यय	विनियोग	योग	प्रतिशत
१. कृषि एवं सहायक क्षेत्र	६१०	२११८	२७२८	१७.१
२. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	१४	१०७३	१०८७	६.८
३. शक्ति	—	२४४८	२४४८	१५.४
४. कुटीर एवं लघु उद्योग	१०७	१८६	२९३	१.८
५. उद्योग एवं खनिज	४०	३२६८	३३०८	२१.०
६. परिवहन एवं संचार	४०	३१६७	३२०७	२०.३
७. शिक्षा	५४५	२७८	८२३	५.२
८. विविध	१०५७	१०५७	१६४८	१२.४
योग	२२४७	१३६५५	१५६०२	१००

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना तथा चतुर्थ योजना में किये जाने वाले व्यय का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि तृतीय योजना में उद्योग एवं सामाजिक सेवाओं पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय किया गया जबकि चतुर्थ योजना में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया। इसका प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यद्यपि दोनों योजनाओं के व्यय प्रतिशत में अधिक अंतर नहीं है, जो कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होता है।

विनियोग का स्वरूप : तृतीय एवं चतुर्थ योजना

(करोड रु. में)

मर्दे	तृतीय योजना		चतुर्थ योजना	
	विनियोग	प्रतिशत	विनियोग	प्रतिशत
१. कृषि	१४६०	१४.०	३७१८	१६.४
२. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	६५०	६.३	१०७३	४.७
३. शक्ति	१०६२	१०.२	२५२३	११.२
४. शान्ति एवं लघु उद्योग	४२५	४.१	७४६	३.३

५	उद्योग एवं खनिज	२,५७०	२४७	१,२६८	२३४
६	यातायात एवं संचार	१,७१६	१६७	४,११७	१८२
७	सामाजिक सेवाएं	१,६६७	१६३	३,५६०	१५७
८	इन्वेन्ट्रीज	८००	७७	१,६००	७१
योग		१०,४००	१००	२२,६३५	१००

चतुर्थ योजना में निजी क्षेत्र में व्यय (Outlay in Private Sector)

चतुर्थ योजना में निजी क्षेत्र में ८६८० करोड़ रु० के विनियोग की व्यवस्था की गई। इस याजना में विभिन्न मंडों में निम्नानुसार व्यय का प्रावधान रखा गया।

निजी क्षेत्र में विनियोग^१

(करोड़ रु० में)

मर्दे	विनियोग	प्रतिशत
१ कृषि एव अन्य क्षेत्र	१६००	१७.८
२ ग्रामीण एव लघु उद्योग	५६०	६.२
३ शक्ति	७५	०.८
४ उद्योग एव खनिज	२,०००	२०.३
५ यातायात एव संचार	६२०	१०.२
६ शिक्षा	५०	०.६
७ आवास एव क्षेत्रीय विकास	२७५	२.४३
८ इन्वेन्ट्रीज (Inventories)	१६००	१७.८
योग	८६८०	१००

चतुर्थ योजना के व्यय एवं विनियोग संलग्न है कि इस याजना में किये जाने वाले व्यय व विनियोग प्रथम तीन पंचवर्षीय याजनाओं में किये गए कुल व्यय से अधिक हैं। इनके बड़े आकार का दर्शक हो कुछ अर्थशास्त्रियों व राजनीतिज्ञों ने इसका आकार

छोटा करने का मुझाव दिया था। परन्तु देश की आवश्यकताओं और समस्याओं को देखते हुए यह आकार अधिक बड़ा नहीं है।

✓ योजना की वित्त-व्यवस्था (Resource Mobilisation) •

सार्वजनिक क्षेत्र में १५०६२ करोड़ रु० की व्यवस्था करने की योजना, इसमें से केन्द्र सरकार को १२७६६ करोड़ रु० और राज्य सरकारों को अपनी योजनाओं के निम्ने ३१०६ करोड़ रु० की व्यवस्था करने की थी। चतुर्थ योजना का मध्यावधि मूल्यांकन (Mid-term appraisal) दिसम्बर १९७१ में सन्नद्ध में पेश किया गया, इसमें वित्तीय साधनों की प्राप्ति में थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में १५६६८ करोड़ रु० की व्यवस्था करने होगी। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा साधनों की गतिशीलता (वित्तीय व्यवस्था) का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होना है

वित्तीय व्यवस्था^२

(करोड़ रु० में)

साधन	केन्द्र	राज्य	योग
१. चालू राजस्व घात से बचत	१,६२५	४८	१,६७३
२. सार्वजनिक संस्थानों से अशुद्धान	१,५३४	४६५	२,०२६
३. रिजर्व बैंक के ऋण	१६५	३७	२०२
४. बाजार से ऋण	६००	५१५	१,११५
५. लाइ निगम तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋण	४०५	—	४०५
६. अन्य बचतें	२४७	४६५	७१२
७. वणिज जमा योजनायें आदि	१०४	—	—१०४
८. प्रोबोर्ण्ड फण्ड	३४३	३१७	६६०
९. पूंजीगत प्राप्तिमा	२,०६०	—४०५	१,६५५
१०. अतिरिक्त वित्तीय साधन	२,१००	१,०६८	३,१६८
११. जीवन बीमा निगम तथा अन्य से ऋण	—	५०६	५०६
१२. विदेशी सहायता	२,६१४	—	२,६१४
१३. घाटे की अर्थ-व्यवस्था	८५०	—	८५०
कुल साधन	१२,७६६	३,१०६	१५,८०२
राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना के कुल साधन	—३,५००	३,५००	—
	९,२६६	६,६०६	१५,८०२

चतुर्थ याजना मे १५६०२ करोड रु० के वित्तीय साधनो म ७८% बजटरी साधनो (Budgetary resources) से प्राप्त होगा विदेशी सहायता से १७% और घाटे की अव्यवस्था से ५ प्र श प्राप्त होगा । तृतीय एव चतुर्थ योजना की वित्तीय व्यवस्था को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है

वित्त व्यवस्था [सार्वजनिक क्षेत्र]

(करोड रु० म)

मर्दे	तृतीय योजना		चतुर्थ योजना	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
१ घरेलू बजटरी साधन	५,०२१	५८५	१२,४३८	७८७
२ विदेशी सहायता	२,४२३	२८३	२,६१४	१६५
३ घाट की अव्यवस्था	१,१३३	१३२	८५०	५३
योग	८,५७७	१००	१५,९०२	१००

निजी क्षेत्र (Private Sector) में वित्त व्यवस्था

निजी क्षेत्र मे वित्त व्यवस्था के लिए यह अनुमान लगाया गया कि निजी क्षेत्र म योजनाकाल म १४,१६० करोड रु० की वचत होगी । इस वचत म से कन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र व विकास क लिए ५६६५ करोड रु० प्राप्त किए जावेंगे । इस प्रकार निजी क्षेत्र म विनियोग के लिए शेष राशि ८४६५ करोड रु० (१४,१६०—५६६५=८४६५) प्राप्त होगी । इसमे अतिरिक्त ३०० करोड रु० की विदेशी सहायता प्राप्त होगी जिसमे से २५० करोड रु० पुराने ऋणो के भुगतान के रूप म वापिस देने होंगे । अतः शुद्ध विदेशी सहायता ३० करोड रु० की प्राप्त होगी । इस प्रकार निजी क्षेत्र मे विनियोग के लिए कुल ८४६५ करोड रु० प्राप्त होंगे । मध्यावधि मूल्यांकन ॥ कुछ मशोर्धन किए गए ओकि निम्न तालिका से स्पष्ट हात है

निजी क्षेत्र में वित्तीय व्यवस्था

(करोड़ रु० में)

मदें	चतुर्थ योजना	
	मूल	सशोधन
१ निजी क्षेत्र में बचनें	१४,१६०	१६,२३५
२ सार्वजनिक क्षेत्र को दो आने वाली राशि	-५,४६५	-६७३२
३ निजी क्षेत्र को प्राप्त बचनें	८,४६५	६५०३
४ शुद्ध विदेशी महामत्ता	३०	-२५७
५ निजी विनियोग के लिए प्राप्त साधन	८,४६५	६२४६

चतुर्थ योजना के प्रमुख लक्ष्य

[Main Targets of Fourth Plan]

योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चतुर्थ योजना के लक्ष्य निर्धारित किए गए । इस योजना में राष्ट्रीय आय में ५.५ प्र. श की दर से वार्षिक वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में ३ प्र. श वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया । आंतरिक बचत की दर को ६ प्र. श से बढ़ाकर १३.६ प्र. श तथा विनियोग की दर को ११.३ प्र. श से बढ़ाकर १४.५ प्र. श करने का प्रावधान रखा गया । साधान के आयात को समाप्त करने तथा और आयात वस्तुओं का आयात ५ प्र. श तक सीमित रखने का आयोजन किया गया । इन योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ विकास करना रखा गया । प्रमुख लक्ष्यों को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है —

मदें	१९६८-६९	१९७३-७४
१ राष्ट्रीय आय (करोड़ रु०)	२८,८००	३७,६००
जनसंख्या (करोड़ में)	५२.७	५६.७
३ प्रति व्यक्ति आय (रु० में)	५४६	६३६
४ बचत (राष्ट्रीय आय का प्रतिशत)	६	१३.२
५ शुद्ध विनियोग (राष्ट्रीय आय का प्रतिशत)	११.३	१४.५

५) योजना में कृषि (Agriculture in the Plan)—चतुर्थ योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने का उद्देश्य रखा गया। कृषि में निरन्तर वृद्धि करने के लिए तथा छोटे कृषकों, छेतिहर मजदूरों आदि को कृषि के विकास में हिस्सा लेने के लिए अनेक कार्यक्रम अपनाने की योजना बनाई गई। इस योजना में कृषि के विकास कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है —

(अ) उत्पादन को अधिकतम करना,

(ब) कृषि में असंतुलन को दूर करना।

उत्पादन में वृद्धि करने तथा असंतुलन को दूर करने के लिए नई नीति का निर्माण करने की आवश्यकता हुई। इस नई नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं —

(अ) सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार तथा विकास।

(ब) रासायनिक खाद, फसल के घाव की सामग्रों, कृषि उपकरण आदि की व्यवस्था तथा साज की सुविधा।

(क) अधिक उपज देने वाली किस्मों का विस्तार।

(द) सघन व विनो की सुविधाओं में सुधार तथा कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम मूल्य-निर्धारण।

(इ) चुने हुए क्षेत्रों में व्यापारिक फसलों के विकास के लिए गहन प्रयत्न।

चतुर्थ योजना में कृषि के विकास के लिये चतुर्मुखी योजना बनाई गई। इस योजना में विकास कार्यक्रम के लक्ष्य विकास की सम्भावना का अध्ययन करके निर्धारित किए गए हैं। कुछ चुने हुए विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य निम्नलिखित हैं —

विकास कार्यक्रम के लक्ष्य

कार्यक्रम	अतिरिक्त लक्ष्य (मिलियन हेक्टर)
१ बहुफलक कार्यक्रम	६०
२ भू-संरक्षण	५६
३ नई भूमि में खेती	१०
४ दली मध्यम व लघु सिंचाई	४२
५ लघु सिंचाई नया क्षेत्र	३२
६ " " घटिया श्रेणी के क्षेत्र का पुनर्व्यापन	१६
७ पूरक सिंचाई—स्वरोपकरण	२४

इस योजना में उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाली फस २४ मि० हेक्टर भूमि में बोया जायेगा तथा छोटे कृषकों के लिए साख की विशेष को जायेगी। कृषि में उत्पादन के भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार से निर्धारित किये गये हैं

कृषि विकास के लक्ष्य

सं०	१९६०-६१	१९७०
१. खाद्यान्न (मि० टन)	६८	१
२. कपास (मि० टन)	६	
३. जूट (मि० टन)	६२	
४. गन्ना (गुड) (मि० टन)	१२	
५. पीपल सरसण (मि० टन)	४०	
६. नाइट्रोजन का प्रयोग (मि० हेक्टर)	११४	
७. सहकारी ऋण (करोड़ ₹०)	४५०	७
८. कुल निश्चित क्षेत्र (मि० हेक्टर)	३५६	

निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाकाल में ₹८१५ करोड़ ₹ व्यय का प्रावधान रखा गया है। इस योजना में सहकारिता एवं सामुदायिक विकास को भी महत्व दिया गया है जिस पर क्रमशः १७६ व ११६ करोड़ ₹ व्यय प्रस्ताव किया गया।

इस योजना में भूमि सुधार कार्यक्रमों पर महत्व दिया गया है। क्योंकि योजना वालों की यह मान्यता रही कि उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि सुधार अनिवार्य है। अतः, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण, भूमि जोतन वालों की सुरक्षा सम्बन्धी नियम बनाये जाने की व्यवस्था की।

गहन कृषि कार्यक्रमों को प्रमुखता दिये जाने के कारण तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए इस योजना में सिंचाई के विकास के लिए सघु सिंचाई योजनाओं पर ५१६ ₹ तथा बड़ी एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं तथा बाढ़ नियन्त्रण पर १०८७ करोड़ ₹ करने का प्रावधान रखा गया।

(२) चतुर्थ योजना में उद्योग (Industries in Fourth Plan) — चतुर्थ योजना औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य ८ प्र. स. से १०% वार्षिक का रखा गया।

उत्पादन में वृद्धि तथा विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में ३३३८ करोड़ रु तथा निजी व सहकारी क्षेत्र में २२५० करोड़ रु के विनियोग का अनुमान लगाया गया। इस योजना में विनियोग का उद्देश्य निम्न प्रकार रखा गया -

- (अ) पहले से स्वीकृति प्राप्त उद्योगों में विनियोग पूरा किया जायेगा।
- (ब) वर्तमान एवं भविष्य के विकास की आवश्यकतानुसार वर्तमान क्षमता में वृद्धि की जायेगी।
- (स) आंतरिक विकास से लाभ प्राप्त किया जायेगा।

इस योजना में बड़े उद्योगों का विकास छोटे उद्योगों के विकास के साथ-साथ किया जायेगा जिससे कि प्रतिस्पर्धा न हो। देश के सन्तुलित विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भारी व आधारभूत उद्योगों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का लक्ष्य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ सभी क्षेत्रों में सन्तुलन स्थापित करने का रखा गया।

चतुर्थ योजना में औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं

औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य

महीने	१९३८-६२ में उत्पादन	१९७३-७४
१. इस्पात पिंड (मि० टन)	६५	१०८
२. एल्यूमिनियम (ट्रकार टनों में)	१२५३	२२००
३. मशीन उपकरण करोड़ रु)	२००	६५०
४. पेट्रोलियम (कच्चा) (मि० टन)	६०६	८६
५. कागज (ट्रकार टन)	६४७०	८५००
६. सीमेंट (मि० टन)	१२२	१८०
७. कच्चा लोहा (मि० टन)	२८१	५१
८. कोयला (मि० टन)	६६५	६३५

इस योजना में गैर कृषि क्षेत्रों में अग्रिम राजस्व की सुविधा प्रदान करने के लिए उद्योगों के विवेन्द्रीकरण को आवश्यक माना। इसके अतिरिक्त उन उद्योगों के विकास को

भी मन्त्र दिया जो कि अधिक रोजगार प्रदान कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि उद्योगों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने की नीति का पालन किया गया है। इनके साथ ही उन उद्योगों के विकास को पर्याप्त महत्व दिया जो कि देश के विकास के लिए आवश्यक हैं। अतः इस योजना में लोहा एवं इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम, खाद एवं उर्वरक, बीड़े भारत की दवा, सीमेंट, कागज, तथा औद्योगिक यंत्र आदि उद्योगों के विकास को महत्व दिया गया है। इन अन्तर्ग में उद्योगों की वर्तमान उत्पादन क्षमता में विस्तार की योजनाय बनाने पर जोर दिया तथा आवश्यकतानुसार नये-नये उद्योग स्थापित करने का आयोजन किया गया।

✓(३) ग्रामीण एवं लघु उद्योग (Village and small industries)—चतुर्थ योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इस योजना-काल में कुल विनियोग ७४६ करोड़ रु का होगा, जिसमें से १८६ करोड़ रु सार्वजनिक क्षेत्र में तथा ५६० करोड़ रु निजी क्षेत्र में व्यय किये जायेंगे। इस अन्तर्ग में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए विरेप व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण की सुविधा के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा औद्योगिक वस्तियों की स्थापना की प्राथमिकता प्राप्त होगी। सभी प्रकार के बड़े का उत्पादन ३४० करोड़ मीटर से बढ़ाकर ४२५ करोड़ मीटर करने का लक्ष्य रखा गया।

४) यातायात व संचार (Transport and communication)—चतुर्थ योजना में यातायात व संचार के विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस योजना में यातायात व संचार के क्षेत्रों का विकास करने के लिए सांख्यिक क्षेत्र में ३२४५ करोड़ रु व्यय करने का प्रावधान रखा गया है जबकि तीसरी योजना में यह राशि २१११ करोड़ रु थी। इस योजना में रेलों के विकास पर १०५० करोड़ रु सड़क व सड़क यातायात पर क्रमशः ८७६ व ६४ करोड़ रु, बन्दरगाह एवं जहाजरानी पर ३३६ करोड़ रु वायु यातायात पर २०३ करोड़ रु तथा संचार व्यवस्था पर ५२० करोड़ रु व्यय का प्रावधान रखा गया। देश के विकास के लिए यातायात व संचार सुविधाओं का विकास एक अनिवार्यता है। इस योजना के विभिन्न लक्ष्य इस प्रकार हैं

यातायात एवं मंचार सम्बन्धी लक्ष्य

मदें	१९६८-६९	१९७३-७४
१ रेलवे द्वारा होया गया मात्र (मि० टन)	२०४	२६५
२ सड़कों (हजार मि० मी०)	६२५	३८५
३ धावाटिन गालिमें (हजार में)	२८६	५८५
४ कारगो (cargo) (हजार जी आर टी.)	२,१४०	३,५००

(५) शक्ति (Power)—आधिक विप्लव में शक्ति का विकास अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चतुर्थ योजना में इस मद में २४५६ करोड़ रु व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इस अवधि में पुरानी परियोजनाओं के विकास की व्यवस्था की जायेगी तथा नयी परियोजनाओं को शुरू किया जायेगा। विद्युत की उत्पादन क्षमता १४३ मिलियन किलोवाट से बढ़ाकर २२ मि० कि० करने का लक्ष्य रखा गया।

(६) सामाजिक सेवाएँ (Social services)—चतुर्थ योजना में सामाजिक सेवाओं पर ३२८० करोड़ रु व्यय का आयोजन किया गया है। इसमें से शिक्षा व्यवस्था पर ८२३ करोड़ रु व्यय होगा। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार को अधिक महत्व प्राप्त होगा। योजना के अन्त तक विद्यार्थियों की संख्या १६३ करोड़ होगी। मेडिकल कॉलेज में १०३ हो जायेगी तथा तकनीकी शिक्षा के लिए स्नातक स्तर पर २५,००० तथा डिप्लोमा स्तर पर ४८,६०० विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान पर १४० करोड़ रु व्यय की व्यवस्था है।

सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए ४१ करोड़ रु के व्यय की व्यवस्था का आयोजन है तथा स्वास्थ्य कार्यों पर ४३१ करोड़ रु व्यय दिये जायेंगे। प्रायोग क्षेत्रों में जलपूर्ति कार्यक्रमों पर व्यवस्था हो सके, जहाँ पानी का अत्यन्त अभाव है। इसके अतिरिक्त पिछड़ी जातियों के विकास के लिए जलम से कादग्रम बनाये गये हैं जिन पर करीब १४२ करोड़ रु व्यय करने का प्रावधान है।

(७) परिवार नियोजन (Family planning)—चतुर्थ योजना में जनसंख्या की वृद्धि की दर को कम करने के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रमों को विशेष महत्व

दिया गया है। इस अवधि में परिवार नियोजन के लिए ३१५ करोड़ रु. का प्रावधान है, जबकि तृतीय योजना में केवल २५ करोड़ रु. ही व्यय किये गये थे। इस योजना में जन्म दर को ३.६ प्रति हजार से घटाकर ३.२ प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वास पैमाने पर प्राचीण एवं शहरी क्षेत्रों में परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें कि अधिकांश सुविधायें मुफ्त प्राप्त होंगी। इसके अनिरीक्त व्यापक रूप से प्रचार एवं प्रसार की व्यवस्था की गई है।

(८) रोजगार (Employment)—चतुर्थ योजना में रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई सस्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि कृषि, प्राचीण क्षेत्रों का विकास व निर्माण कार्य, कुटीर उद्योग, पातायात, विद्युतीकरण आदि मंदों में विनियोग किया जाकर श्रम-प्रधान परियोजनाओं का विस्तार किया जायेगा। इससे केन्द्रीय व राज्य स्तर पर रोजगार की वसामो में वृद्धि होगी।

(९) आयात, निर्यात एवं भुगतान सन्तुलन (Import, export and balance of payments)—चतुर्थ योजना में ७% वार्षिक दर से निर्यातों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इससे निर्यात १३०० करोड़ रु. से बढ़कर योजना के अन्त तक १६०० करोड़ रु. हो जायेंगे। दूसरी ओर आयातों पर निर्भरता को कम करने का निश्चय किया गया है। इस योजना में अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन देश में ही करने का लक्ष्य रखा गया है, फिर भी योजनावधि में ६७३० करोड़ रु. के आयात का अनुमान लगाया गया है। इन लक्ष्यों के प्राप्त होने से चतुर्थ योजना के अन्त तक भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता काफी कम हो जायेगी तथा यह विश्वास किया गया है कि इस क्रम से पाचवी योजना के अन्त तक प्रतिकूलता पूर्णतः समाप्त हो जायेगी।

चतुर्थ योजना की प्रालोचना (Criticism of Fourth Five Year Plan)

चतुर्थ योजना का निर्माण देश की वर्तमान की समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं को देखकर किया गया है। इस कारण यह योजना अधिक महत्वकांक्षी हो गई है। जिस समय योजना का प्रारम्भ बनकर तैयार हुआ, उसी समय कुछ अर्थशास्त्रियों व विद्वानों ने इसकी सफलता के प्रति आशंका व्यक्त की इसकी अधिकांश आलोचनाओं इनमें निर्धारित लक्ष्यों को लेकर ही की गई है। प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :

(१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर अवास्तविक है—इस योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर ५.५ प्र. श. निर्धारित की है जो कि पिछले १८ वर्षों के नियोजन के

अनुभव के आधार पर व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती। आलोचकों के अनुसार अपेक्षित वित्तीय व्यवस्था होने पर भी इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है।

- (२) नौति निर्देश का अभाव—आलोचकों के अनुसार इस योजना में बचत की दर, निर्यात वृद्धि, सांख्यिक समस्याओं की वृद्धि आदि के नौति सम्बन्धी परिणाम सहो नहीं निवाले गये हैं। इससे नौति निर्देश का अभाव इस योजना में भी पाया जाता है।
- (३) कृषि उत्पादन में ५ प्र.श. विकास की दर प्राप्त करना कठिन है—आलोचकों के अनुसार कृषि में ५ प्र.श. की दर से वृद्धि होना कठिन प्रतीत होता है क्योंकि यह उसी समय संभव होगा जबकि अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया जाय। परन्तु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ऐसा होना सभी क्षेत्रों में सम्भव नहीं है।
- (४) योजना रोजगार प्रधान नहीं है—चतुर्थ योजना में यह कहा गया है कि अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी परन्तु इसमें सत्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया गया है अर्थात् कितने व्यक्तियों को वास्तव में रोजगार प्राप्त होगा। चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या करीब १ करोड़ ६० लाख थी तथा योजनाकाल में करीब २ करोड़ ३० लाख नव व्यक्तियों रोजगार प्राप्त करने के लिये घट जायेंगे। इस प्रकार कुल तीन करोड़ ६० लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। इस योजना की रूपरेखा को देखते हुए इतने अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना असम्भव सा प्रतीत होता है।
- (५) निर्यात सम्बन्धी नौति अवास्तविक है—इस योजना में निर्यातों में वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है निर्यातों में इतनी वृद्धि होना कठिन प्रतीत होता है क्योंकि अभी तक निर्यात सम्बन्धी उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त सुधार व वृद्धि दखन को नहीं मिलती है।
- (६) श्रान्ति कारीकार्यक्रमों का अभाव—चतुर्थ योजना में आर्थिक विषमता और प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करने के लिये ऐसे कोई कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है जिन्हें श्रान्तिकारी कहा जाय। अतः यह योजना भी प्रथम तीन योजनाओं की तरह सामान्य कार्यक्रमों के आधार पर 'गरीबी हटाने' का सक्ल परखी है जो कि सम्भव नहीं है। वास्तविकता यह है कि गरीबी हटाने या आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये श्रान्तिकारी नीतियों का अपनाया जाना अनिवार्य है।

उपर्युक्त आलोचनाओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह योजना भी अन्य योजनाओं की तरह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेगी।

परन्तु देश की समस्याओं के निराकरण व आर्थिक प्रगति के लिए योजनाओं का निर्माण आवश्यक प्रतीत होता है ।

चतुर्थ योजना की प्रगति (Progress of Fourth Plan)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन दिसम्बर १९७१ में संसद में पेश किया गया । इसने योजना के पथ में दो वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की गई । इस योजना में हुई प्रगति का वर्णन नीचे किया जा रहा है ।

(१) विकास की दर (Rate of growth)—चतुर्थ योजना में ५.७ प्र. श. वार्षिक वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया था । अतः तक प्राप्त अनुमानों के अनुसार सन् १९६६-७० में विकास की वास्तविक दर ५.२ प्र. श., १९७०-७१ में ४.२ प्र. श., १९७१-७२ में १.७ प्र. श. तथा १९७२-७३ में ०.६ प्र. श. रही । इस प्रकार विकास की दर निर्धारित लक्ष्य से काफी नीची रही ।

(२) कृषि (Agriculture)—चतुर्थ योजना में कृषि क्षेत्र में ५ प्र. श. वार्षिक वृद्धि की दर का लक्ष्य रखा गया । वास्तविक वृद्धि की दर सन् १९६६-७० में ५.१ प्र. श., १९७०-७१ में ४.७ प्र. श. रही । इसके बाद मौसम की प्रतिकूलता के कारण वृद्धि के स्थान पर कमी आयी । १९७१-७२ में १.७ प्र. श. तथा १९७२-७३ में ५.५ प्र. श. की कमी आयी ।

खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य १२६ मिलियन टन रखा गया था । खाद्यान्नों का उत्पादन १९६६-७० में ६६५ मि. टन, १९७०-७१ में १०८४ मि. टन, १९७१-७२ में १०५२ मि. टन, तथा १९७२-७३ में ६५२ मि. टन हुआ । १९७३-७४ में उत्पादन ११४ मि. ट. होने का अनुमान है ।^१

(३) उद्योग (Industries)—चतुर्थ योजना में औद्योगिक विकास में वृद्धि का लक्ष्य ८ से १० प्र. श. का रखा गया । औद्योगिक क्षेत्र में विकास की दर लक्ष्य से काफी नीची रही है । सन् १९६६-७० में औद्योगिक विकास की दर ६.८ प्र. श. रही जो सन् १९७०-७१ में ३.७ प्र. श. रह गई । १९७१-७२ में विकास की दर बढ़कर ४.५ प्र. श. हो गई तथा १९७२-७३ में ५ प्र. श. । अतः तक प्राप्त अनुमानों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि १९७३-७४ में विकास की दर १ प्र. श. से अधिक नहीं होगी । इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में विकास की दर निर्धारित लक्ष्य से

१ वित्तमंत्री द्वारा बजट (१९७४-७५) से पूर्व प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान ११० मि. टन लगाया है, जबकि साध. मंत्री ने ११५ मि. टन बताया है ।

बाफी कम रही है, जिससे राष्ट्रीय आय में भी पर्याप्त वृद्धि सम्भव नहीं हो सकी।

- (४) यातायात एवं संचार (Transport and communication)—चतुर्थ योजना में यातायात एवं संचार में ६४ प्र. श. वार्षिक वृद्धि की दर का लक्ष्य रखा गया। योजना के प्रथम दो वर्षों में ४६ प्र. श. की दर से की दर से वृद्धि हुई। १६-६-७० में वृद्धि की दर ५६ प्र. श. तथा ७०-७१ में ४६ प्र. श. रही तथा १६७१-७२ में ५ प्र. श. और १६७२-७३ में ३.८ प्र. श. रही।

- (५) बैंकिंग और बीमा (Banking and Insurance)—इस क्षेत्र में चतुर्थ योजना में ४७ प्र. श. वार्षिक वृद्धि की दर का लक्ष्य रखा गया जबकि वास्तविक वृद्धि इससे अधिक हुई १६६६-७० में ६२ प्र. श. तथा १६७०-७१ में ६६ प्र. श. की वृद्धि हुई। १६७१-७२ और १६७२-७३ में भी क्रमशः १०.७ प्र. श. तथा १२.४ प्र. श. की वृद्धि हुई।

- (६) सिंचाई (Irrigation)—चतुर्थ योजना में मध्यम व बड़ी सिंचाई योजनाओं द्वारा ४८ मि. हेक्टर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया जिस पर ६५९ करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान था। चतुर्थ योजना के अन्त में केवल ३.३ मि. हेक्टर भूमि पर इन योजनाओं द्वारा सिंचाई सम्भव हो सकेगी, जिसमें करीब ११७० करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है।

लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा ३२ मि. हेक्टर भूमि पर सिंचाई की सुविधा का लक्ष्य रखा गया जोकि योजना के अन्त तक प्राप्त कर लिया जाने का अनुमान है।

- (७) मूल्य वृद्धि (Price rise)—चतुर्थ योजना में मूल्यों की स्थिरता बनाये रखने पर काफी जोर दिया गया, परन्तु इस क्षेत्र में असफलता ही प्राप्त हुई। योजना के प्रथम तीन वर्षों में मूल्यों में वृद्धि का अनुपात कम रहा। परन्तु १६७२-७३ और १६७३-७४ में मूल्यों में वृद्धि का एक नया रिकार्ड स्थापित हुआ। १६७२-७३ में १३.६ प्र. श. तथा १६७३-७४ में २६.५ प्र. श. की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कृषि, उद्योग सभी क्षेत्रों में हुई। इस वृद्धि के कारण चतुर्थ योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा अर्थ व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो गई।

चतुर्थ योजना में हुई प्रगति की जानकारी निम्नांकित तालिका से स्पष्टतः प्राप्त हो जाती है

चतुर्थ योजना में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दरें

(Sectoral Rates of Growth)

(१९६६-७० से १९७२-७३ तक)

(प्रतिशत)

क्षेत्र । उपक्षेत्र	चतुर्थ योजना का लक्ष्य	१९६६-७०	१९७०-७१	१९७१ - ७२	१९७२ - ७३
०	१	२	३	४	५
(१) कृषि	५०	५१	४१	-१७	-५५
(a) कृषि उत्पादन	५०	५२	५२	-१६	-६१
(२) उद्योग	दस १००	६८	३७	४५	५०
(३) खाल एवं निर्माण	७७	५०	१८	२६	४२
(४) विजली, गैस व जलपूर्ति	६३	६४	४८	६६	७५
(५) यातायात एवं संचार	६४	५८	४६	५०	३८
(a) रेलवे	४६	५२	१६	३६	३०
(b) अन्य यातायात	७०	६८	७१	६०	४२
(c) संचार	७६	४४	७६	५५	५२
(६) वैज्ञानिक एवं बीमा	४७	६२	६६	१०७	११४
(७) अन्य सेवाएँ	४७	३३	१०	३८	४१
(८) निर्यात	७०	४२	८६	४८	२२१

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में वैज्ञानिक एवं बीमा तथा निर्यात की छोटकर किसी भी क्षेत्र में प्रस्तावित वृद्धि की दर को प्राप्त नहीं किया जा गया है। इस तथ्य को निम्नांकित तालिका से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। इस तालिका में भौतिक लक्ष्य और प्राप्ति को दर्शाया गया है।

प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य और प्राप्ति*
(Selected Output Projections and Achievements)

संके	नदय	१९७१-७२	१९७२-७३	१९७३-७४ (सम्भावित प्राप्ति)
	१	२	३	
१ चागात्र (मि ट)	१०६	१०५०	६५२	११४०
२ चावन (")	५०	४३१	३८६	४४०
३ गेहूँ (")	२४	२६४	२४६	३००
४ गन्ना (गु) (")	१५	११६	१०६	१३६
५ शाकर (")	४७	३११	३६	४३
६ वनस्पति (हजार टन)	६०५	५६४	५८१	५७५
■ मिन का कपण (विश्वित क्षन महिन)	-३५०	७४८३	८०५०	७८००
■ मनुष्य निमित्त कवडा	१५००	६६८	—	१५००
६ जूट निमित्त वस्तुये (हजार टन)	१५००	११२६	१२११	१२२०
१० पपर व पपर वाड (")	८५०	८०३	८१३	८३०
११ म्युनप्रिट (")	१५०	४००	४२	४३
१२ कक्का लोहा (मि टन)	५१४	३३६	३५	३७
१३ पेट्रोलिएम (") (कक्का)	८५	७४	७४	७७
१४ पेट्रोलिएम वस्तुये (")	२६	१८६	१७६	२१
१५ उवरक (हजार टन)	-४००	१२३०	१३८६	१५१२
१६ सीमेंट (मि टन)	१८	१५०	१५५४	१६०
१७ विजली (मि किलावाट)	८६	—	—	७२०
१८ व्यापारिक गाजिया (हजार (Commercial vehicles, म)	८५	३६७	३६	४८
१९ रेलवे वंगन (हजार)	२१५	८५	१०६	१३

उपयुक्त तालिका म स्पष्ट होजा है कि चतुर्थ पाञ्चा निधारित लक्ष्यो को प्राप्त करन म असफल रही है ।

चतुर्थ योजना की असफलता के कारण (Reasons of its Failure)

चतुर्थ योजना भी तीसरी योजना की भांति असफल रही है। इस योजना की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

- (१) मूल्य स्तर में वृद्धि (Rise in price level) इस योजनावधि में मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। योजना के अंतिम दो वर्षों १९७२-७३ तथा १९७३-७४ में वृद्धि क्रमशः १३.६% तथा २६.५% हुई, जिसके कारण योजना कार्यक्रमों को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका। मूल्य वृद्धि का कारण कृषि व औद्योगिक उत्पादन में कमी तथा घाट की अर्ध-व्यवस्था की अपनाया जाना है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में ही ६०० करोड़ रु की घाट की अर्ध व्यवस्था अपनायी गई।
- (२) योजना का महत्वाकांक्षी होना (Over ambitious)—योजना के प्रारम्भ में ही कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार था कि देश की अर्ध व्यवस्था को देखते हुए इतने व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका।
- (३) पाकिस्तान द्वारा आक्रमण (Attack by Pakistan)—चतुर्थ योजनाकाल में पाकिस्तान द्वारा देश पर आक्रमण कर दिये जाने के कारण बहुत से साधनों की सुरक्षात्मक कार्यों में लगाना पड़ा। इसके साथ ही अगला देश से आये शरणार्थियों पर भी भारी खर्च उठाना पड़ा तथा बगला देश को आर्थिक सहायता देनी पड़ी जिसने उत्पादन कार्य प्रभावित हुए।
- (४) जनता के सहयोग का अभाव (Lack of people's co-operation)—किसी भी योजना की सफलता के लिये जनता का सहयोग होना अनिवार्य होता है। परन्तु योजनाकारों की अकृशन्ता के कारण जनता से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सका। जनता से सहयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि 'ग्रामीण जन-सहयोग को विकास कार्यों में सक्रिय रूप से सम्मिलित बनाया जाय तथा विकास के लाभ समान रूप से वितरित किये जायें।"

योजनाओं की लगातार असफलताओं के कारण जनता का इन योजनाओं से विश्वास हटता जा रहा है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जायें जिससे व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर में सुधार हो, आर्थिक असमानतायें कम हो और सभी को समान कार्य के अवसर प्राप्त हो। इसके लिए आतिथारों वायक्रम, कुशल व ईमानदार प्रशासन तथा जनता के सहयोग की आवश्यकता है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

१. भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये ।
२. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यो और उपलब्धियों (targets and achievements) को बताइये । क्या आप इन उपलब्धियों में सन्तुष्ट हैं ?
३. तृतीय एवं चतुर्थ योजना के अन्तर्गत कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में हुई उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए ।
४. तृतीय एवं चतुर्थ योजना की वित्तीय व्यवस्था का तुलनात्मक वर्णन कीजिए ।
५. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर एक लेख लिखिये ।

अध्याय १८

★

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

[Fifth Five Year Plan]

★ ★ ★

श्रीमती इन्दरा गान्धी के संबोधन में, “हमारा प्रयास आपसी एक पीढ़ी के दौरान गरीबी और असमानता पर विजय प्राप्त करने के लिये समुचित रूप में मुनियोजित एवं सतुलित विकास गति देना है। इस सदन में हमारे ‘पांचवी पंचवर्षीय योजना’ रचनात्मक भूमिका निभायेगी।”

देश के सतुलित एवं योजनायुक्त विकास के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण है। देश में विद्यमान आर्थिक समस्याओं के निराकरण तथा व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से पांचवी योजना में कुल व्यय पहली चार पंचवर्षीय योजनाओं के कुल व्यय से अधिक रखा गया है। इस योजना की रूपरेखा राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन के पश्चात् दिसम्बर १९७३ में सदन के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई। पांचवी योजना में कुल ५३,४११ करोड़ रु के व्यय का प्रावधान रखा गया है। इस व्यय में से ३७,२५० करोड़ रु सावजनिक क्षेत्र में तथा १६,१६१ करोड़ रु निजी क्षेत्र में व्यय होने का प्रावधान है।

योजना के उद्देश्य (Objectives of the Plan)

पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं— (१) गरीबी हटाना, तथा (२) आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ विकास की ऊँची दर, आय का उचित वितरण तथा घरेलू बचतों में वृद्धि आवश्यक है।”

- 1 “Removal of poverty and attainment of self reliance are two major objectives that the country has set out to accomplish in

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है ।

योजना की व्यापक रचना (Strategy of Fifth Plan)^२

‘गरीबी हटाने’ एवं ‘आत्म निर्भरता प्राप्त करने’ के लिए पाचवी योजना में व्यापक रचना की गई है जिसमें निम्नलिखित बातों का समावेश है —

- (अ) राष्ट्रीय आय में ५५ प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि ।
- (ब) उत्पादक रोजगार के अवसरों का विस्तार ।
- (स) ग्यूनतम आवश्यकताओं के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा, पोष्टिक आहार, भूमिहीनों की आवास की व्यवस्था, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा गन्दी बस्तियों (slums) में सुधार तथा सफाई की व्यवस्था है ।
- (द) सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का विस्तार ।
- (य) कृषि, आधारभूत उद्योगों तथा व्यापक उपभोग वस्तुओं उत्पादित करने वाले उद्योगों पर विशेष बल देना ।
- (र) गरीबी के लिये उचित मूल्यों पर अनिवार्य उपभाग वस्तुओं के वितरण एवं प्राप्ति की व्यवस्था ।
- (ल) निर्यातों में तेजी से वृद्धि और आयात प्रतिस्थापन ।
- (व) अन्न वस्तुओं के उपभोग पर कटौति नियंत्रण ।
- (श) कीमतों, मजदूरी दरों और आयों में व्यापक सन्तुलन ।
- (स) आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये सहायक, राजकोषीय तथा अन्य उपाय करना ।

the Fifth Plan As necessary corollaries, they require high growth, better distribution of incomes and a very significant step up in the domestic rate of saving ’

—Draft Fifth Five Year Plan, Vol I, p. 15

इस प्रकार पाचवी योजना में ऐसी व्यूह रचना की गई है जिससे कि योजना में निर्धारित उद्देश्यों को सहज प्राप्त किया जा सके तथा “क्षयित्व के साथ विकास” किया जा सके।

पाचवी योजना में व्यय या विकास परिचय (Development Outlays in Fifth Plan)³ .

पाचवी योजना में कुल ५३,४११ करोड़ रु की राशि व्यय हेतु रखी गई है। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में ३७,२५० करोड़ रु. तथा निजी क्षेत्र में १६,१६१ करोड़ रु के व्यय का प्रावधान है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय में से ५,८५० करोड़ रु चालू व्यय (current outlay) के लिए रखे गये हैं, शेष ३१,४०० करोड़ रु विनियोग कार्यों के लिए है। इस प्रकार पाचवी योजना में उत्पादक कार्यों के लिए (विनियोग) कुल ४७,५६१ करोड़ रु का प्रावधान है। इस योजना में व्ययों का क्षेत्रवार (sector wise) ब्योरा निम्न प्रकार है —

सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय

(करोड़ रु में)

विकास की मद	चौथी योजना	पाचवी योजना	कुल व्यय या प्रोत्साहन	
			चौथी योजना	पाचवी योजना
	१	२	३	४
१ कृषि	३,४६६	४,७३०		
२ सिंचाई		२,६८१	२०७	२०१
३ शक्ति	२,४४८	६,१६०	११६	१६३
४ खनन एवं उद्योग	३,७२६	८,६३६	२१२	१४०
५ निर्माण (construction)	—	२५	—	०१
६ यातायात एवं संचार	३,८८७	७,११५	२३२	१६२
७ व्यापार एवं भंडार	३३६	२०५	२०	०६
८ आवास तथा वास्तविक सम्पदा	२५१	६००	११	१६
९ वैज्ञानिक तथा बीमा	—	६०	—	०२
१० सार्वजनिक प्रशासन एवं सुरक्षा	३१	६८	०२	०३
११ अन्य सेवाएँ,	२,४७३	५,७६०	१४८	१५४
(अ) शिक्षा	८५३	१,७२६	५१	४६
(ब) स्वास्थ्य	४३४	७६८	२६	२०१
(स) परिवार नियोजन	३१५	५१६	१६	१४

०	१	२	३	
(द) पाप हार (Nutrition)	—	४००	—	११
(य) शहरी विकास	१२६	१५३	३२	१५
(र) जल आपूर्ति	—	१०५२	—	२८
(ल) समाज कल्याण	—	२२६	—	०६
(व) पिछड़े वर्गों का कल्याण	१६३	२२६	११	०६
(श) श्रम कल्याण	—	५७	—	०१
(म) विविध	१४६	७७५	१६	०७
१२ विज्ञान एवं तकनीक	१४०	४१६	०८	११
१३ पंचतीय एवं आदिवासी क्षेत्र	—	५००	—	१३
कुल	१६,७७४	३७,२५०.१	१०००	१०००

इस योजना में कुल उपलब्ध साधनों के जस्तगत ही क्षेत्रवार साधनों का वितरण किया गया है जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित स्तरों तक पहुँचने के लिए साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव हो सके। इन योजना में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों (guiding principles) को ध्यान में रखा गया है —

- उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तेजी में पूरा करना जिन पर कि पहले से ही कार्य चल रहा है।
- पहले से अर्जित क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना जिससे कि उनमें लगी हुई पूँजी से अधिक लाभ प्राप्त हो सकें।
- उन मूल क्षेत्रों (care sectors) की अतिरिक्त क्षमता से न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त करना जिन पर कि जागामी शक्तों के विकास की गति निर्भर करती है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम विवास का स्तर प्राप्त करना।

निजी क्षेत्र में व्यय (Private Sector Outlay)

पाचवी योजना में निजी क्षेत्र में १६ १६१ करोड़ रु के व्यय का प्रावधान है जबकि

- क्षेत्रीय आधार पर कुल व्यय ३७,३८२ करोड़ रु होता है। अतः कुल व्यय ३७,२५० करोड़ रु बनाने के लिए १३२ करोड़ रु की कमीति करनी पड़ेगी या इनकी मात्रा में अतिरिक्त साधन (additional resources) जुटाने होंगे।

चतुर्थ योजना में ८,६८० करोड़ रु. ही व्यय किये गये । पाचवी योजना में निजी क्षेत्र में व्यय का क्षेत्रवार व्योरा निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है —

निजी क्षेत्र में विनियोग

(करोड़ रु० में)

विकास की मद	विनियोग	प्रतिशत
१. कृषि	२,६५०	१८.३
२. सिंचाई	—	—
३. शक्ति	१००	०.६
४. खनन एवं उद्योग (Mining and manufacturing)	६,२५०	३८.६
५. निर्माण	७५	०.५
६. यातायात एवं संचार	१,८७०	११.६
७. व्यापार एवं भंडारण	१,१५०	७.१
८. आवास एवं स्थल (sites)	३,६३६	२२.५
९. बैंकिंग व बीमा	१०	०.१
१०. सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा	—	—
११. अन्य सेवाएँ	१२०	०.७
(अ) शिक्षा	१००	०.२
(ब) विज्ञान एवं तकनीक	—	—
(स) स्वास्थ्य	२०	०.१
कुल योग	१६,१६१	१००

निजी एवं सहकारी क्षेत्र में विनियोग की विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में मुख्यतः खनन एवं उद्योग, आवास, कृषि एवं यातायात तथा संचार पर ही विनियोग किया जाएगा । निजी एवं सहकारी क्षेत्र में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर कुल १०.५० करोड़ रु. का विनियोग होगा जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में इस मद में केवल ६.१० करोड़ रु. का प्रावधान है । इस मद में अधिक विनियोग से रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा व्यापक उपयोग की वस्तुओं का अधिक उत्पादन सम्भव होगा ।

पाचवी योजना में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रमुख विकास कार्यों पर व्यय का व्योरा निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रु)

विकास की मद	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल व्यय
१ कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र	७,४११	२,६५०	१०,३५१
२ उद्योग, शक्ति एवं यातायात	२४,२४४	= २२०	२४,४६४
३. समाज सेवा व अन्य कार्यक्रम	५,५६५	४,६३१	१०,१९६
योग	३७,२२०	१६,१०१	५३,३२१

पाँचवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में करीब ७० प्र स तथा निजी क्षेत्र में करीब ३० प्र स विनियोग व व्यय होगा।

योजना की वित्त व्यवस्था (Financial Resources of the Plan)

पाचवी योजना में विशाल पैमाने पर वित्तीय साधन जुटाने का कार्यक्रम तैयार किया गया। साधनों को जुटाने समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि देश का तजी से आर्थिक विकास हो सके और स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

योजना के लिए विभिन्न वित्तीय साधनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है

योजना के अनुमानित वित्तीय साधन*

(Estimated Financial Resources for the Fifth Plan)

साधन	करोड़ रु (१९७०-७३ के मूल्या के आधार पर)
१ चालू विकास व्यय के लिये वजट व्यवस्था	५८५०
२ घरेलू वचर्ते	४५,१३०
(a) सार्वजनिक क्षेत्र	१४,३३६
(i) केन्द्र व राज्यों के वजट से अतिरिक्त	८,३४८
(ii) केन्द्र व राज्यों के गैर वित्तीय उपक्रम	५,९८८

(b) वित्तीय सहायता	७३६
(i) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	४६१
(ii) अन्य साधन	२७५
(c) निजी क्षेत्र	६०,०५५
(i) निजी कॉरपोरेट गैर वित्तीय क्षेत्र	४,१३६
(ii) सहकारी गैर राश्ल सन्ध्यायें	१६६
(iii) घरेलू क्षेत्र	२५,७५७
(३) विदेशी बचतो से शुद्ध प्राप्तिरा	२,४३१
कुल	५३,४११

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस योजना में १,८५० करोड ह बजट प्रस्तावी से, ४४,१३० करोड ह घरेलू बचतो से तथा २,४३१ करोड ह विदेशी सहायता से प्राप्त किये जायेंगे। इस योजना में घरेलू बचतो से अधिक से अधिक साधन जुटाने का प्रयत्न किया गया है जिससे मुद्रास्फीति से बचा जा सके। विदेशी सहायता कुल विनियोग की केवल ३१% ही प्राप्त करने का अनुमान है।

पाचवी योजना के लक्ष्य (Targets of Fifth Plan) :

पाचवी योजना का उद्देश्य योजनाकाल में मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का अनु-कूलतम उपयोग करके देश का ५५% की दर से आर्थिक विकास करना है जिससे १९८५-८६ तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाय तथा नीचे की ३० म. ल. जनसंख्या का उपभोग स्तर बढ़ सके। योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, कुल प्रमुख क्षेत्रों के लक्ष्यों का विवरण इस प्रकार है —

- (१) राष्ट्रीय आय विनियोग एवं बचत—पाचवी योजना में राष्ट्रीय विकास की दर ५५ प्र. श. निर्धारित की गई है। इस विकास की दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूंजी निर्माण व विनियोग की दर १३७ प्र. श. से बढ़ाकर योजना के अन्त तक १८३ प्र. श. करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही बचत की दर १६७३-७४ में १२२ प्र. श. से बढ़ाकर योजना के अन्त तक (१६७८-७९) १५७ प्र. श. करने का लक्ष्य है।

- (२) कृषि विकास एवं सहयोगी क्षेत्र के लक्ष्य—कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के विकास पर इस योजना में कुल ७ ६८० करोड़ रु का व्यय होगा जिसमें से सावजनिक क्षेत्र में ४,७३० करोड़ रु तथा निजी क्षेत्र में २,९५० करोड़ रु व्यय होंगे। इस योजना में साधान का उत्पादन ११४ मि० टन से बढ़ाकर १४० मि० टन करने का लक्ष्य है।
- (३) सिंचाई एवं शक्ति—पाचवी योजना में सावजनिक क्षेत्र में सिंचाई एवं बिजली के विकास पर क्रमशः २,६८१ करोड़ तथा ६,१६० करोड़ रु व्यय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त बिजली पर निजी क्षेत्र में १०० करोड़ रु व्यय का प्रावधान है। इसमें सिंचित क्षेत्र ४५३ लाख हेक्टर से बढ़ाकर ५७५ लाख हेक्टर करने का लक्ष्य है। सावजनिक क्षेत्र में बड़ी व लघु सिंचाई योजनाओं के विस्तार को महत्व दिया जायेगा। इस योजनावधि में १६ ५५ मि० किलोवाट बिजली क्षमता में वृद्धि करने का लक्ष्य है। इसी अवधि में १,१०,००० गावों में बिजली पहुँचाने तथा १५,००,००० बिजली के चलने वाले पम्प सेट (pump sets) लगाने का लक्ष्य है।
- (४) उद्योग एवं खनिज—पाचवी योजना में उद्योग एवं खनिज क्षेत्र में विकास की दर ८१ प्र.श. निर्धारित की है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना में १३,५२८ करोड़ रु के व्यय का प्रावधान है। इसमें से ८,१२८ करोड़ रु सावजनिक क्षेत्र में व्यय होंगे तथा ५,४०० करोड़ रु निजी क्षेत्र में। इस योजना में आधारभूत उद्योगों, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन तथा व्यापक उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों के विकास को अधिक महत्व प्राप्त होगा।

बड़े उद्योगों के विकास के साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी इस योजना में पर्याप्त महत्व दिया गया है। इस भेद में सावजनिक क्षेत्र में ६११ करोड़ रु के व्यय का प्रावधान है। इसमें करीब ६० लाख नये व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है।

- (५) रोजगार—पाचवी योजना में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें कोई सम्बन्धित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। योजना आयोग ने रोजगार को दो भागों में बांटा है—(१) मजदूरी रोजगार (wage employment) तथा (२) स्वयं रोजगार (self employment) आयोग का विचार है कि योजना में व्यापक पैमाने पर होन वाले विनियोग से बड़ी समस्या में

रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन यह अकेला समस्या सुलझाने में समर्थ नहीं है, अतः स्वयं रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के प्रयत्न किये जाने चाहिए। श्रम, सधु उद्योग, सेवायें, वाणिज्य एवं व्यापार सभी क्षेत्रों में रोजगार विस्तार के प्रयत्न होने चाहिए तथा विनियोग करते समय इस बात को महत्व दिया जाय कि श्रम प्रधान उद्योगों व व्यवसायों का अधिक विकास हो।

इस योजना में निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों को निम्नलिखित तालिका से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है —

पांचवी योजना के प्रमुख लक्ष्य (Main Targets of Fifth Plan)

संके	इकाई	चतुर्थ योजना में अनुमानित उपलब्धि	पाचवी योजना के लक्ष्य
१	लाघान	मि० टन	११४२
२	तिलहन	मि० टन	६४
३	गन्ना गुड)	" "	१३४
४	कपास	मि० गाठ	६५
५	जूट	" "	५६
६	चीनी	मि० टन	४३
७	बनस्पति	हजार टन	५७५०
८	पैपर एवं पैपर बोर्ड	" "	८३००
९	ग्युजभिट	" "	४३०
१०	खरक	हजार टन	१५१२०
११	बन्वा लोहा	मि० टन	३७०
१२	पेट्रोलियम (क्रूड)	" "	७७
१३	कोयला	" "	७६०
१४	पेट्रोलियम उत्पाद	" "	२१५
१५	इस्पात	" "	५४
१६	सीमेंट	" "	१६०
१७	ट्रेक्टर	हजार	४००
१८	बस	मि० मोटर	७८०००
१९	रेलवे वाहन	हजार	१३०
२०	मशीनें व औजार	नरोड रु० मूल्य	६४०

सन्धेय में, पाचवी योजना में औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, बेरोजगारी कम करने, मूल्य वृद्धि को रोकना तथा निम्न वर्ग में जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लक्ष्य रखे गए हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति उसी स्थिति में सम्भव है जहाँ उपलब्ध साधनों का कुशलतम उपयोग किया जाय, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त किया जाय, तथा जनता अनुशासित तथा एकवद्ध होकर विकास कार्यों में जुट जाय।

पाचवी योजना की आलोचना (Criticism of Fifth Plan) *

पाचवी पञ्चवर्षीय योजना में गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति आदि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यापक कार्यक्रम बनाए गये हैं तथा ५३,४११ करोड़ ६० व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। परन्तु पाचवी योजना के प्रारम्भ से ही इसकी आलोचना अर्थ-शास्त्रियों, विद्वानों और राजनीतिज्ञों द्वारा की जा रही है। अधिकांश आलोचकों ने इसके लक्ष्यों का महत्वाकांक्षी बनाया है तथा बढ़ते हुए मूल्यों और साधनों की अनिश्चितता के कारण इसकी सफलता में सन्देह व्यक्त किया है। इसकी प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) अधिक महत्वाकांक्षी योजना—पाचवी योजना का आकार बहुत बड़ा है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना बहुत कठिन है। योजना आयोग के सदस्य डॉ० बी एस मिन्हास ने लक्ष्यों के निर्धारण में मतभेद होने के कारण ही आयोग की सहायता से त्याग-पत्र दे दिया। डॉ० मिन्हास का विचार है कि ५५ प्र श वार्षिक वृद्धि की दर तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि ९१,००० करोड़ ६० की योजना है। वर्तमान योजना के आकार व स्वरूप के अन्तर्गत ४ प्र श से ४३ प्र श तक वार्षिक विकास की दर ही प्राप्त की जा सकती है।

डॉ एस टी ओ मिन्हास (Dr B S Minhas) ने शब्दों में— ‘यदि योजना आयोग में देवदूत बैठ दिए जायें तब भी ५५ प्र श वार्षिक विकास की दर प्राप्त नहीं की जा सकती।’^५

- (२) आर्थिक उद्देश्यों की प्रेरणा राजनीतिज्ञ उद्देश्यों से प्रेरित—पाचवी योजना में देश की आर्थिक स्थिति तथा उपलब्ध साधनों की ओर ध्यान नहीं दिया है बल्कि

5 “Even if the mythical angels were ordered into the Yajana Bhawan, the ‘nonness’ of the 55 percent real growth rate plan will not be capable of being preserved”

अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनता को भ्रम में डालने के लिए 'गरीबी हटाओ' और आमनिर्भरता प्राप्ति का नारा लगाया है।

(३) योजना में रोजगार के लिए ठोस कार्यक्रम का अभाव—पाचवी योजना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने व्यक्तियों को वास्तव में रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। आलोचकों का विचार है कि इस योजना में भी अन्य योजनाओं के समान बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होगी। इस प्रकार बड़े आकार के बावजूद भी यह योजना रोजगार के ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत करने में असफल रही है।

(४) क्रान्तिकारी कार्यक्रम का अभाव—इस योजना में भी आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने तथा केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्रान्तिकारी कार्यक्रम नहीं बनाये गए हैं। अन्य योजनाओं की तरह इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया है तथा गरीबों हटाने का संकल्प किया है। परन्तु योजनाओं के २३-२४ वर्ष के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना में भी अमीर और अधिक अमीर होंगे जबकि गरीबों की स्थिति और अधिक खराब ही होगी।

(५) वित्तीय साधनों की कठिनाई—वर्तमान में मूल्य वृद्धि और जनता में असन्तोष के वातावरण में देखने लगा घरेलू क्षेत्र से ४५,१३० करोड़ रु० की वित्तीय व्ययथा करना काफी कठिन प्रतीत होता है। इसके अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विनिमय संकट के कारण अमेरिकन विदेशी सहायता भी प्राप्त करना काफी कठिन है।

श्री एच० वी० आर० आयंगर (H V R Iynger) ने इन योजनाओं को अवास्तविक तथा अव्यावहारिक बताया है। उन्हों के शब्दों में

'We have mistaken paper plans for achievements and targets for accomplishment'

'कुछ अपेक्षास्थितियों का विचार है कि 'यह योजना भी अन्य योजनाओं के समान लक्ष्यों की पूर्ण करने में असफल रहेगी और नियोजन की राय को समाप्त कर देगी।''^६

यद्यपि इस योजना को महत्वाकांक्षी एवं अव्यावहारिक बताया जाता है, परन्तु भारत जैसे देश के लिए जहाँ पर ४० प्र.श. से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा (poverty line)

6 "The built in contradictions in the draft outline of the Fifth Plan would mean a repetition of the failures of target achievement and destroy the very credibility of planning"

से नीचे है, इतने व्यापक विकास कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। अतः गरीबी हटान और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने जैसे लक्ष्यों के लिए यह बहुत बड़ा जाकार नहीं है। योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन में ईमानदारी व कुशलता, जनसहयोग, बठोर परिश्रम व त्याग की आवश्यकता है।

अध्याय से सम्बन्धित प्रश्न

- १ पाचवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों और विकास कार्यों की व्याख्या कीजिए।
 - २ "पाचवी योजना 'अधिक महत्वाकांक्षी' योजना है।" विवेचना कीजिए।
 - ३ पाचवी योजना पर एक लेख लिखिए।
-